

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

राजस्थान विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष कला के पाठ्यक्रमानुसार

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समस्याएं

[Problems of Indian Economy]

लेखक

एस० एल० बोषी

प्रधानाचार्य

राजस्थान विश्वविद्यालय बुंगारपुर

प्रार० एस० शर्मा

प्रधानाचार्य

जोधरा लक्ष्मण विश्वविद्यालय मुकुन्दगढ़

रमेश बुक डिपो

जयपुर

प्रकाशक :

वृजमोहन लाल माहेश्वरी

रमेश बुक डिपो

जयपुर

● सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य 17.50

मुद्रक .

भूलाल प्रिन्टर्स,

जयपुर

भूमिका

द्वितीय वर्ष बच्चा के विद्यार्थियों के हितार्थ 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं' पर यह पुस्तक लिखी गई है। प्रत्येक पुस्तक की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं। इसमें भी कुछ विशेषताएँ हैं, यथा भाषा की सरलता, पाठ्यक्रमानुसार अध्यायों का क्रम और जुलाई 1973 तक के जाँकड़ों एवं तथ्यों का समावेश। भारतीय अर्थ-व्यवस्था की अनेकानेक समस्याएँ हैं और ये समस्याएँ भी अत्यन्त जटिल हैं। इन समस्याओं के विश्लेषण और उनके निवारण के उपायों पर विस्तृत विवेचन एक पाठ्य-पुस्तक में करना कठिन है। परन्तु इन समस्याओं की जानकारी रखना प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। हमारा इस पुस्तक में इस दिशा में ही प्रयास रहा है।

पुस्तक के संशोधन एवं संवर्द्धन में हमें श्री जे०के० टण्डन, प्राध्यापक, वाणिज्य महाविद्यालय, जयपुर का जो सहयोग मिला है उसके लिये हम उनके आभारी हैं।

हमें आशा है कि पुस्तक शिक्षक बन्धुओं की रचि के अनुकूल और विद्यार्थियों के लिए हितकर सिद्ध होगी।

हम श्री रामाकृष्ण माहेश्वरी, व्यवस्थापक, रमेश बुक डिपो, जयपुर के आभारी हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने में रचि दिखलाई। उनकी स्वीकृति एवं सहयोग के बिना शायद यह पुस्तक प्रकाशित नहीं होती। हम चन्द्रोदय प्रेम के व्यवस्थापक को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनके सहयोग के बिना इस पुस्तक का मुद्रण इतने कम समय में सम्भव नहीं हो सकता था। पुस्तक में यत्र-तत्र मुद्रण अशुद्धियाँ रह गई हैं जिसके लिए पाठक हमें क्षमा करेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव

(Impact of British Economic Policies on Indian Economy)

औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् गृह-वर्ह एव फूट के कारण देश की सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था विगड़ गयी थी। अन्तरिक अस्थिरता के कारण इस काल में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी (British East India Company) ने राजनीति में प्रवेश करना प्रारम्भ किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कम्पनी ने यहाँ अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत कर लीं। सन् 1757 ई. में प्लासी के युद्ध के पश्चात् कम्पनी ने बंगाल के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, उस समय किसान तथा राज्य के मध्य, जमींदारों आदि के रूप में कई समस्याएँ थीं। केवल दक्षिण भारत में अब भी किसानों का भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार था। जब तक कोई किसान सरकार को एक निश्चित भूमि कर देता रहता था, तब तक वह भूमि का मानिक बना रहता था। उस समय तक वह भूमि में बेदखल नहीं किया जाता था।

सन् 1760 ई. से प्राचीन भूमि-अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक नयी व्यवस्था जिसे नीलामी व्यवस्था कहते हैं, बंगाल के बर्दवान तथा मिर्जापुर जिलों में प्रारम्भ की गयी। इसके अनुसार भूमि अधिकतम लगान देने वाले को तीन वर्षों के लिए नीलाम कर दी जाती थी। सन् 1772 ई. से यह व्यवस्था पूरे बंगाल सूबे में लागू कर दी गयी, जिसके अन्तर्गत भूमि का पंचवर्षीय प्रबन्ध किया गया। पाँच वर्षों के बाद भूमि पर नई दरें निर्धारित कर दी जाती थी तथा भूमि पुनः नीलाम कर दी जाती थी।

इस काल में मालगुजारी या लगान वसूली का कार्य प्रायः कम्पनी के भुमास्तों तथा कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। वे बड़ी कठोरता से किसानों से उचित या अनुचित तरीकों द्वारा लगान वसूल करते थे। उन्होंने कृषकों की दशा सुधारने अथवा तरकालीन मिर्चाई व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। कर वसूली के सम्बन्ध में स्वयं क्लाइव का यह विचार था, "हमें जो कुछ बाज मिल

मकता है, वह हम अवश्य ले, जनि वाला कल स्वयं अपना ध्यान रखेगा।" ["Let us get what we can today, let tomorrow take care for itself"] इस नीति के परिणामस्वरूप ही सन् 1770 ई. में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे नष्ट की एक तिहाई जनसंख्या समाप्त हो गयी।

इनके पश्चात् सन् 1777 तथा 1781 ई. में भूमि सम्बन्धी व्यवस्था में कई संशोधन किये गये, परन्तु सगान व मालगुजारी की रकमों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कृषि व किसानों की स्थिति और अधिक शोचनीय होगी गयी। सन् 1772 ई. के बाद बारेन हेस्टिंग्स के काल में पाश्चात्यीय भूमि कर निर्धारण व्यवस्था के स्थान पर एक-वर्षीय व्यवस्था चालू की गयी जो देश के कृषि-विकास के लिए घातक सिद्ध हुई।

सन् 1784 में पिट्स टर्निश एक्ट के अन्तर्गत कम्पनी का प्रशासन सीधे ब्राउन के नियंत्रण में ले लिया गया तथा लॉर्ड कार्नवालिस को भारत का सर्वोच्च जनरल बना कर भेजा गया। काफी समय तक विचार-विमर्श करने के पश्चात् सन् 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बन्दोबस्त की घोषणा की।

भूमि का स्थायी बन्दोबस्त या जमींदारी प्रथा

सन् 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने इस प्रथा को सर्वप्रथम बंगाल, बिहार व उड़ीसा में लागू किया। किन्तु बाद में मालबर इन्हें देश के अन्य भागों, जैसे—पू. की पूर्वी भाग, बंगाल, उत्तर तथा दक्षिण मद्रास में भी लागू किया गया। इनके अन्तर्गत पहले के वर एवम करने वाले व्यक्तियों व राजस्व-कलेक्टरों को भूमि में निजी सम्पत्ति के अधिकार देकर भू-स्वामी बना दिया गया। ये अधिकार उन्हें स्थायी तौर पर दिये गये।

ऐसा अनुमान है कि सन् 1793 ई. में केवल बंगाल से ही 30,91,000 पींड मालगुजारी के रूप में वसूल किये गये। उन प्रथा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सगान की दरें भिन्न-भिन्न थीं। मद्रास में स्थायी बन्दोबस्त के काल में मालगुजारी उपज के $\frac{1}{3}$ या $\frac{2}{3}$ भाग के बराबर निर्धारित की जाती थी, जिसे बाजार भाव में रुपये में बदल कर सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था। मालगुजारी निर्धारित करते समय कुछ खपज में से उत्पादन व्यय घटा दिया जाता था। प्रत्येक जमींदार को अपने क्षेत्र में भूमि-मुधार तथा मिर्चाई की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सन् 1799 में बङ्गाली घमूल करने के लिए जमींदारों को विशेष रूप से कानूनी अधिकार प्रदान किये गये, जिसमें लगान व देने वाले, कृषक के माल की सुरक्षा की व्यवस्था थी,।

इस कानूनी अधिकारों में जमींदारों की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गयी। उन्होंने कृषक-कारों को बर्बाद कर दाता त्रिमंश कृषिगत अर्थ-व्यवस्था का ह्रास हुआ। इस व्यवस्था से सरकारी खजाने में भी, अन्तिम में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा सरकारी आय स्थूलतः स्तर पर रह गयी। जमींदारों ने भूमि-मुधार की दिसा में भी कोई उत्साह

नहीं दिखाया तथा ऊँची दर में लगान लेना प्रारंभ कर दिया। यह व्यवस्था अवैधानिक भूमि व्यवस्था थी जिसके कारण सम्पूर्ण सामाजिक वातावरण दूषित हो गया।

उपरोक्त दोषों में यह स्पष्ट है कि स्थायी बन्दोबस्त एक सफल प्रणाली नहीं रही तथा इसी कारण समय-समय पर कृषि-सुधार पर विचार करने वाले आयोगों [कृषि कमीशन (1928), लैंड रेवेन्यू कमीशन, बंगाल (1940) तथा (मुडलेट्ट कमीशन (1943, 1945) ने इसके सम्मूलन की सिफारिश की थी, यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में ही जब इन व्यवस्था को भारत के अन्य भागों में लागू करने के प्रश्न पर विचार किया गया था, तब सन् 1821 ई. में कम्पनी के सचालक मण्डल (Board of Directors) ने इसका विरोध किया था। सन् 1863 ई. में भी भारत मन्त्रि (Secretary of State for India) ने वाइसराय (Viceroy) को अन्तिम रूप से यह आदेश दिया कि इन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए।

अस्थायी बन्दोबस्त (Temporary Land Settlement)

जिन स्थानों पर भूमि का स्थायी बन्दोबस्त नहीं किया जा सका, वहाँ अस्थायी बन्दोबस्त का तरीका अपनाया गया। इन व्यवस्था के पीछे सरकार का दृष्टिकोण यह था कि भू-राजस्व की आय को लोचदार बनाया जाय और निश्चित अवधि के बाद इसमें वृद्धि कर दी जाय। इसका परिणाम यह होता था कि भूमि-सुधार आदि के भाग्य जमींदारों का लगान बढ़ने पर भ्रंशकारी भाव भी बढ जाती थी।

इन व्यवस्था के अन्तर्गत भी जमींदार नीच अनुसूचित भू-स्वामिन् का अधिकार ही रखते थे। ये स्वयं खेती नहीं करते थे। वे हिस्सों की भूमि लगान पर उठा बैठे थे तथा प्राप्त लगान में से अपना हिस्सा रख कर शेष सरकार को दे देते थे। यह प्रथा बंगाल उत्तरी प्रदेस, भू गो व बंगाल को छोड़ कर देश के अन्य भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी भूमि व्यवस्थाएँ भी अस्थायी बन्दोबस्त के अन्तर्गत ही आती थीं।

इस प्रथा में भी जमींदारी प्रथा के दोष, जैसे-स्थानों का शोषण, अति लगान, अनुपातव्य भूमि स्वामिन्, किसानों की वेदवृत्ति जादि पाये गये। इस पद्धति के अन्तर्गत बटाई प्रथा व शिकगी कास्तकारी की प्रथा भी पाई जाती थी।

रैयतवाड़ी प्रथा (Ryotwari System)

रैयतवाड़ी प्रथा की नींव सन् 1792 में पन्ना में डाली थी। सन् 1798 में भूमि की यह व्यवस्था सम्पूर्ण मद्रास-क्षेत्र में रखायित कर दी गयी। बाद में प्लम्बर यह प्रथा बम्बई एवं उत्तरी भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई। इस प्रथा के अन्तर्गत राज्य व रैयत के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध

स्थापित किया गया तथा निम्न ही भूमि का स्वामी होता था। स्थानीय राज्यीय नमंजारी प्रत्येक कान्तकार की भूमि का पूर्ण व्यापार रखता है तथा राज्य द्वारा घोषित दरों के आधार पर कृषक को राजस्व जमा कराना होता है। मालगुजारी को दरें 20 से 30 वर्षों के लिए निश्चित कर दी गयीं तत्पश्चात् इनमें संशोधन कर दिया गया।

मालगुजारी प्रायः उपज के $\frac{1}{3}$ भाग के बराबर निर्धारित की जाती थी, जिसे रूपायों में अदा करना पड़ता था। 1855 ई. में भूमि की पैमायश करा कर 30 वर्षों के अवधि के लिए व्यवस्था की गयी, तथा मालगुजारी मुक्त उपज के $\frac{1}{3}$ भाग के बराबर निश्चित की गयी। बम्बई में भी सन् 1835 ई. में भूमि की पैमायश कराकर भूमि को क्रिस्म के आधार पर 9 वर्गों में बांट दिया गया तथा उनकी श्रेष्ठता के आधार पर मालगुजारी निर्धारित की गयी। सन् 1839 ई. में बम्बई लैंड रेवेन्यू कोड (Bombay Land Revenue Code) का निर्माण किया गया जिसके अनुसार मालगुजारी भूमि के प्रयोग करने के उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित की जाने लगी।

इस व्यवस्था द्वारा भूमि का प्रबन्ध लिखे जाने के पश्चात् गांवों की सामूहिक प्रकृति समाप्त हो गई। भूमिधर किसान अबका रैयत में जमींदारी की भवना जा गई तथा स्वयं खेती न करके अपने नीचे बहुत से शिक्मी शासक रखने लगा। इन प्रथा के अन्तर्गत भूमि पर निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भूमि अधिकारियों (Land Revenue officers) को सौंप दिया गया था। वे अक्सर किसानों को तंग करते थे, तथा कर जमा करने में कठोर उपायों को भी अपनाते थे। इस प्रकार की दुराचालों को देखकर स्वयं सर डॉमस गुनरो ने जो किसी समय रैयतवादी प्रथा का समर्थक था, इसके परिणाम की निंदा की।

महलवादी प्रथा (Mahalwari System) :

जमींदारी तथा रैयतवादी प्रथाओं के दोषों को दूर करने तथा उनके उत्तम पक्षों को मिला कर महलवादी प्रथा बालू की गयी। उत्तर प्रांत, पंजाब तथा मध्य प्रांत के कुछ क्षेत्रों में भूमि व्यवस्था महलवादी प्रथा के अनुसार की गयी। सन् 1833 ई. के रेगुलेशन एक्ट (Regulation Act-1833) के अनुसार सर्वप्रथम आगरा व अवध में लागू किया गया था।

इस प्रथा के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को महल्लो या गांवों में बांट दिया जाता था। प्रत्येक महल्ल की इष्टि भूमि पर या तो उस महल्ल के समस्त कृषकों का समुक्त अधिकार होता था या किसी व्यक्ति विशेष का अथवा कई व्यक्तियों का समुक्त अधिकार होता था। किसान का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व, पैतृक व अपतृक अधिकार रहता था। जिसका भूमि पर पैतृक स्वामित्व नहीं था उनको

भूमि का पारस्परिक सद्भावना के आधार पर समझौते के द्वारा बटवारा किया जाता था।

अतः इसमें सरकार का सम्बन्ध व्यक्तिगत भूमिपर किसानों से न होकर इसके लिए किसी एक व्यक्ति अथवा समुदाय से होता था। यह व्यक्ति अथवा समुदाय ही सरकार को सबकी तरफ से भूमि-लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी माना जाता था। इसके अन्तर्गत भी सरकार ने कृषि के विकास में प्रारम्भ रूप से भाग नहीं लिया।

ग्राम प्रणाली (Village System)

पंजाब में भूमि व्यवस्था 'ग्राम प्रणाली' के आधार पर प्रारम्भ की गयी। इस प्रणाली के अन्तर्गत भूमि पर निजों स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया। माल-गुजारी की रकम गांव के मुखिया या सरकार के प्रतिनिधि द्वारा वसूल की जाती थी। सम्पूर्ण ग्राम पञ्चायत के लिए वार्षिक मालगुजारी की रकम सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती थी। पंजाब में यह प्रणाली आंशिक रूप में चालू रही इसके दो कारण थे—

(1) पंजाब अंग्रेजी राज्य में अन्त में सम्मिलित किया गया था, अतः नयी भूमि-व्यवस्था द्वारा वहाँ की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त नहीं किया गया।

(2) जब पंजाब पर कुछ समय पूर्व ही विजय प्राप्त की गई थी तथा वहाँ के लोगों में दुर्दीप्त जोश समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए विदेशी शासकों ने ग्राम समाज के प्रति उनकी भावनाओं को धनाये रखने का ही प्रयास किया।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में विदेशी प्रशासकों ने जिन भूमि व्यवस्थाओं को लागू किया उनसे भारतीय कृषि में कोई सुधार नहीं हुआ। भूमिपति या रैयत राज्य-कार के भार से दूखना दबा रहता था कि वह भूमि-मुक्तारों के सम्बन्ध में विचार भी नहीं करता था। साम ही भूमिपर रैयत तथा जमींदार स्वयं भूमि पर काबू या खेती नहीं करते थे। उनका स्वार्थ एवं हित कृषकों से प्राप्त होने वाले लगान तक सीमित था। वे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए किसानों पर घोर अत्याचार करते थे तथा उनका शोषण करते थे। जब कभी जमींदार या मल्कार द्वारा (रैयतवादी क्षेत्रों में) लगाव की दरों में वृद्धि की जाती तो ये मध्यस्थ भी जमी या उससे ज्यादा अनुपात में अपने हिस्से की मांग करते और फलस्वरूप आस्तविक जोतने वाले पर लगान का भार बढ़ता चला गया। डा. बी. बी. भट्ट द्वारा प्रस्तुत अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका इस तथ्य की पुष्टि करती है।¹

1 V. V. Bhat: Aspects of Economic Change and Policy in India, Chapter 2
England's Debt to India by Lajpatrai edited by E. M. Bhatia.

19वीं शताब्दी में भू-राजस्व

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	भू-राजस्व	करों से प्राप्त कुल आय	1 का 2 से प्रतिशत
1867-68	20 3	33 7	60 2
1877-78	20 0	34 9	57 3
1895	26 2	56 5	46 4

कुल मिलाकर कृषक की शुद्ध उपज के 60% से 100% तक लगान के रूप में देना होता था। इन सबमें म रमेश दत्त ने यह लिखा है कि “कृषि से प्राप्त लाभ का 50% लिया जाना किसी भी सम्य सरकार के द्वारा शासित अन्य देश के भू-राजस्व से कहीं अधिक भारपूर्ण है।”¹

पर भार बढ़ने के अलावा भूमि सुधार के कार्यक्रमों के न अपनाने व किसानों की दृष्टिनायकों की ओर कोई ध्यान न देने के कारण अधिकांश कृषक खेतिहर श्रमिक मात्र रह गये और भारतीय कृषि की दशा निरन्तर गिरती चली गयी। अविश्व कर देने के कारण कृषक वर्ग में व्यापक निर्भुनता थी जिस कारण उनकी आय घुसालता कम हो गयी तथा भूमि से अधिक पैसावार प्राप्त करने की उनकी इच्छा मर गयी। विदेशी सरकार का केवल भूमि में अधिक से अधिक आय प्राप्त करने का ध्येय रहा। इसका प्रमाण तो इसी तथ्य में मिलता है कि सन् 1870 से 1880 के बीच 230 करोड़ रुपये से अधिक भू-राजस्व के रूप में वसूल किये गये, परन्तु मिर्चाई के साधना के विकास पर राज्य ने इस अवधि में केवल 25 करोड़ रुपये खर्च किए। यही सब भारतीय कृषि के विकास में गतिरोध लाते को पर्याप्त था। साम्प्रतिक बात तो यह भी कि अग्रज अधिकारी मिर्चाई अथवा कृषि व्यवस्था के अन्य सुधारों को पैसे की बरबादी मानते थे।²

दन्तिशयी शताब्दी में कृषि विकास की विशेषताएँ—सन् 1857 ई के पूर्व भूमि व्यवस्थाओं में अनेक परिवर्तन किये गए थे। रंगतवादी व्यवस्था का विस्तार किया गया था तथा लार्ड विलियम बेंटिन्ग द्वारा सन् 1833 ई में अवध व आगरा में महलदारी प्रथा लागू की गई थी। कृषक वग उस समय काफी सम्पन्न थे। देश

1. Ramesh Dutt Indian Economic History of India Vol. I Chapter 12 & 13

2. Ramesh Dutt The Eco History of India, vol II p. 263.

ने साखान्नों तथा अन्य व्यापारिक फर्मों के निर्यात में अधिक वृद्धि की गई। सन् 1875 ई. में भारतीय सिपाहियों के विप्लव (Sepay Mutiny) के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने इस देश की आगम की ओर अपने हाथों में ले ली। तबोपगन्त सरकार ने आन्तरिक शान्ति को बनाये रखने तथा आन्तरिक क्षेत्रों में बचा माल बन्दगाहों तक पहुँचाने के लिए देश में सड़कों तथा रेलों का तेजी से विकास किया। इससे इंग्लैंड की निम्नित वस्तुओं की आन्तरिक भाषों में पहुँचाने में सुविधा हुई। कृषि की स्थिति भी दिन-प्रति-दिन प्रगच्छती गयी। जिसके परिणामस्वरूप निम्न विशेषताओं में देखने को मिलती थी—

(1) भारत इंग्लैंड का एक कृषि-प्रधान उपनिवेश हुआ—इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रान्ति होने के पश्चात् यहाँ के निम्नित माल की खपत तथा कच्चे माल तथा औद्योगिक भूमिकों के लिए साखान्नों की पूर्ति करने वाला देश भारत ही था। रेलों व सड़कों के निर्माण में इन उद्देश्यों की प्राप्ति में और भी सहयोग प्रदान किया, जिससे यह देश 19वीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैंड पर पूर्ण रूप से पराधीनता में आ गया।

(2) औषध बुद्धि—देश में साखान्नों का निर्यात होने से अन्न की कमी हो गई। सन् 1800 ई० से लेकर सन् 1900 ई० तक नियमित रूप से अन्न पकते रहे, जिसके परिणामस्वरूप इन 100 वर्षों में 2 करोड़ 14 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 19वीं शताब्दी के अन्त में 80 प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। कृषि की समृद्धि पर ही लोगों का सुख तथा उनकी समृद्धि निर्भर थी और फसलों के नष्ट हो जाने पर देश में अन्न की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी।

(3) कृषि भूमिक वर्ग का प्रादुर्भाव—19वीं शताब्दी में अन्न भूमि-व्यवस्थाओं को लागू किया गया उनके अन्तर्गत भूमि-कर वसूली की व्यवस्थाएँ हल्की बँटी थी कि किसानों की भूमि पर अपना अधिकार बनाये रखना कठिन हो गया। जमींदारों अथवा गुमास्तों के अधिकाधिक में बनने के लिए वे अपना येन छोड़कर दूसरों की भूमि पर काम करने लगे। इस प्रकार एक ऐसे कृषि भूमिक वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जो अनुपस्थित जमींदारों, व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा शोषित किया जाने लगा।

(4) व्यापिक व्यवस्था का प्रारम्भ—नवीन भूमि-व्यवस्थाओं तथा भू-करों की नवीन प्रणालियों के प्रचलन में आने के बाद जमींदारों व अधिकारों को सुरक्षित बनाने तथा रैयत या किसानों से एक निश्चित राशि भू-कर के रूप में वसूल करने के लिए कानूनी बदलावों, बदलावों की भी, व्यापिक जाच, कुर्की आदि की व्यवस्थाएँ चालू की गयीं।

(5) कृषकों की श्रम-प्रसूता—नवीन भूमि-कर व्यवस्थाओं के अन्तर्गत लगान या मासुबारी जिस कठोरता से वसूल की जाती थी, किसानों के पाद उद्योग बचने

का एकमात्र उपाय महाजनों या साहूकारों से ऋण लेना था। साथ ही गतराताब्दी में अकाल पड़ने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई थी। फर भार की निरंतर वृद्धि से किसानों की ऋण-ग्रस्तता भी बढ़ती गयी।

(6) सरकारी नीति—ब्रिटिश सरकार की नीति भूमि-कर के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त करनी थी। कृषि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भूमि बेचने, रहने रखने तथा हस्तान्तरित करने के नवीन अधिकारों के प्रदान किए जाने से भूमि का विभाजन और अपखण्डन इस सीमा तक हो गया कि जोत की हकाइया अनार्थक हो गई। राज्य और भू-स्वामियों तथा कृषकों के बीच मध्यस्थों की एक ऐसी लम्बी कड़ी कार्यशील हो गयी, जिससे किसानों का बोधन अधिक होने लगा।

प्रश्न

1. "विनाश की प्रक्रिया जो विदेशी शासन की स्थापना के साथ शुरू हुई और जिसे विदेशी प्रभाव की शक्ति ने सहायता दी, वह अन्ततोगत्वा भारत में आर्थिक गतिहीनता या जड़ता में परिणत हुई।" इस कथन की भारत में उन्नीसवीं शताब्दी की ब्रिटिश नीति के सम्बन्ध में पुष्टि करें।

(राज्य प्रथम वर्ष टी. डी. सी., 1971)

घरेलू उद्योगों का पतन

(Decline of Indigenous Industries)

"At a time when the West of Europe, the birth place of the modern industrial system was inhabited by uncivilized tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for the high artistic skill of her craftsmen."

—Industrial Commission, 1918

ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, जो अठारहवीं शताब्दी के मध्य में शुरू हो गई थी, ने सिर्फ ब्रिटेन में ही छोटे उद्योगों तथा श्रमिकों का ही शोषण नहीं किया, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। इस औद्योगिक क्रांति के प्रभाव भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक पूर्ण रूप से छा गये, जिससे देश का प्राचीन औद्योगिक ढांचा गिर कर अपना प्राचीन वैभव एवं कीर्ति खो बैठा। जैसा कि औद्योगिक कमीशन 1918 की रिपोर्ट में कहा गया है—"उस समय जबकि पश्चिमी यूरोप में, जो कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जन्म स्थान है, असम्भोग निवास करते थे, भारत अपने शासकों की अपार सम्पत्ति तथा अपने शिल्पकारों की कलात्मक कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध था।" इस विवरण से यह स्पष्ट है कि प्राचीनकाल से ही भारत में कृषि के साथ-साथ उद्योगों का भी विकास किया गया, लेकिन बड़े-बड़े उद्योगों का हमेशा से ही अभाव रहा। परन्तु आरम्भ-निर्भर ग्राम समाज में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास प्राचीन काल से किया था, उसमें घरेलू उद्योगों का ही विशेष महत्व था। इन उद्योगों के छोटे होने के बावजूद भी, "भारत एशिया की कृषि रूपी जननी, मानव सभ्यता का औद्योगिक कारखाना तथा विश्व व्यापार की धुरी था।"¹

1. India was the agricultural mother of Asia, the industrial workshop of civilization and the hub of world's commerce.

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि "भारतीय उद्योग केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करते थे, बल्कि अपनी निर्मित वस्तुएँ विदेशों को भी भेजते थे।"¹ वस्तुतः पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के सताब्दियों पूर्व, भारतीय समाज अत्यधिक समृद्धिवादी था। भारत में निर्मित कलमत्तक वस्तुएँ विश्व में अद्वितीय मानी जाती थीं। भारत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्माता था। यहाँ की ढाका की मलमल बिस्व-विख्यात थी, लोहे के उद्योग का भी समुचित विकास हो चुका था तथा अनेक वस्तुएँ, जैसे—मूँती तथा रेशमी वस्त्र, शाल कुशल, चन्दन की धनी वस्तुएँ, चाय जूते, बरतने, धमड़ा, चीनी, नील, उम्दाएँ, रंग, नमक, चाय, सोना, ताँबा, कोयला, लकड़ी, अफीम तथा विवाहिता की वस्तुएँ भारत से विदेशों को भेजी जाती थीं। विदेशी व्यापार अधिक विकसित होने के कारण सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में तथा सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुगल शासकों का ऐच्छन अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। भारत की समृद्धि ने ही विदेशी व्यापारियों को यहाँ के व्यापार से लाभ उठाने के लिए आकृष्ट किया था। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी अंग्रेज व्यापारियों की एक ऐसी संयोजित संस्था थी जिसका लाभकारी व्यापार भारत की मरमल, छोट, कमीदे और कढ़ई के काम की वस्तुओं, हिरें-जवाहरान तथा ऊनी और रेशमी कपड़ों पर आधारित था।

प्राचीन भारत में हिन्दू शासकों के काल तक तो भारतीय उद्योग गाँवों में ही पनपते तथा विवर्धित होते रह, यद्यपि उस समय भी नगरी (धार्मिक स्थानों तथा राज-धानियों) में कुछ उद्योग प्रचलन स्थापित किये गये थे। परन्तु मध्यकाल, विशेषकर मुगल शासन-काल में अधिकांश उद्योग-क्षेत्र नगरों में ही केन्द्रित होने लगे थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि मुगल शासकों द्वारा शम समाज की व्यवस्था में हस्तक्षेप किये जाने तथा कृषि पर उत्पत्ती हुई मालगुजारी से परेशान होकर निलम्कारों ने नगरों में बसना प्रारम्भ कर दिया था। यही कारण है कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गाँवों के उद्योग-धन्धों की अपेक्षा नगरों के उद्योग धन्ध अधिक व्यवस्थित थे। इन उद्योग श्रमियों के द्वारा अविनत नगर में रहने वाल धनी व्यक्तिओं तथा राज दर-बार के कुलीनवर्गों सामन्तों तथा नयावों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुएँ निर्मित की जाती थीं। उस समय हाथ में बतन हुए मूँती कपड़ का उद्योग ही मुख्य उद्योग था। और भी दल का कथन है कि 'मुनाई का काम जनता का राष्ट्रीय उद्योग था और कताई का काम लालों रिखा करती थीं।'

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय उद्योगों में मूँती कपड़ों का उद्योग अधिक विकसित एवं विस्तृत था। इसके केन्द्र ढाका, लखनऊ, अहमदाबाद,

नागपुर, मयूरा आदि में। इन उद्योगों के अतिरिक्त काश्मीर तथा पंजाब ऊनी दुशालों के लिए बनारस, नासिक, पूना, महमदाबाद, विशाखापट्टनम तथा तम्रौर पीतल, तांबे तथा अन्य धातुओं की वस्तुओं के लिए, पंजाब तथा सिन्ध ढाल-तलवार के लिए तथा राजपूताना के कई नगर पत्थर की सड़ई, मीनाकारी आदि के लिए प्रसिद्ध थे।

भारतीय उद्योगों की क्रमिक क्षयनति

भारतीय उद्योगों की अवतति सन् 1757 ई० से ही प्रारम्भ हो गई थी, जबकि पलासी के युद्ध के पश्चात् ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी। अपने शासन काल के प्रारम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय व्यापारियों को अधिक मूल्य देकर औद्योगिक केन्द्रों से मात लीजने का प्रयत्न किया। इस व्यवस्था को चालू करने का उसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। वह अपने प्रतिस्पर्द्धी विदेशी व्यापारियों, फ़ार्मिगी तथा अन्य कम्पनियों को भारतीय व्यापार को किसी प्रकार पनपने का अवसर नहीं देना चाहती थी। इस प्रकार भारतीय वस्तुओं की मांग पर एक बार एकाधिकार प्राप्त कर लेने के बाद कम्पनी ने उनकी मात्रा रिम्बो, मूल्यों आदि को अपने पक्ष में नियंत्रित करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारियों की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई। वे कम्पनी की मांग तथा उनके द्वारा निर्धारित मूल्य पर आश्रित हो गये। इससे उनका लाभ कम होना लगा तथा बुनकरों को कम पारिश्रमिक मिलने लगा। व्यापारी अपना स्वतन्त्र व्यापार छोड़ कर कम्पनी के वेतन भागी हुमाइती के रूप में काम करने लगे और बुनकरों का अधिक शोषण करने लग। व उत्पादकों से कम से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे देश का भूतल वस्त्र उद्योग लुप्त हो गया।

कम्पनी ने भारतीय उत्पादकों को कम से कम मूल्य देकर उनसे अधिक से अधिक निर्मित वस्तुएं प्राप्त करने की नीति अपनाई थी। धीरे धीरे कम्पनी ने जब सम्पूर्ण भारत पर अधिपत्य कर लिया तब यह नीति सभी भारतीय उद्योगों के सम्बन्ध में लागू की गई। तबाल में कम्पनी ने मूनी तथा देशी वस्त्रों का अधिक से अधिक निर्यात करने के लिए स्वयं अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की।¹ भारतीय कारीगरों ने इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बाध्य किया गया। इतना ही नहीं उन्हीं उन्हीं समय तक फैक्टरी में बाहर जान नहीं दिया जाता था जब तक कि वह एक निर्धारित मात्रा में काम पूरा नहीं कर लेते थे। अन्य स्थानों पर नियुक्त व्यापारिक रेसीडेंट्स (Commercial Residents) को व अधिदेश दिये गये कि गांवों में रहने वाले कारीगरों

¹ Quoted by Karl Marx Capital A Critical Analysis of Capitalist Production " Vol I, 432

को बिना उपयुक्त मुगताम किये अधिक से अधिक माल का उत्पादन करता था। इस प्रकार कारीगरों की स्थिति कम्पनी के दासों की तरह थी। इस नीति का इतना फ़ोरोस्ता से पालन किया गया कि बहुत से कारीगर अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ कर गावों में जाकर खेती करने लगे। सन् 1834-35 ई० में कम्पनी के गवर्नर जनरल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, "बाणिज्य के दौलत में ऐसी दयनीय स्थिति का अन्य कोई दृष्टान्त नमूना ही मिले। भारतीय मूलि वस्त्रों की बिक्री की हदिको से सफ़ेद नज़र आती है।"¹

इस प्रकार धीरे-धीरे भारतीय व्यापार तथा उत्पादन-व्यवस्था पर कम्पनी का नियन्त्रण और अधिकार बढ़ता गया। परन्तु 18वीं शताब्दी के अन्त तथा 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप बड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किया गया, तब से भारत को एक निर्यातक देश (exporter) के स्थान पर आयातक देश (importer) बनाने के प्रयत्न किये जाने लगे। इन विचारों में सबसे पहले सन् 1813 ई० में चार्टर्ड अधिनियम के अन्तर्गत ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारत में व्यापार करने का एकधिकार समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जब इंग्लैंड के उद्योगपति अपने उद्योगों का निर्यात माल भारत जैसे उपनिवेश में बेचकर ही ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना चाहते थे। इसके लिए दूसरा उपाय यह किया गया कि बड़ा की सरकार ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपना कर उद्योगपतियों को भारत को अधिक से अधिक निर्मित माल निर्यात करने की छूट दे दी तथा दूसरी तरफ़ तटकर (टैरिफ़) नीति द्वारा अपने देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं के आयात को कम कर दिया। परिणामस्वरूप सन् 1814 ई० से सन् 1835 ई० तक भारत में ब्रिटिश निर्मित सूती वस्त्रों के आयात में 30 गुने से अधिक वृद्धि हुई (एक मिलियन गज से बढ़ कर 51 मिलियन गज), जबकि भारतीय निर्मित सूती वस्त्रों का निर्यात निरन्तर कम होता गया (सन् 1814 ई० में $1\frac{1}{2}$ मिलियन गज, सन् 1844 ई० में 63,000 गज तथा सन् 1850 ई० में सम्पूर्ण ब्रिटिश निर्यात का $1\frac{1}{2}$ भाग)।

इन सबके में सन् 1833 में एक चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा कम्पनी की समस्त व्यापारिक क्रियाएँ समाप्त कर दी गयीं और इंग्लैंड के पूँजीपतियों को भारत में अपनी पूँजी विनियोजित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस विशेषाधिकार के फलस्वरूप बड़ा के पूँजीपतियों ने बड़ा अपनी फैक्टरियाँ स्थापित की तथा अन्य उद्योगों में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया। विदेशी पूँजी के प्रवेश

1. "The misery hardly finds a parallel in the history of commerce, The bones of the cotton-weavers are bleaching the plains of India."

में तथा व्यापार पर ब्रिटिश व्यापारियों का एकाधिकार होने के कारण भारतीय प्राचीन उद्योग धन्य नष्ट होने लगे।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय उद्योग धीरे-धीरे अवनति की स्थिति में थे। इन उद्योगों की स्थिति के विषय में मॉन्टगोमरी मार्टिन (Montgomery Martin) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, "सूरत, दाका, मुर्शिदाबाद तथा अन्य स्थानों का, जहाँ भारतीय वस्तुएँ निर्मित की जाती थी, बिनाश एक ऐसी नष्टग्रस्त वास्तविकता है, जिसके सम्मन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता।"¹ इसी सम्बन्ध में सन् 1880 ई. में सर हेनरी कॉर्टन ने कहा था, "सन् 1767 ई. में भारत से इंग्लैंड को 30 लाख रुपये मूल्य की डारा गतलिन का निर्यात किया गया था, सन् 1817 ई. में उसका निर्यात पूर्णतया बन्द हो गया। "दे फुटुम्ब, जो (इस उद्योग के कारण) समृद्धिप्राप्ति थे, नगरी की छोड़ने के लिए विवश हो गये तथा जीविकोपार्जन के लिए गावों में आश्रय लेने लगे" इस प्रकार की बिनाश की स्थिति केवल दाका में ही नहीं बल्कि सभी जिलों में उत्पन्न हो गयी थी।"²

भारतीय घरेलू उद्योगों की अवनति के कारण

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय घरेलू उद्योगों की अवनति के निम्नलिखित मुख्य कारण थे।

(1) मुख्य साम्राज्य के अन्तिम काल में गृह-कलह तथा आन्तरिक मतभेद और गणेश की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में पारस्परिक कलह और भुट होने के कारण केन्द्रीय राज्य-सत्ता बराबर कमजोर होती गयी। जागीरदारों, नवाबों और सामन्तों में भी कूट पड़ गयी। परिणामस्वरूप देश की राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था उल्लिखित हो गयी। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योगों का समुचित विकास नहीं किया जा सका।

(2) राज दरबारों के संरक्षण का अभाव देश में व्यापक राजनैतिक अशान्ति होने के कारण, नगरस्थानों तथा गावों में काम करने वाले कारीगरों की निर्मित वस्तुओं की माग कम हो गयी। राज-दरबार, सामन्तों, नवाबों आदि से

1 "The decay and destruction of Surat, of Dacca of Murshidabad and other places where native manufactures have been carried on, is too painful a fact to dwell upon."

Murray, Hugh "History of British India" p. 16

2. "In 1767 the exports of Dacca muslin to England amounted to Rs. 30 lakhs of rupees, in 1817 they had ceased altogether. Families which were formerly in a state of affluence have been driven to desert the towns and betake themselves to villages for a livelihood. This decadence had occurred not in Dacca only, but in all districts."

Ibid. p. 16

उनको कोई सुरक्षा एवं संरक्षण नहीं मिला दिनमें सूनी व रेखाभी कपड़ों के उद्योग भी स्थिति बहुत ही गंवार हो गयी।

(3) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीति - मुगल शासन के कमजोर होने ही कम्पनी का राजनैतिक प्रभाव बढ़ने लगा। कम्पनी ने दिन-ब-दिनता में कारीगरों में क्षीयनाशित नाम लेकर कम से कम मजदूरी देने अथवा अधिकतम लाभ को न्यूनतम मूल्य पर मजदूरों की नीति अपनायी, उससे कारीगरों में काम करने का उत्साह समाप्त हो गया। फलस्वरूप घरेलू उद्योग धीरे-धीरे समाप्त होने लगे।

(4) देशी व्यापारियों का छटना हुआ प्रभाव - कम्पनी सरकार स्थापित होने के पहले अंग्रेज व्यापारियों को निर्मित माल बेचने का काम देशी व्यापारी या व्यापारिक मण्डल निभा करते थे। परन्तु कम्पनी सरकार की यकती हुई राजनैतिक शक्ति न न केवल अपने शासन का विस्तार किया, बल्कि देश के आन्तरिक तथा विदेशी, दोनों ही व्यापारों पर एकाधिकार प्राप्त करने की नीति अपनायी। व्यापारिक रेगुलेशन्स मुद्राओं तथा अन्य कई प्रकार के मध्यमों को कम्पनी के लिए देश के आन्तरिक लोगों में निर्मित बाजार एकाधिकार करने का विशेषाधिकार देकर देशी व्यापारियों को उनके क्षेत्र समाप्त कर दिया गया। आन्तरिक देशी वैदेशी व्यापारिक आदि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत होने में घरेलू उद्योगों की कच्चे माल की पूर्ण घन-मन्दता आत्मसन्तुष्टता को पूर्ण तथा निर्मित वस्तुओं की विपणन-स्वरथा पूरी नहीं की जा सकी। उन मण्डल परिणामस्वरूप उद्योगों की चलाता कठिन हो गया।

(5) औद्योगिक क्रांति का प्रभाव - इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की मफ-मन्त भारतीय घरेलू उद्योगों की विफलता एवं जवनति पर निर्भर थी। ब्रिटिश सरकार ने अपन इस ग्रेट-ब्रिटेन में वज्जत उद्योगों को एक बोर तो भारतीय वस्तुओं के जायज पर 20 से 50 प्रतिशत तक आयात पर लगाकर संरक्षण प्रदान किया जिससे भारतीय निर्मित वस्तुओं का वहां आयात धीरे-धीरे कम या विस्तृत ही समाप्त कर दिया गया। दूसरी तरफ भारत में स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपना कर ब्रिटिश उद्योगों की निर्मित वस्तुओं में देशी बाजारों को भर दिया गया। मशीन-निर्मित वस्तुएं हाथों में बनी वस्तुओं में वही अधिक सस्ती थी। परिणामस्वरूप देश में विदेशी वस्तुओं की खपत अधिक होने लगी। देशी वस्तुओं की मांग कम हो जाने पर घरेलू उद्योगों को दनाथ रखना कठिन हो गया।

(6) विदेशी सरकार की व्यापार नीति - इंग्लैंड ने अपने व्यापार के विवाम के लिए तो स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनायी, परन्तु भारत को इसे अपनाते की छूट प्रदान नहीं की। औद्योगिक क्रांति की मफलता के लिए भारतीय बाजारों में ब्रिटिश मूल्य वस्तुओं को लेने के लिए व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को बाध्य होता

पटा, मयोनि इंग्लैंड में बना सूती माल दुल्ह-मुक्त था। सूती घस्त्र पर केवल 2½ प्रतिशत शुल्क ही था, जबकि भारतीय वस्तुओं पर इतना अधिक शुल्क लगाया गया कि वे वस्तुएँ विदेशी वस्तुओं की स्पर्धा में टिक न सकी। इसके साथ ही इंग्लैंड को निर्यातकों जाने वाली वस्तुओं पर वहाँ 40 से 60 प्रतिशत अघात शुल्क लगाया जाना था जिससे वहाँ भारतीय वस्तुओं का बाजार पूर्णतया समाप्त हो गया। इसके साथ ही भारतीय वस्तुओं पर अन्ध प्रचार के बच्चे भी लगाये जाते थे, जैसे पुन निर्माण में लायी गयी वस्तुओं पर स्थानीय कर, विदेशी जहाजों से लायी गयी वस्तुओं पर उत्पादन कर आदि। इसके विपरीत इंग्लैंड में भारत में आयात की गई वस्तुओं पर बहुत ही कम 3½ प्रतिशत भूस्वानुसार आयात शुल्क लगाया जाना था जो कि भारतीय वस्तुओं पर लगाये गये भूस्वानुसार कर (6 से 18 प्रतिशत) से बहुत ही कम था। यहाँ तक कि इंग्लैंड में आयात किये गये रेजमी माल पर 20 प्रतिशत अघात शुल्क लगाया गया।

(7) नये सम्राज का निर्माण अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ-साथ पुराने सामन्ती समाज का पतन होता गया। अंग्रेजों ने जमींदारों, व्यापारियों तथा प्रशासन के लिए जिन अधिकारियों के एक नए सम्राज का निर्माण किया, वे अंग्रेजी सरकार की नीति के समर्थक थे। उन्होंने अपनी साम्राजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के रहन-सहन को अपनाया तथा अपनी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। इसके अनिश्चित इस नये सम्राज की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह घरेलू उद्योगों की बहुमूल्य वस्तुओं को खरीद सके। इंग्लिश भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उन्होंने प्राचीन परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन बन्द कर दिया।

(8) यातायात तथा संचार-वाहन का विकास देश में तेजी से चलने का विस्तार गया रेलों का विकास, म्येज नहर का निर्माण तथा तार व डाक की सुविधाएँ उपलब्ध होने के बाद देश के भीतरी भागों में भी दूर-दूर तक विदेशी माल पहुँचाया गया। इससे भारतीय उद्योगों की निमित्त वस्तुओं की माँग घटान हो गयी। घरेलू उद्योग विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में कम मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सके थे कारण अधिक समय तक न टिक सके। रानाडे के अनुसार "इंग्लैंड के आधीन भारत के महान् राज्य ने उन्नीसवीं शताब्दी में प्राचीन उपनिवेशों का स्थान ले लिया। यह आधीन राज्य एक प्रकार से अंग्रेजों का वह कृपितोत्र है जहाँ कच्चा माल पैदा किया जाता है, जिसे अंग्रेज व्यापारी ब्रिटिश पूँजी और धर्म द्वारा निमित्त माल का रूप देने के लिए ब्रिटिश जहाजों द्वारा इंग्लैंड भेज देते हैं। वहाँ से फिर वही माल अंग्रेज व्यापारियों द्वारा इसी आधीन राज्य (भारत) में ब्रिटिश फर्मों के पास निर्यात कर दिया जाता है। आप-गमित तथा मशीनों के विकास

तथा यातायात की सुविधाओं ने मिलकर इस युग की उपर्युक्त प्रवृत्ति को और भी बल दिया। इसके परिणामस्वरूप यह महान् अधीन राज्य धीरे-धीरे कृषि-कार्य में अधिकाधिक प्रवृत्त होता गया और निम्न वस्तुओं के व्यवसाय का बड़ी तेजी से पतन स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने लगा।”

(9) अंग्रेजी राज्य की उपेक्षापूर्ण नीति : रानाडे के कुछ विचार से यह स्पष्ट है कि अंग्रेज शासकों ने भारतीय उद्योगों को जीवित रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को इंग्लैंड का एक ऐसा कृषि-प्रधान उपनिवेश बनाना था, जहाँ से उस देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल तथा लोगों के लिए खाद्यान्नों का निर्यात किया जा सके। यहाँ के उद्योगों में भी यदि नवीन यन्त्रों आदि के प्रयोग की सुविधायें दी जाती, तो शायद पुराने उद्योग पुन जीवित हो उठते।

(10) जन-साधारण की अवस्था : उन्नीसवीं शताब्दी में राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में इतनी तेजी से परिवर्तन हुए कि जन-साधारण भाग्यवादी बन गया। अत्याचार और अन्याय के कारण यहाँ के लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए अधिक दुःखी थे। साथ ही सफ़ाई काल में तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों तथा अपने परम्परागत जीवन के गम्भ मामूजस्य रखापत नही कर सके। परिणामस्वरूप वे कृषि पर अधिक ध्यान देने लगे।

(11) बड़े-बड़े उद्योगों का विकास : उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में भारतीय पूँजीपतियों ने बड़े बड़े उद्योगों के विकास की ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया। यद्यपि उनके पूर्ण उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के संरक्षण में काप्री पूँजी एकत्र की थी, फिर भी उन्होंने घरेलू उद्योगों की गिरती हुई दशा को सुधारने के प्रयत्न नहीं किये। कालान्तर में सूती-कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किये जाने के बाद हथ-करघों द्वारा निमित्त सूती वस्त्रों का घरेलू उद्योग धीरे-धीरे अवनति की प्रथम सीमा पर पहुँच गया।

उपर्युक्त कारणों से यह है कि सहको, रेलो, तार, स्वेज बहर का निर्माण तथा जल व शक्ति दोनों ही यातायात साधनों में प्रत्येक सुधार ने भारतीय कारीगरों की कठिनाइयों को केवल बढ़ाया ही नहीं बल्कि उन्हें बन्धन में पराजित भी कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने पूर्णतया देन के मोतरी भागों के बाजार तथा अंग्रेज व्यापारियों के पहुँचने की सुविधाओं के निर्माण पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया। एक ओर तो अंग्रेज उत्पादकों को भारतीय बाजारों का खोपण करने के लिए पूरी-पूरी सुविधायें दी गयी तथा, दूसरी ओर मेहनती कारीगरों को अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इस व्यवस्था से यह ज्ञात होता है कि भारतीय

घरेलू उद्योगों की ख़बरें जहाँ एक तरफ़ ब्रिटिश सरकार की समेकापूर्ण नीति के परिणामस्वरूप हुयी थी, वहीं दूसरी तरफ़ देश की कुछ आन्तरिक परिस्थितियों वा भी उनके विनाश पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। साहस, पूँजी का समुचित प्रयोग, बद-लती हुई परिस्थितियों में जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, विदेशी सम्पर्क से आधुनिक उत्पादन-विधियों के ज्ञान की प्राप्ति और इन सब में उपर स्वदेशी भावना वा अभाव होने से भारतीय परम्परागत उद्योग का पतन होना स्वाभाविक था।

उपयुक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि विदेशी सरकार की नीति प्रारम्भ से ही देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर एकाधिकार प्राप्त करने की थी। प्रारम्भ में पहले यहाँ के आन्तरिक व्यापार को अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। उद्योग-धन्धा की उत्पादन-व्यवस्था को स्वयं अपने हित में नियन्त्रित करने के बाद यहाँ के व्यापारियों के श्वेत-अस्तित्व को समाप्त कर दिया। बालान्तर में इसी धन में इंग्लैंड में बने घनी व्यवस्थित की पूँजी ने देश में प्रवेश किया और विदेशी पैररिया स्थापित की गयी। विदेशी पूँजीवाद की आधार डिलाए इस क्षेत्र में भी लगी जाने लगी। इस नवीन पूँजीवाद ने यहाँ के धर्मियों तथा बुनकरों का शोषण किया जिसके कलशवत्क न केवल यहाँ के उद्योग बल्कि समाप्त हो गये, बल्कि अभिमानकारी, दलकार एवं बुनार अपना पैतृक पेशा छोड़कर गावों में जाकर कुपकृषन गये। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति ने मृतप्राय उद्योगों की अन्तिम टेम पटुवायी और ममीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में ब्रिटिश सरकार की व्यापारिक नीति के कारण भारतीय घरेलू उद्योग ब टिक सके। साथ ही विदेशी सरकार की भारतीय उद्योगों के विनाश के सम्प्रत्य में अपनायी गयी औद्योगिक नीति देश के औद्योगिक विकास के लिए घातक सिद्ध हुई।

प्रश्न

1 "19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कृषि तथा भारतीय कुटीर उद्योगों का गठबन्धन समाप्त हो गया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कीजिए।

2 अन्तिम काट में परम्परागत भारतीय उद्योगों में भारतीय समृद्धि में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया था? इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

3 अंग्रेजों ने क्यों भारतीय उद्योगों को समाप्त करने की ओर विशेष ध्यान दिया?

4 "19वीं शताब्दी में भारतीय कुटीर उद्योगों की ख़बरों के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए।

5 पिछली शताब्दी में प्राचीन भारतीय औद्योगिक व्यवस्था के समाप्त होना का प्राचीन औद्योगिक विनाश पर क्या प्रभाव पड़ा?

रेल-नीति

(Railway Policy)

"The Indian people feel that this construction (of railways) is undertaken principally in the interests of commercial and moneyed classes and what it assists in the further exploitation of our resources"

—G K GOKHALE

भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को राजनैतिक दृष्टि से एक सूत्र में पिरोने की ओर ध्यान दिया। परन्तु यातायात तथा सदेशवाहन के साधनों के अभाव में इस उद्देश्य की पूर्ति सम्भव नहीं थी। इसके साथ ही देश के भीतरी भागों से कच्चा माल खाने तथा विदेशों निर्मित वस्तुएँ दूर दूर के बाजारों तक पहुँचाने के लिए भी तेज गति में चलने वाली रेलों का निर्माण करना आवश्यक समझा गया। वास्तव में रेलों के निर्माण के पहले न तो अग्रज भारतीय परम्परागत जीवन में पूर्णतया प्रवेश हो कर सके थे और न ही विदेश के बन्दे हुए बाजार से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हो सके थे।

उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही रेल निर्माण की व्यवस्था की गयी। रेलों का निर्माण हो जाने के बाद भारतीय मस्कृति, जीवन तथा अर्थ व्यवस्था पर उनका क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ा। विदेशी सरकार ने भी इस कार्य को विशेष महत्व इसलिए दिया था, क्योंकि उन्होंने यह कल्पना की थी कि रेलों का निर्माण व विकास होने के बाद भारत की सभी आर्थिक बुराईयाँ एवं कमियाँ स्वतः दूर हो जावेंगी।

रेल निर्माण का प्रारम्भ

(१) प्रारम्भिक अनुबन्ध—भारत में रेल-निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले सन् 1831-32 ई. में रखा गया था। उस समय यह विचार किया गया था कि

सर्वप्रथम रेलवे लाइन केवल मद्रास में ही निर्मित की जाय। परन्तु उस समय तक भाप-शक्ति का प्रयोग न किये जाने के कारण रेलें घोड़ों के द्वारा ही धीवी जा सकती थी। इसके पश्चात् सन् 1843 में भाप-शक्ति से चम्पने वाली रेलों के निर्माण की योजना इंग्लैंड में तैयार की-गयी। यद्यपि ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी के सचालकों (Directors) ने इस योजना का विरोध किया था, फिर भी निरन्तर आर्थिक तथा राजनैतिक दबाव पड़ने पर तथा अन्त में तत्कालीन गवर्नर जनरल, लॉर्ड हार्डिन्ग, की जोरदार सिफारिश पर रेल-निर्माण का प्रस्ताव उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद रेल निर्माण करने वाले प्रवर्तकों (Promoters) तथा कम्पनी के सचालकों ने रेल-निर्माण में लगायी गयी विजो पूँजी पर दिये जाने वाले ब्याज अथवा लाभांश (dividend) के सम्बन्ध में सरकारी गारन्टी के विषय पर काफी समय तक मतभेद बना रहा। अन्त में सन् 1849 ई. में यह मतभेद भी प्रवर्तकों के पक्ष में ही समाप्त हो गया। इसी वर्ष भारत-सचिव (Secretary of State for India) द्वारा रेल निर्माण के सम्बन्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) तथा ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे कम्पनी (Great India Peninsula Railway Company) के साथ किये गये समझौतों (Agreements) पर हस्ताक्षर किये गये। रेल-निर्माण के सम्बन्ध में किये गये ये पहले अनुबन्ध थे, जिनमें कुछ शर्तें निश्चित की गयी थी, जो निम्नलिखित हैं—

(1) रेल निर्माण एवं सचालन के कार्य निजी कम्पनियों द्वारा किये जायेंगे।

(2) रेलवे कम्पनियों को गृह्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रधान की जायेगी।

(3) कम्पनियों द्वारा एकत्र की गयी पूँजी पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी 99 वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज देगी। विदेशी कम्पनियों द्वारा लगायी जाने वाली पूँजी पर $4\frac{1}{2}$ से 5 प्रतिशत ब्याज की गारन्टी देगी।

(4) कम्पनी बिना मूल्य लिये 99 वर्षों के पट्टे पर भूमि देगी।

(5) इन अधिकारों के बदले में कम्पनी रेलों के व्यय एवं सचालन पर नियन्त्रण का अधिकार रखेगी।

(6) दोनों रेलवे कम्पनियाँ ठाक, माल तथा शुद्धीय सामग्रियाँ कम भाड़े पर ले जायेंगी।

(7) गारन्टी दिये गये ब्याज से अधिक जो अतिरिक्त लाभ होगा वह उस समय तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा रेलवे कम्पनियों के मध्य बाँटा जायेगा जब तक कि गारन्टी के आधार पर प्राप्त किये गये ऋणों का भुक्तान नहीं कर दिया जायेगा। इसके बाद समस्त लाभ पर रेलवे कम्पनियों का अधिकार होगा।

(8) 99 वर्षों के बाद सम्पूर्ण रेल-व्यवस्था भारत सरकार के अधिकार में चली जायेगी। उस समय मशीन व प्लेट तथा रोलिंग स्टॉक को छोड़कर अन्य किसी रेल-सम्पत्ति के लिए कोई मुआवजा (Compensation) नहीं दिया जायेगा।

(9) ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी प्रथम 25 अथवा 50 वर्षों के बाद पट्टे की अवधि समाप्त होने के पहले भी पू.जी.स्टॉक तथा अस्त्रों का मूल्य घुटा कर किसी भी कम्पनी से उसके रेल-संचालन-व्यवसाय को खरीद लेवेगी।

(10) रेलवे कम्पनियों को भी यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय 6 महीने का नोटिस देने के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपने अधिकारों को समर्पित करके अपनी वास्तविक विनिमोजित पू.जी. वापस माग सकेंगी।

(11) सन् 1853 ई० से सन् 1868 तक रेल-निर्माण—उपर्युक्त सभी शर्तें अगले 20 वर्षों में किये गये रेलवे निर्माण सम्बन्धी अनुबंधों का आधार बन गयी। परन्तु रेल-निर्माण सम्बन्धी नीति तथा समस्त विधि के सम्बन्ध में अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका। अन्त में, यह निश्चय किया गया कि ब्रिटिश पू.जी. की सहायता से भारत में रेलों का निर्माण ऐसी कम्पनियों द्वारा किया जाये, जिनका समावेशन (Incorporation) इंग्लैंड में किया गया हो। यह नीति लॉर्ड-डल्हौजी (Lord Dalhousie) द्वारा सन् 1853 ई. में निर्धारित की गयी थी। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि सबसे पहले चार मुख्य ट्रंक रेल लाइनों का निर्माण किया जाय जिससे सभी प्रेमोटेरियों को आपस में रेलों द्वारा जोड़ा जा सके। यह भाषा भी स्पष्ट की गयी कि इन ट्रंक लाइनों के बन जाने पर देश के द्विपि पदार्थों के निर्यात में काफी सुविधा होगी। फलस्वरूप रेल-निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और सन् 1869 ई. तक गारन्टी कम्पनियों द्वारा 4,255 मील लम्बी रेलवे लाइन का कार्य पूरा कर दिया गया। इस अवधि में गारन्टी किये गये ब्याज की दर 4½ से 5 प्रतिशत तक थी।

परन्तु सन् 1869 के पहले रेलवे-निर्माण कार्य अधिक महंगा तथा खर्चीला सिद्ध हुआ, क्योंकि 5 प्रतिशत ब्याज की गारन्टी मिल जाने के कारण रेलवे कम्पनियों ने रेलवे निर्माण कार्य में अधिकाधिक धन विनियोजित करना प्रारम्भ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रारम्भ से ही सरकार की गारन्टी के रूप में कम्पनियों को अधिक धन देना पड़ा। लॉर्ड डल्हौजी का अनुमान था कि प्रति मील रेलवे लाइन पर 8,000 पौ. व्यय होये, जबकि वास्तविक व्यय (भूमि की लागत छोड़कर) लगभग प्रति मील 18,000 पौ. के बराबर था। इस व्ययव्यय के कई कारण थे, जैसे कार्य प्रारम्भ करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ, कुशल यंत्रों का अभाव स्थानीय दलालों का शान न होना, अनुभव की कमी, चौड़ी लाइनों (ब्रॉडगेज Broad-gauge) का चुनाव, ऊँची निरम वा. निर्माण कार्य, अनावश्यक दुहरी लाइनें आदि।

परन्तु वास्तव में मुख्यतः गारन्टी की बड़ी अधिक रकम का मुगतान किये जाने के कारण ही अनुमान से अधिक धन व्यय हुआ था।

(ii) आरम्भ में ही अधिक धन व्यय हो जाने के कारण रेल निर्माण-कार्य की गति भीमी हो गयी। अतः सन् 1869 में गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस (Sir John Lawrence) ने यह सुझाव पेश किया कि वर्तमान पद्धति, जिसके अन्तर्गत पूरा लाभ लॉ कम्पनी को प्राप्त होता है और पूरी हानि सरकार को सहन करनी पड़ती है, समाप्त कर दी जाय। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नयी रेलों का निर्माण गारन्टी कम्पनियों के स्थान पर राज्य द्वारा ब्याज पर उधार लिये गये स्वयं अपना सरकार की आग में से कुछ धन निकालकर किया जाय। उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तथा सन् 1870 ई. से सन् 1880 ई. तक की अवधि में रेलों का निर्माण सरकार द्वारा किया गया। सन् 1880 तक सरकार ने 2,493 मील लम्बी रेल लाइनों का निर्माण कर लिया तथा कुल रेलवे लाइनों का विस्तार 8,494 मील तक हो इस अवधि में प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 2½ करोड़ रुपये ऋण के रूप में लेना पड़ा।

(iv) सन् 1884 में सन् 1905 तक—यद्यपि सरकार द्वारा रेल-निर्माण का खर्चोला था, फिर भी उसकी गति भीमी होने के कारण अग्रज व्यापारी, उद्योगपति तथा अधिकारी रेलवे-विवाम-कार्य से असन्तुष्ट नहीं थे। इसके साथ ही इस कार्य के लिए सरकारी आग का एक बहुत बड़ा भय भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। सन् 1880 ई. में "दुर्गति आयोग" (Famine Commission) ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्गति से बचने के लिए देश में 20,000 मील रेल लाइनों का होना आवश्यक है। अतः लॉर्ड रिपन ने सन् 1869 में ब्रह्मी नीति को पुनः संशोधित करने का सुझाव दिया। इस विचार करने के लिए सन् 1864 ई. में एक सदस्यीय प्रवर समिति (Parliamentary Select Committee) नियुक्त की गयी। इस समिति ने रेल मार्ग के तीव्र विस्तार पर जोर दिया और यह सुझाव दिया कि इस कार्य में दोनों ही संस्थानों—सरकार तथा निजी कम्पनियों-सेजी से काम करे। इस प्रकार पुनः गारन्टी पद्धति को अपनाया गया, यद्यपि इस बार इनकी शर्तों कुछ ठीक थी। ब्याज की दर घटाकर 3½ प्रतिशत कर दी गयी। साथ ही यह भी निश्चय किया कि प्रारम्भ से ही रेलों सरकार भी सम्पादित होंगी तथा सरकार को अतिरिक्त लाभ में 3/5 भाग मिलेगा। सरकार ने भी इस कार्य में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया, जिससे सन् 1884 ई. के बाद से रेल-निर्माण एवं विस्तार का काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। सन् 1905 की तीसरी जून तक 28,004 मील लम्बी रेल लाइनें बन चुकी थी जिनकी लागत 350 करोड़ रुपये थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में रेल-निर्माण की विशेषताएँ

उन्नीसवीं शताब्दी में रेल-निर्माण की विशेषताएँ अग्रलिखित थीं

(1) भारतीय पूँजी का अभाव—प्रारम्भ में रेलवे-निर्माण-कार्य में विदेशी (ब्रिटिश) पूँजी ही विनियोजित की गयी थी। भारतीय पूँजी का विनियोग नही के बराबर था।

(2) साहस का अभाव—रेलवे निर्माण एवं संचालन में जिस उपक्रम एवं साहस की आवश्यकता थी, उसका सर्वथा अभाव था। रेलवे पम्पनी के प्रवर्तक पूँजी-दाता सरकारी गारंटी के आवार पर ही इस कार्य का संचालन करने के लिए तैयार हुए थे। इसके अभाव में वे इस कार्य के लिए सरकार द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों में ही धन लगाने को तैयार थे।

(3) इन्तुसर्षी क्षतान्धों के अन्त तक हानि—पिछली क्षतान्धी के अन्त तक रेलवे से इतना लाभ भी नहीं हुआ था कि उसमें विनियोजित पूँजी पर दी गई जाने वाले ब्याज की भी व्यवस्था की जा सके। सन् 1900 ई. में पहली बार लाभ हुआ, परन्तु उस समय तक सरकार 76 करोड़ रुपये गारंटी दिये गये ब्याज के लिए दे चुकी थी।

(4) रेल-मार्ग का तीव्र गति से विकास—पिछली क्षतान्धी के अन्तिम वर्षों में रेल-मार्ग का विकास बहुत ही तेजी से किया गया था, यद्यपि इन वर्षों में सरकार को कई वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यह इस बात से स्पष्ट है कि जबकि सन् 1850 ई. से सन् 1891 ई. तक के 41-42 वर्षों में केवल 17,308 मील लम्बे रेल मार्गों का निर्माण किया गया, तब सन् 1892 ई. से सन् 1905 ई. तक के 14 वर्षों में ही 10,746 मील लम्बे रेल-मार्गों का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया।

रेल-निर्माण का आर्थिक प्रभाव

अग्नेय भासकों की दृष्टि से रेलों का भारतीय आर्थिक जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारम्भ से ही इस बात की केवल कल्पना ही नहीं की गयी थी, बल्कि यह विश्वास भी किया गया था कि रेलों के निर्माण से भारत की गरीबी गंवा यहा दार-वार पहले वाला अकाल को समाप्त किया जा सकेगा। सन् 1844 ई. में जॉन चैपमैन (John Chapman) ने सुझावों के विस्तार की अपेक्षा रेल-निर्माण पर विश्वास और दिया था। सन् 1884 ई. की रागरवीय श्रवर समिति (Parliamentary Select Committee) ने रेल विस्तार की जोरदार सिफारिश की थी। उसका यह विश्वास था कि रेल-विस्तार से दुग्धिस से सुरक्षा मिल सकेगी, आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा जा सकेगा, उपजाऊ क्षेत्रों तथा कोयले की खानों से कच्चा माल उठा कोयला प्राप्त करने में सुविधा होगी, लोको को रोजगार मिल सकेगा तथा उनके सामान्य आर्थिक जीवन में सुधार होगा। सन् 1896 ई. में जब समय के सर्वप्रथम जनरल ऑर्टे एल्गिन ने रेलों के आर्थिक महत्व के साथ-साथ उनके सामाजिक तथा राजनैतिक महत्व को भी ध्यान में रखने पर विशेष ध्यान दिया था।

उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि, "महान भारतीय रेल व्यवस्था आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा लोगों की राजनैतिक शान्ति को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठतम माध्यम बनायी जा सकती है।"

भारत में रेलों के विकास का प्रभाव अर्थ-व्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ा। इस विकास के कारण देश के कृषि-उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि मण्डियों का विकास हो जाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से सम्पर्क स्थापित हो जाने से कृषि की फसलों की अच्छी कीमत प्राप्त होने लगी। बंगाल में जूट, उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना, आसाम में चाय के बागानों का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ। इसके अतिरिक्त देश में कई उद्योगों का बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ, क्योंकि श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि हुई। कच्चा माल आसानी से प्राप्त होने लगा तथा सैदाय माल आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगा।

रेलों के विकास से देश में सिर्फ कृषि तथा उद्योगों का ही विकास नहीं हुआ, बल्कि रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि, आन्तरिक व्यापार में वृद्धि, अकाल मादि का सामना, कीमती से स्थिरता आदि पर भी रेलों के विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।

परन्तु रेल-व्यवस्था का वर्तमान उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना ही था। यदि उस समय भारतीय बरतू उद्योगों तथा अन्य उत्पादन श्रोतों का माप ही माप विकास किया जाता, तो सम्भवतः रेलवे-निर्माण एवं विस्तार से देश को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता। परन्तु रेलों द्वारा भारतीय दण्डे माल तथा खाद्यान्नों का निर्यात करके देश में न तो उद्योग-धन्धों को पनपने दिया गया और न ही दुर्भिक्ष को रोका गया। इसके अतिरिक्त रेलों के निर्माण पर जो अल्पविक्रय व्यय्यग हुआ, उसका भार भारतीय जनता पर ही भारी कर के रूप में पड़ा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विप्लवी शताब्दी में बातामात के साधनों में शान्ति के साथ-साथ औद्योगिक शान्ति, अर्थात् भारत में जोड़े व इस्पात तथा अन्य आधारभूत उद्योगों के विकास, की विद्या में सरकार द्वारा प्रयत्न न किये जाने के कारण देश की उसने आर्थिक प्रगति नहीं हुई जितनी की अंग्रेज प्रशासकों ने कल्पना की गयी थी। वास्तव में रेल-निर्माण से अंग्रेजों को ही लाभ हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार करना तथा पूँजी विनियोजित करने के अधिव स्रोत खुल गए।

प्रश्न

1. 19वीं शताब्दी में भारत में रेल-निर्माण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
2. विप्लवी शताब्दी में अंग्रेजों सरकार ने भारत में रेलों का निर्माण क्यों किया? कारणों पर प्रकाश डालिए तथा उसके आर्थिक लाभों का उल्लेख कीजिए।
3. रेलवे-निर्माण के सम्बन्ध में आप गांधीजी प्रथा से क्या समझते हैं। इसकी शर्तों का उल्लेख करते हुए उनके औचित्य पर विचार प्रकट कीजिए।

आर्थिक निकास

(Economic Drain)

"As the price of her rule in India, out of the revenues raised in India nearly one-fourth goes out of the country, and is added to the resources of England"

—Dadabhai Naoroji

यद्यपि भारत के आर्थिक शोषण अर्थात् भारतीय धन की निकासी (drain of wealth from India) के सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने सन् 1867 ई० में किया था, फिर भी यदि हम विषय पर गम्भीर रूप से विचार किया जाये तो यह ज्ञान होगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया सन् 1757 ई० से प्लासी के युद्ध के पश्चात् से ही प्रारम्भ हो गई थी। हा, यह अवश्य है कि उस समय धन की निकासी कम्पनी अधिकारियों द्वारा की गई थी। वह सम्पूर्ण कार्य न्यायसंगत नहीं था। इसीलिये वारेन हेमिंग्टन के विरुद्ध इंग्लैंड में महाभियोग (Impeachment) चलाया, क्लाइव को भर्त्सना की गई थी तथा अन्य कम्पनी अधिकारियों के इस प्रकार के आचरण पर भोम प्रकट किया गया था। परन्तु सन् 1857 ई० के बाद जब से भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बन गया, तब से अंग्रेजी राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत का आर्थिक शोषण किया गया। इसके विरुद्ध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रचार करना प्रारम्भ किया था। बाद में चल कर इन 'आर्थिक निकासी या शोषण' की चर्चित रानाडे, आर० सी० दत्त तथा अन्य राष्ट्रवादियों (Nationalists) ने भी कटु आलोचना की थी।²

इंग्लैंड द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को स्पष्ट करते हुए दादा भाई नौरोजी ने 2 मई, सन् 1867, को ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन, लन्दन, (East India

1. "The great railway system of India" could be made an all powerful agent in the promotion of the material and social advancement and political tranquility of the people"

Quoted by Bipan Chand

in "The Rise and growth of Economic Nationalism in India," p. 179.

Association, London) के समक्ष कहा था, "भारत में एकत्र की गयी आय का लगभग 1/4 भाग भारत में खर्च करने का मूल्य है जो देश से बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के मापनो में जोड़ दिया जाता है।" सन् 1872 ई० में जस्टिस रानाटे ने पूना में दिए गये अपने एक भाषण में कहा था, "भारतीय राष्ट्रीय आय का 1/3 से अधिक भाग किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा ले जाया जाता है।" (Of the national income of India more than one-third was taken away by the British in some form or other)। इस सम्बन्ध में सन् 1838 में मॉन्टगोमरी मार्टिन ने भी अपने रिपोर्ट में लिखा था, "इंग्लैंड से इस प्रकार (धन) की निरन्तर तथा बढती हुई निष्कासी में उसे भी निर्धन बना दिया होता, तब (यह कल्पना की जाती है कि) ऐसे भारत को उसके कितने बाँधों परित्याग भुगतने पड़ते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी दो से तीन पैसे के बराबर है।"¹

आर्थिक शोषण या धन-निकासी के रूप तथा उसकी गणना (Forms and Calculation of Economic Drain):

(i) आर्थिक शोषण या धन-निकासी के रूप : ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय आर्थिक शोषण का रूप यह था कि वह भारत में एकत्र किये गये राजस्व की आय (revenues) का एक भाग निकालकर अपने व्यापारिक कार्यों में विनियोजित कर देती थी। बाद में चल कर राष्ट्रवादियों ने भारत से इंग्लैंड का उस सभी धन एवं वस्तुओं के ऐसे स्थानान्तरण को धन-निकासी या आर्थिक शोषण का ही रूप माना, जिसके बदले में भारत को किसी प्रकार का आर्थिक, व्यापारिक तथा मन के रूप में प्रत्येक लाभ प्राप्त नहीं होता था। इससे यह स्पष्ट है कि आयात पर निर्भरता का आधिरस्य (excess of exports over imports), आर्थिक शोषण का ही एक अन्य रूप था। धन-निकासी के अन्य स्रोत निम्नलिखित थे,

- (1) कम्पनी की आय का अधिकांश भाग विदेशी व्यापार में विनियोग,
- (2) कम्पनी के असधारियों को भारत में विनियोजित विदेशी पूँजी पर दिया गया लाभान्न,
- (3) भारत पर सार्वजनिक ऋण (Public Debt),
- (4) भारत में काम करने वाले अंग्रेज अधिकारियों की आय के एक भाग का इंग्लैंड को स्थानान्तरण,

1. 'So constant and accumulating a drain even on England would have impoverished her how severe then must be its effects on India, where the wages of labourer is from two pence to three pence a day.'

(5) भारत में बमूल किये गये राजस्व का अधिकांश भाग प्रशासन, सुरक्षा, रेल-व्यवस्था आदि पर व्यय;

(6) 'घृह ध्यय' (Home Charges) जो भारत-सचिव (Secretary of State for India) द्वारा भारत के लिए इंग्लैंड में किये जाते थे। इन खर्चों में निम्नलिखित मदें शामिल थी :

(i) भारतीय सार्वजनिक वित्त पर तथा भारतीय रेलवे कम्पनी को दिया गया ब्याज,

(ii) भारत को भेजी गई युद्ध-सम्पत्ती तथा अन्य प्रकार की सामग्रियों की लागत,

(iii) प्रशासन तथा युद्ध-सम्पत्ती व्यय जिनका भुगतान भारत के लिए इंग्लैंड में किया जाता था, जैसे भारत सचिव के कार्यालय का प्रशासन-व्यय तथा ऐसे यूरोपीय अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन व भत्तों की रकम, जो पहले भारत में काम कर चुके थे।

(7) भारत में विनिवेशित विदेशी निजी पूँजी पर उपाधिक लाभ।

(ii) धन-निकासी या वार्षिक शोषण की मात्रा

सन् 1814-15 ई० में 3,446,016 पौ० के बराबर घनराशि भारत से बाहर गई थी। सन् 1857 ई० में यह बढ़ कर 6,162,043 पौ० के बराबर पहुँच गयी थी। कम्पनी शासन के अन्तिम 24 वर्षों में (सन् 1834-35 से सन् 1857-58 ई० तक) कुल कर या धन-निकासी (tribute) की रकम जो भारत से इंग्लैंड को भेजी गयी थी 151,830,989 पौ० के बराबर थी। इस प्रकार इस अवधि में कुल वसूल की गयी मालबुजारी का आधा भाग इंग्लैंड भेज दिया गया। दादा भाई नौरोजी के अनुसार धन-निकासी के निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं -

धन-निकासी

वर्ष	वार्षिक औसत पौ० £ में
1835 से 1839 तक	5,347,000
1840 से 1844 तक	5,930,000
1845 से 1849 तक	7,607,000
1850 से 1854 तक	7,458,000
1855 से 1859 तक	7,730,000
1860 से 1864 तक	17,300,000
1865 से 1869 तक	24,600,000
1870 से 1872 तक	27,400,000

सन् 1893 ई० में 25 करोड़ रुपये से अधिक धन की निकासी हुयी थी तथा सन् 1897 तक के जिल्हे दस वर्षों (सन् 1883 ई० से सन् 1892 ई० तक) में लगभग 359 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय वाचन में सन् 1901 ई० में डी० ई० वाचा (D E Wacha) ने बताया था कि आर्थिक धन निकासी लगभग 30 से 40 करोड़ रुपये तक होती रही है।

आर्थिक शोषण के आर्थिक परिणाम

भार० सो० दल ने इस बड़े पैमाने पर भारतीय धन की निकासी के आर्थिक परिणामों के विषय में लिखा है "जब किसी देश से कर वसूल करके वही व्यय किये जाते हैं तब इससे लोगों के मध्य ही चलन में रहता है, व्यापार, उद्योग तथा कृषि को फलमयी बनाता है तथा इस प्रकार किसी न किसी रूप में लोगों के पास पहुंच जाता है। परन्तु जब किसी देश में वसूल किये गये कर की रकम किसी दूसरे देश में भेज दी जाती है तो वह रकम उस देश के लिए हमेशा के लिए खूब जाती है, वह उसके व्यापार या उद्योगों का नहीं बढ़ाती, या लोगों के पास किसी भी रूप में नहीं पहुंच जाती।"¹ इस कथन से यह स्पष्ट है कि यदि भारत में वसूल किये गये करों की रकम अथवा सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय भारत के आर्थिक विकास तथा उद्योग-धंधों को विकसित करने में व्यय की जाती तो सम्भवतः भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का विकास कब का हो गया होता। इस प्रकार औद्योगिक विकास से देश में लोगों को रोजगार मिलता तथा देश की गरीबी मिट जाती। परन्तु विदेशी दासकों ने केवल भारत के शासन का मसदा ही लिया, उनके बदले में भारत के उद्योगों, व्यापार आदि का विकास नहीं किया। न ही उस धन का प्रयोग लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही किया गया।

इस प्रकार के आर्थिक शोषण से भारत की उत्पादक पूंजी (Productive Capital) धीरे-धीरे कम होती गयी। धन निकासी के कारण ही देश में लोगों के पास पूंजी-संचय सम्भव नहीं हो सका। पूंजी-संचय न होने से ही देश में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकी। इसके साथ ही इसी कारण से देश में न तो पूंजी-निर्माण ही तथा और न ही देश का औद्योगिक विकास सम्भव हो सका। आर्थिक-निकासी से वह हालत यही तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इंग्लैंड ने भारत पर

1 For when taxes are raised and spent in a country the money circulates among the people, franchises trade, industries and agriculture and in one shape or another, reaches the mass of the people. But when the taxes raised in a country are remitted out of it, the money is lost to the country for ever it does not stimulate her trade or industries or reach the people in any form."

सांकेतिक ऋण का भार भी लद दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह ऋण की मात्रा बहुत ही अधिकतम व्याज की दर पर इंग्लैंड पहुँचा दिया गया।

भारत से इस आर्थिक निकासी का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में विकास के कार्यक्रमों में जोर पकड़ा, तथा इंग्लैंड विश्व के सम्पूर्ण राष्ट्रों में गिना जाने लगा और भारतीय अर्थ-व्यवस्था जो कि 'मोन की चिड़िया' के नाम से जानी जाती थी, आर्थिक विकास में बहुत ही पीछे रह गयी।

प्रश्न

1 आर्थिक शोषण या भारत से धन की निकासी से आप क्या समझते हैं ? उसके विभिन्न रूपों तथा 19 वीं शताब्दी में उसकी कुछ अनुमानित रकम का उल्लेख कीजिए।

2 आर्थिक शोषण का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था ?

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत की आर्थिक निष्क्रियता

(India's Economic Stagnation Before Independence)

"Development concerns not only man's material needs but also the improvement of the social conditions of his life. Development is, therefore, not only economic growth but growth plus change, Social, cultural and institutional as well as economic"

—U N O.

भारत सन् 1947 में स्वतन्त्र हुआ। उसके पूर्व यहाँ पर अंग्रेजी राज्य था। प्रभुसत्तात्मक ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारत की अपना एक महत्वपूर्ण कृषि-प्रधान उपनिवेश ही माना था। यहाँ की अर्थ-व्यवस्था उपनिवेशीय अर्थ व्यवस्था (colonial economy) के रूप में ही विकसित की गयी थी। अतः यह स्वाभाविक था कि यहाँ का आर्थिक विकास गतिशील (dynamic) न होकर निष्क्रिय ही रहा। ब्रिटिश सरकार ने भारत की अपने आधिपत्य में लेने के बाद यहाँ की परम्परागत अर्थ-व्यवस्था (traditional economy) को बनाये रखने का ही निरन्तर प्रयास किया था। 19वीं शताब्दी के अन्त में अथवा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो बड़े-बड़े उद्योग स्थापित भी किये गये, वे बुनियादी उद्योग (basic or key industries) नहीं थे। परम्परागत भारत में स्वतन्त्रता के पूर्व आधुनिक तरीके पर औद्योगिक विकास का बीजा तैयार नहीं किया जा सका, जिससे भारत एक अविबसित तथा पिछड़ा हुआ देश माना जाता रहा।

स्वतन्त्रता के पूर्व आर्थिक निष्क्रियता के कारण :

किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था के गतिशील होने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी परम्पराओं को छोड़कर नयी दिशा की ओर जाने लगे। सर्वत्र कृषि पर आधारित अर्थ-व्यवस्था अविकसित देश का प्रतीक है। उसके विकास के द्वारा जब औद्योगिक युग में प्रवेश करने के लिए एक मजबूत आधार-शिला तैयार कर ली

जाती है, तब देश आगे बढ़ने व ऊँचा उठने की स्थिति (take off stage) में आ पाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले उन विदेशी सरकार ने न तो विद्युत् हूए कृषि-उद्योग को सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किया और न ही औद्योगिक विकास का बुनियादी ढांचा ही तैयार किया। वास्तव में वे दोनों कार्य किसी देश की राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही पूरे किये जा सकते हैं। अतः सन् 1947 के पूर्व परन्तु भारत में आर्थिक निष्प्रियता के कारणों का जानना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं—

(1) भारत का परतन्त्र होना—विदेशी सरकार ने प्रारम्भ से भारत का आर्थिक शोषण किया था। यहाँ के व्यापार, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था सभी का विकास इंग्लैंड की अर्थ-व्यवस्था के विभाग तथा अंग्रेजों के हित के लिए ही किया गया। आर्थिक शोषण होने से देश में निरन्तर पूँजी का अभाव बना रहा। विदेशी सरकार की नीति यहाँ पर अंग्रेजी राज्य की प्रमुखा को बनाये रखने की ही रही थी। अतः देश आधुनिक औद्योगिकवाद (modera industrialism) की ओर अप्रसर नहीं हो सका, जिससे केवल कृषि पर ही आधारित अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़ सकी।

(2) परम्परागत अर्थ व्यवस्था—विदेशी सरकार ने इंग्लैंड से औद्योगिक जाति के पश्चात् अपन उद्योगों के लिए अच्छे माल तथा जनता के लिए साधनों की पूर्ति करने के लिए भारतवर्ष की अर्थ व्यवस्था को कृषि पर ही आधारित रखा। परन्तु कृषि के विकास के लिए जिस पैमाने पर मिर्चाई व्यवस्था तथा आधुनिक यंत्रों की आवश्यकता थी, उस पैमाने पर इनकी पूर्ति नहीं की गई। परिणामस्वरूप भारतीय कृषि एक गान्धूनी जुआ बनी रही। स्वयं निष्प्रेषण रहने पर वह औद्योगिक विकास में आवश्यक सहायक प्रदान नहीं कर सकी।

(3) बढ़ती हुई जनसंख्या—भारतवर्ष की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती ही रही है। जनसंख्या में वृद्धि होने से उमरा मार भूमि पर ही पड़ा है। उद्योग-धन्धों का क्षेत्र सीमित होने से 70-80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही जीविका के लिए निर्भर रही है। फलस्वरूप कृषि-उत्पादन के कम होने से लोगों का जीवन-स्तर नीचे गिरना स्वाभाविक है। भारत स्वतन्त्र होने के पहले तक कृषि प्रधान देश ही रहा। परन्तु आवश्यक सुधार नहीं किये जाने से कृषि अविकसित रही जिससे वह बढ़ती हुई जनसंख्या को आवश्यकताओं को पूरा न कर सकी। यही कारण है कि अधिकांश भारतीय जनता के जीवन-स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ।

(4) संस्थागत दोष (Institutional Defects)—अंग्रेजों का शासनकाल भारतीय परम्परागत जीवन का गतिहीन एवं निष्क्रिय ऐतिहासिक काल कहा जा सकता है। सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों में उलझा हुआ समाज अधिक भाग्यवादी हो चुका था। दूसरी ओर, विदेशी सरकार ने भारत में जिस पूँजीवादी व्यवस्था की विकसित किया था, उसने कृषि एवं औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों (किसानों

तथा श्रमिकों) का जोषण ही किया था। ब्रिटिश पूँजी, व्यापार तथा उद्योग-धन्धों ने भारत के आर्थिक विकास पर कम ध्यान दिया था। प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली (Managing Agency System) ने सदैव पूँजीपतियों के हितों को ही ध्यान में रखा जाता था। बैंकिंग, बीमा आदि व्यवसायों का दृष्टिकोण भी अंग्रेजों सरकार के हितों की रक्षा करना ही रहा था, जिस कारण भारतीय पूँजी का विनियोजन भी देश के आर्थिक विकास में नहीं किया जा सका।

(5) शिक्षा तथा अज्ञानता—विदेशी सरकार ने सुरक्षा, आन्तरिक शांति तथा सरकार की शक्ति को सुदृढ़ बनाये रखने की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज में एक ऐसे वर्ग को तैयार किया गया जो प्रशासन संबंधी कार्य करन में समर्थ हो सके। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का उतना प्रसार नहीं किया गया था जितना कि देश के लिए आवश्यक था। इस प्रकार शिक्षा का समुचित विकास न होने से देश अज्ञानता के अवचरण में डूबा रहा। परिणामस्वरूप विदेशों की तरह यहाँ आधुनिक उद्योग-धन्धे स्थापित नहीं किये जा सके।

(6) श्रमिकों की अकुशलता—श्रमिकों के अभिक्षित होने के कारण ही उनकी उत्पादकता में कृत्रिमता नहीं हुई। इसका यह परिणाम हुआ कि उनके जीवन-स्तर में सुधार नहीं हुआ। श्रमिकों को प्रशिक्षित भी नहीं किया गया। केवल उनका शोषण ही किया गया। फलस्वरूप उद्योग-धन्धों की अपेक्षा कृषि पर निर्भर रहना ही लोग पसन्द करते थे। ✓

(7) लघु तथा घरेलू उद्योग-धन्धों का अतिक्रान्त होना—विदेशी सरकार ने कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उसकी नीति का दमस्वरूपत उद्योगों की समाप्ति करने की ही थी। भारतीय पूँजीपतियों ने भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापित करने की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। बड़े उद्योग भी केवल कच्ची-वस्त्रों तथा जूट की वस्तुओं के उत्पादन के लिए स्थापित किये गये थे। फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या हमेशा बनी ही रही।

(8) विदेशी सरकार की नीति—विदेशी सरकार की प्रारम्भ से ही यह नीति रही थी कि भारत की सामान्य अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाय। इस उद्देश्य से ही विदेशी पूँजी ने अर्थ-व्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर रखा था। बड़े-बड़े उद्योगों पर ब्रिटिश पूँजीपतियों का ही अधिकार था। बड़े पैमाने पर स्थापित किये गये अन्य उद्योगों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। इसके साथ भारतीय उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक पूँजी, वच्चा भात, तकनीकी सहायता, मशीन, बल न पुर्जों आदि की सुविधाएँ अंग्रेज पूँजीपतियों के

सहयोग तथा नये उद्योगों के प्रवर्तन एवं संचालन पर उनका एकाधिकार देने पर ही प्राप्त की जा सकती थी।

(9) तट-रक्ष नीति—सरकार की तट-रक्ष नीति भी देश के औद्योगिक विकास के लिए घातक रही है। अंग्रेजी सरकार ने औद्योगिक कमीशन-1918 तथा राज-वित्तीय आयोग (Fiscal Commission)-1921 की रिपोर्टों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। विभेदात्मक संरक्षण नीति (Discriminating Protection Policy) तथा साम्राज्य-पद्धति प्रियायती नीति (Imperial Preference) के कारण पूर्ण रूप से औद्योगिक विकास नहीं किया जा सका। आयात में निरन्तर वृद्धि के कारण सूती-वस्त्र तथा लौह व इस्पात उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे देश में औद्योगिक विकास की गति धीमी पड़ गई।

(10) देश में असंतुलित औद्योगिक विकास—प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश का औद्योगिक विकास असंतुलित रहा है। यहाँ केवल उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन पर ही विशेष ध्यान दिया गया था। यहाँ तक कि रेल-निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद भी लौह व इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयत्न नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त विश्व-युद्धों की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर तो सरकार विशेष ध्यान देती थी, परन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद वह पुनः अपनी पुर्तनी नीति, उद्योगों का विकास न होने देने (de-industrialisation) की नीति को प्रयोग में लाती थी। यही कारण है कि द्वितीय विश्व-युद्ध के काल में भी देश में राष्ट्रीय औद्योगिकी को आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ था। अमेरिकन टेक्नीकल मिशन ने वर्मवर्ड के जहाजी घराने के कारखाने के नामों का निरीक्षण करने पर यह पाया था कि वहाँ घोड़ी की नाव, कौड़ी नावों के लिए छोटे की टिनो तथा रेडों के लिए 'स्विचगियर' बनाने का काम होता था। 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ नैटिविटी' ने भी सन् 1945 में अपने एक लेख में यह प्रकाशित किया था कि "हम लोग सभी कुछ, परन्तु कुछ नहीं, तैयार कर सकते थे। हम लोग प्रत्येक वस्तु तथा किसी भी वस्तु की पूर्ति करने वाले, इस पृथ्वी की सभी वस्तुओं के ठीक करने वाले तथा मरम्मत करने वाले थे, परन्तु किसी भी वस्तु के बनाने वाले नहीं थे। हम लोगों की कोई उत्पादन-व्यवस्था नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। इसके विपरीत केवल एक योजना स्पष्ट तथा पूर्ण यह थी कि युद्ध के पश्चात् देश के औद्योगिकीकरण को रोकना जाय।"¹

1. "We could make everything and yet nothing. We were just suppliers of anything and everything, makers, repairers of all things on earth, but the makers of none. We had no system, no plan. Rather there was a plan clear-cut and through to prevent the industrialisation of the country in the post-war period."

—*Eastern Economist*, Aug 31, 1945

उपयुक्त कारणों के परिणामस्वरूप ही भारत के स्वतन्त्र होने के बाद राष्ट्रीय सरकार को विरासत में ऐसी अर्थ-व्यवस्था मिली जो अनेक बीमारियों से पीड़ित थी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति ही उसका एकमात्र उपचार नहीं था। उसको ठीक करने के लिए उसकी मृतप्राय शिराओं में नवजीवन डालना था। औद्योगीकरण, पूंजी-निर्माण, विज्ञान तथा टेक्नालॉजी का प्रयोग, संस्थागत पुनर्निर्माण, वित्तीय सुविधायें, भारतीय उद्योगों को विदेशी स्पर्धा से संरक्षण आदि को कुछ ऐसी पूर्वगामी आवश्यकताएँ थीं जिनके लिए राष्ट्रीय सरकार को प्रयत्न करना था। इन आवश्यकताओं की पूर्ति एक योजनाबद्ध तरीके से हो की जा सकती थी। अतः देश ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के आर्थिक एवं सामाजिक नव-निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।

प्रश्न

1. स्वतन्त्रता के पूर्व भारतीय अर्थ-व्यवस्था क्या बान्धव में अविनसित थी ? इस सम्बन्ध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए।
2. परन्तु भारत में आर्थिक स्थिरता के कारणों पर प्रकाश डालिए।
3. "भारत में जब तक अंग्रेजी राज्य रहा, उमन इस देश के आधुनिक उद्योगों के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
4. भारत की आर्थिक स्थिरता में भारतीय पूंजीपतियों तथा परम्परागत जीवन-मन्यता का कहा तक दोष रहा है ?

द्वितीय खण्ड

1. भारत में जनसंख्या

Population of India

2. भारत में बेरोजगारी की समस्या

Problems of Un-employment of India

भारत में जनसंख्या

(Population in India)

"The rapid increase of population in our country is one of the most disquieting problems with which we are faced. Despite the wide popularity and efficient organisation of the Family Planning Programme, the population continues to grow at an alarming rate, thus striking at the very roots of planned development."

—S Radhakrishnan

निम्नी मो दस के आर्थिक विकास मे बढा की जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस देश में अनुबूल जनसंख्या तथा ओसो में दस को समृद्धशाली बनाने की भावना पाई जाती है, वह देश निश्चय ही पग-पग पर सफलता प्राप्त करता जाता है। इसके विपरीत जिन देशों की जनसंख्या उनके माधनों के अनुसूप नहीं है, अर्थात् कम या ज्यादा है, वे देश प्रायः पिछड़े रह जाते हैं। भारतवर्ष एक ऐसा ही देश है जहाँ जनसंख्या साधनों की तुलना में बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या की इस वृद्धि के कारण देश के आर्थिक विकास को धक्का लगता है। देश को यह बड़ी हुई जनसंख्या हमारे लिए अभिघात बनी हुई है। इस बड़ी हुई जनसंख्या के कारण ही आज कई अन्य आर्थिक समस्याएँ भी हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं, जैसे—खाद्य की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, निवास की समस्या, पिछड़ेपन को दूर करने की समस्या आदि। जब तक हमारे देश में जनसंख्या की समस्या का समाधान उचित तरीके से नहीं कर लिया जाता, तब तक हम इससे सम्बंधित लगभग समस्याओं को भी हल नहीं कर सकते। सब तो यह है कि हमारे पंचवर्षीय आयोजन उसी समय सफल हो सकते हैं जबकि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रभावशाली रोक लगाने में सफल हो जायेंगे।

जनसंख्या वृद्धि का इतिहास

भारतवर्ष की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। आज भारत के पास कुल विश्व के भू-क्षेत्र का 2.4% भाग है, किन्तु उसे विश्व की कुल जनसंख्या के 15% भाग का भरण-पोषण करना पड़ रहा है। सन् 1881 ई० में भारतवर्ष में

पहली बार जनगणना हुई थी। उस समय भारत की जनसंख्या 25.4 करोड़ थी। सन् 1921 ई० तक जनगणना की गति कुछ-कुछ धीमी थी। सन् 1921 ई० के महाविभाजन के वर्ष तक भारत की जनसंख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उसके पश्चात् जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

भारत में जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या का वर्ष	जनसंख्या (करोड़ों में)	दश वार्षिक वृद्धि या कमी (करोड़ों में)	दशक में प्रतिशत वृद्धि या कमी
1901	23.6	—	—
1911	25.2	+1.6	+5.73
1921	25.1	—0.1	—0.31
महाविभाजनका वर्ष			
1931	27.9	+2.8	+11.01
1941	31.9	+4.0	+14.22
1951	36.1	+4.2	+13.31
1961	43.9	+7.8	+21.50
1971	54.7	+10.8	+24.06

उक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में सन् 1921 ई० तक जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं थी। इसके अतिरिक्त इन वर्षों में वृद्धि की दर भी कोई विशेष ऊँची नहीं थी। दरन् दर देशों की तुलना में काफी कम थी। सन् 1919 ई० में अफेले इन्फ्लूएन्जा महामारी में ही 2 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 1921 से पूर्व भारत जनसंख्या परिवर्तन (demographic transition) की पहली अवस्था में था। लेकिन इसके बाद यह जनसंख्या बिस्फोट की दूसरी अवस्था में पहुँच गया। इसी कारण 1921 ई० वर्ष को महाविभाजन का वर्ष करते हैं।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ से जन्म दर तथा मृत्यु दर के अध्ययन में यह बात स्पष्ट हो पायी है। सन् 1901 ई० से सन् 1921 ई० तक जन्म दर 46 से 49 प्रति हजार के बीच थी और मृत्यु दर 41 से 48 प्रति हजार के बीच थी। लेकिन सन् 1921 से सन् 1961 तक जन्म दर तो प्रायः स्थिर हो रही लेकिन मृत्यु दर में काफी कमी आ गई। मृत्यु दर जो 1911-21 में 48.6 प्रति हजार थी वह सन् 1961-66 में केवल 17.2 रह गई। 1969 में जन्म दर प्रति हजार 39 रह गई है। 1973-74 तक यदि परिवार नियोजन सम्बन्धी सभी कार्यक्रम योजनानुसार सफल होते रहे तो जन्म दर प्रति हजार 32 तक हो जाने की सम्भावना है।

1 अप्रैल 1971 ई० की जनसंख्या 54.7 करोड़ थी। पिछले दशक में अर्थात् 1961 व 1971 के बीच जनसंख्या 10.79 करोड़ बढ़ी है। इस तरह पिछले दशक में जनसंख्या में 24.57 प्रतिशत वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में, जनसंख्या की वृद्धि दर विगत दशक में 2.46 प्रतिशत रही। भारतवर्ष में प्रत्येक डेढ़ सेन्टिड में एक संख्या पैदा होता है।

जनसंख्या का घनत्व (Density of Population) :

जनसंख्या के घनत्व से हमारा तात्पर्य किसी देश में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले निवासियों की संख्या से है। यदि किसी देश की कुल जनसंख्या को वहाँ के क्षेत्रफल से विभाजित कर दिया जाय तो वहाँ की जनसंख्या का घनत्व मालूम हो जाता है। सन् 1971 में भारत की जनसंख्या का घनत्व 182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या का वितरण विभिन्न राज्यों में समान नहीं है। एक ओर तो बहुत बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्र, दूसरी ओर आसाम व जम्मू कश्मीर राज्य हैं, जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों की स्थिति इस प्रकार है —

भारत में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का घनत्व (1971 में)

राज्य	जनसंख्या का घनत्व	राज्य	जनसंख्या का घनत्व
दिल्ली	2723	मान्य प्रदेश	157
केरल	548	मैसूर	153
पश्चिमी बंगाल	507	असम	150
बिहार	324	उड़ीसा	141
तामिलनाडू	316	गुजरात	136
उत्तर प्रदेश	300	मध्य प्रदेश	94
पंजाब	268	राजस्थान	75
हरियाणा	225	हिमाचल प्रदेश	62
महाराष्ट्र	164	नागालैण्ड	31

भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या के औसत घनत्व में भी वृद्धि होती आ रही है। यदि हम भारत की जनसंख्या के घनत्व की तुलना अन्य देशों से करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों में आचार पर भारत का स्थान मध्यम जन-घनत्व वाले देशों में आता है। भारत की स्थिति न तो जापान, दमस्कंद, व जर्मनी जितनी मुश्किल है जिनका घनत्व सन् 1968 में क्रमशः 273, 227, व 243 था और न ही अमेरिका, रूस या कनाडा जितनी अच्छी है जिनका घनत्व क्रमशः 21, 11 व 2 था।

जनसंख्या के घनत्व में प्रन्तर के कारण :

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष के विभिन्न भागों में जनसंख्या का घनत्व समान नहीं है। इस भिन्नता के कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं —

1. प्राकृतिक दशा . सामान्यतः पहाड़ी और पठारी भागों में जीवन-यापन अपेक्षाकृत कठिन होता है। पर्वस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व मैदानों की अपेक्षा कम होता है।

2 जनबाधु सामान्यतः जिन क्षेत्रों का जलवायु स्वास्थ्य-वर्द्धक होता है तथा कृषि व उद्योगों के अनुकूल होता है, वहां अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। लोग साधारणतया अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में ही रहना पसन्द करते हैं।

3 वर्षा जनसंख्या का घनत्व वर्षा की मात्रा पर भी निर्भर करता है। उचित समय और उचित मात्रा में वर्षा आने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों का आर्थिक विकास काफी तीव्र गति से हो जाता है।

4 सिंचाई की सुविधाएँ वर्षा के अभाव में भी यदि किसी क्षेत्र विशेष में सिंचाई की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध हैं तो ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होगा। उदाहरणार्थ, पंजाब का घनत्व बहुत कुछ सिंचाई की सुविधाओं के कारण ही अधिक है।

5 भूमि की उर्वरता जिन क्षेत्रों की जमीन अधिक उपजाऊ होती है, उन क्षेत्रों में कम उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों से अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। यही कारण है कि उत्तर का गंगा-सतलज का मैदान बहुत घना बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जबकि राजस्थान में मरुभूमि होने के कारण कम जनसंख्या निवास करती है।

6 औद्योगिक उन्नति औद्योगिक दृष्टि से विवर्धित क्षेत्रों में लोगों को भरण-पोषण के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में अधिक लोग रहने लगते हैं।

7 सुरक्षा एवं शान्ति जो स्थान सीमाओं में दूर एवं सुरक्षित है, जहाँ धन माल को कोई खतरा नहीं है तथा जहाँ शान्तिमय जीवन बिताया जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों में प्रायः अधिक लोग बस जाया करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी और अपने व्यवसाय की सुरक्षा प्रिय होती है।

8 परिवहन की सुविधा परिवहन की सुविधा वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या

अपेक्षाकृत अधिक निवास करती है, क्योंकि ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से सामान्यतः उन्नतिशील होते हैं।

9 खनिज सम्पत्ति की उपलब्धि बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है, जहाँ खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रों में खानों में काम करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है और लोग सुविधा पाकर दूरी क्षेत्रों में बस जाते हैं।

10 राज्य की राजधानी राज्य की राजधानी राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र होती है, फलस्वरूप बड़ा जनसंख्या का घनत्व शहरों की अपेक्षा अधिक होता है।

11 औद्योगिक क्षेत्र वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद आदि शहरों में जनसंख्या का घनत्व इसलिए अधिक है कि भिक्षण केन्द्र होने के कारण वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं।

12 धार्मिक कारण हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, अजमेर आदि कुछ धार्मिक शहरों का घनत्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि धार्मिक जनता प्रायः ऐसे स्थानों पर बसना पसन्द करती है।

13 आवास-प्रवास राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक या धार्मिक कारणों से जब जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवास प्रवास होता है, तब जिन क्षेत्रों में आवास होता है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है तथा जिन क्षेत्रों से प्रवास होता है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है।

क्या भारतवर्ष में जनसांख्यिक है ?

भारतवर्ष में जनसांख्यिक है या नहीं, इस संबंध में दो विरोधी विचारधाराएँ पाई जाती हैं। कुछ विद्वान् भारतवर्ष में जनसांख्यिक की स्थिति का स्वीकार करते हैं तथा देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने का जोरदार समर्थन करते हैं। इसके विपरीत वहाँ में कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जिनका मत है कि भारत में जनसंख्या अधिक नहीं है। यही नहीं, उनका यह भी मत है कि अगर जनसंख्या और भी बढ़ जाय तो भी भारत उस बड़ी हुई जनसंख्या के शरण पीषण में समर्थ है। सही वस्तु स्थिति जानने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों का संक्षेप में विवेचन करना आवश्यक है। ये दृष्टिकोण हैं —

(क) आवासादी दृष्टिकोण प्रायः वे लोग अपने मत की पुष्टि के लिए अनुकूलतम जनसंख्या विद्वान् की शरण लेते हैं तथा इनका कहना है कि यदि देश में प्राकृतिक साधनों का सम्पूर्ण शोषण किया जाय तो जनसंख्या का भार श्रवण महसूस

नही होगा जितना कि अन्न महसूस होता है। आशानादी दृष्टिकोण रखने वाले विचारकों ने निम्नलिखित तर्क दिये हैं —

1. प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त हमें यह बताता है कि यदि देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, तो जनसंख्या नहीं होगी। भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सन् 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66, 1967-68 में क्रमशः प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 247 5, 267 8, 293 2, 302 7 तथा 323 3 रुपये थी। चूँकि राष्ट्रीय आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसलिए जनसंख्या नहीं माना जा सकता।

2 प्रचुर प्राकृतिक साधन भारतवर्ष में प्राकृतिक साधनों के अतुल भंडार भरे पड़े हैं। हमारे देश में जन सम्पत्ति और खनिज सम्पत्ति की कमी नहीं है। कमी केवल यह है कि इन साधनों का समुचित विदोहन नहीं हुआ है। समुचित विदोहन हो जाने पर जनसंख्या का भूत स्वतः गायब हो जायेगा।

3 अर्थ-व्यवस्था का विस्तारण वर्तमान समय में भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। लघु व कुटीर उद्योग ग्राम समाप्त हो चुके हैं। भविष्य में इनके विकास की बहुत सम्भावनाएँ हैं। कृषि में कई गुनी वृद्धि करके तथा कुटीर उद्योगों का विकास करके भारतवर्ष वर्तमान जनसंख्या से भी अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण कर सकता है। स्वयं महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योगों के महत्व के सम्बन्ध में कहा था कि यदि इनका समुचित विकास कर दिया जाय तो वे वर्तमान जनसंख्या से दूनी जनसंख्या का भरण-पोषण करने में समर्थ होंगे।

4 जनसंख्या का घनत्व उत्तर के बहुत से देशों में जनसंख्या का घनत्व हमारे देश की अपेक्षा नहीं अधिक है। उदाहरणार्थ, जापान, इंग्लैंड, इटली में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः 273, 227, व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में जनसंख्या का घनत्व केवल 160 है। जब अधिक जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्र में जनसंख्या की समस्या नहीं है, तब भारतवर्ष में ही कैसे जनसंख्या हो सकता है ?

5 जन-वृद्धि दर यद्यपि वर्तमान समय में जन वृद्धि-दर 2.46 प्रतिशत है, तथापि यदि दीर्घकालीन दर पर दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि 1901-1951 की अवधि में भारत में जनसंख्या केवल 52% वृद्धि हुई, जबकि मसार के बड़े उन्नत-शील देशों में जनसंख्या की वृद्धि उसी अवधि में 100% हुई अतः भारत में जनसंख्या नहीं कहा जा सकता, पश्चिमी देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ रही है जैसा कि अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट है

1881 से 1930 के बीच 50 वर्षों में

जनसंख्या में वृद्धि

देश	जनसंख्या में वृद्धि दर
भारत	39 प्रतिशत
इंग्लैंड	54 "
जापान	74 "
अमेरिका	186 "

6 कृषि उद्योग बढ़ने की सम्भावना डा० आर० के० दास का मत है कि भारतवर्ष में केवल 30 प्रतिशत जमीन का ही सही प्रयोग हो रहा है। 70% कृषि-योग्य भूमि व्यर्थ पड़ी हुई है। हमारी नदियों का पानी व्यर्थ बह जाता है। यदि हमका 10% भाग भी सिंचाई के काम ला सके तो उपज में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है और जनसंख्या का भार इतना सहमूम नहीं होगा।

7 अन्य तर्क आशावादी व्यक्ति प्रायः यह भी कहते हैं कि मनुष्य केवल पैदल चलने की शक्ति नहीं होता, दो हाथ भी लगाता है। अतः जनसंख्या की वृद्धि में अनावश्यक रूप से घबराना उचित नहीं है। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि उद्योगों में कुशल श्रमिकों का अभाव है और इस आधार पर वे जनसाधन नहीं मानते।

(ख) निराशावादी दृष्टिकोण

निराशावादी दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों का कहना है कि भारतवर्ष में वर्तमान समय में जनसाधन है। उनके तर्क प्रायः मातृसत् के जनसंख्या सिद्धान्त पर आधारित हैं। निराशावादी विद्वानों ने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिये हैं —

1 जनसंख्या में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि मातृसत् के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष में जनसाधन बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या में साक्षरता की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारतवर्ष में इतना साक्षर नहीं है कि घरा की समस्त जनसंख्या का भरण-पोषण हो सके। 15 अगस्त, सन् 1947 से नवम्बर 1966 की अवधि में भारत को 2634 करोड़ रुपये का साक्षर विदेशों से भगाना पड़ा, अतः देश में जनसाधन है।

2 प्राकृतिक प्रतिबन्धों का नाश होना मातृसत् में यह भी बताया है कि जब देश में जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तब प्रकृति अपने नृशत्रु हाथों से लड़ी हुई जनसंख्या का सहार कर देती है। भारतवर्ष में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ें समय-समय पर फैलने वाली महामारियाँ, अकाल, आदि की स्थिति, ये सब बातें साबित करती हैं कि भारतवर्ष में जनसाधन है।

3 ऊँची मृत्यु दर यत् 21 वर्षों के आधिक नियोजन के बावजूद भी भारतवर्ष में मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है आ प्राकृतिक प्रतिक्रिया की उपस्थिति का आभास देती है तथा जनाधिक्य की पुष्टि करती है।

4 भोजन जीवन स्तर भारतवर्ष में लगभग 90% लोग भूख की पीड़ा के निपट हैं। लोगों को गुविषाओं और विषमिता की बीम कहें, आवश्यक आवश्यकताओं की वस्तुएँ भी नहीं मिल पाती। न तन टकने की वपडा और न पेट भरने की भोजन मिलता है। यह स्थिति जनाधिक्य की द्योतक है।

5 बेकारी का पाया जाना भारत में जनाधिक्य के कारण ही लोग बहुत बड़ी मस्या में बेकार हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेकारी की संख्या 35 लाख की ओर बढ़ कर चौथी योजना के अन्त तक लगभग 1 करोड़ 50 लाख हो जायेगी। इसी बड़ी मस्या में लोगों का बेकार होना यह साबित करता है कि देश में जनाधिक्य है।

6 वस्तुओं के मस्या में वृद्धि जनाधिक्य के कारण ही वृषि व उद्योग के क्षेत्रों में योजनाओं के फलस्वरूप जो वृद्धि हुई है, वह जनसाधारण की आवश्यकता से कम पड़ जागी है और बाजार में इन वस्तुओं के मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ जाते हैं।

7 शिक्षा का अभाव जनाधिक्य के कारण ही भारत में तीन-चौपाई लोग शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को शिक्षा-मुविधायें दिलाना कठिन पड़ रहा है।

उपर्युक्त तथ्य यह पूर्णतया साबित कर देते हैं कि भारतवर्ष में जनाधिक्य की स्थिति है। जो लोग यह कहते हैं कि भारत में जनसंख्या की समस्या है ही नहीं, वे केवल कल्पना-लोक में ही विचरण करते हैं। सब तो यह है कि यदि हमने जनसंख्या को रोकने के लिए तुरन्त कदम न उठाये तो हमारा सारा आर्थिक नियोजन असफल हो जायेगा। अतः सौच-ममत्तकर जनसंख्या को सीमित करना परमावश्यक है, अन्यथा जनवृद्धि हमारी आर्थिक प्रगति को नियल जायेगी।¹

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एच विद्वाल डा० राधाकमल मुखर्जी, डा० ज्ञानचन्द्र, प्रो० दत्तल, आदि के मतानुसार भारतवर्ष में जनाधिक्य की समस्या विद्यमान है।

भारतीय जनसंख्या की विशेषताएँ भारतवर्ष में जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ अप्रलिखित हैं —

1. 'Careful population planning is an urgent necessity in India on population growth would tend to eat up economic growth in a marked manner.'

—*Alak Ghosh, Indian Economy—Its Nature and Problems.* p. 175

1. जनसंख्या की अधिकता—भारतवर्ष में सन् 1971 ई० की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 54.7 करोड़ है। देश के वर्तमान साधनों को देखते हुये यह जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है। भारतवर्ष में बढ़ती हुई निर्धनता, सामान्यतः ऊँची जन्म दर, सात्वानों की चिन्ताजनक कमी तथा अकालों की उपस्थिति—ये सभी लक्षण देश में जनाधिमय गानित करते हैं।¹ संसार में चीन को छोड़ कर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1/8 भाग है।

2 जनसंख्या के घनत्व में अन्तर—भारत के सभी भागों में जनसंख्या का घनत्व एक ना नहीं है। एक ओर प० बंगाल, उत्तर प्रदेश व केरल में जनसंख्या का घनत्व अधिक है तो दूसरी ओर आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू व काश्मीर में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। अमेरिका की तुलना में यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जबकि जापान की तुलना में कम। भारत, अमेरिका व जापान में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः 160, 21 व 273 है।

3 कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम है—सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1 में 14 वर्ष तक की उम्र वाले 41.1 प्रतिशत, 15 से 55 वर्ष तक की उम्र वाले 51.1 प्रतिशत तथा 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले 7.8 प्रतिशत व्यक्ति थे। इस आयु रचना से यह पता चलता है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अन्य देशों में कम है।

4 स्त्री पुरुष अनुपात में स्थिति कम—सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या 28.30 करोड़ तथा स्त्रियों की संख्या 26.29 करोड़ थी। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में इस समय प्रति हजार पुरुषों के पीछे 932 स्त्रियाँ हैं। स्त्री पुरुष अनुपात (Sex Ratio) के दृष्टिकोण से यद्यपि योरोप के अनेक भाग स्त्री बहुसंख्यक हैं, किन्तु भारतीय जनसंख्या पुरुष बहुसंख्यक है। यदि हम देश के विभिन्न राज्यों में स्त्री-पुरुष अनुपात का अवलोकन करें तो पता चलता है कि केरल व उड़ीसा स्त्री बहुसंख्यक राज्य हैं। बिहार, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर एवं मध्य प्रदेश यद्यपि पुरुष बहुसंख्यक जनसंख्या वाले राज्य हैं तो भी इनमें स्त्रियों की संख्या राष्ट्रीय औसत (932) से अधिक है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पश्चिमी बंगाल, असम व पंजाब ऐसे प्रान्त हैं जहाँ स्त्रियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। सन् 1901 की तुलना में अगले दशकों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या में निरन्तर कमी होनी चली गई है जैसा कि अगले बृष्ट पर दी गई तालिका से स्पष्ट है—

1 "The appalling poverty of our people, usually high birth rate, serious food shortages accompanied by famines, are usually considered to be the symptoms of over population in India."

स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष

समस्त भारत	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971
	963	953	940	934	947	941	932

5 औसत उम्र का कम होना—भारत में सन् 19०1 से 1960 ई० के बीच पुरुषों की औसत आयु 41.9 वर्ष तथा स्त्रियों की औसत आयु 40.6 वर्ष थी। स्त्री एवं पुरुष दोनों की सम्मिश्रित औसत आयु 41.2 थी। इस समय भारत में जन्म के समय प्रत्याक्षित आयु 53 वर्ष है। आयु प्रत्याशा मृत्यु दर पर निर्भर करती है और मृत्यु दर समय बीमारी, जोषन-दसाओं, पोषण स्तर, स्त्रियों की देखभाल, विशुद्ध भरण वार आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। यदि हम अन्य देशों से तुलना करें तो हमारे देश के निवासियों की औसत उम्र बहुत कम मालूम पड़ती है। अमेरिका में पुरुषों व स्त्रियों की औसत उम्र क्रमशः 65 व 70 वर्ष है। लेकिन यह सलोप का विषय है कि औसत आयु उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा में है जैसा कि विभिन्न ताजिका में स्पष्ट है—

भारत में जन्म के समय प्रत्याक्षित आयु

(वर्षों में)

दशक	पुरुष	स्त्रियाँ
1901-1910	22.59	23.31
1911-1920	19.42	20.91
1921-1930	26.91	26.56
1931-1940	32.00	31.37
1941-1950	32.45	31.66
1951-1960	41.00	40.60
1961-1965	48.70	48.10
1966-1970	53.20	52.60

6 जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर—भारत में जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। सन् 1951 से 1961 में जनसंख्या वृद्धि दर 21% थी। पिछले दशक में अर्थात् 1961-1971 की अवधि में जनसंख्या 10.79 करोड़ बढ़ी है। इस प्रकार जनसंख्या में 24.57 प्रतिशत वृद्धि हुई अर्थात् जनसंख्या की वृद्धि दर 2.46 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। इस समय तो भारतवर्ष में हर 1½ सेकण्ड के बाद बच्चा पैदा होता है और हर वर्ष 210 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। भारतवर्ष एक आस्ट्रेलिया जैसी जनसंख्या में जोड़ लेता है। 1994 तक, एम अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 100 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है।

7 जन्म व मृत्यु दर का ऊँचा होना—भारत की जनसंख्या की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ जन्म दर व मृत्यु-दर अन्य देशों की अपेक्षा ऊँची है। सन् 1951-61 के बीच जन्म-दर 42 प्रति सहस्र तथा मृत्यु दर 23 प्रति सहस्र थी। पिछले दशक में यह वृद्धि 13 प्रति सहस्र थी। इंग्लैंड व फ्रांस में जन्म-दर क्रमशः 15.9 व 19.4 तथा मृत्यु दर क्रमशः 12.6 तथा 13.9 है। सन् 1961-1971 के दशक में मृत्यु दर घट कर 15.6 प्रति हजार रह गई लेकिन जन्म दर इसी अवधि में बहुत कम घटी, अर्थात् 42 प्रति हजार से घट कर 39.8 प्रति हजार रह गई। इस प्रकार हम देखते हैं जनमरदा स्वाभाविक वृद्धि दर सेजी से बढ़ रही है जिसके कारण हम जनसंख्या पिस्कोट' की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं।

8 गाँवों में अधिक जनसंख्या—भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते गाँवों में रहता है। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत भाग ग्रामीणों में तथा शेष 82 प्रतिशत भाग शहरी में निवास करता है। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 43.8 करोड़ अर्थात् 80 प्रतिशत स्थिति गाँवों में रहते थे, जबकि 10.9 करोड़ अर्थात् 20 प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते थे। यदि पिछले कई दशकों का अध्ययन किया जाये तो पता चलता है कि अग्र उत्तरोत्तर शहरी की ओर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—

भारत में 1911-1961 के बीच गाँवों व नगरों की जनसंख्या

जनगणना का वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971
गाँवों में जनसंख्या का प्रतिशत	90.1	90.6	88.7	87.9	86.1	82.7	82.2	80
नगरों में जनसंख्या का प्रतिशत	9.9	9.4	11.3	12.1	13.9	17.3	17.8	20

9 व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या में भिन्नता—सामान्यतः व्यवसायों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है—कृषि, पशु पालन, मत्स्य पालन एवं वन बांदि व्यवसायों को प्राथमिक उद्योग या व्यवसाय कहते हैं, क्योंकि वे उद्योग प्रकृति की सहायता से बनाये जाते हैं तथा मानव जीवन के लिए वे प्रत्येक अनिवार्य से होते हैं। द्वितीयक उद्योग या व्यवसाय में छोटे व बड़े पैमाने के निर्माण उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं। कभी कभी खाद्य जोड़ने के व्यवसाय को भी इसी में सम्मिलित किया जाता है हालांकि यह उद्योग प्राथमिक उद्योगों की श्रेणी में गिना जाता चाहिए। तृतीयक (Tertiary) क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त प्रबंध आदि की क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं। सामान्यतः प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था की दोषक मानी जाती है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों की प्रधानता विकसित अर्थ-व्यवस्था की प्रतीक समझी जाती है। कोलिन क्लार्क (Colin Clark) के शब्दों में— प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक आय के ऊँच औसत स्तर का तृतीयक उद्योगों से अधिको से बड़े अनुपात में काम करने में सदा सम्मग्न रहता है। प्रत्येक व्यक्ति निम्न वास्तविक आय का सदा तृतीयक उद्योगों में काम करने वाले अधिको की कम संख्या और प्राथमिक उद्योगों में कार्य करने वाले अधिको की अधिक संख्या से सम्पन्न होता है।¹ अन्य विकसित व उद्योग प्रधान देशों की तुलना में हमारा देश के अधिकतर लोग खेती में लगे हुए हैं जबकि उन देशों में अधिकतर लोग उद्योगों में लगे हैं। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में केवल 4% तथा अमेरिका में 9% लोग खेती में लगे हुए हैं जबकि भारत में 72.28% लोग खेती में लगे हुए हैं। सन् 1951 तथा 1961 में विभिन्न व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या का वितरण इस प्रकार रहा —

कार्यशील जनसंख्या का क्षेत्रवार विभाजन

व्यवसाय या पेशा	पुरुष अधिको का प्रतिशत	
	1951	1961
1 कृषि व खनिहर श्रमिक	66.85	64.88
2 दग, पायातो व खानों में काम करने वाले	2.79	3.10
3 घरेलू उद्योगों में लगे हुए व्यक्ति	9.84	11.27
4 निर्माण कार्यों में लगे हुए लोग	1.19	1.41
5 व्यापार व वाणिज्य में लगे हुए लोग	5.49	5.29
6 परिवहन व संचार में लगे हुए लोग	2.04	2.28
7 सेवाओं में लगे हुए लोग	11.80	11.77

देशों के अनुसार जनसंख्या के वितरण सम्बन्ध में आँकड़ों का अध्ययन करने से देश की अर्थ-व्यवस्था का पिछड़ापन स्पष्ट हो जाता है। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि व सम्बन्धित व्यवसायों में कार्यरत है। 10 से 12 प्रतिशत जनसंख्या शान, उद्योग तथा निर्माण कार्यों में लगी हुई है। 15 से 17 प्रतिशत लोग तृतीयक व्यवसायों में लगे हुए हैं। 1951 से 1961 के मध्य जहाँ कृषि में लगे हुए व्यक्तियों का अनुपात घटा है वहाँ बागाना, उद्योगों तथा परिवहन में लगे हुए व्यक्तियों का अनुपात बाँको बढ़ा है। फिर भी अन्य देशों की तुलना में यहाँ की जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक है। सम्भाव्यतः यह कारण है कि कृषि पर जनता की अधिक निर्भरता निर्धनता की शोचक होती है क्योंकि कृषि कार्य करने वाले प्रदेशों के उत्पादों का मर्यादित उद्योगों और तृतीयक क्षेत्र में बाँट कराने वाले व्यक्ति की तुलना में केवल एक निहाई हाथों है। द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में शीघ्र गति से विकास न होने के कारण कृषि क्षेत्र के अर्थव्यवस्था लोगों की रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अर्द्ध-रोजगार की स्थिति बनी हुई है। भारत में प्राथमिक उद्योगों की प्रचुरता की निरन्तरता दिनांकित तालिका से स्पष्ट हो जाये है—

75553

वर्ग	1901	1931	1951	1961	1967
प्राथमिक व्यवसाय	71.8	74.8	72.1	72.3	73.2
द्वितीयक व्यवसाय	12.6	10.2	10.6	11.7	10.9
तृतीयक व्यवसाय	15.6	15.0	17.3	16.0	15.9
सौ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

यहाँ यह तृतीयक क्षेत्र का सम्बन्ध है "20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही यह लगभग स्थिर रहा है। इसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। मजदूर वर्ग की इसमें थोड़ी वृद्धि हो गई है जो हमारे पिछड़ेपन की प्रतीक है।

तृतीयक क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात भी घटता-बढ़ता रहा है। इसमें बहुत थोड़ी सी वृद्धि हुई है। यही कारण है कि भारत में निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। निर्योजन बाज़ में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो

जाने के बावजूद भी भारत के व्यावसायिक क्षेत्रों में अब तक नौ विमेष बनने नहीं पाया है। इन समस्याओं को यदि प्रभावशाली ढंग से सुलझाया है तो हमें व्यावसायिक क्षेत्रों में परिवर्तन बल्कि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में अधिक लोगों को रोजगार दिलाना होगा।

10. आर्थिकों की अधिकता—भारत में अनुसूचित परिवार प्रभावों के कारण काम करने वाले लोगों के ऊपर आर्थिकों का बोझ अधिक है। नगरों के मध्य बड़े बड़े बाड़े बंगलों में वे घाबर ही कोई देना होगा तो जहाँ आर्थिकों की दुनियाँ अधिकता हो। 1961 की जनगणना के अनुसार कार्य करने वाले केवल 42.7%, तथा आर्थिक लोग या अनुसूचित उपसंख्या 57.3% थे।

11. निम्न जीवन स्तर—भारतवर्ष की जनसंख्या की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ के लोगों का रहन-पहन का स्तर अपेक्षाकृत अधिक नीचा है। लोगों को आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना नगर में उठाना पड़ती है। जनसंख्या स्तर नीचा है।

12. सामान्य विपदाएँ—भारत के लोगों में निराशा का प्रसार पर्याप्त नहीं हुआ है। अब भी लगभग 74% भाग निराशा की मुविधाओं में बंदिन है। परस्पर लोगों का वीर्यपूर्ण स्तर नीचा है। पीछे पड़ने के अभाव में सामाजिक क्षमता भी नीची है।

भारत में जनसंख्या के कारण

भारतवर्ष में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से हो रही है, जो अपने कारणों को जानना आवश्यक हो जाता है। माध्यमन मनुष्य का काम होना तथा जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या की दर की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। वे कारण जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, वही जनसंख्या वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य में भारतवर्ष में जनसंख्या के कारण निम्नलिखित हैं।

1. विवाह की अनिवार्यता—भारतवर्ष में विवाह अनिवार्य धार्मिक व सामाजिक कार्य है। वे व्यक्ति जो शादी के बिना रह जाते हैं, मनुष्य उन्हें अच्छी निगाह में नहीं देखता। विवाह की आवश्यकता एवं अनिवार्यता जनसंख्या में सहायक है। पश्चिमी देशों में ऐसी बात नहीं है। भारतवर्ष में लगभग उत्पन्न करने योग्य स्त्रियों में से 76 प्रतिशत स्त्रियाँ विवाहित हैं, जबकि दुनियाँ में 35 वर्ष की आयु की केवल 33 प्रतिशत स्त्रियाँ ही विवाहित होती हैं।

2. दाल-विवाह—भारतवर्ष में लगभग 80 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 15-20 वर्ष की उम्र में हो जाता है। परम्परागत प्रजनन की अवधि का विस्तार हो जाता है, क्योंकि सामान्यतः स्त्रियों में 45 वर्ष की आयु तक प्रजनन-क्षमता पाई

जाती है। 15 से 45 वर्ष की अवधि परिवार में बच्चों की वाढ़ का देती है। इंग्लैंड तथा अमेरिका में 30 वर्ष की आयु की अनिवारित रिखा क्रमशः 41 व 23 प्रतिशत है।

3 समुक्त परिवार प्रथा—भारतवर्ष में जनसंख्या के लिए समुक्त परिवार प्रथा भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। यहाँ सामूहिक दायित्व होने के कारण, सन्तान पैदा करते समय, माता-पिता अपना उत्तरदायित्व अनुभव नहीं करते, क्योंकि उनके भरण-पोषण या दायित्व भी उनके बच्चों पर न होकर समुक्त परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है।

4 सन्तान की तीव्र चाहता—धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणों के कारण लोगों में सन्तान-लाभना पाई जाती है। वे समझते हैं कि बिना पुत्र पैदा हुए उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। सन्तान प्राप्ति के लिए बड़-बड़े अनुष्ठान किये जाते हैं। सन्तान प्राप्ति की यह तीव्र चाहता जनसंख्या को अवांश वर्ग से बढ़ाती है।

5 अज्ञान एवं अशिक्षित-भाग्य के एक चौपाई शीव ही शिक्षित है। अधिकांश लोग अनिश्चित एवं अज्ञानो होने के कारण भाग्यवादी बन गए हैं तथा वे बच्चों को भगवान की देन समझते हैं, जिसे रोकना धर्म के विरुद्ध मान्यता बनना समझते हैं।

6 मनोरंजन के साधनों का अभाव—डॉ बन्धोपाध्याय के मतानुसार "स्त्री सम्भोग भारत का एक राष्ट्रीय खेल है।"¹ भारतीय पितानों व धर्मियों की जीवन की तीव्रता को दूर करने के लिए मनोरंजन सम्बन्धी सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं फलस्वरूप वे अपने घरों में ही अपनी तीव्रता को दूर कर लेते हैं, जिसका परिणाम जनसांख्यिक के रूप में प्रकट होता है।

7 निर्धनता—भारत में निर्धन लोगों के परिवार प्रायः बड़े पाये जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि निर्धन लोग बच्चों से कम उम्र से ही काम कराना शुरू कर देते हैं जिससे कि वे परिवार की आय बढ़ा सकें। अतः वे जनसंख्या कम करने के पक्ष में नहीं हैं।

8. अधिक बाल मृत्यु दर—भारतवर्ष में बाल मृत्यु दर बहुत है, अतः माता-पिता इसलिए अधिक बालों पैदा करते हैं कि यदि उनमें से कुछ असमय में मर-कबलित हो जाय तो भी कुछ बच्चे बचे रहें। अतः मृत्यु के विरुद्ध बीमा करने की यह प्रवृत्ति जनसंख्या में वृद्धि कर देती है।

9 - निरोधक सुविधाओं का अभाव—भारत की जनसंख्या का कुछ भाग परिवार नियोजन करना चाहता है, परन्तु आवश्यक सुविधाओं एवं ज्ञानकारी के

1. 'Sex-play is the national sport in India' Dr. Chandra Shekhar

अनाथ में वह ऐसा नहीं कर पाता। साथ ही हमारे देश में सस्ते उपकरण भी लोगों को उपलब्ध नहीं है।

10. जलवायु का प्रभाव—उष्ण जलवायु के कारण भारत में स्त्रियों में प्रजनन-शक्ति (Fertility) जल्दी शुरू हो जाती है और अपेक्षाकृत अधिक होती है। फलस्वरूप जन-वृद्धि की गति बढ़ जाती है।

11. बहु-विवाह प्रथा—भारत में अब तक लोग कई शादियाँ कर सकते थे। मुसलमानों में तो यह रिवाज खत्म कर पाया जाता है। बहु-विवाह के कारण जन-संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है।

12. आवास की समस्या—एक मुठ कपों में बहुत से भारतीय लक्ष्मी, दमौ, पाकिस्तान, वेनिस्मा आदि देशों में राजनैतिक परिस्थितियों के कारण स्वदेश वापस आ गए हैं, अतः जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई है।

13. विधवा विवाह—भारतवर्ष में कुछ नीची जातियों में विधवा स्त्रियों को परिश्रम श्रमिका के पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है जिससे जनसंख्या में बढ़ोतरी की बल मिलता है।

14. स्त्रियों के प्रति सहयोगी भावना का अभाव—भारतवर्ष में स्त्री-सङ्ख्या की आर्थिक दृष्टि में पराधीन होने के कारण केवल कामवृत्ति की पूर्ति का साधन के घर-गृहस्थी सम्भालने वाला माना जाता है। यह भी जनसंख्या की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।

15. विभाजन का प्रभाव—भारतवर्ष में 1947 के बाद जनसंख्या के भार में वृद्धि का एक कारण यह भी रहा है कि देश के विभाजन के बाद अविभाजित भारत के कुल क्षेत्र का 77% भाग भारत में रहा तथा क्षेत्र 23%, पाकिस्तान गया तथा, जबकि जनसंख्या का 81% भाग भारत में रह गया और केवल 19% भाग पाकिस्तान में गया। फलस्वरूप भारत में जनसंख्या का भार अपेक्षाकृत अधिक रहा।

16. अधिक नियोजन का प्रभाव—विविध नियोजन बाल में एक ओर विकिरण सुविधाओं के विस्तार के कारण प्लेग, मलेरिया, हैजा आदि महामारियों की कमी के कारण मृत्यु दर में काफी कमी हो गई है जबकि दूसरी ओर जन्म दर में इतनी कमी नहीं हुई फलस्वरूप जनसंख्या अवाध गति से बढ़ती रही है।

जनसंख्या वृद्धि के उपर्युक्त वर्णित कारणों में से बाल-विवाह तथा प्रार्थना की अनिवार्यता ही जनवृद्धि के प्रमुख कारण हैं। यद्यपि जनसाधारण की निर्धनता भी जनवृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण मानी जा सकती है, तथापि यह धीरे-धीरे देखते-देखते सामाजिक एवं धार्मिक कारण ही इस समस्या के मूल में खोजे जा सकते हैं। ६१०

ज्ञानचंद के शब्दों में, "भारत में अत्यधिक जन्म दर सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का परिणाम है। अतएव जब तक हमारे सामाजिक एवं नैतिक वातावरण में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक पश्चिमी देशों की तरह हमारे देश में भी जन्म दर में कोई थोड़ी भी आशा नहीं की जा सकती।"¹

जनसंख्या की वृद्धि के प्रभाव—भारत में जनसंख्या की उत्तमोत्तर वृद्धि ने कई भीषण समस्याएँ सृष्टी कर दी हैं जिनमें से प्रमुख निम्न हैं—

1 **भूमि पर जनसाधारण में वृद्धि—**जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि ने भूमि पर जनसाधारण को आवश्यकता से अधिक बना दिया है। इससे कृषि उपज भी कम हो ही गई है। गांध ही गांध कृषि विषयक अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

2. **बेकारी की समस्या—**भारत में फैली हुई बेकारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या का अत्यधिक गति में बढ़ना ही है। जब तक जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभावशाली नियन्त्रण न लगाया जावेगा तब तक बेकारी की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

3 **साक्षरता की समस्या—**साक्षरता की बढ़ने के हमारे सारे प्रयत्न जनसंख्या के कारण असफल हो गये हैं। जिनका साक्षरता हम पंचवर्षीय योजनाओं में बढ़ाते हैं, उसके अनुपात में कदा अधिक जनसंख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप साक्षरता की गति पूर्ववत् बनी रहती है।

4 **निर्धनता की समस्या—**भारत के लोग निर्धनता में पिन रह रहे हैं। जनसंख्या के कारण अधिकांश जनता का जीवन स्तर बहुत नीचा है। दस से निर्धनता एवं दरिद्रता को उस समय तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक की जनसंख्या को सीमित नहीं किया जाता।

5 **औद्योगिक केन्द्रों के दुष्परिणाम—**जनसंख्या की वृद्धि न शहरी में निवास की समस्या पैदा कर दी है। लोगों को गन्दे एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में निवास एवं अन्य सुविधाओं की बढ़ना सम्भव नहीं है, फलस्वरूप लोगों की तबड़ी में कष्टमय जीवन बिताना पड़ रहा है।

6 **कम राष्ट्रीय आय की समस्या—**समस्त वर्ष पंचवर्षीय योजनाएँ बनाकर अपने नियोजन की आय बढ़ाना चाहता है। बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्रीय आय को

1 The high birth rate in India is a part of our culture and it is only when the moral sentiments of the community change either by choice or by the force of circumstances. At a fall in the birth rate comparable with the fall which has taken place elsewhere can be expected.

तोत्र गति से नहीं बढ़ने देनी। एक ओर कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो दूसरी ओर उसमें भाग लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय व्यो की रफो रहती है। भूतपूर्व योजना मंत्री श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा है, "जनसंख्या में वृद्धि राजि में चोर में सघान है जो हमारी आर्थिक विवाम में प्राप्त सफलता को हम से छूट ले जाता है।

7. पूंजी निर्माण में बाधा—जनसंख्या की वृद्धि ने भारत में पूंजी निर्माण की गति को भी हतोत्साहित कर दिया है क्योंकि जनसाधारण को जीवनस्तर बनाने रखने के लिए अधिप उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसका परिणाम यह होता है कि बचत तथा विनियोग घट जाते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ठीक ही कहा गया है, "एक अल्प विवसित अर्थ-व्यवस्था में जहां प्रति व्यक्ति पूंजी बहुत कम होती है, जनसंख्या की वृद्धि की अधिक दर बचत की मात्रा में बढोतरी करता और भी कठिन कर देती है जिम पर अधिपतर उत्पादन और आय में वृद्धि की सम्भावनाएँ निर्भर रहती हैं। इसके अतिरिक्त विनियोग का अधिकांश अंश पूंजीगत वस्तुओं की अपेक्षा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया पड़ेगा जिसके फलस्वरूप विकास की सम्भावित दर और कम हो जायेगी।"

8. कार्यक्षमता में ह्रास की समस्या—अधिक जनसंख्या के कारण राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है जिससे लोगों का रहन-सहन का स्तर नीचा हो जाता है। नीचा रहन-सहन का स्तर लोगों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर डालती है।

इसके अलावा जनसंख्या की अबाध वृद्धि समाज के लोगों में तनाव का साताकरण पैदा करती है, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या उनके सभी मनसूबों पर पानी फेर देती है और उनमें निराशावादी दृष्टिकोण पैदा करती है। छात्रों में अनुशासनहीनता, राजनैतिक क्षेत्र में अस्थिरता एवं आर्थिक विकास में गतिरोध के मूल में जनसंख्या की ही समस्या छिपी हुई है। बार-बार होने वाले प्रयत्न के कारण इसी श्रमिक दीर्घकाल तक उत्पादन कार्यों में भाग नहीं ले सकती, फलस्वरूप आर्थिक विव्रान में बाधा उत्पन्न होती है।

जनसंख्या की वृद्धि के सबपर परिणामों तथा परिवार नियोजन की तीव्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डॉ० चन्द्रशेखर ने ठीक ही कहा है, "हम बहुत जल्दी में हैं। एक रात की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। पाव पिनट की हर भूल में बच्चे का जन्म हो जाता है और प्रतिवर्ष भारत में एक आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या जाकर जुड़ जाती है। परिवार नियोजन के बिना हमें एक रात एवं भयावह स्थिति है।"

भारत में जनसंख्या

जनसंख्या की वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा करते हुए दिसम्बर 1958 ई० में अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद में भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ० कर्माकर ने ये उद्घाटन प्रवचन किये थे “जनसंख्या में असाधारण वृद्धि राष्ट्र के समक्ष गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न कर रही है तथा देश के विकास में बाधाएँ उत्पन्न कर रही है। देश का स्वास्थ्य व्यक्तियों के मूल तथा देश के पुनरुत्थान इत्यादि चीजें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जनसंख्या की समस्या पर ही आधारित है।”¹

जनसंख्या समस्या का समाधान—भारत में ही नहीं, जनसंख्या की समस्या विश्व भर के लिए अविचार्य सिद्ध हो रही है। प्रति मिनट 225 बच्चों का जन्म होने से एक धिक्क परिस्थिति पैदा हो गई है। ज़ामतौर से उस समय जबकि न तो भूमि का विस्तार किया जा सकता है और न उर्वरा जमीन को ही एक सीमा से अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब हम समस्या की मुकदमना अत्यधिक आवश्यक है। इस समस्या में निम्नलिखित मुद्दाव महत्वपूर्ण है—

1 **शिक्षा का प्रसार—**शिक्षित होना पर खोप प्रायः ‘मोटर कार बदवा बच्चे में वजुदा मोटर कार को ही प्राथमिकता देग।’ प्रो० महालानोबिस ने भी अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया है कि जिन परिवारों में शिक्षा का प्रवास पाया जाता है, उन परिवारों में प्रायः कम बच्चे होते हैं।

2 **देर से विवाह—**उच्चियों की विवाह उम्र कम से कम 20 वर्ष कर देनी चाहिए। इससे प्रजनन-दर कम हो जायेगा, फलस्वरूप जनसंख्या भी घटेगी। जन्मन व कानून के द्वारा विवाह की आयु बढ़नी चाहिए।

3 **जनसंख्या का समान वितरण—**जनसंख्या का धोचिक वितरण समान किया जाना चाहिए ताकि जनभार सभी स्थानों पर एक सा रहे।

4 **नैतिक समस्या पर बल—**योगों में आत्मनयम की भावना का विकास किया जाना चाहिए जैसा कि गांधीजी का सुझाव था। आत्मनयम जनवृद्धि को रोकने का एक प्रभावशाली एवं आदर्श तरीका है। न्यायदार्ष्टिक दृष्टि में अवश्य यह कठिन प्रतीत होता है।

1. “The abnormal increase in our population is posing serious threat before nation. It is lowering the standard of living, increasing conditions of unemployment, and arresting the growth of the country. The health of the nation, the quality of individual, the economic recovery of the country, are based directly or indirectly on the problem of population.”

5. **ओटोमोबाइल—**देम में बड़े ब लघु तथा कुटीर उद्योगों का विनाश करके तथा भायनों का सम्पत्ति विवेकन करके जनसंख्या की समस्या को हल किया जा सकता है।

6 **स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता—**स्त्रियों को शिक्षित कर यदि उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता दिला दी जाय तो वे निश्चय ही परिवार को जीवित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगी, क्योंकि स्त्रियाँ सामान्यतः प्रेम की निरन्तर पीछा से बचना चाहती हैं।

7 **अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास—**डॉ० राधाकृष्णन् मुंबई तथा डॉ० एम० चन्द्रसेखर ने जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए भारतीयों द्वारा विदेश प्रवास नीति का समर्थन किया है। डॉ० चन्द्रसेखर के मतानुसार प्रवास कम प्रजननवाले देशों में किया जाय तथा इस कार्य को कोई अन्तर्राष्ट्रीय मस्या न कराने।

8 **परिवार नियोजन को कार्यक्रमों को बढ़ावा देना—**देम में परिवार नियोजन के अधिकाधिक केन्द्र खोले जाय तथा विवाहित लोगों को परिवार नियोजन के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाय। गर्भ निरोधक रीति, सम्भारण की रीति तथा निरोधक टिकियो एवं लूप आदि का अधिकाधिक प्रचार किया जाय।

9 **विवेकहीन मातृत्व पर रोक—**भूतपूर्व जनयचना आयुक्त श्री गोपालस्वामी का मुझाव है कि यदि किसी स्त्री के 3 बच्चे हो चुके हूँ और उनमें से एक भी जीवित है तो उसके आसानी मातृत्व पर कानूनन रोक लगा देनी चाहिए।

10 **अन्य सुझाव—**(i) जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को सुधार कर आर्थिक संतुलन स्थापित किया जाय, (ii) जनसंख्या आयोग को जनवृद्धि के रोकने के उपायों पर भी मुनान का चाहिए, (iii) उच्च वंशजों की लड़कियों को परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा देनी चाहिए तथा (iv) परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सामुदायिक विज्ञान-संघों के माध्यम से लागू करना चाहिए।

जनसंख्या नीति—भारत सरकार की जनसंख्या नीति को निम्नलिखित चार कालों में विभाजित किया जा सकता है—(1) उपेक्षा काल अर्थात् 1947 के पूर्व का समय, (2) तटस्थता-काल अर्थात् 1947 से 1951 तक, (3) अनुभूतकाल अर्थात् 1951 से 1961 तक, (4) नियंत्रण नीति के प्रारम्भ का काल अर्थात् 1961 के बाद का समय। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व सन् 1938 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की सिफारिश की थी। सन् 1946 में मोर समिति ने अपनी रिपोर्ट में जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन का समर्थन किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी परिवार नियोजन की आवश्यकता स्वीकार

की बी सेनिन वे कृत्रिम साधनों के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए समय में रहने की सलाह दी थी।

भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरूआत स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त नियोजन काल में ही सही ज्यों में की गई। भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—(1) जन्म दर को सन् 1975-76 तक 41 प्रति हजार से घटा कर 25 या 20 प्रति हजार तक लाना, (2) देश के प्रत्येक दम्पति को छोटे परिवार की आवश्यकता को समझाना, (3) जिस दम्पति की 3 शन्तानें हैं उन्हें आपरेसन के लिए तैयार करना, (4) जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी कुछ कानूनी पहलुओं पर निर्णय लेना, जैसे (क) लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 16 से बढ़ा कर 20 वर्ष करना, (ख) किन्हीं स्थितियों में गर्भपात को वैधानिक रूप देना, (ग) अविविहित व्यक्ति को ज़ायवर में छूट देना तथा (घ) तीन बच्चों के बाद अनिवार्य वन्ध्याकरण की व्यवस्था करना।

भारत में परिवार नियोजन (Family Planning in India)—परिवार नियोजन में सार्वत्र्य परिवार को सोच समझ कर सीमित रखना है तथा बच्चों की उत्पत्ति में पर्याप्त कान्फ़ेन्स रखना है। परिवार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सन्तान दम्पति की इच्छानुसार होनी चाहिए न कि बढनाबढ़। परिवार नियोजन के लिए सन्ततिनिरोध की उचित विधियों को अपनाना आवश्यक होता है। पाश्चात्य देशों में तो परिवार नियोजन को वर्षों पूर्व अपना लिया था और आज यह उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। भारत में परिवार नियोजन को ओर विगत 15-20 वर्षों से विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

परिवार नियोजन के साधनों के सम्बन्ध में कुछ लोग समय पर बरु देते हैं और सन्तति निरोध के उपायों को अनैतिक मानते हैं। लेकिन यह विचार शुद्ध सैद्धान्तिक है। व्यवहार में इन्होंने अन्तर्गत वे प्रभावशाली उपाय आने हैं जिन्हें जन्म दर पर प्रभावपूर्ण रोक लगाई जा सके। इनके अन्तर्गत दर में छादी, मिल्ली, लूप, गोलिडो का प्रयोग, वन्ध्याकरण, नसबन्दी आदि उपाय आते हैं।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में परिवार नियोजन—प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में 126 परिवार नियोजन केन्द्र जहरो में तथा 21 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये। इस योजना में 19 अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गए तथा केन्द्रीय परिवार नियोजन मंडल (The Central Family Planning Board) बनाया गया। इस योजना में 65 लाख रुपये निर्धारित किये गये थे, परन्तु केवल 18 लाख रुपये ही खर्च किये जा सके। विद्वान स्वार्थ्य रूप के Dr Stone को इस समस्या पर मुझाव देने के लिए आमन्त्रित किया गया था।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में परिवार नियोजन—दूसरी योजना में 5 करोड़ रुपये की धनराशि परिवार नियोजन के कार्यों के लिए निर्धारित की गई थी। इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को और भी बढ़ाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए एन केन्द्रीय परिवार नियोजन आयोग की स्थापना की गई तथा प्रत्येक राज्य में भी इसी प्रकार के परिवार नियोजन आयोग स्थापित किए गए। समाचार पत्रों, विज्ञापनों, पोस्टर तथा फिल्मों के द्वारा जन-साधारण को परिवार नियोजन के विषय में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया। इस योजनावधि में 549 सहरी केन्द्र तथा 1100 ग्रामीण केन्द्र खोले गए।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में परिवार नियोजन—तृतीय योजना में 24.86 करोड़ रुपये परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय किए गए। इस योजना के अन्तर्गत भारतवर्ष में 11000 परिवार नियोजन केन्द्र खोले जा चुके थे। इस योजना की अवधि में परिवार नियोजन सम्बन्धी विभिन्न मण्डल बनाया गया। तृतीय योजना में बन्धकरण के आपरेटनों की संख्या 13.3 लाख रही। स्वास्थ्य सम्बन्ध का ताम बदल कर स्वास्थ्य एन परिवार नियोजन सम्बन्धित रखा गया तथा इसके अधीन एक सचिव की देखरेख में एन परिवार-नियोजन विभाग बनाया गया। एक केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था की भी स्थापना की गई।

1966-69 की अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर 63.38 करोड़ रुपये व्यय किये गए।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में परिवार नियोजन—चौथी योजना में परिवार नियोजन के लिए 315 करोड़ रुपये के परिष्कृत की व्यवस्था है और सन् 1973-74 तक वर्तमान जन्म दर 39 प्रति हजार को घटाकर 32 प्रति हजार पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। परिवार नियोजन की इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बन्धकरण, लूण तथा खाने की योग्यता एन इन्जेक्शन के गर्भराक्षक तरीकों के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। बालू गर्भरोधक उपायों को भी आगे बढ़ाया जायेगा ताकि 1973-74 तक 100 लाख व्यक्ति इसे अपना सकें। इन उपायों के फलस्वरूप 1973-74 तक 280 लाख स्त्रियों के सुरक्षित होने की सम्भावना है तथा योजना की अवधि में कुल 180 लाख बच्चों के जन्म के टक्के की भांति है।

विगत नियोजन काल में परिवार नियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। देश में सस्ते खंड, गर्भ निरोधकों की पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने 'निरोध' नामक शिल्ली को लोकप्रिय बनाया है। इसकी बिनी के 2 लाख केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। जुलाई 1971 तक 99 लाख नसबन्धी के आपरेटन किये

गए, 39 लाख लूप प्रयोग किए गए। सन् 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में क्रमशः 16.6 लाख, 14.2 लाख तथा 12.8 लाख वन्ध्यकरण आपरेशन किए गए।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों का मूल्यांकन—वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का खूब जोर-शोर से प्रचार किया गया है, तथापि इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख हैं, (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रचार के कारण भारत को अक्षिप्त तथा विस्तृत जनसंख्या तक यह कार्यक्रम नहीं पहुँच गया, (ii) गर्भ निरोध के अधिकारों साधनों का नि:शुल्क उपलब्ध न होना (iii) लूप के प्रतिशूल प्रभावों के विषय में झूठी अफवाहों का बोलबाला, (iv) निजी डॉक्टरों व साध्यों द्वारा इन कार्यक्रमों का विरोध (v) लूप लगवाने वाली स्त्रियों की पीडा एवं इलाज की उपेक्षा (vi) औरतों को इन कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह तैयार न किया जाना (vii) इन विधियों का ज्ञान होते हुए भी इनका प्रयोग न किया जाना (viii) परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लगे हुए कर्मचारियों में अनुभव का अभाव (ix) मौखिक गर्भ निरोधकों को (oral contraceptives) बनाने वालों द्वारा लूप के विरुद्ध कार्यवाही (x) झूठी कागजी कार्यवाही का बोलबाला एवं लक्ष्य प्राप्त करने में जल्दबाजी (xi) धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विरोध आदि।

उपरोक्त कारणों से परिवार नियोजन कार्यक्रमों की आवासीय सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के लिए सुझाव

(i) विवाह की आयु लड़के के लिए कम से कम 20 वर्ष तथा लड़की के लिए 20 वर्ष निश्चित की जानी चाहिए (ii) परिवार में 3 बच्चे हो जाने के बाद प्रत्येक माता या पिता को आपरेशन करा लेना चाहिए ताकि सन्तान न हो सके (iii) कोड, स्टेपिक पामप्लन जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित पुरुषों अथवा स्त्रियों का अनिवार्य रूप से आपरेशन करवा देना चाहिए (iv) तीव्र में अधिक सन्तान उत्पन्न करने वाले व्यक्तिों पर कठ लगाना चाहिए ताकि वे अधिक सन्तान पैदा करने में हतोत्साहित हो पायें ही वगैरह सन्तान वाले व्यक्तिों को कर में छूट देकर प्रोत्साहन दिया जाय, (v) जनसाधारण में परिवार सीमित करने की प्रेरणा देने के लिए देश के कोने-कोने में परिवार नियोजन सुविधाओं का जाल बिछा दिया जाय (vi) परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ मिला दिया जाय, (vii) परिवार निरोधक दवाइयों एवं उपकरणों का देश में उत्पादन बढ़ाया जाय और उन्हें जनसाधारण में नि:शुल्क वितरित किया जाय (viii) परिवार नियोजन के लिए प्रचार जनता की भाषा तथा व्यक्तिगत अनुसार किया जाय, (ix) परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए अधिक सरकारी परिवार नियोजन

केन्द्र एवं अस्पताल खोले जाय, (x) प्रसूति बाल मे दिए जाने वाले मातृत्व लाभों को एक या दो सप्ताह के बाद समाप्त कर दिया जाय, (xi) परिवार नियोजन विधियों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रलोभन दिये जाय, (xii) परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए योग्य, अनुभवी एवं सहानुभूति रखने वाले कर्मचारियों की ही नियुक्ति की जाय, (xiii) व्यवस्थापन को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाय तथा 2 या 3 सप्ताहों के बाद विवाहित स्त्रियों के लिए गर्भपात कराने की गारंटी छूट दी जाय, (xiv) यौन शिक्षा को अध्ययन के विषय के रूप में भाग्यता प्रदान की जाय ।

उपसंहार

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की वट्टी हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में बाधन हो रही है । अपने देश में निर्यात का बातावरण पैदा कर दिया है । हमारे आर्थिक प्रयत्नों में सफलता में जनसंख्या की समस्या ही बाधक है । भारत का जन-समुदाय इस समस्या की हल किये बिना अच्छे जीवन-स्तर की कल्पना ही नहीं कर सकता । अब सभी व्यक्तियों, मन्त्रियों व सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस समस्या के समाधान के लिए मिलजुल कर प्रभावशाली कदम उठावें । बिना जन-सहयोग के इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता । सब से यह है कि यदि हम इस समस्या का समुचित समाधान कर ले तो हमारी अर्थ व्यवस्था तो तमससाए स्वतः सुलझ जायेगी । इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा है, "जनसंख्या वृद्धि, भारतीय युग में छुपा हुआ एक ऐसा भयंकर घनू है, जो हमारी समस्त योजनाओं को नष्ट-भ्रष्ट कर रहा है । यदि बेकारी दूर करनी हो, अन्न तकट दूर करना हो, निराश्र की समस्या हल करनी हो या प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी हो, तो हमें जनसंख्या की वृद्धि पर कठोर नियंत्रण करना ही पड़ेगा ।" भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री एम सी जमनाल ने भी बबती हुई जनसंख्या के सम्बन्ध में बड़ी रोचक बात कही है, "यदि जनसंख्या की बढ़ने से रोकना न गया तो हमारी प्रगति रेत पर लिखने के समान होगी जिसको जनसंख्या में वृद्धि की लहरें मिटा देगी" ।

देश का भावी सुख एवं समृद्धि इसी बात पर निर्भर है कि हम जनसंख्या की बाढ़ को रोकने में कहीं तक तथा किन्तनी जल्दी सफल होते हैं । आज हमारे पास टहरने और रुक कर विचार करने का समय नहीं है । हमें तो चुरन्त ही कसर कस कर जनसंख्या के विस्फोट को रोकने का प्रयास करना चाहिए । परिवार नियोजन भावोत्पन्न कोरिया, ताइवान, हांगकांग आदि एशियाई देशों में सफल हुआ है । भारत में भी यह सफल होकर रहेगा । आवश्यकता केवल इस-बान की है कि हम इसे सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाय ।

प्रश्न

1. भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।

2 भारतवर्ष में परिवार नियोजन के महत्त्व तथा उसकी प्रगति का पूर्णतः विवेचन कीजिए ।
(राज० टी० डी० सी० तृतीय वर्ष 1964)

(राज० बी० ए० ऑनर्स 1967, शोटनोट)

3 भारत में जनसंख्या घनत्व के क्या कारण हैं और उसके क्या आर्थिक परिणाम होते हैं ?
(राज० बी० ए० 1966)

4 जनसंख्या की वृद्धि का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है ? यदि आप राष्ट्रीय आय में वृद्धि वांछित समझते हैं, तो जनसंख्या के बारे में आपकी क्या नीति होगी ?
(राज० टी० डी० सी० तृतीय वर्ष 1965)

5 "जनसंख्या की समस्या का मुद्दा-स्तर पर मुकाबला करना चाहिए ।" इस कथन की पूर्णतः विवेचना कीजिए । (राज० प्रथम वर्ष टी० डी० सी० कला 1969)

6 भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए । इसे रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए ?

(राज० प्रथम वर्ष टी० डी० सी० कला 1964, 1967)

7 "जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए अनन्त काल से भारतीय अर्थ व्यवस्था अस्थिर बनी रही है, उसमें उचित परिवर्तन नहीं किये गये ।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? यदि हाँ तो कारण दीजिए ।

(राज० प्रथम वर्ष टी० डी० सी० कला 1968)

8 भारत में परिवार नियोजन के महत्त्व तथा उसकी प्रगति का पूर्णतया विवेचन कीजिए ।
(राज० प्रथम वर्ष टी० डी० सी० कला 1965)

9 संक्षिप्त टिप्पणी—परिवार नियोजन

(राज० प्रथम वर्ष टी० डी० सी० कला 1968)

भारत में बेरोजगारी की समस्या

(Problem of Unemployment in India)

बेरोजगारी की समस्या बिश्व के मभस्त अल्प-विकसित देशों की प्रमुख समस्या है। भारत जैसे विद्याल बहुजन मस्यक देश के लिए तो यह और भी कठिन रूप में हमारे समक्ष उभरी मिलनी है। सत कई वर्षों से भारत में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। इसका रूप अत्यन्त भीषण बनता जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शहर हो अथवा गाँव, प्रत्येक वर्ष में चाहे वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, कुशल श्रमिक हो अथवा अकुशल, पुरुषों व स्त्रियों इत्यादि सभी में बेरोजगारी के स्पष्ट दर्शन होते हैं। मानवीय साधनों के अपभ्यय के साथ ही साथ कई अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव भी इसीसे होता है। इस दृष्टि में भी बेरोजगारी की समस्या महत्वपूर्ण एवं बिचारणीय है।

भारत में बेरोजगारी का आकार एवं प्रकृति (Nature and Extent of Unemployment in India)—उन्नत एवं समृद्ध देशों में बेरोजगारी का जो रूप एवं प्रकृति पाई जाती है वंसी प्रवृत्ति भारत जैसे अल्प-विकसित (Under-Developed) देश में नहीं पाई जाती। केन्स (Keynes) ने समृद्ध देशों में बेकारी का जो स्वरूप बताया है वह चक्रीय (Cyclical) माना है जो सफल माग (Effective demand) के अभाव से उत्पन्न होती है। बिश्वु भारत जैसे अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी की स्थिति पूर्णतः अभाव के साथ ही अन्य सहायक साधनों के अभाव से भी बनी रहती है। इस दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी चक्रीय एवं अस्थायी रहती है जबकि अल्प-विकसित देशों में इसका स्वरूप कठिन एवं धुमिपादी (Basic) होता है मोटे रूप भागत में बेरोजगारी के तीन स्वरूप दृष्टिगत होते हैं प्रथम, अपूर्ण रूप में बेरोजगारी है अर्थात् विद्याल योग्य-शक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ इस प्रकार की बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। इसका दूसरा रूप आंशिक बेरोजगारी (Partial Unemployment) कह है अर्थात् सम्पूर्ण वर्ष भर के लिए श्रम-शक्ति का रोजगार में बिलयन नहीं हो पा रहा है। इसे खूली अर्थ बेरोजगारी की मजा दी

जा सकती है। तृतीय रूप में बेरोजगारी निम्न उत्पादकता के कारण होती है। हमारे कृषकों की उत्पादकता अल्प, न्यून अथवा नगण्य है। ऐसी बेरोजगारी छिपी हुई मानी जाएगी।

एक अन्य प्रकार से यदि इसका वर्गीकरण किया जाए तो इसे हम (i) कृषि बेरोजगारी (ii) औद्योगिक बेरोजगारी तथा (iii) खिलिष्ट एवं मध्यम श्रेणी के लोगों में पायी जाने वाली बेरोजगारी, इन तीन रूपों में विभक्त करेंगे। भारत में आर्थिक विकास के साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ी है। किन्तु इन सम्बन्ध में पूर्ण एवं विश्वसनीय आंकड़ों का उपलब्ध होना कठिन है। इसलिए आंकड़ों के अभाव में बेरोजगारी के आकार एवं प्रकार की न्यायोचित जाच भी कठिन है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू में भारत में कुल बेरोजगारी 5 मिलियन व्यक्तियों की थी तथा जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए वह अनुमान लगाया गया कि यह वृद्धि कर योजना के अन्त तक 9 मिलियन पहुँच जाएगी। जिसमें से कुल 4 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की गयीं। अतः प्रथम योजना के अन्त तक यह बेरोजगारी 5 मिलियन व्यक्तियों की थी। योजना आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को विलुप्त समाप्त करने की घोषणा की तथा योजना के अन्त तक बेरोजगारी की संख्या का अनुमान 15-3 मिलियन लगाया तथा इतने ही व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण दूसरी योजना के अन्त तक कुल 9 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार रहे।

तीसरी योजना में मानव अन्तर्गत के पूर्ण उपयोग के लिए सरकार ने कई विकास कार्यक्रम लागू करने के लक्ष्य निर्धारित किए। दूसरी योजना के 9 मिलियन बेरोजगारों को मिलाकर तीसरी योजना के अन्त तक यह संख्या 26 मिलियन बढ़ जाती की जाया थी लेकिन सरकार ने कुल 14 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की तथा तीसरी योजना के अन्त तक कुल बेरोजगारों की संख्या 12 मिलियन पहुँच गई। यह बेरोजगारी और बढ़ती चली गई तथा 1971 के अन्त तक भारत में कुल बेरोजगारों की संख्या बढ़ कर 21 मिलियन पहुँच गई है। अतः बेरोजगारी की समस्या भारतीय अर्थ व्यवस्था में एक चिकट समस्या बन गई है। योजनावद्ध विकास के साथ-साथ यह बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है।

बेरोजगारी के कारण (Causes of Unemployment)—जहाँ तक बेरोजगारी के कारणों का प्रश्न है प्रत्येक क्षेत्र में इसके कारण भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु कुछ समुक्त सामान्य कारण हैं जिनका विवेचन निम्नांकित शीर्षकों में सम्मिलित है

(1) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि—हमारी अर्थ व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की समस्या है। इसका स्पष्ट अनुमान प्रत्येक दसवर्षीय जनगणनाओं से सहज ही लगाया जा सकता है। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 43 करोड़ थी जो वर्तमान में बढ़कर 54.7 करोड़ के लगभग हो गई है। प्रति वर्ष देश में 2.2 की दर से जन वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप श्रम शक्ति में भी तीव्र वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसर इस तुलना में अत्यधिक कम हैं। अतः जनसंख्या की बढ़ि निरन्तर एवं बुनियादी बेरोजगारी को जन्म दे रही है।

(2) मुद्रोत्तर आर्थिक मन्दी एवं छटनी (Retrenchment)—अन्य देशों की भाँति भारत में भी मुद्रोत्तर आर्थिक मन्दी का गहरा प्रभाव पड़ा। मुद्रोत्तर काल में कई विभाग जो प्रतिस्थापित किए गए थे, जैसे नागरिक मरम्मत विभाग (Civil Supply Department) आदि समाप्त कर दिए गए। उनमें वृत्ति प्राप्त लोग बड़ी संख्या में निकाल दिए गए। छटनी की इस कुत्हाड़ी के परिणामस्वरूप पुराने रोजगार की समस्या पुनः आ खड़ी हुई। इसमें सर्वाधिक कठिन परिस्थितियों में मध्यमवर्ग को पिसना पड़ा। पुनर्वास मन्त्रालय में भी अत्यधिक छटनी मार दी गई।

(3) दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति—हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली एकमात्र कलाओं की जन्मदाता है। देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति का औद्योगिक प्रगति के साथ अपेक्षित सतुल्यता का सर्वथा अभाव है। प्रति वर्ष विद्वत्विद्यालयों से लाजों की संख्या में विद्यार्थी मैट्रिक, इन्टर तथा बी ए आदि पास करके निकलते हैं। जिनको कि रोजगार की संलाह में दबर्-दबर् भटकना पड़ता है। सर एन्डरसन ने पत्राव गतिविधि की तैयारी की गई रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति छात्रों को विदेशी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का एक बाल मात्र था। फलस्वरूप प्रत्येक शिक्षित वर्ग सरकारी भौकरी की तलाश में रहता है। दूसरे, इस शिक्षा-पद्धति ने पैतृक पैसों को भी पसु बना दिया। शिक्षा की यह अनुत्पादकता ही है। किसानों ने भी अपने बच्चों को मौकरी की ओर ही प्रेषित किया है। इसके साथ ही देश में तकनीकी शिक्षा का अभाव है। केवल पुस्तकीय शिक्षा धेकारी की समस्या का उपाय नहीं हो सकती।

(4) कृषि का पिछड़ापन—वर्तमान देश होने के कारण हमारे देश में कृषि पर जन भार अत्यधिक है। कृषि करने के पिछड़े एवं प्राचीन तरीकों के कारण अधिक उत्पादन क्षमता का अभाव है एवं अधिक व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएँ नहीं प्रदान की जा सकती। इससे प्राचीन क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी बढ़ी है।

(5) लघु एवं कुटीर उद्योगों का बर्बाद—एक विशाल जनसंख्यक देश के लिए उसके लघु एवं कुटीर उद्योग-वर्धे प्राणस्वरूप है। देश की पुरानी दासता के कारण उनको उचित सुरक्षण नहीं मिला था। इसके साथ ही मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से सहस्रो व्यक्ति बेरोजगार हो गए। मशीनों द्वारा विशाल पैमाने पर बने वस्तुओं में उत्पादन लागत कम लगती है। फलस्वरूप कुटीर उद्योग दृढ़ प्रतियोगिता में नहीं ठहर सके और उनकी प्रत्यक्ष प्रभाव बेरोजगारी पर पड़ा।

(6) सामाजिक कारण—कुछ जाति-प्रथा, शीघ्र विवाह, समुक्त परिवार एवं सामुदायिक असमानताओं के कारण नवयुवकों की प्रवृत्ति सम्बन्धी महत्वाकांक्षों को ठेस पहुँचती है। जाति-प्रथा नवयुवकों को अल्प छोटे कामों की ओर जाने से रोकती है तो शीघ्र विवाह द्वारा उन पर पारिवारिक बोझ खीज हो लाद दिया जाता है। परिणामस्वरूप प्रगति का क्षेत्र अंधूरा रह जाता है। घर के प्रति मोह की भावना भी बेरोजगारी का एक कारण है।

ऊपर लिखे हुए इन कारणों के अतिरिक्त अकुशल एवं अशिक्षित श्रमिकों की संख्या में कृषि भी बेरोजगारी के पड़ोस का प्रमुख कारण है। डॉ० राव ने इस सम्बन्ध में एक कारण यह भी दिया है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के फलस्वरूप उनकी मातृहृती में कार्य करने वालों के भी रोजगार के साधन नष्ट हो गए। साथ ही स्वयं जमींदार लोग भी औद्योगिकीकरण के लिए नीकरियाँ डकने लगे हैं। इसके साथ ही स्त्रियों में शिक्षा प्रसार के कारण मध्यम श्रेणी की स्त्रियाँ भी रोजगार चाहने लगी हैं। अतः स्पष्ट है कि बेरोजगारी की समस्या को किसी अथवा कुछ पहलुओं में नहीं बाँधा जा सकता।

बेरोजगारी दूर करने के उपाय (Remedies) बेरोजगारी की समस्या दृढ़तरी दिकट एवं गम्भीर है कि इसके लिए किसी एक उपाय को लागू नहीं किया जा सकता। हमारे देश की बेरोजगारी बुनियादी (Basic) है अतः इसके लिए अल्प-कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय कार्य में लाने होंगे। अंगामी विनियमों में इन्हीं उपायों का समावेश है।

(1) अल्प कालीन उपाय अल्प-काल में बेरोजगारी दूर करने के निम्नांकित उपाय कार्य में लाने चाहिए।

(i) योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए कार्यों जैसे सिंचाई एवं अन्तः परिवहन आदि में अथवा मचकों के निर्माण कार्यों में प्रशिक्षण विविधों की स्थापना की जानी चाहिए।

(ii) लघु एवं कुटीर उद्योगों की अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक वस्तियों की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ

कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को नया बर इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(11) जिन दिशाओं में मानवीय शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है उनमें प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही व्यवस्था विद्यालय एवं एक अध्यापक स्कूलों द्वारा प्रशिक्षणों में रूचि ली जाए।

(12) यातायात एवं परिवहन सेवाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं में विकास की प्रवृत्ति अपनाई जाए, जिससे अधिकाधिक जन-संख्या इनमें रोजगार पा सके।

(13) निर्माण-कार्यों के विविध तरीके ग्रहण किए जाए। गृह निर्माण एवं गिरि सम्बन्धी कार्यों की प्रगति इसके लिए अत्यावश्यक है।

(14) सामाजिक एवं निजी क्षेत्रों में सहायक निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(2) दीर्घकालीन उपाय—(1) जनगणना में वृद्धि-दर का कम किया जाए। जनता में कम बच्चों की भावना का विनाश शिक्षा के द्वारा दिया जाए। 'कम सन्तान सुखी इंसान' की भावना के साथ जन-जागरूकता होनी चाहिए।

(2) आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आनी चाहिए। उद्योगों का क्षेत्र विस्तार होना चाहिए साथ ही औद्योगिक विविधता अपनायी चाहिए ताकि रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकें। इनके अन्तर्गत खन प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए एवं निम्नलिखित वन का अधिमात्रा भाग उद्योगों की ओर लगाया जाए।

(3) हमारा एक समस्या कृषि की है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाए साथ ही मिटाई, रासायनिक खादों एवं मीटासुनाबाक दवाइयों के प्रयोग द्वारा कृषि की प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि के प्रयास किए जाए।

(4) वर्तमान शिक्षा पद्धति में व्यवहारिकता को स्थान दिया जाए। तकनीकी प्रशिक्षण को शिक्षा का मूलभूत बनाया जाए। शिक्षा का सम्बन्ध रोजगार में सहायक होना चाहिए। देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

(5) देश में रोजगार कार्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए जो रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं के अतिरिक्त व्यवसायिक क्षेत्र में भी मार्ग-दर्शन करें एवं बाजार सम्बन्धी सूचनाओं का एकत्रीकरण करें।

(6) समय-समय पर सरकार द्वारा पूरक जन-व्यवस्था कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए।

उपर के इन कारणों के अतिरिक्त, अतिरिक्त श्रम शक्ति का प्रयोग उत्पादक कार्यों में किया जाना चाहिए। पारिस्थितिक न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रख

कर दिया जाना चाहिए। शारीक क्षेत्रों में समन्वय द्वारा ग्राम-सुधार जैसे कार्यों में प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ऐसी योजनाओं द्वारा ग्रामों में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, गांव ही तकनीकी ज्ञान में भी नियमितता बचावत बनी रहेगी। इसके साथ ही जन-प्रवाग (Migration) द्वारा देश में जनसंख्या का घनत्व विशेष स्थानों से कम दिया जाए। इसी समस्या की समान रूप से सघनता रहेगी कहीं अधिक कहीं कम की नहीं।

बेरोजगारी दूर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों की रिपोर्टों में भी इन समन्वय में उपाय बताये गए हैं। हमारे देश के भौतिक एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया गया है। मद्रास समिति ने 'शेबीग उपनिवेश' (Farm Colonies) का सुझाव भी दिया था, किन्तु व्यवहारिकता इसमें कम ही है इस समन्वय में पलायन नृत्तिहीनता जाँच समिति ने एक यह भी सुझाव दिया था कि उत्पन्न कक्षाओं में उन्हें छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो तीव्र बुद्धि वाले हों, जिनमें उत्कृष्टता की प्रतिभा हो। यदि ऐसे छात्र निर्धन हैं तो उन्हें सरकारी सहायता प्रदान की जाए। ट्रावनकोर की समिति ने एक सुझाव यह दिया था कि प्रत्येक प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता-परीक्षा रखी जाए।

मध्यम श्रेणी एवं शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी—हमारी वर्तमान बेरोजगारी में शिक्षित वर्गियों की समस्या अति विकट है। इसमें ऐसे शिक्षित व्यक्ति-वर्ग सम्मिलित है जो आर्थिक दृष्टि से इतने मृदु नहीं हैं कि अपने रोजगार की स्वयं व्यवस्था कर सकें। वे लोग शारीरिक श्रम के बोध भी नहीं होते साथ ही सामाजिक श्रेष्ठता उत्कृष्टता की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। एक शिक्षित व्यक्ति का अधिक समय तक बेरोजगार रहना देश की सुरक्षा एवं स्थिरता में बड़ा व्यवधान है। ऐसे लोग अपने लिए आजीवन उद्यम कर अधिष्ठापन उत्पन्न कर सकते हैं।

दूसरे प्रकार की बेरोजगारी प्रायः शिक्षा प्रणाली के दूषित होने का बोध है। प्रतिवर्ष विद्यालय मकान में विद्यार्थियों का शिक्षण-मन्त्रालयों से निकलना तथा शिक्षा का पुस्तकीय होना इनका प्रधान कारण है। वर्तमान शिक्षा पान पुस्तकीय ज्ञान के बल नहीं है जो शिक्षित वर्ग के हाथ पैर काट देती है व उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप में पंगु बना देती है। दूसरे, अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत वाणिज्य, उद्योग आदि का पर्याप्त विकास नहीं है। युवकों का श्रम में निरवकाश नहीं, श्रम का शौर्य, श्रम की महत्ता उनकी दृष्टि में उपेक्षणीय तथा हेम है। युवकों की महत्वाकांक्षा श्रम के स्तर से ऊँची है। इसके साथ ही आत्मनिर्भरता, सयुक्त परिवार प्रथा एवं अन्य सहायक व्यवसायों की सूचना एवं प्रदर्शन के साधनों के अभाव में मध्यम-वर्गीय बेरोजगारी विशेष बड़ी है।

इसके लिए शिक्षा प्रणाली को सुधार कर इसे व्यावहारिक एवं व्यवसायिक रूप दिया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ आर्थिक विभाग के अधिशासिक अवसर समझ आने चाहिए।

अदृश्य एवं कृषि बेरोजगारी—इस प्रकार की बेरोजगारी का यही अर्थ है कि प्रायोग अर्थ-व्यवस्था में अविनाश लोगों को पूर्ण कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। भूमि पर अनाधिक्य भार ही इसका मूल कारण है। कृषकों की यह बेरोजगारी अदृश्य अथवा अप्रत्यक्ष है। वास्तव में दृष्टिगत तो यही होना है कि सभी कार्यों में जुटे हुए हैं किन्तु अनुपात में वे अविन ही हैं।

इसका प्रमुख कारण जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि, कृषि की प्रकृति पर निर्भरता अल्प-विकास अर्थ-व्यवस्था, कृषि का अलाभकारी होना, ग्रामीण बातावरण की प्रतिकूलता, मनुष्य-परिवार-व्रथा, उत्तराधिकार के नियम, आदि हैं। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि ग्राम्य जीवन में शिक्षा का प्रसार किया जाए। साथ ही अर्थ-व्यवस्था को उच्च स्तर में चलाया जाए। शिक्षित जनता स्वयं ही जनवृद्धि का विरोध करेगी। इसके साथ ही भूमि सम्बन्धी बातों में आवश्यक सुधार किया जाए। तीव्र औद्योगीकरण, बुटीर उद्योगों का विकास, कृषि प्रणाली में तत्वीयतम प्रयोग कर उत्पादन क्षमता में वृद्धि, तथा लघु विकास कार्यक्रमों, मिर्चाई, सड़क निर्माण तथा अन्य मार्गजन्य कार्यक्रमों को अपना कर इस प्रकार की बेरोजगारी दूर की जा सकती है।

पंचवर्षीय योजनाएं एवं रोजगार नीति—बेरोजगारी की विषम समस्या को दृष्टिगत में रखते हुए हमारी राष्ट्रीय सरकार ने देश का विकास नियोजन द्वारा करना चाहा। इन योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य लोगों की रोजगार दिनांक रहा है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना हमारी इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण तथा महान् शक्ति में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कार्य की व्यवस्था करना, अनाधिक्य के साथ कुछ रहीं श्रम-शक्ति का उपयोग करना एवं गृह उद्योग एवं कृषि में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना आदि विषय प्रमुख रहे हैं। आवासीय पतितों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किए गए रोजगार सम्बन्धी कार्यों का ही उल्लेख सम्मिलित है।

प्रथम योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रख कर बनाई गई तथा कृषि के विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई। प्रथम योजना के अन्तर्गत उतनी ही बेरोजगारी बनी रही जो कि योजना के प्रारंभ में थी (5 मिलियन व्यक्ति)। कुल रोजगार 4 मिलियन व्यक्तियों को

दिया गया, जो कि प्रथम योजना के अन्त तक कुल 9 मिलियन बेरोजगारों में से थे। प्रथम योजना में रोजगार न बढ़ने का जो मुख्य कारण था, वह यह था कि नए प्रकार के विनियोगों को नहीं जुटाया जा सका तथा मजदूरी और आय में जो वृद्धि हुई उससे व्यक्तियों के उपभोग-स्तर में भी तीव्र वृद्धि हुए, जिससे वचन को नहीं बढ़ाया जा सका। इसके साथ-साथ जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है, रोजगार में वृद्धि नहीं होती बल्कि उस अनुपात में बेरोजगारी फैल जाती है, जिसको कि योजना आयोग ने विशेष महत्व नहीं दिया। योजना आयोग ने कुल मानव-शक्ति का भी ठीक अनुमान नहीं लगाया, जिसके कारण बेरोजगारी और खटपट हुई। अतः प्रथम योजना में सरकार ने देश में रोजगार की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए।

दूसरी योजना—दूसरी योजना के अन्त तक कुल बेरोजगारों की संख्या 9 मिलियन बढ़ चुकी तथा कुल रोजगार इस अवधि में 6.3 मिलियन व्यक्तियों को दिया गया, हालांकि सरकार ने दूसरी योजना में रोजगार की सुविधाएँ अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने का श्रेय इसलिए अपने हाथ में लिया कि दूसरी योजना-उद्योग-प्रधान थी, इसलिए नए उद्योगों के विकास के साथ नए रोजगार के माध्यम भी उपलब्ध कराए जा सके। लेकिन वही विनियोग की समस्या, मानव-शक्ति का गलत अनुमान लगाना, उपभोग-स्तर का बढ़ना, सरकार की गलत नीतियाँ, विदेशी विनियम की समस्याएँ आदि कुछ ऐसी समस्याएँ थी, जोकि देश में रोजगार की सुविधाएँ निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार नहीं उपलब्ध करा सकी। खास तौर से योजना आयोग ने जनसंख्या वृद्धि का अनुमान 1% से लेकर 1.3% के बीच में लगाया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 2% की दर से हुई जिससे मानव शक्ति का अनुमान ठीक प्रकार से नहीं लगाया जा सका।

तृतीय योजना—तीसरी योजना में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने रोजगारों के प्रभावों की व्यापकता एवं सतुल्य, ग्रामीण औद्योगीकरण तथा ग्रामीण निर्माण कार्यों—इन तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया। तीसरी योजना के अन्त तक कुल बेरोजगारों की संख्या 26 मिलियन बढ़ चुकी आये का लक्ष्य था, जिसमें से 14 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देने के बाद 12 मिलियन व्यक्ति तीसरी योजना के अन्त तक बेरोजगार रहे। तीसरी योजना में इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार को लक्ष्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जोकि प्रथम दो योजनाओं में थी। ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए, उनकी पूरा नहीं किया जा सका। चीन के बुद्ध के कारण नए उद्योगों का विकास नहीं किया जा सका तथा साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि 2.5% की दर से हुई, जबकि योजना आयोग द्वारा समाविष्ट दर बहुत ही कम थी।

चतुर्थ योजना—1969 में जिन समय चतुर्थ योजना का प्रारम्भ हुआ, उस समय भारत में कुल बेरोजगारों की संख्या 111 मिलियन थी, जिसमें 25 मिलियन गरीब व्यक्तियों के धर्म-शक्ति में प्रवेश कर जाने से यह संख्या घट कर 41 मिलियन पहुँच जाने का भय है। चतुर्थ योजना के विकास कार्यक्रमों के अनुसार 21 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं तथा बाकी 21 मिलियन व्यक्ति योजना के अन्त तक बेरोजगार रह जायेंगे। 1971 के अन्त तक की बेरोजगारी की संख्या को देखते हुए जोकि 21 मिलियन है, यह आशंका की जा रही है, कि योजना के अन्त तक शायद यह संख्या 30 मिलियन के ऊपर पहुँच जाएगी। सरकार ने रोजगार दिलाने के इन तरीकों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के स्तर में सुधार, टेक्नीकल शिक्षा का विकास, निर्माण कार्यों का विकास, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, प्राकृतिक साधनों को दुरुस्त निकालना, आदि कार्य कर अपने हाथ में लिए हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में देश की अर्थ-व्यवस्था चल रही है, यह रोजगारी और बढ़ती चली जाएगी।

पाचवी योजना—पाँचवी योजना जो कि 1974 से शुरू होने वाली है, रोजगार की समस्या को एक विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षित बेरोजगारों तथा अशिक्षित बेरोजगारों के लिए अलग-अलग सरकारी नीतियाँ बनाई गई हैं। पाँचवी योजना में ग्रामीण निर्माण कार्य, पशु पालन व्यवसाय, लघु उद्योगों के विकास की तरफ सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इन क्षेत्रों का विकास देश की प्राचीन जनता को रोजगार दिलाने के लिए करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पाँचवी योजना में 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए अलग-अलग वर्ग के व्यक्तियों को अलग-अलग रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः पाँचवी योजना में देश में गरीबी तथा बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है।

निष्कर्ष 22 वर्ष के आधिक निपाजन के बाद भी भारत अत्यन्त विपन्न समस्याओं में घिरा हुआ है। गरीबी तथा बेरोजगारी यह दो समस्याएँ ऐसी हैं जो कि किसी भी देश के विकास के कार्यक्रमों में एक विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन भारत सरकार ने अपनी चारों योजनाओं में इन समस्याओं के लिए कोई विशेष कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया। कुछ समस्याएँ तो प्राकृतिक देन हैं और कुछ ऐसी हैं, जिनके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। देश को बढ़ती हुई जनसंख्या, वित्तीय साधनों का अभाव, उपभोग के स्तर का बढ़ना जिससे वस्तु को प्रोत्साहन नहीं मिल सका, अशिक्षा, ओछो-ओकरण का अभाव, वार्षिक चिन्ता की बीनी दर, नवीनतम प्रशिक्षणों की कमी आदि कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, जिनके ऊपर सरकार का ध्यान इन

परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य है। अगर यही गरीबी, अगर यही बेरोजगारी देश में बढ़ती गई तो अवश्यमेव देश में एक ऐसी क्रान्ति आएगी जिसको कि आज का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सरकार को इन दो समस्याओं का समाधान (गरीबी तथा बेरोजगारी) अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर दूर करने के प्रयत्न करते चाहिए।

प्रश्न

- 1 भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उनको दूर करने के सुझाव दीजिए।
- 2 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा उठाए गए कदम बताइये।

तृतीय खण्ड

- 1 भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि
(Agriculture in India's Economy)
- 2 भारत में भूमि का उपयोग, कृषि उपज एवं फसलों का स्वरूप
(Land Utilisation, Agricultural Products and Cropping Pattern in India)
- 3 भूमि का उप विभाजन एवं अपसृष्टन
(Subdivision and Fragmentation of Land)
- 4 भारत में सिंचाई उर्वरक एवं अन्य कृषिवस्तु आदान
(Irrigation, Fertilizers and other Agricultural Inputs in India)
- 5 भूमि व्यवस्था एवं भूमि-सुधार
(Land Tenures and Land Reforms)
- 6 खाद्यान्नों की उत्पत्ति एवं खाद्य नीति
(Production and Food Policy)
- 7 नवीन कृषि नीति
(New Agricultural Strategy)
- 8 भारत में कृषि साख
(Agricultural Credit in India)

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि

(Agriculture in India's Economy)

"Everything may wait but agriculture cannot. There is nothing more important in India to-day than better agriculture"

—Jawahar Lal Nehru

भारत एक कृषि-प्रधान देश है। यह की 70% जनसंख्या कृषि पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर रहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को गांधी का देश तथा कृषि को भारत की अत्मा कहा है। सर्वश्री जेधार एक डेरी ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्वपूर्ण स्थान की चर्चा करते हुए सत्य ही कहा है, "भारत के आर्थिक जीवन में सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कृषि की अत्यधिक प्रधानता है।"

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व

भारत में कृषि के महत्व के सम्बन्ध में जितना लिखा जाय, सोचा है। वास्तव में भारतीय आर्थिक व्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्व का अनुमान हम निम्नलिखित तथ्यों से लगा सकते हैं

1. **जीविका का प्रमुख स्रोत** : भारतवर्ष की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग, प्रत्यक्षरूप से, अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यदि परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित लोगों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो यह प्रतिशत बढ़ कर और अधिक हो जायगा। सन् 1901 से लेकर सन् 1971 तक के जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि कृषि पर निर्भरता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत की तुलना में अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनेडा जैसे विकसित देशों में कृषिकर्मीयों लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी कम है और कहीं-कहीं तो 5 प्रतिशत से भी कम है।

2. **राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत** : कृषि हमारी राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। राष्ट्रीय आय समिति तथा केन्द्रीय माँख्यकीय संगठन द्वारा प्रकाशित आँकड़े इन बातों की पुष्टि करते हैं कि भारतवर्ष में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित रोजगारों,

यथा पशुपालन, वन व्यवसाय, आदि का राष्ट्रीय आय में लगभग 45% योगदान है। भारत में जितनी आय व्यापार, परिवहन व उद्योग-धन्धों से मिला वर प्राप्त होती है, उतनी राष्ट्रीय आय तो केवल कृषि से ही प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय की दृष्टि से भारत को अन्य देशों में तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कृषि का स्थान कितना ऊँचा है। आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा इंग्लैंड में राष्ट्रीय आय का क्रमशः 13, 5 व 4 प्रतिशत भाग ही कृषि से प्राप्त होता है।

3 राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत : भारतवर्ष में राज्य सरकारों की कृषि से पर्याप्त आय प्राप्त होती है। कृषि-क्षेत्रों से मिलने वाली मालगुजारी उनकी आय का एक महत्वपूर्ण एवं स्वाधीन साधन है। राज्य सरकारों के बजटों में करोड़ों से प्राप्त आय का 30 से 50 प्रतिशत भाग तथा कुल आय का लगभग 15 प्रतिशत भाग भू-राजस्व या मालगुजारी से ही प्राप्त होता है। कृषि भूतकाल में भी सरकार की आय का प्रमुख स्रोत थी और आज भी प्रमुख स्रोत बनी हुई है।

4. खाद्य सामग्री की उपलब्धता : भारत में 54.7 करोड़ जनसंख्या तथा 40 करोड़ पशुओं के लिये भोजन एवं चारा कृषि में ही प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवश यदि किसी वर्ष कृषि की दशा बिगड़ जाती है तो देश को अल्प देनों में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। गांधारणा आवश्यक खाद्य पदार्थों का केवल 5 प्रतिशत भाग ही बाहर से भगवाना पड़ता है और शेष देश में ही उपलब्ध हो जाता है।

5 औद्योगिक विकास के लिये कृषि का महत्व : कृषि हमारे देश के प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति का स्रोत है। सूती वस्त्र उद्योग, गठमन उद्योग, पीनी उद्योग, वनस्पति घी तथा तेल उद्योग एवं बगान उद्योग, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित हैं। बहुत से कुटीर व लघु उद्योग, यथा हाथ करपा बुनाई, तेल पेरना, चावल गूटना आदि, भी कच्चे माल के लिए कृषि पर ही आश्रित रहते हैं। फलों का उद्योग, अचार-मुरब्बा उद्योग, मधु-मखली, मुरी-पालन आदि भी कृषि पर निर्भर रहते हैं। यही नहीं, कृषि उद्योगों के लिए वास्तवीय श्रम शक्ति प्रदान कर औद्योगीकरण में सहायता प्रदान करती है। कृषि विकास औद्योगिक विकास को एक आधार प्रदान करता है और मजिध में आधुनिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

6 रोजगार का प्रमुख साधन मनु 1971 की जनगणना के अनुसार 68.63% भारतीय कार्यशील जनता को कृषि रोजगार प्रदान करती है। 1 अप्रैल, 1971 को भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या लगभग 18.4 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 42.87 प्रतिशत व्यक्ति किसान थे तथा 25.76 प्रतिशत खेतिहर किसान थे।

7. **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का महत्व** : भारतवर्ष से निर्यात को जाने वाली वस्तुओं में तिलहन, तम्बाकू, चाय, जूट, लाख, मसाले आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सभी वस्तुएँ कृषि से ही प्राप्त की जाती हैं। सन् 1941 ई० से पहले भारत के निर्यात का तीन-चौथाई भाग कृषि उपजों का ही था। आज भी लगभग 50 प्रतिशत निर्यात होने वाली वस्तुएँ कृषि से ही प्राप्त होती हैं। यही नहीं, यदि निर्यात होने वाली निमित्त वस्तुओं में 20 प्रतिशत कृषि अन्न को और मिला लिया जाय तो कुल निर्यात में कृषि का योगदान 70 प्रतिशत के लगभग हो जायेगा। भारत में केवल चाय का निर्यात ही प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये का होता है।

8. **सरकार के विभिन्न ढाँचे का आधार** भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वित्त-व्यवस्था बहुत सीमा तक कृषि पर ही आश्रित है। माछागुजारी के अद्विष्टिका बिक्री कर, सिंचाई-कर, कृषि व्याप-कर, सम्पत्ति-कर व मुगार-कर, स्टाम्प फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इत्यादि राज्य सरकारों की आय के प्रमुख साधन हैं, जो कृषि पर निर्भर लोगों से ही प्राप्त होते हैं। केन्द्रीय सरकार भी इसी प्रकार कृषि-पदार्थों के निर्यात में निर्यात कर तथा कृषि पर आधारित उद्योगों की उत्पत्ति से उत्पादन कर प्राप्त करती है। भारत में कृषि की दशा ठीक रहने पर ही वित्त मंत्री अपने बजट को समुचित रख सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए किसी विद्वान ने यह ठीक ही कहा है कि 'भारतीय बजट मानसून पर निर्भर जुड़ा है।'

9 **परिवहन के लिए कृषि का महत्व** : भारत कृषि-प्रधान देश होने के नाते ग्रामों का देश है। यहाँ परिवहन के साधनों को मुख्यतः रेलों को जितनी आय कृषि-उत्पन्न तथा कृषक जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने से जाने से होती है, उतनी आय अन्य उद्योगों से नहीं हो पाती। परिवहन के साधनों के अति-मित्त मदेस वाहन के साधनों—ऑन एव तार सेवाओं—को ही कृषि में पर्याप्त आय प्राप्त होती है। अतः कृषि परिवहन एवं उद्देश वाहन के साधनों के विकास को प्रोत्साहित करती है।

10 **कृषि का आर्थिक नियोजन में महत्व** : भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि को प्रधानता दी थी। इस योजना की सफलता का मुख्य कारण भी कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि ही था। दूसरी योजना में कृषि को शीर्ष स्थान देने के कारण ही वह पूर्ण सफल नहीं हो सकी। तृतीय योजना में पुनः कृषि को आवश्यक महत्व दिया गया है। तृतीय योजना के बाद बनाई गई वार्षिक योजनाओं में भी कृषि को विशेष महत्व दिया गया है। भारत की चतुर्थ योजना एवं आगे जाने वाली अन्य योजनाओं में भी कृषि के महत्व को कम नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अमफलता हमारी सारी योजनाओं को चौपट कर सकती है।

11. कृषि ।। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्व : भारतीय कृषि को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष महत्व प्राप्त है। चाय, भुगुफली व गन्ने के उत्पादन में भारत का स्थान संसार में प्रथम है। तिलहन, तम्बाकू, पटसन आदि के उत्पादन में भी भारत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि की उपज में भारत को विदेश के कृषि-उपज-मानचित्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

12 मूल्य-स्तर को प्रभावित करने में कृषि का महत्व : मूल्य-स्तरों के स्थायित्व के सम्बन्ध में भी भारतीय कृषि का विशेष महत्व है। भारत में मूल्य-स्तर कृषि उपजों से प्रभावित होते हैं। जिस वर्ष उपज कम होती है, उस वर्ष आद्यान्नों के मूल्य चढ़ जाते हैं, फलस्वरूप अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि उपज अच्छी होती है तो आद्यान्नों का मूल्य गिर जाता है, फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी गमी आ जाती है। अतः भारत के मूल्य-स्तर पर कृषि उपजों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

13 आन्तरिक व्यवसाय एवं वैकिंग व्यवस्था के क्षेत्र में कृषि का महत्व— भारत के आन्तरिक व्यापार में कृषि का बहुत अधिक महत्व है। सब्जों की मरिया एवं मसूरों के व्यापारिक क्षेत्रों में प्रायः जो कुछ व्यापार होता है, उसमें कृषि उपज की ही प्रधानता होती है। इसी प्रकार भारतीय वैकिंग व्यवसाय भी बहुत कुछ परोक्ष रूप में कृषि पर ही आश्रित है। भारत में भारी वैकिंग व्यवसाय का विकास एवं प्रगति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि वैक कृषि क्षेत्र में अपनी मात्रा का कितना विस्तार करते हैं।

14 कृषि का राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्व—कृषि का भारत में राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी महत्व है। कृषक भारतीय गणतन्त्र के बहु-संख्यक नागरिक हैं। राज्य की विधान सभाओं एवं देश की लोक सभा में उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत है। वे राज्य के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। इसीलिए राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उनका विशेष प्रभाव है। देश की रक्षा के लिए भी इनमें से ही सैनिक प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कृषि का बहुत अधिक महत्व है। समस्त देश का आर्थिक ढांचा ही एक प्रकार से कृषि पर आधारित है। भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्वपूर्ण स्थान को दृष्टिकोण में रखते हुए ही बी. जॉन (सन) ने एक स्थान पर उद्धृत की श्रुति है, “यदि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार करना है, तो यहाँ की कृषि को उन्नति करनी चाहिए।” यदि भारतवर्ष में कृषि असफल रहती है तो यहाँ की समस्त अर्थ-व्यवस्था असफल हो जायेगी। अतः आर्थिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में यह एक निश्चित मत बनता जा रहा है कि आर्थिक विकास की गतिविधियों के

लिए एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। विद्वान् अर्थशास्त्री 'फ्रेड एव हूवर' ने भारतवर्ष के सदस्य में ठीक ही कहा है कि "अर्थ-व्यवस्था के पिछड़े हुए जग (कृषि) का विकास सम्पूर्ण आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है और यदि कृषि विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो सम्पूर्ण आर्थिक विकास गतिहीन हो जावेगा।" भारत की आर्थिक व्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, इसका अंशाल भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लार्ड मेयो (Mayo) के निम्न-लिखित कथन से भी समझा जा सकता है—

"आने वाली अनेक पीढ़ियों तक धन एवं सम्यक्ता के विकास की दृष्टि से भारत की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से उसकी कृषि की प्रगति पर ही निर्भर करेगी। ससार में सम्भवतः कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका कृषि में इतना प्रत्यक्ष, सीधा एवं घनिष्ठ स्वार्थ निहित है। भारत सरकार केवल सरकार ही नहीं, अपितु एक भू-स्वामी भी है।"¹

भारतीय कृषि की पिछड़ी हुई दशा

(Backwardness of Indian Agriculture)

यद्यपि भारत एक कृषि-प्रधान देश है, तथापि यहाँ की कृषि अवस्था अत्यन्त पिछड़ी हुई है। ग्राही कृषि कमोन्स के सामने अपनी गवाही देते हुये भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि सलाहकार डॉ० नवाटटन ने कहा था, "भारत में हमारी पिछड़ी हुई जातियाँ तो हैं ही, हमारे पिछड़े हुए उद्योग भी हैं और इन उद्योगों में से दुर्गम-वश कृषि भी एक है।"² उन्होंने दली राम्बन्ध में यह भी कहा था, "हम चाहे जिस दृष्टिकोण से देखें, कृषकों के स्वतंत्रता का आकार व बनावट, प्रयोग में आने वाले कृषि औजार व खाद, फसलों के हेर-फेर (Rotation of crops) की पद्धति, बीजों का गुण, सिंचाई-सुविधाओं एवं भूमि-सुधार सम्बन्धी स्थिति, बिक्री-व्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था, सहायक उद्योग, सभी दृष्टिकोणों से हमारा कृषि-उद्योग अत्यधिक पिछड़ी हुई स्थिति में है, जिसके फलस्वरूप कुल एवं प्रति एकड़ उत्पादन अत्यधिक कम है, जो अन्य देशों में पैदा होने वाली उपज का प्रायः एक-तिहाई या एक-बीयाई भाग होता है और यह भी मूसल या अकाल के समय लगभग ख़ुब हो जाता है।

1 "For generations to come, the progress of wealth and civilization in India must be dependent on her progress in agriculture. There is perhaps no country in the world in which the state has so immediate and direct interest in agriculture. The Government of India is not only a Government but also the chief landlord."

—Lord Mayo

2 "In India we have our depressed classes, we have our depressed industries, and agriculture—fortunately, as one of them."

Dr. Clouston

डॉ० क्लाउस्टन का मत है कि भारतवर्ष की कृषि उपज अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक कम है। निम्न तालिका में भारतवर्ष के कृषि-उत्पादन की तुलना सप्ता के कुछ प्रमुख देशों से की गई है—

प्रति हेक्टर किलोग्राम में भू-उपज (1968 में)

देश	उपज	देश	उपज
धान		कपास	
भारत	1610	भारत	120
जापान	5720	रूस	830
संयुक्त अमेरिका	4960	मैक्सिको	730
गेहूँ		मूँगफली	
भारत	1100	भारत	650
इंग्लैंड	3550	जापान	2070
मक्का		अमेरिका	
भारत	1000		
अमेरिका	4930		
फ्रांस	5260		

भारत की कृषि उत्पादकता में वृद्धि बड़ी धीमी गति से हो रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में भूमि की उत्पादनशीलता सामान्यतः बढ़ती रही है तथा उसे बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये। जब से भारत में व्यापिक नियोजन का प्रारम्भ हुआ है तब से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वर्ष 1949-50 से 1970-71 की अवधि में कृषि की उत्पादकता में जो वृद्धि हुई है, वह निम्नलिखित तालिका से जाना जा सकती है

कृषि-उत्पादकता सूचकांक

वर्ष	साधारण उत्पादकता	घैर साधारण उत्पादकता	सभी पशुओं की उत्पादकता
1949-50	100	100	100
1960-61	117	106	118
1965-66	106	103	110
1970-71	146	118	141

भारतवर्ष में कृषि में प्रति भूमि उत्पादन भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में कृषि-कार्य के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, उससे वही अधिक व्यक्ति लिये हुए हैं। कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता के सम्बन्ध में डॉ० बलजीतसिंह का अनुमान है कि भारत में औसत वार्षिक खन-उत्पादकता (हासरो में) 105 है, जबकि नार्वे, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व एशियाई जर्मनी में क्रमशः 973, 2157, 2126, 2265, 2408, 2442, 3461, 3495 है।¹

भारतीय कृषि के पिछड़े होने के कारण

भारतवर्ष में कृषि पिछड़ी हुई वशा में है, यह बात ऊपर के भूम्यपन से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। इस पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं —

1. जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार—जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण भारतीय कृषि अत्यधिक ही गई है, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ाव के कारण खेत छोटे-छोटे हो गये हैं जिन पर लाभदायक कृषि नहीं की जा सकती। खेतों को न तो परती छोड़ा जा सकता है और न ही पर्याप्त मात्रा में खाद दी जा सकती है। प्रो० जॉन ई० रसेल (John E. Russell) का अनुमान है कि भी एकड़ भूमि पर पोलैंड में 31 व्यक्ति, रमानिया में 30 व्यक्ति, यूगोस्लाविया में 33 व्यक्ति तथा फिनेन में केवल 6 व्यक्ति काम करते हैं, जबकि भारत में प्रायः इतनी ही भूमि पर 148 व्यक्ति काम करने हैं। एतदवस्था में भारत में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है।

2. खेतों का छोटा आकार—भारत के खेत बहुत छोटे हैं। यहां किसानों की छोटे-छोटे खेतों में, जो काफी दूरी में बिखरे हुए होते हैं, खेती करनी होती है। इससे उनकी समय व श्रम गंष्ट होता है। वे आधुनिक कृषि-यन्त्रों के प्रयोग से भी वंचित रह जाते हैं। भारतवर्ष में औसत जोत का आकार लगभग 7.5 एकड़ है, जबकि जर्मनी में 21 एकड़, इंग्लैंड में 62 एकड़, डेनमार्क में 80 एकड़ तथा अमेरिका में 145 एकड़ है। इस प्रकार खेतों का आकार आकर कृषि उपज की वृद्धि के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है।

3. खेती के पुराने ढंग—भारतीय कृषक सद्विवेकी हैं। वह आज भी उसी

पुराने तरीको से खेती करता है जिससे उपज नही बढ़ सकती।¹ न तो खेती की ढंग से खाद दे पाता है और न ही आधुनिक तरीको का इस्तेमाल। हकीर के फकीर होने के कारण उसकी खेती की हालत आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, जबकि समार के अन्य देश कृषि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से कृषको द्वारा आधुनिक ढंग के बन्धों का, जैसे गुपरे हुए हल, पॉपमॉर्ट, चारा काटने की मशीनें आदि के प्रयोग किये जाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इनका उपयोग अभी बहुत सीमित है। डॉ० विलियम कैप के अनुसार ट्रैक्टर द्वारा एक एकड़ ज़मीन बनाने पर केवल 3 रु० 14 पैसे लागत आती है जबकि दुर्बल पशुओं द्वारा 9 रु० 83 पैसे। इसमें बन्धों के बारे पर 6 रु० 88 पैसे व्यय होय जबकि ट्रैक्टर के पेट्रोल पर केवल 1 रुपया ही व्यय होगा।²

4 खाद का अभाव—भारत में खेतों की गोबर की खाद की कमी है। देश में गोबर का प्रयोग उपज बनाने में जो किया जाता है, फलस्वरूप लगभग 555 मिलियन टन गोबर उपजों के रूप में जला दिया जाता है। हड्डी, मछली या आधुनिक नई खादों का प्रयोग बहुत कम है, फलस्वरूप उत्पादकता भी बहुत कम है। रासायनिक खाद खरीदने की क्षमता न होने के कारण किसान खेतों की आवश्यक खाद नहीं दे पाता।

5 उत्तम बीजों का अभाव—भारत में अच्छे बीजों की ही कमी प्रायः, एता नहीं है। प्रायः किसान के पास जो बीज होते हैं या गांव के महाजन या शनि में जो बीज मिल जाते हैं, निम्न ऊर्ध्व ही वो देता है। अच्छे बीजों के अभाव में अच्छी फसल की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रगतिशील बीजों का प्रयोग केवल 18 से 20 प्रतिशत ही होता है।

6 पशुओं के द्वारा खेती—भारत में जिन पशुओं द्वारा खेती की जाती है, वे प्रायः दुर्बल होते हैं। न तो उन्हें भर पेट चारा मिल पाता है और न बीमारियों

1. The farmer by using the old type of wooden plough and light appliances works on the field. The plough that looks like a half open pen knife and just scratches the soil and hand sickle made for a child then for a man the old fashioned iron wing tray that wags the seed to shift the grain from the chaff and rude shopper with its waste of fodder, are made placed from their primitive and unmemorial functions."

—M. L. Darling Punjab Peasant in Prosperity and Debt p. 157

2. Dr. K. William Kapp Hindu Culture Economic Development & Planning in India p. 131.

में मुक्ति, ऐसे पशु खेती की उपज बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाते। पशुओं की नस्ल भी घटिया किसम की है। कमजोर एवं घटिया किसम के पशुओं से गहरी जुताई सम्भव नहीं होती और बिना गहरी जुताई कृषि उपज नहीं बढ़ाई जा सकती।

7. फसलों के रोग, कीटाणु व बूहों द्वारा क्षति—समय पर पानी व खाद न मिलने के कारण फसलें प्रायः रोगग्रस्त हो जाती हैं एवं उनमें कीड़े लग जाते हैं, जो फसलों को चोष कर देते हैं। प्रायः टिड्डियों के दल अच्छी खेती हुई फसल को चट कर जाते हैं। राष्ट्रीय व्यावहारिक शोध परिषद (N C A E, R.) का अनुमान है कि भारत के कुल खाद्यान्न का 15 प्रतिशत भाग कीड़े-भेड़ों, टिड्डियों व बूहों द्वारा खेतों में नष्ट कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत अनाज गंदासी में कीटाणुओं व बूहों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 1500 करोड़ रु० की क्षति हो जाती है।

8. कृषकों की निर्धनता—भारतीय दृष्टक अत्यधिक निर्धन है। वह मुश्किल से अपना भरण-पोषण कर पाता है। खेतों में सुधार सम्बन्धी कार्यों को करने के लिए उसके पास धन का अभाव रहता है और वह उपज बढ़ाने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। फलस्वरूप कृषि की अवस्था पिछड़ी की पिछड़ी हो रह जाती है। निर्धनता दृष्टक को कृषि विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। वह कृषि को लाभ की भावना से न करके सुझर पसर करने की भावना मात्र से करता है, अतः कृषि विकास में किसी आश्चर्यजनक प्रगति की कल्पना करना व्यर्थ है।

9. कृषकों की शिक्षा—अशिक्षित होने के कारण किसान छड़ियाड़ी है। वह कृषि उपज बढ़ाने के महत्व की भली भाँति नहीं समझ पाता। प्रायः अपनी क्षति एवं साधन फालतू कार्यों में गवा बैठता है, यथा मुक्कमनाजी एवं सादी-बिवाह के अवसर पर पानी की गरह पैसा उहा देता है। यदि इसे वह कृषि उपज बढ़ाने में प्रयोग करे तो उपज निश्चय ही कुछ न कुछ बढ़ सकती है, पर अशिक्षित होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता।

10. सिंचाई के साधनों का अभाव—भारत जैसे कृषि-प्रधान देश की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है जो अनिश्चित रहती है। अतः सिंचाई के साधनों पर किसानों को आश्रित रहना पड़ता है। मोस्त (Knowels) ने इस सम्बन्ध में टीक ही कहा है, "भारत में मानसून न जाये तो कृषि उद्योग में ताले-बन्दी हो जाए।"¹ भारतवर्ष में कुल कृषि-योग्य भूमि में 22 प्रतिशत को कृषि साधन द्वारा सिंचाई की जाती है तथा 78 प्रतिशत को प्रकृति की कृपा पर छोड़ दिया जाता है। डॉ० केंप

1 "If monsoon fails, there is a lock out in Agricultural industry in India."

के अनुसार सप्ताह पर उपलब्ध जल सम्पदा का 40 प्रतिशत से भी कम भाग सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

11 प्राकृतिक प्रकोप—भारत में प्रतिवर्ष बाढ़ों से करोड़ों रुपये की कृषि उपज नष्ट हो जाती है। नमी-नमी इसी प्रकार सूखा पड़ने से, वर्षा के अभाव में करोड़ों रुपये की कमल सूख कर नष्ट हो जाती है। इस प्रकार भारत अनिश्चित, अनाश्चित, समय से पूर्व कृषि तथा समय के बाद कृषि की समस्या निरन्तर बनी रहती है। वर्षा की इस अनिश्चितता तथा अनियमितता के कलम्बर में कृषि की प्रायः भीषण क्षति उठानी पड़ती है। वस्तुतः भारतीय कृषि 'मानसूनी जुआ' बनकर रह जाती है। यही नहीं, भूमि-कटाव तथा उर्वरा शक्ति के क्षय का भी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

12. कृषकों की श्रमप्रस्तता—भारतीय कृषक श्रम में अन्य लोग हैं, बड़ना है एक मर शणा है, मर कर श्रम का भार अपनी सनानों पर छोड़ जाता है। खेती में पैदावार एक तो ज्यादा होती ही नहीं और यदि किसी वर्ष अच्छी फसल हो भी गई तो किसान किजूर-खर्ची में घन गवा बैझा है और श्रमी या श्रमी बना रहता है। श्रमप्रस्तता सामाजिक नियम देनी के पिछड़ेपन को नहीं सुधार सकता।

13 फसलों की बिक्री की असुविधा—भारतीय ग्रामों में परिवहन के साधनों का अभाव है। भारतीय कृषक गांव के साहकायों के श्रमी होते हैं। इस सबका प्रभाव पड़ता है कि गांव में ही उसे अपनी फसल बेचनी पड़ती है। उसे अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि गांव में प्रायः बहुत कम मूल्य पर उसे अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य होता पड़ता है।

14 कुटीर उद्योगों का पतन—गांव में कुटीर उद्योगों के पतन के परिणाम-स्वरूप कृषकों की आयदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो गया है। जब वे बेरोजगारी या अर्ध-बेरोजगारी के दिवार हो रहे हैं। सभी लोगों के खेती पर आश्रित होने के कारण खेती भी अनार्विक हो गई है और उपज उत्तरोत्तर घटती जा रही है। कुटीर उद्योगों के पतन ने कृषकों को निर्धन बना दिया है। फलस्वरूप वे कृषि में पन लगाने में असमर्थ हैं।

15 रोगपूर्ण लगान प्रथा—जयेंजों के समय जमींदारी प्रथा ने कृषि-सुधार के रास्ते में रोड़े अटकाये थे। वर्तमान समय में यद्यपि कृषक भू-स्वामी हो गया है, पर बहुत से किसानों को बोले अनार्विक है, जग में लगान देने में असमर्थ है। परन्तु उन्हें कुछ न कुछ लगान अब भी देना ही पड़ता है। लगान का यह भूत उन्हें हमेशा मताता रहता है और उन्हें मन लगा कर खेती नहीं करने देता।

16 किसानों का गिरा हुआ स्वास्थ्य—भर-पेट भोजन न मिलने के कारण किसान प्रायः दुबल रहता है। उन पर भी महाभारतियों का प्रकोप उसे और भी दुर्बल एवं अकार्यकुशल बना देता है। बीमारियों में प्रायः उसे प्रकृति का ही सहारा लेना पड़ता है। स्वास्थ्य के बिना हुए होने के कारण किसान खेतों में अधिक परिश्रम नहीं कर पाते। बिना रक्तिन परिश्रम के कृषि की उपज को बढ़ाना सम्भव नहीं है।

17 निराशावादी एवं भाग्यवादी दृष्टिकोण—भारतीय किसान 'भाग्य' पर भरोसा करता है और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। भाग्यवादी होने के कारण वह सालभर धन खर्च करता है। अभावों से भरी जिन्दगी उसमें निराशा पैदा करती है और यह फिर किसी भी कार्य में मन नहीं लगा पाता। परिणामस्वरूप, कृषि किसान के नष्ट दृष्टिकोण के कारण पिछड़ी रह जाती है।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषि प्रणाली अत्यन्त दीर्घपूर्ण है। यह परम्पराओं से जकड़ी हुई है। श्री अशोक मेहता ने तीन ही कहा है, 'कृषि के क्षेत्र में स्थिरता की स्थिति हो एक परम्परागत समाज का मुख्य लक्षण है। ऐसे समाज में पुरानी छिमी पिटी कृषि की पद्धतियाँ, पानी या उर्वरकों का अपर्याप्त उपयोग विस्तृत रूप में भूमि की खराब एवं मिट्टी का कटाव, जमजोर व अलमन्नद जग के बीज तथा पुराने खेतों के जल देखने को मिलते हैं।'¹

कृषि की पिछड़ी हुई दशा को सुधारने के सुझाव

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन को दूर करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम न तो देश को आजाजनों के मामले में आत्म निर्भर बना सकते हैं और न ही देश की सम्पूर्ण आर्थिक अवस्था को ही सुधार सकते हैं। यदि भारतवर्ष का आर्थिक उत्थान करना है तो भारतीय कृषि में सुधार परमावश्यक है। बिना कृषि सुधार के देश की दमनीय दशा से छुटकारा पाना असम्भव सा लगता है।

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नान्वित सुझाव महत्त्वपूर्ण हैं—

1 आर्थिक जोतों का निर्माण—भारत में कृषि जोतों और अधिक उप-विभाजन एवं अपसंखन से रोकना जाना चाहिए तथा खेतों के न्यूनतम आकार को निश्चित कर दिया जाना चाहिए ताकि कृषि खेत अनाधिक न हो सके। जो खेत छोटे-छोटे हैं और बिखरे हुए हैं, ऐसे खेतों की चक्कन्दी कर दी जानी चाहिए। चक्कन्दी के अनिवार्य सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

1 Ashok Mehta Presidential Address to the 24th Conference of the Indian Society of Agricultural Economics, Dec., 1964

2. मिनाई की उत्तम व्यवस्था—यद्यपि मिनाई की बड़ी-बड़ी योजनायें देश में चल रही हैं और इस क्षेत्र में काम भी किया गया है तथापि खेतों के विस्तृत क्षेत्र अब भी मिनाई की सुविधाओं से वंचित हैं। कुओं, तालाबों, नहरों एवं ट्यूब वेलों की सुविधाये क्षेत्र के अनुकूल बढ़ाई जानी चाहिए। मिना पम्पाउट मिनाई के साधनों के अच्छे बीज तथा उर्वरकों आदि के प्रयोग से अधिक लाभ नहीं उठाना जा सकता। भारत में विभिन्न मिनाई योजनाओं के बावजूद भी अनेक देश के कुल जल-स्रोत का केवल 10 प्रतिशत भाग ही मिनाई के लिए प्रयुक्त होता है, शेष जल व्यर्थ बहा जाता है। अतः कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए उपलब्ध जल का अत्युत्तम उपयोग होना चाहिए।

3 भू-जनसंसार पर रोक—ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की प्रभावशाली दम में फैलावा जाय ताकि जनन-वृद्धि न बढ़ सके, लोगों के खेत अधिक बने रहें, उनकी स्थिति सुधर सके और वे कृषि सुधार में अपना योगदान दें सकें। लोगों को कृषि के अनिवार्य अन्य उद्योगों में रोजगार देकर भी भूमि पर जनसंख्या कम किया जा सकता है।

4 कुटीर उद्योगों का विकास—कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास से भूमि पर जनसंख्या की निर्भरता कम हो जायगी, लोगों की आयदनी बढ़ेगी और लोग खेती में सुधार कर सकेंगे। कृषि पर उचित ध्यान होने से कृषि पुनः लाभदायक घन्टा हो सकेगी। जहाँ कृषि क्षेत्र की बेकारी एवं अर्द्ध-बेकारी को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिये।

5 कृषि-यन्त्रों का प्रयोग : सरकार को अपने उपयुक्त खण्डों के माध्यम से खेतों के उपज एवं आधुनिकतम यन्त्रों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को उचित एवं कम मूल्य पर कृषि-यन्त्र प्राप्त हो सकें और वे इनको महामना में कृषि-उत्पन्न बढ़ा सकें। कुछ मिला कर भाग में 12,500 एकड़ पर एक ट्रैक्टर है, जबकि अन्य देशों में इतने ही कृषि क्षेत्र पर ट्रैक्टर इस प्रकार हैं, जापान 9, पश्चिमी जर्मनी 33, डेनमार्क 57 तथा ब्रिटेन 106। उत्पादन वृद्धि के लिए कृषि यन्त्रों में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है।

6 उत्तम कोटि के बीजों का प्रयोग—सरकार को विभिन्न कमलों के उत्तम बीजों के सम्बन्ध में अनुसंधान करना चाहिए तथा उचित मूल्य पर इन बीजों को किसानों तक पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से कृषि उपज में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके लिए प्रत्येक जिले में सरकारी अथवा सहकारी फार्मों की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ गुणवत्ता के बीजों को खेती करके उनकी मात्रा बढ़ाई जा सके। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे बीज गोदामों की स्थापना भी की जानी चाहिए।

7 खाद का प्रयोग देश में होने वाले गोबर वा दुग्धयोग रोकना चाहिए तथा उसे केवल खाद के रूप में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। प्रचार द्वारा किसानों को अच्छी खाद के महत्व में परिचित कराना चाहिए। रासायनिक खाद को, जो अपने देश में बनाई जा रही है, उचित मूल्य पर वितरित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उचित प्रकार की खादों से कृषि उपज को दूना किया जा सकता है। भारत में लगभग 10 लाख टन में भी अधिक रासायनिक खाद की मांग है, जबकि आयात तथा देश के उत्पादन से केवल 6 लाख टन खाद ही उपलब्ध हो पाती है। अतः खाद के उत्पादन में वृद्धि तथा इसके वितरण में सुधार करके इसका कृषि उपज बढ़ाने के लिए संयोजित उपयोग किया जाना चाहिए।

8 पशुओं की रक्षा में सुधार खेती के नर्च में माने वाले तमान पशुओं की पालने की पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए। उनके रोगों के इलाज एवं उनकी नस्ल सुधारने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ लोगों का यह भी सुझाव है कि बूढ़ एवं शक्तिहीन पशुओं को बिनष्ट कर दिया जाय इससे बचे हुए पशुओं की भरपूर चारा मिल सकेगा तथा पशु-नस्ल सुधर सकेगी।

9 सहकारिता का प्रसार : गावों में सहकारी आन्दोलन का विकास किया जाना चाहिए। सहकारी खेती, सहकारी कृषि साज, सहकारी विपणन व्यवस्था आदि किसानों की अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाई जा सकती है। भारतीय कृषि की पिछड़ी हुई दशा से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह सहकारी आन्दोलन ही है।

10 कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार : भारतवर्ष की भूमि का एक बहुत बड़ा भाग बेकार पड़ा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार भारत की लगभग 80 करोड़ एकड़ भूमि में से केवल 32 करोड़ एकड़ भूमि में ही कृषि की जाती है। शेष भूमि जंगल, मरुस्थल, अथवा बंजर के रूप में है। जल जंगलों को साफ करके तथा मरुस्थलीय भूमि में मिर्चाई सुविधाओं का विस्तार करके कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि की जानी चाहिए। तराई की सादर योजना, उड़ीसा की दण्डकारण्य योजना एवं उत्तरी राजस्थान की नहरी मिर्चाई योजनाओं की भाँति अन्य योजनाएँ अपनाई जानी चाहिए।

11 अन्य सुझाव : कृषि अवस्था को सुधारने के लिए अन्य अनेक सुझाव दिये जा सकते हैं, यथा (क) फसलों की फीटाखुओं से रक्षा की व्यवस्था, (ख) कुपकों में शिक्षा प्रसार, (ग) भूमि संरक्षण की व्यवस्था, (घ) कृषि विपणन की उचित व्यवस्था, (ङ) ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के साधनों का विकास, (च) कृषि साज की व्यवस्था, (छ) कृषि के क्षेत्र में नए-नए अनुसंधानों द्वारा उपज बढ़ाने के लिए प्रयत्न (ज) फसल प्रतियोगिताओं द्वारा कुपकों का प्रोत्साहन, तथा (झ) कुपकों में कृषि के प्रति अभ्यावादी दृष्टिकोण पैदा करना आदि।

सक्षेप में, भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में, जहाँ कृषि को देश की अर्थ-व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, कृषि की उन्नति मुख्यतः उत्तम खाद, अच्छे बीज, कीटे-मकोड़ों को मारने की दवा तथा सिंचाई की सुविधा आदि पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में प्रो लिविस (Lewis) का निम्नांकित कथन महत्वपूर्ण है

"The secret of rapid agricultural progress in the under-developed countries is to be found much more in agricultural extension in fertilisers, in new seeds, in pesticides and in water supplies than in altering the size of the farm, introducing machinery, or in getting rid of middle-men in marketing operation"¹

प्रश्न

1 हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्व का विश्लेषण कीजिए और भारतीय कृषि में कम उत्पादकता के कारणों का उल्लेख कीजिए।

(राज० वि० वि० प्रथम वर्ष टी० जी० सी० 1965)

2 भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताइये। आपके मतानुसार कृषि के पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन-सा है? उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए।

(रा० वि० वि० बी० ए० 1962)

3 कृषि उपज कम होने के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(रा० वि० वि० बी० ए० 1963)

4 भारतीय कृषि-सुधार को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए और यह भी समझाइये कि इससे यदि अधिक तीव्र कैसे की जा सकती है?

(राज० बी० ए० 1966)

5 भारत में प्रति एकड़ कृषि उत्पात्ति कम होने के क्या कारण हैं? इन्हें बढ़ाने के उपाय बताइये।

(आयरा बी० ए० 1962)

6 भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएँ कौन सी हैं। उनको हल करने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

(राजस्थान प्रथम वर्ष टी० जी० सी० क्लास 1969)

भारत में भूमि का उपयोग, कृषि-उपज एवं फसलों का स्वरूप

(Land Utilisation, Agricultural Products and Cropping Pattern
in India)

"Every village's first concern will be to grow its own food crops and cotton for its cloth. It should have a reserve for its cattle, recreation and playground for adults and children. Then if there is more land available it will grow useful money crops thus excluding tobacco, opium and the like."

—MAHATMA GANDHI

भारत में भूमि का उपयोग (Land Utilisation in India)

किसी देश के आर्थिक विकास में उस देश की सम्पूर्ण भूमि का प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु उस भूमि के केवल उस भाग का प्रभाव पड़ता है जिसका किसी न किसी आर्थिक क्रिया में उपयोग किया जा सके। किसी देश की समस्त भूमि कृषि उपयोग के लिए भी उपलब्ध नहीं होती। देश के कुछ भू-क्षेत्र में वन, पहाड़, झील, चारागाह, मकान, सड़क, नहर, रेल आदि अनेक दूसरे उपयोगों के लिए भूमि छोड़ने के अनिवार्य हमें वह भूमि भी छोड़नी पड़ती है जो मस्जिद, दफ्तर आदि की दृष्टि से कृषि के काम नहीं आ सकती है। संक्षेप में किसी भी देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में से इन सबको निवाहने के पश्चात् जो भू-भाग बचता है, वही कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है।

भारतवर्ष में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 68 करोड़ हेक्टर अथवा 81 करोड़ एकड़ है। इसमें से 30 56 करोड़ हेक्टर अर्थात् 93 5 प्रतिशत भूमि की जानकारी के आगड़े उपलब्ध है, लेकिन शेष 2 12 करोड़ हेक्टर क्षेत्र की जानकारी से सम्बन्धित आगड़े उपलब्ध नहीं है। कुल भू-क्षेत्र में से 19 42 करोड़ हेक्टर भूमि कृषि-योग्य है। शेष 13 26 करोड़ हेक्टर क्षेत्र पर कृषि नहीं की जा सकती है, अर्थात् 41 प्रतिशत

भूमि कृषि कार्य में नहीं आ रही है। भारतवर्ष में मन् 1950-51 व 1967-68 में भूमि के उपयोग की स्थिति निम्न तालिका में दिखाने आपकी में शक्त की जा सकती है :

भूमि का उपयोग (करोड़ हेक्टर में)

वर्ग	1950-51	1967-68
1 कुल क्षेत्र जिसमें आने के उपलब्ध है	28.43	30.33
2 वन	4.05	6.23
3 नदी की कमले व वृक्ष-समूह की भूमि	1.99	0.41
4 स्थायी चारागाह व बाघर भूमि	0.67	1.39
5 ऊपर व कृषि के अयोग्य भूमि एवं खेती के अनिश्चित अन्य कार्यो में प्रयुक्त भूमि	4.75	4.81
6 कृषि-योग्य बाघर भूमि	2.29	1.66
7. चालू परती छोड़ कर अन्य परती भूमि	1.74	0.87
8 चालू परती	1.07	1.21
9 विपुल कृषि क्षेत्र	11.87	13.47
10 एक से अधिक बार कृषि क्षेत्र	1.32	2.33
11 कुल कृषि क्षेत्र	13.19	16.30

भारतवर्ष में 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 5470 लाख है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा 0.6 हेक्टर आती है। यदि हम कुल भू-क्षेत्र से कृषि अयोग्य भूमि को हटा दें अर्थात् पर्वतों, पठारों से चिरी हुई भूमि, कच्छ कारण, राजस्थान का मरुस्थल आदि को निकाल दें तो प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि जो 1961 में 0.30 थी वह 1971 में घट कर 0.25 हेक्टर रह गई। खेती-योग्य भूमि में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में कहीं अधिक तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण प्रति-व्यक्ति भू-क्षेत्र का घटना स्वाभाविक ही है।

यद्यपि प्रति व्यक्ति भू-क्षेत्र हमारे देश में 0.25 है तथापि यदि हम प्रति कृषक भू-क्षेत्र को लें तो यह 1.75 हेक्टर होता है, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार देश में 787 लाख कृषक थे जो 1380 लाख हेक्टर बुवाई की भूमि के स्वामी थे और इस भूमि पर लेगी करते थे। अखिल भारतीय ग्रामीण संसद संसद प्रतिवेदन के अनुसार भारतवर्ष में बड़े कृषक जो कुल कृषकों का 30 प्रतिशत है, कुल बुवाई क्षेत्र के 58 प्रतिशत भाग में खेती करते हैं। इन बड़े कृषकों में से ऊपर के 10%, कृषकों के पास 30 प्रतिशत बुवाई का क्षेत्र है। मध्यम कृषक, जो कुल कृषकों का 40% है, 30% से भी कम क्षेत्र पर बुवाई करते हैं। छोटे किसान जिनका

अनुपात लगभग 30 प्रतिशत है, केवल 10 प्रतिशत से कुछ ही अधिक क्षेत्र पर बुवाई करते हैं। यदि हम औसत बुवाई क्षेत्र के हिसाब से देखें तो देख के बड़े कृषकों के पास 12 हेक्टर या कुछ अधिक, मध्यम कृषकों के पास 2.5 हेक्टर या इससे कुछ अधिक तथा छोटे किसानों के पास केवल 1.2 हेक्टर की ही औसत उपलब्ध है। इस प्रकार भारतवर्ष में न केवल बुवाई क्षेत्र का वितरण ही असमान है, अपितु प्रति कृषक भूमि की मात्रा भी बहुत कम है।

कृषि उपज

भारतवर्ष एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। यही कारण है कि भारतवर्ष में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हमारे देश का कुल भू-क्षेत्र 81 करोड़ एकड़ है। समस्त भू-क्षेत्र में से केवल 39.4% भूमि पर ही वास्तविक रूप से कृषि की जाती है। कृषि-योग्य भूमि में से केवल 5.15 करोड़ क्षेत्र पर वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं।

भारत की फसलें—समस्त भारत में सामान्यतः मौरस के अनुसार निम्न-लिखित दो फसलें होती हैं—

1. **खरीफ**—इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल (धान), मूंग, उड़द, जूट, तम्बाकू, कपास, तिलहन, गन्ना आदि कृषि पैदावार उगाई जाती हैं। ये फसलें जून या जुलाई मास में बोई जाती हैं और अक्टूबर या नवम्बर में काटी जाती हैं।

2. **रबी**—इसमें गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई आदि की फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें अक्टूबर या नवम्बर में बोई जाती हैं और अप्रैल या मई में काटी जाती हैं।

उक्त फसलों के अनिश्चित कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो वर्ष भर लड़ी रहती हैं। इन्हें बारहमासी फसलें कहते हैं, जैसे गन्ना, चाय, कहुवा, नारियल इत्यादि।

इकनामिक टाइम्स के अनुसंधान विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार सन् 1964-65 में, कुल कृषि-उत्पादन में खरीफ की फसलों का भाग 62%, या, रबी की फसलों का भाग 24% था और बारहमासी फसलों का भाग 14% था। केवल गादधानों के उत्पादन में खरीफ की फसलों का भाग 71% था तथा रबी की फसलों का भाग 29% था।

फसलों को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(क) साव फसलें तथा (ख) अ-साव फसलें।

(क) **साव फसलें**—हमारे देश की प्रमुख साव फसलें निम्नलिखित हैं—

1. **चावल**—भारत में चावल अधिकांश जनसंख्या का भोज्य पदार्थ है।

इसके लिये तेज गर्मी तथा अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिये इसको

पंदावार नदी के डेल्टामें, तटीय प्रदेशों एवं मानसून के दिनों बाद से फिर जाने वाले क्षेत्रों में होती है। यह मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तामिलनाडू, उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में पैदा किया जाता है। हमारे देश में धान की कई किस्में बोई जाती हैं तथा धान की खेती में अनेक नदीयों का उपयोग किया जाता है।

भारत में साधानों के उत्पादन के लगभग 40% भाग में चावल होता है। विश्व के चावल उत्पादन क्षेत्र का 33% भाग भारतवर्ष में है। इस प्रकार भारतवर्ष विश्व में चीन के बाद चावल का प्रमुख उत्पादक है। सन् 1935 ई. में वर्मा के भारत से निकल जाने के बाद हमारी आत्म-निर्भरता समाप्त हो गयी है और अब हमें विदेशों से चावल आयात करना पड़ता है। सन् 1970-71 में 424 लाख टन चावल पैदा हुआ जो कि 374 लाख हैक्टर भूमि पर बोया गया था तथा इसकी 1134 मिली ग्राम प्रति हैक्टर थी। सन् 1950-51 में यह 380 लाख हैक्टर भूमि पर बोया गया था तथा 206 लाख टन पैदा हुआ। उस समय इसकी उत्पादित 668 मिलीग्राम प्रति हैक्टर थी। योजनाकाल में चावल का उत्पादन लगभग 92 प्रतिशत बढ़ा।

भारत में चावल की पैदावार बढ़ाने के लिये जापानी ढंग का प्रयोग किया जा रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे। हाल ही में चावल (धान) की 11 नई किस्में प्रारम्भ की गई हैं।

2 गेहूँ — गेहूँ उत्तरी भारत के लोगों का मुख्य भोजन है। इसके लिये ठण्डी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान में होता है। साधानों के कुल उत्पादन में 12% भाग गेहूँ का है। सन् 1970-71 में 179 लाख हैक्टर भूमि पर गेहूँ बोया गया था तथा 232 लाख टन इसकी उपज हुई थी। इसकी उत्पादित 1299 मिलीग्राम प्रति हैक्टर थी। जबकि 1950-51 में यह 97 लाख हैक्टर क्षेत्र में बोया गया था, 64 लाख टन पैदा हुआ था तथा इसकी उत्पादित केवल 663 मिलीग्राम प्रति हैक्टर थी। इस प्रकार 1950-51 से 1970-71 के मध्य गेहूँ के क्षेत्र में 84 प्रतिशत और उपज में 36.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। देश के विभाजन के पश्चात् गेहूँ के उत्पादन में भी भारत अब आत्मनिर्भर नहीं रहा है और इसका विदेशों से आयात किया जाता है।

3 प्याज-बाजरा—ये साधान निम्न व्यक्तियों के भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। ये दोनों ही खरीफ की फसलें हैं तथा इनके लिए गर्म तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। वे फसलें भारत के विभिन्न भागों में उगाई जाती हैं। महाराष्ट्र, पंजाब प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिलनाडू,

पंजाब, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ये खाद्यान्न प्रमुखतः लगाये जाते हैं। ज्वार की औसत प्रति हेक्टर उपज 1970-71 में 470 किलोग्राम तथा बाजरे की 620 किलोग्राम थी।

4 मक्का (Maize)—यह पशु खाद्य एवं मानवीय माहुर दोनों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। इस फसल का औद्योगिक महत्व भी है। मक्का की खेती यद्यपि सारे भारतवर्ष में होती है तथापि उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पंजाब इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। विगत नियोजन काल में इसकी फसल के क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों में ही वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 व 1970-71 में इनकी फसल के क्षेत्रफल में 87 प्रतिशत और उत्पादन में 232 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सन् 1970-71 में 74 लाख टन मक्का पैदा हुई थी तथा 58 लाख हेक्टर भूमि में बोई गई थी। इसकी उत्पादित इस वर्ष 1270 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी।

5 जौ (Barley)—यह गेहूँ के ही आकार का होता है तथा इसे अनेकांकृत कम उपजाऊ भूमि एवं पानी की आवश्यकता होती है। इसका महत्व खाद्यान्न में साथ-साथ नगदी फसल के रूप में भी है, क्योंकि उससे बीयर (Beer) भी बनायी जाती है। भारत में जौ मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान में लगाया जाता है। भारत में 1970-71 में 26 लाख हेक्टर भूमि में जौ बोया गया था तथा लगभग 29 लाख टन उत्पन्न हुआ जबकि 1950-51 में यह 31 लाख हेक्टर भूमि पर बोया गया था तथा 24 लाख टन पैदा हुआ था।

6 चना (Gram)—यह गेहूँ व जौ के साथ ही बोया जाता है तथा इसके लिए उष्ण जलवायु, मनुई मिट्टी व कम वर्षा की आवश्यकता होती है। चना मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश व प. बंगाल में बोया जाता है। भारत में लगभग 10 लाख हेक्टर भूमि पर चना बोया जाता है और प्रति वर्ष लगभग 58 लाख टन पैदा होता है।

7 दालें (Pulses)—वने के अलावा मूंग, उड़द, मटर, मसूर, सोठ, अरहर आदि की दालें भी देश भर में बोई जाती हैं। साकाहारी लोगों के लिए यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है तथा मनुष्य के जीवन के आवश्यक अंग है। भारतवर्ष में 1970-71 में 224 लाख हेक्टर भूमि में दालें बोई गई थी और 116 लाख टन उत्पन्न की गई थी।

(ख) अ-खाद्य फसलें—अ-खाद्य फसलों में तन्तु या रेखें वाली फसलें, वे व फसलें व अन्य फसलें आती हैं।

(अ) तन्तु या रेखें वाली फसलें—भारत में रेखें वाली फसलों में पटसन व कपास मुख्य हैं—

1 कपास—यह भारत की सबसे बड़ी रेशे वाली फसल है। उत्तर में कपास पैदा करने वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है। भारत में कपास प्रायः सभी भागों में बोई जाती है, परन्तु उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण भारत में फाली मिट्टी के क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम है। गुजरात, आन्ध्र प्रदेश व मद्रास में भी कपास पैदा की जाती है। भारत में इस समय कुल कृषि क्षेत्र के 46 प्रतिशत भाग में कपास पैदा की जाती है। भारतवर्ष में सन् 1950-51 में 59 लाख हेक्टर क्षेत्र में कपास बोई गई तथा 29 लाख बाल कपास का उत्पादन हुआ। सन् 1970-71 में 76 लाख हेक्टर भूमि पर इसे बोया गया तथा 46 लाख गांठों का उत्पादन हुआ। इस वर्ष कपास की उत्पादितता 108 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी, जबकि 1951 में यह केवल 88 किलोग्राम प्रति एकर थी। भारत में की जाने वाली कपास की किस्म प्रायः घटिया होती है। अतः रेशे रेशे की कपास आयात की जाती है।

2 पटसन या जूट—जूट की खेती के लिए गये तथा तर जलवायु नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी तथा पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में जूट मुख्यतः प० बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा में उगाया जाता है। कुल उपज की बांधी मात्रा बेजब बंगाल में ही पायी जाती है तथा आसाम व बिहार में लगभग 20-20 प्रतिशत उत्पादन होता है। विभाजन से पूर्व अखंड भारत को जूट के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त था। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल प्रान्त के पटसन उगाने वाले क्षेत्र का एक तिहाई भाग पाकिस्तान में चला गया, जबकि पटसन के भारे कारखाने भारत में ही रह गये। इन कारखानों के लिए कच्चे माल की पूर्ण व्यवस्था के लिए यह आवश्यक हो गया कि जूट की उपज बढ़ाई जाय। सन् 1970-71 में लगभग 750 लाख हेक्टर भूमि में जूट की खेती की गई और 49 लाख गांठें पैदा की गई। भारत ने जूट का प्रयोग बोरेटों, पत्रों, दरियाई आदि बनाने में किया जाता है।

(आ) घेय फसलें—घेय फसलों में चाय, कहवा व तम्बाकू को शामिल किया जा सकता है। चाय व कहवा तो उद्योगिक घेय माने जाते हैं और तम्बाकू रसायन पैदा करने वाला पदार्थ माना जाता है।

1 चाय—आगतवर्ष विदेश में चाय उत्पादन करने वाले देशों में सर्वप्रथम है तथा चाय निर्यात करने वाले देशों में भी भारत का नाम सर्वप्रथम आता है। चाय उत्पादन के मुख्य क्षेत्र आसाम, प० बंगाल, काश्मीर की घाटी तथा नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। भारतवर्ष में 1970-71 में लगभग 3,53,000 हेक्टर भूमि पर 1000 गांठें और 4 लाख 22 हजार टन उत्पादित की गई। देश में कुल उत्पात का लगभग 30 से 35 प्रतिशत भाग उपभोग किया जाता है, शेष निर्यात कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप लगभग 10 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार के कोष में आ जाते हैं।

भारत में कृषि उपज

2 चाफ़ी या कहूया—चाय की माँति कहवो भी पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। भारत में मेसूर राज्य में देश के कुल उत्पादन की 80 प्रतिशत नहुवा उत्पन्न विद्या जाता है। तामिलनाडू व केरल में भी कह्वे का उत्पादन होता है। हमारे देश में लगभग 11 करोड़ हेक्टर भूमि पर नहुवा बोया जाता है। सन् 1970-71 में चाफ़ी का उत्पादन 108000 टन हुआ।

3 तम्बाकू—तम्बाकू उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तम्बाकू के लिए उपजाऊ भूमि एवं सिचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत में बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र, बिहार व तामिलनाडू तम्बाकू उत्पादन के क्षेत्र हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में भी बोटी बहुत गांधा में तम्बाकू पैदा की जाती है। भारत में 1970-71 में तम्बाकू 45 लाख हेक्टर भूमि में बोई गई थीर 344 लाख टन पैदा की गई। भारत बिदेखों को तम्बाकू का निर्यात करता है।

(इ) अन्य फसलें (i) गन्ना—गन्ने की पैदावार के लिये उपजाऊ जमीन, तेज गर्मी, चिकनी मिट्टी तथा तेज वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में गन्ने के उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पं० बंगाल, पंजाब व महाराष्ट्र हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में भी गन्ना पैदा होता है, परन्तु उत्तर प्रदेश के मुगावले में कम पैदा होता है। उत्तरी क्षेत्रों में लगभग 70% गन्ने की उपज होती है। दक्षिणी क्षेत्र में प्रति एकड़ गन्ने की उपज अधिक है और साथ ही यह काफी रसदार भी होता है। 1970-71 में भारतवर्ष में गन्ने की खेती 27 लाख हेक्टर भूमि पर की गई थीर 132 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया गया। प्रति हेक्टर गन्ने का उत्पादन 4966 लाख टन था। 1950-51 से सन् 1970-71 तक गन्ने की फसल के क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा उपज में 135 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ii) तिलहन—भारतवर्ष में पैदा की जाने वाले मुख्य तिलहन हैं—गू गफली, भलसी, एरण्ड, सरसो, तिल, विनीला, नारियल आदि। तिलहन का प्रयोग भोजन बनाने में तो किया ही जागा है साथ ही साथ साबुन, दवाइयाँ, इत्र, वार्निश आदि के निर्माण में भी इनका प्रयोग होता है। विश्व के तिलहन उत्पादक देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। गू गफली के उत्पादन में तो भारत विश्व में प्रथम है। भलसी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है तथा एरण्ड के उत्पादन में तो भारत को एकाधिकार प्राप्त है। भारत में लगभग कुल कृषि के 86% भाग में तिलहन बोए जाते हैं। सन् 1970-71 में 153 लाख हेक्टर भूमि पर तिलहन की खेती की गई तथा 92 लाख टन तिलहन पैदा किया गया। प्रति हेक्टर तिलहन का उत्पादन 599 किगो ग्राम था।

(iii) रबड़—भारत में रबड़ मुख्यतः दक्षिण भागों में ही पैदा किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक-क्षेत्र तामिलनाडू, मेसूर एवं केरल हैं। भारत का अधिकांश

रबड़ केरल में उगाया जाता है। भारत में लगभग 1 लाख 55 हजार हेक्टर भूमि पर रबड़ उगाया जाता है और लगभग 46 हजार टन पैदा किया जाता है।

अन्य फसलों एवं उपजों के अतिरिक्त भारत में अन्य वस्तुओं भी पैदा की जाती है। कई प्रकार के फल एवं सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। सच तो यह है कि भारत-भर में उगाई जाने वाली समान वस्तुओं का उत्प्रेषण करना कठिन है, परन्तु जिन वस्तुओं का आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक महत्व है, उन्हीं का वर्णन इन अध्याय में किया गया है।

भारत में फसलों का स्वरूप (*Cropping Pattern in India*)

एक प्रगतिशील देश में फसलों का स्वरूप देश की परिस्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहना चाहिये, तभी उस देश की कृषि-प्रणाली उस देश के आर्थिक विकास में वरदान साबित हो सकती है। फसलों के स्वरूप में स्थिरता कृषि-क्षेत्र की प्रगति को चुनौती देती है तथा राष्ट्र के नियोजित विकास में बाधा बनती है। आज हम नियोजन के युग में रह रहे हैं। हम दक्ष में उन्हीं और उतनी ही वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं, जिनकी तथा जितनी देश की आवश्यकता है। यदि कृषि उत्पादन अनियोजित तथा आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो और फसलों का स्वरूप देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बदल जा सके तो नियोजन, वास्तविक कृषि क्षेत्र में, अमफल हो जायेगा। अतः आज के युग में फसलों के स्वतन्त्र तथा देश की आवश्यकताानुसार इसमें परिवर्तन की सम्भावना का होना अति-आवश्यक है।

फसलों के स्वरूप में परिवर्तन की सम्भावना फसलों के स्वरूप में परिवर्तन करना सम्भव है अपना नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है। कुछ विद्वानों का मत है कि फसलों के स्वरूप को बदलना असम्भव है या अत्यधिक कठिन है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का यह मत है कि फसलों के स्वरूप को बदल जा सकता है। श्री एम. एन. सिन्हा के अनुसार फसलों को नहीं बदल जा सकता। उनका कहना है कि, "परम्परागत तथा ज्ञान के अभाव में बिना स्तर वाले देश में, कृषक नये प्रयोग करने की तैयार नहीं होता। वे हर एक बात को सदासीनता एवं भावनादिना की भावना से स्वीकार करते हैं। उनके लिये खेती व्यापार की वस्तु न होकर जीवन की एक प्रणाली है। एक कृषि-प्रधान समाज में, जिनके सदस्य परम्पराओं में बंधे हुए एवं अशिक्षित हैं, फसल में परिवर्तन की अधिक सम्भावना नहीं रहती है।"¹

भारत जैसे रुढ़िवादी एवं प्रजातांत्रिक देश में भी सिन्हा का उक्त मत कुछ-

1 S. N. Sinha *Economics of Cropping Pattern*, AICC Economic Review, Vol. Jan. 1964

कुछ सही हो सकता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश में सरकार के पास ऐसे अधिकार नहीं होते कि वह किसानों की फसल विशेष को उगाने या न उगाने के लिए बाध्य कर सके। ऐसे देशों में फसलों के स्वरूप में परिवर्तन के लिए न तो निषेध ही किया जा सकता है और न निर्देशन ही दिया जा सकता है। फिर भी उन स्थानों में जहाँ पहली बार खेती की व्यवस्था की जा रही हो, फसलों के स्वरूप को बदल जा सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार चीज, पानी, धातु, श्रम या आर्थिक सहायता देकर फसलों के स्वरूप में परिवर्तन करा सकती है।

समाजवादी देशों में फसलों के स्वरूप में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत आसान बात है। ऐसे देशों की सरकारों को केवल यह तय करना होता है कि कौन सी फसल और कितनी भूमि पर उगाई जानी चाहिए। यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है तो सरकारी खेती के प्रबन्धक एवं कृषकों को यह नियम लागू करना ही होगा।

फसलों के स्वरूप को निर्धारित करने वाले तत्त्व

फसलों के स्वरूपों निर्धारित करने वाले कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख यह है—

(क) भौतिक कारण फसलों के स्वरूप को निर्धारित करने में किसी प्रदेश विशेष की मिटटी, जलवायु, वर्षा आदि या महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उदाहरणार्थ, यदि ज्वार व बाजरा शुष्क क्षेपित व वर्षा वाले क्षेत्रों में ही सजाता है तो ज्वार के लिए वाली मिट्टी चाहिए वरन् के लिए उपजाऊ दमट मिट्टी की आवश्यकता होती है धान के लिए वर्षा की अधिकता होना आवश्यक है। अतः सामान्यतः फसलों का स्वरूप भौतिक या भौगोलिक कारणों पर निर्भर करता है। यदि इन कारणों में परिवर्तन ही जाय या मनुष्य भौतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सके तथा सिंचाई, खाद आदि के द्वारा तो फसलों के स्वरूप को बदल जा सकता है।

(ख) आर्थिक कारण देश की फसलों के स्वरूप का प्रभावित करने में आर्थिक कारणों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज के भौतिकवादी युग में किसान इन कारणों से काफी प्रभावित होता है। आर्थिक कारणों में निम्न मुख्य हैं—

1. कृषि पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन—जिन कृषि वस्तुओं के मूल्य ऊँच होते हैं, किसान प्रायः उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में जुट जाते हैं। इनके विपरीत जिन वस्तुओं के मूल्य नीचे हैं या गिरते रहते हैं, किसान ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कम या बन्द कर देते हैं। व्यावहारिक अध्ययनों से मूल्य में परिवर्तनों और फसलों के बीचों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित होता है। खाद और कृषि मन्त्रालय में भी इस सम्बन्ध में जो तथ्य एकत्रित किये हैं उनसे यह ज्ञान होता है कि मूल्यों में परिवर्तन का वस्तु विशेष के उत्पादन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है।

2 अधिक साम तथा आय की सम्भावना—कुछ विद्वानों का मत है कि किसान की अधिक आय की अभिलाषा फसलों के ढांचे या स्वरूप पर प्रभाव डालती है। किसान प्रायः उन्हीं फसलों को उगाता चाहते हैं जिनसे उन्हें अपेक्षाकृत अधिक आय प्राप्ति की सम्भावना होती है। इस सम्बन्ध में डॉ० राजकुण्ठ का मत है कि फसलों के स्वरूप को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण फसल का प्रति एकड़ सादेन लाभ होता है। यदि किसी एक फसल का मण्डोल लाभ अन्य फसल से कम है, तो ऊपरी वाली फसल को जगह दूसरी फसल हो पैदा करेगा।

3 जेत का व्यापार—जत के आकार और फसलों के स्वरूप में प्रतिष्ठित सम्बन्ध रहता है। छोटे रेत रखने वाले किसान बड़े रेत रखने वाले किसानों की अपेक्षा व्यापारिक फसलों के लिये कम क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं क्योंकि सबसे पहले वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना चाहते हैं, यदि उसके बाद जमीन का टुकड़ा बच जाता है, तब वे व्यापारिक फसलें उगाते हैं, अन्यथा नहीं।

4 जोखिम के विरुद्ध बीमा—भौतिक कारणों से फसलों के नाश हो जाने के भय में कभी कभी किसान सामान्य फसल के बजाय अन्य फसलें बीं दते हैं, जिनके बीने में कम से कम जोखिम होती है। उदाहरणार्थ, जूफ क्षेत्रों में गेहूँ त बाँकर उबार बाजरा इसलिए छोड़ा जाता है कि यदि वर्षा पर्याप्त न भी हो तो भी यह फसलें ही बाँचेगी। अतः फसल सम्बन्धी जोखिम को कम से कम करने की आवश्यकता भी फसलों के ढांचे को प्रभावित किया है।

5 आवासीय को पूरि—मीठ, खाद, पानी की उपलब्धता और बाजार गृह विपणन परिवहन की सुविधाएँ भी फसलों के स्वरूप का प्रभावित करती हैं। मध्य प्रदेश के अनेक किसानों ने मृगफली के बीजों की आमांश से उपजकरता के कारण ही इसकी खेती को काफी बढ़ा लिया है। इसी प्रकार अन्य आवासों की उपलब्धि का प्रभाव भी जल के स्वरूप पर पड़ता है।

6 भूमि स्वामित्व—जिनात भू-स्वामी होने के नाते फसलों के स्वरूप को अपने अधिकतम लाभ की दृष्टि में रखते हुए स्वयं चुनता है और का लाभदायक फसल की जगह अधिक लाभदायक फसल चोना है। बटाई प्रथा के अन्तर्गत सामंतिज खेती करने वाले किसानों को भूमिपतिवों के फसले के अनुरूप ही फसलों का स्वरूप स्वीकार करना होता है। जैसा मालिक कहेगा, उन्हे वही और उनकी ही फसल चोनी होगी।

(ग) सरकारी नीति एवं सहायता—सरकार वैधानिक प्रशासनिक एवं अन्य कपायों से फसलों के स्वरूप में परिवर्तन कर सकती है। सरकार जिन फसलों को

बढ़ावा देना चाहे, उन फसलों के उर्वरक, बीज, मिनाई सुविधा आदि देकर उठावा दे सकती है। यही नहीं, उत्पादन शुल्क व निर्यात-शुल्क में छूट देकर तथा आर्थिक सहायता देकर भी कुछ फसलों को अन्य फसलों की अपेक्षा बढ़ावा दे सकती है। सरकारी नीति एवं सहायता के प्रभाव से देश में फसलों के स्वरूप को परिवर्तित किया जा सकता है।

भारतवर्ष में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व फसलों का स्वरूप

Pattern before Independence—यह मोटे तौर पर दो फसलें होती आई हैं—खाद्य फसलें एवं अखाद्य या व्यापारिक फसलें। बीसवीं शताब्दी के कृषि उपज सम्बन्धी आँकड़ों से हमें ज्ञात होता है कि प्रारम्भ तक खाद्य फसलों का ही अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि जनसंख्या का अधिकतर भाग गांवों में रहता था तथा यह अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर था। उसी उस समय की प्रमुख आवश्यकता की वस्तु खाद्य पदार्थ ही थे। उस समय उद्योगों की अल्प-विकसित दशा होने के कारण व्यापारिक फसलों का उत्पादन सीमित था।

समय के साथ-साथ भारतवर्ष के लोगों ने भी उद्योग-वस्तुओं का धीरे-धीरे विकास किया, देश की सामान्य जनसंख्या गांवों से नगरों की ओर जाने लगी, लोगों की आवश्यकता के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ और उन्हें भोजन के अलावा अनेक अन्य वस्तुओं की आवश्यकता भी होने लगी। कारखानों द्वारा उत्पादित माल उनकी इच्छित वस्तुओं की पूर्ति करने लगे। उद्योगों के विपणन ने कच्चे माल की माँग को बढ़ा दिया, परन्तु उनके मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। यही कारण है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर आज तक के कृषि उपज के इतिहास के अध्य-
लोचन से यह तथ्य पूर्णरूप से स्पष्ट हो जाता है कि कृषि उपज में खाद्यान्नों का महत्व निरन्तर गिरता गया है और व्यापारिक फसलों का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। पर चूँकि यह सब इतना धीरे-धीरे हुआ, इसलिए लोगों को फसलों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन का केवल हल्का सा ही आभास मिला। फिर भी यह परिवर्तन महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली रहा है। भारत, जो कि कभी विश्व के खाद्य भण्डार का खलिहान कहा जाता था, खाद्यान्नों के उत्पादन में इतना पिछड़ गया है कि उसे अपने ही निवासियों की उदर-पूर्ति के लिये विदेशों से आयात करना पड़ता है।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक फसलों के स्वरूप में तथा जनसंख्या में मोटे तौर पर जो परिवर्तन हुए हैं वे अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट हो जाते हैं—¹

1 Studies in Indian Agricultural Economics, P. 10.

भारत में जनसंख्या एवं फसलों का बदलता स्वरूप (1900-1945)

वर्ष	जनसंख्या का निर्देशक	कुल बोई गई भूमि के क्षेत्र का निर्देशक		
		खाद्य फसलें	अखाद्य फसलें	कुल फसलें
1901-1915	100.0	100.0	100.0	100.0
1921-1925	108.0	100.1	118.2	108.9
1931-1935	120.5	111.3	132.5	114.8
1941-1945	137.9	113.8	141.3	218.4

ऊपर दी गई मारिणों से यह स्पष्ट है कि बीसवीं शताब्दी के प्रथम 45 वर्षों में देश की जनसंख्या 37% प्रतिशत बढ़ी, जबकि कुल बोया गया क्षेत्र केवल 16% प्रतिशत ही बढ़ा। इस अवधि में खाद्य-पदार्थों के क्षेत्र में 13.8 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि अखाद्य पदार्थों के क्षेत्र में 41.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस अवधि में गन्ध-फसलों में सबसे अधिक वृद्धि हुई के क्षेत्र में (34.9%) तथा सबसे कम पदार्थ के क्षेत्र में (10.82) हुई। चावल, बाजरा एवं जौ की फसलों में क्रमशः 17.4, 22.2 तथा 13.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। अखाद्य या व्यावसायिक फसलों के अन्तर्गत सबसे अधिक वृद्धि गन्ध की फसल में (53.6%) तथा सबसे कम वृद्धि रेशमाली फसलों (23.9%) में हुई। तिलहन तथा दालिया-पदार्थों की उपज में वृद्धि क्रमशः 28.6 तथा 42.8 प्रतिशत थी। इस अवधि में कुल फसलों के अनुपात में खाद्य-पदार्थों का अनुपात 3.3 प्रतिशत में कम हो गया तथा गन्ध व्यावसायिक फसलों का अनुपात इतनी ही मात्रा में बढ़ गया। कुल बोया गया क्षेत्र भी 1900-01 ई० में 2772 लाख एकड़ में बढ़ कर मई 1944-45 ई० में 3283 लाख एकड़ हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद फसलों का स्वरूप

(Cropping-pattern after Independence)

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सभी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन ध्यान में देवक पर पता चलता है कि अखाद्य फसलों में खाद्य फसलों की तुलना में कहीं अधिक वृद्धि हुई है।¹

अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका फसलों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य फसलों के आधेन क्षेत्रफल धीरे-धीरे बढ़ा है, जबकि व्यापारिक या उद्योग फसलों के आधेन क्षेत्रफल तेजी से बढ़ा है। इस परिवर्तन के बावजूद भी गन्ध फसलों का अब भी सबसे अधिक

1 Indian Agriculture in Brief, 1971, pp 96-97.

महत्व है, क्योंकि मसूर धानफल का $\frac{1}{4}$ से अधिक भाग इन्हीं फसलों को पैदा करने में प्रयुक्त होता है।

भारत में फसलों का बदलता स्वरूप (1950-51 से 1970-71 तक)

वर्ष	खाल-फसलें	अन्धकार-फसलें	कुल फसलें
1949-50	100 0	100 0	100.0
1950-51	97 9	100 8	99 9
1955-56	111 9	130 7	115 0
1960-61	116 9	141 2	120 8
1965-66	116 5	154 6	122 5
1968-69	121 9	146 2	125 6
1969-70	125 1	151 4	129 1
1970-71	125 4	153 2	129 6

भारत में एक अनुमान के आधार पर 75% से 80% भाग पर खाद्य फसलें पैदा की जाती हैं, 10% क्षेत्र पर जलहन, 6% क्षेत्र पर रेखेवाली फसलें और 3.5% भाग पर वाणान व अन्य फसलें उगाई जाती हैं।

भारत के लिये आदर्श फसल स्वरूप

भारत के लिये आदर्श फसल-स्वरूप क्या हो? इस सम्बन्ध में प्रायः 3 विचारधाराएँ पाई जाती हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत के मामले में खाद्य समस्या का त्रिकोण रूप है। अतः खाद्यान्नों के उत्पादन पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। दूसरे प्रकार के विद्वानों का मत है कि कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार उतन समय ही होगा, जबकि उनकी उनकी फसल का अधिकारिण मूल्य मिले। दूसरे शब्दों में, वे व्यापारिक फसलों के उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में प्रवृत्त होते हैं। तीसरे समुदाय के विद्वानों का मत है कि हमें केवल वे ही फसलें उगानी चाहिये जो योजना-आयोग द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रख कर नियत किये हुये योजना-आयोगों की प्राप्ति करने में सहायक, हो चूकें। हमारे देश का योजना-बद्ध विकास हो रहा है, अतः तीसरा दृष्टिकोण ही भारत के लिये आदर्श फसल-स्वरूप निर्धारण के लिये उपयुक्त साबित होगा।

प्रश्न

1. भारत की मुख्य व्यापारिक फसलें क्या हैं तथा उनका भौगोलिक विवरण क्या है? (आगरा बी. काम 1962)
2. फसलों के स्वरूप से आप क्या समझते हैं? फसलों के स्वरूप को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए।
3. भारतवर्ष में फसलों के स्वरूप का ऐतिहासिक विवेचन कीजिए तथा भारत के लिये आदर्श फसल स्वरूप का सुझाव दीजिए।

भूमि का उप-विभाजन एवं अपखण्डन

(Sub-division and Fragmentation of Land)

"The inefficiency of agriculture is due more to the small size and scattered nature of the holding than due to ignorance or want of alertness on the part of the peasants."

—Dr. R. K. Mukherjee

कृषि की उत्पादकता बहुत कुछ खेतों के आकार पर निर्भर करती है। भारत जैसे विशाल कृषि-प्रधान देश में जहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो एवं कृषि-योग्य भूमि सीमित हो खेतों का छोटा होना स्वाभाविक है। भारत में कृषि अनार्यक है। खेतों का छोटा होना कृषि को और भी अलाभकारी बना देता है। आज देश में कृषि-उत्पादन की वृद्धि के लिए मनुष्य प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा कृषि उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं में भूमि के उप-विभाजन एवं अपखण्डन की समस्या के अध्ययन एवं निवारण का बहुत अधिक महत्व है। इस समस्या को हल किये बिना तथा आर्थिक जोनों के निर्माण के अभाव में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना सम्भव नहीं है।

कृषि-इकाइयों के आकार

कृषि-जोतों का वर्गीकरण विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से दिया गया है। साधारणतः कृषि-जोतों को तीन भागों में बाटा जाता है, (i) आर्थिक जोत; (ii) आधारभूत जोत, तथा (iii) अनुकूलतम जोत।

(i) आर्थिक जोत—आर्थिक जोत के सम्बन्ध में श्री कीटिंग के विचार इस प्रकार हैं—“आर्थिक जोत से वांछ्य ऐसी जोत में है जिससे कि कृषक अपने व्यावसायिक व्यय निकालने के बाद इतनी आय प्राप्त कर ले कि उसका एवं उसके परिवार का ब्यय के साथ उचित रूप से जीवन-निर्वाह हो सके।”¹

३१० मान ने भी इसी से मिलती-जुलती परिभाषा दी है। उनके शब्दों में "एक आर्थिक जोत वह है जो एक बीसत आकार के परिवार की जीवन का सतोप-जनक समझा जाने वाला न्यूनतम स्तर प्रदान करती है।"¹

आर्थिक जोत का आकार क्या हो, इस पर भी विद्वानों के मतों में अन्तर पाया जाता है। कोटिग के मतानुसार भिचाई के लिए कम से कम एक अर्धे गुए की सुविधा के साथ 40 से 50 एकड़, एक ही चक्र की भूमि, आर्थिक जोत कहायेगी। ३१० मान का विचार है कि 20 एकड़ भूमि को आर्थिक जोत का आकार माना जा सकता है। श्री स्टैन्ले जेवन्स (Stanley Jevons) के अनुसार आर्थिक जोत वही है जो रहन-सहन का उचित स्तर प्रदान करती है। उनके अनुसार आर्थिक इकाई में कम से कम 30 एकड़ भूमि होनी चाहिए। डार्लिंग (Darling) के अनुसार यदि किसान के पास आय के अन्य साधन प्राप्त हैं तो 8 से 10 एकड़ भूमि उसको न्यूनतम स्तर प्रदान करने के लिए काफी है।²

आर्थिक जोत के आकार को निर्धारित करने वाले मुख्य तत्त्व निम्न हैं : (1) कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता, (2) कृषि-विधि (3) भिचाई की सुविधा, (4) खेती का स्वस्व, (5) उगाई जाने वाली फसल की प्रकृति, (6) बाजार से दूरी या निकटता, (7) कृषक की सामाजिक दशा एवं (8) कृषि का उद्देश्य। इन तत्वों को ध्यान में रख कर ही आर्थिक जोत का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(ii) आधारभूत जोत—यह कृषि जोत की सबसे छोटी इकाई है। इससे कम भूमि पर खेती का काम करना अनावधिक होगा। अतः आधारभूत जोत से हमारा तात्पर्य व्यक्तिगत आधार पर की जाने वाली लाभदायक कृषि के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र से है।

(iii) अनुकूलतम जोत—इसे आदर्श जोत भी कह सकते हैं। यह खेत का वह आकार है जिससे एक किसान को उसके द्वारा लगाये गये श्रम व पूँजी से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। भारत में आदर्श जोत का आकार आर्थिक जोत के आकार का तीन गुना अधिक माना जाता है।

जब जोतों के अलावा एक पारिवारिक जोत भी होती है। पारिवारिक जोत से हमारा मतलब कृषि-भूमि के ऐसे आकार से है जो किसानों को कम से कम इतनी पैदावार भवश्य दिलावे, जिससे उसको प्रतिवर्ष 1,600 रुपये की औसत आयशुनी प्राप्त हो सके तथा मजदूरी व आवश्यक सचों की तिकाल कर कम से कम 1,200 रुपये प्रतिवर्ष खोप बन जायें।

1. H. Mann Land & Labour in Deccan Valleys

2. M. L. Darling Punjab Peasants in Prosperity & Debt.

भारत में कृषि-भूमि का उप-विभाजन एवं अपखण्डन

भारतवर्ष में कृषि जोतो की दो मुख्य समस्याएँ हैं, यथा—(i) उप-विभाजन, तथा (ii) अपखण्डन। सरैया सहकारी समिति के मतानुसार—‘अनुसूचक एवं अशाम-श्रद्ध खेती भारतीय कृषि उत्पादन में सबसे बड़ी बाधा है।’ गणित के विचारानुसार अशामकारी कृषि जोती की दो समस्याएँ हैं—(क) खेतों के आकार का छोटा होने जाना, तथा (ख) किसानों के खेत एक चक्र में न होकर दूर-दूर फैलने जाना। इन समस्याओं का विस्तारपूर्वक विवेचन अपेक्षित है।

उप-विभाजन का अर्थ—कृषि जोतों के उप-विभाजन से हमारा तात्पर्य परिवार के विभाजन अथवा अन्य कारणों से एक जोत के कई व्यक्तियों में बीच बट जाने से है। हमारे देश में यह एक शिकायती हो गई है कि भू-स्वामी की मृत्यु के पश्चात् उसकी भूमि छोटे-छोटे भागों में बट जाती है। उप-विभाजन या तो भू-स्वामी द्वारा अपनी भूमि का कुछ भाग देव देने, दान या चपहार में दे देने आदि से होता है। इस प्रकार देश में प्रायः भू-स्वामी की मृत्यु के पश्चात् या उनके जीवन-काल में ही भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बट जाती है और उसके खेतों का आकार पीड़ी-दर-पीड़ी छोटा होता जाता है। यह प्रक्रिया हमारे देश में लम्बे समय से चली आ रही है और अब भी चल रही है।

अपखण्डन का अर्थ—कृषि जोतों के अपखण्डन से आशय है खेतों का एक जगह न होकर अनेक जगहों पर बिखरे होना। भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों एक चक्र में न होकर दूर-दूर बिखरे होते हैं तथा इन टुकड़ों के बीच प्रायः काफी अन्तर होता है, जिसके फलस्वरूप इन सब टुकड़ों को मिला कर एक खेत के रूप में खेती नहीं की जा सकती। भारत में भूमि का उप-विभाजन (Sub-division) प्रायः अपखण्डन (Fragmentation) के साथ साथ वाया जाता है।

भारत में कृषि जोतों का आकार :

(अ) उप-विभाजन—भारत में कृषि-जोतों का आकार बहुत छोटा है, जबकि गन्धार के अन्य देशों में कृषि जोतों का आकार बड़ा है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है

देश	जोत का औसत आकार (एकर में)	देश	जोत का औसत आकार (एकर में)
न्यूजीलैण्ड	491	हालैण्ड	26 00
अमेरिका	145	डेन्मार्क	37 05
इंग्लैण्ड	20	भारत	7 39
फ्रांस	20		

विहले पृष्ठ पर दी गई सारिणी से स्पष्ट है कि भारत में कृषि-जोत अन्य देशों की तुलना में काफी छोटी है। देश के विभिन्न राज्यों में भी जोतों का आकार भिन्न-भिन्न है, जैसा कि आगे दी गई तालिका से ज्ञात होता है ¹।

भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति कृषक परिवार द्वारा जोती गई भूमि का औसत (एकड़ में)

राज्य	प्रति परिवार औसत भूमि	राज्य	प्रति परिवार औसत भूमि
केरल	18	आन्ध्र प्रदेश	30
अरुण एवं कश्मीर	38	मैसूर	105
पश्चिमी बंगाल	41	मध्य प्रदेश	106
तामिलनाडु	46	गुजरात	125
आसाम	47	महाराष्ट्र	129
बिहार	48	पंजाब	138
उड़ीसा	52	राजस्थान	160
उत्तर प्रदेश	53	सम्पूर्ण भारत	739

भारत में कृषि जोतों के उप-विभाजन की सीमा का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है—

जोतों का क्षेत्र	सदस्या		क्षेत्र	
	लाख में	प्रतिशत	लाख एकड़ में	प्रतिशत
1 एकड़ से कम	266	42.1	40	1.2
1 एकड़ से 5 एकड़	180	29.1	484	14.4
5 एकड़ से 10 एकड़	88	14.2	623	18.5
10 एकड़ से 20 एकड़	54	8.7	752	22.4
20 एकड़ से 40 एकड़	25	4.1	695	20.7
40 एकड़ से 100 एकड़	10	1.6	563	16.8
100 एकड़ से अधिक	0.1	0.2	200	6.0

Source: National Sample Survey, 8th Round

1. Sher & S. Sharma: A study of the Structural and Tenurial Aspect of Rural Economy in the light of 1961 Census Indian Journal of Agricultural Economics, Oct-Dec 1965

पृष्ठ 105 पर दी हुई ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि भारत में कुल ज़ोनो का 71 72 प्रतिशत भाग 5 एकड़ या इससे भी कम है।

(ख) अपखण्डन : भारतवर्ष में खेतों का बंसार छोटा नहीं है, अपितु किसानों के खेत दूर-दूर फैले हुए हैं जिसमें खेतों करने में कठिनाई होती है। श्री शालिम के अनुसार पंजाब के एक गांव में 548 भूस्वामियों के पास 16,000 खेत थे। श्री रामलाल मल्ला की जांच के अनुसार, पंजाब के होशियारपुर जिले के देरामपुर गांव में 34 % किसानों में से प्रत्येक के पास 15-25 टुकड़े थे। कृषि सम्बन्धित राष्ट्रीय आयोग ने एक उदाहरण में बताया है कि गंजा में एक जमींदार की भूमि 800 टुकड़ों में बटी हुई थी और दूर-दूर फैली हुई थी। डा० मान ने बिम्बला सौदागर नामक गांव में पता लगाया कि 156 भू-स्वामियों के पास 729 खेत थे, जिनमें 446 खेत एक एकड़ से कम थे तथा 211 खेत $\frac{1}{2}$ एकड़ से कम थे। श्री कीटिंग (Keting) के अनुसार बम्बई के एक गांव में आधे एकड़ से भी कम आकार का खेत लगभग 20 स्वामियों में बंटा हुआ है। रत्नागिरि में किसी खेत का आकार प्रायः 000625 एकड़ तक छोटा होता है जिस पर खेतों की जाँची का मुकना तक कठिन हो जाता है। देन में हाल ही में किए गए खेत प्रबन्ध अध्ययनों से भी खेतों के अत्यन्त छोटे तथा भिन्न-भिन्न स्थानों पर फैले होने का पता चलता है।

उप-विभाजन एवं अपखण्डन के कारण देश में उप-विभाजन एवं अपखण्डन उत्तरोत्तर होता आया है और होता आ रहा है। इसके अनेक कारणों में से मुख्य कारण इस प्रकार हैं —

(1) उत्तराधिकार विधायक : भारत में कानून द्वारा मृतक पिता की सम्पत्ति में पुत्रों को बराबर हिस्सा मिलता आया है। नए कानून के अनुसार हिन्दुओं में न केवल पुत्रों को ही, बल्कि पुत्रियों को भी इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। इससे दिन-प्रतिदिन उप-विभाजन एवं अपखण्डन बढ़ता आ रहा है और भविष्य में भी यदि यह न रोका गया, तो इसी प्रकार बढ़ता रहेगा।

(2) जनसंख्या में वृद्धि : भारतीय कृषकों के पास जीविका का साधन केवल खेती ही है। जनसंख्या-वृद्धि के साथ-साथ खेतों पर जनसंख्या बढ़ता जाता है, क्योंकि खेती के सिवाय कुम्हों के पास अन्य धन्य धन्य ही नहीं है। 1953 में प्रकाशित जन-गणना विवरण-पत्र के अनुसार सन् 1921 की तुलना में प्रति व्यक्ति कृषि का क्षेत्र लगभग 25% कम हो गया। अनुमान है कि कृषि पर आश्रित प्रति व्यक्ति के भाग में औसतन एक एकड़ से भी कम भूमि बाँटी है, जो कि सतोषजनक जीवन बिताने के लिए अरुणार्थक कम है। प्रो० वाट्सियान यर्नेन्ट ने मतानुसार, “भूमि का उप-विभाजन और अपखण्डन न केवल उत्तराधिकार व दायित्वों के नियमों के कारण

होता है, अपितु इसका कारण ही प्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या की भूमि की प्यास है जिसे अकुपि व्यवसायो में रोजगार दिलाना सम्भव नहीं होता।¹

(3) व्यक्तिवाद का उदय पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर, भारतीय भी अब परिवार से पृथक् रहने लगे हैं। इससे परिवार की छेती के उप-विभाजन एवं अपखण्डन में वृद्धि हुई है।

(4) समुक्त कुटुम्ब-प्रथा का ह्रास भारत में समुक्त कुटुम्ब-प्रथा टूटती जा रही है जिससे भूमि का उप विभाजन निरन्तर बढ़ रहा है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य खेत में से अपना हिस्सा भक्षण कर लेता है।

(5) कुटीर उद्योगों का पतन ब्रिटिश साम्राज्य की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण हंगारे कुटीर उद्योग नष्ट हो गये, जिससे इन उद्योगों में लगी हुई जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती पर आश्रित हो गया। इससे भूमि के उप-विभाजन एवं अपखण्डन में वृद्धि स्वाभाविक ही थी।

(6) भूमि से श्रेष्ठ भारतीय कृषक का भूमि से कटाव होता है। वह भूमि को जीविना का साधन ही नहीं समझता, बरन् प्रतिष्ठा व सम्मान का आधार भी मानता है। अतः हर व्यक्ति पैतृक भूमि में हिस्सा पाने के लिए लालापित रहता है।

(7) कृषकों में अकर्मकर्मता भारतीय कृषक अल्पभार से प्रायः दबा रहता है और भूमि को वह धरोहर के रूप में रखता है। 'रुब न चुका सकने पर भूमि का हिरा गहाजन को ब देना है, जिससे भूमि का उप-विभाजन होता है।

(8) कृषि-प्रथा के दोष देश की कृषि पद्धति दोषपूर्ण है। पशुओं के हेर-पर के लिए कुछ भूमि, बिना खेती किये छोड़ती पड़ती है। भूमि के हिस्से कर लिये जाते हैं, जिससे भूमि टुकड़ों में बंट जाती है।

(9) उर्वरता में अन्तर कुछ खेती की भूमि उपजाऊ होती है और कुछ की कम उर्वर होती है, जिससे उत्तराधिकारी बीना प्रकार की भूमियों में हिस्सा बटाते हैं और इस प्रकार भूमि के टुकड़े अधिक हो जाते हैं।

(10) सास की प्रथा भारत में कृषि की 'बटाई' प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के अन्तर्गत भूस्वामी स्वयं खेती न करके अन्य लोगों में भी खेती करा सकता है। अतः भूस्वामी अपनी भूमि को कई व्यक्तियों को 'बटाई' पर उठा देता है। इस प्रकार खेत बिखर जाते हैं।

1. "Thus sub-division and fragmentation of land was, not only due to the laws of Succession and inheritance but to the land hunger created by growing population incapable of being absorbed in normal agricultural operation."

(11) कृषकों में अधिशास्य अज्ञानता : भारतीय कृषक अज्ञानता के कारण उप-विभाजन एवं अपखण्डन की बुराईया नहीं समझता, जिससे वह नकबन्दी, सहकारी एवं सामूहिक कृषि का विरोध करता है।

(12) अन्य कारण औद्योगीकरण का अभाव, खेती की चकबन्दी का न होना, राजाओं, नवाबों एवं जमींदारों द्वारा प्रदत्त होकर अपने नीचरी की भूमि में टुकड़े बनाप में खेती की आवस्यता आदि कारण भी भूमि के उप-विभाजन एवं अपखण्डन के लिए उत्तरदायी हैं।

उप-विभाजन एवं अपखण्डन के लाभ भारत में कई विद्वान ऐसे भी हैं जो उप-विभाजन एवं अपखण्डन की दोष-हित में समझते हैं। इनमें डा० राधाकृष्ण मुक्जी प्रमुख हैं। डा० मुक्जी के अनुसार—“भारत के कई भागों में अलग-अलग खेतों पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा कम होने या उमड़ा वितरण हर क्षेत्र में उचित न होने पर यदि एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरे खेत में अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। इससे अलावा भारत में फसलों का हेर-फेर, जो भारतीय एवं पारंपरिक कृषि में अनवरत चलता है, इसलिए संभव हो सका है कि यहां के खेत अपखण्डित हैं।”

संक्षेप में उप-विभाजन एवं अपखण्डन के नकारार्थ का प्रमाण निम्न तर्कों द्वारा दिया जाता है —

(1) प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का कुछ न कुछ भाग मिल जाना है जो स्थापनगत है, (2) सबके पास भूमि होने में सबकी टर्ब कृषि में खेती रहती है, (3) छोटे-छोटे खेतों पर मजदूरी लागू हो रही है, (4) भूमि का केन्द्रीयकरण नहीं हो पाता, (5) कुटीर उद्योगों के अभाव में अधिकतम जनसंख्या को रोजगार मिल जाता है, (6) फसलों के परती रहने में सुविधा रहनी है, (7) पूरे कृषक परिवार को काम मिल जाता है, (8) हर व्यक्ति को बुरे मौसम में भी कृषि में कुछ न कुछ प्राप्त हो ही जाता है, तथा (9) कई फसलें एवं माद्य बिकर किसान स्वावलम्बी बन सक्ता है।

भारत सरकार के कृषि प्रबन्ध अध्ययनों द्वारा निष्कर्ष निकाले गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी यह सिद्ध करते हैं कि देश को अर्थ-व्यवस्था में छोटे खेतों का महत्व बड़े खेतों की अपेक्षा अधिक है। ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं — 1) प्रति एकड़ उपज और खेतों के लाभ का अनुमान उत्पन्न है जहाँ खेती का बाजार बिक्री छोटा होगा, प्रति एकड़ उपज उतनी ही अधिक होगी, (ii) बड़े खेतों की तुलना में छोटे खेतों पर अधिक श्रमिक काम में लगाए जा सकते हैं, (iii) जिनसे भी राज्यों के आकड़े उपलब्ध हैं, उन सब में छोटे फार्म पर बड़े खेतों की अपेक्षा अधिक उपज होती है;

(iv) छोटे खेत की अधिक प्रतिफल भूमि सिंचित है; (v) सिंचित भूमि में अनिचित भूमि की तुलना में अधिक आम्हिकी की आवश्यकता होती है, (vi) छोटे खेतों में काफी सस्या में बाहरी आम्हिक-मजदूरी पर रसे जाते हैं ।

उप-विभाजन एवं अपसाइडन के दोष भूमि के उप-विभाजन एवं अपसाइडन के दोष बहुत बम्भीर हैं और इन दोषों की तुलना में गुणों का महत्व कीका पड जाता है । इसके प्रमुख दोष इस प्रकार हैं —

१। १० साल में उप-विभाजन तथा अपसाइडन के सामूहिक दोषों का पणन करते हुए कहा है, “भूमि के टुकडों में बट जाने के कारण बिमान का उत्पाद लण्डा पड जाता है, आम की बहुत हानि होती है, हद-बन्धों के कारण बहुत-सी भूमि व्यर्थ चली जाती है और खेतों पर बहन बोरी करना अनम्भव हो जाता है ।”¹

१ भूमि का दुरपयोग खेत छोटे-छोट टुकडों में बटे होने में खेतों के बीच में मेड एवं रास्ते बनाने में बहुत-सी जमीन, जिसमें रंगी होनी चाहिय, बेकार हो पडी रहती है ।

२ आम व समग्र का दुरपयोग खेत दूर-दूर होने से कृषक को एक टुकड से दूसरे में जाने के लिए काफी समय एवं श्रम नष्ट करना पडता है ।

३ जोत को अनाविकना निरन्तर उप-विभाजन के कारण, खेत छोटा होते होते इतना अनाविक हो जाता है, जिससे कृषक के परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो जाता है ।

४ भिचाई में असुविधा छोटे-छोटे टुकडों की सिचाई के लिए न तो वह हर टुकडे में मुजा खदना सकता है और न प्रत्येक टुकडे के पास से होकर नाली हो निकलना सकता है, जिसमें भिचाई की सुविधा से खेत बचित रह जाते हैं ।

५ कृषि-सुधार में असुविधा खेतों का छोटे-छोटे टुकडों में बटे होने से कृषि-सुधार भी सम्भव नहीं हो पाता । ट्रैक्टर, ब्वाटर, डीजल इन्जिन एवं अन्य आधुनिक कृषि-यन्त्र छोटे-छोटे खेतों पर लाभदायक नहीं होते । पक्की बाड बनाना व पशुओं के बाडे खाना भी इन टुकडों पर लाभदायक नहीं होता ।

६ मुकदमेबाजी में वृद्धि : छोटे-छोटे खेतों की मेडे बनाने में भी अनेक दिक्कतें आती हैं । एक किसान ने दूसरे व्यक्ति की जरा भी भूमि मेड बनाने के लिए ली तो लडाई-झगडा हो जाता है । यहां तक कि मुकदमेबाजी की नीबत आ जाती है ।

1. “Fragments too destroys enterprise, results in an enormous wastage of labour, leads to a very large loss of land owing to boundaries and makes it impossible to cultivate holdings as intensively as would otherwise be possible.”

गावों में ऐसी घटनाएँ होना सामान्य बात हो गई है। इसी तरह पानी की माँगियाँ व पशु निवालेने के भी जगह होते हैं।

7. उर्वरता ह्रास भूमि के एक छोटे टुकड़े में परिवार की साध आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए सभी टुकड़ों पर खेती करनी होगी है। भूमि परती नहीं छोड़ी जा सकती, जिससे उर्वरा-शक्ति का उत्तरोत्तर ह्रास होना जाता है।

8. देख-भाल की कठिनाई पगलों की गुंथारने एक गद्दु-पगिरी से रस्ता के लिए खेतों की निरन्तर देख-भाल आवश्यक होती है। लेकिन दूर-दूर खेत होने के कारण कृषक उचित देख-भाल नहीं कर पाता।

9. उत्पादन व्यय में वृद्धि छोटे और बिसरे हुए खेतों पर कृषि करने में उत्पादन व्यय अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। एक अनुमान के अनुसार हर 500 मीटर की दूरी पर भूमि के ऊपर 53% खाद के जाने पर 20% से 25% तथा खरिदना से घर तक उपज लाने में 15% तक व्यय बढ़ जाते हैं।

10. किसानों के ऋणभार में वृद्धि छोटे-छोटे खेतों पर लागत व्यय अधिक होने के कारण लाभ कम मिलता है। कृषक कठिनाई से अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाता है। गावों विपत्तियों के लिए कुछ भी नहीं बचा पाता। जीवन में आकस्मिक विपत्तियाँ आनी ही रहती हैं, उसे ऋण सेना ही पड़ता है, जिससे उनका ऋण-भार बढ़ता जाता है।

11. वस्तुतः यह गहन खेतों का न होना भूमि के सीमित होने के कारण, भारतीय किसान न तो अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया की भाँति बस्तुतः खेती को ही अपना सकता है और माधनों की सीमितता के कारण न ही हार्लैंड की भाँति गहन खेती ही कर सकता है। डा० मान के शब्दों में “वस्तुतः बस्तुतः में छोटे खेतों की सभी बुराईयाँ हैं, क्योंकि मशीनरी और श्रम बचाने वाली विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता और दूसरी ओर बड़े खेतों की भी बुराईयाँ इसमें हैं क्योंकि स्वयं किसान द्वारा वस्तुतः गहन कृषि की विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता जो कि छोटे खेतों में व्याप्तियों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ है।”

खेती के उप-विभाजन एवं अर्ध-संघन के दोषों की व्याख्या करते हुए, डा० राधाकमल मुखर्जी ने ठीक ही कहा है, “भारत के अधिकांश भागों में कृषि की

1. “It has, in fact all the evils of very small holdings in that it prevents the use of machinery and labour-saving methods and on the other hand, of large holdings in that it hinders the adoption of really intensive cultivation by hand labour which is a great advantage of the small holders.”

अनुरादकता के लिए किसानों की जममानता लापरवाही अथवा काम करने की अनिच्छा आदि की अपेक्षा जोतों के उप-विभाजन तथा अपसृष्टन अधिक उत्तरदायी है। इस प्रकार की जोतों में किसान को पर्वीन मात्रा में काम नहीं मिलता जिससे वह वर्ष के अधिकांश समय में बेकार रहता है। किसानों की श्रृण-श्रुतता जोतों के उप-विभाजन का कारण तथा परिणाम दोनों है और कभी-कभी उदासीनता तथा श्रृण प्रसवता साथ-साथ चलती है।¹

उप-विभाजन एवं अप-सृष्टन के दोष निवारण के उपाय

जोतों के उप-विभाजन एवं अपसृष्टन के कारण, भारत जैसे कृषि-प्रधान देश की खेती अनाधिक हो गई है। वह देश जो कभी धन-धान्य से परिपूर्ण रहता था, आज अकाल के कगार पर खड़ा है। अतः इस समस्या का हल निकालना परमावश्यक है। इस समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं—

- (क) आधिक जोतों का निर्माण,
- (ख) सहकारी कृषि,
- (ग) सहकारी ग्राम प्रबन्ध, तथा
- (घ) अन्य सुझाव।

(क) आधिक जोतों का निर्माण — उप-विभाजन एवं अपसृष्टन के दोषों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि आधिक इकाइयों का निर्माण किया जाय। इस दिशा में निम्न कदम उठाये जाने चाहिए

1. जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण — इस व्यवस्था के अनुसार जिन छोटी-छोटी के पास निर्धारित अधिकतम सीमा में अधिक भूमि हो, वह सरकार के अधिकार में आ जानी चाहिए ताकि इस भूमि को उन किसानों को दिया जा सके जिनके खेत अनाधिक हैं। इससे अनाधिक आठे आधिक एवं लाभकर बन सकेंगी।

2. वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था — जिन किसानों के पास बहुत ही छोटी जोतें हैं, उन्हें अपनी जोतें छोड़ कर गांवों में अन्य वैकल्पिक भन्धे लेने को प्रेरित करना चाहिए। इससे छोटी छोटी जोतों को मिला कर आधिक जोत बनाने में सहायता मिलेगी।

1. In many tracts, as the incidence of arable use is due more to the small size and scattered nature of the holdings than to ignorance or want of alertness on the part of the peasants. Such holdings do not afford sufficient work for the cultivator and leave him almost unemployed during most part of the year. Agricultural indolence is at once the cause and effect of the excessive division of holdings and very often enforced idleness and indebtedness go together.

3 उत्तराधिकार नियमों में सुधार—वर्तमान प्रचाली के अनुसार पिता की सम्पत्ति से पुत्र-पुत्रियों को समान हिस्सा मिलता है। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि भू-सम्पत्ति केवल बड़े खंडों को ही प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था भी सामाजिक न्याय के प्रतिकूल होगी तथा इससे असन्तोष की भावना पैदा होना स्वाभाविक ही है, अतः हमें यह सुधार और जरूर दिया जाय कि भू-सम्पत्ति तो बड़े खंडों को ही मिले, लेकिन यह इस सम्पत्ति की आय में से आनुपातिक भाग अपने भाइयों को भी दे। इससे उप-विभाजन की समस्या काफी हद तक सुधर जायेगी।

4. विभाजन की न्यूनतम सीमा-निर्धारण—सरकार को अधिनियम बना कर विभाजन की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए, जिससे अधिक भूमि का विभाजन न हो सके।

5. बंजरभूमि—बंजरभूमि से सारपय कई छोटे-छोटे खेतों की पुनर्गठनवादा द्वारा एक बड़े खेत या खेत में परिणत करना है। इस व्यवस्था में सभी कृषकों के बिखरे हुए छोटे-छोटे खेतों को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर हर भू-स्वामी को उनकी आवश्यकतानुसार एवं एक एक खेतों का वितरण कर दिया जाता है। स्ट्रिकलैंड के अनुसार, "बंजरभूमि वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा स्वामित्वधारी कृषकों को अपने चर-उधर बिखरे हुए खेतों के बदले में उसी किस्म एवं कुछ उत्तरी ही आकार में एक-दो खेतों को देने के लिए राजी किया जाता है। इस तरह का विनियम यूरोप के सभी देशों में पिछली तीन सताब्दियों में सम्पन्न हुआ है।"¹

(ख) सहकारी खेती (Co-operative Farming)—सहकारी खेती सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों के बीच वह रास्ता है डा० ओटो शिलर (Otto Schiller) के शब्दों में, 'सहकारी कृषि कृषि-व्यवस्था का वह रूप है, जिसमें भूमि का प्रयोग संयुक्त रूप में किया जाता है।'² जिन किसानों के पास छोटे छोटे या मध्यम आकार के खेत हैं, वे सहकारी कृषि समिति बना कर सहकारी ढंग पर कृषि कर सकते हैं। इससे इन खेती के छोटे आकार समाप्त हो जायेंगे और बड़े पैमाने की कृषि के लाभ प्राप्त हो सकेंगे। सहकारी कृषि मुख्यतः चार प्रकार की हो सकती है—(1) सहकारी

1 "It is a process whereby owners of right-holding tenants are persuaded or compelled to surrender their scattered plots and receive in their place an equal area of land of the same quality in one or two blocs. An exchange of this kind has in the past three centuries been carried out in all the countries of Europe."

—Strick Land

2 "Co operative Farming is understood as a form of farm management in which the land is used jointly."

—Otto Schiller

बच सकते हैं। इनका समित्त विवरण नीचे दिया जा रहा है

(2) सहकारी उ

(3) सहकारी कायदा व दृष्टि (Co-operative law and vision)

(4) अग्रहारी सामयिक दुः

सहकारी खेती के सूत्र—भारतवर्ष में भूमि सुधारों का अन्तिम लक्ष्य सहकारी

सहकारी खेती के मूल—भारतवर्ष में भूमि सुधारों का अन्तिम लक्ष्य सहकारी खेती की स्थापना करना है। सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों का प्राप्त करने में सहकारी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी के शब्दों में, “मेरा यह दृढ़ विश्वास है

कि हम तब तक कृषि का पूरा लाभ नहीं उठ सकते, जब तक कि हम सहकारी संती न करने लगे। वया यह बात विवेक सम्मत प्रतीत नहीं होती कि एक गांव के 100 किसान परिवार जमीन की 100 हिस्सों में बांटने के बजाय मिल कर सामूहिक संती करें और उससे प्राप्त आय आपस में बांट लें।" स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू भी सहकारी कृषि के प्रबल समर्थक थे। सामान्यतः सहकारी कृषि से निम्नांकित लाभ प्राप्त होते हैं—

(1) सहकारी कृषि में कृषि उपज में कृषि होगी, (2) गांवों में रहने वाले लोगों की गरीबी दूर होगी तथा आमवासियों में इससे एक नए जीवन एवं एक नई भाषा का संचार होगा, (3) सहकारी कृषि में वर्गहीन समाज (classless society) की स्थापना करना सरल एवं सुविधापूर्ण होगा, (4) खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार (State Trading in Food grains) को बन्द मिलेगा, (5) जोतों की अधिकतम सीमा के निर्धारण में सहायता प्राप्त होगी, (6) सहकारी कृषि उप-विभाजन एवं अपजगत के दोषों को दूर कर सकेगी तथा वैज्ञानिक कृषि को सम्मन देनादेगी, (7) धन-शक्ति की पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकेगा, (8) कृषि में सम्मिश्रित पूँजी, जैसे बैंक, कृषि-यंत्र, निपाई के साधनों का अच्छी प्रकार से उपयोग सम्भव हो सकेगा (9) सहकारी कृषि द्वारा फसलों का नियोजन (Crop-planning) सम्भव हो सकेगा (10) कृषि सम्बन्धी आकटे एवजिन करने में सुविधा होगी और विश्वासनीय आकड़े प्राप्त किये जा सकेंगे, (11) सहकारी कृषि द्वारा कृषकों की सामाजिक सुरक्षण, अच्छे निवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाएँ दीगई जा सकती हैं, (12) सहकारी कृषि के पञ्चमरूप सरकार तथा कृषकों में अधिक सहयोग बढ़गा जिससे सरकार को अपनी कृषि नीति लागू करने में सुविधा होगी, जैसे खाद्यान्न वसूली की नीति, बीजों के वितरण की नीति आदि तथा (13) सहकारी कृषि के पञ्चमरूप किसानों का सामाजिक एवं नैतिक स्तर ऊँचा उठेगा, सामूहिक भावना (Community spirit) पैदा होगी तथा जीवनश्रीव भावना का विकास होगा।

सहकारी संती के दोष—सहकारी संती का विरोध सामान्यतः निम्न कारणों से किया जाता है।

(1) कृषक में निजी उत्थम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो जायेगी तथा वह केवल एक श्रमिक मात्र रह जायेगा, (2) किसान का अपनी भूमि से इतना लगाव है कि वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए सहकारी संती की सफलता में संदेह है, (3) सहकारी कृषि यंत्रीकरण की प्रोत्साहित करेगी, पञ्चमरूप बेरोजगारी बढ़ जायेगी, (4) सहकारी कृषि सामानियों के निर्माण एवं संचालन

के लिए योग्य तथा कुशल प्रवर्धकों का अभाव है, (5) महकारी कृषि के अन्तर्गत उपज में प्राप्त लाभ तथा मजदूरी का वितरण करना कठिन कार्य होगा, (6) भारतीय कृषक हदियों से बचा होने के कारण भए विचारों का स्वागत नहीं करता, अतः भारत का ग्रामीण क्षेत्रीय घातावरण महकारी कृषि के अनुकूल नहीं है, तथा (7) बड़े खेतों की अपेक्षा कई छोटे खेतों से अधिक उपज प्राप्ता होती है।

(ग) सहकारी ग्राम प्रबन्ध (Joint Village Management)—योजना लायीय न उप-विभाजन एवं अपखण्डन में सुविधा पाने के लिए अल्पम लक्ष्य महकारी ग्राम-प्रबन्ध रखा है। इसके अन्तर्गत समस्त गांव को एक इकाई माना जायेगा। भूमि पर स्थानित छोटे अक्षित-विशेष का हो होगा, विस्तृत खेतों का काम सामूहिक रूप से किया जायेगा। गांवों की सारी जमीन बड़े-बड़े हिस्सों या ब्लॉकों में बाँट दी जायेगी, ताकि बड़े पैमाने की कृषि के लाभ प्राप्त हो सकें। इस प्रकार भूमि के समस्त वर्तमान अधिभार तथा पैतृक सम्पत्ति के मान्य एवं मदा से चले जा रहे नियम सुरक्षित बने रहेंगे। यह व्यवस्था जनतावादी है तथा इसके द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग में परिवर्तन किया जा सकता है।

ग्रन्थ सुझाव

1. भौतिक विकास—भारतवर्ष में बड़ पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाय तथा घुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाय, ताकि भूमि पर से जनसंख्या का भार कम हो सके और जोतों का उप-विभाजन घट सके।

2. जनसंख्या-वृद्धि पर नियंत्रण—भारत में उप-विभाजन एवं अपखण्डन की समस्या, जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ जटिल होती गई है। जन जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए, ताकि भूमि का उप-विभाजन और न हो पाये।

3. शिक्षा का प्रसार—शिक्षा के प्रसार से श्रेष्ठ उन्नत खेती के महत्त्व को समझेंगे, जिनमें भूमि का उप-विभाजन व अपखण्डन नहीं होने देंगे। साथ ही महत्वांगी खेती एवं वृक्षबन्दी जैसी व्यवस्थाओं में रुचि लेने लगेंगे।

4. नये क्षेत्रों में खेतों की जगह—कृषि में अभी तक लाभ में न आ रही जमीन एवं बंजर भूमियों का कृषि योग्य बनाना चाहिए, जिनमें कृषि क्षेत्रों का विस्तार हो सके। हाथ-हीन ग्रामीण कृषकों की ऐसी भूमि के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5. भूमि का राष्ट्रीयकरण—कुछ विद्वानों का मत है कि भारत की समस्त भूमि का राष्ट्रीयकरण करके सरकारी कृषि व्यवस्था प्रचलित की जाय, पर यह सुझाव व्यावहारिक प्रणीत नहीं होता।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम -

(1) अधिकतम जोत की सीमा का निर्धारण—भारत के विभिन्न राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले अधिनियम पारित हो चुके हैं। ये अधिनियम निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी अधिकतम भूमि रख सकता है। साथ ही ये भविष्य में भूमि प्राप्त करने पर भी रोक लगाते हैं।

इन व्यवस्था को लागू करने के कारण राज्य-सरकारों की बड़ी मात्रा में भूमि प्राप्त हुई है, जिसका बटवारा भूमिहीन किसानों में किया जा रहा है।

(2) भावी उप-विभाजन पर रोक—भविष्य में भूमि के और अधिक टुकड़े न हो सकें, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ऐसी ग्यूनम सीमाएँ निर्धारित कर दी गई हैं, जिसमें नीचे उप-विभाजन नहीं हो सकता। कुछ राज्यों में ग्यूनम क्षेत्र इस प्रकार हैं—देहली 8 एकड़, उत्तर प्रदेश 3½ एकड़, मध्य प्रदेश 5 एकड़ सिंचित एकड़ 15 एकड़ असिंचित भूमि।

(3) चकवन्दी की व्यवस्था—जोनों की चकवन्दी का अर्थ है, जिसके कृषकों के स्थान पर किसान को एक चक या उन क्षेत्रों के कुल मूल्य के बराबर एक खत प्रदान करना है। उप-विभाजन एवं अपखण्डन की समस्या का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाधान है। चकवन्दी किसानों द्वारा स्वयंसेवा में की जा सकती है, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से की जा सकती अथवा सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त पचासत के सहयोग से की जा सकती है। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चकवन्दी की व्यवस्था पर पर्याप्त जोर दिया है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत 1 20 करोड़ हेक्टर भूमि की चकवन्दी हो चुकी थी। तीसरी योजना में 2 4 करोड़ हेक्टर भूमि की चकवन्दी की जानी थी। मार्च 1969 तक 2 96 करोड़ हेक्टर भूमि की चकवन्दी की जा चुकी थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 में 3 90 करोड़ हेक्टर भूमि पर चकवन्दी की जाने की योजना है। चकवन्दी का कार्य पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र में सतोपजनक रहा है, जबकि गुजरात, मैसूर व बिहार में इसकी प्रगति धीमी रही है। भारतीय में चकवन्दी सबसे अधिक 13 राज्यों एवं मधीय क्षेत्रों में पारित किए जा चुके हैं। आसाम, जम्मू व कश्मीर तथा पश्चिमी बंगाल में अभी तक चकवन्दी का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। आशा है कि ये राज्य भी इस क्षेत्र में शीघ्र काम उठावेंगे।

(4) सरकारी कृषि एवं सहकारी पाप-प्रबन्ध—सरकार ने कृषि के विकास में सहकारी कृषि के महत्व को स्वीकार करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी कृषि के विनाश की व्यवस्था की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रायः सभी राज्यों में सहकारी कृषि के सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाये गये। द्वितीय योजना-

वधि में सहकारी कृषि के विकास हेतु उचित व हद नीव रखी गई। तृतीय योजना के अन्त तक 3,500 कृषि (सहकारी) समितियां बनी थी। मार्च 1966 के अन्त तक 2,749 सहकारी कृषि समितियां मार्गदर्शी परियोजनाओं (pilot-projects) के क्षेत्रों में स्थापित हो चुकी थी और 277 लाख एकड़ कृषि क्षेत्र उनके अधिकार में था। 30 जून 1969 तक आरम्भिक वर्ष में कुल 8143 सहकारी कृषि समितियां थीं, जिनकी संख्या संस्था 22 लाख थी। केवल 2 प्रतिशत कृषकों ने ही सहकारी कृषि समितियां स्थापित की हैं तथा ये कुल क्षेत्र के लगभग भाग अर्थात् 4 प्रतिशत की मात्रा करती हैं। इन समितियों के अन्तर्गत 45 लाख हेक्टर कृषि क्षेत्र था।

फरवरी 1960 में प्रकाशित निजलिगुप्ता समिति की रिपोर्ट में सहकारी समितियों की सफल बनाने के सम्बन्ध में कहा गया है, 'असफल सहकारी समितियों का अध्ययन यह बतलाना है कि वे जिन कारणों से असफल हुईं, उन्हें दूसरी सहकारी समितियों में दूर किया जा सकता है और सफल सहकारी समितियों का उदाहरण हमारे इस विश्वास की पुष्टि करता है कि सहकारी खेती छोटे और मध्यम वर्ग के कृषकों के लिए अच्छी है और यह सफल हो सकती है। आवश्यकता इन बातों की है कि सरकार और जनता दोनों मिल कर इस विषय में निरन्तर प्रयास करें।'¹

(5) बेकार भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए प्रयत्न—बेकार भूमि को खेती के योग्य बनाने और कृषि धमिकों को बसाने की केन्द्र-प्रयोजित योजना के अन्तर्गत मार्च 1968 तक 1,83,468 हेक्टर बेकार भूमि खेती योग्य बनाई जा चुकी थी। इसमें में सबसे अधिक 20,738 हेक्टर भूमि महाराष्ट्र में तथा उसके बाद 44,536 हेक्टर भूमि पंजाब में है। इस भूमि पर एक लाख से अधिक भूमिहीन अधिक अधिक बसाये जा चुके हैं। सबसे अधिक परिवार अर्थात् 40,039 परिवार पंजाब में बसाये गये हैं। भूमि-सुधार ध्येय तथा श्रम व अनुदान के रूप में बसाने के प्रागन्मिक ध्येय पर सरकार ने 4 करोड़ 59 लाख रुपये खर्च किये।

अभी केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का लाख अधिक भूमिहीन कृषि धमिकों को ही मिल रहा है। ऐसे क्षेत्रों में कृषि कार्य समुदाय खेती सहकारी समितियों के द्वारा किया जा रहा है। सुधारी गई भूमि के अधिकतम भाग में खेती की जा रही है।

1. 'These successful societies offer experience which can be avoided in others and successful ones confirm our belief that co-operative farming is good for small and medium cultivators and can be a success. What is needed is the sustained and continuous efforts on the part of the people and the government.'

उप-विभाजन एवं अपसृष्टन भारतीय कृषि के लिए अनिवार्य बना हुआ है। इससे छुटकारा पाना हमारे लिए आवश्यक है, अन्यथा हमारी कृषि की अवस्था पिसड़ी रह जायेगी। खेतों के उप-विभाजन एवं अपसृष्टन को रोकने के जिन उपायों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, उनमें सहकारी कृषि ही सर्वोत्तम है एवं देश की परिस्थितियों के अनुकूल है। अतः इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न

1. आर्थिक जोन किसे कहते हैं ? भारत में कृषि जोनों के उप-विभाजन तथा अपसृष्टन के कारण जोर दोष मक्षेप में समझाइये तथा इन समस्या के उपचार के लिए सुझाव दीजिए। (राजस्थान टी० टी० सी० प्रश्न वर्ष कला 1964)

2. मक्षिण टिप्पणी लिखिये—(1) भारत में कृषि जोन।

(राजस्थान टी० टी० सी० प्रश्न वर्ष कला 1965)

3. भारत में अलग-अलग कृषि जोनों की समस्या का विवेचन कीजिए। इसके उपचार के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ? (बांगरा बी० ए० 1965)

4. भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से कृषि-जोनों के विभाजन और अपसृष्टन की समस्या को दूर करने के लिए जो उपाय ग्रहण किये गये हैं, उनका विवरण दीजिए। (राजस्थान टी० टी० सी० प्रश्न वर्ष कला 1968)

भारत में सिंचाई, उर्वरक एवं अन्य कृषिगत आदान

(Irrigation, Fertilizers and other Agricultural
Inputs in India)

"The need for providing irrigation facilities to all villages cannot be emphasised too greatly. This is the foundation upon which agriculture depends for its progress and in the absence of which it remains a gamble."

—Mahatma Gandhi

भारत कृषि-प्रधान देश है। कृषि-उत्पन्न पानी की उपलब्धि पर निर्भर करती है। सामान्यतः पानी वर्षा से प्राप्त होता है, परन्तु वर्षा भारत में अनिश्चित रहती है और कृषि को केवल वर्षा के सहारे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अतः कृषि-उत्पादन-क्षेत्र के लिए सिंचाई का महत्त्व बढ जाता है। सिंचाई के अभाव में भारतीय कृषि वर्षा के हाथ का जुआ ही घनी रहेगी। अतः कृषि-विकास के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधनों का होना परमावश्यक है। सर चार्ल्स टूबीलियन के शब्दों में

"भारतवर्ष में सिंचाई ही सब कुछ है। जल सोने से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जब भूमि पर जल पड़ता है, तो भूमि की उर्वरा-शक्ति में कम से कम 6 गुनी वृद्धि होती है और वह भूमि जो कभी बंजर पड़ी रहती थी, उपजाऊ हो जाती है। अतः भारत में सिंचाई ही सब कुछ है।"¹

इसी सदर्भ में श्री नानावती व अत्रारिया के ये विचार उल्लेखनीय हैं, "भारतीय कृषि वर्षा के हाथ का जुआ है। किसी वर्ष वर्षा होती हो नहीं और यदि होती भी है तो मध्य से बहुत पहले या मध्य में बहुत बाद में, यहाँ तक कि सामान्य

1 "Irrigation is everything in India. Water is more valuable in India than gold, because when water is applied to land, it increases its productivity at least six fold and generally a great deal more."

वर्षा के वर्ष में भी समय पर वर्षा के न आने व वर्षा के मौसम के असमान वितरण के कारण भी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।¹

भारत में मिर्चाई की सुविधाओं के विकास की आवश्यकता एवं महत्व

भारत में मिर्चाई के लिए साधनों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग रोती पर आश्रित है और यहाँ की रोती स्वयं मिर्चाई पर आश्रित है। भारत में मिर्चाई के महत्व के कारण निम्न हैं—

1 वर्षा की अनिश्चितता—भारत में वर्षा अनिश्चित रहती है। कभी समय से पाव में वर्षा होती है, कभी समय से पहले ही निपल जाती है। कभी यदि प्रारम्भ में ठीक समय पर वर्षा हो गई, तो बाद के महीनों में वर्षा नहीं होती। फलस्वरूप भारतीय कृषि मानसून का जुआ बन कर रह जाती है। वर्षा की अनिश्चितता से कृषि की रक्षा मिर्चाई-व्यवस्था ही कर सकती है।

2 वर्षा का असमान वितरण—भारत के सभी भागों में वर्षा का समान वितरण नहीं है। यदि चेन्नई की में 500 नव पानी बरस जाता है तो राजस्थान के कई हिस्सों में 5 स भी कम पानी बरसता है। जल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रोती के लिए मिर्चाई की आवश्यकता पड़ती है।

3 वर्षा का असामयिक वितरण—भारत में अधिकांश जल-वृष्टि जून से अक्टूबर तक होती है। सर्दियों में बहुत बड़ी वर्षा होती है। वह भी गन्ध रपाना में नहीं होती। अतः जिन महीनों में वर्षा होती है, उनको छोड़कर अन्य महीनों में रोती के लिए मिर्चाई की आवश्यकता पड़ती है।

4 अधिक जल चाहने वाली फसलें—गन्ना, चावल, कपास आदि कुछ ऐसी फसलें हैं, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से जल चाहिए। ये फसलें केवल जहाँ जगहों पर उगाई जा सकती है, वहाँ मिर्चाई की पर्याप्त सुविधा हो। सर्दियों में वर्षा की कमी या अभाव के कारण रबी की फसल के लिए मिर्चाई परमावश्यक है।

5 कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये—भारत में अन्य देशों की तुलना में कृषि-उपज प्रति एकड़ बहुत कम है। मिर्चाई के साधनों में वृद्धि करके इसे बढ़ाया जा

1 'Indian agriculture has been called a gamble on rains. In any year, not only may the rains not arrive, but they may arrive too early or too late. Even a year of normal average rainfall may, thus, witness famine conditions because of the untimely commencement or end of the Monsoon and the uneven distribution of rainfall over the season.'

सकता है। उत्तम बीज, खादों तथा आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग का लाभ उसी समय उठाया जा सकता है जब वर्षापूर्व सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हों।

6 कृषि-योग्य क्षेत्रों के विस्तार के लिए भारत में बहुत सी भूमि सिंचाई के साधनों के अभाव में बेकार पड़ी हुई है। यदि सिंचाई की व्यवस्था समुचित प्रकार से हो जाय तो इन क्षेत्रों को लहलहाते क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, राजस्थान नहर के बन जाने से राजस्थान में कई जयहूँ नदी भूमि पर बेसी प्रारम्भ की गई है। इसी प्रकार बजर जमीन को भी सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है।

7 अभाव निवारण के लिये भारत जैसे अकाल-ग्रस्त देश में सिंचाई के साधनों का विकास करके, मानसून पर निर्भरता समाप्त की जा सकती है और वर्षा के अभाव से पड़ने वाले अकालों से बचा जा सकता है।

8 कृषि नियोजन की सफलता के लिये कृषि नियोजन से देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारी जा सकती है, परन्तु स्वयं कृषि नियोजन उसी समय सफल हो सकता है, जब वर्षा पर कृषि की निर्भरता समाप्त की जाय और सिंचाई के साधनों का विकास किया जाय।

9 उद्योगों के लिये कच्चे माल की उपलब्धता के लिये बहुत से उद्योग कृषि क्षेत्र के कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। कच्चे माल की निरन्तर उपलब्ध उसी समय हो सकती है, जबकि वर्षा या सहारा छोड़ कर सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की जाय।

10 सरकारों आय में वृद्धि सिंचाई के साधनों के विकास के फलस्वरूप कृषि-उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे व्यापार, उद्योग, परिवहन आदि सभी को लाभ होता है। गमस्त आर्थिक क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप सरकार को प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूपों में लाभ पहुँचता है।

11 बहुतों हुई जनसंख्या में राहत पाने के लिये देश में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिये अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ती है। अधिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा कर ही प्राप्त किये जा सकते हैं। उत्पादन बढ़ाना सिंचाई के साधनों पर निर्भर करता है।

12 बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या के हल के लिये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या को भी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कुछ सीमा तक हल किया जा सकता है, क्योंकि इन सुविधाओं के विकास से ग्राम पर नई प्रकार के काम मिल सकेंगे।

13 अन्य कारण उपर्युक्त कारणों के अलावा भारत में सिंचाई सुविधाओं

के विकास में अन्य कई मांगों की सम्भावना है, जैसे (i) इससे कारागाहों का विकास हो सकेगा, (ii) कृषि व कृषि-युग्मकों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा, (iii) कृषि-उत्पन्न में वृद्धि के फलस्वरूप विदेशी विनिमय सपट की समस्या हल हो सकेगी।

अतः सिंचाई के साधनों का भारत में बड़ा महत्व है और अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ इन साधनों के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में श्री नोब्ल (Knowles) के निम्न-कृत वाक्यांश महत्वपूर्ण हैं

“सिंचाई के कार्यों ने जीवन की रक्षा का प्रबन्ध किया है, क्योंकि भूमि की उपज उसके मुख्य तथा उसमें प्राप्त आय में वृद्धि हुई है। अतः दुर्भिक्ष के समय इस सहायता की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है और यह सम्पूर्ण क्षेत्रों की सम्पन्नता में सहायक हुई है।”¹

सिंचाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चतुर्थ योजना (1969-74) के प्रारूप में कहा गया है, “पर्याप्त मात्राओं एवं ठीक समय पर जल उपलब्ध होना कृषि उत्पादकता के प्रमुख निर्धारकों में से है। सघन कृषि की सम्माननाओं का लाभ उठाने में सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि वर्ष भर जल की सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती। देश के कुछ फसली क्षेत्र का भाग 2/3 पूर्णतः वर्षा पर ही निर्भर है जो कि वर्ष के कुछ ही महीनों में सकेन्द्रित रहती है। कच्ची-कच्ची वायुवा जल वर्षा तो पर्याप्त है, किन्तु पानी की उपलब्धता इसकी अपेक्षा होती है कि बहुत कमसे प्राप्त करने में कठिनाई रहती है। 70 प्रतिशत फसली क्षेत्र में वर्षा जल और अनिश्चित है, जिन कारण प्रमुख फसली पशुओं की समय कृषि सम्भव नहीं हो पाती। इस प्रकार सिंचाई का विकास भारतीय कृषि की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है।”²

भारत में जल की सम्भावनाएँ (Water Potential in India)

अनुमान है कि भारत में जमीन के ऊपर 1672 अर्ब 60 करोड़ घन मीटर (एक अर्ब 35 करोड़ 60 लाख एकड़ फुट) पानी है। जमीन के नीचे भी पानी का बड़ा भंडार है जिसका अभी अनुमान नहीं लगाया गया है। भूमि की सतह के ऊपर के पानी के सम्बन्ध में सरकारी तौर पर अध्ययन करके पहले यह अनुमान लगाया गया था कि करीब 555 अर्ब घन मीटर (45 करोड़ एकड़ फुट) पानी सिंचाई के योग्य है। लेकिन 1972 में सिंचाई आयोग द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार 666 अर्ब घन मीटर (54 करोड़ एकड़ फुट) पानी सिंचाई के योग्य है। जमीन के

1 Dr Knowles Economic Development of British Empire Overseas, Vol I pp 367-368.

2 Fourth Five Year Plan (Draft 1969-74) p 182

तीस 204 अरब घन मीटर (16 करोड़ 50 लाख एकड़ फुट) पानी सिंचाई के काम आ सकता है। मन् 1971 तक सिंचाई के काम में जमीन के ऊपर के जल साधनों में से 246 अरब 70 करोड़ घन मीटर (20 करोड़ एकड़ फुट) पानी तथा जमीन के नीचे के जल साधनों में से 98 अरब 60 करोड़ घन मीटर (8 करोड़ एकड़ फुट) पानी का उपयोग होने लगा था। सिंचाई वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पड़ोसी चीन (1951) के प्रारम्भ में 2 करोड़ 26 लाख हैक्टर था, जो बढ़ कर 3 करोड़ 90 लाख हो गया।¹

भारत में सिंचाई के साधन भानु जंमे बिजाल देव की भौगोलिक रचना एक ही नहीं है। दमोलिए महा पर विभिन्न साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। एक ओर यदि हमारे भारत के कुओं और तहरी की प्रशिक्षण है, तो दूसरी ओर बहिष्णो भारत में तालाबों की प्ररमार है। मक्षप में सिंचाई के विभिन्न साधनों का विवरण इस प्रकार है।

1 कुओं द्वारा सिंचाई (Well Irrigation) भारतवर्ष में यह अति प्राचीनकाल से सिंचाई का साधन रहा है। अनुमान है कि देव में 20 लाख से भी अधिक कुएँ हैं जिनमें से मात्र से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं साथ तापितनाडु पजाब व महाराष्ट्र प्रांतों में पाये जाते हैं। औसतम एर कुआ 5 एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकता है। भारत में कुओं व ट्यूब वेलों से विमुद्ध बोये गये क्षेत्र के लगभग 34% भाग पर सिंचाई हागी है। ट्यूब वेल 60 फुट से लेकर 300 फुट तक गहरा होता है और प्रति घण्टा 3,300 गैलन पानी खींच सकता है। एक ट्यूब वेल में 500 एकड़ की सिंचाई आसानी से की जा सकती है। ट्यूब-वेल द्वारा सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार पजाब गुजरात तथा महाराष्ट्र के क्षेत्र बड़े उपयुक्त हैं, क्योंकि वहां भूमि की निचली सतह में जल है तथा भूमि भी उपजाऊ है। सन् 1965-66 तक सरकार द्वारा स्थापित ट्यूब वेलों की कुल संख्या 10,000 थी। जमीनदापो द्वारा लगाय गये ट्यूब-वेलों की संख्या भी पर्याप्त है। एक अनुमान के अनुसार भारत में अब तक 11 लाख ट्यूब वेल निर्मित किये जा चुके हैं। कुएँ उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार गुजरात, पजाब, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में काफी संख्या में पाये जाते हैं। कुल संचित क्षत्र के लगभग 34% भाग में केवल कुओं से ही सिंचाई की जाती है।

2 तालाबों द्वारा सिंचाई नदियों या वर्षा के जल को संचित करके तालाबों का निर्माण किया जाता है। सिंचाई का यह साधन भी पुराना है। भारत में

विशुद्ध बोधे गये क्षेत्र के लगभग 3.4% भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाब बुजो की भांति व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हो सकते, बल्कि सरकार अथवा समाज के होते हैं। भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई के क्षेत्र हैं—तामिलनाडु, अण्ड्र, मंसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तालाबों के निर्माण में नहरों अथवा बुजों की अपेक्षा कम पूंजी लगती है तथा इनका उपयोग तुरन्त होने लगता है। इनमें सिंचाई करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि वर्षा के अभाव में पानी नहीं बच पाता और सिंचाई नहीं हो सकती है। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की लगभग 17 प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है।

3 नहरों द्वारा सिंचाई : सिंचाई की दृष्टि से वर्षा के बाद नहरों का ही स्थान है। भारत में नहरों सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। भारत में विशुद्ध बोधे गये क्षेत्र के 77% भाग पर तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लगभग 42 प्रतिशत भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। भारत में नहरें मस्ती, मुविधानक एवं मृत्तिरिक्त सिंचाई का साधन होने से अत्यधिक लोकप्रिय हो रही हैं। लम्बाई की दृष्टि से भारत में नहरें सर्वाधिक हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, तामिलनाडु तथा अण्ड्र प्रदेश में नहरों से सिंचाई होती है। नहरें तीन प्रकार की होती हैं

(क) बारहमासी या स्थायी नहरें ये नहरें सर्वत्र सिंचाई के लिए पानी बनाये रखती हैं तथा इनके द्वारा सिंचाई नियमित व समानांतर रहती होती है। सरकार इस प्रकार की नहरों के निर्माण पर जोर दे रही है।

(ख) मौसमी या अस्थायी नहरें इनमें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी आता है। प्लवङ्ग में वर्षा के मौसम में ही जल प्रदान कर सकते हैं।

(ग) बाँध की नहरें ये वे नहरें हैं जिनमें बाँधों के दोनों किनारों पर बांध लगाता पानी इनटूटा किया जाता है और सूखे मौसम में उनका उपयोग किया जाता है।

4 नदी-घाटी-योजनाओं द्वारा सिंचाई - “नदी घाटी-योजनाएँ अत्यन्त भारत के तीर्थ-स्थान हैं” स्वर्गीय पं० नेहरू के इस वाक्य में नदी-घाटी योजनाओं के महत्व की झलक मिलती है। भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पञ्चायत देश के आर्थिक संस्थान में कृषि के महत्वपूर्ण योगदान को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के निर्माण का बीड़ा उठाया है। इन योजनाओं से एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी, यथा-सिंचाई की सुविधा, जलविद्युत का निर्माण, नौकायन, बाट-निष्पन्न, भूमि-वटाव-निष्पन्न, वृक्षारोपण, मत्स्य उद्योग का विज्ञान आदि।

भारत की प्रमुख नदी-घाटी योजनाएँ : भारत की प्रमुख नदी-घाटी योजनाएँ अग्रलिखित हैं :

1 भाखरा नागल योजना यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है। इसे पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य को लाभ प्राप्त हो रहा है। इस पर 175 60 करोड़ रुपये की लागत की सम्भावना है। यह योजना सन् 1948 ई० में प्रारम्भ की गयी थी और लगभग पूरी हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष लगभग 67 6 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा रही है। इस योजना का सर्वाधिक महत्व यह रहा है कि उत्तरी राजस्थान व पूर्वी पंजाब के रेबीले भागों को सिंचाई का लाभ मिलने लगा है जिसके कारण ये क्षेत्र अनाज की परिधि के बाहर हो गये।

2 दामोदर घाटी योजना दामोदर घाटी योजना भी एक बहु उद्देशीय योजना है जो पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों में दामोदर घाटी क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई है। जल संग्रह करने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत नदी पर बार हस्तों पर बांध बनाए गए हैं और नदी के दोनों ओर नहरें निकाली गई हैं। नहरों से लगभग 973 लाख एकर भूमि पर सिंचाई होने की सम्भावना है। इस योजना में सिंचाई का लाभ बंगाल को तथा अन्य लाभ बिहार को भी प्राप्त होता है।

3 तुलसीदा योजना इस योजना को आन्ध्र प्रदेश व मैसूर राज्य मिल कर विधानित कर रहे हैं। यह योजना लगभग 3 93 लाख हेक्टर भूमि को सिंचाई का लाभ द करेगी तथा इस पर 19 27 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। यह योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्पन्न हो जायेगी। इस परियोजना से 3 83 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई प्रारम्भ हो चुकी है।

4 हीराकुण्ड योजना यह उड़ीसा राज्य की योजना है तथा इस योजना के अन्तर्गत महानदी पर हीराकुण्ड जलाशय बनाया गया है जो सिंचाई में सभी जलामयों से विषय है। यह जलाशय 15 748 फुट लम्बा है और इससे 63 फुट एकड़ जल का संग्रह हो सकता है। इस योजना को दो भागों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम भाग पूरा हो चुका है। इस पर 67 82 करोड़ रु० व्यय हो चुके हैं और 24 3 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई की सुविधाएँ मिलने लगी हैं। दूसरे भाग से 6 38 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो गयी तथा इस पर 14 95 करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है।

5 राजस्थान नहर परियोजना जुलाई 1957 में स्वीकृत राजस्थान नहर योजना राजस्थान की यह भूमि की सिंचाई करेगी तथा इस योजना को पूरा करने में 184 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। जाना है कि नहर में लगभग 26 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी तथा बांधों के पूरा हो जाने पर सिंचित क्षेत्र 36 लाख

एकड़ के लगभग हो जायेगा। मिचाई की सुविधा के साथ साथ इससे गगानगर, वीकानेर तथा जैसलमेर जिलों का विस्तार रेगिस्तान हरियाली से लहलहा उठगा और घन-धान्य से परिपूर्ण हो जायेगा। राजस्थान नहर की कुल लम्बाई 3,500 मी होगी। इस नहर को दो चरणों में बनाने का प्रस्ताव है। पहले चरण में 122 मील तक मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान नहर 162 मील की लम्बाई तक (पीठर सहित) पूरी हो चुकी है और इसके नीचे का 22 मील का निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

6 **चम्बल योजना** चम्बल योजना राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकार की मिली जुली योजना है। इस योजना के अन्तर्गत चम्बल पर 3 बांध बनाये जायेंगे। पहला बांध कोटा में कोटा बैरेज के नाम से, दूसरा बांध बांधीनागर के नाम से तथा तीसरा रामाप्रताप सागर बांध के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना से राजस्थान की 7 लाख एकड़ भूमि को मिचाई की सुविधा प्राप्त होगी। कोटा बांध का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 20 नवम्बर मई 1960 से मिचाई के लिए पानी मिलने लगा है। बगरे और तीसरे चरण पर कार्य चल रहा है। कुल योजना के पूर्ण होने पर 566 लाख हेक्टर भूमि की मिचाई की सुविधायें प्राप्त होगी।

7 **गण्डक योजना** यह भारत व नेपाल सरकार की मिली जुली योजना है जिस पर दोनों सरकारों द्वारा 4 दिसम्बर, 1959 को हस्ताक्षर किये गये थे। इस योजना से भारत में उत्तरप्रदेश और बिहार की तथा नेपाल की लाभ प्राप्त होता है। इस योजना से लगभग 1490 लाख हेक्टर भूमि की मिचाई हो सकेगी। यह योजना अधिकांशतः चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण हो जायगी।

8 **कोसी योजना** इस योजना में भी बिहार तथा नेपाल की मिचाई की सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। इस योजना पर लगभग 66 करोड़ व्यय होने का अनुमान है तथा इसमें बिहार व नेपाल राज्य की 31 लाख एकड़ भूमि की मिचाई की जा सकेगी।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त अन्य कई और योजनाएँ प्रगति के पथ पर हैं और उन पर काम चल रहा है। इन योजनाओं में वाकलापादा योजना तथा मधु-राक्षी धाम, मागार्जुन सागर जलियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन तमाम योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर भारत में कृषि-योग्य निश्चित भूमि का भाग काफी बढ़ जायेगा।

सरकार एवं मिचाई की सुविधायें स्तम्भितता प्राप्ति के पश्चात् देश की कृषि-व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने मिचाई के माधनों के विकास की ओर ध्यान दिया। देश में कई बहुउद्देशीय योजनाओं को चाल दिया

गया जिनमें अन्य लाभों के अतिरिक्त कृषि-क्षेत्र भी सिंचाई का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है। नदी योजनाओं के साथ-साथ सरकार ने अनेक छोटी योजनाओं को भी लागू किया है। इनके अन्तर्गत कुओ, नलबूखो, छालाबो एवं नहरो के निर्माण कार्य था। ये योजनाएँ सीधे लाभ पहुंचाने वाली और अपेक्षाकृत कम खर्चीली रही हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व सन् 1950-51 में भारत में सिंचित क्षेत्र केवल 2.26 करोड़ हैक्टर था जो कुल कृषित क्षेत्रफल का 17.6% अर्थात् पाचवें भाग से भी कम था। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में, यही, मध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर लगभग 1830 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इन तीनों योजनाओं में वृद्धि न मध्यम सिंचाई कार्यक्रमों पर क्रमशः 300, 380 व 576 करोड़ रुपये व्यय किए गए। छोटी सिंचाई योजनाओं पर प्रथम द्वितीय व तृतीय योजना में क्रमशः 70, 200 व 260 करोड़ रुपये व्यय हुए।¹ इन योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई के क्षेत्र में लगाये गए नदियों के फलस्वरूप सन् 1965-66 में कुल सिंचित क्षेत्रफल में 83 लाख हैक्टर भूमि की वृद्धि हुई। इस प्रकार सन् 1965-66 में सन् 1950-51 की तुलना में कुल सिंचित क्षेत्रफल में लगभग 36.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सन् 1966 से 1969 तक अपनाई गई वार्षिक योजनाओं क्रमशः 134.5, 132.3, व 169.9 करोड़ रु. पड़ी व मध्यम सिंचाई योजनाओं पर खर्च किए गए। फलस्वरूप कुल सिंचाई क्षमता 375 लाख एकड़ हो गई। इस प्रकार 1950-51 से 1968-69 के मध्य सिंचाई प्रतिष्ठानों में 67% वृद्धि हुई।

अप्रैल सन् 1969 में केन्द्रीय सरकार ने श्री अनीत प्रसाद जैन की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। आयोग ने निम्न बातों पर विचार किया: (1) सन् 1903 से लेकर अब तक भारत में सिंचाई के विकास की समीक्षा करना तथा सिंचाई के फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि के योगदान पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, (2) सूखा एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था का अध्ययन करना तथा सुधार के लिए सुझाव देना, (3) ग्रामिणों की दृष्टि से देश को आपसिभिन्न बताने के लिए सिंचाई के सभी साधनों के विकास की विस्तृत रूपरेखा बनाना तथा इसके लिए आवश्यक शोधों का अनुमान लगाना, (4) विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए पानी की उपलब्ध देखना, (5) सिंचाई के कार्यों के प्रशासनिक व सप्लानेशनक पक्ष की जाँच करना जिससे परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके, (6) सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति के आधार को सुझाना, तथा (7) सिंचाई से सम्बन्धित किसी अन्य विषय की जांच करके उपयोगी सुझाव देना।

सिचाई आयोग ने अप्रैल 1972 में अपना विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है। इस प्रतिवेदन में सिचाई, की नई सुविधाओं के विकास के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिचाई : तृतीय योजना की समाप्ति के पश्चात् सूखे की स्थिति के कारण यह अनुभव किया जाना लगा कि वर्षा की अनिश्चितता की समस्या को लघु सिचाई योजनाओं द्वारा हल किया जा सकता है। फलस्वरूप तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मध्य की अवधि में कुओं व नलकूपों के विकास पर अधिक बल दिया गया। इस योजना में सिचाई की छोटी परियोजनाओं पर 516 करोड़ रु तथा बड़ी व मध्यम स्तरों की परियोजनाओं पर 951 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया जिनमें से 38.4 प्रतिशत धनराशि योजना के प्रथम दो वर्षों में खर्च की जा चुकी है। छोटी योजनाओं पर कुल व्यय की जानी धनराशि का भी 58 प्रतिशत भाग प्रथम 3 वर्षों में व्यय किया जा चुका है। चौथी योजना के दौरान 48 लाख हेक्टर अनिश्चित भूमि पर सिचाई की सुविधा प्राप्त होने लगेगी इस प्रकार सन् 1973-74 में 1950-51 की तुलना में सिचाई क्षमता लगभग दूनी हो जायेगी। इस योजना में छोटे कुपों के लाभार्थ योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी तथा भूमि गत जल के सर्वेक्षण व विज्ञान पर जोर दिया जायेगा। इस योजना में वर्षा व सिचाई व्यवस्था के अभाव वाले क्षेत्रों को भी प्राथमिकता देने की व्यवस्था है।

भारत अब तब तीस पंचवर्षीय योजनाएँ तीस वार्षिक योजनाएँ पूरी कर चुका है। इस अवधि में 68 बड़ी और 438 मझोली योजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया जिनके द्वारा कुल क्रमशः 1 करोड़ 64 लाख हेक्टर और 36 लाख हेक्टर भूमि की सिचाई हो सकेगी। इनमें 22 बड़ी तथा 329 मझोली योजनाएँ पूरी हुई हैं। शेष पर चुकी विभिन्न कारणों में काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे काम भी पूरे किए जा चुके हैं, जैसे छिछले या गहरे हुए खोदना, नलकूप लगाना, तालाबों की मरम्मत और छोटे लोती नदी-नाली का सुधारना काम आदि। इस सारी अवधि में (1951-71) सभी आकार की परियोजनाओं, पर कुल 38 अरब 23 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

भारतीय सिचाई व्यवस्था की कमियाँ :

भारतीय सिचाई व्यवस्था में कई दोष व कमियाँ पाई जाती हैं जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं

1. नियोजन के वर्षों बाद भी, अभी तक सिंचित क्षेत्र कुल क्षेत्र का केवल 23 प्रतिशत भाग ही है जो आवश्यकता से अत्यधिक कम है। आज भी भारतवर्ष में लगभग 77 प्रतिशत कृषि क्षेत्र मानसून की दया पर निर्भर करता है।

2 कुल सिंचित क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर फुओ तथा तालाबों से सिंचाई होती है जो स्वयं वर्षा पर निर्भर करते हैं। यदि वर्षा न हो तो ये साधन भी बेकार हो जाते हैं।

3 नालियों की यथोचित व्यवस्था के अभाव में, कई स्थानों पर पानी के जमाव (Water logging) की समस्या पैदा हो जाती है, जो भूमि की सतह पर रेह वाले मिट्टी (alkaline) को जन्म देती है।

4 अधिकांश बड़ी बड़ी नहरों में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता।

5 सिंचाई की उपलब्ध सुविधाओं का भी कई कारणों से यथोचित उपयोग नहीं हो पाता।

भारत में सिंचाई के साधनों के विस्तार में बाधाएँ भारतवर्ष के कृषि-विकास के लिए तीव्र गति से सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना आवश्यक है, परन्तु हम विकास के मार्ग में कई कठिनाइयाँ हैं, जो इस प्रकार हैं

1 धन सन्ध की कठिनाई सिंचाई की विविध योजना के विस्तार के लिए बहुत बड़ी धन राशि की आवश्यकता पड़ती है। दुर्भाग्यवश हमारा देश निर्धन है और बहुत अधिक धन राशि व्यय करने में असमर्थ है। किताब भी निर्धन है और उनसे करो के द्वारा सिंचाई के लिए अतिरिक्त कर्ज प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

2 तकनीकी शिक्षा की कमी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रायः हमें विदेशों से विद्वानों को बुलाना पड़ता है जो अत्यधिक खर्चीला है।

3 छुपको में नाबिस्वहीनता भारतीय कृषक नहरों पानी को सरकारी पानी समझ कर उसका अपव्यय करते हैं। मांग ही व पहले तो वर्षा की ओर आकर्षित होकर बैठ रहते हैं। जब वर्षा नहीं आती तब देर से नहरों या नलकूपों के पानी के लिए भाग दौड़ करते हैं, फलस्वरूप कमला की ठीक समय पानी नहीं मिल पाता।

4 सिंचाई के लिए आवश्यक सामग्री का अभाव सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इस्पात मशीनें एवं सीमेंट की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इनकी कमी के कारण हमारी सिंचाई योजनाओं की प्रगति मन्द पड़ जाती है।

5 अनुसंधान के क्षेत्र में शिथिलता सिंचाई की विविध योजनाओं से सम्बन्धित अनुसंधान के कार्य को प्रायः उपेक्षित रखा गया है। प्रायः योजनाओं को बिना पूरी तरह अन्वेषण किये ही प्रारम्भ कर दिया जाता है। कल पड़ होता है कि

या तो धन की बरबादी होती है या योजना विधेय को बीच में ही छोड़ दिया जाता है।

6 राजनैतिक उद्देश्यों की प्रधानता प्रायः नेतागण अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं को चालू करने के बारे में ऐसी सोचानाची करते हैं कि मानो ये योजनाएँ राष्ट्र की न होकर उनकी व्यक्तिगत योजनाएँ हों। उनका दृष्टिकोण घोट प्राप्त करने का होता है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे केवल अपने ही क्षेत्र का विकास चाहते हैं। इस प्रकार जिन क्षेत्रों में सिचाई की सचमुच ही आवश्यकता रहती है, वे क्षेत्र प्रायः योजनाओं की परिधि में ही नहीं आ पाते।

7 भ्रष्टाचार भारत में भ्रष्टाचार की ऐसी भरमार है कि इसकी चपट में बड़े-बड़े इंजीनियर तक भा जाते हैं। देश के हित व कल्याण का ध्यान न रख कर, ठेकेदारों से मिल कर पैसे खा जाते हैं। फल यह होता है कि एक ओर योजना की लागत बढ़ जाती है और दूसरी ओर योजनाओं के कभी भी टूटने या क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है।

8 जन सहयोग की कमी यद्यपि सिचाई सम्बन्धी योजनाएँ जनता के लाभ के लिए ही बनाई जाती हैं तो भी जनता इनके प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण रखती है। इसका कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि इन योजनाओं के बनने में उनसे राय नहीं ली जाती है तथा योजना के निर्माण की धीमी प्रगति एवं फँसे हुए भ्रष्टाचार में भी उनका उत्साह मारा जाता है।

सुझाव भैसूर राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री निजिलिंगप्पा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन, सिचाई सम्बन्धी योजनाओं को और अधिक लाभकारी बनाने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए, किया गया था। इन समिति ने जनवरी सन् 1965 में अपनी रिपोर्टें पेश कर दी थी और सिचाई व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव दिये थे।

1 नई योजनाओं साधारण के उत्पादन के दृष्टिकोण से बनाई जाय। उनही योजनाओं को लिया जाय जो पैमाने पर राष्ट्रीय हित की अधिकतम वृद्धि कर सकें।

2 सिचाई योजनाओं में लाभ का दृष्टिकोण को रचना चाहिए समिति के मतानुसार यह लाभ की दर 15% अर्थात् 100 रुपये के निवेश पर 150 रुप की उत्पत्ति-दर से होना चाहिए। यह लाभ दर सामान्य क्षेत्रों के लिए है। पिछड़े क्षेत्रों में भी लाभ प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए, चाहे लाभ की दर प्रारम्भ में कम ही क्यों न हो।

3. विभिन्न योजनाओं में समन्वय समिति ने छोटी, मध्यम व बड़ी योजना-

नालों में समन्वय स्थापित करने की सिफारिश की है, ताकि सिंचाई योजना को अधिकतम लाभकर बनाया जा सके।

4 ध्वज का स्थानान्तरण सिंचाई पर खर्च की निर्धारित राशि अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित न की जाय।

5 पहले पुरानी योजनाओं को पूरा किया जाय नई योजनाओं को उसी समय लिखा जाय जब पुरानी योजनाएँ पूर्ण हो जाय।

6 जल शुल्क को वसूली सिंचाई से होने वाले लाभों के 25 से 40% भाग को जल शुल्क के रूप में वसूल किया जाय।

7 सुधार शुल्क देने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता जिन क्षेत्रों के किसान सुधार शुल्क देने को तैयार हो, उन क्षेत्रों को नई सिंचाई योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।

अन्य सुझाव

1 सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान किसानों व सहकारी समितियों को तालाबों, नुओं व नलकूपों को बनाने के लिए सहायता के रूप में ऋण एवं अनुदान दिया जाय।

2 राज्य सरकारों को अधिक अनुदान केन्द्रीय सरकारों को चाहिए कि वह राज्य सरकारों को अधिक अनुदान देकर विविध प्रकार की सिंचाई की योजनाओं के विकास को सफल बनाये।

3 धनदान का उपयोग जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं के विकास का कार्य भिया जाय, वहाँ की जनता को धनदान के लिए प्रेरित किया जाय।

4 अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन—अनुसंधान केंद्रों की राशियाँ में वृद्धि की जाय तथा इसे प्रोत्साहन दिया जाय।

5 अनुचित उपयोग पर रोक पानी की किन्नूलक्ष्मियों को रोकने के लिए सिंचाई पर पानी के प्रयोग की मात्रा के आधार पर लिखा जाय।

उपसंहार

भारतवर्ष में सन् 1968-69 ई० तक कुल 31.9 मि. हैक्टर भूमि पर छोटी मध्यम तथा बड़ा योजनाओं द्वारा सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध थी, परन्तु देश की विभागला को देखते हुए ये सुविधायें अपर्याप्त हैं। भारत में अब भी भूमि का एक विभाग भाग जो सिंचाई योग्य है, सिंचाई की सुविधाओं से वंचित है। अतः यदि देश को अनाज, अन्नान, सुखमरी से बनाया है और देश को घन धान्य से परिपूर्ण करना है, तो सिंचाई के साधनों का विकास तेजी के साथ करना ही होगा। सिंचाई की सुविधाएँ मिलने पर हजारों एकड़ वज्र भूमि लहलहाते हुए खेतों में बदल जायेगी। देश

का साथ सफ़ट जो हमेशा हमे भयभीत बिये रहता है, हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा ।

रासायनिक उर्वरक

(Chemical Fertilizers)

स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने ठीक ही कहा था कि यदि हमारी खाद-समस्या नहीं सुलझती, तो हमारी सभी योजनाएँ बेकार हो जायेंगी । खाद-समस्या को सुलझाने के लिए पैदावार बढ़ाना आवश्यक है और पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग अत्यन्त आवश्यक है । यदि उन्नत कृषि विधियों और उत्तम जल-निकासी विधियों तथा कीड़ा मकोड़ों से फसलों की रक्षा करने के लिए प्रभाव-शाली उपायों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें तो देश में कृषि-उपज को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है ।

फसलों का आहार के रूप में नत्रजन, फास्फोरस और पोटैश की आवश्यकता होती है । ये समस्त पोषिक तत्व बड़े प्रसार के रासायनिक उर्वरकों में मिल जाते हैं, जिनमें अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया सल्फेट आदि छोटे-से तथा सल्फेट आदि पोटैश मुख्य हैं । अमेरिका ने इन्हीं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग मात्र से कृषि उत्पादन में ७१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । निश्चय ही भारत में इन उर्वरकों का प्रयोग घटा कर कृषि उपज में आन्तरीन वृद्धि की जा सकती है ।

भारत में उर्वरकों का प्रयोग विलग 2७ वर्षों में भारत में उर्वरकों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है, किन्तु अब भी भारत में प्रति एकड़ उर्वरक की औसत खपत विश्व का कुछ ३ भाग है । भारतीय कृषक खाद का प्रयोग नाम मात्र के लिए करते हैं । पशुओं की खाद को तो वे प्रायः ईंधन के रूप में जला डालते हैं और रासायनिक खाद खरीदने की उनमें सामर्थ्य नहीं है, कवस्वरूप भारत में कृषि योग्य क्षेत्र में प्रति हेक्टर उर्वरक का उपयोग विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम था, जैसा निम्न तालिका से ज्ञात होता है

उर्वरकों का प्रति हेक्टर उपयोग

(किलोग्राम में)

(1966-67 में)

देश	प्रति हेक्टर	देश	प्रति हेक्टर
नीदरलैंड	610	चीन (ताइवान)	270
बेल्जियम	520	विश्व	34
न्यूजीलैंड	१०3	भारत	8
जापान	3०4		

यदि अखिल भारतीय ग्रीकृत की तुलना में हम विभिन्न राज्यों द्वारा उपभोग किए जाने की स्थिति का अवलोकन करें तो कुछ राज्यों में उर्वरकों का प्रयोग अधिक मात्रा में हो रहा है, जैसे, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, पंजाब व आन्ध्र-प्रदेश में क्रमशः 41.82, 36.14, 23.24, 1.73 व 16.80 किलो उर्वरक प्रति हेक्टर उपभोग में आया जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इसका इतना उपभोग नहीं होता। उदाहरणार्थ, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य-प्रदेश व असम में प्रति हेक्टर केवल 2.16, 2.02, 1.95 व 0.98 किलोग्राम ही उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। देश में 'हरित क्रांति' को सफल बनाने के लिए उर्वरकों का निरन्तर उपयोग बढ़ता जा रहा है।

उर्वरकों का उत्पादन एवं आयात—भारतवर्ष में सुपर फॉस्फेट व एमोनिया सल्फेट द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व भी पैदा किया जाता था, लेकिन उर्वरक उद्योग का पस्तुत विकास पिछले 12 वर्षों में ही अधिक तेजी से हुआ है। इस समय देश में उर्वरकों का उत्पादन सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों में हो रहा है। निजी क्षेत्र में उर्वरक पैदा करने के कारखाने, एल्नोर, बाराणसी, दशोदा, विशाखापट्टनम, कोटा व कामपुर में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय उर्वरक निगम (Fertiliser Corporation of India) काय का सर्वोच्च बड़ा उत्पादक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1961 में की गई थी। इस निगम के अन्तर्गत सिदरी (बिहार), तमाल (पंजाब), ट्रांश्चे (महाराष्ट्र), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) तथा नामरूप (आसाम) में पाच इकाइयां उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं। निगम की 4 नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो शीघ्र ही उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देंगी। ये परियोजनाएँ बुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल), बरीली (बिहार), नामरूप (असम), व मिर्जरी (बिहार) में हैं।

इनके अलावा निगम ने तीन उर्वरक कारखाने स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी सम्भाला है। कोयले पर आधारित ये कारखाने सुसार में गवने बने होंगे। इनकी स्थापना रामगुडम (आन्ध्र प्रदेश), तल्लेर (उड़ीसा) और कोरवा (मध्य प्रदेश) में की जायेगी। रामगुडम व तल्लेर में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। कोयले पर आधारित प्रत्येक कारखाने की लागत लगभग 75 करोड़ रुपये होगी और उनकी दैनिक क्षमता 900 टन अमोनिया व 1500 टन मूरिया बनाने की होगी। यदि नाइट्रोजन बनाएँ तो इनमें से प्रत्येक कारखाना प्रति वर्ष 2,28,000 टन नाइट्रोजन बना सकेगा। सरकार ने गिज्ञान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि इस्त्रिया (पश्चिमी बंगाल) में 73 करोड़ रुपये की लागत से एक उर्वरक परियोजना प्रारम्भ की जायेगी। यह कारखाना देश में उपलब्ध ईंधन-तेल पर आधारित होगा और इसकी वार्षिक उत्पादन

क्षमता 3,77,000 टन नाइट्रोफास्फेट, 1,65,000 टन यूरिया और 60,000 टन सोडा एम होगी और नाइट्रोजन के हिसाब से इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,50,000 टन होगी और फास्फेट के हिसाब से 6000 टन।

भारतवर्ष में रासायनिक खाद के उत्पादन व आयात की स्थिति का अनुमान निम्न आकड़ों में लगाया जा सकता है :

(पौषण के हजार टनों में)

वर्ष	नाइट्रोजन खाद		फास्फेट खाद		पोटान खाद आयात
	उत्पादन / आयात		उत्पादन / आयात		
1951-52	16	29	11	—	6
1965-66	232	326	111	14	85
1969-70	716	667	222	94	120
1970-71	830	477	229	32	120

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजनाकाल में रासायनिक खादों की पूर्ति में काफी वृद्धि की गई है। चतुर्थ योजना के प्रारम्भ के दो वर्षों में नाइट्रोजन खाद की उत्पादन क्षमता 10.2 लाख टन से बढ़ कर 13.4 लाख टन हो गई है। इसका उत्पादन लक्ष्य योजना के अन्त तक अब संशोधित करके 24 लाख टन रखा गया है। उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी हाल के कुछ वर्षों में उर्वरकों का काफी आयात किया गया है। लगभग 130 र० का वार्षिक आयात हुआ है।

उन्नत बीज—कृषि उपज में वृद्धि के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग आवश्यक है। इनके प्रयोग से उत्पादन में 10-12 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। भारतवर्ष में 1966 से अपनाई जा रही नई कृषि नीति के अन्तर्गत विभिन्न फसलों में नई किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। कृषि विभाग एवं कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद ने उन्नत किस्म के बीजों का विकास करने एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ की विरल प्रसिद्ध किस्मों का भारतवर्ष में विकास किया जा रहा है। द्वितीय योजना में प्रत्येक विभाग खण्ड में बीज पापों का निर्धारण किया गया ताकि उन्नत किस्म के

बीजों की बड़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके। सरकार ने उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन एवं वितरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation) की स्थापना की है। सन् 1970-71 तक 146 लाख हेक्टर भूमि उन्नत बीजों के अन्तर्गत आई जा चुकी है, जबकि चतुर्थ योजना के अन्त तक 250 लाख हेक्टर भूमि को उन्नत बीजों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है।

कृषि का यन्त्रीकरण (Mechanisation of Agriculture)

कृषि यन्त्रीकरण से तात्पर्य खेती की समस्या क्रियाओं में हल चलाने से लेकर फसल के काटने व तेचने तक मशीनों का प्रयोग करना है। इसके अन्तर्गत जहाँ भी सम्भव होता है, पशु एवं मानव शक्ति की जगह यन्त्रों का कृषि कार्यों में प्रतिस्थापन किया जाता है। पाश्चात्य देशों में कृषि में यन्त्रीकरण के कारण ही कृषि क्रान्ति हुई। वहाँ के कृषक आजकल उन्नत एवं आधुनिकतम कृषि यन्त्रों का प्रयोग करते हैं तथा कृषि को लाभदायक उद्योग के रूप में व्यपनाए हुए हैं, जबकि दूसरी ओर भारतीय कृषकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कृषि औजार एवं कृषि कार्य ■■■ लिए अधिकांश उपयुक्त नहीं हैं।

विगत वर्षों में भारतवर्ष में फार्म मशीनरी एवं ट्रैक्टरों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष में एक ओर तो ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तथा दूसरी ओर इनकी कमी की पूर्ति आयात करके की जा रही है। सन् 1970 में भारत में ट्रैक्टरों का उत्पादन 20500 हुआ था। देश में कृषि यन्त्रों की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए पावर टिलर्ज, डिस्क हैरोज आदि कृषि यन्त्रों के आयात की भी व्यवस्था की जा रही है। भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि यन्त्रों के वितरण की व्यवस्था के लिए कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं। ये निगम ट्रैक्टर व अन्य फार्म मशीनों की आसानी खेती पर बेचते हैं या किराए पर देते हैं तथा सेवा केन्द्रों की व्यवस्था करते हैं।

कृषि यन्त्रीकरण के विषय में तर्क बहुत से विद्वानों का मत है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में यन्त्रीकरण उपयुक्त नहीं है। यन्त्रीकरण के निपट में श्रम, ये तर्क दिये जाते हैं (1) भारत में खेतों का आकार इतना छोटा है (3 से 12 एकड़ के बीच) कि यन्त्रीकरण के लिए कोई जगह नहीं, (2) कृषि यन्त्रीकरण लाखों कृषकों की बेरोशकारी के गर्त में दकेल देगा। पूर्ण यन्त्रीकरण की स्थिति में भारत में उपलब्ध कुल क्षेत्रफल को 30 से 40 लाख कृषकों द्वारा जोता जा सकता है, (3) कृषि यन्त्री-

नरुण से हमारी पशु सम्पत्ति फायदा हो जायेगी, (4) पूर्ण वृषि यन्त्रीकरण के लिए, बड़े पैमाने पर फार्म मशीनरी की प्राप्ति करना जरूरी है क्योंकि विदेशी मुद्रा के संकट के कारण न तो इनका आयात हो सकता है और न निर्माण ही, (5) फार्म मशीनरी के परिचालन के लिए पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की अधिनाधिक आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी हमारे देश में कमी पाई जाती है।

कृषि यन्त्रीकरण के पक्ष में तर्क कृषि यन्त्रीकरण के विपक्ष में दिये गये तर्कों का उत्तर दिया जा सकता है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं (1) भारत की वर्तमान जनसंख्या की परिस्थितियों में 20 से 30 एकड़ के आकार के खेतों के लिए उपयुक्त कृषि मशीनरी प्राप्त की जा सकती है अर्थात् छोटे-छोटे खेतों पर भी यन्त्रों का उपयोग हो सकता है, (2) आर्थिक रूप से यन्त्रीकरण करने पर बेरोजगारी का अत्यधिक भय उत्पन्न नहीं होगा। साथ ही यन्त्रीकरण के परिणाम स्वरूप फोमले, लोहे, इस्पात परिवहन आदि की अधिक मांग होने से नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, (3) कृषि मशीनरी का उत्पादन देश में ही किया जा सकता है तथा आयात पर निर्भरता समाप्त की जा सकती है, (4) पेट्रोल, डीजल व मिट्टी के तेल का उत्पादन स्वयं भारत में बढ़ाया जा सकता है, (5) कृषि यन्त्रीकरण से बड़े पैमाने की गतिमानताएं प्राप्त की जा सकती हैं, (6) कृषि यन्त्रीकरण कृषकों को भारी धका देने वाले कामों से छुटकारा दिला सकता है, (7) कृषि यन्त्रीकरण से प्रति व्यक्ति एवं प्रति एकड़ उत्पादनता बढ़ाई जा सकती है (8) कृषि यन्त्रीकरण उद्योग, परिवहन आदि के क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़ा सकता है।

उपसुंनत विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि यन्त्रीकरण एक अच्छी नीति है। कृषि में यन्त्रों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ाने से उत्पादनता में वृद्धि होगी और रोजगार के साधनों का भी अन्तर्नोगत्वा विकास होगा।

प्रश्न

1 सदिप्य लिपिणी लिखिए (अ) भारत में बहुउद्देश्यी नदी घाटी योजनाएं।
(राज० टी० डी० सी० प्र० वर्ष कक्षा 1966)

■ भारतीय वृषि के लिए सिंचाई का क्या महत्व है? पिछली दो योजनाओं में सिंचाई के विकास का मूल्यांकन कीजिए।

(सामर, बी० ए० 1963)

3 भारत में सिंचाई के विभिन्न मापना का वर्णन कीजिए और उनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिये।
(गोरखपुर बी० ए० 1960)

4. "नदी-घाटी योजनाएँ वर्तमान भारत के तीर्थस्थान हैं।" विवेचन कीजिए। (राज० बी० ए० 1864)

5. 'राजस्थान नहर' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (राज० बी० ए० 1964)

6. "भारत में कृषि-उत्पत्ति के लिए सिंचाई के साधनों की उत्पत्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बिना ~~लाज~~ समस्या सुलझ नहीं सकती।" इस कथन की मूर्च्छा कीजिए। (राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष कला 1968)

7. Describe the steps taken during recent year for extention of irrigation facilities with particular reference to Rajasthan.

(Raj B A Second Yr 1960)

भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधार

(Land Tenures and Land Reforms)

'A land reform, which has stopped half-way or has been only half-heartedly undertaken, almost inevitably creates conditions which are inimical to justice as well as to overall development.'

—Prof . D R. Gadgil

भूमि-व्यवस्था से हमारा आशय उस व्यवस्था से है, जिसमें किसानों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की व्यवस्था होती है। किसान सदैव से ही अपनी भूमि के प्रति आकर्षित रहा है। जिन व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि पर उसका अधिकार होता है उस व्यवस्था में वह जी-जान लगाकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करता है। जहाँ भूमि में उसे कोई अधिकार नहीं दिया जाता, वहाँ वह कृषि के प्रति उदासीन हो जाता है, फलस्वरूप उत्पादन भी कम हो जाता है। संक्षेप में, किसान को भूमि में अधिकार दिये बिना, कृषि-उपज बढ़ाने की सही योजनाएँ देश पर लागू नहीं होगी। अतः कृषि-उपज बढ़ाने में भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

स्वतन्त्रता के समय भारत में प्रचलित भूमि-व्यवस्था

स्वतन्त्रता के पूर्व भूमि-व्यवस्था या भूमि-स्वामित्व प्रणाली की तीन प्रणालियाँ, भारत में प्रचलित थी, जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं -

(क) **रयतवाड़ी प्रणाली (Ryotwari System)** इस प्रणाली को धामन नूनरो ने सर्वप्रथम सन् 1972 ई० में मद्रास में लागू किया था। धीरे-धीरे यह प्रणाली बम्बई, बरार, कर्ना, मध्य प्रदेश तथा आसाम में प्रचलित की गई। इस पद्धति में किसान का सम्बन्ध सीधे सरकार से होता है तथा बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है। किसानों को स्वयं अपने खेतों का लगान सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है। जब तक वह लगान देता है, तब तक वह भूमि का स्वामी बना रहता है, परन्तु लगान न देने की स्थिति में भूमि पर राज्य का स्वामित्व हो जाता है। किसानों को इस प्रणाली में अपनी भूमि को प्रयोग में लाने, बदलने व छोड़ने का पूर्ण अधिकार होता है। इस

व्यवस्था में पहले मध्यस्थ नहीं थे, परन्तु जनमस्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण इस प्रथा में भी काश्तकार व उप-काश्तकार पैदा हो गये। पट्टेस्वरूप यह व्यवस्था भी मध्यस्थों से अछूती न रही। यह प्रथा मद्रास, गुजरात, मद्रासप्रदेश तथा मध्यप्रदेश में प्रचलित है।

(ख) महालवादी प्रथा (Mahalwari System) : इस प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम आगरा व अवध में सन् 1833 ई० में 'रेगुलेशन एक्ट' के आधार पर हुआ। बाद में इसे पंजाब व मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में भी लागू कर दिया गया। 'महाल' शब्द का अर्थ है गांव। इस प्रथा में महाल या गांव से सम्बन्धित किसानों का एक समूह संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से अपना लगान चुकाता है। प्रत्येक गांव का एक नम्बरदार होता है जो गालगुजारी सरकारी कोष में जमा कराता है। इस प्रथा को 'सन्मिलित ग्राम स्वामित्व प्रथा' भी कहते हैं। भूमि पर सभी लोगों का स्थायी सम्पत्ति के रूप में अधिकार होता है। इस प्रथा में गांव की बैकार व बजर भूमि, कुंदा, दूध आदि मजदूरी किसानों की संयुक्त सम्पत्ति होते हैं। यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ता है, तो सम्पूर्ण भूमि गांव वालों की हो जाती है। यह प्रथा उत्तर-प्रदेश, पंजाब, तथा मध्यप्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है।

(ग) जमींदारी प्रथा (Zamindari System) : भारतवर्ष में जमींदारी प्रथा मुगलों के समय से लची आ रही है, परन्तु वर्तमान जमींदारी प्रणाली के श्रीगणेश करने का श्रेय झांडे कार्नवालिस को है, जिन्होंने सन् 1793 ई० में भारतीय किसानों को एक निश्चित रकम देने के बदले बूस्वागित्व अधिकार दिये थे। यह प्रथा उस समय इंग्लैण्ड में प्रचलित प्रथा पर आधारित थी। इस प्रथा में सामान्य भूमि का मालिक जमींदार होता है जो स्वयं भूमि को नहीं जोड़ता है, बल्कि भूमि को लगान पर उठा देता है। इस प्रकार काबूकी तौर पर लगान देने की जिम्मेदारी जमींदार के ऊपर ही होती है जो सरकार एवं काश्तकारों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करता है। जमींदार द्वारा सरकार को दिये जाने वाले लगान की मात्रा दो प्रकार से निर्दिष्ट होती है : (1) स्थायी प्रबन्ध इसमें लगान की मात्रा हमेशा के लिए एक ही बार निर्दिष्ट कर दी जाती है, तथा (2) अस्थायी प्रबन्ध—इसमें लगान की मात्रा समय पर निर्दिष्ट की जाती है।

जमींदारी प्रथा को लागू करने से जटिल सरकार को निश्चित लाभों की सम्भावना थी —

(1) सरकारी अथ में स्थिरता एवं निश्चितता, (2) भूमि उन्नति की सम्भावना (3) एक स्थायी-अन्य व्यक्तिगताली वर्ग का निर्माण, (4) परकारी अथ की वसुली में सरलता।

1. जमींदारी बंद प्रायः सभी राज्यों में लगान कर ही गई है।

जमींदारी प्रथा के दोष : गमय एवं परिस्थितियों के बदलने के साथ-साथ इस प्रथा में अनेक दोष पैदा हो गये, फलस्वरूप, सर्वसाधारण जनता इस प्रथा की विरोधी हो गई। इसने मुख्य दोष निम्नलिखित हैं:

1. **कृषकों का शोषण :** जमींदारी ने अनुचित एवं अत्यधिक लगान लेना तथा भेटे, बेमार एवं मजराओं की प्रयाजों द्वारा निर्धन एवं जर्जर कृषक वर्ग का शोषण किया।

2. **समाज पर अनुपादक वर्ग का भार—**यह वर्ग कोई कार्य नहीं करता था। किसानों की गाड़ी कमाई को छीन कर विलासितापूर्ण जीवन बिताता एवं ऐसीभाराग करना ही इनकी विनम्रता रह गई थी।

3. **भूमि सुधार में बाधा** जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत भूमि-सुधार पर तो न जमींदारों ने कोई सुधार किया और न किसानों ने, क्योंकि किसानों को हुंसेला ही बेदखली का भय बना रहता था।

4. **देशद्रोही धर्म** जमींदार अंग्रेज शासकों के मक्के भक्त थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दवाने के लिए इन्होंने देशभक्तों के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किये।

5. **सरकार की वार्षिक ह्रास** एक ओर तो जमींदार किसानों से उनकी उत्पत्ति का लगभग 50 से 60% भाग लगान के रूप में लेता था और दूसरी ओर वह सरकार को सदा के लिए निश्चित लगान देता था जो प्रायः उनके द्वारा दसूले गये लगान से बहुत कम होता था। फलस्वरूप सरकार की मालगुजारी में कम रकम मिलती थी।

6. **ग्रामीण समाज में दो वर्गों का उदय :** इस प्रथा के परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज दो वर्गों में बंट गया, धनी एवं निर्धन वर्ग। धनी वर्ग जमींदार वर्ग सम्पन्न था एवं समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। दूसरी ओर किसानों के अधिकार छिन गए तथा उन्हें दानों की भांति जीवन-यापन करने के लिए बाध्य होता पड़ा।

7. **सरकार एवं कृषक वर्ग में दूरी** जमींदारी प्रथा के फलस्वरूप सरकार का ध्यान केवल मालगुजारी वसूल करने पर ही रहा। मालगुजारी भी उसे जमींदारों से मिलती थी, ^{दूर} न कृषकों से नहीं। परिणामतः सरकार का कृषक वर्ग से प्रत्यक्ष सम्पर्क समाप्त हो गया।

8. **मुकदमेबाजी में वृद्धि :** जमींदारी प्रथा में जमींदार अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिए प्रायः किसानों को बेदखल कर दिया करते थे तथा खेत दूसरे किसानों को ऊँची लगान दर पर उठा दिया करते थे। किसान ऐसी बेदखली का विरोध करते थे जिससे मुकदमेबाजी में वृद्धि होती गई।

9. सामाजिक अस्तोष में वृद्धि जमींदार धन के नशे में दुराचारी बनते चले गए। भूखे, नगरे, दरिद्र, किसानों की याही कमाई पर विलासितापूर्ण जीवन बिताने के कारण, वे जनता में घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे। उनके दुष्कार्यों का परिणाम यह हुआ कि समाज में भीषण अस्तोष की ज्वाला धधक उठी, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी।

10 अनेक मध्यस्थों का जन्म जमींदारी प्रथा में जमींदारों की मिलाती प्रवृत्ति के कारण वे इसका कार्य स्वयं न देखते थे, बरन् अपने कारिंदों पर छोड़ देते थे। कारिंदे अपने लाभ को ध्यान में रखते थे और बड़े-बड़े किसानों को उप-किसानों में भूमि बांटने की छूट दे देते थे, फलस्वरूप कई मध्यस्थ पैदा हो जाते थे। इस सम्बन्ध में पलाउड कमीशन ने बताया है कि बंगाल के यांमिकजमींदार तथा खेती करने वाले वास्तविक किसानों के बीच 50 से भी अधिक मध्यस्थ थे।

इस प्रकार जमींदारी प्रथा में देश के कुपक वर्ग का लगातार शोषण किया गया उसे भूख, गंदा और कगाल बना दिया। प्राचीन काल में खेती और खेती करने वाले की समाज में जो उच्च स्थान प्राप्त था, उससे उसे नीचे गिरा कर गुलामी की भांति जीवन-यापन करने पर बाध्य कर दिया गया। जमींदारों की ज्यादातर इतनी गड़ गई थी कि सिवाय इस प्रणाली को समाप्त करने के और कोई चारा ही न था। बिना जमींदारों एवं जमींदारी प्रथा के समाप्त किये, कृषि की हीन अवस्था को सुधारा ही नहीं जा सकता था, जमींदार समाज का अनुपयोगी एवं अनुराधाक्ष अंग बन गये थे। जमींदारी प्रथा एक अनुपस्थित जमींदारी थी जिससे विषय में कार्वर (Carver) ने यह उगुक्त की है, "गुड, अकाल और महानारी के बाद बावों की जिस दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, वह है अनुपस्थित जमींदारी।"¹

भारतवर्ष में भूमि-सुधार (Land Reforms in India)

"न तो वैज्ञानिक कृषि और न सहकारिता ही प्रगति कर सकती है, जब तक कि भूमि प्रणाली में सुधार न किया जाय"। भूमि-सुधार के सम्बन्ध में डा० राधा कर्मल मुखर्जी के ये विचार पूर्णतः सही लगते हैं —

भारतवर्ष में भूमि-सुधार सम्बन्धी कदम यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भी उठाये गये थे, तथापि वे प्रभावशाली न थे और भूमि-व्यवस्था प्रायः ज्यों की त्यों चली आ रही थी। आजादी के पश्चात् देश की लोकप्रिय सरकार ने इस सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये।

1 "Next to war, famine and pestilence the worst thing that can happen to the rural community is absentee land-holdism."

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि का कार्यक्रम बनते समय यह अनुभव किया गया कि हमारी भूमि-व्यवस्था में कई गम्भीर दोष हैं और उन्हें दूर किए बिना कृषि विकास सम्भव नहीं। इन दोषों को दूर करने के लिए 1947 के पहले ही कुछ कानूनी उपाय किए गए थे, पर ये अपर्याप्त सिद्ध हुए। स्थिति की गम्भीरता को और सचिवालय में प्रदत्त सामाजिक न्याय के बवनों को देखते हुए भूमि-व्यवस्था में तुरन्त सुधार करने की उच्च प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि-सुधार कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा मिली। देश की पञ्चवर्षीय योजनाओं में, प्रारम्भ से ही, भूमि-सुधारों के गहन पर ध्यान दिया गया और यह स्पष्ट रूप में घोषित किया गया कि जब तक देश में भूमि-सुधारों की उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त की जाती, देश की कृषि व्यवस्था नहीं सुधर सकती।

भूमि-सुधार के उद्देश्य (Objectives of Land Reforms) :

भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं —

(i) भू-स्वामित्व तथा वितरण की विषमताओं को मिटा कर अधिक विषमता को कम करना, (ii) भूमि-क्षेत्र से वैधानिक दोषों का निवारण करके कृषि-व्यवस्था के विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, (iii) कृषि उत्पादन के मार्गों की सभी कठिनाइयों को दूर करने अथवा उत्पादन के मार्गों को प्रशस्त करना, (iv) भूमि प्रयोग की कुशल व्यवस्था को सम्भव बनाना, (v) आम तथा अदम्य की सामाजिक विषमताओं को मिटाना आदि।

पञ्चवर्षीय योजना में भूमि सुधार प्रथम योजना में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर भूमि नीति निर्धारित की गई जिसकी प्रमुख बातें थी—(i) राज्य तथा किसानों के बीच सभी प्रकार के मध्यस्थों को समाप्त करना, (ii) बड़े-उड़े भूस्वामियों की भूमि की सीमा निर्धारित करना और इस प्रकार प्राप्त हुई अतिरिक्त भूमि को बाँटना; (iii) छोटे-छोटे तथा मध्य वर्ग के भूस्वामियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जोतों की चकबन्दी करना, भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन की रोकना तथा सहकारी कृषि को अपनाये के लिए प्रोत्साहन देना, (iv) वास्तविकी कानूनों में सुधार जिससे रूग्ण में कमी की जा सके तथा किसानों को इनके द्वारा जोती जाने वाली भूमि खरीदने की सुविधा प्रदान की जा सके, तथा (v) श्रेतिहर श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना। इस योजना काट में मध्यस्थों के सम्मुख के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति हुई और प्रायः सभी राज्यों में इस सम्बन्ध में कानून पास किए गए। देश की कुल भूमि का प्रायः 43 प्रतिशत भूमि मध्यस्थों के अधीन थी जो अब राज्य

के अधीन आ गई थी। लेकिन ग्रन्थ भूमि सुधार कार्यक्रमों-जैसे-लगान का नियमन व कमी तथा चकवन्दी आदि, के सम्बन्ध में विशेष प्रगति नहीं हुई।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में भूमि सुधार को विशेष महत्त्व दिया गया। खेतों की चकवन्दी को भीघ्रता से लागू करने की सिफारिश की गई। जोड़ों की अधिकतम सीमा निर्धारण करने का कार्य भी तीन या 4 वर्षों में समाप्त करने का सुझाव दिया गया। इस योजना में सहकारी खेती अपनाने पर बहुत जोर दिया गया था। राज्य सरकारों को ऐसा कदम उठाने के लिए कहा गया ताकि 10 वर्षों में हो देना के अधिकतर कृषि क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर कृषि की जा सके।

नागपुर का भूमि-सुधार प्रस्ताव (Nagpur Resolution on Land Reforms) : द्वितीय योजनावधि में ही जनवरी 1959 में होने वाले नागपुर अधिवेशन में भूमि सुधार की पूर्ण रूप रेखा प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रमुख बातें निम्नांकित हैं —

(i) ग्रामीण सगठन, ग्राम पंचायत तथा ग्राम-सहकारिता पर आधारित हो जिनके पास पर्याप्त अधिकार व साधन हों।

(ii) कृषि का भावी विकास समुक्त सहकारी कुषिपर आधारित होना चाहिए।

(iii) वर्तमान उष्ण भावी ज़ात की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इसके फलस्वरूप जो जमीन मरकाट के कब्जे में आए उस पर पंचायतों का अधिकार होना चाहिए तथा उसका प्रबन्ध भूमिहीन किसानों की सहकारिता के हाथ में होना चाहिए।

(iv) कृषक को उचित लाभ दिलाने की दृष्टि में दूर फसल का उसकी बुझाई के सीमम से काफी पहले न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देना चाहिए और आवश्यकत। पड़ने पर पैदावार को भीषे खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(v) वज्र भूमि को कृषि योग्य बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

(vi) लाघानों के बीच व्यापार को राज्य के हाथ में सौपना चाहिए।

तृतीय योजना में भूमि सुधार के सम्बन्ध में प्रधान उद्देश्य उक्त कार्यक्रमों की कार्यान्वित करना था, जिन्हें द्वितीय योजना में प्रारम्भ किया गया था। योजना में भूमि सुधार कार्यक्रमों को यथा क्षीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया गया।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में भी भूमि सुधार को कृषि विकास की योजना का एक आवश्यक अंग माना गया है। इस योजनाकाल में भूमि सुधारों की दिशा में निम्न कदम उठाये जाने की व्यवस्था है - (i) योजनाकाल में भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने पर विशेष बल दिया जावेगा, (ii) राज्य सरकारें लगान के प्रचलित स्तरों एवं पट्टेबाती से सम्बन्धित अन्य शर्तों में संशोधन करेगी ताकि उत्पादन पर

अनुकूल प्रभाव यह सके; (iii) योजनाकाल में भूमि-अधिकारों का अभिलेखा तैयार करने की विशेष व्यवस्था की जायेगी; (iv) राज्यों की योजनाओं में भूमि की छोटी-छोटी इकाइयों को मिलाने पर 28.4 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। (v) इस योजनाकाल में कृषि अधिक को बसाने पर राज्य सरकारों की योजनाओं पर 5.54 करोड़ रु. व्यय करने की व्यवस्था की गई है; (vi) योजनावधि में भूमि सुधार कार्यक्रम का सामयिक मूल्यांकन किया जायेगा।

भारत में भूमि-सुधार के उपाय (Land Reform Measures in India): स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि-सुधार की दिशा में एक के बाद एक चले-चले कदम उठाये गये, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :

(क) मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Intermediaries)

(ख) कानूनी कानूनों में सुधार (Tenancy Reforms)

(ग) जमीन का सीमा निर्धारण (Ceiling of Land Holdings)

(घ) कृषि का पुनर्संगठन (Reorganisation of Agriculture)

(ङ) मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Intermediaries);

मध्यस्थों की समाप्ति एवं 'भूमि उसकी जो उसे जोते-बोये', वगैरह पार्टी की कृषि-नीति के ये महत्वपूर्ण आधार थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रथम चुनाव घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि वह मध्यस्थों को उचित मुआवजा देकर, उनके भू-स्वामित्व के अधिकारों को हटेशा हटेशा के लिए समाप्त कर देगी।¹ फलस्वरूप शक्ति में आते ही इसने जमींदारी, जामींदारी व अन्य नामों से फैली मध्यस्थता को समाप्त कर दिया। ये मध्यस्थ देश की समस्त भूमि के 43 प्रतिशत भाग में फैले हुए थे। भारत के विभिन्न राज्यों में अपने अपने क्षेत्रों में अभिनियम पारित करके मध्यस्थों को समाप्त कर दिया है। जहाँ पहले जमींदारी के पास देश के कृषि योग्य क्षेत्र का 43%, था, वहाँ अब केवल 5% ही रह गया और 38% क्षेत्र पर जमींदारी समाप्त कर दी गई। लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों का अब सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

जमींदारी श्रेया को समाप्त करने के लिए जो कानून पास किए गए हैं, उनकी प्रमुख बातें निम्नांकित हैं :

(1) जमींदारी से उनकी भूमि लेने के बदले में उन्हें मुआवजे के रूप में वन दिया गया। यह वन उनकी भूमि की शुद्ध आय का कुछ गुना है। इन मुआवजों का

1. "The reform of land system, which is so urgently needed in India, involves the removal of intermediaries between the peasant and the State. The rights of such intermediaries should, therefore, be acquired on payment of equitable compensation."

बाजार तथा दर विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न थी। ज्यों-ज्यों बाय बढ़ती जाती, त्यो त्यो दिए जाने वाले मुआवजे की दर घटती जाती है।

(ii) मुआवजे की रकम नगद या बाँड के रूप में दी जाने की व्यवस्था की गई थी तथा इनके चुकाने का समय 10 से 30 वर्ष रखा गया था। आसाम, आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, तामिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों ने क्षतिपूर्ति या मुआवजा नगद देने का निश्चय किया, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात व महराष्ट्र राज्यों ने नगद व बाँड के रूप में मुआवजा देने का निश्चय किया। बड़े-बड़े मध्यस्थों को प्रायः बाँड देने का सिद्धान्त अपनाया गया तथा छोटे मध्यस्थों को नकद में ही मुआवज देने का निर्णय किया गया।

(iii) जमींदारों से खुद खेती करने के लिए भूमि रखने की अनुमति दी गई है तथा अधिकतम भूमि की सीमा निर्दिष्ट कर दी गई है।

(iv) किसानों के लिए कृषि सम्बन्धी सतः पूर्ववत् ही हैं, अन्तर केवल इतना है कि अब उनका सरकार से सीधा सम्बन्ध है। अपने निर्दिष्ट लयान का कुल गुना धन लेकर वे भूस्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

(v) मुआवजे के रूप में अब तक 570 करोड़ रुपये में से केवल 320 करोड़ रुपये ही नकद या बाँडों के रूप में चुकाये गये हैं। इस प्रकार देश के 43 प्रतिशत क्षेत्र में जमींदारी, जागीरदारी व इनाम के रूप में फैले हुए मध्यस्थों के अधिकारों को समाप्त किया जा चुका है। इन सुधारों के बाद सरकार का लगभग दस करोड़ फास्तकारों से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। यद्यपि जमींदारी प्रथा अब समाप्त हो चुकी है, तथापि योजना आयोग की भूमि सुधार समिति के अनुसार अभी भी भूमि का बहुत सा भाग अनुपस्थित भूस्वामियों के पास है। इसे भी शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए। निजी कृषि की व्यवस्था सही ढंग से दी जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत न केवल भूस्वामी का गांव में रहना ही जरूरी हो, अपितु वह भूमि पर कार्य भी स्वयं करें। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन हो जाने से वह नहीं समझ लेता चाहिए कि कृषि विकास स्वतः हो जायेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'यह तो बेचल विकास के पार्श्व की एक बड़ी बाधा को हटाना है। इस बाधा के दूर हो जाने के पश्चात् भूमि व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए, जिसके फलस्वरूप भूमि के उप-विभाजन एवं बंधन संचयन के दोष दूर हो सकें तथा कृषि उत्पादन अधिकारिणी हो सके।

(घ) क़ायदकारी क़ानूनो में सुधार (Tenancy Reforms) इस व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित सुधार आते हैं

(1) भू-जोखों की सुरक्षा (Security of Tenure),

- (ii) लगान में कमी (Reduction in Rents),
- (iii) किसानों को भू-स्वामित्व दिलाना (Ownership for Tenants)
- (iv) स्थायी सुधारों के लिए मुआवजा (Compensation for Permanent Improvements)
- (v) लगान से छूट (Remission of Rent), तथा
- (vi) अन्य सुधार (Miscellaneous Improvements)

(1) भू-जोतों की सुरक्षा (Security of Tenure) लगभग सभी राज्यों में या तो कानून बन कर भू-जोतों की सुरक्षा बर दी गई है या की जा रही है। योजना आयोग का यह दृष्ट भव है कि भूमि सुधारों का उम समय तक कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, जब तक कि किसानों को उनकी जोता के सम्बन्ध में सुरक्षा न प्रदान की जाय।¹ भू-जोतों की सुरक्षा आवश्यक है तथा किसानों को इस सम्बन्ध में पूर्ण आश्वासन मिलना चाहिए कि उनकी जमीन को किसी बहाने से कोई भी न छीन सकेगा तथा जब तक वे मालगुजारी देते रहेंगे, उन्हें वेदमल न दिया जा सकेगा। इसका अच्छा परिणाम यह निकलेगा कि किसान अपने खेतों को हमेशा हमेशा के लिए अपना समझ कर उन पर स्थायी सुधार करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे भूमि में स्थायी सुधार होगा। कृषक व कृषि की दशा में आश्चर्यजनक सुधार होगा। कृषक को भूमि पर स्थायी अधिकार मिलने से देश की कृषि अवस्था में आश्चर्यजनक प्रगति होगी। श्री आर्थर यंग ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है 'निजी सम्पत्ति का जादू रेत को गीला बना देता है। निजी व्यक्ति को रक्ष चट्टान का सुरक्षित अधिकार दे दीजिये और वह इसे जंगल में बदल देगा, उसे नौ वर्ष के ठंके पर एक जंगल दे दीजिये और वह इसे मरुस्थल में बदल देगा।'²

प्रायः देश के सभी राज्य भू-जोतों की सुरक्षा के महत्त्व से परिचित हैं। 12 राज्यों में सभी सघीय खेतों में भू-जोतों की सुरक्षा सम्बन्धी कानून बन चुके हैं। देश की कुल वृक्षों में जाने वाली भूमि के 9% भाग को पूरी सुरक्षा मिल चुकी है। 49% भाग में आंशिक सुरक्षा तथा 19% भाग में अस्थाई सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। अभी 12% भाग में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी है परन्तु इस ओर भी प्रयत्न जारी है।

1 Planning Commission Progress of Land Reforms p 7

2. "The magic of private property is as sand in a gold. Give a man a secure possession of black rock and he will turn it into a garden. Give him a nine years lease of a garden and he will convert it into a desert."

—Arthur Young

(ii) लगान में कमी (Reduction in Rents) : भूमि-सुधार कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया गया है कि लगान की दरें कम कर दी गई हैं। पहले माधारणतः कुल उपज का आधा भाग लगान के रूप में ले लिया जाता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने किसानों से कुल उपज का केवल $\frac{1}{4}$ से $\frac{1}{3}$ भाग तक ही लगान के रूप में लिए जाने की सिफारिश की थी। द्वितीय योजना में भी इन बातों पर काफी बल दिया गया था। परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में लगान की दरें निर्धारित कर दी हैं। इन दरों में समानता नहीं पाई जाती। आन्ध्र, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों में लगान कुल उपज का या तो $\frac{1}{4}$ भाग है या इससे भी कम है। आन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, पंजाब व जम्मू व कश्मीर में लगान अब भी कुल उपज के $\frac{1}{3}$ भाग से लेकर $\frac{1}{2}$ भाग तक है, जो अनुचित रूप से अधिक है। उत्तर प्रदेश में काश्तकार बड़ी लगान दे रहे हैं जो पहले वे जमींदारों को देते थे।

(iii) किसानों की भू-स्वामित्व विलाना (Ownership for tenants) : भूमि सुधार कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया गया है कि खेती करने वाले किसानों को खेती के स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। प्रारम्भ में यह किसानों की इच्छा पर था कि वे भूमि-सम्बन्धी अधिकार खरीदें, परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐच्छिकता की भावना को हटाने का सुझाव दिया गया था। पंजाब, गुजरात, केरल, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उन क्षेत्रों में जो केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं, किसानों के भू-स्वामित्व सम्बन्धी कानून बन चुके हैं। कुछ राज्य अभी ऐसे बच गये हैं, जहाँ इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, जैसे आसाम, बिहार, जम्मू व कश्मीर एवं तामिलनाडु में अब भी इस सम्बन्ध में कानून बनने योग्य हैं। चौथी योजना की रूपरेखा में यह बताया गया था कि किसानों को भू-स्वामी बनाने के लिए अन्य कई राज्यों में भी व्यवस्था कर दी गई है। फलस्वरूप 30 लाख खेतिहर व बर्दाश्त 70 लाख एकड़ भूमि के मालिक बन गए हैं। बताया है कि निकट भविष्य में देश के सभी भागों में खेती करने वाले कृषक खेती के स्वामित्व अधिकार को प्राप्त कर लेंगे।

(iv) स्थाई सुधारों के लिए मुआवजा (Compensation for Permanent Improvements) : देश के कई राज्यों में इस प्रकार के नियम बना दिए गए हैं कि भूमि छोड़ने के समय काश्तकारों के खेती में बनाए गए घर, नालियाँ, कुएँ तथा पेड़ लगाने आदि से सम्बन्धित भूमि सुधारों के लिए काश्तकारों को मुआवजा दिया जायेगा।

(v) सगान से छूट (Remission of Rent) : प्राकृतिक सफ़्टो, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल आदि के समय काश्तकारों का सगान माफ़ कर दिया जाता है।

(vi) अन्य सुधार (Miscellaneous Improvements) : काश्तकारों से ली जाने वाली बेवार को अब गैर-वानूनी ठहरा दिया गया है। यदि कभी सगान न देने की स्थिति में नीलामी आदि करनी पड़ी तो वर्तमान फसल, हल, बैल तथा अन्य कृषि यन्त्र नीलाम नहीं किए जायेंगे।

(vii) जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण (Ceiling on Landholdings) : भारत के अधिकतर राज्यों में कृषि-जोत की अधिकतम सीमा के निर्धारण से सम्बन्धित अधिनियम पारित किये जा चुके हैं। प्रत्येक राज्य में भूमि की स्थिति एवं उर्वरा शक्ति को ध्यान में रख कर अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित की गई है। जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण में दो प्रकार की सीमाओं का निर्धारण होता है, यथा (क) भूमि की जोत की भावी उच्चतम सीमा, अर्थात् भविष्य में कोई किसान अधिकतम कितनी भूमि रख सकेगा या खरीद सकेगा, (ख) वर्तमान जोतों की उच्चतम सीमा, अर्थात् वर्तमान समय में किसान कितनी अधिकतम भूमि रख सकता है। जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करके कई लाभों की अपेक्षा की गई है, जैसे (i) सभी किसानों की भूमि का कुछ न कुछ भाग मिल जाय, (ii) बहुत बड़े-बड़े खेतों को उचित आकार में बदल दिया जाय, ताकि उनका प्रबन्ध आसानी से हो सके, (iii) अधिकतम सीमा निर्धारण के फलस्वरूप जो जमीन सरकार की दब रही थी, उसमें और अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा, (iv) भूमिहीन श्रमिकों को भूमि-स्वामित्व मिलने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी, (v) भूमि स्वामित्व पहले की अपेक्षा अधिक ममान हो जाने से खेतों की चकवर्दी करना बरख हो जायगा, (vi) भूमि के सगान वितरण से सहकारी कृषि के लिए अनुकूल वातावरण पैदा होगा, (vii) आर्थिक समानता समाजवादी समाज की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी।

जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से कुछ दोष उत्पन्न हो जाने की सम्भावना है, अब कुछ विद्वानों ने अधिकतम जोत निर्धारित करने के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए हैं। ये तर्क हैं

(i) इस प्रकार प्राप्त की हुई भूमि में भूमिहीन श्रमिकों की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा, (ii) भूमि ऐसे लोगों के पास चली जायेगी, जिनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं (iii) बड़े-बड़े मूकवन्धित खेतों के जिन पर वैज्ञानिक ढंग से बाधुनिक खेती की जा सकती है, टुकड़ हो जायेंगे, (iv) जब सहकारी ढाँचा पर सीमा लगान उचित नहीं समझा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में जोत की अधिक-

सम सीमा निर्धारित करना व्यापपूर्ण नहीं है, (v) छोटे-छोटे भू-स्वामी होने से बाजार में बाँकर बिकने वाली उपज की मात्रा (Marketable Surplus) कम हो जायेगी; (vi) आपसी बैर-विरोध में वृद्धि से सरकार के वित्तीय बोझ में वृद्धि तथा प्रशासन व्यवस्था आदि की भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

वस्तुतः उच्चतम सीमा के विरोध में दिए गए तर्क भ्रमपूर्ण एवं आधार-रहित हैं। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करना न केवल उचित है, अपितु आवश्यक भी है।

देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम जोत की जो सीमाएँ वर्तमान में प्रचलित हैं, के लिए निर्धारित की गई हैं, वे अधोलिखित हैं :

भारत के विभिन्न राज्यों में भूमि की उच्चतम जोत

राज्य	भावी जोतों की उच्चतम सीमा	वर्तमान जोतों की उच्चतम सीमा
आन्ध्र प्रदेश	10 से 216 एकड़	27 से 324 एकड़
मासाम	30 एकड़	50 एकड़
बिहार	20 से 60 एकड़	20 से 60 एकड़
गुजरात	19 से 132 एकड़	19 से 132 एकड़
जम्मू व कश्मीर	22 75 एकड़	22 75 एकड़
केरल	15 से 36 एकड़	15 से 36 एकड़
मध्य प्रदेश	25 से 75 एकड़	25 से 75 एकड़
तामिलनाडु	24 से 120 एकड़	24 से 120 एकड़
महाराष्ट्र	18 से 126 एकड़	18 से 126 एकड़
मैसूर	18 से 144 एकड़	27 से 216 एकड़
उड़ीसा	20 से 80 एकड़	25 से 80 एकड़
पंजाब	30 प्रमाणित एकड़ ¹	30 प्रमाणित एकड़
राजस्थान	22 से 336 एकड़	22 से 336 एकड़
उत्तर प्रदेश	12 5 एकड़	40 एकड़
पश्चिमी बंगाल	25 एकड़	25 एकड़
हिमाचल प्रदेश	30 एकड़	30 एकड़

1. प्रमाणित एकड़ से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है, जिनमें 10 यव केट्ट या इसके बराबर अन्य कोई दूसरी उपज पैदा होती हो।

योजना आयोग ने सिफारिश की है कि निम्न प्रकार के खेत उन्नयन जोन फार्मों के अन्तर्गत छोड़ दिए जाएं

(i) चाम कहुवा, खट आदि के खेत, (ii) फलदार वृक्षों के संगठित बगीचे, (iii) विशेष खेत (Specialised farms) जैसे कि पशु-पालन, दूध व मत्स्यन क्षेत्रों के लिए पशु रखना तथा जन के लिए भेड़ें पालना आदि, (iv) सुव्यवस्थित संगठित खेत (Efficiently managed farms consisting of complete blocks), तथा (v) लोगों की मिलों के आधीन मन् के खेत ।

(घ) कृषि का पुनर्संगठन (Reorganisation of Agriculture) इसके अन्तर्गत जो कार्य किए गए हैं, उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

1 चक्रवन्दी (Consolidation of holdings) किसान के बिखरे हुए खेतों को एक बड़े खेत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को चक्रवन्दी कहते हैं । इसमें उप-विभाजन व अपसंख्यन सम्बन्धी तथाम दोष दूर होने हैं । भूमि-सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चक्रवन्दी के कार्यों पर बल देने पर जोर दिया गया है । लेकिन सभी राज्यों में चक्रवन्दी की विधा में समान प्रगति नहीं हुई है । सन् 1957 से चक्रवन्दी के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों में चक्रवन्दी सबसीड्य का 50 प्रतिशत भाग देना स्वीकार कर लिया । द्वितीय योजना के अन्तर्गत 2 96 करोड़ एकड़ भूमि की चक्रवन्दी हुई थी । प्रथम तीन योजनाओं में लगभग 6 करोड़ एकड़ भूमि की चक्रवन्दी की गई । चतुर्थ योजना में चक्रवन्दी के लिए 28 4 करोड़ रुपय का आवधान किया गया है । पंजाब व हरियाणा राज्यों में चक्रवन्दी सम्बन्धी प्रायः सभी कार्य पूरा हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों में चक्रवन्दी के कार्य धीरे धीरे चल रहा है । चक्रवन्दी के कार्य में विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति का अन्दाजा निम्न तालिका से लगाया जा सकता है ।¹

राज्य	चक्रवन्दी (लाल हैक्टर भूमि में)
हरियाणा	सम्पूर्ण कार्य पूरा हो गया
पंजाब	सम्पूर्ण कार्य पूरा हो गया
उत्तर प्रदेश	94 80
आन्ध्र प्रदेश	3 39
बिहार	0 85

1 हिन्दुस्तान समाचार वाणिज्य, पृष्ठ 222

राज्य	चक्रवन्दी
गुजरात	10 11
अम्मु व काश्मीर	0 25
मध्य प्रदेश	29 15
महाराष्ट्र	53 47
मैसूर	8 07
राजस्थान	17 52
दिल्ली	0 68
हिमाचल प्रदेश	1 55

2 सहकारी खेती काबेस के सन् 1959 ई० के अधिवेशन में सहकारी कृषि सम्बन्धी प्रस्ताव पास किए गए थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र में सहकारी खेती की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा इन राज्यों में सहकारी सहाकार बोर्ड स्थापित किए गए हैं। जब 1969 तक 8143 सहकारी कृषि-समितियाँ स्थापित हो चुकी थी, जिनमें 2 19 लाख सदस्य थे और जिनके अन्तर्गत 4 25 लाख हेक्टर भूमि आ चुकी थी।

3 भूमि प्रबन्ध में सुधार - प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि के कुशल प्रबन्ध पर बल दिया गया है। इसके अन्तर्गत बेकार पड़ी भूमि का उपयोग, उत्तम बीजों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं, जिनसे बीमारियों एवं कीटाणुओं पर रोक लगाई जा सके। भूमि-प्रबन्ध में सुधार से सम्बन्धित कार्यों की प्रगति धीमी रही है और अभी तक केवल दो राज्यों व तमिल क्षेत्रों में ही इस सम्बन्ध में कानून बने हैं।

4 भू-दान आन्दोलन - सन् 1951 ई० में महारत्ना गांधी के परम शिष्य भाचार्य विनोबा भावे ने भूमि के असमान वितरण तथा गणव्यक्ति अन्ध समस्याओं के निदान के लिए भू-दान आन्दोलन प्रारम्भ किया था। यह आन्दोलन देश के लगभग 1 करोड़ से अधिक भूमिहीन किसान-परिवारों का बड़े भू-स्वामियों से दान में भूमि प्राप्त करके भूमि दिलाने में सशर में एक अद्वितीय मिशाल है। भू-दान के साथ-साथ ग्राम-दान भी प्रारम्भ हो चुका है। भू-दान व ग्राम-दान आन्दोलनों के पीछे भूमि के उचित वितरण का उद्देश्य है जो समाज जाति के खातिमय तरीकों से संभव बनाया जायेगा। मार्च 1967 के अन्त तक कुल 42.7 लाख एकड़ भूमि भूदान में मिली, जिसमें से 12 लाख एकड़ भूमि बाँटी जा चुकी है। अक्टूबर 1967 तक 39,672 ग्राम प्राग-

दान आन्दोलन के अन्तर्गत दान मिल चुके थे।¹ सन् 1969 के बाद मूदान कार्यक्रम और अधिक तेजी से लागू किया गया है। इस समय भूमिहीन मजदूरों को धान बनाने के लिए भी भूमि देने से सम्बन्धित कार्यक्रम भी अपनाए जा रहे हैं।

भूमि-सुधार कार्यों की प्रगति की सम्भाव्यता भारतवर्ष में भूमि-सुधार, सम्बन्धी किये गये अनेक कार्यों के फलस्वरूप मध्यम वर्ग की समाप्ति हो गई है। किसानों को भू-स्वामित्व प्राप्त हुआ है तथा उनकी जीतों को सुरक्षा प्राप्त हुई है। उनका लगान अब अपेक्षाकृत कम हो गया है। खेत जोतने वाला ही अब खेत का मालिक भी है। साथ ही सीमा निर्धारण, चकबंदी, महकरी खती आदि के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है, परन्तु यह बड़ा दुःख की बात है कि इन तमाम सुधारों का क्रियान्वयन सतोपजनक नहीं रहा है। इनके क्रियान्वयन में कई दोष हैं जो निम्न हैं —

(i) भूमि-सुधार कार्यों के बीच समुचित समन्वय का अभाव पाया जाता है।

(ii) भूमि-सुधार नीति बिल्म्बपूर्ण रही है। मध्यम वर्ग के सम्मूलन में 10 वर्ष का समय लग जाना उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जमींदारों व जागीरदारों को कानून से बच निकलने का सुअवसर प्राप्त हो गया।

(iii) भूमि सुधारों के फलस्वरूप मुकदमेबाजी की प्रचुरता मिली है, जिससे काफी समय व धन की बरबादी हुई है।

(iv) भूमि सुधार सम्बन्धी नीति देश के लिए काफी महंगी पड़ी, क्योंकि राज्य सरकार को कई ही रूप मुआवजे के रूप में देने पड़े।

(v) भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों में अलग-अलग राज्यों में भिन्नता पाई जाती है तथा इनमें अनेक दोष रह गये हैं। डा० डेनियल थोर्नर के अनुसार, "सम्बन्धी बात तो यह है कि भारतवर्ष में भूमि सम्बन्धी कानून की कल्पना ही गलत ढंग से की गई है। विधान सभाओं में पेश किये गए विधेयकों में काफी कमियाँ थी, फिर इन विधेयकों में अनेक घातक संशोधन करके उन्हें और भी कमजोर कर दिया गया।"²

(vi) भूमि सुधार सम्बन्धी नीति ने भू-स्वामित्व में अनिश्चितता की भावना पैदा कर दी। फलस्वरूप कृषि विनियोग व उत्पादन कम हो गया।

(vii) राज्य जिला, खण्ड और ग्राम स्तर पर सरकारी अधिकारियों का नकारात्मक रुख भूमि सुधारों के मार्ग में रोड़ अटकता है। राजस्व अधिकारी, सारा कर वटवारी वटवारी के प्रति उपेक्षा करते हैं।

1 India 1968 P 251

2 Dr. Daniel Thorner, Land and Labour in India ■ 8

(viii) सार्वजनिक कानून 480 (P. L. 480) के अन्तर्गत अमेरिका से छात्रागो की प्राप्ति हो जाने के फलस्वरूप, शासन तन्त्र भूमि-सुधारों को गम्भीरतापूर्वक लागू करने की आवश्यकता ही नहीं अनुभव करता, जबकि कृषि-विकास के कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी विशेषतः उन्हीं पर है।

(ix) भूमि-सुधार की कल्पना और भूमि-सुधार नियम बनाने में काफी समय लगता है और साथ ही साथ भूमि-सुधार नियम बनाने और लागू होने में भी काफी समय लग जाता है।

(x) भूमि सुधारों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों में की गई जाचों से पता चला है कि भूमि-सुधार कानूनों का लाभ विस्तृत क्षेत्रों में वास्तविक वास्तकार को बहुत कम मिल पाया है।

(xi) जमींदारी डेन्मूलन कानून में रहों अपूर्णताओं के कारण बड़े जमींदारों ने खुद पाश्त की जाड़ में काफी भूमि स्वयं रक्ष ली है।

(xii) भूमि सुधार कानून में काश्तकारों को प्राप्त सरक्षण के बावजूद भी देश के कुछ कृषि क्षेत्र के काफी बड़े भाग पर और कानूनी काश्तकारी (जैसे बटाई प्रथा) जारी है।

(xiii) अपूर्ण प्रलेखों के कारण काश्तकार अपने दावे सिद्ध करने में अपने को असमर्थ पते हैं, फलस्वरूप आज भी काश्तकारों की बेदखली जारी है।

(xiv) सामाजिक श्याम तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों व छोटे किसानों की सहायता के लिए जोरों की उच्चतम सीमा से निर्धारण में भी विफल हुआ है। उच्चतम सीमा निर्धारण से कृषकों को अभी तक कोई लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। बेरस, उड़ीसा व मैसूर में तो सीमा लगाने का कार्य अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। राजस्थान व आन्ध्र में ये कानून लागू तो हो गये हैं, पर अब तक थटिरिनन भूमि विशेष परिणाम में नहीं मिल सकी है। मध्य प्रदेश व असम में प्राप्त भूमि वितरित की जा चुकी है पर यह बहुत कम है।

डा० बलजीत सिंह ने भूमि सुधार सम्बन्धी दोषों का वर्णन करते हुए लिखा है कि भूमि-सुधार कार्यों के अन्तर्गत भूमि वितरण की समस्या को अच्छी तरह से मुहजाने का प्रयास नहीं किया गया। भूमि को अब भी दूसरों से छुत्वा कर लोग लाभ उठा रहे हैं। उमान भी किन्हीं प्रांतों में अधिक लिया जा रहा है।”

2 "Not only have the recent land reforms not touched the issue of land distribution but they have also failed in preventing sub-letting and rack-renting. Quite many of those who till the soil have no land rights whereas many of those who do not cultivate still own and possess land." Prof. Baljit Singh

सुझाव : भूमि-सुधारों के दोषों को दूर करने के लिए फोर्ट काउन्सेशन के कृषि-उत्पादन-दल ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। ये सुझाव हैं : (1) भूमि-सुधारों के विषय में अनिश्चितता समाप्त की जाय, (2) कृषि-व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, ताकि रोजगारों में वृद्धि के समय भूमि जोतों के बाजार में सरलता से संधोधन किया जा सके, (3) रोजगार के अन्य साधनों को भी खोजना चाहिए, (4) कृषकों को भूमि-अवस्था में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया जाय, (5) भूमि-संरक्षण को जोर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तथा (6) अधिकतम जोत निर्धारित करने के साथ-साथ न्यूनतम प्रसाधनों को भी निर्दिष्ट कर देना चाहिए आदि।

भूमि-सुधार के उपर्युक्त सुझावों के अलावा भूमि प्रलेखों में भी संधोधन किया जाना चाहिए। उनमें सही व साना जानकारी का समावेश किया जाना चाहिए। जिन राज्यों के प्रलेखों में त्रुटियाँ हैं, उन्हीं राज्यों के भू-स्वामियों के भू-अधिकार सुरक्षित हैं। उन सभी राज्यों में जहाँ बटाईदार को कास्तकार नहीं माना गया है, बटाईदारों के नाम प्रलेखों में शामिल करके उन्हें कास्तकारों का स्तर प्रदान किया जाना चाहिए। रोजगार के वैकल्पिक साधनों के अभाव तथा बहुत से बटाईदारों के भू-स्वामियों की जोखें अनाधिक होने के कारण बटाईदारों का एकदम भू-स्वामी बनना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बटाईदारों को बेदखली से बचाने के लिए भूमि पर खती करने का मौसमी अधिकार दिया जाना चाहिए। बटाईदारों का लगान भी उपज का अंश न होकर नकद होना चाहिए तथा लगान का निर्धारण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिये। लगान सम्बन्धी मामलों की सुनवाई दीवानी अदालतों के बजाय राजस्व अदालतों में होनी चाहिए। 'खुद-कास्त' की परिभाषा भी मशोषित करके सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए। 1948 में पारित बम्बई कास्तकारी कानून में दी गई खुद कास्त की परिभाषा को आदर्श माना जा सकता है।

भूमि-सुधार के अन्तर्गत राज्य सरकारों को चाहिए कि वे जोतों की सीमा नीची करने के लिए तत्काल कदम उठाए। किसी स्थिति में भूमि की अधिकतम सीमा पारिवारिक जोत से तिगुने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में नागरिक समिति बननी चाहिए और भूमि-हस्तावन्तों के पक्ष में जनमत तैयार करना चाहिए, क्योंकि केवल सरकारी तंत्र से अतिकारी भूमि सुधार कानून को लागू करना संभव नहीं है।

राजस्थान ने भूमि-सुधार सन् 1949 से पूर्व राजस्थान कई छोटी-छोटी रियासतों में बटा हुआ था। हर राज्य के अपने-अपने नियम थे। सामान्यतः

लगभग 40 प्रतिशत कृषकों का राज्य से सीधा सम्बन्ध था। शेष 60% भूमि मध्यस्थों के पास थी जो एक ओर तो किसानों से काफी मालगुजारी वसूल करते थे और दूसरी ओर सरकारी कोष में बहुत वन जमा कराते थे। प्रायः कुल उपज का 50% भाग मालगुजारी के रूप में वसूल किया जाता था, परन्तु राजस्थान राज्य वन जाने के पश्चात् यहाँ द्रुत गति में भूमि-सुधार कार्य किये गये।

सर्वप्रथम सन् 1949 में The Rajasthan (Projection of Tenants) Ordinance जारी किया गया। इसमें किसानों को वेदसली से बचाने की व्यवस्था की गई। सन् 1951 में Rajasthan Produce Rents Regulation Act पारित किया गया। इस अधिनियम में किसानों से कुल उपज के 1/6 भाग अधिक व अधिक माल-गुजारी के रूप में, लिये जाने की वैधानिक व्यवस्था की गई। लगान या मालगुजारी सम्बन्धी एक और अधिनियम सन् 1954 में पारित किया गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि मध्यस्थ किसानों से निर्धारित लगान के दूने भाग से अधिक लगान नहीं ले सकते हैं।

सन् 1955 ई० में राजस्थान कायदाकारी कानून (Rajasthan Tenancy Act 1955) पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कायदाकारी व उप-कायदाकारी को भूमि सम्बन्धी अधिकार प्रदान किया गया। अब सातेदार किसान भूमि को बेच सकते थे तथा गिरवी रख सकते थे। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसानों व कृषि धर्मियों को गांव में निशुद्ध भूमि मकान आदि बनाने के लिए दी जा सकती थी। बेवार प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था।

सन् 1959 ई० में जमींदारी व विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट (Rajasthan Zamindari and Biswedari Act, 1959) पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राजस्थान में जमींदारी व विश्वेदारी को प्रथा को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लगभग 3, 24,587 जमींदार जमींदारी से मुक्त कर दिए गए तथा उन्हें लगभग 11 करोड़ मुआवजे देने की व्यवस्था की गई। जमींदारी को समाप्त करने से सम्बन्धित अधिनियम सन् 1952 ई० में ही पास किये जा चुके थे, लेकिन कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण इन्हें देर से लागू किया जा सका। जमींदारों को लगभग 60 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी गई।

राजस्थान में चकवन्दी के सम्बन्ध में भी अधिनियम पारित किया जा चुका है तथा अब तक 20 लाख एकड़ भूमि की चकवन्दी की जा चुकी है। भूमि की सीमा-निर्धारण के सम्बन्ध में भी सन् 1960 ई० में अधिनियम पारित किया

जा चुका है तथा सशोधन सहित अब में नियम लागू किये जा चुके हैं। इन अधिनियमों के अनुसार राजस्थान में एक कृषक परिवार 22 से 336 साधारण एकड़ भूमि से अधिक नहीं रख सकेगा।

भूम्याकन इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूमि-सुधारों की दिशा में राजस्थान में काफी काम किया गया है। अब राजस्थान से जमींदार, जमींदारी एवं विस्वे-दारी सभी प्रयास समाप्त हो चुकी हैं और लगभग 90% से भी अधिक किसानों को भू-अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु भूमि-सुधार कार्यक्रम में कुछ त्रुटियाँ भी हैं जिनकी ओर योजना आयोग की राय-कार्यक्रम समिति ने ध्यान दिलाया है। इस समिति के अनुसार राजस्थान में भूमिधर तथा भू-राजस्व का ढाँचा वैज्ञानिक नहीं है तथा भूमि कागूज जटिल तथा भ्रामक है। समिति ने सुझाव दिया है कि किसानों की सुविधा के लिए सम्बन्धित कानून हिन्दी में प्रकाशित किये जाने चाहिए। समिति ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में भूमि विषयक अधिनियमों को सरल बनाने, भू-राजस्व की दरों में सशोधन करने तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी सिफारिश की है। बताया है कि इन सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार भूमि-सुधार क्षेत्र में आवश्यक सुधार करेगी। राज्य सरकार ने भूमि-सुधार सम्बन्धी नीति को गम्भीरतापूर्वक लागू करने का जो विचार किया है, इससे यह विश्वास किया जा सकता है कि निकट भविष्य में भूमि सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी।

संक्षेप में राजस्थान में जमीनों बाँटने के ली गई हैं और जमींदारी तथा विस्वेदारी पद्धत समाप्त कर दिए गए हैं। भूतत्पूर्व ज़ातकों के स्टेटो का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाया जा चुका है। प्रत्येक रैयत को बाँटिक 1200 रु० की न्यूनतम आय वाले क्षेत्र के पट्टे की पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है और उसे स्वामित्व का अधिकार भी है। जोड़ की सीमाएँ 22 से 336 एकड़ तक निश्चित हैं। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही अभी की जाती है।

निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि-सुधार कार्यक्रम गटे ही उत्साह के साथ प्रारम्भ किए गये हैं। विभिन्न राज्यों से जमींदारी, जमींदारी या अन्य मध्यस्थों का उन्मूलन इस विश्वास में कारिकारी पथ रहा है। लेकिन भूमि सुधार कानूनों में अब भी कई त्रुटियाँ हैं। कानून बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में बहुत विलम्ब हुआ है। देश के कई भागों में अब भी बहुत सी भूमि पर खेती बटाई पद्धति पर की जाती है। ऐच्छिक परिवर्तन के नाम पर अब भी काश्तकारों की वेदखली होनी है। उचित कृषक सम्बन्धी वाराओं को

भी प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया है। भूमिहीन एवं छोटे किसानों के पास आज भी कृषि-कार्य के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। इन सबके वातजुद भी हम यह नहीं कह सकते कि भूमि-सुधार की विद्या में कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य अवश्य हुआ है, लेकिन उसकी गति धीमी रही है। इस सन्दर्भ में प्रो० दान्तवाला का यह कथन बड़ा ही उपयुक्त है, "भूमि-सुधार के लिए उठाए गए अब तक के कदम निश्चय ही सतोषजनक हैं, किन्तु इन्हें उचित रूप में लागू करने के जभाव में इनका परिणाम सतोषजनक नहीं हो पाया है।"¹

भूमि-सुधार कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से केंद्रीय सरकार देश की सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे भूमि-सुधार अभियानों की गति को दूर करे तथा भूमि-सुधार कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करें, ताकि देश के बहुमूल्यक किसानों का कल्याण हो तथा कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

प्रश्न

- 1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में सम्पन्न भूमि-सुधार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। (राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष कला 1967)
- 2 टिप्पणी लिखिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में भूमि-सुधार। (राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष कला 1966)
- 3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में सम्पन्न भूमि-सुधार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस सम्बन्ध में राजस्थान का विशेष उल्लेख कीजिए। (राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष कला 1965)
- 4 राजस्थान में भूमि-सुधार की प्रगति से आप कहा तक सतुष्ट हैं? कृषकों के सतोष के लिए और अधिक क्या करना चाहिए? (राज० टी० डी० सी० तृतीय वर्ष कला 1965)
- 5 कृषि अर्थ-व्यवस्था में भूमि-सुधार का क्या महत्व है। राजस्थान में इसे भूमि-सुधार पर विशेष प्रकाश डालते हुए, भारत में आज तक हुए भूमि-सुधार का वर्णन कीजिए। (राज० टी० डी० सी० तृतीय वर्ष कला 1967)

1 "By and large, land reforms in India enacted so far and those contemplated in the near future ... are in the right direction and yet due to lack of supplementation, the actual results are far from satisfactory."

6 स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त राजस्थान में जो भूमि-सुधार किए गए हैं, उनकी विवेचना कीजिए। अपने उद्देश्यों को पूरा करने में ये कहां तक सफल हुए हैं? इस सदर्भ में राज्य में भूमि की जोतो पर जो अधिकतम जोत अधिनियम लागू किया गया है, उसकी विवेचना कीजिए। (राज० बी० ए० बानर्स 1967)

7 अपने देश में जमींदारी उन्मूलन से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार प्रभावित हुई है? (राज० टी० डी० सी० प्रथम क्ला 1967)

8 सहकारी कृषि से क्या अर्थ है? भारत में इसके भ्रष्टव तथा प्रगति का उल्लेख कीजिए। (राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष क्ला 1965)

9 State clearly the directions in which land reforms have been introduced in our country and examine their results

(Raj B A Honours, 1966)

खाद्यान्नों की उत्पत्ति एवं खाद्य नीति

(Production and Food Policy)

"It is amazing how at the present moment in India, the vital basic importance of agricultural production, and more especially Food Production, is the one firm thing on which every thing has to rest. When I come back to this the whole success and failure of our Planning hangs by that single thread of our agricultural production and especially food production."

Pt Jawahar Lal Nehru

भोजन मानव की सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिस देश में खाद्यान्नों का अभाव होता है, वह देश आर्थिक दृष्टि में पिछड़ा हुआ माना जाता है। जिस देश की सरकार अपनी जनता को पेट भर भोजन नहीं दे सकती, वह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। वह देश कभी भी सम्मानपूर्वक अपना स्थिर उठा कर नहीं चल सकता, जिसे भोजन के लिए दूसरे देशों का सहता करना पड़े। दुर्भाग्यवश, भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। हमे अपने देश के लोगों को खाद्य सामग्री दिलाने के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का खाद्यान्न विदेशों से मगाना पड़ता है। निश्चय ही यह लज्जाजनक बात है कि देश की लगभग दो-तिहाई धन-सम्पन्न कृषि उपज में लगी हुई है, फिर भी हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न पैदा नहीं होता। विलियम पी. टर्नर ने ठीक ही कहा है

"प्रजातन्त्र के जीवित रहने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की पूर्ति होना आवश्यक है, क्योंकि अन्य स्वतन्त्रताओं का उपभोग करने के लिए मूल से स्वतन्त्रता पाना परमावश्यक है।"

भारत में खाद्य समस्या केवल खाद्यान्नों के अभाव की ही समस्या नहीं है, बरन बड़ी विविध समस्या है तथा इस पर भारत का भविष्य निर्भर करता है। भूख मनुष्य की एक ऐसी भूखमूत आवश्यकता है जिसकी पूर्ति किसी भी मूल्य पर होना आवश्यक

है। "पर्याप्त एवं पोषित भोजन के अभाव में भारत की विशाल जनसंख्या के कल्याण का आदर्श उनके लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करना तथा जनतावादी समाजवाद की स्थापना करना बिल्कुल असम्भव है।"¹ प्रो० इन्दुमाला ने ठीक ही कहा है, "मरा यह निश्चित विचार है, कि हम एक खनद का सामना नहीं कर रहे हैं, अपितु एक दीर्घकालीन रोग का उपचार करना है।"²

खाद्य समस्या का स्वरूप

भारतवर्ष में खाद्य-समस्या के स्वरूप को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत रख कर अध्ययन किया जा सकता है

1 **खाद्यान्नों की मात्रा में कमी** भारतवर्ष की कुल जनसंख्या के लगभग एक तिहाई भाग को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। डॉ० राधाकृष्णन मुखर्जी के मतानुसार भारत में अनाज की कमी होती जा रही है। इन कमी को पूरा करने के लिए हम हर वर्ष खाद्यान्नों का विदेशों से आयात करना पड़ता है। सन् 1947 से सन् 1961 ई० तक भारत ने औसतन प्रति वर्ष 30 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया है। एक अनुमान के अनुसार यदि देश के संपन्न लोगों को पर्याप्त भोजन दिया जाय तो लगभग प्रति वर्ष 75 लाख टन खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। जिसे विदेशों से मगाकर पूरा किया जाता है। इसमें 60 लाख टन जन्म की और छप 15 लाख टन बालों की कमी होती है। सन् 1965 व 1971 में खाद्यान्नों का आयात क्रमशः 1 करोड़ 4 लाख टन व 87 लाख टन हुआ। ये दोनों वर्ष सूखे के वर्ष थे। सन् 1968 से पंचवार में वृद्धि होने के कारण आयात में कमी हुई। सन् 1968, 1969, 1970 व 1971 में क्रमशः 57, 39, 36 व 21 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया गया।

2 **खाद्यान्नों के मूल्यों में दृष्टरोधक वृद्धि** स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1955-56 से खाद्यान्नों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है। प्रथम योजना काल में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि की अपेक्षा कमी रही। थोक मूल्यों के सूचकांक का आधार वर्ष 1952-53 की मानकर हम देखने हैं कि मार्च 1951 के अंत में खाद्यान्नों के थोक मूल्यों का सूचकांक 100 था, जो मार्च 1955 के अंत तक केवल 70 रह गया था। जुलाई 1955 के बाद से खाद्यान्नों के मूल्य में जो वृद्धि होनी प्रारम्भ हुई, वह निरन्तर बढ़ती चली गई। मार्च 1956 के अंत में सूचकांक 85

1 Without enough food, India's hope for improving her welfare achieving social justice and securing democracy will become almost impossible of attainment

Ford Foundation Team

2 M. L. Dangwala India's Food Problem (1961) p 1

हो गया दूसरी योजना की अवधि में (1956-61) में साधनो के मूल्य में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तृतीय योजना काल में अनाज के भाव हथोड़े से भी अधिक हो गए। खेती मूल्यों के सूचनाकोका आधार वर्ष 1961-62, मानने पर 1967-68 व 1968-69 में अनाज के सूचनाक कमज. 228 व 201 रहे। 1970-71 में में यह 207 हो गया। इस प्रकार 1961-62 से 1979-71 के वर्षों में साधनो के भावों में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई।¹

साधनो के मूल्य में जिन अनुपात में वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आम में इसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई, फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पास साधन खरीदने के लिए पद-व्यक्ति की कमी हो गई।

3 भोजन में पोषिक तत्वों का अभाव भारत के निवासियों को प्रतिदिन 3000 कैलोरीज की आवश्यकता है, किन्तु उसे केवल 2200 कैलोरीज ही उपभोग के लिए मिल पाती है। सन् 1940 में सर जॉन मेगा (Sir John Megaw) ने अनुमान लगाया था कि भारत में केवल 39% लोगों को उपयुक्त भोजन प्राप्त होता है, 41% लोगों को निम्न कोटि का और 20% लोगों को अत्यन्त न्यून कोटि का भोजन प्राप्त होता है। इस गवका अमर यह होता है कि भारतीयों को पोषिक भोजन नहीं मिलता, फलस्वरूप वे प्रायः रोगग्रस्त रहते हैं और देश में मृत्यु-दर भी अधिक है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुचित आहार की व्यवस्था करने के लिए हमें दालों के उत्पादन में 28.5%, सब्जियों में 65.3%, फलों में 55.9%, दूध में 54.9%, तिलहन में 72.3%, धी में 100% तथा अंडों में 93.1% की वृद्धि करनी होगी।

4 साधन वितरण व्यवस्था का दोषपूर्ण होना परिवहन के साधनों का विकास देश के सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ है। अतः कई क्षेत्र अब भी देश में ऐसे हैं, जहाँ समय पर साधन परिवहन के साधनों के अभाव के कारण, नहीं पहुँच पाता। यही नहीं मूल्य नियंत्रण भी प्रभावशाली नहीं है, फलस्वरूप धूम-खोर और चोर बाजारों में मनमानी भावों पर साधन बेचते हैं। इस प्रकार यदि देश में अनाज उपलब्ध भी हो तो वह जन-साधारण को उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता, अतः भारत में साधन की समस्या केवल उत्पादन की ही नहीं है अपितु सुव्यवस्थित वितरण के अभाव की भी है।

5 निर्धन जनसंख्या के लिए साधन-साधनों की व्यवस्था भारत के निवासी इतने अधिक निर्धन हैं कि वे अपने जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक साधन भी नहीं खरीद पाते। अतः उन्हें केवल साधन ही नहीं दिलाता आवश्यक है, बरन् सस्ती दर से दिलाता जरूरी है, अन्यथा वे भूख से पीड़ित रह जायेंगे। इस प्रकार भारत

की वर्तमान खाद्य समस्या का एक प्रमुख कारण सामान्य जनता में वितरित शक्ति का अभाव है।

भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन

(Food Production in India)

भारत वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन इसकी मांग की तुलना में बहुत कम है। स्वतन्त्रता प्राप्ति में पूर्व भी भारत में ऊना खाद्यान्न नहीं पैदा होता था जिसकी मांग थी फिर भी ब्रिटिश सरकार ने खाद्यान्नों के अभाव को मुक्त रूप से स्वीकार नहीं किया। 19वीं शताब्दी में भी खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता में कम था। सन् 1873 में 1906 के बीच खाद्यान्नों के फट्टर मूल्य में, अभाव के कारण ही खाद्यान्नों के मूल्य में टाई मुने से भी अधिक वृद्धि हुई थी।

बीसवीं शताब्दी में खाद्यान्नों का अभाव सर्वप्रथम 1921 में सम्भोरता में महसूस किया गया जबकि हमारे देश में खाद्यान्नों का आपात, निश्चिन्ता में बढ गया। सन् 1936 में वर्षा के अभाव से अलग हो जाने से चावल उत्पादन क्षेत्र में कमी आ गई और खाद्यान्नों का उत्पादन 13 लाख टन से घट गया। सन् 1947 में देश को विभाजन के परिणामस्वरूप 77 लाख टन में खाद्यान्नों की कमी हो गई। विभाजन के फलस्वरूप भारत में जनसंख्या ता 82 प्रतिशत रह गई जबकि चावल, ज गेहूँ के अन्तर्गत बोई जाने वाली भूमि का भाग कमजोर केवल 65 व 60 प्रतिशत ही रह गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक देश में खाद्यान्नों का उत्पादन इतना नहीं हो पाया है कि हम इनके आवागो से मुक्ति पा सकें।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रायः उणा-चत्वार्य अंश रत है। सन् 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग पांच करोड़ 51 लाख टन हुआ जो प्रथम योजना के अन्त में 6 करोड़ 92 लाख टन तक पहुँच गया। द्वितीय योजना के अन्त में यह 8 करोड़ 22 लाख टन हो गया। तृतीय योजना के अन्त में मूख एव अनाज की निश्चिन्ता के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हुई और उत्पादन घटकर 7 करोड़ 24 लाख टन रह गया। सन् 1967-68 के बाद से खाद्यान्नों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रही है। निरीक्षण काय में खाद्यान्नों के उत्पादन से सम्बन्धित आकड़ों का यदि विश्लेषण किया जाय तो विशिष्ट होगा कि 1964-65, 1967-68, 1969-1970 तथा 1970-71 के वर्षों खाद्यान्नों के उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम रहे हैं, जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिये गये आँकड़ों में ज्ञात होता है।

के बाद में तो कभी समय के पहुँचे हो जाती है। कभी वर्षा आवश्यकता से कम तो कभी ज्यादा होती है। इस सबका असर यह होता है कि जनोत्पादन कभी आवश्यक तानुस्तरूप नहीं होता और खाद्यान्नों की कमी हो जाती है।

3. रेबी प्रकोपों की बहुलता भारत की कृषि पर सदैव प्रकृति का प्रकोप छाया रहता है। प्रतिवर्ष लाखों टन खाद्यान्न बाढ़, भूकम्प, आधी, ओले या अत्यधिक वर्षा से नष्ट हो जाता है। कभी कभी टिड्डी-दलों के हमलों के कारण भी बहुत सा अनाज नष्ट हो जाता है।

4. देश का विभाजन बर्मा व पाकिस्तान में अलग हो जाने के परिणामस्वरूप देश के बावल व गहू पैदा करने वाले काफी क्षेत्र इन देशों में चले गये। 1947 में देश के विभाजन से भारत अनाजों में आधीन भूमि का क्षेत्रफल केवल 75%, बावल उपजान का अंश 68%, गहू उपजान का अंश 63%, तथा सिंचाई का क्षेत्र केवल 69% हो रहा था। जबकि जनसंख्या 82% देश में रह गई। यही नहीं, बहुत बड़ी मरम्मत से वारणधियों में आ जाने के कारण भूमि पर असुरक्षा का दबाव बढ़ गया, जिससे खाद्यान्नों की कमी महसूस होने लगी। इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न की कमी में वृद्धि हो गई और देश को खाद्यान्नों के आयात के लिए विवश होना पड़ा।

5. प्रति एकड़ कम उपज भारतीय कृषि पिछड़ी होने के कारण प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में कृषि की जाने वाली कुछ भूमि के प्रायः 1/3 प्रतिशत भाग में खाद्यान्नों की खेती होती है, फिर भी लाख फसलों की प्रति एकड़ कम उपज के कारण देश में यथोचित मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो पाना व्यवस्थित देश में राख सफट की स्थिति बनी रहता है।

6. फसलों के स्वरूप में परिवर्तन भारत में किसानों का दृष्टिकोण व्यवसायिक होता जा रहा है। भूमि में उतार चढ़ाव को ध्यान में रख कर किसान बड़ी फसल वाला व जो उसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ दे। फलस्वरूप अब खाद्यान्न फसलों गहू और जौ बना मटर आदि के स्थान पर वह व्यापारिक वस्तुएं, यथा कपास, जूट, तिलहन व ना आदि पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप देश में खाद्यान्नों का अभाव हो गया है।

7. पूँजी वितरण व्यवस्था भारत में खाद्यान्नों का वितरण प्रायः आपसी वर्ग के माध्यम से होता है। ये लोग अपने स्वयं को बढ़ाने के लिए अनाज संचयन करते हैं और बाजार में कृत्रिम कमी उत्पन्न कर मुनाफाखोरी करते हैं जिससे खाद्यान्नों की पूर्ति कम रह जाती है। सरकार द्वारा खाद्यान्नों के वितरण की प्रणाली भी बड़ी क्षिप्त है। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि सरकार के पास अन्न के पर्याप्त

भण्डार होने के बावजूद भी उनके उपभोगताओं तक ठीक समय पर नहीं पहुँचाया जाता।

8 किसानों के उपभोगस्तर में वृद्धि व्यापारिक फसल होने के कारण कृषकों को अब अपेक्षाकृत अधिक पैसों मिलने लगे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका उपभोग स्तर बढ़ गया है। इस प्रकार एक ओर तो वे अधिक खाद्यान्नों का उपभोग करने लग रहे और दूसरी ओर उनके द्वारा खाद्यान्नों की उपज कम हो गई है, फलस्वरूप खाद्यान्नों का अभाव पाया जाता है।

9 भोजन की वरिष्ठादी भारत में एक ओर यदि लोगों को खाने की पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो दूसरी ओर सम्पन्न लोगों द्वारा बड़ी बड़ी दावतों और भोजनों में अन्न की बर्बादी होती है। अन्न विधवा के कारण रोग कीड़े, चूहा, सन्दूक व अन्य जीव-जन्तुओं के मारम के विरोधी है। फलस्वरूप ये पशु पक्षी खाद्यान्नों को एक बहुत बड़ा भाग का सफाया कर जाते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Food Technological Research Institute) के अनुसार देश के कुल खाद्य उत्पादन का 21 प्रतिशत भाग, जिसका मूल्य लगभग 4,600 करोड़ रुपय होगा कीटी, नुस्तर कर माने वाले जलबरी तथा बीजपूर्व तटस्थ-व्यवस्था के कारण नष्ट हो जाता है।¹

10 उपभोग-सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन 30 राधाकृष्ण मुखर्जी के मतानुसार उपभोग सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन भी खाद्यान्नों के अभाव के लिए उत्तरदायी है। एक ओर तो किसानों में पीथिक खाद्यान्नों के स्वाद पर घटिया खाद्यान्नों के उत्पादन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है दूसरी ओर बढ़िया खाद्यान्नों का उपभोग बढ़ रहा है, जिससे खाद्यान्नों की कमी महसूस होती है।

11 जनता की निधमता भारतवर्ष की अधिकांश जनसंख्या निर्धन है। निर्धनता के कारण जन साधारण गेहूँ, चावल तथा अन्य पीथिक खाद्यान्नों खरीदने की स्थिति में नहीं है। जब देश में खाद्यान्नों के भूख में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो निर्धन लोग महंगाई के फलस्वरूप यथोचित मात्रा में खाद्यान्न नहीं खरीद पाते और उनके लिए खाद्य समस्या अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार कभी-कभी देश में खाद्यान्नों के होने के बावजूद भी खाद्य-मस्यवा उत्पन्न हो जाती है। सन् 1943 का बंगाल का भीषण अकाल इसका जबरन प्रदर्शन प्रस्तुत करता है।

12. समस्या के प्रति उदासीन दृष्टिकोण . बिरोडोर मुल्की एवं एन्डर्स मैमन ने भारत की खाद्य समस्या का एक कारण यह भी बताया है कि नव 1964-65 तक भारत सरकार एवं जनता ने इन समस्या को सम्मोहतापूर्वक नहीं लिया। चूँकि भारत को पी. एल 480 के अन्तर्गत अमरीकी अनाज सरलता से मिलता रहा है फलस्वरूप यहाँ कभी भी स्वावलम्बन की दिशा में बढ़ने के लिए दमनकारी के प्रयास नहीं किए गए।

खाद्य समस्या को हल करने के सुझाव

भारत की खाद्य समस्या कोई साधारण मसूदा नहीं है, जैसा कि एक पुरानी बीमारी है। प्रा. दानवाला न ठीक ही कहा है, "हमें एक मसूदा को नहीं, जैसा कि पुराने रोग को ठीक करना है और इसके उपचार सामान्य हैं, अपनाएँ नहीं।"¹

भारत जैसी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में, जिसमें जनसंख्या और आप के बढ़ने के कारण खाद्यान्नों की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, एक उपयुक्त राष्ट्रीय खाद्य नीति की आवश्यकता है जिसके प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए, (i) खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना (ii) खाद्यान्नों का स्वायत्त-पूर्व विवरण, तथा (iii) खाद्यान्नों के मूल्य को उचित स्तर पर स्थिर रखना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं

1. उत्पादन में वृद्धि भारत में खाद्यान्नों की उत्पत्ति में वृद्धि बिना बिना खाद्य समस्या को नहीं मुलनाया जा सकता। अतः सिंचाई की सुविधायें बढ़ाना, उत्तम बीज व खाद्य की व्यवस्था करना, खतबन्दी व गहरी खेती को अपनाया जावे ऐसे तरीके हैं जिससे कृषि उपज में वृद्धि हो सकती है। श्री वर्म के अनुसार नैदानिक तरीकों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि उपज में सामान्यतः 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है 20% उचित माद्य के प्रयोग द्वारा, 5%, उत्तम बीजों के प्रयोग द्वारा तथा 3%, कीड़े-मकोड़ों से फसलों की रक्षा के द्वारा।²

2. खेती के क्षेत्र का विस्तार वज्र, दण्डक भूमि, तराई की भूमि आदि जो खेती के योग्य बनाकर खेती के क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। भूमि सम्बन्धी उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार देश में 600 लाख एक्ड कृषि योग्य भूमि बेकार है जिसका उद्धार कर कृषि-योग्य बनाया जा सकता है। ऐसी भूमि के उपयोग से देश की खाद्य समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है।

1. "What is the cure is not a crisis but a chronic malady and the remedies for it are of a routine nature rather than of spectacular nature"

—Prof. M. L. Dantwala

2. *Born Technical Possibilities of Agricultural Development in India.*

3 जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या पर रोक लगाने बिना इस समस्या का निराकरण सम्भव नहीं है। क्योंकि जनसंख्या और खाद्य-सामग्री यदि अपनी वर्तमान गति में बढें, तो जनसंख्या साथ-साथी से काफी जग बढ़ जायेगी। अतः 'Grow more Food' के साथ-साथ 'Grow less Children' आन्दोलन भी चलाया जाना चाहिए।

4 उपभोग की आवश्यकता में सुधार भारतीय जनो भोजन में मुख्यतः अन्न का ही उपभोग करने है। उन्हें अन्न का उपभोग कम करना चाहिए और फल, शाक-सब्जी, दाल, मांस-मछली का उपभोग उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए।

5 विशेष ध्यान में सुधार सरकार को खाद्यान्व वितरण की व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जो प्रत्यक्ष, चोर-बाजारी व सरत फीरोशाही से मुक्त हो और लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके। सरकार का उचित दर वाली सरकारी दुकानों पर अनाज बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए।

6 देश का औद्योगिकरण इसी भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम पड़ेगा। कृषि की उत्पादनता बढ़ेगी उद्योगों के विकास में राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। उस समय विदेशों से भी अनाज मगाना अनुपयुक्त होगा।

7 खाद्यान्न के मूल्य को घटाई। इससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त जायेगा। फलस्वरूप यह उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रवृत्त हो रहेगा।

8 कृषि प्रशासन में सुधार प्रशासनिक लाल फीरोशाही को दूर करना, अनुसंधान, फसल निर्माण कृषि कृषि एवं अनुदान व्यवस्था में सुधार करना, तथा राज्य के कृषि कर्मचारियों को सक्रिय बनाना परमावश्यक है, अन्यथा कृषि में सुधार नहीं हो सकेगा और न ही उत्पादन में वृद्धि होगी।

9 ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। किसानों में फैली बेकारी और अर्द्ध-बेकारी को दूर करने के लिए कुटीर एवं छोटे उद्योगों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। एक तो जनसंख्या का भूमि पर दबाव कम हो जायेगा और दूसरे किसानों की आमदनी बढ़ जायेगी, जिसे वे उत्पादन बढ़ाने में प्रयुक्त कर सकेंगे।

10 सामुदायिक योजनाओं द्वारा प्रशस्त सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा अपने प्रयत्नों में तेजी लाकर खाद्य-समस्या को सुलझाया जा सकता है। सामुदायिक विकास समूहों के कार्यकर्ता किसानों को नई कृषि विधियों की शिक्षा देकर एवं जल प्रसार की व्यावहारिक सुविधाएं देकर कृषि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

11. उचित भण्डार-व्यवस्था : सरकार वन के कुल छायायन उत्पादन एवं उपभोग के अनुमानों के आधार पर मात्रा में जिनकी अतिरिक्त छायायनों की आवश्यकता हो, उने वायात करके अपने भण्डार पहले से ही भर ले, ताकि संकटकाल में इन्हें भण्डारों से छायायनों की पूर्ति की जा सके ।

12. राज्यों में सहयोग की भावना का निराकरण : वन समस्या के निदान के लिए वन के सभी राज्यों को मिल कर प्रभावनाधी बंदम उठाने चाहिए । अतिरिक्त वाले राज्यों की सरकारें अपने वायित्व की समस्याओं तथा राजनीति एवं क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनापयन्न राज्यों से सहयोग न करें ।

13. अन्य मुद्दाय : उन्नोक्त मुद्दायों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य मुद्दायों की ओर भी ध्यान देने में समझा सज्जन सङ्गी है, यथा—(1) पञ्चानन गमिनियों की स्थापना एवं उत्पादन बढ़ाने का उत्तरदायित्व उनके कर्मों पर रखना, (2) वृष्टि सरकारी गमिनियों का विकास करना, (3) वनों भोजनार्थों के अलावा छोटी व मध्यम आकार की निचाई भोजनायों का निर्माण करना, (4) भूमि-व्यवस्था के माय विप-वाड करने के बजाय, भूमि-मुद्दाय सम्बन्धी कानूनों की संशोधित करना, (5) गाय, भैंस, मुर्गियों आदि की अधिकधिक मरुता में पाव कर भोजन में परिचित दत्वों की वृद्धि करना, (6) सरकार द्वारा छायायन की अवाचरी व मटेवाजी को रोकने के लिए प्रभावनाली बंदम उठाना, (7) छायायनों के कृत्यों में वृद्धि न होने देने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त 'बफर स्टॉक' का निर्माण किया, तथा (8) सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य बजट (National Food Budget) का निर्माण आदि ।

खाद्य-समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न :

1. छायायनों के मूल्यों पर नियन्त्रण : जब छायायन स्थिति खराब होने लगती है, तब सरकार उचित विवरण के उद्देश से छायायनों के मूल्य पर नियन्त्रण लगा देती है । भारत में सन् 1942 ई० में पहली बार इन प्रकार का नियन्त्रण लगाया गया था, परन्तु सन् 1947 ई० में बायोमी के अन्तरोप पर हटा लिया गया था । इसे सन् 1948 में पुन उलू किया गया । आज भी किसी न किसी रूप में मूल्य-नियन्त्रण या गाननिष व्यवस्था लागू है ।

2. अधिक अन्न-उपज्रायो-आन्दोलन : यह आन्दोलन भी सन् 1942 ई० में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु जब समय यह नष्ट नहीं हुआ था । सन् 1943 के बाद इसे तथा रूप दिया गया तथा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से मिला दिया गया ।

3. खाद्य स्वावलम्बन आन्दोलन : सन् 1947 ई० में एक खाद्य स्वावलम्बन आन्दोलन चालू किया गया था । श्री वे. एम. मुन्शी ने इन आन्दोलन की सफल

बनाने के लिए कई सुझाव दिये। सन् 1952 ई० तक इस आन्दोलन के द्वारा देश की साधानों के मामले में स्वावलम्बी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा न हो सका।

4 साधानों के निर्यात पर रोक केन्द्रीय सरकार ने बंगाल के अकाल के पश्चात् साधानों के निर्यात पर रोक लगा दी है। साधानों के निर्यात न होने से देश के लिए साधानों की जगलक्षता अब बढ जायेगी।

5 अन्य दशाओं आन्दोलन अन्न-पदार्थों आन्दोलन के अन्तर्गत किसानों और व्यापारियों को अनाज को सुरक्षित भण्डारों में रखने के वैज्ञानिक तरीके बताने जाते हैं, ताकि गहले-घोदामों में कीड़े, चूने आदि से अनाज की रक्षा की जा सके। इस आन्दोलन को भी भारत सरकार ने ही चलाया है।

6 विदेशों से साधानों का आयात साधान की कमी को पूरा करने के लिए सरकार विदेशों से बड़ी मात्रा में साधानों का आयात करती है। सरकार ने अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मा तथा सोवियत एंस से विगत वर्षों में साधानों का आयात किया है। अधिकतर अनाज अमेरिका से, शार्वजिनिक नियम 480 के अन्तर्गत आयात किया गया है। सन् 1951 से 1971 की अवधि में लगभग 9 करोड़ टन साधान का आयात किया जा चुका है। विगत वर्षों में भारत में साधानों के आयात की स्थिति का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है

वर्ष	साधानों का आयात (मिलियन टनो में)
1951	6.9
1956	1
1961	6
1966	10.4
1967	8.7
1968	5.7
1969	3.9
1970	3.6
1971	2.1
1972	4.1

7 साधानों का सरकार द्वारा वितरण सरकार ने देश भर में सस्ते अनाज की दुकानें खोली है, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर साधान उपलब्ध कराये जाते हैं। अथवा सन् 1965 ई० में सरकार ने उन सभी नगरों में राशनिय प्रारम्भ कर दी, जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर थी। विगत वर्षों में सरकार द्वारा वितरित किया गया साधान अगले पृष्ठ पर दी गई। तालिका में दिखाया गया है।

सरकार द्वारा खाद्यान्ना का वितरण

वर्ष	वितरण (लाख टन में)	वर्ष	वितरण (लाख टन में)
1960	49.4	1966	140.8
1961	39.8	1967	130.0
1962	43.7	1968	101.0
1963	51.8	1969	90.0
1964	86.7	1970	89.0
1965	100.8	1971	77.0
		1972	100.0

8 खाद्यान्ना की जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर रोक सरकार ने वह पैमाने पर खाद्यान्ना का सप्ले करने वाले व्यापारियों एवं उत्पादकों को मना देने के लिए कानूनी व्यवस्था की है। आवश्यक पदार्थ अधिनियम (Essential Commodities Act) तथा भारतीय प्रतिरक्षा नियम (D fence of India Rules) के अन्तर्गत इन व्यापारियों एवं उत्पादकों ने बिस्व बाइबोहिया का ना सकते हैं जो अनुचित लाभ उठाने के लिए जमाखोरी का अपराध करते हैं।

9 भारतीय खाद्य निगम की स्थापना देश भर में खाद्यान्नों का व्यापारपूर्ण वितरण करने के लिए तथा अनाज के मूल्यों को स्थिर बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 1965 ई० में खाद्य निगम (Food Corporation of India) की स्थापना की। यह सरकारी प्रतिनिधि के रूप में खुले बाजार में खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय करता है। खाद्यान्नों के व्यापारित वितरण के साथ साथ यह निगम कृषि उत्पन्न बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा विगत वर्षों में खाद्यान्ना के कृय विक्रय की दिशा में लिए गए कार्यों का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है।

भारतीय खाद्य निगम की प्रवृत्ति

वर्ष	व्रय	(लाख टनों में)
		विक्रय
1869-68	87.1	66.4
1969-71	97.3	88.5
1970-71	88.1	70.4

सन् 1970-71 में निगम ने 739 करोड़ रु का खाद्यान्न खरीदने एवं 684 करोड़ रुपय का खाद्यान्न बेचा।

10 अन्य प्रयत्न सरकार द्वारा खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए अन्य कई कदम भी उठाये गये हैं, जैसे, (1) तृतीय योजना के अन्त में नई कृषि विकास

की विधि का अपनाया जाना, (ii) खाद्य नियंत्रण एवं सार्व वी शैवीय व्यवस्था; (iii) विनाशाल अन्न भण्डारों का निर्माण, (iv) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली (v) खाद्यान्नों के संचय के लिए बंधों के अण पर प्रतिपत्र, (vi) रिजर्व बैंक द्वारा अनाज का स्टॉक बाजार खेवत के लिए साध नियंत्रण आदि ।

सरकार द्वारा उठाए गए उपभुंक्त वर्गिन बदलों के बावजूद भी हमारी खाद्य समस्या में सुधार नहीं हो सका है तथा खाद्य नीति प्राय असफल रही है जिनके कई कारण हैं जैसे—(i) राजनीतिक दबाव में बाहर कृषि मूल्य प्रायोग की सिफारिशों की अवहम्मा, (ii) शीघ्र प्रतिक्रिय देने वाली योजनाओं की ओर अधिक ध्यान न देना, (iii) जनसंख्या के नियंत्रण में असफलता (iv) सरकार की नीतियों में व्यवस्था एवं हमका शीघ्र सनुष्ट हो जाना, (v) राज्यों में पारस्परिक सहयोग का अभाव, (vi) अष्ट एवं प्रभावहीन प्रशासन आदि ।

पंचवर्षीय योजनाएं एवं खाद्य नीति (Food Policy under Five year Plans):

भारत सरकार ने खाद्य समस्या को मुद्दाने के लिए नियोजन काल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है —

प्रथम योजना प्रथम योजना में सन् 1950-56 तक अधिक अन्न उत्पादन का लक्ष्य 76 मि० टन रखा गया, ताकि प्रति व्यक्ति 14 बीस माहुर दिलाया जा सके । सन् 1952 ई० में अधिक अन्न उपजाने आन्दोलन की जांच के लिए कुल-माचारी समिति की नियुक्ति की गई । इस समिति ने उताप कि इस आन्दोलन के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले । इस समिति का मत था कि गाँव के लोगों के जीवन का उन्नत करने के लिए कृषि सधार पर जोर दिया जाना चाहिए । आयात समाप्त करने से समस्या नहीं सुलझ सकती । इस योजना के अन्तर्गत खाद्य नीति में तीन बातों पर जोर दिया गया—(i) आद्यान् के उत्पादन में वृद्धि, (ii) आद्यान् के वितरण की उचित व्यवस्था, (iii) आद्यान् के आयात को पर्याप्तभव कम करना । इस योजना के अन्तर्गत कृषि विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें थी (i) मायुदायिक विकास परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा (Community Development Projects and National Extension Service) का प्रारम्भ किया जाना, (ii) मिषाई के छाटे प्रदे साधनों का प्रयोग करना, (iii) भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून पास करना, तथा (iv) कृषि वित्त तथा खेती के लिए ऋण, यन्त्र आदि विविध प्रकार की सामग्री बढ़ाना । अनुकूल जलवायु एवं कृषि विज्ञान कार्यक्रमों के फलस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1950-51 में 55 करोड टन से बढ़ कर सन् 1955-56 ई० में 69 करोड टन हो गया । बन्नी फनल के फलस्वरूप खाद्यान्नों का आयात सन् 1951 ई० में लगभग 69 लाख टन से घट कर सन् 1955 ई० में केवल 10 लाख टन रह गया ।

द्वितीय योजना : इस योजना में अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य एक करोड़ टन रखा गया था, अर्थात् सन् 1955-56 में 6.9 करोड़ टन से उत्पादन बढ़ा कर सन् 1960-61 में 7.5 करोड़ टन करना था। बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद तथा केन्द्र व राज्यों के कृषि मंत्रियों द्वारा पुनर्विचार के बाद लक्ष्य बढ़ा कर 8.00 करोड़ टन कर दिया गया। कृषि उपज बढ़ाने के उन्ही तरीकों पर जोर दिया गया, जिन्हें प्रथम योजना के अन्तर्गत सुझाया गया था। योजना काल के दौरान खाद्यान्नों के मूल्य में वर्षाधिक वृद्धि के कारणों की जाँच करने के लिए 24 जून, 1957 ई० की भी अगोचर मेहता की अध्यक्षता में एक खाद्यान्न जाँच समिति (Food Grains Enquiry Committee) की नियुक्ति की गई। इस समिति ने खाद्यान्नों के लिए एक प्रभावशाली मूल्य-स्थिरानकरण नीति को लागू करने के लिए एक उपयुक्त संगठन अर्थात् खाद्यान्न स्थिरानकरण संघटन (Food Grains Stabilisation Organisation) नियुक्त करने का सुझाव दिया। अल्पकालीन सुझाव के तौर पर समिति ने गन्धे के वितरण के लिए 'फ्लूर प्राइज शाप' तथा गृहकारी समितियों की प्रभावता देने की सिफारिश की। समिति ने ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर तथा वाणिज्यिक एवं सिंचाई की योजनाओं के नियामक पर भी जोर दिया। समिति खाद्यान्न के उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई गतिविधि सुझाव न दे सकी। सरकार ने समिति के अधिवाह सुझावों को स्वीकार कर लिया। लेकिन इन प्रयत्नों के बावजूद भी इस योजना में अधिक सफलता न मिली तथा सन् 1960-61 ई० में खाद्यान्न उत्पादन 8.22 करोड़ टन हुआ। इस योजना के दौरान सन् 1958-59 ई० में तो खाद्य समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया था।

तृतीय योजना : इस योजना में सन् 1965-66 तक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 10 करोड़ टन रखा गया था, ताकि प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा के 1961-62 ई० में 16 औंस से बढ़ा कर 1965-66 ई० में 17.5 औंस तक की जा सके। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने इस योजना में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, यथा (i) कृषि पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र व केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन परिषद (Agricultural Production Board) की स्थापना की गई, (ii) जून 1965 ई० में भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) की स्थापना की गई। यह निगम खाद्यान्नों के ऋण विक्रय, मध्य तथा वितरण की व्यवस्था करेगा। (iv) जून 1965 ई० में ही एक कृषि-मूल्य परिषद (Agricultural Price Commission) की स्थापना की गई जो सरकार को मूल्य नीति के सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श देगी। जलवायु की प्रतिभूति एवं देश के ऊपर मुद्रा-संकट के बादलों के परिणामस्वरूप तृतीय योजना के लक्ष्य भी प्राप्त न किए जा सके। तृतीय योजना के अन्त में

खाद्यान्न उत्पादन लगभग 7 42 करोड़ टन था, जो लक्ष्य से कम था। खाद्यान्न-उत्पादन की कमी के कारण खाद्य समस्या ने भयंकर रूप ले लिया। देश को अकाल से बचाने के लिए अमेरिका, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया से अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा।

खाद्यान्न नीति समिति 1966

15 मार्च 1966 को श्री बी. बंकेटपंध्या की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसे प्रचलित खेतीय व्यवस्था और अनाज की वर्तमान बसूली व वितरण की जाँच करने तथा देश के विभिन्न राज्यों व वर्गों के बीच उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों के वितरण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए कहा गया था। इस समिति के प्रमुख मुद्दाब ये, (i) राष्ट्रीय खाद्य वनकट बना कर, उपलब्ध अनाज का नियोजित वितरण किया जाय, (ii) खाद्य वनकट के निर्माण, इसकी समीक्षा, सशोधन, व कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य परिषद का गठन किया जाय, (iii) भूमिहीन कुपको को अन्न उपलब्ध कराने के लिए गांवों में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाय, (iv) मूल्य स्थिरता के लिए कम से कम 40 लाख टन खाद्यान्नों का बफर स्टॉक आगामी 3-4 वर्षों में निर्मित किया जाय तथा इसका प्रवर्ध भारतीय खाद्य निगम को मौका जाय, (v) अनाज संचय के लिए गोदामों का तीव्रगति से निर्माण किया जाय तथा खाद्यान्न बसूली को प्रार्थगिकता दी जाय, (vi) उचित वितरण व प्रवर्ध की स्थिरता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्तर्राज्यीय गतिशीलता पर नियन्त्रण रक्खा जाय, (vii) भारतीय खाद्य निगम सभी राज्यों में प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करे तथा दिन-प्रतिदिन की बसूली एवं वितरण से सम्पर्क रखे तथा (viii) खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जाय, लेकिन बसूली का मूल्य (Procurement-prices) न्यूनतम मूल्य से ज्यादा हावा चाहिए।

एकवर्षीय योजनाएँ (1966-69) तृतीय योजना के पश्चात् देश में एक-एक वर्ष की तीन योजनाएँ क्रियामित की गईं। वन् 1966-67, 67-68 एवं 68-69 में नई कृषि नीति अपनाए जाने के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन क्रमशः 74 2, 95 1 व 94 0 करोड़ टन हुआ। इन वर्षों में अच्छी वर्षा, अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, कृषि मशीन दवाइयों आदि के अधिवाधिक उपयोग के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में खाद्य नीति चौथी योजना में खाद्य नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं :

(1) उपभोक्ता मूल्यों की स्थिरता सुनिश्चित करना तथा विशेष रूप से कम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।

(2) उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना।

(3) अनाजों का पर्याप्त समीकरण भण्डार यानी 'बकर स्टॉक बनाना,' ताकि कम और बढ़ती या गिरती कीमतों का मुकाबला किया जा सके।

इस योजना में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए नष्टकारी समितियों तथा उचित मूल्य वाली दूकानों के माध्यम से व्यापारित किया जायेगा तथा निजी व्यापार को नियमित किया जायेगा। सरकार किसानों में आद्यात्म भारतीय खाद्य नियम, गृहकारी समितियों तथा ऐसी अन्य मन्थ्याओं में सरोदेवों, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

पर्याप्त समीकरण भण्डार बनाने के लिए कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 1968-69 में इसके लिए 20 लाख मीट्रिक टन अनाज एकत्र किया गया। इस भण्डार को बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन के जाने का लक्ष्य है। प्रतिवर्ष 60 लाख से लेकर 1 करोड़ मीट्रिक टन तक अवयव अनाज वसूल किया जायेगा। अनाज पर क्षेत्रीय प्रतिस्पर्ध लगाने की नीति को भी व्यापहारिक रूप दिया जायेगा।

चौथी योजना के तत्कालावधान में उत्पादन का लक्ष्य 12.9 करोड़ टन रखा गया है। आद्यात्मों की वृद्धि के लिए ऋण उपज बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा तथा कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे, यथा : मिर्चाई सुविधाओं का विस्तार, (ii) अच्छे विस्म के बीजों के उत्पादन में वृद्धि, (iii) इपि उपकरणों की व्यवस्था, (iv) रामायनिक उर्वरकों की पूर्ति में वृद्धि (v) भूमि नरक्षण एवं भूमि सुधार पर जोर, तथा (vi) अधिक उपज देने वाली फसलों पर जोर आदि।

भारत सरकार की वर्तमान साख्त-नीति भारत सरकार की वर्तमान साख्त-नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं।

(क) साद्यात्मों की क्षेत्रीय व्यवस्था—इसके अन्तर्गत अनेक राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र मिला कर एक क्षेत्र नियमित किया गया। इस प्रकार के अनेक क्षेत्र गेहूँ व बाजल के लिए नियमित किए गए, ताकि एक क्षेत्र विशेष में प्रतिरेष व अभाव के राज्य जा सकें तथा राज्य के क्षेत्र विशेष में स्वतन्त्र रूप से आवागमन हो सके। अनेक अर्थन्यात्रियों के द्वारा क्षेत्रीय व्यवस्था के विरोध किए जाने के कारण 4 अग्रेज 1970 में उन्हें के क्षेत्र नमोण कर दिए गए हैं।

(ख) समीकरण भण्डार (Buffer Stocks) का निर्माण करना ताकि आद्यात्मों के मूल्य में स्थिरता लाई जा सके। जन् 1968-69 में 16 लाख टन के स्टॉक से यह कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो 1971-72 तक 49 लाख टन तक पहुँच चुका था तथा जिसका मूल्य 431 करोड़ रुपए था।

(ग) साद्यात्मों में सरकारी व्यापार—भारतीय साख्त नियम के माध्यम से सरकार अनाज का स्वयं-विक्रय करती है, ताकि मूल्यों में अनृषित उतार-चढ़ाव को रोका जा सके। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने अनाज के क्षेत्र व्यापार को अपने हाथ में लेने की घोषणा की है।

(घ) मसूदे अनाज की दुकानों तथा नगरों में राशनिक के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज के वितरण की व्यवस्था कर रही है।

(च) रिजर्व बैंक अनाज का सट्टा व्यापार खोलने के लिए प्रभावशाली साख गिराने की नीति अपना रही है।

(ज) अनाज की खाद्य-आदतों (Food habits) में परिवर्तन एवं सतृप्त भोजन के लिए प्रचार का कार्य किया जा रहा है।

(झ) निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर जोर दे रहा है।

(ञ) खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ही सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें नई कृषि विकास नीति (New Agricultural Strategy) महत्वपूर्ण है। अब हम निम्न अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होने की कल्पना कर सकते हैं।

अनाज के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता पर चल देते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के निम्नांकित विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं।

अब समय आ गया है जब हम अनाज में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस कार्यवाही करना चाहें। ऐसा करना इच्छित जरूरी है, क्योंकि पिछले ११ वर्षों में अनाज की उत्पादन में बहुत ही कम वृद्धि हुई है। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय उत्पादन में वृद्धि और वस्तुओं के कार्यक्रम की और कुशल बनाना है। हम विनियोजन कर काम करना तो हमसे आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा।¹

— श्रीमती इन्दिरा गांधी

प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों पर उत्तर दें।

(राज टी वी की प्रथम वर्ष कक्षा 1965-67)

2. "भारत समस्या का कुछ स्तर पर सुधारण करता जा रहा है।" विवरण दीजिए।

(राज टी वी 1965)

3. "Even after fifteen years of economic planning, India faces at present a serious food crisis. Give reasons and outline the measures taken by the Government to solve the food problem in country."

(Raj B A Honours, 1966)

4. भारतीय खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए आप कौन-कौन से उपाय सुझाएंगे? उन्हें अविवरण देकर बताइए। (राज प्रथम वर्ष टी वी सी कक्षा 1969)

नवीन कृषि नीति

(New Agricultural Strategy)

"The government should realise the urgency of the agricultural reorganisation problem and draw up a new agrarian policy, based on through institutional changes for the 'dynamisation of the rural sector"

—Alak Ghosh

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थ-व्यवस्था का आधार कृषि है। जनसंख्या का लगभग तीन-चौथाई भाग कृषि पर आश्रित है। देश की राष्ट्रीय आय में इसका महत्वपूर्ण भाग रहता है। परन्तु इतना सब कुछ होने के बावजूब भी यहाँ कृषि की अवस्था खोचनीय है। कृषि क्षेत्र की 55 करोड़ जनता को भरण-पोषण करने में असमर्थ है। कृषक, जो कृषि-कार्य सम्पादित करता है, स्वयं निर्धन है। दिन भर के भयंकर परिश्रम के बाद दो बक्का का भोजन भी नहीं खाता। कृषि का यह पिछड़ापन स्वयं कृषक ही के लिए अभिशाप नहीं है, अपितु सारे देश के लिए भी राज्या की वारता है। निःसन्देह आज कृषि का पिछड़ापन सरकार के लिए चुनौती है। यदि सरकार इस चुनौती का उचित उत्तर देने में सक्षम है, तो देश सुशाहली की कल्पना कर सकता है, अन्यथा देश का भविष्य वर्तमान से भी अधिक बुरा होगा। सरकार ने यह भली भाँति समझ लिया है कि कृषि के विकास में और अधिक सम्बन्धित परीक्षण नहीं किये जा सकते। अब नई एवं दृढ़ नीति अपनाकर कृषि का शीघ्र विकास परमावश्यक है। यदि देश में कृषि-विकास नहीं हो पायेगा तो देश आपेक्षित आर्थिक उन्नति नहीं कर पायेगा।

सद्यन्तर् भारत में कृषि-विकास एवं कृषि सम्बन्धी नीति

औद्योगिक अल्प-विकसित देशों में, जिनमें अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, मास की तुलना में खाद्य-पदार्थों और कृषिगत कच्चे माल की अत्यधिक कमी है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन देशों में प्रति एकड़ उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है। कृषि उपज बढ़ाने की विविध योजनाओं

के बावजूद भी बहुत कम देश खाद्य उत्पादन में वृद्धि की दर दीर्घकाल तक बनाये रखने में सफल हुये हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा प्रथम में क्रमशः गाठ प्रतिशत व पञ्चवीं प्रतिशत जनसंख्या खेतों के व्यवसाय में लगी हुई है, फिर भी ये देश अपनी समस्त जनता के लिये खाद्यान्न उपलब्ध करने की स्थिति में हैं। इसके विपरीत अल्प विकसित देशों में लगभग 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या खेतों करती है, लेकिन फिर भी ये देश अपनी जनता के लिये पूरा खाद्यान्न पंदा करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें दूगरे विश्व युद्ध के पश्चात् उन्नत देशों से खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता पड़ती रही है। भारतवर्ष भी ऐसा ही एक अल्प-विकसित कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 70 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या खेतों से ही अपना जीवन-यापन करती है। लेकिन फिर भी खाद्यान्न के मामले में भारत को अन्य देशों का मुहं ताकना पड़ता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की लोकप्रिय सरकार ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि विकास सम्बन्धी एक व्यापक एवं प्रभावशाली नीति अपनाई। आजादी के मात्र ही साथ देश का विभाजन हुआ, कलम्बस पट्ट, कपास जैसी महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादक क्षेत्रों का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया। अतः स्वतन्त्र भारत में, देश की सरकार को ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ी जिससे जनता के लिये खाद्यान्नों एवं दूध के कारखानों के लिये अच्छे माल की पर्याप्त उपलब्धता हो सके और देश कृषि-उत्पादों में स्वावलम्बी बन जाय। इस दिशा में प्रभावशाली प्रयत्न, देश के आर्थिक नियोजन के मध्य-साथ प्रारम्भ हुए। देश की पञ्चवर्षीय योजनाओं में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और यह सर्वथा उचित भी था, क्योंकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि के महत्व की कल्पना नहीं की जा सकती थी।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में कृषि

भारत में आर्थिक नियोजन की गणना के लिए कृषि विकास अत्यन्त आवश्यक है। योजना आयोग के सदस्यों में, "देश के निर्वाचित आर्थिक विज्ञान के किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिये कृषि पुनर्गठन एवं सुधार आधारभूत महत्त्व का है। यद्यपि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विविध अंग एक दूसरे में काफी सम्बन्धित हैं तथा उन्हें भी योजना अधिकारियों द्वारा समन्वित रूप से चलाया जाना चाहिए, तथापि सम्पूर्ण योजना उसी समय सफल हो सकेगी, जब कृषि में लगी हुई धन, शक्ति एवं भूमि का अधिकतम लाभदायक उपयोग हो। इस अर्थ में कृषि का महत्व आधारभूत एवं बड़ा व्यापक है।"¹

¹ "In any scheme of planned economic development of the country agricultural reorganisation and reform hold position of basic importance....While the

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बड़ी तथा गम्भीर सिंचाई की योजनाओं द्वारा कुल 63 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हुईं। छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा इसी अवधि में कुल 100 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई। प्रथम योजनावधि में खाद तथा उर्वरक के उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई। अमोनियम सल्फेट की कुल खपत 2 लाख 75 हजार टन से बढ़कर 6 लाख टन हो गई। फास्फोरम खादों की खपत 43,000 टन से बढ़ कर 78,000 टन हो गई। योजनावधि में केन्द्रीय ट्रैक्टर मण (Central Tractor Organisation) द्वारा लगभग 12 लाख एकड़ भूमि का उद्धार (Reclamation) किया गया, राज्यों के अपने ट्रैक्टर मणों के द्वारा लगभग 28 लाख एकड़ भूमि का उद्धार किया गया। भूमि सुधार कार्यों के लिए किसानों की अनुदान एवं ऋण प्रदान किए गए, फलस्वरूप लगभग 10 लाख एकड़ भूमि वा उद्धार हुआ। देश के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की गई। किसानों को उन्नत बीज प्राप्त हो सकें। इस योजनावधि में जापकी तरीके से धान की खेती पर जोर दिया गया। सामुदायिक विकास योजनाओं (Community Development Projects) एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं (National Extensive Service) के अन्तर्गत लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को लाभ प्राप्त हुए। प्रथम योजना काल में कृषि विकास सम्बन्धी विविध प्रयत्नों के फलस्वरूप कृषि पदार्थों के उत्पादन में 17 प्रतिशत तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 120 लाख टन की वृद्धि हुई। प्रथम योजनाकाल में कुछ वस्तुओं के उत्पादन में निर्धारित लक्ष्यों से अचिर वृद्धि हुई, जबकि कुछ वस्तुओं के उत्पादन में लक्ष्य भी पूरे नहीं किए जा सके, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है

फलस	1950-51 में उत्पादन	1955-56 में उत्पादन-लक्ष्य	1955-56 में वास्तविक उत्पादन	वास्तविक वृद्धि लक्ष्य के आधार पर
खाद्यान्न (लाख टन में)	540	616	638	+ 42
निराहार (लाख टन में)	51	55	56	+ 1
गन्ना (गुड़) (लाख टन में)	56	63	60	- 3
ज्वार (लाख धान्ने में)	29	42	40	- 2
जूट (लाख टन में)	33	54	42	- 12

पिछले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम योजनावधि में उत्पादन में लक्ष्य से काफी अधिका वृद्धि हुई। निरुद्ध व कपास के उत्पादन में भी लक्ष्य लगभग पूरे हो गये, लेकिन गन्ने व जूट के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि नहीं हुई तथा उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के निर्योजित विकास की दिशा में भारत में पहली बार प्रयत्न किया गया था जब कुछ ऋतियों का रह जाना स्वाभाविक था। प्रथम योजना में कृषि विषयक कार्यक्रम का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण शेष यह था कि योजना बनाते समय देश में कृषि साख सम्बन्धी कोई व्यापक योजना नहीं बनाई गई। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम का दूसरा शेष यह था कि योजना में सहकारी कृषि पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया था। योजना कृषि आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सहकारी ग्राम व्यवस्था को कृषि तथा ग्रामीण संगठन के क्षेत्र में अन्तिम प्राथमिकता के रूप में अपनाया था, परन्तु योजनावधि में सहकारी खेती की आशानोत सफलता प्राप्त नहीं हुई। सहकारी कृषि आन्दोलन की असफलता का मुख्य कारण यह था कि सरकार के पास उस समय भूमि-सुधार की कोई विस्तृत योजना नहीं थी। प्रथम योजनाकाल में भूमि के उप विभाजन एवं अधखाने की दुरावस्था को दूर करने के लिए काई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये, फलस्वरूप कृषि की औसत जोत प्रायः अन्यायिक हो गयी रही।

उपयुक्त दोषों के बावजूद भी कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसके लिये कुछ सीमा तक प्रकृति के सहयोग की भी श्रेय दिया जा सकता है। योजनाकाल में कृषि में सत्यावस्य परिरक्षण नहीं किया जा सके, जो कृषि के स्वाधीन विज्ञान के लिये आवश्यक था और जिनके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में सम्भवतः आश्चर्यजनक वृद्धि हुई होती।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि—भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग प्रधान योजना थी। इस योजना में कृषि को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया। योजना आयोग का विचार था कि चूंकि प्रथम योजना में कृषि को काफी संतुष्ट बनाया जा चुका है, अतः देश के संतुलित विकास को दृष्टि में रखते हुए उद्योगों की इस योजना में प्राथमिकता देना आवश्यक था। द्वितीय योजना में कुल 4,800 करोड़ रुपये व्यय किया जाना था, जिनमें से 1,034 करोड़ रुपये कृषि विकास के लिए प्रस्तावित किये गये थे। इस प्रकार बड़ा प्रथम योजना में कृषि कार्यक्रमों पर 31 प्रतिशत व्यय का प्रावधान था बड़ा दूसरी योजना में यह प्रतिशत घट कर 20 प्रतिशत ही रह गया। द्वितीय योजना में कृषि विकास पर वस्तुतः 930 करोड़ रुपये ही व्यय किए जा सके। इससे से 530 करोड़ रुपये कृषि तथा सामुदायिक विकास पर खर्च किए

गए तथा जेय 420 करोड रुपए सिंचाई की बढी व छोटी योजनाओं पर खर्च किए गये। द्वितीय योजना मे कृषि, पशुपालन, वन व भूमि मरलण, मत्स्य उद्योग, सहकारिता व विविध कृषि कार्यक्रमों मे खर्च 170, 56, 47, 12, 47 व 9 करोड रुपए व्यय किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना मे इसी मदों पर क्रमश 197, 22, 10, 4, 7, व 1 करोड रुपये का व्यय किया गया था। इस प्रकार यद्यपि द्वितीय योजना मे प्रथम योजना की तुलना मे कृषि को कम महत्व दिया गया, तथापि द्वितीय योजना मे कृषि पर कुल व्यय आर्थिक दृष्ट से अधिक था। द्वितीय योजना मे कृषि कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय निम्न तालिका मे दिखलाये गये है। (करोड रुपये)

मद	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
योजना प० कुल व्यय	4800	4600	100
कृषि तथा सामुदायिक विकास	568	530	11
सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण	416	420	9
कृषि पर कुल व्यय	1054	951	20

द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे कृषि सम्बन्धी प्रमुख तत्व थे (i) भूमि के प्रयोग का नियोजन, (ii) अल्प-कालीन व दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण, (iii) विकास कार्यक्रमों और सरकारी सहायता मे समायाजन, तथा (iv) एक उचित मूल्य नीति। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे कृषि उत्पादन मे जो प्रगति हुई, वह निम्नांकित तालिका मे दी गई है।

कमरे	1955-56 मे उत्पादन	1960-61 मे उत्पादन का लक्ष्य	1961-61 मे वास्तविक उत्पादन	वास्तविक वृद्धि लक्ष्यो के आधार पर
आद्यायन (लाख टन)	658	805	797	-8
तिलहन (लाख टन)	56	76	65	-11
गन्ना शुद्ध, (लाख टन)	60	78	104	+ 26
कपास (लाख गॉल)	40	60	54	-11
पटसन (लाख गॉल)	42	55	40	-15

पिछले पृष्ठ पर दी गई नीचे की तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि गन्ने के उत्पादन को छोड़ कर, अन्य कृषि वस्तुओं के लक्ष्य नहीं प्राप्त किये जा सके। इसके लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियाँ काफी हद तक जिम्मेदार थी। यह भी आरोप लगाया जाता है कि राज्य सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र में आवश्यक विनियोग न किए जाने से भी कृषि-विपयक लक्ष्य नहीं प्राप्त किए जा सके। योजना आयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के महत्व से परिचित था, लेकिन फिर भी इसकी यह धारणा गलत साबित हुई कि कृषि पर अपेक्षाकृत कम व्यय करने पर भी कृषि उत्पादन पर बुरा असर न पड़ेगा और कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता ही रहेगा।

द्वितीय योजना काल में सिंचाई सम्बन्धी लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए जा सके। सन् 1955-56 ई० में कुल 562 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। लक्ष्य यह था कि द्वितीय योजना के अन्त तक 850 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। किन्तु द्वितीय योजना के अन्त में लगभग 700 लाख एकड़ भूमि में ही सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकी। भू-संरक्षण सम्बन्धी कार्य भी आशातीत प्रगति न कर सके। वर्षों के प्रयोग में, योजना के अन्तिम वर्ष को छोड़ कर, पृष्ठ नहीं की जा सकी। संक्षेप में द्वितीय योजना की अवधि में कृषि उत्पादन में मन्तोपजनक प्रगति न हो सकी और यह योजना कुछ हद तक इस दिशा में असफल रही।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि—तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने पुनः कृषि विकास को पर्याप्त महत्व दिया। योजना आयोग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 'तृतीय योजना की सफलता मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है। योजना आयोग के अनुसार ही, तृतीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। वास्तव में द्वितीय योजना ने इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि कृषि के उत्पादन में कमी आर्थिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, जिसे किसी भी तरह दूर करना आवश्यक है।' इसलिए कृषि उत्पादन को यथा सम्भव अधिकतम करना होगा और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तृतीय योजना में पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने होंगे। तृतीय योजना में ग्राम-अर्थ-व्यवस्था के विकास के कार्यक्रम तैयार करते तथा क्रियान्वित करते समय मार्गदर्शक सिद्धान्त यह होना चाहिए कि 'जो कुछ भी भौतिक रूप से व्यवहार्य है, उसे द्वितीय रूप से व्यवहार्य बनाया जाय और इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश की क्षमता का विकास अधिकतम संभव सीमा तक करना होगा।

नवीन कृषि नीति

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास कार्यक्रमों पर कुल 1281 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है :—¹

कृषि उत्पादन पर व्यय व्यवस्था

(करोड़ रु०)

वर्ग	व्यय की जाने वाली धनराशि	वास्तविक व्यय
कृषि उत्पादन	226 07	1760
छोटी सिंचाई योजनाएँ	176 76	
भूमि संरक्षण	72 73	
सहकारिता	80 10	
सामुदायिक विधान	126 00	
बड़ी और माध्यम सिंचाई योजनाएँ	599 34	
कुल व्यय	1261 00	1760

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि, मधु सिंचाई योजनाओं एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर 1103 करोड़ रुपए व्यय किये गये। मध्यम तथा बड़े बाजार की सिंचाई योजनाओं पर तृतीय योजनावर्ष में 657 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस प्रकार तृतीय योजना काल में कृषि कार्यक्रमों पर कुल 1760 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। जो दश योजना के कुल प्रत्यासित व्यय का 22 प्रतिशत भाग था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के सदस्यों की प्राप्ति के लिए सिंचाई, भू संरक्षण, भूमि उद्धार, शुष्क खेती, अच्छे एवं सुधरे यन्त्रों के प्रयोग तथा खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग पर पर्याप्त जोर दिया गया। गौ-गो के संरक्षण, बीजों के उत्पादन एवं वितरण तथा वैज्ञानिक क्रियाओं के प्रयोग के कार्यक्रमों को अपनाया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन की निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।¹

फलक	1961-66 ई० में उत्पादन का लक्ष्य	1961-66 में वास्तविक उत्पादन
छाद्यान् (लाख टन में)	1000	723.0
तिरहन (लाख टन में)	100	61.4
गन्ना, गुट (लाख टन में)	102	121.0
बजान (लाख गाँठें)	70	48.0
जूट (लाख गाँठें)	62	45.0
सम्बाहू (हजार टन)	325	400.0
चाय (हजार टन)	408	373.0

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के क्षेत्र में बड़ी विरागा हुई। गन्ने व जूट के लक्ष्यों को छाड़ कर अन्य फसलों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। वर्षों की अमिनिश्चिता और सूख की स्थिति ने खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उद्योगों के लिए कच्चे माल के उत्पादन को घटका पहुँचाया। इस योजनावधि में कृषि क्षेत्र में वांछित सस्यागत परिवर्तन नहीं किया जा सके और वही खेतों के उच्च विभाजन व अपखण्डन के क्षायों का दूर किया जा सका। कृषि सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों को भी पुरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। इस योजना की अवधि में ही चीन व पाकिस्तान के हमल न भी कृषि विकास के मार्ग में बाधा पहुँचाई।

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति बग़ाय सुभरने के विगड़ती चली गई। सन 1961-62 में कुल जाद्यान्न उत्पादन 81 करोड़ टन परन्तु यह घट कर सन 1962-63 व 1963-64 ई० में क्रमशः 78 व 79 करोड़ टन ही रह गया। मई 1964-65 व 1965-66 ई० में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 89 व 90 करोड़ टन ही रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय योजना के कृषि उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य पूरे नहीं हो सके।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में देश के 15 छोटे एवं बड़े जिलों में मध्य कृषि कार्यक्रम को भी चालू किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य में से एक जिला चुना गया, जिनमें सिंचाई की वसाएँ अनुकूल थी, वर्षा निश्चित रूप से होती थी तथा जहाँ सहकारी आन्दोलन दृढ़ आधार पर स्थापित हो चुका था। इन नए

कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों एवं सहकारी समितियों द्वारा सभी किसानों को उर्वरक, उन्नत बीज तथा तकनीकी सहायता आदि देकर कृषि के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न किया गया। कृषि कार्यक्रमों पर पर्याप्त जोर देने के बावजूद भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में सतोषजनक प्रगति न हो सकी। खाद्यान्नों की उपलब्ध कम हो जाने के कारण इनके मूल्यों में वृद्धि हुई। खाद्यान्नों के मूल्य में जो बढ़ि तृतीय योजना काल में प्रारम्भ हुई, वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई और आज भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

सन् 1966-67, 1967-68 व 1968-69 की वार्षिक योजनाओं में कृषि कार्यक्रमों पर क्रमशः 287, 321 व 304 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस अवधि के दौरान सामुदायिक एवं मिर्चाई के अन्तर्गत क्रमशः 170, 167 व 166 करोड़ रुपये और खर्च किए गए। इन वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन क्रमशः 74 2, 95 6 तथा 98 मिलियन टन हुआ।

चतुर्थ योजना (1969-74) में कृषि के लिए सरकारी क्षेत्र में 3817 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में 1800 करोड़ रु० के विविवोधन का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन, लघु मिर्चाई, मूल संरक्षण, वित्तीय सहायता, सहकारिता, सामूहिक विज्ञान एवं पचासों पर क्रमशः 510, 476, 151, 263, 151 तथा 116 करोड़ रु० व्ययकिये जायेंगे। सन् 1974 में अर्थात् चतुर्थ योजना में अन्त में खाद्यान्न उत्पादन के 12 90 मिलियन टन तक पहुँच जाने की आशा है। योजना आयोग ने चतुर्थ योजना में कृषि नीति के अन्तर्गत दो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए हैं, प्रथम, आगामी वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना तथा द्वितीय छोटे किसानों तथा धुष्क क्षेत्र के किसानों सहित अधिक से अधिक ग्राही जनता की दृग योग्य बनाना व के विकास कार्यक्रमों में भाग ले सकें तथा इससे लाभ उठा सकें।

चतुर्थ योजना में कृषि उपज के निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए

फलक	अनुमानित लक्ष्य
1 खाद्यान्न (दस लाख बी० टन)	129 0
2 तिलहन (" ")	10.5
3 गन्ना-गुह (" ")	15 0
4 पचास (दस लाख गांठे)	8 0
5 जूट (" ")	7 4

उपयुक्त विवेचन के अन्तर्गत हमने यह देखा है कि भारतवर्ष में कृषि उपज अथवा खाद्यान्न उत्पादन में, आयोजन काल के अन्तर्गत बड़े उतार-चढ़ाव हुए हैं। भारत जैसे प्रकृति पर निर्भर रहने वाले देशों में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जब तक देश की प्रगति पर निर्भरता समाप्त या कम नहीं कर दी जाती, तब तक सम्भवतः कृषि उद्योग की दृढ़ बस्तिरक्षा से मुक्ति नहीं मिल सकती। नियोजन काल के दौरान भारत में होने वाले खाद्यान्न उत्पादन को आगे की मारणी में दिशाया गया है।

नियोजन-काल में खाद्यान्न-उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)	वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)
1951-52	55	1960-61	82
1952-53	61	1961-62	82
1953-54	72	1962-63	80
1954-55	70	1963-64	81
1955-56	69	1964-65	88
1956-57	72	1965-66	72
1957-58	66	1966-67	74
1958-59	78	1967-68	95
1959-60	76	1968-69	94
		1970-71	108
		1971-72	112

कृषि विकास सम्बन्धी सरकार की नई नीति की प्रस्तावना—भारतवर्ष में कृषि की बिना अब तक सतोषजनक नहीं रही है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि हमारे देश में इस समस्या को मुलताने के लिए न तो सामूहिक प्रयत्न किये गये और न ही कृषि को परम्परागत तरीकों से छुड़ाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किया गया। श्री परेसनाथ बटर्ज के शब्दों में, “दरअसल भारतीय कृषि की स्थिति में अभी तक सुधार न होने के कारण यह है कि परम्परागत कृषि-पद्धति से छुटकारा पाने के लिए बृहद स्तर पर सभी राज्यों द्वारा एकाग्रचित होकर पूरी तरह से कदम नहीं उठाये गये। अन्वयार्थ की भाव तो यह है कि भारतीय कृषि के बारे में अभी तक लोग यह नहीं जानते कि इन क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है। कृषि सम्बन्धी जाँचों में भी कई कमियाँ रह गई हैं, जिनके कारण सरकारी दौड़ों में भी अक्षयकाण व्यक्त की जाने लगी है। खेती के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के भौतिक

पहलू या लक्ष्य मान लेती की आधारभूत कठिनाइयों या कमियों पर काबू पाने के लिए काफी नहीं है।¹ अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुछ व्यावहारिक कदम उठाये जायेंगे और कृषि विकास के लिए नई नीति अपनाई जायेगी। चौथी योजना की प्रस्तावित स्फुरेखा में कहा गया है, “यदि हमें अपने खान्दानों के आयात पर निर्भरता समाप्त करनी है, तो उत्पादन की आधुनिक विधियों का अधिकार अधिक प्रयोग करना तथा कृषि विकास द्वारा प्रदत्त ज्ञान एवं सुविधायों का उपयोग करना आवश्यक है। यदि हम अल्पकाल में ही परिणाम हासिल करना चाहते हैं तो कृषि विकास के लिए नई नीति (Strategy) अपनानी होगी।”²

कृषि-विकास की वर्तमान व्यूह रचना—(Present Strategy of Agricultural Development) : कृषि विकास की वर्तमान व्यूह रचना (Strategy) के अन्तर्गत कृषि विकास के क्षेत्र में जिन मुख्य कार्यक्रमों को अपनाया गया है, वे निम्न-लिखित हैं

1. **सिंचाई सम्बन्धी नया दृष्टिकोण—**सरकार द्वारा स्वीकृत मूल सिद्धान्तों में सिंचाई व्यवस्था के बारे में प्रमुख परिवर्तन हुआ है। अभी तक सिंचाई व्यवस्था मुख्यतः अनावृष्टि के दिनों में नुकसान से बचने का एक साधन माना जाता था, लेकिन अब इस सिद्धान्त के आधार पर दूसरा सिद्धान्त अपनाया गया है। इसके अनुसार सिंचाई व्यवस्था की कृषि-उत्पन्न बढ़ाने का एक प्रमुख साधन माना गया है। इस सम्बन्ध में दूसरी प्रमुख बात यह है कि सभी दोषों पर समान रूप से ध्यान न देकर, कुछ चुने हुये क्षेत्रों में, जहाँ सुविधाएँ उपलब्ध हों, विशेष ध्यान दिया जायेगा। अब यह अनुभव लिया आ रहा है कि छोटी सिंचाई की योजनाओं पर एक

1. “Indeed one of the reasons of the poor state of the Indian agriculture has been the inconsistency of concerted attention and action on a mass scale to cause a break away from tradition. Curiously, Indian agriculture has all along remained a dark continent, nobody knowing exactly what has really happened. Agricultural statisticians have been fraught with a number of weaknesses on which doctores have been expressed even in official circles. ‘Systematic exercises in targetry in the physical aspects of achievements have not been able to transcend the home difficulties and inaccuracies’” —Kishna Chatterjee, *Approach to Agriculture in the Fourth Five Year Plan* AICC Economic Review, Aug. 1961

2. “If our dependence on imported foodgrains has to cease, it is necessary to make far greater use of modern methods of production and to bridge the gap between demand and production by the application of the latest advances in the science and agriculture. A new strategy or approach is needed if we are to achieve results over a short span of time.” —Fourth Five Year Plan: A Draft Outline, p. 175

और तो कम पैसा खर्च होता है और दूसरी ओर ये योजनाएँ शीघ्र फल देने वाली होती हैं, अतः अब इनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दण्डो-अमेरिकन सहायता कार्यक्रम के अधीन स्पिल ओवर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट्स (Spill Over Tube-well Projects) आरम्भ किये गये हैं। देश के विभिन्न भागों में भूजल को खोदा जा रहा है। जमीन के भीतर के पानी का पता लगाने के लिए Ground Water Exploration Projects चलाये जा रहे हैं। इस प्रकार वर्षा और नहरी सिंचाई के अभाव को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि जल साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके तथा प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जा सके। 1966-67 और 1967-68 के दो वर्षों में लगभग 28 लाख हेक्टर भूमि को छोटी सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया है और 1968-69 में 14 लाख हेक्टर भूमि को छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाना था।¹

2 उन्नत बीजों के प्रयोग पर बल—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुछ नए प्रकार के बीजों को प्राप्त किया गया था, जिन्हें अब उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। उन्नत किस्म के चावल बीज 1970-71 तक 51 लाख हेक्टर भूमि में प्रयुक्त किए जाने की सम्भावना थी। चावल के उन्नत बीज काग में लाने से प्रति हेक्टर 3363 से 6720 किलोग्राम उपज हुई है। बैंगूर तथा केरल प्रान्तों में ताइपु क न 360 तथा चापमान न 3 के बीज से प्रति हेक्टर 5484 किलोग्राम से 6725 किलोग्राम चावल पैदा हुआ है। इसी प्रकार पटन के एबीटी 27 नम्बर के बीज से प्रति हेक्टर 4484 किलोग्राम से 5650 किलोग्राम तक उपज हुई। यहाँ तक कि सूताग्रस्त क्षेत्रों में उन्नत किस्म के बीजों से 707 लाख हेक्टर भूमि पर खरीफ की फसल के लिए खेती की जा रही है और बची हुई भूमि पर रबी की फसल लगाई जा रही है तथा इस सम्बन्ध क्षेत्र में उन्नत बीज काम में लाने की व्यवस्था कर दी गई है। राज्यों में बीज निगम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि बीजों के उत्पादन, प्रभावीकरण और वितरण में समन्वय स्थापित हो सके। सरकारी भाँडारी व सहकारी समितियों के माध्यम से बीजों का वितरण किया जा रहा है। जेके राज्यो में 'बीज बहुमुखन फार्म' बनाए गए हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की भी स्थापना की गई है।

3 कीट नशक औषधियों के प्रयोग पर बल—भारत में कृषि फसलों की कीट महोदों से विशेष हानि होती है। नई कृषि योजना में सरकार कीटनाशक

1 भी जला सहाय्य की विन्द, मु० राष्ट्रीय राज्य पन्नी खास एव कृषि कृषि विभाग योजना न० नया धरण अर्थिक नमोना 26 जनवरी, 1969.

औषधियों और पौधों की रक्षा के उपकरण तैयार करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है तथा औषधियों के वितरण करने की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। देश में पौध सुरक्षण निर्देशावली के अन्तर्गत 14 केन्द्रीय पौध सुरक्षण केन्द्रों द्वारा फसलों के कीड़ों, रोगों आदि का निबन्धन करने के लिए परामर्श दिया जाता है तथा कीड़ों के विनाश सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों को कीटाणु नाशक औषधियों और पौध सुरक्षण से काम आने वाले यन्त्र दिए गए हैं। निर्देशावली के विमान फसलों पर कीटाणुनाशक औषधियाँ छिड़कते हैं तथा टिहड़ो दलों के आक्रमण से फसलों की रक्षा करते हैं। सन् 1965-66 में 1 करोड़ 65 लाख हेक्टर भूमि को पौध सुरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुँचाया गया था। सन् 1967-68 में इन कार्यक्रमों से 3 करोड़ 64 लाख हेक्टर भूमि को लाभ पहुँचा। सन् 1968-69 ई० में पौध सुरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 5 करोड़ 46 लाख हेक्टर भूमि लाभ का कार्यक्रम अस्थापित किया गया।¹ कीटाणुनाशक औषधियों और पौध सुरक्षण उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने का आदेशान भी सरकार द्वारा दिया गया है।

4. **उर्वरकों के प्रयोग पर ध्यान**—भारत में खेती के खेतों से प्रतिवर्ष 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपये की बर्बादी हो रही है। खाद की बर्बादी को रोकने के लिए तथा उर्वरकों के उत्पादन व प्रयोग की वृद्धि करने के लिए सर्व कृषि नीति में ध्यान दिया गया है। देश में उर्वरक उद्योग का प्रोत्साहित किया जा रहा है। रासायनिक खाद के मामले में स्वावलम्बी होने में अभी कई वर्ष लग सकते हैं। रासायनिक खाद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की है। विन लैन्ड को दल पदार्थों की सर्वाधिक आवश्यकता है, वहाँ रासायनिक खाद पदार्थ मितरित किए जा रहे हैं। अभी भारत में उर्वरकों के उत्पादन की योजनाएँ चालू हैं। मल-मूत्र युक्त पानी के उपयोग की योजनाएँ भी विभिन्न नगरों और कस्बों में चल रही हैं। सम्पादित खाद तथा नाइट्रोबायल कम्पोस्टिंग की वृद्धि की जा रही है। मृद्ध्य की साद को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा निम्नो के मध्य हरी खाद के बीजों का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कई विधियों के तहत वर निबन्धन दिया जा रहा है तथा इनके निर्वर्त पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस समय देश में मिट्टी, नागल, दुग्ध, हरकेला तथा अरज्या (केरल) में रासायनिक खाद का उत्पादन हो रहा है तथा कोटा व गोरखपुर में भी हाज हो में कार्य प्रारम्भ किया गया है।

उर्वरकों के और नए कारखाने स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। भारत में प्रति हेक्टर कृषि भूमि 2.33 किलोग्राम रासायनिक खाद की खपत है, जबकि विश्व का औसत 22.19 किलोग्राम है। अतः उर्वरकों के उत्पादन की वृद्धि के लिए निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। 1965-66 में भारतवर्ष में उर्वरकों का उत्पादन 7.8 लाख टन था, जो 1967-68 में 16.84 लाख टन हो गया। 1968-69 के उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य 28 लाख टन रखा गया था।⁴

5 कृषि यंत्रों के प्रयोग पर बल—लघुयुग 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर अब सभी यह स्वीकार करने लगे हैं कि खेती और उद्योगों का एक-दूसरे में घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए। कृषि का विकास बिना औद्योगिक विकास के सम्भव नहीं है, क्योंकि कृषि यन्त्र तथा आवश्यक माध्यम उद्योगों से प्राप्त होती हैं तथा उद्योगों की कृषि में व्यापारिक फसलों की प्राप्ति होती है। नई कृषि नीति के अन्तर्गत खेती के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। कृषि उद्योग निगम खेती की मशीनों और औजारों के निर्माताओं तथा किसानों के बीच सम्पर्क स्थापित करने का काम करेगा। इसके साथ-साथ यह निगम खेती के औजारों की खरीद, रखे बंसे की व्यवस्था करने तथा मशीनों और उपकरणों की मरम्मत कराने की भी व्यवस्था करेगा। मुख्यतः छोटे किसानों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छोटे किसानों के लाभ के लिए औजारों के छोटे-छोटे कारखाने, ट्रेक्टर मरम्मत करने के केन्द्र, इत्यादि नई कृषि नीति को सफल बनाने के लिए खोले जा रहे हैं। इन गण्य देस में देस के बने हुए ट्रेक्टरों की संख्या 13000 है, जबकि कुल ट्रेक्टरों की संख्या 60000 है। यन्त्रीकरण की दिशा में पहली तीन योजनाओं में पैसे की कमी, ऊँची निर्यात लागत, प्रचार की कमी आदि के कारण कोई विशेष प्रगति नहीं की जा सकी। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए चौथी योजना में 250 चुने गए जिलों में से प्रत्येक में जिला स्तर पर एक कृषि औजारों का केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जहाँ स्वतन्त्र कृषि औजारों का उत्पादन, रखरखाव, मरम्मत एवं प्रचार का कार्य किया जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कम से कम 20 प्रतिशत उपकरणों की स्वतन्त्र कृषि उपकरण, औजार एवं यन्त्र प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6 कृषि विज्ञान को सुदृढ़ बनाने पर बल—कृषि उपज बढ़ाने के लिए कृषि साधन का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार नवीन कृषि नीति के अन्तर्गत किसानों को

आयान चर्चों पर अधिकाधिक धात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न करेगी। चौथी योजनावाचि में सरकारी साध के ढांचे में फसल-ऋण-प्रणाली (Crop Loan System) को अपनाया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुसार ऋण दिलाने का पूरा प्रबन्ध किया जाएगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत सुधार सेने वाले कृषक को भूमि के मूल्य के आधार पर ऋण नहीं दिया जाएगा, बरन् बीज, लाव, औजार व कीटनाशक पदार्थों के रूप में ऋण दिए जायेंगे तथा ऋणों को विपणन से सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया जाएगा। सामान्यतः कृषि ऋण सह-कारिता के माध्यम से दिए जायेंगे, लेकिन जिन भागों में महकारी आन्दोलन अधिक-गित तथा में है, वहाँ कृषि साख निगमों (Agricultural Credit Corporations) को पूरक साधन के रूप में खोला जाएगा। दीर्घकालीन ऋण केन्द्रीय भूमि विकास बैंको द्वारा दिए जायेंगे, जिनके ऋण पत्र रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक व बीमा निगम द्वारा खरीदे जायेंगे। व्यापारिक बैंको का भी कृषि के लिए निस्स दिलाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वह भी इस ध्यान में तथा कृषि कार्यक्रमों को सफल बनाने में आवश्यक योगदान दे।

7 भूमि सुधार एवं भू-संरक्षण पर धन—देश के प्रायः सभी भागों में सघन-धन का सम्पन्न हो चुका है तथा अब भूमि के मालिक प्रायः वे ही लोग हैं जो आन्द में भूमि जोते हैं। पट्टेदारों तथा में सुधार किया गया है। उचित लगान निश्चित करने की दशा में कदम उठाए गए हैं। जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित की जा चुकी है तथा इससे बनी भूमि को भूमिहीन कृषकों में बांट दिया गया है। जोतों को नकबन्दी और उनके टुकड़-टुकड़ होने पर रोक लगा दी गई है तथा सरकारी व महकारी धाम प्रबन्ध के विनाम की प्रोत्साहन दिया गया है। भूमि सुधार के क्षेत्र में अब तब ये अब कार्य रिये जा चुक है। नवी कृषि नीति के अन्तर्गत, चौथी पञ्चवर्षीय योजना में भूमि सुधार कार्यक्रम के दोषों को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। भू-संरक्षण योजना के माधोन भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा देश के विभिन्न भागों में भू-संरक्षण के कार्यक्रमों को तेजी से लागू किया जा रहा है।

8 सहायक साधनों के उत्पादन पर धन—जोसल भारतवासी के भोजन में पोषक तत्वों की बढ़ाने के लिए सहायक अन्न पैदा करने के कार्यक्रम को भी बढ़ाया जायेगा। दल कार्यक्रम के अन्तर्गत आलू, लकुरनन्द, टैपेनो और केले जैसे फल तथा मलरी और दूध की पूर्ति बढ़ाने की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही साथ व्यापारिक फसलों की विविध योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन सब फसलों के उत्पादन के लिए समुचित सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

9 अनुकूल क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता के बढ़ाने पर धन—महान कृषि जिला

कार्यक्रम तथा पैकेज प्रोग्राम—सन् 1959 ई० में भारत सरकार ने फोर्ड फाउण्डेशन (Ford Foundation) के विशेषज्ञों की एक समिति को आमन्त्रित किया, जिसका मुख्य कार्य भारतीय कृषि की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका समाधान करना था। इन विशेषज्ञों ने देश के विभिन्न भागों का विविधत अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट 'India's Food Crisis and Steps to meet it' प्रेषित की। इस समिति ने बताया कि :

(1) यद्यपि देश के कृषि उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, परन्तु प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ सकी है। इसके लिए तकनीकी प्रयोगों को और भी अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(2) लक्ष्यों को अति शीघ्र प्राप्त करने के लिए हमें सभी कृषि उन्नत करने के तरीकों को ऐसी जगहों में काम में लाना चाहिए, जहाँ पर इनसे शीघ्र ही फल प्राप्त होने लगे। खास कर ऐसे स्थान चुने जाय, जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हों और साथ ही फसलों की देवी प्रकोप में रक्षा की जा सके।

फोर्ड फाउण्डेशन की उपर्युक्त सलाह गानते हुए भारत सरकार ने देश के साक्षीस्थान में 59 से 60 प्रतिशत वृद्धि करने के लक्ष्य को ध्यान में रख कर गहन कृषि जिला कार्यक्रम (Intensive Agricultural District Programme) तथा पैकेज कार्यक्रम (Package Programme) सन् 1960-61 से प्रारम्भ किया। यह कार्यक्रम उन जिलों में कार्यान्वित किया गया, जहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी तथा प्राकृतिक प्रकोपों की सम्भावना मध्यम रूप से तथा साथ ही ऋण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी समितियाँ और पंचायतें पूर्ण उन्नत थीं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम सात जिलों को चुना गया। ये थे—तम्रोर (मद्रास), पश्चिमी गोंदावरी (आन्ध्र प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात), रायपुर (मध्य प्रदेश), अलीपट्ट (उत्तर प्रदेश), पार्की (राजस्थान), लुधियाना (पंजाब)। गहन कृषि जिला कार्यक्रमों की सफलता की देख कर इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे नौवें नवम्बर राज्यों में भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रकार इस समय केरल को छोड़ कर यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक राज्य के एक-एक जिले में चल रहा है। केरल राज्य में इस कार्यक्रम को दो जिलों में चालू किया गया है।

इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. इस कार्यक्रम के पूर्व देश में ऋण एवं अन्य कृषिगत आवश्यकताएँ समय पर समुचित रूप में पूरी नहीं होती थीं। लेकिन इस कार्यक्रम में कृषकों की आवश्यकतानुसार सभी सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

2. राजस्वगत लाद, उन्नत बीज, यन्त्र तथा कीटनाशक पदार्थ आवश्यकता-नुसार पूर्ण मात्रा में सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

नवीन कृषि-नीति

3. कृषि उपज की बिक्री से सम्बन्धित सभी दोंषों को दूर किया जाएगा। इन दोषों से सहकारी विपणन की व्यवस्था होगी, जिससे कृषकों को अपनी फसलों का अच्छा मूल्य मिल सके।

4. भ्रष्टार गृहों की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

5. खेती करने के उन्नत ढंग को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा।

6. सम्बन्धित क्षेत्रों में परिवहन के साधनों में सम्बन्धित सुधार एवं विकास किया जाएगा।

7. अधिक उत्पादन के लिए सम्पूर्ण गांव की एक योजना तैयार की जायेगी जिसमें उनके सामाजिक, आर्थिक जीवन को उठाया जाएगा तथा पशुओं के उत्थान पर भी बल दिया जाएगा।

8. प्रत्येक जिले में अच्छे-बुरे दान्यों के निर्माण, बीज-वरीक्षण एवं मृमि-परीक्षण प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की जायेंगी।

9. योजना के पूरी हो जाने पर इस कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता जानने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

10. कार्यक्रम में सभी कार्यक्रमियों का स्थानान्तरण एवं उन्नति उनकी पाँच वर्षों की प्रगति को ध्यान में रख कर ही की जायेगी।

इस प्रकार गहन-कृषि-जिला-कार्यक्रम एक दश-सूत्रीय योजना के रूप में चालू किया गया है। वर्तमान समय में जबकि प्राकृतिक परिस्थितियों तथा विपरीत श्रुतु-वृत्ताओं ने हमें कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में पीछे छोड़ दिया है, गहनता की नीति ही एकमात्र इन समस्याओं से निपटने का उपाय है।

10 गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम—(Intensive Agricultural Area Programme) भारत में 'गहन कृषि जिला कार्यक्रम' को कुछ सीमित क्षेत्रों में ही अपनाया गया है, जिसके कारण इसकी उपयोगिता भी कुछ सीमित क्षेत्रों को ही मिल पायी है। अतः इनके अनुभव के आधार पर पैकेज रोति (Package System) को देश के अन्य सम्भाव्य क्षेत्रों में चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी कृषि-विकास-काम प्रायः उसी प्रकार चलाए जाते हैं, जिस प्रकार गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अन्तर सिर्फ इतना है कि इसके कार्यक्रम छोटे पैमाने पर होते हैं तथा व्यय में भी बचत होती है। इसी कारण गहन कृषि विकास कार्यक्रमों को चालू करता अपेक्षाकृत कम खर्चना है। भारत में ये कार्यक्रम 1960-61 से चालू किये गये थे। इस कार्यक्रम का भी प्रमुख उद्देश्य प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए

किसानों को कुछ उन्नत कृषि-रीतियों को एत रास्य अपनाने को प्रोत्साहित करना है। इस नमोदश के अन्तर्गत 75 जिलों में 646 खण्ड धान के लिए 54 जिलों में 356 खण्ड ज्वार-बाजरे के लिए और 30 जिलों में 200 खण्ड गन्ने के लिए छोटे या थुके हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार ने अपनी नवीन कृषि-नीति में कृषि उत्पादन वृद्धि के विषय में व्यावहारिक एवं सीधे फल देने वाली नीति अपनाई है। 1968 के प्रारम्भ होते-होते अल्पकालिक फसल लगाने, अधिक प्रतिफल देने वाले बीज खेती के क्षेत्र में डालने, छोटी योजनाओं का राष्ट्रीय आधार पर निर्माण करने, रामाग्रनिक खाद जैसे उत्पादन साधनों (inputs) की पूर्ति और उत्पादन के लिए संगठन बनाने, नवीनतम यन्त्र, कीटनाशक औषधियों, खेती के औजारों, सुधरे हुए बीज तथा अन्य की व्यवस्था करने इत्यादि के रूप में, देश में वृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। सरकार की इस नवीन नीति का किसानों ने भाग्यवश स्वागत किया है और ये नीति में प्रस्तावित कार्यक्रमों की उम्मीद से अपनाते लगे हैं। इस प्रकार के बहुमुखी कार्यक्रमों से, देश निश्चय ही कुछ वर्षों में पैदावार बढ़ाने के लिए तैयारी तक पहुँच जायेगा।

नई कृषि नीति की हमीला—भारत में नई कृषि नीति देश के अनुकूल है अथवा नहीं है, इस पर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान तो इसे देश की वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इस नीति की सफलता पर संदेह व्यक्त किया है। जत दोनों प्रकार की विचारधाराओं का विवेचन करना उचित होगा।

नई नीति के समर्थकों का मत—इस नीति के समर्थकों के विचार हैं—

(1) इस नीति की अपेक्षाकर हम उत्पादन में ही 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करके खोपी यादना के अन्त तक खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो पायेंगे।

(2) भारत में जंगल काटने वाले साधनों की पूर्ति नीतिगत है। इसलिए सीमित साधनों की चूने हुए क्षेत्रों में उपयोग करके हम सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

(3) नई नीति में उर्वरकों के प्रयोग पर अधिक जोर दिया गया है, इसके कृषि क्षेत्र में वर्तमान प्रतिफल प्राप्त हो सकेंगे।

(4) इस नीति के अन्तर्गत अपनाए जाने वाले IADP व JALP कार्यक्रमों को धीरे-धीरे व्यापक बनाया जा सकेगा। उन्नति कृषि अवस्था को देखकर देश के

अन्य भागों के लोगों को इसी प्रकार के कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

(5) यह नीति अंतर्व्यवस्था साधनों की उपलब्धता में वृद्धि करने, विदेशी विनिमय को बढ़ाने में मदद देगी, जो अभी साधन आयात करने में चुकानी पड़ती है।

नई नीति के विशेष में सर्व— भारत की नवीन कृषि नीति की आलोचना भी की गई है। प्रमुख आलोचना निम्न बातों को लेकर की जाती है —

(1) डॉ. बी. के. आर. सी. राव का मत है कि नई नीति से क्षेत्रीय असमानताएँ उत्पन्न हो जायेंगी। इससे 6 करोड़ किसान परिवारों में असंतोष फैलेगा।

(2) नई नीति से सम्पन्न कृषक परिवारों में सम्पन्न लोगों को अधिक लाभ पहुँचेगा और वह बात समाजवादी विचारधारा के प्रतिकूल होगी।

(3) श्री आर. एस. सावले (R. S. Savale) का मत है कि नई नीति में सर्वरकों पर विचारों से भी अधिक और दिया गया है, जो उचित नहीं है। कृषि विकास में सिचाई को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक है।

(4) ए. वी. पान्से (V. G. Panse) तथा कुछ अन्य विद्वानों ने सर्वरकों की प्रतिष्ठित मान्यता को अव्यक्त बतलाया है।

(5) कुछ विद्वानों ने नई नीति की इस आधार पर आलोचना की है कि इसमें सूक्ष्म सुधारों पर आवश्यक जोर नहीं दिया गया है।

(6) महान कृषि जिला कार्यक्रम (IADP) के अंतर्गत कृषि उत्पादन में आयातकूल वृद्धि नहीं हुई है। अतः यह कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा, इसके सम्बन्ध में कुछ विद्वान आशंकित नहीं हैं।

(7) डा. पान्से ने विदेशी निर्यात के बीजों की भारतीय परिस्थितियों में बीज पाने की भी आलोचना की है। उनका मत है कि नवीन नीति के अन्तर्गत विदेशी बीजों को सर्वर पर्याप्त प्रयोग एवं अनुभव के बिना स्वतंत्र से सली नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में नवीन कृषि नीति का मिला जुला स्मागल हुआ है। यह सही है कि इस नीति के द्वारा अन्तर्व्यवस्था हमें कृषि उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, लेकिन यह तभी होना जब इस नीति को सोच समझ कर तथा परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए अपनाया जाय। नूतन सरकार कृषि विकास के बारे में व्यावहारिक नदम जठा रही है तथा किसानों में भी

उत्पादन की नई विधि अपनाने में जोर दिया जा रहा है। अतः ऐसी भाषा की जा सकती है कि कृषि विकास की नई ग्यूह रचना निश्चय ही भारतीय कृषि की उन्नति के पथ पर अग्रसर नरेगी।

नवीन कृषि नीति की सफलता के लिए सुझाव व सफलता की शर्तें: भारतवर्ष में कृषि विषयक नवीन नीति उनी समय सफल हो सकती है, जबकि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाय

(1) नवीन कृषि नीति से उनी समय अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है, जबकि उचित प्रकार के रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग उचित मात्रा में तथा उचित समय पर किया जाय। इसलिए यह आवश्यक है कि उर्वरकों के वितरण को यथोचित स्तर पर लाया जाय तथा इनके प्रयोग के सम्बन्ध में किसानों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाय।

(2) भारत जैसे विशाल देश में मिट्टी में विविधता पाई जाती है। इसलिए जो बीज एक प्रकार की मिट्टी में अच्छे परिणाम देता है, वह आवश्यक नहीं है कि अन्य मिट्टियों में भी उन्हीं अच्छे परिणाम प्राप्त हों। अतः कृषि वैज्ञानिकों को मिट्टी का पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा स्वल्प क्षेत्रों के लिए स्वल्प बीजों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिये।

(3) कृषि कार्यों के लिए कुगकों की कम व्याज दर पर उचित मात्रा में उचित समय पर ऋण दिवान की व्यवस्था की जानी चाहिए, अन्यथा कृषक नवीन कृषि नीति का फायदा नहीं उठा पायेंगे।

(4) यदि नवीन कृषि में परम्परावादी कृषि की अपेक्षा अधिक जोखिम है, अतः इसकी सफलता के लिए कृषि मूल्यों की स्थिरता पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि कृषकों को उनकी महत्त्व व विनियोग का उचित पारिधमिक मिल सके।

(5) नवीन कृषि नीति की सफलता के लिए सरकारी विभागों, पञ्चायतों, सहकारी समितियों व अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना जाना चाहिए तथा इन्हें नवीन नीति की सफलता के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिये।

(6) नवीन कृषि नीति को क्रियान्वित करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे केवल कनी कृषक ही लाभान्वित न हों, अन्यथा इससे बाय की असमानता में वृद्धि होगी। प्रगतिशील किन्तु निर्धन किसानों को, जो बहुत कम हैं, को अधिकतम इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिये।

(7) फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए। इस दिशा में कृषि रोग निरोधक उपायों को तथा फसल बीमा योजना को अपनाना चाहिए।

(8) भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो कमियां रह गई हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाना चाहिए। नवीन कृषि नीति की सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करेगी कि कृषकों को खुद काष्ठ सम्पन्धी समस्या शीघ्रातिशीघ्र हल की जाय।

प्रश्न

1 भारत में कृषि के सुधार के लिए यत्न कुछ वर्षों में क्या कदम उठाए गए हैं ? उनके परिणामों की जांच कीजिए।

(राजस्थान वि वि द्वितीय वर्ष टी डी सी 1969)

2 भारतीय अर्ध-सहस्रिका में कृषि के महत्व पर प्रकाश डालिए। विगत पञ्चवर्षीय योजनाओं में कृषि की दशा सुधारने के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख कीजिए।

3 भारतीय कृषि विकास की नवीन ध्येय रचना (New Agricultural Strategy) की समीक्षा कीजिए।

4 "भारतीय कृषि की दशा, पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उठाए गए कदमों के बावजूद भी, शोचनीय ही बनी हुई है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ? भारत में कृषि नीति की सफलता के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

5 भारत में कृषि विकास की नवीन ध्येय रचना के पक्ष व विपक्ष में तर्क देते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

6 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए—

(क) पैकेज कार्यक्रम (Package Programmes)

(ख) गहन कृषि जिला कार्यक्रम (Intensive Agricultural District Programme, IADP)

(ग) सामुदायिक विकास (Community Development)

(राजस्थान वि वि द्वितीय वर्ष टी डी सी बला 1969)

भारत में कृषि-साख

(Agricultural Credit in India)

"The lesson of universal history is that essential of agriculture is credit. Neither the condition of the country, nor the nature of land tenure, nor the position of agriculture affects the one great fact that agriculturists must borrow"

—F. Nicholson

कृषि-क्षेत्र के लिए साख उपलब्ध कराने की व्यवस्था परमावश्यक है। साख की दृष्टि से स्वावलम्बी बन जाने के लिए मन् 1970-71 की अवधि तक देहाती क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकता लगभग 2,400 करोड़ रुपये आंकी गई थी। परन्तु भारतीय किसानों को कृषि-उत्पन्न बढ़ाने के लिए सस्ती एवं समय पर साख उपलब्ध नहीं हो पाती। "आजकल जिस प्रकार कृषि-साख उपलब्ध है, वह उचित मात्रा से कहीं कम है, उचित प्रकार की नहीं है और आवश्यकता की कमोटी के सम्बन्ध में प्रायः सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती।"¹ अतः यह आवश्यक है कि सरकार कृषि-साख समस्या की चुनौती को स्वीकार कर, कृषकों को सस्ती एवं समय पर साख सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करे। ग्रामीण साख सर्वेक्षण (Rural Credit Survey) के विवरण में ठीक ही कहा है, "साख कृषक की उसी प्रकार से सहायता करती है जैसे फासी पर लटकते हुए व्यक्ति को जल्लाद की रस्मी।"²

कृषकों की साख सम्बन्धी आवश्यकताएं अन्य उद्योगों की भांति कृषि उद्योग में सफलता के लिए भी सस्ते एवं पर्याप्त ऋण की आवश्यकता है। भारतीय

1 'To-day the Agricultural credit that is supplied falls short of the right quality, is not of right type does not serve the right purpose and by a restriction of need often fails to go to the right people.'
All India Rural Credit Survey

2 'Credit supports the farmer as the hangman's noose supports the hanged.'
Rural Credit Survey

किसान बहुत ही छोटी जोत पर जीवन निर्वाह के लिए कृषि कार्य करता है। उसकी आय इतनी कम होती है कि वह भूमि पर स्थायी सुधार नहीं कर सकता। वह दिन-प्रतिदिन के कृषि कार्य के ऊपर भी अपने पास से कुछ नहीं लगा सकता। परस्परभूमि भारतीय कृषि में गाँव-अध्वर्या को सुधार के बिना किसी प्रकार की उन्नति की कल्पना करना निराशाजनक होगा। भारतीय किसान के लिए गाँव की उपलब्धि निराला आवश्यक है। कृषकों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में श्री निकल्सन ने लिखा है, "किसानों को चालू खर्चों यथा बीज, खाद आदि का क्रय, पशु, औजार एवं कच्चे माल का क्रय, ऋण चुकाने, नवी भूमि खरीदने, सिंचाई एवं जल-निकासी की व्यवस्था करने, मकान आदि बनवाने, मोजन-मसन खरीदने, मालगुजारी चुकाने विवाह एवं अन्य सामाजिक उत्सवों पर खर्च करने, गहने खरीदने, मुकदमे लड़ने आदि के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है।"

भारतवर्ष में कृषि साध की पूर्ति के लिए कोई संस्थागत रूप नहीं है। ऋण देने के लिए महाजनो अथवा साहूकारों की तो कमी नहीं है, लेकिन उचित व्याज-दर पर समयानुसार सशुद्ध साख की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रो० हैमिल्टन ने ठीक ही कहा है, "यहाँ धावों में बहुत खेतर है, किन्तु यँक एक भी नहीं है।"¹

कृषि साख के प्रकार : यदि खेती से सम्बन्धित आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय तो किसानों को निम्न तीन प्रकार के साख की आवश्यकता पड़ती है

1. अल्पकालीन ऋण - ये 15 माह से कम, अल्प अवधि के लिए, लिये जाते हैं। इनकी आवश्यकता खेती के चालू खर्चों जैसे बीज, खाद आदि को खरीदने फसल-कटाई एवं मजदूरी चुकाने, मालगुजारी देने आदि के लिए पड़ती है। अल्प-कालीन ऋण फसल के बाद चुका दिये जाते हैं या उनके चुकाने जाने की आशा की जाती है। इसे मौसमी ऋण भी कहा जाता है। केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति के अनुमान के अनुसार किसानों की अल्प-कालीन साख की वार्षिक आवश्यकता कम से कम 3 से 4 अरब रुपये तक है। डा० वरजीतसिंह ने 3 से 6 अरब रुपये आका है।

2. मध्यकालीन ऋण - मध्य-कालीन ऋण प्रायः 15 महीनों से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए लिये जाते हैं। इनकी आवश्यकता प्रायः कुओं के निर्माण, पशु व कृषि के यंत्र मोल लेने, छोटे-छोटे कृषि-सुधार करने आदि के लिए पड़ती है।

3. दीर्घकालीन ऋण - ये ऋण प्रायः 5 वर्षों से अधिक के लिए लिये जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता पक्के कुओं, नलकूप लगवाने, तालाबों, बांधों

1. "People have many banks but no bank"

एक पानी सोखने की तालिका बनवाने, ठसर एव पहाड़ी क्षेत्रों की समतल करने जंगलों को साफ करने, नहरें बनाने, भूमि सुधार, बाढ़ लगाने, मछली व भारी मशीनें जैसे ट्रैक्टर खरीदने, आदि के लिए पड़ती है। केन्द्रीय खाद्य समिति के अनुसार किसानों की दीर्घकालीन साख की वार्षिक आवश्यकता वस से कम 2 अरब रुपये है।

भारत में कृषि-साख के साधन रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में कृषि साख के निम्नलिखित साधन हैं —

श्रेण का स्रोत	कुल साख का प्रतिशत (1951-1952)	कुल साख का प्रतिशत (1961-1962)
(अ) राजकीय एव सहकारी साधन		
(1) सरकार	3 3	2 6
(2) सहकारी समितियाँ	3 1	15 5
(3) व्यापारिक बैंक	0 9	0 6
		— 18 7
(भा) व्यक्तिगत साधन		
(1) गवर्नियों से श्रृण	14 2	8 8
(2) जमींदार	1 5	0 6
(3) कृषक महाजन	24 9	36 0
(4) पैसोवर महाजन	44 8	13 2
(5) व्यापारी एव आदतिया	5 5	8 8
(6) अन्य व्यक्ति	1 8	13 9
		— 81 3
कुल योग	100 0	100 0

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय कृषक को अपनी साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उसकी लगभग आधी ऋण-आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। सहकारी समितियों एवं अन्य संस्थाओं का योगदान बहुत कम है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय किसान सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी साधनों से अनुमानित 150 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष ऋण लेता है।

(1) सरकार द्वारा ऋण : भारतवर्ष में राज्य सरकारें कृषकों को अल्प तथा दीर्घ-कालीन, दोनों प्रकार के ऋण देती हैं, जिन्हें तकावी ऋण (Taccavi Loans) कहते हैं। ये ऋण भूमि-सुधार अधिनियम 1883 एवं कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अन्तर्गत दिये जाते हैं। प्रथम अधिनियम के अन्तर्गत किसान को भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए दीर्घकालीन ऋण 20 वर्षों तक के लिए दिये जाते हैं, जिनकी अंशदमी वार्षिक रूप से ब्याज (6 से 6½% ब्याज दर तक) महित होती है। दूसरे अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को उनकी चासू आवश्यकताओं, यथा, बीज, बेल, खाद, हल आदि खरीदने के लिए अल्प-कालीन ऋण दिये जाते हैं। ये बहुत एक या दो वर्षों के लिए दिये जाते हैं और इन पर ब्याज-दर भी कम होती है।

सरकारी ऋणों के दोष—सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की पद्धति दोषपूर्ण है, परन्तु यद्यपि ये ऋण किसानों में लोकप्रिय नहीं हो सके हैं। ये दोष इस प्रकार हैं—(i) इनके देने में बहुत समय लम्बाया जाता है, (ii) ये कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए ही दिये जाते हैं, (iii) इन पर ब्याज दर अपेक्षाकृत अधिक है, (iv) इनको प्राप्त करने में कई वैधानिक कार्यवाहियाँ करनी पड़ती हैं, (v) सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से इनमें से अपना कमीशन काट लेते हैं, (vi) इन ऋणों को वसूल करने में कठोरता धरनी जाती है, तथा (vii) छोटे किसानों को ऋण कठिनाई से प्राप्त होता है।

तकावी ऋणों को उपयोगी बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह इन्हें समय पर दे, इनका प्रचार जनता में करे तथा इन्हें वसूली करने में सक्ती न बरते।

(2) सहकारी साख समितियाँ (Co-operative Credit Societies)

गांवों में सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को साहू-कारों एवं मजदूरों के बगल से छुड़ाना है। यही एक ऐसा साधन है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों के एकाधिकार को समाप्त कर उन्हें उचित ब्याज दर पर ऋण देने के लिए बाध्य कर सकता है। इस समय देश में दो लाख से अधिक कृषि साख समितियाँ हैं, जिनकी सदस्यता दो करोड़ से भी अधिक है। ये समितियाँ ऋण, सम्बन्धी सुविधाओं के साथ-साथ किसानों का मार्गशिक्षण एवं वैयक्तिक उत्थान भी करती हैं। एक अनुमान के अनुसार ये समितियाँ ग्रामीण परिवारों की 15 से 26 प्रतिशत भाग की पूर्ति करती हैं। ये समितियाँ अल्पकालीन, दीर्घकालीन एवं अनुत्पादन-तीनों प्रकार के ऋण देती हैं। इन समितियों को सरकारी सहायता प्राप्त होती रहती है।

सन् 1951-52 में, रिजर्व बैंक के ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के अनुसार सहकारी ऋण समितियाँ किसानों के कुल ऋण का केवल 3 प्रतिशत भाग ही देती थी। अब से सहकारी एजेंसी को सबल बनाने के लिए कई प्रयास किये गये, ताकि

बहु अधिकारिक मात्रा में कृषि ऋण देने में समर्थ हो सके। फलस्वरूप सन् 1961-62 में किसानों के कुल वार्षिक उधार में सहकारी समितियों द्वारा दिये गये ऋण का अनुपात 15.5 प्रतिशत हो गया, अर्थात् उक्त वर्ष इन समितियों ने कुल मिला कर 244 करोड़ रुपये का ऋण दिया। इन समितियों द्वारा दी जाने वाली ऋण की मात्रा में हाल के वर्षों में क्रमिक वृद्धि हुई है। सन् 1967-68 में इन समितियों द्वारा वितरित अल्प एवं मध्य-कालीन ऋणों की राशि 460 करोड़ रुपये थी। इनके अलावा इन समितियों के द्वारा 75 करोड़ रु० दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में दिये गये। सन् 1969-70 में लगभग 540 करोड़ रुपये के ऋण सहकारी समितियों द्वारा अल्प व माध्यम काल के लिए दिए गए। इसी वर्ष, केन्द्रीय भूमि विकास बैंक के माध्यम से 153.3 करोड़ रुपये की दीर्घकालीन साज दिलवाई गई।

सहकारी साज समितियों की कमियाँ सहकारी साज समितियों की असा-भुक्त लोकप्रिय नहीं हो सकी है और आज भी ग्रामीण जनता महाजनो के ऋण से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाई है। सहकारी साज समितियों की असफलता एवं कमियों के सम्बन्ध में सहकारी योजना समिति तथा अन्य कई विद्वानों ने निम्न कारण बताये हैं

(i) सहकारी उदासीनता, (ii) जनता की निरक्षरता, (iii) आन्दोलन का ऋणों के सम्पूर्ण जीवन पर न फैल पाना, (iv) प्रारम्भिक साज समितियों के आकार का छोटा होना, (v) अवैतनिक सेवाओं पर निर्भर होना, (vi) दोषपूर्ण संचालन, (vii) सदस्यों व भण्डारा का अभाव, (viii) समीपित उत्तरदायित्व, (ix) सदस्यों का दोषपूर्ण चुनाव, (x) आन्तरिक मतभेद, (xi) पलायन, तथा (xii) अनियमित भुक्तान इत्यादि।

सहकारी साज समितियों के उक्त दोषों को दूर करके इन समितियों में नये जीवन के संचार करने की आवश्यकता है, तभी ये संस्थाएँ और अधिक लोकप्रिय हो सकेंगी।

3 सहकार III महाजन (Money Lenders) किसानों की साज प्रदान करने वाले स्रोतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत ग्रामीण साहकार या महाजन हैं। अति प्राचीन समय से यह किसानों को ऋण देने वाले हैं और आज भी हमारी कृषि-सम्बन्धी साज का सर्वाधिक भाग इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। साहकार दो प्रकार के होते हैं—(i) पेसेवर एवं (ii) बरे-मेशवर। वे साहकार जो रुपये के लेन-देन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में साज खरीदने व बेचने का व्यवसाय भी करते हैं, पेसेवर साहकार कहलाते हैं। कृषि साज के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर-पेसेवर साहकार में जमींदार या समृद्ध किसान आते हैं, जिनका व्यवसाय रूपी

उधार जना-देना तो नहीं है, परन्तु धन पास होने पर वे धरोहर रख कर रुपया उधार दे देते हैं।

ये दोनों वर्ग मिल कर कृषकों की साक्ष सम्बन्धी 49% आयव्ययताओं की पूति करते हैं। पेशेवर महाजन तो व्यक्तिगत साक्ष पर उपादन या अनुपादन, दोनों ही प्रकार के ऋण, बिना किसी साक्ष लिखा-पढ़ी के गुरान दे देते हैं।

ऋण की साहकारी प्रथा के दोष इन प्रथा में पीरे-पीरे दोष जाने लगे और साहकारी ने स्वायंसेवक ग्रामीण समाज का बोध करना शुरू कर दिया। साहकार प्रथा के कुछ दोष इस प्रकार हैं (i) ऋण देते समय अग्रिम वर्ष तक का व्याज काट लेना, (ii) ऋण देने से पहले 'गिरह खुलाई' अर्थात् बक्षिणा की माँग करना, (iii) कोरे कागज पर किमान से दस्तखत करा लेना या अगुटे का निशान लगा लेना, ताकि नियमित रूप से व्याज न बसूल होने पर मनपानी रकम लिखी जा सके, (iv) व्याज या बसूलन प्राप्ति की रसीद नहीं देना, (v) ऋण सम्बन्धी लिखा-पढ़ी में ऋण से अधिक रकम दर्ज कर लेना, (vi) व्याज की दर बहुत अधिक होना और चक्रवृद्धि दर से व्याज बसूल करना। अखिल भारतीय ग्रामीण साक्ष सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) के ठीक ही कहा है "ऋण देने में उसे जो असुविधा, आलस उठानी पड़ती है, उनको देखते हुए उसके द्वारा की जाने वाली व्याज की दर बहुत अधिक प्रतीत होती है।" (vii) ये महाजन किसानों की अनुत्पादक कार्यों के लिए भी सुगमता से ऋण दे देते हैं, तथा (viii) ऋणों की भूमि या आयदाद का बिक्रीनामा पहले से ही दस्तखत करके रख लेते हैं, ताकि भुगतान न मिलने पर वे उनकी आयदाद हड़प सकें।

साहकारों द्वारा जो जाने वाली मास के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रो० रिट्कवैल्ड ने कहा है, "साहकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मास का प्रगुल दोष यह नहीं है कि व्याज-दर ऊँची होती है अथवा हिनाब-किताब झूठे होते हैं, बरन यह है कि वे अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं और फसल होने पर भी वे अपने ऋण के भुगतान के लिए व्याज नहीं करते। स्वाभाविक उनका उद्देश्य केवल यह होता है कि उनका स्वयं सक्ति प्रकार से विनियोजित होता रहे और वे केवल व्याज पर ही जीवन रहे।"

साहकारों की इसी बोध-प्रवृत्ति की ओर बर्बर्ट बेनिंग जॉन्स समिति ने ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है, "साहकार के लेन-देन का दम इस प्रकार का है कि एक बार उसके फेर में पड़ कर उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है।"

सुझाव कृषि वित्त उप-समिति (ग्रामवित्त समिति) ने ऋण की महाजनो प्रथा के दोषों को दूर करने के अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, यथा—(1) महाजनो

का अनिवार्य पजीवन (रजिस्ट्रेशन), (ii) महाजनो को लाइसेंस देना, (iii) निर्धारित विधि के अनुसार हिमाय-निष्ठाव रखा जाना, (iv) महाजनो के वहीरातो व हिमाय-विताव का समय-समय पर निरीक्षण किया जाय, (v) महाजनो द्वारा ली जाने वाली रियाय की दर सीमित की जाय (vi) अनुचित वस्तुओं का निषेध किया जाय, (vii) प्राप्त किये घन की रसीद देना, तथा (viii) गृह लेने वालो को समय समय पर ड्योरा देना आदि ।

उक्त विचारों व्यावहारिक न होने के कारण क्रियान्वित नहीं की जा सरी हैं । साहूकारी प्रथा के दोष अब भी बने हुये हैं और इसके दुषो किसानों का शोषण हो रहा है । हुपको मे निष्ठा तथा सहकारिता की भावना के प्रसार से ही इस प्रथा से मुक्ति मिल सकती है । बंगाल अकाल आयोग (Bengal Famine Commission) ने साहूकारी प्रथा मे सुधार करने का सुझाव देते हुए कहा था, “अन्तिम महाजन अभी बहुत समय तक बाव मे अण्ड वाटने के काम को मुख्य रूप से करता रहेगा । इन बात को रबीवार कर लेने के आधार पर ही ग्रामीण छात्र के सम्बन्ध मे कोई नीति बनाई जानी चाहिए, साथ ही यह भी स्वीकार करना पडेगा कि इस प्रणाली मे भी सुधार करना पडेगा ।

4 व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) इन बैंको का हुपको से सीधा सम्बन्ध नहीं है । साहूकारी छात्र समितियो तथा सरकारी एजेन्सियो की सहयोग देकर ये बैंक परोक्ष रूप से किसानों को वित्तीय सहायता दे सकते हैं । ये बैंक कृषि-विकास योजना के लिये आर्थिक सहायता देने वाले ‘लैंड गारंटेज्ड बैंको’ के ऋण पत्रो मे रकम लगाते हैं । इसके अलावा ये बैंक उन उद्योगो मे भी रकम लगाते हैं, जो उर्वरक तथा खेती के औजार सबको जरूरतों की पूर्ति करते हैं । परन्तु प्रत्यक्ष रूप से हुपको को नष्ट देने मे ये बैंक पूर्णतः असमर्थ हैं । अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही इस सवध मे कुछ कार्य किया है । अन्य बैंको ने ग्रामीण वित्त मे कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया है । केन्द्रीय बैंकिंग जोइंट समिति ने व्यापारिक बैंको के सम्बन्ध मे ठीक ही कहा था, “जैसे-जैसे व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली हुपको की ओर बढ़ती है, वैसे-वैसे वह धीमी पडने लगती है और हुपको के द्वार पर पहुंच कर तो नितान्त गति-रह्य हो जाती है ।” सन् 1967 ई० मे रिजर्व बैंक ने एक देहाती ऋण ममीक्षा समिति की रचना की थी । इस समिति का मुख्य काम तो ऐसे तौर-तरीको को सुझाना था, जिनके जरिये वर्तमान कृषि ऋण व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया जा सके, ताकि पंचवर्षीय योजना मे बढ़ती हुई कृषि ऋण सम्बन्धी मांग को पूरा किया जा सके । इस समिति मे साक्ष तौर से कहा गया था कि यह कृषि ऋण के सम्बन्ध मे व्यापारिक बैंको के योग-दान की जानकारी । अक्टूबर 1967 मे इस समिति के माध

बैंक बायो की लाभप्रद वातपीत हुई थी। जासा है कि इन विचार-विमर्शों से बैंक वालों को कृषि क्षेत्र के प्रति अपने नये रुख अपनाने में मदद मिलेगी।¹ सन् 1968 ई० में व्यापारिक बैंकों ने कृषकों को अधिक ऋण देने का फैसला किया था। सन् 1969 ई० में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप यह जासा की जाने लगी है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य व्यापारिक बैंक अब किसानों को सीधे ऋण प्रदान करने लगेंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को कृषि के लिए ऋण देने के लिए नई सुविधाएं तथा प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई थी। सन् 1969-70 में व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1300 नए बैंक खोले थे। राष्ट्रीयकरण के बाद से व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। जून 1971 में किसानों के ऋणों की संख्या 8 लाख से भी अधिक हो गई थी। जून 1971 तक व्यापारिक बैंक द्वारा कृषि साख के रूप में 6 अरब 43 करोड़ रुपये के ऋण दिए जा चुके थे।

5 सम्बन्धियों से ऋण (Debts from Relatives) किसानों को अपने सम्बन्धियों से भी ऋण प्राप्त होता है। सन् 1951-52 के ऋण सर्वेक्षण के अनुसार किसानों को अपने सम्बन्धियों से कुल ऋण का 14 प्रतिशत भाग प्राप्त होता था। सन् 1961-62 में यह भाग घट कर 8.8 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार के ऋणों पर सामान्यतः ब्याज नहीं लिया जाता तथा इनकी बसुली की शर्तें भी आसान होती हैं। इस प्रकार के ऋण किसानों को नविभाजनक लगते हैं।

6 भूमि बन्धक बैंकों द्वारा कृषि-साख की व्यवस्था किसानों की दीर्घ-कालीन ऋणों की आवश्यकता भूमि बन्धक बैंकों द्वारा पूरी होती है। ये बैंक किसानों की भूमि का धरोहर में रख कर उन्हें दीर्घ-कालीन ऋण प्रदान करते हैं। भूमि-बन्धक बैंकों से मिलने वाले ऋण की ब्याज की दर कम होती है और उसको काफी समय बाद लौटाया जाता है। इस प्रकार ये ऋण कृषि विकास में बहुत सहायक हो सकते हैं। यद्यपि सत कुछ वर्षों में भूमि-बन्धक बैंकों ने काफी प्रगति की है, तथापि किसानों की गाल-तान्वाची आवश्यकताओं की पूर्ति में उनका योगदान कम रहा है। इन बैंकों द्वारा प्रति वर्ष जो रकमा दीर्घ-कालीन ऋणों के रूप में दिया जाता है, वह संशुद्धा अपर्याप्त होता है। केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों की संख्या 1951-52 में 6 थी जो 1969-70 में बढ़ कर 19 हो गई, जबकि प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या इसी अवधि में 289 से बढ़कर 309 हो गई। इसी अवधि में इनके द्वारा उधार दिए गए ऋणों की मात्रा 3 करोड़ रुपये से बढ़ कर 153 करोड़ रुपये हो गई।

7 कृषि-साख के क्षेत्र में रिजर्व बैंक का योगदान रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से

1. 'कृषि वित्त नागरिक बैंकों के लिए चुनौती,' डॉ० ए० सी० शाह, जयपुर, जुलाई, 1968

सुपको को ऋण नहीं देता, वरन् राज्य सहकारी बैंको के माध्यम से देता है। राज्य सहकारी बैंको से केन्द्रीय सहकारी बैंक को और प्राथमिक सहकारी समितियों को ऋण मिलता है और ये सरसामों अन्तर्गत खास किसानों को ऋण देती हैं। सन् 1950-51 में रिजर्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था, जबकि सन् 1970-71 में ये बढ़कर 420 करोड़ रुपये हो गया। रिजर्व बैंक की राशि का वितरण सहकारी साख्त समितियों के माध्यम से होता है।

प्राचीन साल सर्वेक्षण समिति 1954 के सुझाव पर दीर्घकालीन कृषि-साध की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक ने दो कोषों की स्थापना की :

(क) राष्ट्रीय कृषि साख्त (दीर्घकालीन) कोष [National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund] : यह कोष 3 फरवरी, 1956 को स्थापित किया गया। इस कोष से सरकार ने प्रारम्भ में 10 करोड़ रुपये जमा के रूप में दिये तथा अगले पाँच वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये जमा करने की व्यवस्था थी। इस कोष के उद्देश्य हैं : (i) राज्य सरकार को 20 वर्ष की अवधि के लिए ऋण तथा अग्रिम देना ताकि वे सहकारी समितियों के अन्तर्गत सरोद सँभालें; (ii) राज्य सहकारी बैंको को 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के लिए मध्यकालीन ऋण देना, (iii) केन्द्रीय भूमि-अन्वयक बैंको को अधिक से अधिक 20 वर्षों की अवधि के लिए ऋण देना, तथा (iv) रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय भूमि-अन्वयक बैंको के ऋण-पत्र सरोदना।

30 जून 1971 को इस कोष में 190 करोड़ रुपये जमा थे और इसमें से कुल 66 करोड़ रुपये उधार दिया हुआ था।

(ख) राष्ट्रीय कृषि साख्त (स्थिरीकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] इस कोष को 30 जून, 1956 को स्थापित किया गया था। इस कोष का उपयोग राज्य सहकारी बैंको को मध्यकालीन ऋण तथा अग्रिम देने के लिए किया जाता है। इस कोष में जून 1956 से अगले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक द्वारा जमा किये जाने की व्यवस्था थी। 30 जून 1971 तक इस कोष में 30 करोड़ रुपये जमा थे और इसमें से 5 करोड़ रुपये के ऋण बढ़ाया थे।

रिजर्व बैंक केन्द्रीय भूमि अन्वयक बैंको के ऋण पत्र सरोद कर, कृषि पुनर्बिल निगम के अन्तर्गत सरोद, सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर तथा इन बैंको का निरीक्षण आदि करके कृषि साख्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस प्रकार भारतवर्ष में कृषि-साख्त के क्षेत्र में रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

8 कृषि-साख के क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया का योगदान : स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया की स्थापना सन् 1955 में हुई (इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके)। यह बैंक कृषि-साख के क्षेत्र में निम्न कार्य कर रहा है (i) इसने किसानों में बैंक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित बनाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोली हैं। 30 दिसम्बर सन् 1971 तक इन शाखाओं की संख्या 2477 थी, (ii) यह बैंक सहकारी साख समितियों को कम ब्याज-दर पर अल्पकालीन ऋण देता है, (iii) यह बैंक सहकारी विपणन एवं विपणन समितियों को कृषि-वस्तुओं के विपणन में सहायता देता है, तथा (iv) यह बैंक वस्तुओं के संग्रह के लिये गोदामों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है (v) यह बैंक भूमि-वन्द्यक बैंकों को सहायता देता है।

स्टेट बैंक ने सन् 1969 में छोटे किसानों की साख पूँजी सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक योजना लागू की है, जिसके अन्तर्गत पशु-पालन एवं मुट्ठीर तटोमी के विकास के लिए उपहार दिया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि विकास के लिए मध्यमकालीन ऋण भी दिए जा सकते हैं। लघु कृषक योजना की सफलता के लिए स्टेट बैंक कुछ गोवों को (बासक की भाँति) गोद से लेता है और उनमें रहने वाले सभी मजदूर किसानों को राशि प्रकार के कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देता है।

9 कृषि पुनर्वित्त निगम 8 मार्च 1963 को भारत सरकार ने रिजर्व बैंक की सहायता से कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की है। इसका उद्देश्य कृषि के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना है। यह निगम सहकारी व अन्य कृषि वित्त संस्थाओं को ऋण देकर उनके साधनों को बढ़ाता है। यह निगम 5 करोड़ रुपये की पूँजी से प्रारम्भ किया गया था। 5 करोड़ रुपये इसे केन्द्रीय सरकार ने ध्यान-गुन-ऋण के रूप में दिया था। निगम की अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रुपये है। इसके अध्यक्षों में रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि-वन्द्यक बैंक, जीवन बीमा निगम, अनुसूचित बैंकों के नाम उल्लेखनीय हैं। निगम का प्रबन्ध 9 सदस्यों के एक संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग के डेप्युटी गवर्नर हैं।

यह निगम मुख्यतः कृषि नाश की पुनर्वित्त संस्था है। यह कृषि विकास के नये-नये कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनके लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा भूमि वन्द्यक बैंक से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती। इस निगम द्वारा जिन कार्यों के लिये सहायता दी जाती है वे हैं— (i) भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिये ऋण देना ताकि उपजम्बू सिंचाई सुविधाओं का उपयोग पूरी तरह किया जा सके, (ii) सुपारी, काजू, इलायची, अमूर आदि विशेष प्रकार की फसलों

के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, (iii) यांत्रिक खेती के लिये आवश्यक कृषि-यन्त्र, जैसे ट्रैक्टर-यन्त्र तथा पम्पिंग सेट्स द्वारा बिजली के प्रयोग के लिए आवधिक महायता, तथा (iv) पशुपालन, डेरी फार्मों तथा भुर्रा पालन आदि योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

इस निगम से केन्द्रीय भूमि-व्ययक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित बैंक तथा सहकारी समितियाँ ऋण व अग्रिम के रूप में अधिक से अधिक 25 वर्षों तक के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं । या तो इन संस्थाओं को उचित व पर्माण्व अमानत देने की आवश्यकता पड़ती है अथवा मूलधन व व्याज के भुगतान के लिये सरकार के आश्वासन पर ही ऋण दिया जाता है । 30 जून 1970 की समाप्त होने वाले वर्ष में इस निगम ने काफी प्रगति दिखाई । इस समय तक इन्होंने कुल 59 करोड़ रुपये की राशि वितरित की थी । 1969-70 में इन्होंने 142 योजनाएँ स्वीकृत की थी जिनमें कुल 92.78 रुपये व्यय किए जाने थे । 1969-70 में इन्होंने 28 60 करोड़ रुपये की राशि वितरित की थी ।

10 कृषि वित्त निगम—इसकी स्थापना अप्रैल 1968 में की गई । इसकी अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये तथा परिदृष्ट पूंजी 5 करोड़ रुपये हैं । यह निगम व्यापारिक बैंकों की कृषि शाखा बढ़ाने में सहभाग प्रदान करता है । इस निगम में राज्य विजली बोर्डों, केरल बागान निगम लिमिटेड आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की है । इसकी वित्तीय सहायता के फलस्वरूप ही पम्प सेटों की विपरीत व वृद्धि हुई है । इस निगम ने विभिन्न साधन प्रदान करने वाली संस्थाओं में समन्वय स्थापित करके कृषि वित्त की दिसा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

जनत आभयान से यह स्पष्ट है कि यद्यपि कृषि साधन के क्षेत्र में कई संस्थाएँ अपना योगदान दे रही हैं, तथापि इनके सम्मिलित प्रयासों से वास्तव में ये मुवि-धायें, देश का कृषि क्षेत्र की विशालता की देखते हुए कम हैं । किसानों को पर्माण्व माना में एवं सस्ती व्याज दर पर ऋण की उपलब्धि कराना परमावश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में सहकारी पर प्रतिवन्ध लग जाने के चलनरूप तथा अनोदारी प्रथा के समाप्त हो जाने के कारण, किसानों को इन खेतों से ऋण नहीं प्राप्त हो रहा है और दूसरी ओर कृषि-विकास को प्रोत्साहन देने के कारण इनको साधन सम्पत्ती मार्गें बंद गई हैं । कृषि वित्त की गति वास्तव में अप्रगट मांग है, जो बढ़ती हुई कृषि के साथ बढ़ती जायेगी । अब कृषि साधन के विस्तार के लिये और अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिये । इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं —

1. सहकारी साधन समितियों का विस्तार किया जाता चाहिये, क्योंकि ये समितियाँ कृषि साधन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं । इन

समितियों का प्रमुख दुसरा वर्गकारियों के हाथ में होना चाहिए तथा इन्हें वसूल न होने वाले तथा लगभग बढ़ने वाले ऋणों की सहायता चाहिए। सहकारी साख समितियों तथा सहकारी बिक्री संस्थाओं में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए तथा कृषकों में उपज ऋण (Crop Loans) को बढ़ावा देना चाहिये। किसानों को अपनी उपज सहकारी बिक्री समितियों के माध्यम से ही बेचना चाहिये।

2. तकदीरी ऋण व्यवस्था को सरल बनाना चाहिये। इसके अन्तर्गत अधिक एवं समय पर ऋण मिल जाने चाहिये। यदि ये ऋण भी सहकारी साख समितियों के माध्यम से दिलिये जायें तो इनके दोष दूर हो जायेंगे और सहकारिता को बल मिलेगा। भारत सरकार की अमेरिकी सरकार की तरह प्रत्याभूत ऋण निगम (Guaranteed Credit Corporation) खोलने चाहिये, जो किसानों की ऋण सन्धानों सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

3. रिजर्व बैंक को मध्य एवं दीर्घकालीन ऋणों की अधिकारिक व्यवस्था करनी चाहिये। इसे चाहिये कि वह देश में जो अपने मापीय ले ले। रिजर्व बैंक विभिन्न संस्थाओं से किसानों को दिये जाने वाले ऋणों में समन्वय का कार्य भी कुशलतापूर्वक कर सकती है।

4. व्यापारिक बैंकों को कृषि-साख के क्षेत्र में अधिकारिक सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5. लाइसेन्स-गृहा गोदामों (Licensed Ware Houses) की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिये, ताकि किसान इन गोदामों में अपनी उपज जमानत पर रख कर बैंकों से सस्ती ग्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकें।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में वपत के लिये किसानों को उत्साहित करना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डाकखानों को राब-राब तक पहुँचाना चाहिये तथा सहकारी समितियों का विवास किया जाना चाहिये।

7. भूमि-वर्गाक बैंकों का अधिक विस्तार किया जाना चाहिये तथा इनका व्यापक जाल बिछाना चाहिये। इन्हें कुशल स्टॉक रखना चाहिये। किसानों की समय पर वसूली होनी चाहिए तथा इन्हें भूमि के ऋण एवं सुधार पर और देना चाहिये।

8. महाजनो को साख-सम्बन्धी कार्य करने के लिए लाइसेंस देना चाहिये तथा उचित व्याज लेने के लिए उन्हें सहाय किया जाना चाहिये। रिजर्व बैंक को चाहिये कि वह इन पर प्रभावशाली नियंत्रण रखे, जिससे किसानों का शोषण न हो।

9. कृषि-वित्त के क्षेत्र में सहयोग करने वाली उपाय संस्थाओं को उत्पादक ऋणों पर ही जोर देना चाहिए।

10. सन् 1950 ई० में ग्रामीण ऋण व्याज समिति ने सन् 1954 ई० में ग्रामीण पर्यवेक्षण समिति, सन् 1960 ई० में संकुल लाल समिति तथा अन्य समितियों

में ग्रामीण वित्त व्यवस्था को सुधारने के लिए जो महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक सुझाव दिये हैं, उन्हें धीरे-धीरे अपनाना चाहिए।

11 किसानों द्वारा लिया गया ऋण कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करता है अथवा नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसानों को नकद ऋण न देकर वस्तुओं के रूप में दिया जाय, तो यह कृषि कार्यों में ही व्यय किया जाएगा।

पञ्चवर्षीय योजनाओं में कृषि साख

(Agricultural Credit in the Five Year Plans,

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना इस योजनावधि में सरकार तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा 1955-56 ई० तक 43 करोड़ रुपये का कृषि-साख प्रदान किया गया। इसमें से 30 करोड़ रुपये अल्पकालीन, 11 करोड़ रुपये मध्यकालीन तथा 2 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिए गये।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना सरकार तथा सहकारी समितियों द्वारा इस योजनावधि में कुल 241 करोड़ 80 कृषि साख के रूप में प्रदान किए गए। इसमें 203 करोड़ रुपये अल्प एवं मध्यकालीन साख के रूप में दिए गये तथा शेष 38 करोड़ रुपये दीर्घकालीन साख के रूप में थे।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना इस योजनावधि में सरकार तथा सहकारी समितियों द्वारा कुल 550 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया। इसमें से दीर्घ तथा मध्यम कालीन साख की मात्रा 400 करोड़ रुपये तथा अल्पकालीन साख की मात्रा 150 करोड़ रुपये थी।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना 1969-74 इस योजना के अन्तर्गत सन् 1973-74 तक 1050 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य है, सहकारी संस्थाओं द्वारा बहुप योजना में 700 करोड़ रुपये कृषि साख के लिए दिए जाने का प्रबन्धन है। योजनावधि में भूमि-निष्पात बैंकों का भी पर्याप्त विस्तार किया जायेगा। चौथी योजना में एक मुख्य प्रयत्न यह किया जायेगा कि छोटे किसानों के हित साधन के लिए सहकारी ऋण समितियों और भूमि विकास बैंकों की नीति का और कार्य प्रणालियों में अनु-पूर्ण परिवर्तन किया जाय। इस योजनाकाल में सहकारी बैंकों को प्राथमिक क्षेत्रों में और अधिक आसानी से सहायता दी जायेगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि-क्षेत्र में साख उपलब्ध कराने की समस्या हमारे लिए एक गम्भीर चुनौती बन गई है। "विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो कृषि साख आवश्यक प्रदान की जा रही है, वह ठीक मात्रा से कम है, ठीक प्रकार की नहीं है तथा आवश्यकता की कमी की ओर ध्यान में रखते हुए बहुधा ठीक व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पाती।" अतः कृषि साख के दोषों को दूर कर पर्याप्त मात्रा में, सस्ते

ब्याज पर कृषकों को ऋण दिलाने की व्यवस्था अनिवार्य है। इस क्षेत्र में सहकारी मान्य समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। गोरवाला समिति ने ठीक ही कहा है, "सहकारिता असफल रही है, परन्तु सहकारिता को अवश्य सफल होना है।" समय की मांग है कि ग्रामीण, ऋण उपलब्ध कराने में व्यापारिक बैंक तथा सहकारी साख समितियाँ मिल कर कार्य करें। इस प्रकार इनके सम्मिलित प्रयास से कृषि वित्त की समस्या सफलतापूर्वक सुलझाई जा सकती है।

ग्रामीण ऋण-प्रस्तता की समस्या

(The Problem of Rural Indebtedness)

ग्रामीण ऋण-प्रस्तता के सम्बन्ध में शाही कृषि आयोग का यह कथन सर्वथा सत्य है, "भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में अपना जीवन व्यतीत करता है, ऋण में ही मर जाता है।"¹ ऋण-प्रस्तता किसानों के लिए अभिशाप और देश की कृषि के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। बीमारी बीरस एन्स्टे ने ऋण-प्रस्तता को कृषि के पिछड़े होने का एक महत्वपूर्ण कारण बतलाया है। भारतीय किसानों की ऋण-प्रस्तता को श्री उल्क (Wolff) ने इस प्रकार व्यक्त किया है, "देश महाजन के बगल में फँसा हुआ है, ऋण की खेदियों ने कृषि को जकड़ रखा है।"²

ग्रामीण ऋण की प्रकृति - भारतीय किसानों दो प्रभेद, तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है—दीर्घ-कालीन, मध्य-कालीन एवं अल्प-कालीन। इन ऋणों की प्रकृति दो प्रकार की होती है—

(क) उत्पादक ऋण : उत्पादन कार्यों के लिए लिये जाने वाले ऋण उत्पादक ऋण कहलाते हैं। भूमि-सुधार सम्बन्धी ऋण साद, बीज, पशु, औजार, कुँआ आदि के सम्बन्ध में अर्च करने के लिए लिये जाने वाले ऋण, उत्पादक ऋणों की श्रेणी में आते हैं। भारत में इन ऋणों की माँग अपेक्षाकृत कम रही है।

(ख) अनुत्पादक ऋण - उपभोग या सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के सम्बन्ध में लिये जाने वाले ऋण अनुत्पादक ऋण कहलाते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये शादी-ब्याह या मुकदमेवाली आदि के लिये जा ऋण लिये जाते हैं, वे अनुत्पादक ऋणों की श्रेणी में आते हैं।³

1. "The Indian peasant is born in debt, lives dies in debt and bequeathes debt."

Report of Royal Commission on Agriculture, p. 265.

2. "The country is in the grip of Mahajans. It is the bonds of debt that shackle agriculture."—Wolff

3. ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (गोरवाला समिति) 1951-54.

कृषि-ऋण की सीमा . समय-समय पर अनेक विद्वानों एवं समितियों ने ग्रामीण ऋण-प्रस्तता की सीमा के अनुमान लगाये हैं, जिससे भारत की ग्रामीण ऋण प्रस्तता की मात्रा पर प्रकाश पड़ता है। ये अनुमान इस प्रकार हैं —

वर्ष	अनुमानकर्ता	ऋण की मात्रा (रुपये में)
1912	सर एडवर्ड मैकलमन	300 करोड़
1924	डी एम० एन० डार्लिंग	600 "
1931	केन्द्रीय बैकिंग जाँच समिति	900 "
1935	डा० पी० जे० थॉमस	1,200 "
1935	डा० राधा कृष्ण मुखर्जी	1,200 "
1937	कृषि साख विभाग—रिजर्व बैंक	1,800 "
1951	अ० मा० साख मधेक्षण समिति	750 "
1954	ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति	364 रुपये प्रति परिवार
1962	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	2,789 करोड़ (406 रुपये प्रति परिवार)

उक्त तालिका के अनुमानों से पता चलता है कि द्वितीय विश्व-युद्ध तक ग्रामीण ऋण की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, किन्तु इस युद्ध के कुछ समय बाद तक ग्रामीण ऋणप्रस्तता में कमी आई है। इसका प्रमुख कारण साक्षात्तों एवं अन्य कृषि-उपजों के मूल्य में वृद्धि एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार माना जा सकता है। लेकिन स्थगनशक्ती के बाद वाले दसक में ऋण-प्रस्तता में पुनः वृद्धि हुई है, जैसा कि रिजर्व बैंक की आन्तरिक ऋण एवं विनियोग सर्वेक्षण रिपोर्ट 1965, में पता चलता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जून 1962 में भारत में कुल ग्रामीण ऋण-प्रस्तता की मात्रा 2,789 करोड़ रुपए थी। ऋण-ग्रस्त व्यक्तियों में 75% कृषक थे जिन पर 2,380 करोड़ रुपए का ऋण-भार था। औसत किसान परिवार पर ऋण-भार 406 रुपए था। केवल 1961-62 के वर्ष में ही ग्रामीण जनता द्वारा 1332 करोड़ रुपए ऋण लिए गए, जो कि प्रति परिवार 180 आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के गाँवों में रहने वाले लोग अभी तक समृद्ध नहीं हो सके हैं। ग्रामीण ऋण केवल घुग्ने ही नहीं, चरनजब भी लिए जाते हैं।

ऋणप्रस्तता का कारण . भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं .

1 **कृषक की निर्धनता** राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार प्रति कृषक परिवार की वार्षिक आय 390 रुपए है। आय की इस कमी के कारण किसान गरीब है और उन्हें प्रायः परिवार के भरण-पोषण के लिए ऋण लेना पड़ता है।

निर्धनता के मुकाम से फौरा हुआ भारतीय किसान अपनी क्षुधा शांत करने के लिए साहूकारों एवं किसानों से ऋण लेता है। निर्धनता किसान को ऋण लेने के लिए बाध्य करती है और निर्धनता के कारण ही वह ऋण वापस नहीं कर पाता, जो उस पर बोझ बन जाता है।

2. **मनार्थिक ओलों का बाहुल्य** देश से लगातार उप-विभाजन एवं अप-सृजन के फलस्वरूप कृषि जोतो का रूप मनार्थिक हो गया है। खेती से पर्याप्त आय नहीं प्राप्त होती, जिससे ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। श्री एम. एल. डामिंग ने ठीक ही कहा है, "बिना ऋण लिए कुछ एकड़ भूमि पर किसी परिवार का पालन-पोषण करने के लिए मुश्त, परिश्रम तथा मितव्ययता की आवश्यकता होती है, जो ग्राम गरीब देशों में नहीं पाई जाती। ऋण लिए बिना सुख-दुखर जगता उन्नी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार से कि अटलांटिक महासागर के तूफान को झलना एक नाव के लिए असम्भव होता है। भारत में खेत बहुत छोटे व बिखरे हुए होते हैं और प्रकृति का व्यवहार भूमि पर भी विनाशक हो सकता है, जितना कि समुद्र पर।"¹

3. **कृषि भूमि पर जनान्धार में वृद्धि** भारतवर्ष में प्रति वर्ष जनसंख्या एक करोड़ की वृद्धि से बढ़ रही है। इस बड़ी हुई जनसंख्या से लगभग 70 लाख छोटे ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते हैं इसलिए जनसंख्या का भूमि पर भार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रति व्यक्ति औसत आय कम होती जा रही है चूंकि अपनी आमदनी से उनका काम नहीं चलता, इसलिए बाध्य होकर कृषकों को ऋण लेना पड़ता है। ऋण लेने के साथ-साथ उनकी गरीबी बढ़ती है तथा वे ऋण चुकान में असमर्थ हो जाते हैं।

4. **कृषि की अनिश्चितता** भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में वर्षा न होने पर फसल निगट जाती है और जीवन-मागत के लिए ऋण वा सहारा लेना पड़ता है। इसलिए भारतीय कृषि को गारंटी का जुआ कहा गया है।

5. **प्राकृतिक प्रकोप** बाढ़, सूखा, फसलों के रोग एवं गिद्धी-बलो के आक्रमण के कारण उत्पादन अत्यन्त कम हो जाता है। ये प्रकोप प्रायः धाना करते हैं और प्रकाश के वर्ष किसानों को ऋण जकड़ लेता पड़ता है।

6. **निर्माण की अस्वस्थता** असहजता एवं अयोग्य योजना के कारण किसान प्रायः बीमार रहता है। उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे वह कम उत्पादन कर पाता है। एक ओर बीमारी के कारण उसकी आमदनी कम हो जाती है तथा दूसरी ओर दवा-दान में उसका खर्च बट जाता है। फलस्वरूप उसे ऋण लेना पड़ता है।

7 **वैतक ऋण** : ग्रामीण ऋणों की वृद्धि का एक प्रमुख कारण यह भी है कि वैतक ऋण व्यापकित प्रतिवन्ध के अभाव में पिता से पुत्र को हस्तांतरित होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय वृषक को ऋण विरासत में मिलता है। वह ऋण में ही पैदा होता है, ऋण में ही रहता है और ऋण में ही मरता है। इसे प्रकार ऋण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता है।

8 **वृषकों की असिला** : अयिजित होने के कारण वह महाजन से ऋण लेते समय भगूठा लगा देता है। महाजन मनचाही रकम भरता रहता है और ऋण व्याप्त-मकर ही हो सके पाना है। अयिजता के कारण हो किसान अच्छे दायों में भी मितव्ययता नहीं कर पाते तथा माए दिन अनावश्यक खर्च करके अपने गिर पर अनावश्यक ऋण का बोत साद लेते हैं, जो उन्हें शिद्दी भर टोना पड़ता है।

9 **कृषकों की फिजूलखर्ची** : भारतीय किसान शारी, मृत्यु, आठ आदि सामाजिक व धार्मिक उत्सवों पर पानी की तरह पैसा खर्च करता है, जिससे वह सदैव ऋणग्रस्त रहता है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय किसान अपने ऋण का 40 से 50 प्रतिशत भाग सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों पर व्यय करने के लिए लेता है। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण (1951-52) के अनुसार वृषक के कुल ऋण का लगभग 47 प्रतिशत भाग पारिवारिक खर्चों के लिए तथा शेष शेषों के कार्यों के लिए था। पारिवारिक खर्चों में से 40 प्रतिशत बिबाहों तथा अन्य उत्सवों व मुकदमेबाजी के लिए, 35 प्रतिशत मृत्यु के समय व्यय के लिए, तथा 30 प्रतिशत बीमारी तथा दवाइयों के लिए था।

10 **मुकदमेबाजी की आदत** : किसान बहुत सा धन तो मुकदमेबाजी में ही नष्ट कर देता है। डालिंग के अनुसार, "अपना वह कहा जाता है कि एक एकड़ के एक बहुत छोटे से भूमि तब के लिए, हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ा जाता है तथा पीनसारी के मुकदमों में हमारी म्बवे व्यय कर दिये जाते हैं।" ¹ मुकदमेबाजी के लिए किसानों को ऋण लेना पड़ता है, अतः अत्यधिक मुकदमेबाजी भी ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता का एक कारण है। मुकदमेबाजी के लिए भारतीय न्याय-वृद्धि एवं भूमि-प्रथा भी किसी हद तक उत्तरदायी है।

11 **महाजनों द्वारा शोषण** : महाजन बोले-भाले किसानों की मतमाता लूटते हैं, अत्यधिक व्याज लेते हैं, निष्ठा-पादी में गडबडी करते हैं तथा आपदाओं हथ पालते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक बार उनके चंगुल में फस कर वह निराल नहो पाना, और पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऋणग्रस्त बना रहता है। श्री एन० एन० डालिंग ने महाजनों द्वारा किसानों के इस शोषण का वर्णन करते हुए उक्ति ही कहा है,

"किसान अपने छाग से उसी प्रकार वचन कर दिये जाते हैं, जिस प्रकार कि भेड़ अपने ऊन से वचन कर दी जाती है।"¹

12 पशु-धन की हानि चारे के अभाव एवं बीमारियों की भरमार के कारण पशु-धन का अत्यधिक विनाश हो जाता है। पशुओं के रोग सत्रामक एवं घातक होते हैं। एक मास सेकंदो पशु भर जाते हैं। अतः नये पशु खरीदने के लिए उसे जल सेना पटना है, क्योंकि पशुओं के बिना खेती नहीं की जा सकती।

13 सरकारी भूमि कर-भोर्न श्री रमेशचन्द्र दत्त एवं अन्य अनेक विद्वानों ने ग्रामीण जलप्रदूषण का प्रमुख कारण भूमि-कर की अधिकता बताया है। ये कर प्रायः ऐसे समय पर एवं ऐसी कठोरता से वसूले जाते हैं कि इन्हें चुकाने के लिए किसानों व महाजनो ने ऊँची दरों पर जल लेने पड़ते हैं। मिथार-करों का भी प्रायः यही असर होता है।

14 व्याज की ऊँची दर व्याज की ऊँची दर के कारण एक बार जल लेने के बाद उसे चुकाना कठिन हो जाता है। बम्बई जाय समिति के अनुसार, "यह बात नहीं है कि व्याज बहुत कम जल चुकता है। वास्तव में यह अधिक चुकता है। वे तो ऊँची व्याज की दर तथा महाजन की अनुचित बातें हैं, जो कि किसान की जलप्रदूषण में कमी नहीं होने देते।" भारतीय ग्रामीण साक्ष्य सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) रिपोर्ट के अनुसार साहूकार व महाजनों द्वारा ली जाने वाली व्याज दर कहीं-कहीं, जैसे बिहार व उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल व हिमाचल प्रदेश में 40 प्रतिशत तथा उड़ीसा में 70 प्रतिशत तक पहुँच गई है।

15 दोषपूर्ण विपणन प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की असुविधा तथा व्यापकों की निर्धनता एवं विवेकता के कारण उन्हें अपनी फसल की गौणों से ही बेचना पड़ता है। प्रायः महाजन ही समस्त फसल के आधे भाग लवा कर अपना उपहार चुकता कर लेता है और किसानों का अपनी फसल का श्वायचित्त मूल्य नहीं मिल पाता और यह जल लेने के लिए विवश होना है।

16 सहायक दम्बों का अभाव नुतीर उड़ीसों का पतन हो जाने के कारण किसानों के पास अब सहायक दम्बों से प्राप्त जामदनी नहीं है, जिससे उनमें अर्द्ध-वर्गोजगारी की स्थिति फैल गई है। इस स्थिति में किसानों को भरण-पोषण के लिए जल सेना पड़ता है। वर्ष के तीन, चार महीनों के अतिरिक्त वे प्रायः बेकार रहते हैं।

1 "The sheep was as easily shorn at his goats as the sheep of its fleeces,"

17 भूमि के मूल्य में वृद्धि भारतीय किसानों में अधिक भूमि प्राप्त करने की लालसा पाई जाती है। भूमि का मूल्य अब पहले से कई गुना बढ़ गया है, अब उन्हें पहले से अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होती है।

18 खेती में उत्पात्ति द्वारा नियम की निर्बाधता किसान पैदावार बढ़ाने के लिए ऋण द्वारा अच्छे खाद, योज, यंत्र आदि का प्रयोग करता है, लेकिन पैदावार उसे आनुपातिक रूप से घटती दर पर प्राप्त होती है, जिससे ऋण बर्ना रह जाता है।

19 कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन अच्छी फसलों के होने तथा भूमि के मूल्य बढ़ जान के कारण, किसानों की ऋण लेने की दक्षि (भूमि को धरोहर रख कर) भी बढ़ गई है। फलतः सोपा सरा किसान अधिक ऋण लेकर ऋणी का ऋणी ही बना रहता है। श्री एम एन खलिग ने ठीक ही कहा है, "कमलों की अनिदिघतता के समान ही फसलों की सम्पन्नता भी भारतीय कृषकों की ऋण-श्रतता का कारण बन जाती है।"

20 सरकारी नीति अग्रणी आत्मन-काल में जमींदारों द्वारा बंधोरापूरक लगान वसूल किया जाता था। अन्य कई प्रकार से उनका लोपण किया जाता था, जिससे कृषक ऋणग्रस्त रहता था। दही बरिपाटी कई पिछड़े इलाकों में अब भी पाई जाती है। किसानों की ऋण लेने की आदत भी पड़ गई है।

इस प्रकार भारतीय कृषक की पिछड़ी हुई अवस्था उसे ऋण लेने की बाध्य करती है। परिस्थितियोंका वह ऋण लेने को बाध्य है। चूंकि उसके अधिकांश ऋण अनुत्पादक है तथा कृषि व्यवसाय अनिश्चित एवं अलभकारी है, अब उसकी ऋण-श्रतता की समस्या भी स्थायी-सी ही बन गई है।

ग्रामीण ऋणश्रतता के दुष्परिणाम

ग्रामीण ऋणश्रतता के कई दुष्परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख दृग प्रकार हैं— (i) कृषक अधिकाधिक निर्धन होता जाता है और उसके रहन-सहन का स्तर भी गिरता जाता है (ii) कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसान बेमन से काम करता है। वह जानता है कि जो कुछ पैदा होगा, महाजन से जायेगा, (iii) उसे भूमि की गिरवी रख कर ऋण लेना पड़ता है जिसे अन्ततः महाजन हड़प जाता है, (iv) ऋणश्रतता से कृषकों का नैतिक पतन होता है, क्योंकि ऋणी होने के कारण उसे सूटकारों की कई अनुचित प्रकारों से सेवा करनी पड़ती है, (v) कभी-कभी ऋणश्रतता के कारण उसे बेगार भी करनी पड़ती है, (vi) ऋणश्रतता के कारण ही उसे अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता, (vii) भूमि कृषकों के हाथ से अव्यक्त बगै के हाथ में चली जाती है, जिससे भूमिहीन कृषि

अधिक वर्ग का उदय होता है, (viii) श्रमप्रतता ग्रूमि-सुधार के मार्ग में रोड़े डट-वाती है, तथा (ix) इससे राजनैतिक एवं सामाजिक असंतोष फैलता है और अन्ततः साम्यवाद की बढ़ावा मिलता है। इस सदर्थ में डा० योंगा का निम्नलिखित कथन बड़ा उपयुक्त प्रतीत होता है “श्रमशक्त समाज आवश्यक रूप से एक सामाजिक ज्वालागुसी है। विभिन्न वर्गों के मध्य असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है और यह निरन्तर बढ़ता हुआ असंतोष उत्तरनाक होता है। सम्भव है कि वह कभी भी प्राप्ति का रूप न ले तो भी बार बार पैदा होने वाला असंतोष अन्तिम से भी अधिक भयंकर होता है। इसी अनुशङ्कता स्थायी बनती है और पुनर्निर्माण के कार्य रुक जाते हैं।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि “श्रमप्रतता ने भारतीय किसान को आर्थिक दृष्टि से दिवालिया, सामाजिक दृष्टि से हीन तथा नैतिक दृष्टि से पतित बना दिया है।” प्रो० जलक घोष ने ठीक ही कहा है, “श्रम के भार ने किसान को कठोर बना दिया है, उसकी कार्य-क्षमता नष्ट हो गई है और अपने कार्य के प्रति उसका कोई उत्साह नहीं रहा है। दृग्का परिणाम का उत्पादन, निरन्तर श्रमप्रतता और बहुत श्रमों के रूप में हमारे सम्मुख है। इन सबके पारस्परिक दूषित प्रभाव के कारण भारतीय कृषि की प्रगति बिल्कुल रुक गई है और उद्योग समृद्धि के दर्शन नहीं होते। ग्रामीण श्रम किसान को उसी तरह सहारा बिये हुए है, जिस तरह जस्तादा का रस्ता फाँसी की सजा पाये व्यक्ति को सहारा देता है।”¹

श्रमप्रतता को दूर करने के लिए सुझाव

यह श्रमप्रतता समाज में अधिक कुचक्र को जन्म देती है। अब कृषकों को इनसे मुक्ति दिलाना आवश्यक है। इस सदर्थ में ये सुझाव उचित हैं— (i) कृषकों के शिक्षा का प्रचार किया जाय, (ii) पुराने ऋणों के परिमोच के लिए उचित अविनियम बनाये जाने चाहिये, (iii) सहकारी साज आन्दोलन को सुदृढ़ किया जाय, (iv) श्रम देने वाली एग्रेसिवों को केवल उत्पादक श्रम देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, (v) कृषि उत्पादन में बाधक कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए, (vi) मालगुजारी की दर कम होनी चाहिए तथा सकल के समय इससे मुक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए (vii) आर्थिक शक्ति के समय कृषकों को आर्थिक सहमता;

1. The volume of indebtedness made him callous, undermined his efficiency and destroyed his initiative for work. The result was low productivity, perpetual indebtedness and ancestral debts. All these worked in a vicious circle and virtually submerged Indian agriculture in a stagnant pool devoid of progress and prosperity. Rural credit supports the farmer as a *luzman's* rope supports the *hanged*’

(viii) कुटीर व सहायक उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, (ix) महाजनो की शोषण-नीति को समाप्त; (x) किसानों की फिजूल खर्ची को आदत कम करके बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए, (xi) मुकदमेवाजी से बचाने के लिए ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करना चाहिए, (xii) कृषि उपज के विक्रय की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, तथा (xiii) प्रचार द्वारा सामाजिक व्यथों को कम करके अल्पवय को रोकना चाहिए तथा सरकारी सहयोग प्रदान करना चाहिए।

श्रृणुप्रस्तुता को दूर करने के लिए किये गये सरकारी प्रयत्न

प्राचीन श्रृणुप्रस्तुता से कृषि एवं कृषकों को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं —

भूमि के मुक्त हस्तान्तरण के फलस्वरूप किसान भूमि की जमानत के बाध पर मनमाला श्रृणु होते हैं। इससे श्रृणु लेने-देने को प्रोत्साहन मिलता है और धीरे-धीरे किसानों की जमीन महाजनों के हाथ में जाने लगती है।

(1) भूमि हस्तान्तरण पर रोक श्रृणु के बढ़ते किसान की भूमि हड़प लेने के महाजन के प्रलोभन को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कानून बनाये हैं। अब यह व्यवस्था की जा चुकी है कि श्रृणु के बढ़ते किसान की भूमि साहूकार को नहीं दी जा सकती, चाहे वह फायलफार हो या नहीं। सन् 1901 ई० का पञ्जाब भूमि बेदखली अधिनियम इस सदन में प्रथम उत्प्रेक्षणीय विधान है। जामदल भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध के साथ-साथ किसानों के धोखारे, पण्डों तथा मकान के कुर्को तथा नीलामी पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। किसान की गिरफ्तारी पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा श्रृणु के किस्ती में भुगतान करने की व्यवस्था भी कर दी गई है।

(2) कृषक सहायता अधिनियम इस सम्बन्ध में सन् 1879 ई० में दक्षिण भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसका नाम दक्षिण कृषक सहायता अधिनियम रखा गया, जिसके अनुसार श्रृणु के कारणों की जांच तथा क्षयदाताओं व कृषकों के बीच हुए प्रसविदों की जांच की व्यवस्था की गई। किसानों को विवाकिया घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। व्याज मूल्य व ऊँची व्याज दर को कम करने की व्यवस्था की गई।

(3) श्रृणु को अनिवार्य रूप से कम या समाप्त करने की व्यवस्था श्रृणु समझौता विभागों को कार्यान्वित करने में स्वेच्छा के सिद्धान्त से समझौते में शोषता नहीं हो पाती थी, इसीलिए इसे मुक्तारूप से कार्यान्वित करने के लिए कानून द्वारा श्रृणु को अनिवार्य रूप से कम करने की व्यवस्था की गई। इस सम्बन्ध में तामिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मैसूर तथा केरल में अधिनियम बन चुके

है। इनके अन्तर्गत (i) ऋणों की बकाया रकमों तथा व्याज-दरों का काम करने की व्यवस्था, (ii) आसामी षर्तों के लिए व्याज-दर निर्दिष्ट करने की व्यवस्था, तथा (iii) बकाया ऋणों की रकम की इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि महाजन द्वारा बसूली की गई कुल धन-राशि मूलधन के दुगुने से अधिक न हो पाए।

(4) साहूकारों पर नियंत्रण . राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किसानों को ऋण से छुटकारा दिलाने के लिए साहूकारों की शिकायतों पर नियंत्रण लगाने की सिफारिश की थी। अतः विभिन्न राज्यों में सन् 1930 के बाद साहूकारों व महाजनो द्वारा धोषण को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। ये कदम हैं, (1) महाजनो की रजिस्ट्री एवं लाइसेन्स ऋण लेने तथा देने के लिए, अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व महाजनो की रजिस्ट्री करा कर लाइसेन्स लेना जरूरी बना दिया गया है, ताकि राजदूतों नरते पर उनका लाइसेन्स रद्द किया जा सके। पंजाब, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जा चुकी है। (2) कानून द्वारा यह आवश्यक बना दिया गया है कि महाजनो को लेन-देन का हिसाब नियमित रूप से रखना चाहिए। (3) कर्ज के लिए व्याज की अधिकतम दर निर्दिष्ट कर दी गई है तथा कई प्रांतो में चक्र-वृद्धि व्याज करने पर पाबन्दी लगा दी गई है। (4) महाजनो द्वारा जब किसान के बीजार, पशु तथा मकान कुर्क नहीं कराये जा सकते हैं।

(5) ऋण समझौता विधान . केन्द्रीय बैंकिंग आध ममिति की सिफारिशों के आधार पर महाजन तथा ऋणी दोनों के पारस्परिक समझौते के अनुसार ऋण राशि को काम करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार का अधिनियम सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में सन् 1933 में पारित हुआ था जिसके अनुसार ऋण राशि को काम करने के लिए ऋण समझौता बोर्ड (Debt Conciliation Board) की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार के अधिनियम, पंजाब, बंगाल, आसाम, मद्रास में क्रमशः सन् 1934, 1935, तथा 1936 में पारित हुए। यद्यपि इन सभी राज्यों में समझौता विधान की कार्य-वाही भिन्न भिन्न है, फिर भी इनमें कुछ समानता पाई जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 3 में 9 सदस्यों का एक समझौता बोर्ड बनाया जाता है, जिसका अध्यक्ष एक सरकारी अधिकारी होता है। इस बोर्ड में ऋणी तथा ऋणदाता दोनों के प्रतिनिधि भी रहते हैं। बोर्ड के सामने बोना पक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने है। ऋण-दाता की वार्षिक रिपोर्ट को दफ्तरीय रूप से रखते हुए बोर्ड द्वारा ऋण की राशि कम-जरा दी जाती है और ऋण बसूली के लिए 15 या 20 वर्षों की क्रिस्त निर्धारित कर दी जाती है।

ऋण समझौता बोर्डों की मध्य प्रदेश, बंगाल, तामिलनाडु तथा पंजाब में काफी सफलता मिली है। लेकिन किसान के पास पटी हुई ऋण राशि चुकाने के साधन भी न होने से कारण कुछ कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसान

जब तक अपने ऋण की अन्तिम किस्त नहीं चुका देता, तब तक उसे अन्यत्र से ऋण नहीं मिल सकता ।

(6) वैकल्पिक एजेंसी की व्यवस्था सरकार ने सन् 1904 ई० से सहकारी साख आन्दोलन खड़ा रखा है, जिसके माध्यम से सरकार ग्रामीण कृषकों को कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था करती है । इस क्षेत्र में साख समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इन्हीं के कारण सहकारी को भी अपनी श्याम दर नीची करनी पड़ी है । सहकारी साख के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋण के लिए सहकारी साख समितियों का तथा दीर्घकालीन ऋणों के लिए भूमि-व्यवस्था बैंकों की स्थापना की गई है ।

(7) हितकारी विभागों की स्थापना इन विभागों का उद्देश्य कृषि व्यवसाय को लाभप्रद बनाना है । इनके द्वारा कृषि-सुधार के अनेक उपायों से, जैसे चक्करी, अच्छे बीजार, कृषि उत्पादन बढ़ता है और कृषकों को आर्थिक दशा सुधरती है । फलस्वरूप उसे ऋण लेने की कम आवश्यकता पड़ती है ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हमारे ऋण सम्बन्धी कानून प्रगतिशील हैं, तथा इसी भारतीय कृषकों को बहुत कुछ राहत मिली है । सहकारी साख समितियों के छोले जाने के फलस्वरूप तथा विगत द्वितीय विश्व युद्ध में मह्य वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणप्रवृत्ति में कुछ कमी अवश्य आई है, लेकिन यह कहना उपयुक्त न होगा कि ग्रामीण ऋणप्रवृत्ति की समस्या का समाधान हो गया है । ऋण सम्बन्धी कानूनों का किमानो द्वारा पूरा कामवा नहीं उठाया गया है, क्योंकि अधिकांश एवं निर्जनता ने उनके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं । सरकार ने विगत कुछ वर्षों में कृषि वित्त दिलाने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका पहले विवेचन किया जा चुका है, लेकिन इन सभी उपायों से समस्या की गम्भीरता को ही कम किया जा सकता है, उसे पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता । इसका अन्तिम उपचार तो केवल कृषि की उन्नति में है । जब तक भारत में कृषि उद्योग को लाभ-दायक नहीं बनाया जाता, तब तक किसानों को ऋण लेने की आवश्यकता रहेगी तथा ऋणप्रवृत्ति भी बनी रहेगी ।

ग्रामीण ऋणप्रवृत्ति की समस्या भारतीय किसानों एवं देश की अर्ध-व्यवस्था के लिए एक जटिल समस्या बनी हुई है । जब तक इस समस्या पर अनेक दिशाओं से विचार नहीं किया जायेगा, तब तक इसके हल होने की संभावना नहीं है । सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किये गये कर्मों से किसानों को राहत अवश्य मिली है, परन्तु इस दिशा में अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है । अभी इस समस्या का रपर्स मात्र हो रहा है । इसके स्थायी हल के लिए सरकार को अपनी सामाजिक व आर्थिक

नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना एटोला देश की सरकारों को प्रेरणा देना तथा सामुदायिक योजनाएँ इस दिशा में प्रसन्नतापूर्वक प्रवर्तन कर रही हैं।

प्रश्न

1 भारत में ग्रामीण ऋणप्रस्तुता के कारण तथा दोष बताइये। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या साधन अपनाये गए हैं ?

(राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष, कला, 1966, 1967)

2 भारत में बढ़ती हुई कीमतों के कारण ग्रामीण ऋण बढ़ रहा है या घट रहा है ? इस समस्या के समाधान के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें।

(राज० टी० डी० सी० कला, तृतीय वर्ष 1967)

3 ग्रामीण भारत की वर्तमान वित्त व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिये। क्या स्थिति सतोषजनक है ? यदि नहीं, तो स्थिति सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए।

(राज० बी० ए० 1964)

(4) Is rural indebtedness increasing or decreasing in India ? How would you like to solve this problem ?

(Raj T D C Third Yr Arts 1964)

खण्ड-चतुर्थ

उद्योग व श्रम

भारत में कुटीर व लघु उद्योग

(Cottage and Small Scale Industries in India)

"In the present and foreseeable future, cottage and village industries have an essential place in Indian economy and have to be encouraged in every way India would become an industrialised nation only when there are lakhs of units of small industries functioning in different parts of the country"

—Jawahar Lal Nehru

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का अत्यधिक महत्व है। महात्मा गांधी के शब्दों में भारत का मोल उसके कुटीर उद्योगों में ही निहित है। भारतवर्ष में यद्यपि आज बड़े बड़े उद्योगों का विकास हो रहा है, तथापि कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व पर इसका तनिक भी असर नहीं पड़ा है। भारतवर्ष की बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता एवं फैली हुई बेकारी तथा अर्द्ध-बेकारी के सदन में कुटीर उद्योगों का महत्व बढ़ा बना रहेगा। सच तो यह है कि भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएँ उस समय तक हल नहीं की जा सकती, जब तक देश में कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्रों के क्षेत्रों में समुचित विकास नहीं किया जाएगा।

अर्थ एवं परिभाषा

कुटीर उद्योग में उद्योग मुख्य रूप से परम्परागत पद्धति पर चलाए जाते हैं और परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें वैज्ञानिक श्रम का बहुत कम या बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होता तथा केवल परिवार के सदस्यों की सहायता से ही चलाए जाते हैं। ये उद्योग पूर्ण कालिक अथवा अर्ध कालिक हो सकते हैं। साधारणतः ये उद्योग कृषि से सम्बन्धित होते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। इस प्रकार के उद्योगों से पूँजी की अपेक्षा श्रम की ही प्रधानता रहती है। शक्ति चालित मशीनों का उपयोग नहीं के बराबर होता है। इसकी बनी हुई चीजों की माँग प्रायः स्थानीय होती है। राज्य कोषीय आयोग के अनुसार "कुटीर उद्योग वह है जो

पूर्णतया या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण या आंशिक धनसाधन के रूप में चलाया जाता हो।”¹ श्री चिन्तामणि देशमुख के शब्दों में, “कुटीर उद्योग का तात्पर्य सामान्यतः बड़े उद्योगों के समकित उत्पादन को छोड़ कर उत्पादन के अन्य सभी रूपों से लगाया जाता है। जो व्यक्ति इसमें लगे होते हैं, वे मुख्य रूप से अपने ही प्रयत्न और निपुणता पर निर्भर होते हैं तथा अपने घरों में काम करते हुए केवल साधारण औजारों का प्रयोग करते हैं। हाल ही में कुछ विविध आविष्कारों के फलस्वरूप इनमें से कुछ ही उद्योग सामने आए हैं। वे अधिकतर परम्परागत क्रियाओं के रूप में हैं और उत्पादन की आधुनिक प्रविधियों और रूपों के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर अपने को बनाए रखने के लिए बचपन कर रहे हैं।”

लघु उद्योग लघु उद्योग कुटीर उद्योगों से अलग होते हैं। इनमें वेतन भोगी अधिक कार्य करते हैं तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः छोटे-छोटे कारखानों के रूप में विविध वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सामान्यतः ऐसे उद्योग बाहरी में स्थापित किए जाते हैं, जो दूर-दूर से कच्चा माल भेजते हैं तथा अपना तैयार माल दूर-दूर तक भेजते हैं। ये उद्योग सामान्यतः पूर्ण-कालिक होते हैं। राज्यकोषीय आयोग के अनुसार “लघु उद्योग यह है, जो मुख्यतः 10 से 15 श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है, लेकिन यह श्रमिकों के घर पर नहीं चलाया जाता है। इनमें वे सब इकाइयाँ व संस्थान शामिल कर लिये जाते हैं, जिनमें 5 लाख रुपये से कम पूँजी लगी हुई होनी है।”² श्री चिन्तामणि देशमुख के मतानुसार, “छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग से कुछ भिन्न हैं, वह इन अर्थ में भिन्न हैं कि छोटे पैमाने के उद्योगों में श्रमिकों को लगाने वाले छोटे साहसिकों/मालिकों भी सम्मिलित हैं।”

परन्तु लघु पैमाने के उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता था, जिनमें 5 लाख रुपये से कम की पूँजी का विनियोग हुआ हो और यदि व्यक्ति का प्रयोग हो रहा हो तो 10 से कम तथा सविन का प्रयोग न हो

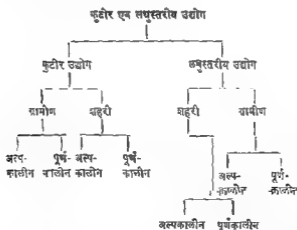
1. “A cottage industry is one which is carried on wholly or primarily with the help of the members of the family either as a whole or as a part-time occupation.”

Report of the Fiscal Commission, p. 104.

2. “A Small Scale Industry is one which is operated mainly with hired labour, usually with 10 to 50 hands and is not carried on in the cottage of the worker. It includes all units or establishments having a capital investment of less than 5 lakhs.”

रहा हो तो 100 से कम व्यक्तियों को रोजगार दिया गया हो। लघु-उद्योग बोर्ड की सिफारिशों को मान कर भारत सरकार ने, इसकी परिभाषा में सुधार कर दिया और अब उन उद्योगों को लघु उद्योगों के अन्तर्गत रखा गया, जो प्रति पारी शक्ति के प्रयोग के साथ 50 श्रमिकों से कम को तथा बिना शक्ति के प्रयोग के 100 श्रमिकों से कम को रोजगार देते हो। भारत सरकार ने लघु उद्योगों की परिभाषा में पुनः सुशोधन कर दिया। अब कुटीर उद्योग से ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ सम्मिलित की जाने लगी हैं, जिनमें पूँजी विनियोग 5 लाख रुपये से कम का हो, चाहे रोजगार देने वाले श्रमिक कितने ही क्यों न हों। केन्द्रीय लघु उद्योग बोर्ड (Central Small Scale Industries Board) की सिफारिश के आधार पर लघु पैमाने के उद्योग की परिभाषा में 1966 में फिर से सुशोधन किया गया। नवीन सुशोधित परिभाषा के अन्तर्गत पूँजी विनियोग की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ा कर 7.5 लाख रुपये कर दी गई है। पूँजी विनियोग से आकाश केवल अन्न एवं मशीनों पर किए गए विनियोग से है, भूमि व भवन पर दिया गया विनियोग सम्मिलित नहीं है। इस परिभाषा में भी श्रमिकों की संख्या पर जोर नहीं दिया गया।

कुटीर एवं लघु-उद्योगों का वर्गीकरण : राज-कोपीय भाषण ने कुटीर एवं लघु उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है-



कुटीर उद्योग दो प्रकार के होते हैं—ग्रामीण एवं शहरी। ग्रामीण कुटीर उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं—अल्पकालीन व पूर्णकालीन। अल्पकालीन कुटीर

उद्योगों के अन्तर्गत कृषि में सहायता पहुँचाने वाले उद्योग आते हैं, जैसे ठीकरी बनाना, रेशम के कीटों पालना, हाथकरवा आदि ।

पूर्ण-कालीन कुटीर उद्योग के अन्तर्गत वे उद्योग आते हैं, जिनमें गाँव के रहने वालों को पूरे समय के लिए रोजगार मिलना है, जैसे, मिट्टी के बर्तन बनाना, बड़ईगोरी करना, लुहारगोरी, इत्यादि । शहरी कुटीर उद्योग भी दो प्रकार के हो सकते हैं—अल्पकालीन व पूर्णकालीन । सामान्यतः शहरी में पूर्णकालीन उद्योग ही पाये जाते हैं, जैसे मोने-बाँदी का काम, लकड़ी के खिलौने बनाना तथा रंग आदि के कार्य । अल्पकालीन कुटीर उद्योग शहरी में प्रायः कम अपनाए जाते हैं । पत्ता बनाने का उद्योग प्रायः अल्पकालीन होता है ।

लघु-उद्योग दो प्रकार के होते हैं—(1) शहरी तथा (2) ग्रामीण । शहरी लघु उद्योग को भी दो हिस्सों में बाटा जा सकता है—अल्पकालीन व दीर्घकालीन । अल्पकालीन शहरी लघु उद्योग में वे काम आते हैं, जिनमें कारीगरों को मौसम-विशेष में छोटे समय के लिए काम मिलता है, जैसे ईंट बनाना । पूर्णकालीन शहरी लघु उद्योग में शहरी के स्थायी रूप से चलने वाले कारखाने आते हैं, जैसे, धमड़े के कारखाने, होजरी के कारखाने आदि । अल्पकालीन ग्रामीण लघु उद्योगों के अन्तर्गत गाँव के मौसमी उद्योग आते हैं, जैसे गूँच या खड़बारी बनाना । पूर्णकालीन लघु-उद्योग में वर्ष भर चलने वाले छोटे-मोटे उद्योग आते हैं, जैसे-बूते बनाना, कालोन बनाना इत्यादि ।

कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्त्व पर अवश्यता . भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों के महत्त्व के सम्बन्ध में महारत्ना ग्राम्फी ने कहा था, “भारत का उद्धार कुटीर उद्योग-बन्धों द्वारा हो सम्भव है ।” बड़े पैमाने के उद्योगों पर बल देने वाले स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू भी कुटीर व लघु उद्योगों के महत्त्व से अनभिज्ञ नहीं थे । एक स्थान पर उन्होंने कहा है, “भारत अभी एक औद्योगिक राष्ट्र होगा जबकि यहाँ पर लायों की संख्या में छोटे-छोटे उद्योग हों । देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में इन उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । योजना आयोग के दायों में, ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य, कार्य के अवसरों में वृद्धि करना है, अर्थ एवं रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना तथा एक अधिक सन्तुलित एवं एकीकृत अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना है ।”¹ इन उद्योगों का महत्त्व अग्रलिखित कारण से बहुत अधिक है.

1. The primary object of developing small industries in rural areas is to extend work opportunities raise incomes and standard of living and to bring about a more balanced and integrated rural economy.”

—Planning Commission,

1 कुटीर व लघु-उद्योग बेरोजगारी व अर्द्ध रोजगारी को दूर करते हैं भारतवर्ष में बेरोजगारी व अर्द्ध रोजगारी की समस्या का हल बहुत कुछ हद तक कुटीर व लघु उद्योगों के विकास में ही निहित है। भारतीय किसान जो कि वर्ष में आधे से अधिक दिन तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, इन उद्योगों के द्वारा अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकता है। वेगन्धमार व्यक्ति छोटे उद्योगों की स्थापना करने अपना भरण पोषण कर सकते हैं। बड़े कारखानों की अपेक्षा छोटे लघु व कुटीर उद्योगों में ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है। भारतवर्ष में इस समय अनुमानित कुटीर उद्योगों में 2 करोड़ व्यक्ति लग हुए हैं। केवल हस्तकर्म उद्योगों में ही 50 लाख लोग लगे हुए हैं जो सभी संचालित उद्योगों (बस पैमाने के उद्योग, हनिज एव सामान उद्योग) में लग हुए व्यक्तियों के बराबर है। अतः बेरोजगारी की समस्या के समाधान की आशा केवल लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा ही की जा सकती है।

2 कम पूँजी की आवश्यकता कुटीर उद्योगों को चालू करने के लिए भूतपदान मशीनों एवं बड़ी इमारतों की जरूरत नहीं पड़ती। कुटीर उद्योग पूँजी प्रधान (Capital intensive) न होकर श्रम प्रधान (Labour intensive) होते हैं। अतः भारत जैसे देश के लिये जहाँ सामान्यतः पूँजी का अभाव पाया जाता है, कुटीर व लघु उद्योग बड़ा अनुकूल साबित हो सकते हैं। क्योंकि इन्हीं कम पूँजी से चलाया जा सकता है तथा अधिक श्रमिकों को काम दिलाया जा सकता है।

3 आर्थिक विषमता का निराकरण बड़ा पैमाने के उद्योगों के कारण देश में एक ओर निर्धनता का साम्राज्य विद्यमान है तथा लोग जीवन की अनिवार्यताओं को भी पूरा करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, तथा दूसरी ओर बहुत वैभव नजर आता है। यह सामाजिक अन्धकार की दृष्टि में अनुचित है। कुटीर उद्योगों के विकास से इस प्रकार की आर्थिक विषमता घेदा नहीं होती। कुटीर एवं लघु उद्योग प्रायः परिवार के सदस्यों की सहभागिता से चलाए जाते हैं और जहाँ वेतन भोगी श्रमिकों से काम कराया जाता है, वहाँ भी उनका अधिक धोषण नहीं हो पाता, क्योंकि उत्पादक एवं श्रमिकों में निकट का सम्पर्क बना रहता है। ऐसे उद्योगों का प्रत्यक्ष प्रायः व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक स्तर पर आधारित होता है, जिनकी पूँजी और आय दोनों ही अधिक नहीं होती, मजदूर-स्वामी इनके स्वभाव से अधिक अन्तर्भाव नहीं कर पाते।

4 भूमि पर से जनभार का कम होना भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि पर जनसंख्या का भार अत्यधिक बड़ा हुआ है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के द्वारा ग्रामीण जन संख्या के एक बहुत बड़ा भाग को भूमि पर से हटाया जा सकता है और लाभदायक कार्यों पर लगाया जा सकता है। इसके भूमि पर भार कम हो जायेगा और कृषि जोते जायिव हो जायेंगे।

5. उद्योगों का विकेन्द्रीकरण : उद्योगों के केन्द्रीकरण के कारण कई नगरों में अनेक समस्याएँ पैदा हो गई हैं तथा आवास की समस्या, नैतिक पतन एवं अस्वस्थ वातावरण की समस्या आदि भी इसी के परिणाम हैं। विकेन्द्रीकरण की इन समस्याओं का निराकरण कुटीर उद्योगों के विकास से दूर किया जा सकता है, क्योंकि कुटीर उद्योग देश के विभिन्न क्षेत्रों में चलाये जा सकते हैं। इनके लिए किसी स्थान-विशेष में केन्द्रित होना जरूरी नहीं है। इनका बिनास ग्रामीण व नगरी क्षेत्रों में समानता के साथ किया जा सकता है।

6. औद्योगिक संघर्षों से मुक्ति : कुटीर व लघु पैमाने के उद्योगों में पूँजी-पतियों व धर्मियों के वर्ग नहीं होते। काम करने वाले प्रायः सभी श्रमिक होते हैं। यदि कोई पूँजी मालिक भी होता है तो भी पैमाना छोटा होने के कारण वह अपने श्रमिकों की समस्याओं से पूर्णतः परिचित होता है। इन समस्याओं के उत्पन्न होते ही उनका समाधान कर दिया जाता है। इस प्रकार कुटीर व लघु उद्योगों के विकास से हड़ताल व ठाळे वगैरह नहीं होती। औद्योगिक आन्दोलन सधर्ममय न होकर सहयोगमय होता है।

7. राष्ट्रीय आय में वृद्धि : कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास से जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को काम मिलता है, जिससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) के अनुसार भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय में, विद्यालयीय उद्योगों की अपेक्षा लघु-उद्योगों का योगदान प्रति वर्ष अधिक होता है।

8. उत्पादित माल की श्रेष्ठता : कुटीर उद्योगों के लिए भारत प्राचीनकाल से प्रसिद्ध रहा है। कुटीर उद्योगों द्वारा बना हुआ माल श्रेष्ठ होता था तथा अपनी कलात्मक प्रवृत्ति के लिए विद्वद-विद्वान या। आज भी कुटीर उद्योगों द्वारा बनाया गया माल अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक एवं टिकाऊ होता है, क्योंकि इसे बनाने में कलाकार अपनी आत्मानुभूति से काम करता है, अतः सामान्यतः कुटीर उद्योगों का बना हुआ माल अपेक्षाकृत श्रेष्ठ होता है।

9. सहायक आय का उत्तम साधन : कुटीर एवं लघु उद्योगों को अपनाकर गाँव के सतिहर श्रमिक और नगरी में काम करने वाले श्रमिक अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार अपने रहन-सहन के स्तर को सुधार सकते हैं।

10. कार्य की स्वतन्त्रता : कुटीर व लघु उद्योगों में श्रमिकों को मालिकों की तरह काम नहीं करना पड़ता। श्रमिक या कार्यरत स्वतन्त्रतापूर्वक एवं सुविधासुमार कार्य करते हैं। भारतीय कृषि का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है कि लोग स्वच्छता से एवं स्वतन्त्रतापूर्वक काम करना चाहते हैं। अतः कुटीर व लघु-स्वारीय उद्योग भारतीय लोगों के स्वभाव के अनुकूल पड़ते हैं।

11 समाजवादी समाज की स्थापना के अनुकूल देश में सही अर्थों में समाजवादी समाज की स्थापना उभी संभव हो सकती है, जबकि बड़े-बड़े उद्योगों की बजाय कुटीर व लघु उद्योगों का विकास देश के कोने कोने में किया जाय। बड़े उद्योग आर्थिक विषमता को जन्म देते हैं, जबकि छोटे उद्योग इसे दूर करके गमज-वादी समाज की स्थापना में योगदान देते हैं।

12 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहस्रक यदि देश को आर्थिक क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाना है, तो यह कार्य कुटीर व लघु उद्योगों से अपेक्षाकृत अधिक सरलता से हो सकता है। ये उद्योग कम पूँजी से, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए देश भर में चलाये जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर हर एक चीज के उत्पादन के लिए हमारे देश में माधनों व सुविधाओं की कमी है। देश में कुटीर उद्योगों को माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।

13 संचालन की सरलता कुटीर एवं लघु उद्योगों का संचालन सरलता से किया जा सकता है क्योंकि इनके लिए न तो अधिक पूँजी चाहिए और न ही बहुत अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी। इनके औजार भी देश में ही बनाने जा सकते हैं और इन्हें कच्चा माल भी सामान्य क्षेत्रों से मिल जाता है। अधिक भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों का संचालन अपेक्षाकृत सरल एवं सुविधापूर्ण है।

14 माय के अनुरूप उत्पादन कुटीर व लघु-उद्योगों में उत्पादन व उपभोक्ता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। उत्पादक, उपभोक्ता की रुचि व माँग की मात्रा से परिचित होते हैं, अतः उत्पादन उपभोक्तानों की रुचि व अनुसार जतना ही किया जाता है, जितनी कि उनकी माय होती है। कुटीर व लघुस्तरीय उद्योगों में अत्यधिक उत्पादन या ग़लत उत्पादन की समस्या पैदा नहीं होती।

15 देश की सम्यक्ता एवं संस्कृति के अनुरूप भारतीय लोग सहयोग, सहा-नुमति, समानता, सहकारिता, भाईचारे की भावना तथा उसके विकास की भावना में सदैव से ही विश्वास रखते चले आये हैं। कुटीर उद्योग इन्हीं भावनाओं के पोषक हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में विद्वेष, स्वार्थपरता, धोपण, कट्टा, गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा आदि अमानवीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। अतः ये उद्योग हमारी सम्यक्ता व संस्कृति के अनुकूल नहीं हैं।

16 देश की सुरक्षा के अनुकूल - आधुनिक युद्ध में एक देश के औद्योगिक नगरों के औद्योगिक संस्थानों को पहले नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, ताकि उस देश की अर्थ व्यवस्था को क्षिन्न भिन्न किया जा सके। कुटीर एवं लघु-उद्योगों की प्रधानता होने से देश को इस प्रकार की धमुरला का सामना नहीं करना पड़ता।

17 **मानवीय मूल्यों की रक्षा :** बड़े पैमाने के कारखानों में श्रमिक भी एक प्रकार की कार्य करने की मशीन बन जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रगति के फलस्वरूप उत्पन्न औद्योगिक नगरो में श्रमिकों का सामाजिक एवं नैतिक उत्थान रुक जाता है तथा मानवीय मूल्यों को बाधात पहुँचता है, जबकि कुटीर एवं लघु-उद्योग से सादे जीवन एवं उच्च विचार की भावना पैदा होती है तथा मानवीय मूल्यों की रक्षा होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की वर्ग-व्यवस्था में कुटीर एवं लघु-उद्योगों का विशेष महत्व है तथा इन उद्योगों ने विकास की आवश्यकता बहुत अधिक है। सन् 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में इन उद्योगों की आवश्यकता एवं महत्व पर उल्लेखनीय जोर दिया गया है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में यह कहा गया था कि "कुटीर एवं लघु उद्योग बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक रोजगार प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय आय के अधिक व्यावसायिक वितरण को सम्भव बनाते हैं तथा पुंजी एवं योग्यता सम्बन्धी प्रसाधानों के अधिक प्रभावपूर्ण घोषण में सहायक होते हैं। यदि देश भर में औद्योगिक उत्पादन के छोटे-छोटे केन्द्र स्थापित कर दिए जाय तो अति-योजित नागरीकरण की समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है।"¹ भारत सरकार की यदि देश की वर्ग व्यवस्था को संतुलित करना है तो उसे बड़े उद्योगों के साथ कुटीर उद्योगों के विकास पर भी समुचित ध्यान देना पड़ेगा। डा० इरामा प्रसाद मुकुर्जी के शब्दों में, "भारत गीबो का देश है, अतः सरकार की संतुलित वर्ग-व्यवस्था की दृष्टि से कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को सर्वाधिक महत्व प्रदान करना चाहिए।"

कुटीर उद्योगों का महत्व आज विश्व के सभी देशों में स्वीकार किया जा रहा है। फ्रान्स, जर्मनी, इटली तथा स्विटजरलैंड में इन उद्योगों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। फ्रान्स में सेरीकल्चर, सिल्वी कल्चर तथा वाइन कल्चर कृषकों के प्रमुख सहायक घन्थे हैं। स्विटजरलैंड में घड़ी निर्माण सम्बन्धी कार्य सहायक उद्योग के रूप में ही चलाया जाता है। चीन एवं जापान में ठाखी परिवार अपने खारी समय में कोयल पालते हैं। फ्रान्स में प्रायः सभी कारखानों में 100 से कम श्रमिक हैं। जापान में 80 प्रतिशत से भी अधिक कारखानों में 30 से कम तथा बेल्जियम में 90 प्रतिशत कारखानों में 5 से भी कम अधिक कार्य करते हैं। इंग्लैंड में 5 से 30 व्यक्तियों

1. "They provide immediate large scale employment, they offer a better method of ensuring a more equitable distribution of national income and they facilitate an effective mobilisation of resources of capital and skill which might otherwise remain unused. Some of the problems that unskilled unemployment tends to create will be avoided by the establishment of small centres of industrial production all over the country."

—Journal of Industry and Trade, Jan, 63.

को काम दिलाने वाले सरवानों की संख्या काफी है, जिनमें कुल भ्रम शक्ति के 29 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जर्मनी में 12.6 प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कुटीर उद्योगों पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि अमेरिका में सन् 1965 में 95 प्रतिशत कारखाने लघु उद्योगों के क्षेत्र में थे, जिनमें देश के 40 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इस प्रकार विश्व के जब सभी देशों ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्त्व को समझ कर इन्हें अपनाया है तो भारत में इन उद्योगों का महत्त्व तो और भी अधिक है।

कुटीर एवं लघु उद्योगों की कठिनताएँ एवं समस्याएँ भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों के महत्त्व को सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन इन उद्योगों का विकास भारतवर्ष में उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। इन उद्योगों के विकास के मार्ग में कई कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ हैं। जब तक इनका निराकरण नहीं हो जाता, कुटीर एवं लघु उद्योग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकते। ये कठिनाइयाँ अथवा समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

1. विश्व सम्प्रदायी कठिनाई कुटीर व अद्युस्तरिय उद्योगों की कच्चा माल खरीदने, धातुओं को मजदूरी देने, व तैयार माल के संग्रह के लिए अल्पवालीन ऋण की आवश्यकता होती है। मशीनों, जोखार व भवन निर्माण के लिए मध्य व दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। भारतवर्ष के शिल्पी निर्धन हैं और वे उपयुक्त कार्यों के लिए पूर्ण नहीं एवज कर पाते। महाजनो, साधुमारो आदि से ऋण लेने पर एक तो व्याज अधिक देना पड़ता है, दूसरे ये लोग शिल्पियों के माल को बहुत सस्ता खरीद कर उनका शोषण करते हैं। बम्बई आर्थिक तथा औद्योगिक जांच समिति 1940, ने अपने प्रतिवेदन में ठीक ही लिखा है, “लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों की लोकप्रियायी समस्या निरा की है। अधिकांश ये उद्योग किसी एक व्यक्ति के अधिकार में अथवा साझेदारी में चलाये जाते हैं और उनके पास अपने औजारों की दबा सुपारने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। उनके पास बच्चे माल को खरीदने के लिए भी धावश्यक पूर्ण नहीं होती और जब बाहर से ऋण लेना पड़ता है, तो उन्हें ऊँची दर से व्याज देना पड़ता है।”

2. कच्चे माल की समस्या इन उद्योगों की उचित धन्य पर, उचित समय पर तथा उचित मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये उद्योग भी प्रायः उसी कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, जिन पर बड़े उद्योग निर्भर करते हैं। बड़े उद्योग बड़ी मात्रा में व सगठित रूप में कच्चे माल का प्रयोजन करते हैं, अतः उन्हें अच्छा, सस्ता व समय पर माल मिल जाता है, जबकि छोटे उद्योगों के साथ ये सुविधाएँ नहीं हैं। अभावित किया हुआ कच्चा माल भी उन्हें बहुत दूर से मिलता है। यही नहीं,

लघु-उद्योगों की बड़े-निर्मित (Semi-finished) माल, जैसे मशीनों का भाग, लोहे व पीतल की चादरें प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है।

3 उत्पादन की रुढ़िवादी पद्धति हमारे कुटीर व लघुस्तरीय उद्योग अब भी प्राचीन औजारों का ही प्रयोग कर रहे हैं। उनके उत्पादन का डग भी वही पुराना है। इन कारखानों के परिणाम स्वरूप इन उद्योगों में न तो उच्चकोटि का और न ही सस्ता सामान बन पाया है। इन उद्योगों के सम्बन्ध में अनुमोदन की सुविधाओं का अभाव है तथा उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे अल्पकार मशीन पद्धतियों एवं औजारों के प्रयोग से बचते रह जाते हैं।

4 विपणन की समस्या इन उद्योगों को परिवहन व विज्ञान की सुविधा नहीं होने के कारण, सिलिण्डरों की मृदुलमस्तरता, संगठन के अभाव तथा मध्यस्थों की अधिकता के कारण, अपने उत्पादित माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। प्रायः लाभ का 40 प्रतिशत तक भाग मध्यस्था द्वारा हड़प लिया जाता है।

5 बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा बड़े पैमाने के उद्योगों को अपने पैमाने की विशालता के कारण कारखाने का आन्तरिक व बाह्य बचते प्राप्त होती है। उनकी लागत श्रम बहुत कम हो जाती है। इसके विपरीत छोटे व कुटीर उद्योगों की ऊँची लागत होने के कारण सस्ता माल बेचने में कठिनाई होती है। अतः वे प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। भारतवर्ष में कई कलात्मक चरेणु उद्योग प्रतिस्पर्धा के कारण ही समाप्त हो गये हैं।

6 संगठन का अभाव कुटीर उद्योग को चलाने वालों में संगठन का अभाव है, जिससे कच्चे माल के खरीदने, बने हुए माल को बेचने, विज्ञापन करने, सामान लाने व ले जाना, वित्त प्राप्त करने आदि में कठिनाई होती है। बड़े पैमाने के उद्योगों को संगठन के कारण समाप्त लाभ प्राप्त होते हैं, जबकि कुटीर व लघु-उद्योग संगठन के अभाव में पिछड़े हुये रह गए हैं।

7 स्वाधीन करों की बढ़ता हुआ भार भारतीय राष्ट्रीय श्रेणी में तथा छोटे-छोटे वस्तु में स्वाधीन सरकारों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्रों से होकर जाने वाले माल पर कर में वृद्धि की है। इससे कुटीर व लघु उद्योगों को काफी क्षति पहुँची है, क्योंकि उनकी वस्तुओं और भी अधिक महंगी हो जाती है।

■ उपभोक्ताओं की अहंति उपभोक्ता संस्था व अच्छा माल पसंद करते हैं। कुटीर उद्योगों का माल अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। अब लोग इन्हें नहीं खरीदते। स्वदेशी भावना की भी उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है। लोग विदेशी, सस्ते व दिखावटी माल को प्राथमिकता देते हैं। परिणाम यह होता है कि इन उद्योगों को अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

भारत में कुटीर व लघु उद्योग

9 शिक्षा की अक्षिप्तता भारतीय शिल्पकार अधिक्षित है। शिक्षा के अभाव में उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। अधिक्षा के कारण ही उन्हें मध्यम स्तर के हैं तथा वे संगठन नहीं बना पाते। शिक्षा के अभाव में ही उनका इष्टिकोण भी संकुचित व सीमित होता है, जो उन्हें विकास की ओर नहीं जाने देता और वे हठिवादी यातावरण में मोड़ी बहुत प्रगति करके संतुष्ट हो जाते हैं।

10 उत्पादन का सीमित क्षेत्र भारतवर्ष में कुटीर उद्योग जनसाधारण के छोटे आनन्दक वस्तुओं का उत्पादन न करके, विस्तारिता की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन वस्तुओं का मूल्य ऊँचा होता है और ये वस्तुएं सीमित मात्रा में ही होती हैं। किसी समय कारीगरों को इन वस्तुओं के निर्माण में बहुत लाभ हुआ करता था, परन्तु राजाओं, नवाबों व जमींदारों का युग समाप्त हो गया है और इन वस्तुओं का उच्च मूल्य जन-साधारण नहीं दे सकते।

11 शिक्षा की सहयोग व सहकारिता का अभाव भारतवर्ष में इन उद्योगों की सहकारिता के आधार पर चलाने की चेष्टा की जा रही है। सहकारी आन्दोलन की प्रगति हमारे देश में धीमी रही है, फलस्वरूप इन उद्योगों की भी विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुये। मर्चेन्ट व वाणिज्य के मतानुसार अमिको में सहयोग तथा सहकारिता का अभाव कुटीर उद्योगों के विकास में बाधक बन रहा है।¹

12 मशीनरी तथा बीजारों का अभाव भारतवर्ष में लघु उद्योगों के लिए मशीनरी एवं बीजार या तो मिलने ही नहीं और यदि मिलते हैं तो उनके लिए बहुत ऊँचे दाम देने पड़ते हैं। जिन जगहों पर लघु उद्योग विद्युत का प्रयोग करते लगे हैं, वहाँ प्रायः विद्युत निर्यात रूप से नहीं प्राप्त होती और यदि मिलती भी है तो उसके लिये अधिक ऊँची दर देनी पड़ती है।

सुझाव .

भारतीय एवं अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। परन्तु इन उद्योगों की कठिनाइयों व समस्याओं का हल निकालने पर ही वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनकी कठिनाइयों व समस्याओं को दूर करने के सुझावों में अत्रलिखित महत्वपूर्ण हैं।

1 बड़े उद्योगों के साथ सहयोग कुटीर एवं लघु-उद्योगों एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के मध्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिये इन उद्योगों के नार्य-

क्षेत्र को जहाँ तक सम्भव हो बरत कर देना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो तो आपन को तरह हमारे देश में भी छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों को सम्मिलित रूप से तथा एक-दूसरे के पूरक के रूप में उत्पादन कार्य करना चाहिए।

2. सुसंगठित बिजली व्यवस्था कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल की बिजली के लिए यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल की बिजली के लिए नगरी में बिजली केन्द्र खोले जाने चाहिए। देश-विदेश में इनके माल की प्रदर्शनिया आयोजित की जानी चाहिए। बिजली एवं विशासन के लिए सहकारी बिजली समितियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

3. तकनीक में सुधार कुटीर एवं लघु उद्योगों की तकनीकी कुशलता बढ़ाने के लिए, इन उद्योगों में प्रयोग में लाये जा रहे औजारों एवं उत्पादों बिधियों में सुधार किया जाना चाहिए तथा तकनीक सुधारों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिये।

4. उचित प्रशिक्षण कुटीर एवं लघु उद्योगों में तबे कारीगरों की उत्पादन की आयुनिष्ठतम बिधियों की जानकारी कराई जानी चाहिए। उन्हें यथोचित प्रशिक्षण की सुविधाएँ दिलाने के लिए विभिन्न हस्तकलाओं में सम्बन्धित औद्योगिक विद्यालय खोले जाने चाहिए।

5. मशीनरी एवं औजारों की पूर्ति कुटीर एवं लघु उद्योगों की आयु-निरुत्तम यन्त्रों से सुलब्ध करने के लिए किता खरीद-पद्धति (hire-purchase system) पर औजार दिग्गजों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन औजारों के प्राप्ति क्षेत्रों में प्रदर्शन किये जाने चाहिए। इस दिग्गज में मार्पदर्शी वर्कशॉप (Pilot Work Shops) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

6. कच्चे माल की पूर्ति राज्य सरकारों की सहायता एवं सहकारिता के माध्यम पर, लघु उद्योगों को, कच्चे माल की उचित समग्र, उचित मात्रा एवं उचित मूल्य पर प्राप्त होने की सुविधा दिलाई जानी चाहिए।

7. वित्त सम्बन्धी सुविधा कुटीर एवं लघु उद्योगों को वित्त सम्बन्धी कठिनाई से बचने के लिए, अपनी सहकारी समितियाँ बनायी चाहिये, जो उचित समय पर ऋण व्याज दर पर आवश्यक वित्त उपलब्ध करा सकेंगी। नगरी में लघु उद्योगों को सास प्रदान करने के लिए राज्य वित्त निगम अच्छा साधन है, यदि ये अपनी कार्य प्रणाली को लान्कीतेजाही से बचा सकें।

8. अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कुटीर एवं लघु उद्योगों के सम्बन्ध में इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि वर्तमान कुटीर एवं लघु उद्योगों में कौन से उद्योग ऐसे हैं, जो उन्नति कर सकते हैं तथा कौन से नए उद्योग काम में लिये जा सकते हैं।

भारत में कुटीर व लघु उद्योग

इस जाच के आधार पर प्रमुख कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम निश्चित किये जाय।

9. सस्ती बिजली की सुविधा जापान एवं स्विट्जरलैंड में कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास में सस्ती बिजली की सुविधा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय उद्योगों की प्रगति के लिए यहाँ भी सस्ती बिजली की सुविधा दिलाई जानी चाहिए, ताकि इनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि हो सके।

10. अन्य सुझाव कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त वित्त सुत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव भी दिये गए हैं, जैसे, (i) कुछ विशेष उत्पादन क्षेत्र लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दिये जाने चाहिये, (ii) लघु उद्योगों के प्रत्येक उद्योग के लिए एक-एक ऐसी सस्था बनाई जावे जो सम्बन्धित उद्योगों की समस्याओं को हल कर सके, (iii) लघु उद्योगों के उत्पादन की खेपटता के स्तर निर्धारित किये जाने चाहिये तथा इन्हें समस्त उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिए; (iv) कुटीर एवं लघु उद्योगों की वस्तुओं की विप्री कर, उत्पादन कर, निर्यात कर आदि करो से मुक्त कर दिया जाना चाहिये, (v) देश में स्वदेशी भाषना का लोगो में प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि लोग इन उद्योगों की वस्तुओं को बर्तन एवं चाय से खरीदें, (vi) विविधों की औद्योगिक सहकारी समितियों (Industrial Co-operatives) का गठन करके अपना संगठन दृढ़ करना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन दल (International Planning Team) द्वारा दिये गए सुझाव फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा नियुक्त किये गये अन्तर्राष्ट्रीय दल ने सन् 1954 में निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिए।

1. देश के भिन्न भागों में चार बहुउद्देश्य तकनीकी मस्थान (Multipurpose Institute of Technology) की स्थापना की जाय। ये मस्थान लघु उद्योगों को व्यावसायिक प्रबन्ध, वित्त तथा विप्री सम्बन्धी सहाय प्रदान करेंगी।

2. नमूना सम्बन्धी एक राष्ट्रीय विद्यालय (A National School of Design) की स्थापना की जाय। इस मस्थान में कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए नए-नए नमूने तथा डिजाइन आदि के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान की जायेगी।

3. लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विप्री के लिए एक विप्री सेवा निगम (A Marketing Service Corporation) की स्थापना की जाय, जो लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विप्री व्यवस्था करे।

4. एक लघु उद्योग निगम (Small Industries Corporation) बनाया जाय। उत्पादन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी विकास के लिए प्रदर्शनार्थ छोटे-छोटे केन्द्रों को खोला जाय।

5 दो निर्यात सम्बर्द्धन कार्यालय (Export Promotion Office) खोले जाएं, जिनमें से एक उत्तरी अमरीका में तथा दूसरा यूरोप में खोला जाय।

सरकार ने इस दल की सिफारिशों के आधार पर बहु-उद्देशीय क्षेत्रीय तकनीकी संस्थाएँ, राज्य वित्त नियम, राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम और विपणन सेवा संगठन, आदि की व्यवस्थाएँ की हैं।

कर्षे समिति के सुझाव

प्रो० कर्षे की अध्यक्षता में ग्राम तथा लघु-उद्योग समिति (Village and Small Scale Industries Committee) ने सन् 1955 में अग्रलिखित सुझाव दिये

(i) लघु उद्योग सहकारिता के आधार पर स्थापित किये जाय, (ii) कर्म-विनियम समितियों को स्थापना की जाय, (iii) राष्ट्रीय सहकारी विकास व गोदाम नियम (National Co-operative Development and Warehousing Corporation) को लघु-उद्योगों की भी सहायता करनी चाहिए, (iv) स्टेट बैंक व रिजर्व बैंक द्वारा लघु-उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, (v) राज्य वित्त नियमों द्वारा लघु-उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना चाहिए, (vi) लघु-उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को ग्राम व लघु-उद्योग मंत्रालय की स्थापना करनी चाहिए, (vii) कुछ बड़े पैमाने पर चलने वाले कारखानों के उत्पादन की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, ताकि छोटे उद्योगों को भी बाजार प्राप्त हो सकें, (viii) बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन पर छप कर (cess) लगा कर इससे प्राप्त रकम को कुटीर व लघु-उद्योगों के विकास के लिए वर्ष क्रिया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय लघु उद्योग के सुझाव अखिल भारतीय लघु-उद्योग मण्डल (All India Small Scale Industries Board) ने अपनी बैठक में जुलाई, सन् 1966 में निम्नलिखित सिफारिशें की—(i) केन्द्र में एक वित्तीय संस्था, वित्त-सम्बन्धी समस्या की मुलम्माओं के लिए स्थापित की जानी चाहिए, (ii) दुर्लभ कच्चे माल की पूर्ति का 1/3 भाग लघु उद्योगों को दिया जाय (iii) लघु उद्योगों की पूर्वोन्नीमा 10 लाख रुपये रखी जाय, (iv) केन्द्रीय लघु-उद्योग संगठन (Central Small Scale Industries Organisation) को सुदृढ़ बनाने के लिए योग्य तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय, (v) लघु-उद्योग सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने के लिए लघु-उद्योगों की, राज्य के उद्योग निर्देशक से रजिस्ट्री कराना अनिवार्य बनाया जाय।

सरकार द्वारा कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए उठाये गये कदम

भारत सरकार ने वर्ष 1948 व सन् 1956 की औद्योगिक नीतियों में कुटीर व लघु उद्योगों के विकास पर समुचित बल दिया और देश के औद्योगीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निवारित की। इन उद्योगों के लिये निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य किए गये

(1) विविध मण्डलों की स्थापना यद्यपि कुटीर व लघु उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सामान्यतः राज्य सरकारों की है, तथापि इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिलाने के लिए भारत सरकार ने बहुत से बोर्डों की स्थापना की है, जिनके कार्य धन सहाय-सहाय हैं। ये बोर्डें सर्वोच्च स्तर उद्योगों के विकास का कार्यक्रम बनाने में सहायता देते हैं। ये बोर्डें निम्नलिखित हैं

(i) कुटीर उद्योग बोर्ड (Cottage Industries Board) इस बोर्ड की स्थापना लघु उद्योग के विकास के लिए लघु उद्योगों का सर्वेक्षण करने के लिए की गयी।

(ii) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (All India Khadi and Village Industries Board) यह बोर्ड जनवरी 1953 में स्थापित किया गया तथा सन् 1950 में खादी व ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्य करता है। इसके कार्यक्षेत्र में कई ग्रामोद्योग सम्मिलित हैं—यथा खादी तेल साबुन, बिनासलाई, गुट, मधुमक्खी-पालन आदि। प्रत्येक राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल भी इसी कार्य को सम्पादित करते हैं।

(iii) अखिल भारतीय हस्त शिल्प मण्डल (All India Handicrafts Board) इसकी स्थापना नवम्बर 1952 में की गई। 1958 में भारतीय हस्त-शिल्प विकास विभाग की भी स्थापना की गई। यह बोर्डें दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन तथा विप्री में वृद्धि करने की चटा करता है। इसने देश भर में 190 से अधिक बन्दार खोलकर शिल्प वस्तुओं की विप्री की व्यवस्था की है। इसने देश में 19 पाइलेट केंद्र खोले हैं, जिनमें प्रशिक्षण, अन्वेषण, परीक्षण आदि कार्य किये जाते हैं।

(iv) अखिल भारतीय हाथ करपा मण्डल (All India Handloom Board) हाथ करपा उद्योग के लिए सन् 1952 में इस बोर्ड की स्थापना की गई। इसने बुनकरों की सहायकी गतिवियों की स्थापना की है। इसने एक केन्द्रीय बाजार समिति (Central Marketing Organisation) भी बनाया है।

(v) केन्द्रीय विप्री मण्डल (Central Marketing Organisation)—सन् 1953 में इस सेवा की स्थापना की गई तथा इसका प्रधान कार्यालय मद्रास में

रपाईत किया गया। राज्य सरकारों को रवाई, बुलाई एवं स्थानांतर के लिए मिले-जुले कारखाने सोरने, आधुनिक औजारों की व्यवस्था करने और विक्री केन्द्र खोलने आदि के लिए आर्थिक सहायता दी गई।

(vi) लघु उद्योग मण्डल (The Small Scale Industries Board), अन्तर्राष्ट्रीय योजना विशेषज्ञ बल के सुझावों पर सन् 1954 में इसका गठन किया गया। यह मण्डल लघु-उद्योगों के विकास की योजनाएँ बनाता है, उन्हें लागू करता है तथा लघु-उद्योगों को प्राविधिक व अन्य सुविधाएँ देता है।

(vii) नारियल कटा मण्डल (The Coconut Board) यह सन् 1954 में गठित किया गया। यह नारियल की कटा से बनने वाली वस्तुओं को लोकप्रिय बनाता है। यह एक कारखाना भी खोलने जा रहा है, जिसमें नारियल की कटा से उत्तम कोटि की फरों बनाई जाएंगी।

(viii) केन्द्रीय रेशम मण्डल (Central Silk Board) : यह सन् 1949 में गठित किया गया था। यह रेशम उद्योग के अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है।

2. तकनीकी सहायता कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास में तकनीकी सहायता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तकनीकी सहायता के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं

(i) केन्द्रीय लघु उद्योग संस्थान (Central Small Scale Industries Institute) सरकार ने केन्द्रीय लघु उद्योग संस्थान की स्थापना की है, जो अपने सेवाओं (Service Institutes) एवं प्रसार केन्द्रों (Extension Centres) के माध्यम से प्रतिशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की व्यवस्था करता है। अनेक राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थानों (Small Industries Service Institutes) का जाल सा बिछा दिया गया है, जो छोटे उद्योगपतियों को नए लघु उद्योग स्थापित करने एवं उत्पादन बढ़ाने में तकनीकी सलाह देते हैं। इस समय भारतवर्ष में 19 लघु-उद्योग सेवा-संस्थान कार्य कर रहे हैं।

(ii) औद्योगिक प्रसार केन्द्र (Industrial Extension Centres) इनकी स्थापना तकनीकी सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए की गई है जिससे लघु उद्योग अपनी तकनीकी में सुधार कर सकते हैं।

(iii) क्षेत्रीय तकनीकी संस्थान (Regional Institutes of Technology) लघु उद्योगों को अपनी तकनीकी एवं प्रबन्ध में सुधार करने से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए देश में चार क्षेत्रीय तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई है।

(iv) नाना सम्बन्धी एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है, जो नए-नए डिजाइन बना कर उनका लघु उद्योग केन्द्रों में प्रदर्शन करता है, जिससे नई मशीनों का प्रयोग बढ़ाया जा सके।

(v) ग्रामोद्योग अनुसंधान संस्थान (Village Industries Research Institute) उत्पत्ति की तकनीक एवं ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित अनेक विषयों में अनुसंधान के लिए हमकी रक्षापना की गई है।

(vi) आविष्कार प्रोत्साहन मण्डल (Inventions Promotion Board) यह मण्डल हताश देवर व वित्तीय सहायता द्वारा विविधियों को आविष्कार करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

(vii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) इसकी स्थापना सन् 1955 में हुई। यह निगम लघु उद्योगों को निम्नो पर मशीनें दिये जाता है तथा व्यापक की दर बहुत कम ली जाती है। यह निगम सरकारी विभागों के लिए लघु उद्योगों द्वारा बनाए गए माल की खरीद की भी व्यवस्था करता है एवं आदेश के अनुसार सामान तैयार करने के लिए पूंजी आदि के रूप में सहायता देता है। इससे सम्बन्धित चार संस्थान, बम्बई, कलकत्ता, सद्दाम व दिल्ली में खोले गए हैं।

3 वित्तीय सहायता कुटीर एवं लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता दिलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं

(i) राज्य सरकारें उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम (State Aid to Industries Acts) के अन्तर्गत ऋण प्रदान करती हैं। द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में क्रमशः 13 व 17 करोड़ रु० इस नियमों के अन्तर्गत दिए गए। इन ऋणों की उपार्जनता सीमित है, क्योंकि इनकी धन राशि कम और शर्तें कड़ी हैं। (ii) सन् 1960 से बैंकों व अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा गारंटी दिला कर ऋण देने की इस व्यवस्था को रिजर्व बैंक चला रहा है, ताकि ये स्वयं बिना भय के लघु उद्योगों को ऋण दे सकें। (iii) सन् 19०6 में स्टेट बैंक लघु उद्योगों के विस्तार व विवेकीकरण के लिए सम्पत्तियों पर ऋण देता है तथा मशीनों के क्रय के लिए 'किस्त सात योजना' के अधीन सात सुविधाएं देता है। (iv) सन् 19०1 के राज्य वित्त अधिनियम के अधीन विभिन्न राज्यों में राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई है। ये निगम भी लघु उद्योगों को वित्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये निगम अच्छी सम्पत्ति पर 10 से 12 वर्ष तक के लिए सम्पत्तिका ऋण देते हैं जिससे स्थाई पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। (v) रिजर्व बैंक वित्त निगमों की पूंजी में हिस्सा लेकर व सहकारी तथा व्यापारिक बैंकों के माध्यम से लघु उद्योगों की वित्त

सम्बन्धी सहायता करता है, तथा (vi) औद्योगिक महकदमी समितियाँ निरूपणारों को वागान शर्तों पर ऋण सुविधा प्रदान करती हैं।

4 विपणन सुविधाएँ नवें समिति न मुचाव पर लघु स्तरीय एव बुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित माल को महकदमी ढन से बेचने के लिए विपणन समितियों व विपणन समी वी स्थापना की गई है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल को वित्री बदान के लिए विभिन्न स्थाना पर वित्री केन्द्र खोले गए हैं। अनेक राज्य सरकारों ने बड़े बड़े नगरों म बुटीर उद्योगों एव हस्तशिल्पो की दूबानें खाली हैं। सरकार अपने विदेशी दूतावायों तथा अन्य संगठनों द्वारा विदेशों मे प्रदर्शनियों का आयोजन करती हैं और केन्द्र खोलती हैं, ताकि इनके निर्माण मे दृढ़ि हो मके।

5 औद्योगिक वस्तियों का निर्माण लघु उद्योग बों के मुचाव पर सन् 1955 स राज्य सरकारों ने औद्योगिक वस्तिया (Industrial Estates) स्थापित करती प्रारम्भ की हैं। इन वस्तियों म भरचार भवन, घातावाह, फल, सजित आदि की सेबायें प्रदान करती हैं ताकि उद्योगों का प्रादशिक एव सतुन्वित विकास हो मके। ये वस्तिया 10 से 50 व 60 एकड़ तक के क्षेत्र मे फैली होती हैं। सरकार यह भूमि लेकर उसे ठीक करती है मन्वे वनबाती है तथा विभिन्न फंक्टरियों का निर्माण करती है। सरकार सापीय उपचार (Heat treatment), बिजली की भट्टियों (Electric furnaces) आदि जैसी समुक्त सेवाओं के लिए वर्कशॉप्स स्थापित करती है, नदोकि छोट वारखानों से इनका प्रबोध सम्भव नहा है। अमियों के निवास के लिए धरो की सुविधा भी प्रदान की जाती है। या तो य कैकिया सीध ही खरीद ली जाती है या किराया खरीद प्रणाली पर ली जाती है। अगस्त 1959 तक भारत मे कुल 501 औद्योगिक वस्तिया विभिन्न अवस्थाओं मे थी, किन्तु से 465 मे उत्पादन कार्य प्रारम्भ हा चुका था।

॥ राज्य सरकारों द्वारा सहायता उपसुक्त सुविधाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने बुटीर व लघु उद्योगों के विकास क लिए और भी कई अन्य काय किय हैं यथा (i) सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम के अन्तगत बह उद्योगों से प्राप्त उपकर छोट उद्योगों पर वय दिया जाता है (ii) लघु उद्योगों को करी म छूट तथा दरिबहत मय म रियायत दी जाती है (iii) सरकार कुछ चीजों की खरीद केवल लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की करती है, जैसे—सरकारी निम्न अणों के कर्म-धारियों के लिए यूनीफार्म खारी का ही बनाया जाता है। (iv) उत्पादन के कुछ क्षण सुरक्षित रख कर बुटीर एव लघु उद्योगों को कुछ समय के लिए सरक्षण दिया जाता है, (v) राज्य द्वारा आर्थिक सहायता (Subsidies) देकर लघु उद्योगों की सहायता की जाती है।

सामान्यतः लघु-उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी राज्यों में उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) तथा अन्य सहायक वित्तीय, विज्ञान एवं सांख्यिकीय संस्थाओं का गठन किया गया है। इन उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की मुख्य कार्य नीति निर्धारण करना, विकास कार्यक्रमों में तालमेल बँटाना तकनीकी सहायता विनियम, प्रशिक्षण विनियम तथा आर्थिक सूचना सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करना है।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कुटीर व लघु उद्योग

प्रथम योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीणों व लघु उद्योगों पर 43 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इस योजना के अन्तर्गत (i) कुटीर व लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई। (ii) विभिन्न उद्योगों की समस्याओं के निराकरण के लिए विविध मंडलों का गठन किया गया। (iii) कुटीर उद्योगों की वृद्ध उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने की व्यवस्था की गई। (iv) दस नुवने हुए ग्रामीण उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। (v) वृद्ध उद्योगों पर उप-कर लगाए गए। (vi) सहकारी सप्लाई, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि पर धन दिया गया था।

द्वितीय योजना द्वितीय योजना में 175 करोड़ रुपये खर्च किये गए। सरकार ने इस योजना में कर्ब समिति की मुख्य सिफारिशों पर अमल करने की चेष्टा की। इस योजना में उद्योग-विस्तार-सेवा तथा राज्यों में लघु उद्योग सेवा मण्डलों स्थापित की गयी। 66 औद्योगिक वस्तियों का निर्माण किया गया, इनमें शक्ति या प्रयोग करने वाले लगभग 1,000 लघु-स्तरीय कारखाने खुले।

इस योजना में कुटीर व लघु-उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए योजना आयोग ने कहा था, "द्वितीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार देना है। छोटे पैमाने के तथा ग्रामीण उद्योगों के द्वारा अधिक अवसरों का काम मिलता है। उनकी ही पूँजी लगा कर इन उद्योगों में बड़े उद्योगों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्ति खपाये जा सकते हैं। ग्रामीणों की अर्थ-व्यवस्था का अधिक संतुष्टि तथा समन्वित विकास हो पाता है।"

इस योजनाकाल में कई छोटे उद्योगों, जैसे—मनीनी जीन्सर, धुलाई मशीनें, दिक्कली के पक्षी, मोटरों, इमारती सामान और अन्य औजारों सम्बन्धी उद्योगों में विशेष वृद्धि हुई।

तृतीय योजना तृतीय योजना में अप्रलिम्बित क्षेत्रों में प्रयत्न करने के कार्य-क्रम रखे गए थे

1. उत्पादन में सुधार कर उत्पादन लागत घटाना ।
2. अधिक सहयोगता, अनुदानों, सुरक्षित बाजार आदि की व्यवस्था करना ।
3. गाँवों एवं कस्बों में इन उद्योगों का विकास करना ।
4. लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के सहयोग के रूप में विकसित करना ।
5. कारीगरों को सहकारी ढंग पर संगठित करना ।

तृतीय योजना तृतीय योजना में इन उद्योगों पर 241 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इन उद्योगों में 63 लाख व्यक्तियों को पूर्णकालीन रोजगार तथा 80 लाख व्यक्तियों को आंशिक तथा अर्द्ध-रोजगार दिलाया गया। जूते, चमड़े, वाहनिकल, सिलाई की मशीनों विज्ञानों के पत्रों, हाथ के औजारों, रथ, वाणिज्य, साधन आदि के उत्पादन में इस योजनाकाल में 25 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम ने 1965-66 में 244 करोड़ रुपये के मूल्य की 16,000 मशीनें दिलवाईं। इस योजना के अंतर्गत इन उद्योगों के निर्माण में भी वृद्धि हुई। 1960-61 की तुलना में निर्यात 25 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1965-66 में 54 करोड़ रुपये के बराबर हो गया।

वार्षिक योजनाओं में इन उद्योगों पर 132 करोड़ रु व्यय किए गए।

चतुर्थ योजना (1969-74) इस योजना में सरकारी क्षेत्र में ग्राम एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए कुल 293 करोड़ रुपए की धन व्यवस्था है। इस योजनावधि में निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 560 करोड़ रुपए की पूंजी लगाए जाने की आशा है। चौथी योजना के कार्यक्रम के उद्देश्य हैं (क) लघु उद्योगों की उत्पादन तकनीकी का तेजी से विकास करना, (ख) उद्योगों के फैलाव और विविधीकरण को बढ़ावा देना तथा (ग) कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना।

इस योजनावधि में कुटीर एवं लघु उद्योगों सम्बन्धी अनुसंधान सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी, उत्पादन तकनीक विकसित की जाएगी, डिजाइन को उन्नत बनाया जाएगा और औद्योगिक विस्तार सेवाओं तथा परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा जाएगा। अके-बड़े सहयोग में दम्पकारी केन्द्र खोले जाएँगे। निर्यात का माल तैयार करने वाले कारखानों को ऋण एवं कच्चे माल की सुलझाई में प्राथमिकता दी जाएगी।

हाथकरघा, शक्ति चालित करमा और खादी उद्योगों में फिन्हाल अनुमानित 33,500 लाख मीटर सूती कपड़े के उत्पादन में वृद्धि होकर चौथी योजना के अन्त तक 42,500 लाख मीटर तक हो जाने की आशा है। हाथकरघा उत्पादन का निर्यात मूल्य 1967-68 में लगभग 9 करोड़ रुपये रहा और 1973-74 तक इसके लगभग 15 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान है। नारियल जटा उद्योग का निर्यात मूल्य, जो 1967-68 में लगभग 13 करोड़ रुपए का था, 1973-74 तक बढ़कर लगभग 17 करोड़ रुपए हो जाएगा।

चतुर्थ क्रोडना में, हाथकरघे एवं शक्ति चालित करघे पर 42.98 करोड़ रु., खादी एवं ग्रामोद्योग पर 96.43 करोड़ रु. तारियल जटा उद्योग पर 4.42 करोड़ रु., रेशम के कीड़े पालने के उद्योग पर 19.37 करोड़ रु., हस्तशिल्प पर 14.52 करोड़ रु., औद्योगिक संस्थानों पर 13.15 करोड़ रु. तथा सामोद्योग सम्बन्धी कार्य-कला पर 5.10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस प्रकार इस योजना अवधि में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर 293 करोड़ रु. व्यय किए जाने का अनुमान है।

भारतवर्ष के कुछ प्रमुख कुटीर व लघुस्तरीय उद्योग—भारतवर्ष के कुछ प्रमुख कुटीर व लघु उद्योग अवलिखित हैं -

(1) **हाथकरघा व खादी उद्योग** यह उद्योग देश का प्रमुख कुटीर व लघु स्तरीय उद्योग है। इस उद्योग में लगभग 24 लाख करघे हैं तथा 140 लाख व्यक्ति काम करते हैं। यह उद्योग देश के कुल रूपड़े की मात्रा के $\frac{1}{5}$ मात्रा की पूर्ति करता है। इस उद्योग के प्रमुख पैदाइश-वस्त्रात्त, इटावा, बनरोहा, टोडा, मऊ, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश), चन्देरी (म० प्रदेश), कर्नाटक (महाराष्ट्र), कोयंबटूर (महाराष्ट्र) तथा रांगपुर।

2 **तारियल की जटा का उद्योग (Coar Industry)** इस उद्योग में लगभग 1 लाख शक्ति कार्य कर रहे हैं। यह उद्योग प्रति वर्ष 182 लाख टन तारियल जटा की रस्सी बनाता है यह उद्योग मुख्यतः केरल में केन्द्रित है। इस उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात करके भारतवर्ष विदेशी विनिमय (10-12 करोड़ रुपये का) प्राप्त करता है।

3 **गुड़ व खण्डितारी उद्योग** यह उद्योग बिहार व उत्तर प्रदेश में मुख्यतः केन्द्रित है। हमारे देश में गन्ने के रस से गुड़ व खण्डितारी बनाया जाता है। खजूर के रस से भी गुड़ बनाया जा रहा है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 80 से 100 लाख टन गुड़ बनाया जाता है। इसे किमान सहायक उद्योग के रूप में अपनाते हैं।

4 **तेल पेंचों का उद्योग** भारत में तिलहन बहुत बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है तथा निर्यात भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घनी द्वारा तेल पैदा जाता है। महुरी में इस छोटे-छोटे कारखानों में लघु उद्योग के रूप में चलाया जाता है।

5 **रेशम उद्योग** यह उद्योग 35 हजार व्यक्तियों की पूर्ण रोजगार तथा 27 लाख व्यक्तियों की अर्द्ध-रोजगार विद्यता है। भारत में प० बंगाल, अजमम, जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में यह उद्योग चलाया जाता है। भारत सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए कई अनुसंधान केन्द्र खोले हैं। इस उद्योग से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने के लिए 4 प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थायें भी खोली गई हैं।

6 **बीडी-सियरेट उद्योग** भारत विश्व के तम्बाकू उत्पादन का $\frac{1}{3}$ भाग पंदा करता है। इस उद्योग में लगभग 5 लाख लोग कार्य करते हैं। भारतवर्ष में महाराष्ट्र, मद्रास, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मैसूर आदि राज्यों में बीडी उद्योग चलाया जाता है। कलकत्ता, बम्बई, महारनपुर, मुंभेर, बगलीर आदि सियरेट बनाने के मुख्य केन्द्र हैं।

7 **बमड़े का उद्योग** भारतवर्ष में विश्व के सर्वाधिक पछ पाये जाते हैं। इनके मरने पर इनके बमड़े के बूते व अन्य कई सामान कुटीर व लघु उद्योग में बनाये जाते हैं। आगरा, कानपुर, मन्नान, दिल्ली, अमृतसर आदि बूते व बमड़े की अन्य वस्तुओं के बनाने के केन्द्र हैं।

8 **अन्य उद्योग** भारत में अन्य बहुत से कुटीर व लघु उद्योग पाये जाते हैं यथा—बरेली होसियारपुर, कर्तारपुर में लकड़ी का फर्नीचर, मेरठ एवं जालपर में लकड़ी के लक के सामान, मैसूर में चन्दन की लकड़ी तथा काश्मीर में अखरोट की लकड़ी पर खुदाई का बहुत नवीक काम किया जाता है। पीतल, तांबा, कासा व चांदी के बर्तनों के उद्योग मुरादाबाद, मिर्जापुर, बनारस, हावरा, हरदोई, फतेहाबाद आदि स्थानों में पाये जाते हैं। इन उद्योगों के अतिरिक्त झेकरी का काम, तास व बेंत का काम, छपाई, कढ़ाई, नुनाई, कोंच का सामान, बाद्य-वृन्द बनाने, फलों को सुरक्षित पैक करने आदि से सम्बन्धित लघु उद्योग आदि भी हमारे देश के विभिन्न भागों में चलाए जाते हैं।

उपसंहार

भारतवर्ष में कुल रजिस्टर्ड कारखानों में से 40,000 कारखाने बर्मान् 91.6% कारखाने लघु पैमाने पर चलाये जा रहे हैं। इनमें लगभग 14.37 लाख लोगों को काम मिला हुआ है इन उद्योगों में लगभग 292 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है, जो कुल निर्माण उद्योग पूंजी का 2.28% भाग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में इन उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योग चाहें बड़ा हो या छोटा, आज के युग में सफलता उद्योग की भित्त साक्षी है, जिसका माल अच्छी किस्म का हीगा तथा अन्य उत्पादकों के साथ होड़ में टिक सकेगा। अतः आवश्यकता इस बात की है लघु उद्योगों का पुनर्संगठन एवं आधुनिकीकरण किया जाय। कुटीर उद्योगों के मार्ग की सभी बाधाएँ हटा कर उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पुनः जीवित किया जाय। केन्द्रीय व राज्य सरकारें इन उद्योगों के प्रति अपना दायित्व निभाने की चेष्टा कर रही है। यह दिन दूर नहीं, जब ये उद्योग पुनः अपने सौमे हुये प्राचीन वैभव को प्राप्त कर सकेंगे। कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रबल समर्थक राष्ट्र पिता बापू न केवल ही कह पा

'I have no doubt in my mind that we add to the national wealth if we help the small scale industries True swadeshi consists in encouraging and reviving home industries That alone can help the dumb millions

प्रश्न

1 भारतवर्ष में लघु उद्योगों के विकास का वर्णन करते हुये बताइये कि क्या वे समृद्ध हुये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? इसका कारण बताइये ।

(राज प्रथम वर्ष टी डी सी कला 1968)

2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—'भारत में ग्रामीण उद्योगों का महत्व' ।

(राज प्रथम वर्ष टी डी सी कला 1967)

3 भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है ? इनके उचित विकास के मार्ग में मुख्य बाधाओं का उल्लेख कीजिये ।

(राज प्र वर्ष टी डी सी कला 1964)

4 भारत में कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले वर्तमान साधनों को बतलाइये । उनकी कमी को पूरा करने के सुझाव दीजिए ।

(राज बी ए 1963)

5 भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर उद्योगों के विकास का क्या महत्व है ? इन वर्षों में इनके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

(राज बी ए 1961, 62, 64)

भारत में औद्योगीकरण

(Industrialisation in India)

"The industrial programme for the Fourth Plan has to keep in view the objectives of development of backward regions and dispersal of industries with due regard to technical and economic considerations"

—A Draft Outline of Fourth Five-Year Plan.

आधुनिक ढंग के औद्योगीकरण का योगदान भारतवर्ष में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ था। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता एवं अपेक्षापूर्ण नीति के कारण उद्योगों की प्रगति अपने प्रारम्भिक चरण में बहुत धीमी रही। वस्तुतः उद्योगों के विकास की प्रक्रिया केवल प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ही प्रारम्भ हुई। 1929 की महान मंदी, जिसमें सम्पूर्ण विश्व की अर्थ-व्यवस्था को हिला दिया, भारतीय उद्योगों के मरलाप मिला जाने के कारण जीवित बने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध ने औद्योगीकरण विकास में नई चेतना का संचार किया। लेकिन उस समय तक भी भारतीय उद्योगों का विकास देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर नहीं किया गया था। देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् ही देश की लोकप्रिय सरकार ने पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत बड़े उद्योगों के विकास की आधारशिला को मजबूत बना कर उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। बत वर्षों में नियोजित ढंग से औद्योगिक विकास का परिणाम यह हुआ है कि देश में कुछ उद्योगों ने बड़ी तीव्र गति से उन्नति की है। आज भारतवर्ष के कुछ बड़े पैमाने के उद्योग विधास की उस सीमा तक पहुँच रहे हैं, जहाँ उनकी तुलना सत्तार के अन्य औद्योगिक राष्ट्रो से की जा सकती है।

इस अन्वय के अन्तर्गत हम देश के कुछ प्रमुख उद्योगों के विकास, उनकी समस्याओं व उनकी वर्तमान स्थिति का अवलोकन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि वर्तमान समय में औद्योगिक विकास के रास्ते में, हमारे देश में, क्या-क्या काहटें

हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है तथा सरकार इस दिशा में क्या-क्या कदम उठा रही है। भारत का औद्योगिक गतीव बिश्व-विख्यात था। भारत जब तक अपने उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करके औद्योगिक मानचित्र पर अपना नाम नहीं अंकित कर देता, तब तक उसे अपनी प्रगति की गति छिपित नहीं करनी है।

1. लोहा व इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry)

परिचय

लोहा व इस्पात उद्योग, आधारभूत उद्योगों में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा किसी भी देश का आर्थिक बिनास बहुत कुछ इस उद्योग पर ही निर्भर करता है।¹ कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार के साधन तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली सैकड़ों वस्तुओं के निर्माण के लिए लोहा व इस्पात बहुत आवश्यक है। लोहे की उपयोगिता एवं महत्व में अंग्रेज नवि वर्णवर्णन ने ठीक ही कहा है, “लोहा महल की रानी के लिए आवश्यक है, चांदी महल की दासी के लिए और तबिया प्रत्येक कारीगर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन लोहा देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।” सच तो यह है, लोहा व इस्पात उद्योग न केवल औद्योगिक आधारशिला के लिए ही आवश्यक है, बल्कि वर्तमान सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की आधारशिला के लिए जरूरी है। भारतवर्ष में लोहे व इस्पात उद्योग के विकास की सम्भावनाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि इन उद्योग के विकास के लिए हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है। देश में 2,100 करोड़ टन लोहे के भंडार हैं। जूना, पश्चर, मैंगनीज व कोलमाइट जैसी धातुओं की भी प्रचुरता है। कोयले की खानें भी निकट हैं। एक गिनाकर देश की स्थिति लोहे व इस्पात उद्योग के विकास के लिए सार्वभौम है।

उद्योग का विकास (Development of Industry) . भारतवर्ष में लोहे व इस्पात के उद्योग का विकास बहुत पहले ही शुरू था। प्रो. बिस्मिल के मतानुसार, “लोहे की ढलाई इंग्लैण्ड में तो थोड़े ही दिनों से प्रारम्भ हुई है, लेकिन भारतवासी लोहे गलाने व इस्पात बनाने की कला का ज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल से रखते हैं।” ईसा से 300 वर्ष पूर्व दिल्ली में स्थापित अशोक की स्तूप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

भारत में आधुनिक ढंग से लोहा बनाने का प्रयास सन् 1830 व 1875 ई में किए गए थे। 1830 में जोशिया मार्शल हीथ (Joshua Marshall Heath) ने मद्रास के पास लोहे बनाने के कारखाने के लिए असफल प्रयत्न किया था। सन्

1. Knowles Industrial and Commercial Revolution during the 19th Century, p 17.

1875 में बंगाल में बाराकर आयरन वर्क्स (Barakar Iron Works) की स्थापना की गई, लेकिन यहाँ केवल लोहा ही बनाया जा सकता था, इस्पात नहीं।

नाटिया व मर्वेन्ट के अनुसार, भारतवर्ष में चौथी व पाँचवी शताब्दी में भी टिकाऊ व मुन्दर लोहे की वस्तुओं का उत्पादन होता था तथा ये वस्तुमें विदेशों को पर्याप्त मात्रा में निर्यात की जाती थी।¹ आधुनिक युग में इस उद्योग का वास्तविक प्रारम्भ सन् 1907 ई. में माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष बिहार में राबो नागक स्थान पर श्री जमशेद जी टाटा ने 'टाटा आयरन व स्टील कम्पनी' की स्थापना की थी। इससे सन् 1911 व सन् 1913 में क्रमशः बच्चा लोहा व स्टील का उत्पादन प्रारम्भ किया। प्रथम विश्व युद्ध से इस उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला। उत्पादन तथा माग दोनों में ही वृद्धि हुई। बढ़ती हुई माँग की पूर्ति करने के लिए टाटा आयरन व स्टील वर्क्स का विस्तार किया गया तथा सन् 1918 में बंगाल में आसनसोल के पास हरीपुर में 'इन्डियन आयरन व स्टील कम्पनी' की स्थापना की गयी। सन् 1923 में भद्रावती नामक स्थान पर एक और लोहे व इस्पात का कारखाना चालू किया गया, जिस भाषणल 'मैसूर आइरन व स्टील वर्क्स' के नाम से जाना जाता है।

1922-23 में इस कारखाने को कड़ी विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सन् 1924 में इस उद्योग को सुरक्षण प्रदान किया गया, जो 31 मार्च, 1947 तक चालू रहा। 1939 में 'स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल' की स्थापना बर्नपुर में की गयी। द्वितीय विश्व युद्ध में इस उद्योग का समुचित विकास हुआ, पर युद्ध समाप्त हो जाने के बाद ही इसे सकटों में धेर लिया। सन् 1946 में भारत सरकार द्वारा एक 'स्टील पैनल' (Steel Panel) की नियुक्ति की गयी, जिसने यह सुझाव दिया कि यदि किसी उद्योगपति विधार्थित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो तो सरकार को सामंजसिक शेष में लोहे व स्टील कारखाने खोलने चाहिये।

सन् 1947 तक भारतीय लोहे व इस्पात उद्योग की क्षमता बहुत कम थी, यद्यपि इस्पात व लोहे की बनी हुई वस्तुओं की माँग बहुत थी। लोहे व इस्पात की वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए इसका विदेशों से आयात करना पड़ता था। आयात मूल्य भारत में उत्पादित मूल्य की अपेक्षा अधिक हुआ करता था।

इस उद्योग में सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारतवर्ष में निम्न-लिखित तीन बड़े कारखाने थे (1) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर (TISCO), (2) स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल, बर्नपुर (SCOB)²; तथा (3) मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती।

1. Wades and Merchant Our Economic Problems, p. 379

२. इसे बाद में 1953 में बर्नपुर की स्थितिवन आयातक एण्ड स्टील कम्पनी में विभा दिया गया।

योजनाओं के अन्तर्गत सोहरा व इस्पात उद्योग का विकास सन 1948 में भारत सरकार ने अपनी पड़ोसी औद्योगिक नीति धोषित की, जिसमें भविष्य में लोहे व इस्पात उद्योग का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में करने का प्रावधान किया। प्रथम योजना में इस उद्योग के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था तथा 17 लाख टन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इसी योजना में 10 लाख टन क्षमता वाले 3 बड़-बड़े कारखानों की स्थापना सम्बन्धी कार्य की भी अंतिम रूप मिल चुका था। ये तीनों कारखाने राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्य प्रदेश) व दुर्गापुर (व. बंगाल) में क्रमशः जर्मनी, रूस व ब्रिटेन की सहायक व तकनीकी सहायता से स्थापित किये जाने थे। इस योजना में पहले से ही स्थापित लोहे व स्टील उद्योगों की भी विकसित किया गया। चूँकि यह योजना मुख्यतः कृषि प्रधान थी, अतः उद्योगों के विरास के लिए कुछ अधिक प्रयत्न नहीं किए जा सके। लोहे व इस्पात के उत्पादन में केवल थोड़ी सी वृद्धि हुई, जो कि 1951-52 में 10 लाख टन से बढ़ कर 1955-56 में 12 लाख टन पहुँच गया।

द्वितीय योजना में इस उद्योग के विकास के लिए 431 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया तथा 43 लाख टन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों ने इस योजना में उत्पादन शुरु कर दिया था। यह कारखाने राउरकेला (उड़ीसा) में जर्मन, भिलाई (मध्य प्रदेश) में इसी तथा दुर्गापुर (बंगाल) में ब्रिटिश सहायता से स्थापित किए गए। इनमें से प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता 10 लाख टन थी। सार्वजनिक क्षेत्र में इन कारखानों के चालू करने के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों की वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दिला कर उनके विस्तार को प्रोत्साहित किया गया। टाटा मापरन व स्टील ने अपनी तैयार इस्पात की क्षमता 8 लाख टन से बढ़ा कर 15 लाख टन की। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी ने तैयार इस्पात की क्षमता 11 लाख टन तथा मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स ने 85,000 टन तक अपनी क्षमता कर ली। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों के सम्मिलित उत्पादन का लक्ष्य 30 लाख टन था, जबकि इनका वास्तविक उत्पादन 1960-61 में 6 लाख टन ही हुआ। इन तीनों इस्पात कारखानों का प्रबन्ध सरकारी प्रमुखता हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत कर दिया गया। सन् 1960-61 में इस्पात का कुल उत्पादन 24 लाख टन था, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रह गया।

तृतीय योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य 92 लाख टन रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों की क्षमता दूनी कर देने का निर्णय लिया। 10 लाख टन क्षमता वाले एवं नव कारखानों को बाजारों में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना में उत्पादन लक्ष्य थे—इस्पात के टोके 92 लाख

टन, तैयार इस्पात 68 लाख टन। इस योजना में इस्पात विस्तार के कार्यक्रम पर 525 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस्पात विस्तार के कार्य का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग 20 लाख टन मिश्रित (alloy) व विशेष इस्पात (Special Steel) बनाने की योजना थी, क्योंकि ये इस्पात मूल्यवान होते हैं तथा इनके उत्पादन से विदेशी मुद्रा में काफी वृद्धि की सम्भावना होगी है।

तृतीय योजना में इस उद्योग की प्रगति सतोषजनक नहीं रही। सन् 1965-66 में इस्पात ढोको का उत्पादन 65 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन केवल 45 लाख टन ही रहा। सन् 1970-71 में इस्पात ढोको का उत्पादन 61 लाख टन हुआ तथा 79 करोड़ रुपये का ढोका व इस्पात विदेशों को निर्यात किया गया।

17 अप्रैल, 1970 को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सांतेम (हमिलनाडु), होसपेट (मैसूर) तथा विशाखापत्तनम (आन्ध्रप्रदेश) में मिनी स्टील प्लांट लगाने की घोषणा की। यह तीनों कारखाने भारतीय इंडीयनरो द्वारा लगाए जायेंगे।

भविष्य के कार्यक्रम इस्पात उद्योग की वर्तमान क्षमता को बढ़ा कर 1973-74 तक 120 लाख टन कर देने का लक्ष्य है तथा उत्पादन का लक्ष्य 108 लाख टन इस्पात है। कोकाशे स्टील लि० जनवरी 1964 में स्थापित की गयी, जिसका कि प्रथम चरण 1974 में पूरा होने की आशा है, जोचित रूप की सहायता से बनाया जा रहा है। कोकाशे कारखाने की प्रारम्भिक क्षमता 15 से 20 लाख टन होगी, जिसे बाद में 40 लाख टन तक बढ़ाया जा सकेगा। भिलाई की वर्तमान 20 लाख टन की क्षमता को 35 लाख टन तथा दुर्गापुर की वर्तमान 16 लाख टन की क्षमता को बढ़ाकर 34 लाख टन करने का लक्ष्य है। कर्कला की उत्पादन क्षमता 25 लाख टन हो जायेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की भी विस्तार प्रदान किया जायेगा। टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी व इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी की उत्पादन क्षमता क्रमशः 20 व 10 लाख टन से बढ़ाकर चौथी योजना के अन्त तक क्रमशः 30 व 13 लाख टन कर दी जायेगी।

अर्सेनाल स्थिति इस समय भारतवर्ष में कोइलेर इस्पात के ऊँचे कारखाने उत्पादन में है, जिसमें से टाटा आयरन व स्टील कम्पनी निजी क्षेत्र में है तथा बाकी पांच कारखाने इण्डियन आयरन व स्टील कम्पनी (जिसे सरकार ने 1972 में अपने हाथ में लिया), मैसूर आयरन व स्टील वर्क्स तथा राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर के कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। बिहार में कोकाशे नामक स्थ रचना

रूसी सरकार की सहायता से सीमा लीड व इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जिसका प्रारम्भिक निर्माण कार्य मई 1968 से प्रारम्भ हो चुका है। सरकारी क्षेत्र में बोकरो के अतिरिक्त तीन मिनी स्टील प्लांट खार्बेन, हास्पेट तथा विशाला-पटनम में भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन बड़े-बड़ कारखानों के अतिरिक्त देश में कई छोटे-छोटे कारखाने भी चल रहे हैं। यद्यपि भारत ने विगत कुछ वर्षों से इस्पात उद्योग के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। तथापि विश्व के इस्पात उत्पादन करने वाले देशों में इसका 13 वा स्थान है। भारत में कुल विश्व के इस्पात का केवल 1.42% इस्पात ही पैदा किया जाता है। प्रति व्यक्ति उपयोग की दृष्टि से भी भारत का स्थान 36 वा है। जबकि अमेरिका में प्रति वर्ष 488 किलोग्राम, रूस में 334, पश्चिमी जर्मनी में 428, जापान में 252 किलोग्राम है, भारत में केवल 14 किलोग्राम है।

उद्योग की समस्याएँ एवं सुझाव लोहे व इस्पात उद्योग को वर्तमान समय में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें प्रमुख निम्न लिखित हैं।

1. अच्छे कोयले की कमी भारतवर्ष में लोहे को चलाने के लिये भयंकर कोयले की कमी है। इस कमी के कारण इस्पात उद्योग की अभावविधा होती है। इस सम्बन्ध में कोयले की दुलाई व दूर से अच्छे कोयले को लाने के लिये दुलाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

2. तकनीक व प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव इस उद्योग के लिये उच्च कोटि की तकनीकी व प्रशिक्षित कर्मचारी देश में नहीं मिल पाते। फलस्वरूप बहुत अधिक वेतन देकर विदेशों से इन्हे बुलाना पड़ता है। लेकिन यह समस्या भी धीरे-धीरे हल हो जायेगी, क्योंकि देश में ट्रेनिंग स्कूल व इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना हो गई है। विदेशों से भी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आ रहे हैं।

3. परिवहन की कठिनाई हमारे देश में कच्चे लोहे को इस्पात के कारखानों में पहुँचाने के लिये सस्ते, सुगम, पर्याप्त व द्रुतगामी माध्यम नहीं है। रेलों के विकास व कारखानों तक सीढ़री लाइन बिछाकर यह समस्या हल की जा सकती है।

4. इस्पात के मूल्य निर्धारण की समस्या भारतवर्ष में इस्पात की मांग उत्पादन से अधिक है। परिणामस्वरूप इसका आयात किया जाता है। आयात किया हुआ इस्पात महंगा पड़ता है, जब सरकार उपभोक्ता की आवाज दरो-पर ही माल बेचती है और होने वाले लाभ को, एक समताकोष के माध्यम से, इस्पात के कारखानों के आयुष्मिकीकरण पर खर्च करती है। इस प्रकार निश्चित किया हुआ मूल्य परिवर्तित

होता रहता है, जिससे असुविधा होती है। आत्म-निर्भरता की स्थिति में यह समस्या स्वतः दूर हो जायेगी।

5. **पूँजी का अभाव :** लोह व इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है जिसमें कारखाना लगाने के लिए बहुत पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। इस्पात का एक छोटा कारखाना लगाने में भी 150 से 200 करोड़ रुपये की पूँजी लग जाती है। पुराने कारखाने में अभिनवीकरण के लिए भी बहुत पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भारत में पूँजी की कमी है, इसलिए इस उद्योग का तेजी से विकास नहीं हो सका। पूँजी के अभाव के कारण ही इस उद्योग के कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशों से सहायता लेकर स्थापित किए जा रहे हैं।

उपयुक्त कठिनाइयों के अलावा इस उद्योग के सामने कुछ अन्य समस्याएँ भी हैं, जैसे—मजदूरों की अविद्यता, कम एन पूँजी के मध्य सततपूर्ण सम्भव विवेकीकरण व आधुनिकीकरण का अभाव, निजी क्षेत्र के प्रति सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति आदि। वृ कि देश के आर्थिक विकास में लोह व इस्पात उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, अतः इन उद्योगों की सभी कठिनाइयों एवं समस्याओं को यथा सीमा दूर किया जाना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में लोहा व इस्पात उद्योग बिनो-दिन उन्नति करता जा रहा है। प्राकृतिक सुविधाओं की देखते हुये वह कल्पना की जा सकती है कि भारतवर्ष निरन्तर भविष्य में ही इस उद्योग में आत्म-निर्भर हो जायेगा। स्टील उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार एक नई नीति अपनाने जा रही है। जिसके अन्तर्गत उद्योग के सदस्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी। सरकार विदेशों में उन्नतकोटि के तकनीकी जानकारी की सेवाओं से भी लाभ उठाने की योजना बना रही है।

सूती वस्त्र उद्योग

(Cotton-Textile Industry)

श्री इकानेन का भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में कथन है कि "भारत का सूती-वस्त्र उद्योग देश के अतीत का गौरव, वर्तमान और भविष्य का सम्बन्ध, किन्तु सदैव आशा की वस्तु रहा है।"¹

सूती-वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। प्राचीन काल में ही भारत इस उद्योग के लिए काफी विख्यात रहा है। इस बात का प्रमाण द्वारा दौत-

1. "For India cotton manufacture is ancient glory, past and present tribulation but always a hope."

हात है। आधुनिक संदर्भ में यह उद्योगहमारे देश में लघुमग डेढ सौ वर्ष पुराना है। इन उद्योग ने अपने इस छोटे से जीवन काल में कई प्रकार के उत्तार चढाव देखे हैं। वर्तमान समय में भी यही उद्योग देश के सर्गज्ज्ञ उद्योग में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी, विश्व के प्रथम पाँच सूती-वस्त्र उत्पादन करने वाले देशों में, भारतवर्ष का स्थान काफी ऊँचा है। भारत विश्व के कुछ सूती वस्त्र-उत्पादन का 14% भाग पैदा करता है। जापान के पश्चात् नियतिक देशों में भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तथा उत्पादक देशों में अमेरिका के पश्चात् इसका पहला स्थान है। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग न केवल हमारी विशाल जनसंख्या की कपड़े की आवश्यकताएँ ही पूरी करता है, वरन् बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमाने में भी यह काफी सहायक है। भारतवर्ष में सूती-वस्त्र-उत्पादन दो तरह से किया जाता है—कुटीर व छोटे उद्योग के रूप में तथा बड़े पैमाने के रूप में। कुटीर उद्योग के रूप में, भारत में सूती-वस्त्र उद्योग का अतीत बहुत गौरवमय था। बड़े उद्योग के रूप में इसका विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही प्रारम्भ हुआ।

संक्षिप्त इतिहास : आधुनिक ढंग के सूती-वस्त्र उद्योग का प्रारम्भ सन् 1818 ई० से माना जा सकता है, जबकि कलकत्ता में प्रथम मिल स्थापित हुई। लेकिन वास्तविक विकास की दृष्टि से यह उद्योग केवल सन् 1854 ई० से भारतवर्ष में विकसित हुआ, जबकि पम्बई में कई सूती मिलों की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध में इन उद्योग को विकसित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किन्तु युद्धोपरान्त अनेक समस्याएँ माने से, जैसे—हड़ताल, विदेशों से विशेषकर जापान से प्रतिस्पर्धा, मूल्यों में उच्चावचन, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन आदि के कारण उद्योग पर बुरा भरण पड़ा। उद्योग के सर्वांगीण विकास की ध्यान में रखते हुए 1927 में संरक्षण प्रदान किया गया।

सन् 1927 ई० से लेकर 1947 ई० तक इन उद्योग की सरकारी संरक्षण प्राप्त रहा। संरक्षण के अन्तर्गत इस उद्योग ने बड़ी तेजी से प्रगति की। देश में विविध प्रकार के सूती वस्त्र तैयार होने लगे तथा वस्त्रों के उत्पादन में गुणात्मक सुधार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने के समय भारत वस्त्र सम्पन्धी अपनी आवश्यकता का 10 प्रतिशत भाग विदेशों से भगाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह उद्योग अपनी उन्नति को चरण सीमा पर पहुँच गया। एक ओर तो जापान से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई तथा दूसरी ओर मित्र देशों की सेनाओं के लिए बहुत अधिक आर्डर प्राप्त हुए। वस्त्र सम्पन्धी भाग बढ़ गई, फलस्वरूप उत्पादन भी बढ़ गया। 1939 से 1944 के मध्य वस्त्रों के मूल्यों में लगभग पाँच गुनी वृद्धि हो गई। फलस्वरूप 1943 में उत्पादन तथा वितरण नियमित किया गया। सन् 1947 ई० में देश का

विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतवर्ष व पाकिस्तान के हिस्से में क्रमशः 380 व 14 मिलें आईं। सन् 1947 ई० में कपास उत्पादन करने वाला 40 प्रतिशत भाग पाकिस्तान में चले जाने के कारण, इसी वर्ष सूती वस्त्र पर से तरक्षण हटा लिए जाने के कारण, सन् 1949 ई० में कपड़े के अवमूल्यन के कारण तथा सन् 1950 ई० में हड़तालों की लहर के कारण यह उद्योग कठिनाई में रहा।

प्रथम योजना : सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कार्यक्रम का शुभारम्भ सन् 1950-51 में प्रथम योजना के विकास के साथ हुआ। उस समय देश में 388 सूती बरत मिलें थी, जिनमें 109 काज तकुए और 194 शाल करघे थे। सूत का उत्पादन 118 करोड़ पौण्ड था तथा वस्त्र उत्पादन 372 करोड़ गज था। योजना के अंत में 1955-56 ई० तक सूत का उत्पादन 164 करोड़ पौण्ड तथा कपड़े का उत्पादन 510 करोड़ गज हुआ। इस प्रकार योजनावधि में सूत के उत्पादन में 38.5 प्रतिशत तथा कपड़े के उत्पादन में 37.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति वस्त्र की क्षमता 1950-51 ई० में 11.8 गज से बढ़ कर 1955-56 ई० में 16.5 गज हो गई। उत्पादन में वृद्धि के कई कारण थे, जैसे—कपास की उपलब्ध में वृद्धि, कपड़े के वितरण, मशीनों तथा उत्पादन पर निपटण्य का हटाया जाना व सरकार द्वारा कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन आदि। इस योजनावधि में सूती वस्त्र उद्योग का दक्षिणी क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ।

द्वितीय योजना दूसरी योजना का शुभारम्भ 1956 से हुआ। इस योजना में सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन का लक्ष्य 580 करोड़ गज रखा गया। प्रति व्यक्ति बरत क्षमता को 16.5 गज से बढ़ा कर 18.5 गज करने का लक्ष्य रखा गया। निर्यात लक्ष्य 100 करोड़ गज कपड़ा रखा गया। सन् 1958 में श्री रमन की अध्यक्षता में सूती-वस्त्र आच समिति गठित की गई। इस समिति ने वस्त्र उद्योग पर उत्पादन कर कम करने, विवेकीकरण व स्वचालित करघे लगाने के सुझाव दिए। सन् 1960-61 तक देश में 479 सूती वस्त्र मिलें हो गई। कपड़े का उत्पादन केवल 51.5 करोड़ गज रहा जो लक्ष्य से कम था। कपड़े के निर्यात में कमी हुई। इस योजनावधि में इस उद्योग की स्थिति विगड़ने के कई कारण थे, जैसे—जापान, चीन व पाकिस्तान से प्रतिस्पर्द्धा, लागत व्यय में वृद्धि, खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि, जिराहे क्षेत्रों की वस्त्र परीदने की क्षमता कम हुई आदि।

तृतीय योजना : तृतीय योजना में मिक क्षेत्र के कपड़े में उत्पादन का लक्ष्य 580.4 करोड़ गज तथा घाघे के उत्पादन का लक्ष्य 225 करोड़ पौण्ड निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजनावधि में 25,000 स्वचालित करघों के लगाने की व्यवस्था थी। इस योजना के पहले चार वर्षों में सूती कपड़े

के उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की, लेकिन अन्तिम वर्ष निराशाजनक रहा। सन् 1965-66 में हमारे सूती वस्त्र का उत्पादन केवल 515 करोड़ मज ही हुआ, जो लक्ष्य में कम था।

चतुर्थ योजना (1969-74) चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में मिल क्षेत्र में सूती वस्त्र के उत्पादन का लक्ष्य 51,000 लाख मीटर तथा सूती धागे का उत्पादन 11,500 लाख किलोग्राम रखा गया है। योजना काल में पुनर्स्थापन तथा आधुनिकीकरण पर 132.5 करोड़ रु० तथा विस्तारीकरण पर 134 करोड़ रु० व्यय करने का अनुमान है।

भारतवर्ष में सूती वस्त्र उत्पादन की प्रगति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाती है :

मिमी द्वारा उत्पादित कपड़ा

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटर में)	निर्यात (मिलियन मीटर में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन डालर में)
1951-52	3727	—	—
1960-61	6728	628	120.8
1963-66	7740	486	97.2
1966-67	7313	418	80.6
1967-68	7511	450	87.1
1968-69	7902	497	94.0
1969-70	7753	437	92.9
1970-71	7596	447	100.4

वर्तमान स्थिति वर्तमान समय में भारतवर्ष में 672 सूती-वस्त्रों की मिलें हैं, जिनमें 381 कटाई तथा 291 मिश्रित मिलें हैं। इस उद्योग का वार्षिक उत्पादन 1,500-1,400 करोड़ रुपये का है।¹ इस उद्योग में 10 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 30 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। भारत की सूती मिमी में इस समय 170.8 करोड़ तकिये लगे हुए हैं तथा 209 लाख करपे काम

1. श्री मनुमाई दाहः सम्प्रदा, सन् 1968.

कर रहे हैं। इस उद्योग में बिजली से चलने वाले 2 लाख के उपभोग कर रहे हैं तथा हाथ से चलने वाले करघों की संख्या 30 लाख है। इस उद्योग में लगभग 500 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इस उद्योग में लगभग 120 करोड़ रु० की भारतीय कपास का प्रयोग होता है तथा भारत सरकार को इस उद्योग से प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है।

सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of Cotton Textile Industry)—भारत के सूती वस्त्र-उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ निम्न-लिखित हैं :

(i) हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग में कई क्षेत्र हैं, जैसे, मिल, निजली के करघे तथा हाथ करघे के क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा होती है, (ii) हमारे देश में मोटे, मध्यम, सूती तथा उत्तम प्रकार, अर्थात् सभी प्रकार के करघों का निर्माण होता है; (iii) लच्छ वस्त्र बनाने के लिए लम्बे रेशे वाली कपास का अभाव पाया जाता है, (iv) सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन तथा वितरण पर अनेक प्रतिबाध हैं; (v) इस उद्योग के अन्तर्गत कई अनावक इकाइयाँ चल रही हैं, (vi) यह उद्योग कुछ प्रमुख नगरों में ही केंद्रित रहा है जैसे, बम्बई, अहमदाबाद, बालपुर, घोलापुर गाँव। बम्बई व अहमदाबाद अभी भी इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, जहाँ देश के कुल करघों व तकुओं में से आधे करघे व तकुएँ कार्यरत हैं, लेकिन धीरे-धीरे इस उद्योग का विवेकीकरण किया जा रहा है।

उद्योग की समस्याएँ एवं उपचार इस उद्योग को कई कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. कच्चे माल की कमी यद्यपि भारतवर्ष में विभाजन के परिणामस्वरूप रई की कमी को पूरा करने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये हैं, तथापि हमारी तीन पंचवर्षीय योजनाओं में रई का उत्पादन 21 लाख गांठों से बढ़ कर 54 लाख गांठों हो गया तथा अब भी हमें रई का, खास कर लम्बे रेशे वाली रई का, आयात करना पड़ता है। कपास की प्रति एकड़ उपज भारत में बहुत कम है। घटिया किसान की कपास का उत्पादन आगमन वर्ष में 120 पीण्ड प्रति एकड़ है। कपास की कमी को पूरा करने के लिए हम प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपये की कपास विदेशों से मगाते आ रहे हैं। कपास की प्रति एकड़ उपज बढ़ा कर ही इस समस्या का हल किया जा सकता है।

2 अन्तर्गत उत्पादन इकाइयाँ : भारत में इस समय सूती वस्त्र मिलों में से 45 की हालत अच्छी नहीं है। 31 मार्च 1969 तक 59 सूती वस्त्र मिलें बन्द थी तथा 14 एसी मिलें थी, जो बन्द होने की हालत में थी। अगर वे बन्द हो जायें

तो लगभग 70 हजार मजदूर बेकार हो जायेंगे। एक नवीन जाच के अनुसार 50 प्रतिशत मिलें माध्य न्यूनतम स्तर की हैं। ये प्रतिवर्ष करोड़ी रुपये के घाट पर चल रही हैं। भारत सरकार ने ऐसी जलाशयों को मदद के लिए 'राष्ट्रीय कपड़ा निगम' स्थापित किया है। सन् 1972 में भारत सरकार ने कानून बना कर देश को जितनी भी बन्द मिलें थी, उनको अपने नियन्त्रण में ले लिया है।

3 अधिक लागत व्यय कच्चे मान व मजदूरी तथा महंगाई भरो में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप, इस उद्योग की लागत व्यय बढ़ जाती है। महंगाई के कारण इस उद्योग का उत्पादन-व्यय 27 प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि प्राप्ति में केवल 18 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। सरकार को चाहिए कि वह कच्चे माल की कीमत के बारे में उचित नीति अपनाये तथा कपड़े व सूत पर से उत्पादन शुल्क कम करे।

4 अभिनवीकरण की समस्या : भारतवर्ष में अपिकाश मशीनें बहुत पुरानी व घिसी पिटी हुई हैं जो वर्तमान द्रवि एच माग की पूर्ति करने में असमर्थ हैं। बम्बई की मिलों में लगी हुई 75 प्रतिशत के लगभग मशीनरी 25 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं और घिस पिट चुकी हैं। इससे इस उद्योग का उत्पादन कम हो गया है और उत्पादन लागत बढ़ गई है। उद्योग की कई आवश्यक मशीनें तो उपलब्ध भी नहीं हो रही हैं। राष्ट्रीय उद्योग निगम द्वारा इस सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता बढ़ाई जानी चाहिए तथा सन् 1959 ई० के कार्यकारी बड (Working Group) की निष्कारिधों व सुझावों पर जमल किया जाना चाहिए।

5 प्रतिस्पर्धा की समस्या : भारतवर्ष को इस समय जापान, चीन व पाकिस्तान से काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मिलों द्वारा बहिया किस्म का कपड़ा नहीं बनाया जाता, जैसा कि अमेरिका और लकनायर की मिलों में बनाया जाता है। विदेशों में सम्यता के प्रसार एवं जीवन-स्तर में सुधार के कारण अब विदेशों में मोटे तथा मध्यम किस्म के कपड़े का बाजार कम होता जा रहा है। हमारी मिलों में आधुनिक रंगों का प्रयोग भी विदेशी मिलों की भांति नहीं किया जा रहा है, फलस्वरूप हम प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पा रहे हैं। साथ ही बापाठ करने वाले देशों ने तरह तरह के नियंत्रण लगा दिए हैं। मिस्र, तुर्की तथा पुर्तगाल आदि कई नए देश भी अपने निर्यात को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए 'सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन समिति' व 'सूती कपड़ा निर्यात समिति' इस उद्योग की सराहनीय सेवा कर रही हैं। अभिनवीकरण, प्रशिक्षण, विशासन आदि से इस उद्योग को मदद मिल सकती है। किस्म में सुधार एवं लागत में कमी करना आवश्यक है।

6 पूँजी की कमी भारतीय उद्योगों को आधुनिकता प्रदान करने के मार्ग में पूँजी का अभाव खटकता है। आधुनिक स्वचालित मशीनों की इस क्षेत्र में लगने के लिए हमें लगभग 120 करोड़ रुपय विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। गत वर्षों में स्थापित विदेशी संस्थाओं को हम और अधिक ध्यान देना चाहिए।

7 मित्त व हाथ करवा उद्योगों के बीच उचित समन्वय की समस्या—आज-कल हाथ करवा उद्योग की बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार बड़े उद्योगों पर उपकर लगाती है जिससे इन्हें और क्षति पहुँचती है। हाथ करवा उद्योग लोगों में बेरोजगारी दूर करते हैं अतः सरकार के इस कार्य को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी प्रत्यक्ष यह होना चाहिए कि कच्चे उद्योग अपने पंरों पर खर्च हो जायें तथा बड़े उद्योगों की अनावश्यक करो के मुक्ति मिल जाय।

8 औद्योगिक सहायता अन्य उद्योगों की अपेक्षा भारतवर्ष में सूती वस्त्र उद्योगों में अधिक अपेक्षाकृत अधिक संगठित हैं। परिणामस्वरूप आये दिन किसी न किसी बात को लेकर हड़तालें होती रहती हैं, जिससे उद्योग की क्षति पहुँचती है। औद्योगिक शांति स्थापित करके ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

9 मशीनों का अभाव भारतवर्ष की मिलों में विदेशी मशीनों से काम चल रहा है। यह सचमुच ही बड़ी कठिनाई की बात है कि गत वर्षों में हम इस दिशा में निभरता समाप्त न कर सके। हम पोलैण्ड, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड जैसे छोटे देशों से सूती उद्योग के लिए मशीनों का आयात करते हैं। देश की किसी पिटी मशीनों की बदलने के लिए देश में सूती वस्त्र उद्योग सम्बन्धी मशीनों का निर्माण किया जाना चाहिए।

10 क्षमता अक्षमता—भारतवर्ष में सूती वस्त्र उद्योग का विकास भारत के दक्षिणी भागों में उत्तरी भागों की तुलना में बिल्कुल ही नहीं हुआ है। इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए जून 1961 में सरकार ने सूती धात के उत्पादन के लिए 5 दक्षिणी कर्मों को 50,000 तकुशों की कुल क्षमता रखने वाले कारखाने खोलने की अनुमति दी है।

11 उत्पादन कर में वृद्धि इस उद्योग की कठिनाईयों में एक प्रमुख कठिनाई यह भी है कि सरकार ने सूती कपड़ों व धातों पर उत्पादन कर उत्तरोत्तर बढ़ाया है और बढ़ानी आ रही है। सन् 1950-51 में उत्पादन कर 9.25 करोड़ रुपये में बढ़कर 1955-56 में 28.18 करोड़ रुपये, 1960-61 में 66.40 करोड़ रुपये तथा 1965-66 में 28.18 करोड़ और 1968-69 में 117.98 करोड़ रुपये हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन व्यय का $\frac{1}{3}$ भाग उत्पादन कर (excise duty) के नैट चर्ज जाता है। अतः इस उद्योग

पर सरकार द्वारा उत्पादन कर भार और अधिक न बढ़ाया जाना चाहिए तथा डूबते हुए उद्योग को उठाने के लिए इसे सहायता दी जानी चाहिए।

12. अन्य समस्याएँ : इस उद्योग को सन् 1965 ई. से मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे उत्पादन व उत्पादन-क्षमता कम हो गई है। धर्मियों की कार्य-कुशलता भी अपेक्षाकृत कम है। अनुसन्धान की दृष्टि से भी यह उद्योग पिछड़ा हुआ है। व्यक्तियों में प्रशिक्षण व तकनीकी ज्ञान का अभाव है। अशिक्षित होने के कारण वे नई-नई विधियों का विरोध करते हैं। सूती कपड़ा उद्योग को पर्याप्त तथा निरन्तर बिजली व शक्ति न मिलने के कारण भी बहुत कठिनाई होती है। जब तक ये कठिनाइयाँ दूर नहीं कर दी जाती, तब तक यह उद्योग विकास के पथ पर नहीं बढ़ सकता।

सन् 1967 में सरकार ने सूती वस्त्र कंपनी अधिनियम (Cotton Textile Companies Act) पास किया जिससे सरकार ने एक सूती वस्त्र निगम (Cotton Textile Corporation) की स्थापना का फैसला किया। फलस्वरूप अप्रैल 1968 में एक सूती वस्त्र निगम (Cotton Textile Corporation) की स्थापना की गई। इस निगम का काम सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई बीमार मिलों को बलाने की व्यवस्था करना तथा वित्त प्रदान करना है। साथ ही यह निगम आधुनिक प्रकार की नई सूती मिलें स्थापित करेगा।

भारतवर्ष से सूती वस्त्र उद्योग इस समय बड़ी घयनीय स्थिति से होकर गुजर रहा है। प्रत्यक्ष की अनुकूलता, धर्मियों का असहयोगी रवैया, सरकार की विवेकहीन नीति आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्होंने भारत के इस उद्योग की स्थिति असहोपमनक बना दी है। उद्योगपतियों ने राज्यों को उद्योग में न रुका कर तथा पुरानी मशीन का प्रतिस्थापन न करके इस उद्योग की अर्थ सौद दी है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यह उद्योग बहुत बड़े संकट में फस जायेगा, जिसके फलस्वरूप देश के औद्योगीकरण की बहुत बड़ी क्षति होगी।

जूट उद्योग

(Jute Industry)

जूट उद्योग भारत का द्वितीय प्रमुख उद्योग है तथा देश की अर्थ-व्यवस्था में इस उद्योग का एक विशिष्ट स्थान है। यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है। भारतवर्ष में यह उद्योग सिंधी से चला आ रहा है। जूट से टाट, बोरीयाँ, घटाइयाँ, कान्चीन, दरियाँ, रस्सियाँ, पाँवदान आदि अनेक वस्तुएँ बनाई जाती हैं। सन् 1947 के विभाजन से पूर्व जूट उद्योग के क्षेत्र में भारत का एकाधिकार था। देश के विभाजन के पश्चात्, पाकिस्तान हमारे इस उद्योग का प्रतिस्पर्धी

वन गया था। लेकिन 1971 में वनशा देश एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हो गया है, जिसमें भारतके जूट उद्योग का और विकास सम्भव हो गया है। भारतवर्ष में ही जूट पैदा किया जाता है। बंगाल में थमिङ्को की अधिकता है तथा यह उद्योग मुख्यतः निर्यात पर आधारित है वन इस उद्योग का बंगाल में ही स्थानीकरण हो गया है।

संक्षिप्त इतिहास सन् 1855 में श्रीरामपुर के निकट रिझराग्राम में सर जार्ज आर्कलेण्ड द्वारा प्रथम आधुनिक पद्धति की जूट मिल की स्थापना की गई थी। बीरे-बीरे इस उद्योग का विकास होता रहा है। सन् 1859 में इस उद्योग ने पहली बार एकिन आर्किट करण का प्रयोग किया। 1868 में 1873 ई० के बीच इस उद्योग ने जूट वन बसाया तथा अपने अधिकांशों को 25 प्रतिशत तक लाभ दिया। इन काल में इस उद्योग की बहुत मो नई इकाइयाँ भी चालू हुईं। सन् 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस उद्योग ने अत्यन्तनीय प्रगति की तथा इस समय देश में 60 जूट के कारखाने थे। युद्ध काल में भिन्न राष्ट्रों की सेना के लिए भारतीय मिलों ने 139 करोड़ बोरे, 71 करोड़ पौण्ड जूट के कपड़े तथा 10 लाख पीण्ड बुतली तैयार की। जूट के सभी कारखानों में दस समय बढ़ी हुई माप को पूरा करने के लिए अपनी सम्पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन किया। युद्ध काल में कारखाना अधिनियम में डिलाई व कच्चे जूट के नियमों पर पाबन्दी लगाने से इस उद्योग ने काफी लाभ कमाया। युद्ध की समाप्ति पर जूट की माँग में विराट हो गयी तथा सन् 1929 की आर्थिक मन्दी का इस उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक मन्दी के कारण जूट की वस्तुओं का निर्यात घट गया। सन् 1928-29 में जहाँ भारत 57 करोड़ रु की वस्तुओं का निर्यात करता था, वहाँ 1933-34 में केवल 11.4 करोड़ रु० का सामान ही विदेशों को भेज सका। आर्थिक मन्दी के काल में जूट के कारखानों में कार्य के पन्टे कम कर दिए गए तथा बर्ही करणों को बन्द कर दिया गया। 1936 में जूट के उत्पादन में वृद्धि करने तथा ऐसी सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय केन्द्रीय जूट समिति (Indian Central Jute Committee) बनाई गई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने से इस उद्योग की स्थिति स्वतः सुधर गई तथा उत्पादन व लाभ दोनों में वृद्धि हुई, क्योंकि युद्ध के कारण जूट के माल की माँग बहुत बढ़ गई तथा जूट मिलें अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने लगीं।

सन् 1947 में देश के विभाजन का भारतीय जूट उद्योग पर बुरा असर पड़ा। 1947 में देश में 111 जूट की मिलें थीं। विभाजन के परिणामस्वरूप जूट की सभी मिलें भारतवर्ष में ही रह गईं, लेकिन जूट पैदा करने वाला 72% क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया जिससे देश के चलने कच्चे जूट की समस्या उत्पन्न हो

गयी। पाकिस्तान के वस्तुपूर्ण रवये के कारण भारत को जूट उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की चेष्टा करनी पड़ी। 1949 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण कच्चे माल के आयात में कठिनाई हुई। इस समय 72 लाख गांठों की आवश्यकता थी, जबकि देश में 33 लाख गांठें ही पैदा होती थी।

योजनाओं के अंतर्गत उद्योग की प्रगति प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, कच्चे माछ की दृष्टि से उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिये नये कारखानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बंगाल, बिहार व आंध्र में जूट की गहरी खेती द्वारा उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये गये। इस योजना में जूट के उत्पादन का लक्ष्य 51 लाख गांठें रखा गया तथा जूट निर्मित वस्तुओं का लक्ष्य 12 लाख टन रखा गया था। वर्ष 1955-56 में कच्चे जूट का उत्पादन 42 लाख गांठें हुआ था व जूट निर्मित वस्तुओं का उत्पादन 10.97 लाख टन हुआ जो लक्ष्य से कम था। जूट के सामान का निर्माण लक्ष्य 6.5 लाख टन से बढाकर 10 लाख टन करने का था, लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में वास्तविक निर्माण 8.75 लाख टन हुआ। द्वितीय योजना के अन्तर्गत केवल एक नई इकाई खोलने की आज्ञा प्रदान की गई। जूट के बने हुए माल में 12 लाख टन वृद्धि का लक्ष्य रखा गया तथा कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य 65 लाख टन गांठ रखा गया। निर्माण का लक्ष्य 9 लाख टन रखा गया। योजनावधि में उत्पादन व्यवस्था करने, मशीनों का आधुनिकीकरण करने तथा निर्माण बढाने के लिए विभाग प्रयत्न किए गए। इन योजना के अंत में कच्चे जूट का उत्पादन केवल 43 लाख गांठें हुआ तथा जूट वस्तुओं का उत्पादन 9.70 लाख टन हुआ। तृतीय योजना में कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 62 लाख गांठें रखा गया तथा जूट के सामान का उत्पादन लक्ष्य 13 लाख टन रखा गया। इसके अलावा 'मिस्टा' (जूट की स्थानापन्न वस्तु) से 13 लाख गांठें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निर्माण का लक्ष्य केवल 9 लाख टन रखा गया है। तृतीय योजना में कच्चे माल की पूर्ति सम्बन्धी कठिनाइयों के बावजूद उत्पादन में निर्माण के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए। इस योजनावधि में जूट की हरिया सतहों के रूप में जेम्बी से बिस्तर हुआ है जेम्बी उद्योग के उत्कर्ष, विकास का पूरी तरह नवीनीकरण कर दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 74 लाख गांठें कच्चे जूट की उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्योग की उत्पादन क्षमता नये कारखानों को जोड़कर नई बढाई जायेगी, अपितु पुराने कारखानों की क्षमताओं का ही विस्तार किया जायेगा। विगत वर्षों में जूट उद्योग में होने वाले उत्पादन की अवलिखित साक्ष्य में दिताया गया है :

जूट निमित्त माल का उत्पादन (हजार टनी में)

वर्ष	उत्पादन
1950-51	837
1955-56	1071
1960-61	1097
1965-66	1302
1966-67	1117
1967-68	1156
1968-69	998
1969-70	944
1970-71	958

वर्तमान स्थिति भारतवर्ष में इस समय 112 जूट के कारखाने हैं। इन कारखानों में 101 कारखाने पंजरा में हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में क्रमशः 4, 3, 3, 1 कारखाने हैं। इन कारखानों में 73,000 रुपये लागे हुये हैं। इस समस्त कारखानों की उत्पादन-क्षमता 14 लाख टन वार्षिक है। इस उद्योग में लगभग 2 57 लाख लोग कार्य में लगे हुये हैं तथा लगभग 91.49 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। सन् 1970-71 में 190 करोड़ रुपये की जूट की वस्तुओं का निर्यात किया गया।

जूट उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ

(Special Features of the Jute Industry)

भारतीय जूट उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं : (i) यह उद्योग पश्चिमी घाट में ही केन्द्रित है क्योंकि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ कच्चा माल, पानी तथा बिजली सफलता से प्राप्त हो जाती है, (ii) भारत के जूट उद्योगों का उद्भव एवं विकास ब्रिटिश पूँजी से हुआ है, (iii) भारतीय जूट उद्योग अपने विकास के लिए निर्माण एवं वित्तीय बाजारों पर निर्भर है। भारत में उत्पादित जूट के माल का 80% 90 प्रतिशत भाग का निर्यात कर दिया जाता है; (iv) इस उद्योग का नियंत्रण प्रबन्धक एजेंसियों के अधीन है। जूट उद्योग की उत्पादन क्षमता का लगभग 1/4 भाग दो प्रबन्धक एजेंसियों के अधीन है (v) भारत में म्यापा जट मिटे के अतिरिक्त बड़े हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में स्थापित मिलों के अतिरिक्त छोटे हैं; (vi) जूट के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार ने कभी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया है, तथा (vii) विगत कुछ वर्षों से जूट उद्योग का उत्पादन व निर्यात प्रायः स्थिर रहा है।

जूट उद्योग की कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ तथा सुझाव : भारतीय जूट उद्योग को सामने निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ हैं—

1. कच्चे मास का अभाव : भारतवर्ष के जूट के समस्त कारखानों को अपनी सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए कम से कम 72 लाख गांठों की आवश्यकता होती है। कच्चे जूट का उत्पादन इतना नहीं होता, उत्पादनार्थ 1966-67 में कच्चे जूट की केवल 62 गांठें ही उत्पादिता की गई थी। इस समस्या का निदान केवल यही है कि प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की चेष्टा की जाय, क्योंकि यदि अधिक जैन में इसका उत्पादन किया जानें सगेना, तो कारखानों की पूर्ति कम हो जायेगी।

2. विदेशी प्रतिस्पर्द्धा : भारतीय जूट उद्योग प्रमुखतः निर्यात उद्योग है, परन्तु उसे अनेक बड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी प्रतिस्पर्द्धा का इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पाकिस्तान के अतिरिक्त मध्य-पूर्व तथा अफ्रीका के सुदूरपूर्व के कुछ देश, जैसे—साइलैण्ड, थाई, माइजीरिया आदि भी अपने-अपने देशों में जातिनिर्भरता की दृष्टि से जूट उद्योग का विकास कर रहे हैं। भारत को प्रतिस्पर्द्धा की चुनौती का सामना करने के लिये; (i) कच्चे जूट की उत्पादन विधि सुधारनी चाहिये, (ii) अभिनवीकरण अवकाश चाहिये; तथा (iii) जूट-निर्यात वस्तुओं को आर्थिक सहायता (Export Bonus) देनी चाहिये।

3. अभिनवीकरण की समस्या : भारतवर्ष के जूट की मिलों में लगी हुई मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान व अन्य देशों में नई-नई मशीनें लगाई गई हैं। अतः यदि हमें प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावशाली ढंग से सामना करना है, तो बिना देर किये इस उद्योग में अभिनवीकरण की योजना लागू की जानी चाहिये। भारत सरकार द्वारा आधुनिकीकरण के लिए ऋण तथा आवश्यक मशीनरी आयात करने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। देख में ऐसी मशीनरी तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक आधुनिकीकरण पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी और धनराशि की आवश्यकता है। सरकार द्वारा शीघ्रकाल के लिए, कम धन पर इस धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

4. स्थानापन्न वस्तुओं का भय : भारत से मुख्यतः टाट के बोरो का निर्यात किया जाता है। अमेरिका में टाट के स्थान पर अब कागज के बोरो का प्रयोग होने लगा है। अन्य अनेक स्थानापन्न वस्तुओं का भी निर्माण किये जाने की सम्भावना है। अतः हमें जूट-वस्तुओं के मुख्य काम करने होंगे, उनके उत्पादन में विविधता लानी होगी तथा नये नये बाजारों की खोज करनी पड़ेगी, ऐसा करने पर ही यह उद्योग पनप सकेगा।

5 ऊँची लागत व्यय : भारतीय जूट उद्योग को कच्चे जूट के लिये अपेक्षा-कृत अधिक मूल्य देना पड़ता है। यमिनी में मन्दूरी की उत्तरोत्तर बढ़ती भी लागत व्यय बढ़ाती है। लागत व्यय बढ़ जाने के परिणामस्वरूप जूट उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षतिग्रस्त हो जाती है। जूट अभिनवीकरण, छोटी छोटी इकाइयों का एकीकरण, दो पालियों का चम्पना, कच्चे घास के लिये समीकरण भण्डारों की स्थापना करना, आदि कदम उठाने ज़रूरी चाहिये।

6 परिवहन सुविधाओं की कमी : जूट उद्योग में बंगाल में ही केन्द्रित है। पंजाब अन्य बहुत से उद्योगों का भी केन्द्र है, इस कारण रेलवे अधिकारी जूट व जूट के माल के बजाय अन्य वस्तुओं की दुर्गति को प्राथमिकता देते हैं। जूट को मविमों द्वारा लाया जाता है जो बड़ा अनुविधानतक है। असम में त्रिपुरा में उत्पादित जूट यातायात के माध्यमों के अभाव के कारण बंगाल की जूट मिलों तक नहीं पहुँच पाता। इस समस्या का निराकरण यातायात के साधनों के विकास द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जूट उद्योग के लिये सस्ते व द्रुतगामी परिवहन के साधनों की सुविधा दिलाना आवश्यक है।

7 अनुसंधान सुविधाओं का अभाव : भारतवर्ष में जूट उत्पादन के सम्बन्ध में अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाएँ भी बहुत सीमित हैं। केवल 'जूट उद्योग शोधघाटा' (Jute Industry Research Institute) कटकता ही इस सम्बन्ध में कुछ अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करती है। उत्पादन लागत को कम करने, उत्तम कौटि का माल बनाने तथा जूट की नई नई उपयोगी वस्तुएँ बनाने के लिए अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिये।

8 अन्य समस्याएँ : जूट समस्याओं के अतिरिक्त, तकनीकी विशेषज्ञों की कमी, कुशल व प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव, कीमती में विरासद, कच्चे जूट की पूर्ति की अनिश्चितता आदि कई अन्य समस्याएँ हैं, जिनका निराकरण आवश्यक है। भारत को जूट निर्यात बढ़ाने के लिए करोड़ों में कमी की ज़रूरी चाहिए। पाकिस्तान अपने जूट के निर्यात पर 32 प्रतिशत उत्पादन (Subsidy) दे रहा है जबकि भारत निर्यात पर कर लगाता है। इससे जूट का निर्यात कम हो रहा है। भारत से जूट का निर्यात 1960-61 में 284 मिलियन डॉलर से घट कर 1970-71 में 254 मिलियन डॉलर हो रहा गया है।

जूट उद्योग की समस्याओं के निराकरण के कुछ सुझाव ऊपर प्रस्तुत किये गये हैं। भारत सरकार ने सन् 1962 ई० में श्री मन० मी० श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इसे जूट उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने व सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। इसने सन् 1963 ई० में अपने निम्न-लिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं : (i) अच्छे क्रिम के बीज व रासायनिक खाद का

प्रयोग करने प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जाय, (ii) राजकीय कृषि विभागों के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिये एक जूट विकास बोर्ड की स्थापना की जाय, (iii) कच्चे जूट के मसह व वर्गीकरण की सुविधाएँ दिलाई जाय तथा इसकी बिक्री के लिये नियमित मंडियों का गठन किया जाय, (iv) जूट मिलों की वस्तु की पूर्ण नियमित रूप से मिलनी चाहिये; (v) विदेशों से जूट आयात पर लगे निषेधनों को हटवाने के लिये चेष्टा की जानी चाहिये, (vi) नए-नए प्रकार के जूट पदार्थों के उत्पादन के लिये 'Market Intelligence Service' का गठन किया जाना चाहिए।

यह रूप का विषय है कि भारत सरकार ने परम्परागत वस्तुओं के उत्पादन एवं पुराने बाजारों में ही सामान की बिक्री की प्रवृत्ति को दूर करने तथा नए क्षेत्रों को खोजने के लिए एक जूट समिति का गठन किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, "यदि जूट उद्योग कृत्रिम रेशों (Synthetic Fibres) के प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थान प्राप्त करना चाहता है तो इसे भी तकनीकी परिवर्तनों का अनुकरण करना होगा तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकता व रुचि की जानकारी प्राप्त करनी होगी। तकनीकी परिवर्तनों के अपनाने से कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं जैसे सूती धाँसे का उत्पादन, टाट (Hessian) को अधिक सफेद बनाने की प्रक्रिया आदि। लेकिन अभी तक देश का जूट उद्योग इन नवीन उत्पादों (Products) के उत्पादन में बहुत कम रुचि लेता है। भारत की जूट मिलें उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में रुचि नहीं लेती तथा विशिष्ट वस्तुओं के लिए निर्यात किए गए मूल्य विवशी माँदरी को बखरीदार कर देती हैं।"

जूट उद्योग भारत को मूल्यवान विदेशी विनिमय दिलाने वाला उद्योग है। निर्यात बाजार का महत्व इस उद्योग के लिए स्वभाविक अधिक है। अब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के इस युग में, जूट उद्योग की प्रतिस्पर्धा दानित को बढ़ाना परमावश्यक है, क्योंकि यह उद्योग समाप्त हो जायेगा। अतीत में इस उद्योग ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की थी। तथा अब बंगला देश के एक महान राष्ट्र के रूप में उदय हो जाने से, जहाँ पाकिस्तान के मुल 60% कच्चे जूट का उत्पादन होता है तथा भारत व बंगला देश की बढती हुई मित्रता को देखते हुए, इस उद्योग का भविष्य बहुत ही उत्तम है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को भी अपने प्रयत्न जारी रखने होंगे।

चीनी उद्योग (Sugar Industry)

भारतवर्ष के मसठिन उद्योगों में लोहा व इस्पात उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग के पश्चात् चीनी उद्योग का ही स्थान है। चीनी भोजन का प्रमुख पदार्थ है, जिसका

समुचित आहार में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय वर्षाव्यवस्था में इसका दोहरा महत्व है। एक ओर तो कृषि के क्षेत्र में किसानों में प्रिय व्यावसायिक क्रम है और दूसरी ओर यह महत्वपूर्ण उद्योग है जो जीवन की आवश्यक वस्तु की श्रुति करता है। भारत वर्ष में इस उद्योग में लगभग 102 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है तथा डेढ़ लाख से भी अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। इस उद्योग के माघ 20 लाख गन्ना उत्पादन करने वाले कृषकों की समृद्धि भी जुड़ी हुई है। केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने उत्पादन कार के रूप में आय प्राप्त होती है। गन्त कई वर्षों से चीनी के निर्यात से विदेशी विनिमय भी प्राप्त किया जा रहा है।

संक्षिप्त इतिहास - जैसे ही चीनी उद्योग हमारे देश का प्राचीन घरेलू उद्योग रहा है। पर बीसवीं शताब्दी में सन् 1903 ई० से यह आधुनिक रूप के कारखानों के रूप में चलाया जा रहा है। इन उद्योग का विकास प्रारम्भ में धीमी गति से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् सत्तार के लगेक देशों में चीनी के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई फलस्वरूप हमका मूल्य गिरने लगा। भारत में इस समय बहुत बड़ी मात्रा में चीनी का आयात होने लगा और यह महा बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध होने लगी। भारत सरकार द्वारा आय को दृष्टि से विदेशी चीनी पर कर लगाया गया था, लेकिन 1917 पर 11 लाख टन भी विदेशी चीनी का मूल्य भारतीय चीनी के मूल्य से कम ही पड़ता था। ऐसी स्थिति में भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों में इस उद्योग के लिए संरक्षण की मांग की जाने लगी। सरकार ने इस उद्योग की स्थिति की जांच करने के लिए 1929 में एक प्रमुख मण्डल नियुक्त किया जिसकी सिफारिशों के आधार पर इस उद्योग को 1931 में संरक्षण प्रदान किया गया।

संरक्षण के पश्चात् इस उद्योग ने बड़ी तीव्र गति से विकास करना प्रारम्भ किया। सन् 1921-32 में देश में चीनी कारखानों की संख्या केवल 32 थी तथा ये 16 लाख टन चीनी का उत्पादन करते थे। लेकिन संरक्षण से प्रोत्साहित होकर चीनी कारखानों की संख्या 1938-39 में बढ़कर 132 हो गई तथा चीनी का उत्पादन 67 लाख टन हो गया। सन् 1931 से पूर्व हम प्रतिवर्ष 10 लाख टन चीनी का आयात करते थे जो 1938-39 में घटकर केवल 22 हजार टन रह गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संरक्षण के फलस्वरूप कुछ ही वर्षों में भारत विश्व के चीनी उत्पादक देशों में गण्यमान होने लगा।

सन् 1939 के पश्चात् इस उद्योग ने विशेष उन्नति नहीं की। द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीय चीनी उद्योग को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ बल्कि माघ यह जाने और यातायात की कठिनाई के कारण चीनी के वितरण पर नियन्त्रण किया गया जो

1947 तक चलता रहा। सन् 1943-44 में चीनी का उत्पादन 12 लाख टन था जो 1946-47 में घटकर केवल 9 लाख टन रह गया था।

सन् 1944 में इस उद्योग के कच्चे घाल करने की स्थिति सुधारने के लिये केन्द्रीय गन्ना समिति नियुक्त की गई। 1947 के देश के विभाजन का असर इस उद्योग पर नहीं पड़ा, क्योंकि देश के चीनी के कारखाने व गन्ना उत्पादक क्षेत्र देश में ही रह गये थे। सन् 1950 ई० में इस उद्योग को दिया जाने वाला संरक्षण हटा लिया गया।

पंचवर्षीय योजनाओं में चीनी उद्योग : प्रथम योजना सन् 1951 में, अर्थात् प्रथम योजना के प्रारम्भ में, भारतवर्ष में 158 चीनी के कारखाने थे जिनके द्वारा 11 लाख टन चीनी उत्पादन की जाती थी। इस योजना में चीनी उत्पादन का लक्ष्य 16.5 लाख टन रखा गया। योजना के दौरान में चीनी कारखानों की संख्या बढ़कर 160 हो गई और उत्पादन लक्ष्य से काफी अधिक निकल गया, अर्थात् अन्तिम वर्ष में उत्पादन 18.6 लाख टन पहुँच गया। उत्पादन बढ़ने के फलस्वरूप चीनी के मूल्य कुछ कम हुए तथा चीनी का आयात भी अब आवश्यक न रहा। इस योजनावधि में इस उद्योग की प्रगति का प्रमुख रहस्य यह था कि योजना के अन्तिम दो वर्षों में गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई जिससे चीनी मिलों को अपनी पूरी क्षमता भर काम करने का अवसर मिल सका। अतः उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इस योजनावधि में सन् 1954 में 43 चीनी मिलों की स्थापना तथा 42 पुरानी चीनी मिलों के विस्तार की एक योजना की स्वीकृति दी गई। इस योजनावधि में इस उद्योग के विकास के लिए 15 करोड़ रुपये व्यय किए गए। द्वितीय योजना में उत्पादन लक्ष्य 25 लाख टन रखा गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरानी मिलों के विस्तार पर बल दिया गया। योजनावधि में सहकारी क्षेत्र में 35 नई मिलें खोलने का लक्ष्य था। इस योजनावधि के अन्त में चीनी मिलों की संख्या 175 थी। तृतीय योजनाकाल में इस उद्योग के विकास एवं विस्तार कार्यक्रम पर 56 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 1960-61 तक देश में 30 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हो चुकी थी। इस योजनाकाल में चीनी के उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव हुए। योजना के प्रथम वर्ष में चीनी का उत्पादन ठीक रहा लेकिन अगले दो वर्षें खराब रहे। लेकिन, फ्रिज, बाद में दो वर्षों में स्थिति सुधर गई तथा 1960-61 में चीनी का उत्पादन 30.29 लाख टन हुआ जो लक्ष्य से भी अधिक था। तृतीय योजना में 30 से 35 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इस योजनावधि में सहकारिता के आधार पर 25 नए चीनी के कारखाने खोलने वाले की व्यवस्था की और यह आशा की गई थी कि लक्ष्य का समग्र एक चौथाई उत्पादन सहकारी मिलों से प्राप्त होगा। चीनी उद्योग

सम्बन्धी मशीनरी के सम्बन्ध में भी यह आशा थी कि इस योजनावधि के अन्त तक देश इनके सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जायेगा। तृतीय योजना के अन्त में जर्मात 1965-66 में चीनी का उत्पादन 35.10 लाख टन हुआ। इस समय चीनी मिलों की संख्या 186 थी जिनमें 65 सहकारिता के आधार पर चलने वाली मिलें थी।

तृतीय योजना के बाद के दो वर्ष इस उद्योग के लिए अच्छे मानित नहीं हुए, क्योंकि लगातार सूखे के कारण गन्ना उत्पादन बहुत कम रहा तथा इसके अभाव में कई मिलों को बन्द रहना पड़ा। 1966-67 में चीनी का उत्पादन केवल 23 लाख टन रहा तथा 1967-68 में 22.49 लाख टन। 1970-71 में यह उत्पादन 37.40 लाख मिलियन टन तक पहुँच गया।

चौथी योजना में चीनी का उत्पादन सक्षम 45 लाख टन रखा गया है। इस काल में 70 नये कारखाने और स्थापित किए जायेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चीनी के उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उस्ताहवर्द्धक सफलता प्राप्त हुई है। चीनी उत्पादन की वृद्धि बहुत कुछ ऊँच पर निर्भर रहती है, क्योंकि गन्ना एक ऊँच पैदाई है। गन्ने की उपज स्वयं अन्य कारणों के साथ प्राकृतिक कारणों पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि चीनी के उत्पादन में समय-समय पर घट-बढ़ होती रही है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है -

वर्ष (नवम्बर से अक्टूबर)	चीनी का उत्पादन (लाख टनो में)	वर्ष (नवम्बर से अक्टूबर)	चीनी का उत्पादन (लाख टनो में)
1955-56	18.90	1963-64	25.69
1956-57	20.74	1964-65	32.60
1957-58	20.00	1965-66	35.10
1958-59	19.51	1966-67	23.00
1959-60	24.82	1967-68	22.49
1960-61	30.29	1968-69	35.60
1961-62	27.14	1969-70	42.60
1962-63	21.52	1970-71	37.40

चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति सन् 1969 तक देश में 205 चीनी के कारखाने थे। इसमें से अधिकतर कारखाने उत्तर प्रदेश (71) व बिहार (30) में थे। इन चीनी कारखानों की उत्पादन क्षमता 38 61 लाख टन के लगभग की है। इनमें 70 कारखाने सहकारी क्षेत्र में थे। अधिकतर सहकारी क्षेत्र के कारखाने महाराष्ट्र (20) में तथा शेष गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में है। चीनी उद्योग प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में केंद्रित हो गया था, लेकिन अब यह उद्योग देश के अन्य भागों में, खासकर दक्षिण में भी विकसित हो रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मैसूर व आन्ध्र राज्यों में अब यह उद्योग उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है। दक्षिण भारत में गन्ने की विस्म अपेक्षाकृत अच्छी है। बड़ा के कारखाने उत्तर के कारखानों की अपेक्षा अधिक प्रबन्ध कुशल हैं और हो सकता है कि निश्चित भविष्य में चीनी उत्पादन के क्षेत्र में वे उत्तर भारत से बाजी मार ले जाए। इस उद्योग के विकास में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि अब पिछले 15 वर्षों से सहकारिता के क्षेत्र में यह उद्योग सफलता से चलाया जा रहा है। इस उद्योग की एक अन्य विशेषता चीनी का निर्यात है। भारत वर्ष पहले चीनी के मामले में आरथ निरर नही था। उसे विदेशों से चीनी का आयात करना पड़ता था, लेकिन अब वत 22 वर्षों से यह उद्योग निर्यात के द्वारा देश की आवश्यक विदेशी मुद्रा भी प्रदान कर रहा है। गत कुछ वर्षों में चीनी के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है :—

चीनी निर्यात से अनुमान विदेशी मुद्रा

वर्ष	चीनी का निर्यात (करोड रु० में)
1951-52	0 65
1955-56	0 96
1960-61	3 28
1965-66	11 34
1966-67	16 12
1967-68	15 94
1968-69	10 19
1969-70	8 59
1970-71	27 57

चीनी उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of the Sugar Industry) भारत में चीनी उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं :

(1) भारत में यह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश व बिहार में ही केन्द्रित है। इन दो राज्यों में गन्ने की कुल फसल का 66 प्रतिशत भाग बोया जाता है तथा देश की कुल चीनी मिलों की 75 प्रतिशत मिलें इन्हीं दो राज्यों में हैं।

(2) भारतीय चीनी की उत्पादन लागत विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक है।

(3) इस उद्योग की अधिकांश मिलों की स्थापना 20-30 वर्ष पूर्व हुई थी, अतः इनकी मशीनें पुरानी हैं जिनके बदलने की आवश्यकता है।

(4) भारत में चीनी दो प्रकार की होती है, सफेद चीनी व साख्तारी। सफेद चीनी के उत्पादन पर साख्तारी का उत्पादन व मूल्यों का प्रभाव पड़ता रहता है, क्योंकि साख्तारी के मूल्य बढ़ जाने से गन्ने के पौत की दिसा मिलों की ओर न होकर साख्तारी उत्पादन की ओर हो जाती है।

(5) पहले यह उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र में था, लेकिन अब सहकारी क्षेत्र उत्तरोत्तर अधिक हिस्सा बढ़ाता जा रहा है।

(6) भारत में पहले उत्पादन कम होने के कारण चीनी का आयात होता था, लेकिन अब निर्यात होने लगा है।

(7) भारतीय चीनी उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण की प्रधानता नहीं है। सरकार ने इस उद्योग के उत्पादन मूल्य, वितरण व परिवहन आदि पर समय-समय पर अपना नियन्त्रण रखा है।

(8) भारत में चीनी उद्योग की स्थिति उत्पादन की दृष्टि से सर्वत्र अस्थिर रही है, कभी कम कभी अधिक।

उद्योग की समस्याएँ एवं सुझाव

भारतवर्ष में चीनी उद्योगों की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे निम्नांकित हैं :

1 **उत्पादन लागत की समस्या :** भारत में चीनी उत्पादन की लागत विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक है। गन्ने की प्रति एकड़ कम उपज, गन्ने में चीनी की मात्रा का कम होना तथा गन्ने के पेरने की क्षमता कम होने के कारण हमारी लागत व्यय बढ़ जाती है। भारतीय चीनी के उत्पादन में 60 प्रतिशत भाग गन्ने का होता है। अतः लागत व्यय को कम करने के लिए उच्च कीटि का यन्त्र पैदा किया जाय, प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जाय, गन्ने पेरने की क्षमता में भी वृद्धि की जाय।

2 रिपति सम्बन्धी समस्या भारतवर्ष में चीनी उद्योग उत्तरी भारत में केन्द्रित हो गया है जबकि इसके विकास व उत्पत्ति की दृष्टि से दक्षिणी भारत में उपलब्ध है। बहा की अनुकूल स्थिति में उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक और सस्ता हो सकता है। सन् 1960-61 में उत्तर प्रदेश व बिहार में जहाँ देश का प्रायः दो तिहाई गन्ना पैदा किया जाता है, गन्ने की प्रति एकड़ उपज क्रमशः 12 1/2 तथा 11 1/2 टन थी जबकि तामिलनाडु व आन्ध्र में 58 2 टन तथा महाराष्ट्र में 31 टन थी। अतः देश में नई खुसने वाली चीनी की फॅक्टरिया दक्षिण में ही खुलनी चाहिये।

3 प्रति एकड़ गन्ने की उपज का कम होना भारतवर्ष में प्रति एकड़ गन्ने की उपज क्षय चीनी उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है। जावा तथा हवाई द्वीप में प्रति एकड़ गन्ने की उपज क्रमशः 56 तथा 52 टन है जब कि भारतवर्ष में औसत प्रति एकड़ उपज केवल 15 टन ही है। कानपुर व सलमऊ में प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए जो अनुसंधान दालाए जा रही हैं, वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

4 गन्ने की निर्यात का खराब होना भारतीय गन्ने की किस्म अपेक्षाकृत खराब है, भारतीय प्रति एकड़ उत्पादित गन्ने से 1 37 टन चीनी मिलती है, जबकि फ्यूबा, हवाई द्वीप व जावा में प्रति एकड़ में उत्पादित गन्ने से क्रमशः 2 58 टन, 6 88 टन तथा 6 44 टन चीनी प्राप्त होती है। गन्ने से प्राप्त चीनी का प्रतिशत ब्राज़ीलिया में 14 33, फ्यूबा में 12 25, मारिशस में 12 8 तथा जावा में 11 49 है जबकि भारत में यह केवल 9 5 प्रतिशत ही है। गन्ने से अपेक्षाकृत कम चीनी प्राप्त करने का एक कारण यह भी है कि मिलों में गन्ना पहुँचाने में देर होती है जिससे गन्ने का रस सूख जाता है और चीनी का अनुपात घट जाता है। उम्मत बीज, सिक्काई की सुविधा, अच्छी खाद आदि से उत्पादन की किस्म व मात्रा दोनों ही बढ़ाई जा सकती है।

5 अनाधिक आकार के चीनी के कारखाने हवार देश में अधिकतर चीनी कारखाने छोटे आकार के हैं, जिनकी गन्ना पेरने की दैनिक क्षमता केवल 700-800 टन है। अन्य देशों में कारखानों की दैनिक गन्ने की खपत 3,000 टन होती है। 'भारतीय चीनी उत्पादनका दृश्य' (Indian Sugar Producing Capacity Survey) में छोटी छोटी चीनी मिलों के बिलंब का गुनाव दिया है।

6 तार्किक विशेषज्ञों व अनुसंधान सुविधाओं की कमी अनुसंधान के क्षेत्र में भारतवर्ष में केवल दो खस्राएँ हैं। सामान्यतः चीनी कारखानों को विशिष्ट प्रविष्टि प्राप्त विशेषज्ञ मिल नहीं पाते। अतः अनुसंधान सम्बन्धी व तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये।

7. **अद्वितीय पदार्थों के पूर्ण उपयोग की समस्या :** चीनी उद्योग में खोई, सीरा, प्रेसमह, केनट्रेस आदि अद्वितीय पदार्थ बचते हैं, जिनसे विविध प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। भारत में इन पदार्थों का समुचित लाभ नहीं उठाया जा रहा है। आजकल देश की चीनी मिलों में प्रतिवर्ष 300 से 400 हजार टन सीरा (Molasses) निहलना है जिसमें से अधिकतम बेकार हो जाता है। इससे 20 से 25 मिलियन गैलन जलकोइल तैयार की जा सकती है। गन्ने की खोई से जागज, काई बोई आदि तैयार किया जा सकता है। यदि इन अद्वितीय पदार्थों का समुचित उपयोग किया जाय तो एक ओर तो किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा दूसरी ओर वे भी अधिक भी पैसा लायेंगे। इन अद्वितीय पदार्थों का उचित उपयोग करने के लिए इन उद्योगों की सामूहिक प्रयत्न करने चाहिए।

8. **समन्वय का अभाव** इस उद्योग के तीन अंगों, यथा—चीनी, गुड़, ग्राह-सारी में समन्वय नहीं है, फलस्वरूप एक दूसरे के मार्ग में बाधाएँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि सापेक्षिक रूपों में अन्तर के कारण इनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा होने लगती है। अतः इन तीनों उद्योगों में समन्वय स्थापित करना चाहिए।

9. **परिवहन सम्बन्धी समस्या** भारत में चीनी मिलें घने के क्षेत्रों के पास न होकर बड़ी दूर होती हैं। इन सड़ों से मिलों तक गन्ना पट्टावे से परिवहन की अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। भारत के शमीन क्षेत्रों में गाँवों तक ही नहीं या वे अच्छी नहीं हैं। इसलिए यहाँ से मिल तक गन्ना लाने में अशुविधाएँ एवं देरी होती है। साथ ही देश में आज न समन्वय का रस सूख जाता है। परिवहन सम्बन्धी असुविधाएँ दूर करने, चीनी उद्योग की उन्नति के लिए रस्ते, दूरगामी व पक्की पविद्धन के साधन उपलब्ध कराए जाएँ।

10. **निर्यात की समस्या** भारतवर्ष, विदेशी मद्रा को प्राप्त करने के लिए कुछ वर्षों में चीनी का निर्यात करता है। भारत में लगभग 10 अल्पेक्षक अतिरिक्त के कारण, भारतीय चीनी मजबूत पड़ती है। लेकिन अन्तराष्ट्रीय मूल्य अन्तर की राशि देना नकार इस उद्योग को अन्तराष्ट्रीय बाजारों में चीनी के खन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस प्रकार सरकार को घाटा होता है। यह समस्या उपायन करने पराक्षर सुलझाई जा सकती है।

11. **आय समस्याएँ** कई प्रकार के तरीकों की समस्या, ईंधन के अभाव की समस्या, घरेलू भाग में वृद्धि की समस्या आदि अन्य समस्याएँ हैं, जिनका निराकरण मौल्य होना चाहिए, ताकि उद्योग के विकास के मार्ग की बाधाएँ दूर हो जाएँ।

उपसृत अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इस उद्योग के सामने वर्तमान समय में कई समस्याएँ हैं। इनमें से कुछ समस्याएँ बाह्यी से हल की जा सकती हैं। सरकार इस उद्योग की उन्नतशील बनाने के लिए प्रयत्न कर रही है। अनुसंधान पर भी

जब अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को चीनी के वितरण सम्बन्धी अपनी नीति सुधारनी चाहिये तथा समस्याओं को घरे से हटाकर इस उद्योग को विकास-पथ की ओर ले जाने के लिये रचनात्मक कार्य करने चाहिए।

1. भारत में उद्योगों के पिछड़ेपन के कारण

यद्यपि भारतवर्ष में स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात् औद्योगिक विकास की गति में तेजी आई है, तथा निम्नो व सार्वजनिक क्षेत्रों में पुराने उद्योगों के विकास और नये उद्योगों को चालू करने के 'मराहनीय' प्रयत्न किये गये हैं, तथापि हमारे उद्योगों में विकास के उस तोपान पर अभी तक कदम नहीं रखा है, जिस पर विश्व के अन्य उद्योग-प्रधान देश पहुँच चुके हैं। भारतीय उद्योगों के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ व समस्याएँ हैं। इन बाधाओं को जब तक दूर नहीं कर दिया जाता, तब तक हमारे उद्योगों का विस्तारपन भी दूर नहीं हो सकता। ये समस्याएँ गहन में निम्नांकित हैं :

1 पूँजी का अभाव : भारतवर्ष में सामान्यतः पूँजी का अभाव पाया जाता है। लोगों में संचय की इच्छा, शक्ति व साधनों की कमी है। इनके अभाव में पूँजी का निर्माण गैर गति से होता है। भारत में सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। हमारी संचय की दर राष्ट्रीय आय का केवल 8.5% भाग ही है। बिना पूँजी उद्योगों का विकास असम्भव सा प्रतीत होता है।

2 विदेशी पूँजी की कमी : देश की पूँजी कम होती है। विदेशी पूँजी की उपलब्धता भी पर्याप्त नहीं है। औद्योगीकरण के लिये आवश्यक पूँजीगत सामान, जैसे, मशीनों के अभाव में देश के औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें विदेशों से मशीनों की भारी संख्या में आवश्यकता होती है। ये विदेशी मशीनें विदेशी पूँजी के अभाव में प्राप्त नहीं की जा सकती।

3 प्रश्रुति पर निर्भरता : भारतवर्ष में अधिकांश उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। सूती-वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, गूँठ-उद्योग आदि प्रमुख उद्योग कृषि पर आश्रित हैं। ज़रिफ़ रा. उत्पादन प्राकृतिक प्रकाशों के कारण अनिश्चित सा रहता है, फल-स्वल्प इन कारणांशों को दृष्टा साल विविधित रूप से तहों मिल पाता तथा मूल्यों में बहुत अधिक उतार-अवतर होते रहते हैं। इसका असर इन उद्योगों के विकास पर बुरा पड़ता है।

4 राष्ट्रीय शक्ति की कमी : भारतवर्ष में शक्ति के साधनों के रूप से खनिज तेल, कोयले व जल-विद्युत का प्रयोग किया जाता है। जल-विद्युत का विकास अभी तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया है। कोयला और खनिज तेल शक्ति के साधन के रूप में बहुत महँगे पड़ते हैं। बिना सस्ते शक्ति के साधन के औद्योगिक विकास गति की तीव्र नहीं किया जा सकता।

5. आधारभूत उद्योगों का अभाव : भारतवर्ष में उपभोग वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योगों का ही प्रमुखता से विकास हुआ है। इस्पात, सीमेंट, इन्जीनियरिंग, भारी रासायनिक तथा पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के उद्योगों का देश में यथोचित विकास नहीं हुआ है। जपान, स्विट्जरलैण्ड व इटली जैसे छोटे देशों में भी भारत की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली व इन्जीनियरिंग जैसे मूलभूत उद्योगों में समे हुये है।¹ मूलभूत उद्योगों के अभाव में सफल औद्योगीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती।

6 तकनीकी व प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव : भारत में तकनीकी विद्ये-एशी की कमी है। इसके अभाव में औद्योगीकरण को नई दिशाएँ व उचित मार्ग दर्शन नहीं प्राप्त हो पाता। कर्मचारियों में भी सामान्य प्रशिक्षण के अभाव में अपेक्षित पाये कुशलता नहीं पाई जाती। योजनाबद्ध में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम अपनाये के आवश्यक, भविष्य में कुशल, प्रशिक्षित एवं सुयोग्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाने की माता है।

7 सुयोग्य प्रबंधकों का अभाव : मेहनतबर्ष के मतानुसार, भारत के लोगों की निर्धनता, प्राणिक व सांस्कृतिक सम्पन्न तथा राशियों से चली आ रही सकृषित विचारधारा न सुयोग्य प्रबंधकों का अभाव पैदा कर दिता है।² सुयोग्य प्रबंधकों के अभाव में उद्योग-धन्धों का समुचित विकास नहीं हो सकता। जो योग्य प्रबंधक है वे भी निर्मा राशियों का राष्ट्रीय ह्वायों से ऊपर रखते हैं फलस्वरूप उद्योगों की गति अत्यन्त मन्द रही है और कुछ विषय क्षेत्रों तक ही सीमित रही है।

8 विवेकीकरण की भीमी प्रगति : भारतवर्ष के भूरी-वस्त्र, लूट व चीनी उद्योगों की मशीन क्रांती पुरानी पड़ गई है जिन्हे बदलने की प्रगति बहुत धीमी रही है। पुरानी मशीनों के कारण तथा विवेकीकरण की नीति को पूरी तरह न अपनाये जाने के कारण यहां के उद्योगों की लागत अधिक होती है जिसके व विदेशी प्रतिस्पर्द्धियों का सामना नहीं कर पाते और उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है।

9 कुशल की निर्धनता : 1950-51 आर० देशाई के मतानुसार औद्योगीकरण की नीमी गति के लिए कुशल की गरीबी जिम्मेदार है।³ कुशल की कम खर्च के अभाव में उद्योगों के बने हुए माल को आवश्यक बाजार नहीं मिल पाता, फलस्वरूप औद्योगिक विकास की गति भी मन्द पड़ जाती है।

10 करो की अक्षमता : गत वर्षों से भारत सरकार ने कई नये कर लगाने शुरू कर दिये हैं जैसे, उपहार कर, मृत्यु कर, सम्पत्ति कर, अदि। उत्पादक करो का

1 Economic Survey for Asia and Far East (1958) p. 96

2, Malleabattam Prospects for Indian Development p 163-64

3 Dr A. R. Desai Nationalism After Independence, p 107-8

भी भार अधिक है। इसके अलावा बिजली कर व स्वामीय करों की भी अघिबता है। इन वस्तुओं से एक ओर तो पूँजी के मूल्य में उदासोन्नता आती है और दूसरी ओर उद्योगपतियों में औद्योगिक विस्तार की भावना समाप्त हो जाती है।

11 औद्योगिक अन्तर्गत स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। सरकार ने अपनी श्रम-नीति के माध्यम से एक ओर तो श्रमिकों की मजदूरी, सखा, दानस, आदि में वृद्धि की अनिवार्य व्यवस्था की है तथा दूसरी ओर उनके संगठनों को अत्याधिक महत्त्व देकर उन्हें हड़तालों के लिए परीक्षम्भ से प्रेरित किया है। इन सबका प्रभाव उद्योगों के विकास पर बुरा पड़ा है।

12 परिवहन के साधनों का अपर्याप्त विकास : यातायात व परिवहन के साधनों की कमी जानकर उन स्थानों पर महसूस होती है, जहाँ उद्योगों का केंद्रीकरण हो गया है। तमाम उद्योगों के एक जगह केंद्रित हो जाने के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत कम महत्त्व के उद्योगों को यातायात सम्बन्धी कई कठिनायियों का सामना करना पड़ता है।

13 असंतुलित क्षेत्रीय विकास : भारत में, क्षेत्रीय व भौगोलिक दृष्टि से उद्योगों का संतुलित विकास नहीं हुआ है। बलरत्ता, बम्बई, नानपुर, जहमदाबाद, अमरावतीपुर, सोलापुर, भिलाई, दुर्गापुर, सिन्धी, कोटा, तामिलनाडू आदि शहरों में ही अधिकांश उद्योग केंद्रित हैं। देश का एक बहुत बड़ा भाग औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जब तथा कारखाना खोलने का समय आता है जो राजनैतिक दबाव के फलस्वरूप वे बरकरारने उल्टी ओर में खुल जाते हैं जहाँ पहले से ही कई कारखाने विद्यमान होते हैं।

14 भारत सरकार की औद्योगिक नीति : भारत में स्वतन्त्रता के बाद की औद्योगिक नीतियों की क्रमशः सन् 1948 व 1956 में घोषणा की गई तथा इसके बाद भी विभिन्न समर्थों पर इन औद्योगिक नीतियों में कई बार परिवर्तन किए गए। प्रो० यॉन का अनुमान है कि सरकार की औद्योगिक नीति ने उद्योगपतियों को निजी क्षेत्र की पूँजी की सुरक्षा के सम्बन्ध में थप एवं अका से डाल दिया है जिससे आशातीत पूँजी का निवेश उद्योगों में होकर उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक की।

भारत में तीव्र गति में औद्योगीकरण के लिए सुझाव

(Suggestions for Rapid Industrialization in India)

भारतवर्ष के औद्योगिक विभाग में उपबुक्त वर्णित बाधाओं से रोकें अट-नाये हैं। यदि हमें विदेश के औद्योगिक मानचित्र पर अपना स्थान बनाना है तो

औद्योगिक विकास के लिए कई कदम उठाने पड़ेंगे, यथा, (i) पूँजी निर्माण में वृद्धि-देय में पूँजी निर्माण में वृद्धि की जानी चाहिये। देशवासियों को बचत ■ लिए प्रोत्साहित करना चाहिये। औद्योगिक संस्थानों की दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख की पूर्ति के लिए वित्त निगमों के कोषों तथा कार्य क्षेत्र में वसूली की जानी चाहिये। (ii) प्राकृतिक संपत्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से विवेकपूर्ण किया जाना चाहिये। देश में उपलब्ध खनिज पदार्थों, वन्य जंगलों, बिजुल, शक्ति आदि का देश के औद्योगिक विकास के लिए यथोचित उपयोग किया जाना चाहिए। (iii) परिवहन व संचार-वाहन के साधनों का विकास किया जाना चाहिए ताकि देश के विभिन्न भागों से कच्चा माल एवं नरक औद्योगिक संस्थानों में सीमित मात्रा में एक कर्म क्षेत्र पर पहुँचाया जा सके साथ ही बड़े हुए माल को भी वायु मार्ग से सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। (iv) श्रमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण सुविधाओं व श्रमिकों की कार्यक्षमता में प्रयोजित वृद्धि की जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण, जागतिक व्यवस्था, लाभ सहभाग्य आदि योजनाओं द्वारा श्रमिकों में कार्य की प्रति रुचि एवं उत्साह पैदा किया जा सकता है। (v) विदेशी पूँजी को आकर्षित करने का प्रयत्न किए जाने चाहिए। भारत एक विकासशील देश है जिसके प्राकृतिक सौत विशाल हैं लेकिन देश की आन्तरिक पूँजी के द्वारा ही इन प्रबल साधनों का विवेकपूर्ण नहीं किया जा सकता। अतः सरकार को इन प्रकार की औद्योगिक नीति अपनानी चाहिए जिससे विदेशी पूँजीपति हमारे देश में पूँजी लगाने के लिए प्रोत्साहित हों। (vi) विदेशीकरण का कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए—भारत की अधिकांश चीनी, जूट एवं सूती वस्त्र उद्योगों की मशीनों को नहीं मशीनों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उद्योगों को चाहिए कि वे उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी सभी कार्यों में कुशलता की वृद्धि करें तथा खर्चों में घटो करें ताकि अत्यंत न्यय अधिन न जाए। (vii) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की कुशलता सुचारु उन्हे आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए (viii) निजी उद्योगों व सार्वजनिक उद्योगों में सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। देश के औद्योगिक विकास ■ सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर कार्य करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह निजी क्षेत्र की कच्चे माल व वित्त सम्बन्धी कठिनाइयों की दूर करे तथा इन उद्योगों को भी वही सुविधाएँ दिलाए जो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को प्राप्त हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र में सुविधाओं के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। (ix) कुटीर व लघु उद्योगों में तथा बड़े उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग की भावना का बढावा देना चाहिए तथा दोनों को विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। इन उद्योगों में बजाय प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए ताकि ये एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हुए देश के औद्योगीकरण की

शक्ति को सीधेता प्रदान करें। (2) श्रमिकों व मालिकों के सम्बन्धों को सुधुर बनाकर औद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए। आर दिन हड़ताल व तालेदन्धियों को रोमने के सभी सम्भव उपाय किए जाने चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त, योजनाबद्ध विकास के माध्यम से औद्योगिक निर्माण व विकास के कार्य देश में काफी प्रगति हुई है। सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के द्वारा सरकारी व निजी क्षेत्रों में विकास में तालमेल बँटाने की चेष्टा की है। उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध वित्तीय सम्पायें खोली गई हैं। शिक्षा-प्रणाली को भी अधिकधिक उद्योगोन्मुख बनाया गया है। औद्योगिक अनुसंधान को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा दूसरी संस्थाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कुछ चुने हुये क्षेत्रों में उपनुरा प्रोत्साहन देकर विदेशी पूँजी, तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के भी प्रयास किये गये हैं।¹ आशा है कि सही महँकारी नीति वा सम्बल पाकर, उद्योगवर्तिका व श्रमिकों के सहयोग से भारतीय उद्योग भविष्य में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त करेगा।

प्रश्न

1. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—'भारत में सौदा एवं उत्पात उद्योग'।
2. भारत में सूती-श्रम उद्योग अथवा चीनी उद्योग क विकास तथा विपन्न समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।
3. भारतीय औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों का संक्षेप कीजिए।
4. भारतीय उद्योगों की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए।
5. भारतीय सूती वस्त्र का विकास इत्यादि बताते हुये इसकी प्रगति का संक्षेप कीजिए और बताइये कि उद्योग के सम्मुख कौन कौन सी गम्भीर समस्याएँ हैं ?
6. भारतीय जूट उद्योग का विकास इत्यादि बताते हुये इसकी प्रगति का संक्षेप कीजिये और बताइये कि इस उद्योग के सम्मुख कौन-कौन सी गम्भीर समस्याएँ हैं ?
7. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से लौह तथा उत्पात उद्योग की प्रगति का संक्षिप्त विवरण कीजिए तथा यह भी बताइये कि राज्य ने इसके विकास के लिए क्या प्रयत्न किये हैं ?

1. दो कश्चरीयों के सहित भारत का औद्योगिक विकास-कुछ प्रमुख विवरण, आप्त समीक्षा, जनवरी 10, 1968

औद्योगिक वित्त

(Industrial Finance)

"Lack of finance has been the main drawback in the path of industrialisation of nearly all the underdeveloped countries. It is this factor that has been responsible for the co-existence of poverty and unused resources."

—U. N Report

वित्त आधुनिक उद्योग का जीवन रक्त है¹ इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उद्योगों की स्थापना एवं सफल संचालन के लिए उचित धन दर दर, सरलता में यथोचित मात्रा में वित्त की पूर्ति आवश्यक है। आखिरी उत्पादन की क्रियाएँ विशाल पैमाने पर की जा रही हैं, आज विश्व का कोई भी देश, औद्योगिक उत्पादन उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि उद्योगों में लगाने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पूँजी न हो। आधुनिक विश्वासकाय उद्योगों के लिए तो पूँजी मात्रा के समान है। उनकी सफलता एवं असफलता इसी की पूर्ति पर निर्भर करती है। यद्यपि पूँजी की आवश्यकता छोटे पैमाने के उद्योगों को भी होती है, परन्तु उनकी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से की जा सकती है, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत बहुत कम पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। बड़े उद्योगों को बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति किसी एक साधन से करना प्रायः असम्भव होता है। डा० नाभागोपालदास के मतानुसार, किसी भी उत्पादक संस्था के लिए आज के युग में, वित्त की व्यवस्था सरलतापूर्वक नियमित रूप से तथा उचित दर पर होना अत्यन्त आवश्यक है।²

औद्योगिक वित्त की आवश्यकता - उद्योग बड़ा हो अथवा छोटा, बिना पूँजी या वित्त के नहीं चलाया जा सकता। कार्य-संचालन के लिए उद्योगों को अल्पकालीन

1. "Finance is the life blood of Industry"

2. Nabhogopal Das : *Industrial Enterprise in India*, p. 14

ए दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है। कच्चे माल की खरीददारी के लिए, मजदूरी व वेतन के भुगतान के लिए, बनी हुई वस्तुओं की बिक्री तथा भेजने के लिए और इसी प्रकार के अन्य छोटे-मोटे कार्यों के लिए अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। भवन निर्माण, मशीनों के क्रय आदि के लिए दीर्घ-कालीन पूँजी या वित्त की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः पूँजी बाजार उद्योगों की दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जबकि मुद्रा बाजार अल्प-कालीन वित्त सम्बन्धी प्रवस्था करता है।

औद्योगिक वित्त स्रोत : भारतवर्ष में औद्योगिक वित्त कई स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं—

1. निजी पूँजी (Personal Capital) : निजी पूँजी उद्योग में लगाई जाती है। प्रारम्भ में उद्योग निजी पूँजी के बल पर ही चलाये जाते थे। आज भी औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में निजी पूँजी लगी हुई है। कई क्षेत्रों में निजी पूँजी के साथ-साथ अन्य स्रोतों से भी पूँजी प्राप्त की जाती है, ताकि उद्योग की सुरक्षापूर्वक चलाया जा सके। बहुत से नए उद्योगों की प्रारम्भिक काल में, जब उन्हें पूँजी मिलने का कोई अन्य साधन नहीं था, तब इसी साधन से पूँजी प्राप्त होती थी। पुरानों औद्योगिक मरचाओं की भी सृष्टि के समय प्रायः निजी पूँजी से ही सहायता मिलती है।

2. जनता द्वारा निवेश (Investment by Public) : उद्योग साधारणतः विभिन्न प्रकार के अंशों का निर्माण करते हैं, जैसे पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares), सामान्य अंश (Equity Shares) आदि। साधारण जनता अपनी इच्छा से इन अंशों की खरीदती है। उसे इस वित्तियोग के प्रतिफलस्वरूप लाभांश (Dividend) प्राप्त होता है तथा उद्योग को आवश्यक पूँजी मिलती है। अधिक आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक संस्थाएँ ऋण पत्र जारी करके जनता से आवश्यक पूँजी प्राप्त कर सकती हैं। ऋण-पत्र भी कई प्रकार के होते हैं। भारतवर्ष में ऋण-पत्र अधिक प्रचलित नहीं हो पाये हैं, क्योंकि (i) हमारे देश में सुव्यवस्थित पूँजी बाजार नहीं पाया जाता, (ii) ऋण-पत्र धारियों को अध्याधिकारों की अपेक्षा कम सुविधाएँ दी जाती हैं। (iii) इन्हें न तो कम्पनियों और न ही निवेशकों अधिक पसन्द करते हैं। (iv) भारत के बैंक भी उन कम्पनियों को उधार देने में हिचकती हैं जिन्होंने ऋण-पत्र बेचकर पूँजी प्राप्त की हो। (v) सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ अधिक लोकप्रिय हैं।

इस प्रकार भारतवर्ष में औद्योगिक संस्थाएँ अपनी स्थायी पूँजी का अधिकांश भाग अंश पत्रों द्वारा ही प्राप्त करती हैं। विगत वर्षों में भारत में अल्प पूँजी का निर्माण अपरिचित रहा है :

वर्ष	1951	1956	1961	1966	1967	1968	1970
घन राशि (करोड़ रु० में)	79	451	596	483	460	770	1201

3 प्रबन्ध अभिकर्त्ता (Managing Agents) भारतवर्ष में औद्योगिक विकास के अभाव के कारण, औद्योगिक वित्त प्रदान करने का प्रमुख दायित्व प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं पर हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, फर्म व्यवसाय कम्पनी, जिसे कम्पनी के साथ किए गए समझौते के अनुसार कम्पनी के कार्यों की व्यवस्था का अधिकार प्राप्त हो, प्रबन्ध अभिकर्त्ता कहलाता है। यह प्रणाली विश्व में अपने स्तर की निरासी प्रणाली है जो विश्व के अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती। प्रबन्ध-अभिकर्त्ता, औद्योगिक संस्थान की प्रारम्भिक पूँजी जुटाने में सक्रिय सहयोग देते हैं। वे लोग स्वयं बड़े-बड़े व्यवसायी होते हैं। उद्योग या कम्पनी के विकास एवं विस्तार में लगे जब यह आवश्यक पड़े तो वे भी स्वयं ही व्यवसायी बन जाते हैं। इनकी मजदूरी से प्रभावित होकर जनता भी उद्योग-पत्रों में सरलता से पूँजी लगाने को तैयार हो जाती है। प्रबन्ध अभिकर्त्ता ही ही बारम्बार पर बैंक भी कम्पनी को पूँजी उधार देने को तैयार हो जाते हैं।

प्रबन्ध अभिकर्त्ता सामान्यतः निम्नलिखित कार्य करते हैं। (i) वे किसी भी नई कम्पनी अथवा फर्म को स्थापना में प्रवर्तक तथा प्रमोटर (Promotees and pioneers) का कार्य करते हैं, (ii) वे नए उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी की व्यवस्था करते हैं, उनके पुनर्संयोजन, विप्रेक्षीकरण एवं प्रसार के लिए दीर्घ पूँजी तथा अन्य कार्यों के लिए अल्पकालीन पूँजी प्रदान करते हैं, (iii) वे उद्योगों के दैनिक प्रबन्ध का कार्य करते हैं, तथा (iv) वे उद्योग के लिए बड़े माल, मशीनरी के खरीदने में तथा बने हुए माल को बेचने में एजेंट का कार्य करते हैं।

भारत के औद्योगिक विकास में अभिकर्त्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस योगदान की पूर्वांक करते हुए राजकोषीय आयोग (Fiscal Commission 1945-50) ने कहा था, 'बिना 75 वर्षों में प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली ने भारतीय उद्योगों की महत्वपूर्ण सेवा की है। औद्योगीकरण के प्रारम्भिक दिनों में जब न तो उद्योगों की ही अभिकर्त्ता थी और न पूँजी की ही, प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने उद्योगों की व्यवस्था की। भारत के सूती वस्त्र, जूट तथा इस्पात आदि मुख्यवस्तु उद्योग अपनी वर्तमान स्थिति के लिए कई सुविधाएँ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के उत्साहपूर्ण नेतृत्व के श्रेणी हैं।'।

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली ने निस्सन्देह भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन बिना कई नयीं से इस प्रणाली में कई दोष आ गए हैं, इनमें से प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं —

(i) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के अन्तर्गत उद्योगों में औद्योगिक प्रतिफल की अपेक्षा आर्थिक प्रभुत्व प्रदान हो जाता है ।

(ii) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के अन्तर्गत एक अभिकर्ता के अधीन अनेक उद्योग-धर्मों की व्यवस्था रहने के कारण, व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती ।

(iii) अनेक प्रबन्ध अभिकर्ता कर्मों की व्यवस्था अयोग्य एवं अष्टाचारी व्यक्तियों द्वारा होती है, जिससे इस प्रणाली में नियन्त्रण सम्बन्धी अनेक गृहाण्य आ गई है ।

(iv) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रायः अपने अधीन एक कम्पनी की भाविन्य-राशि दूसरी कम्पनियों में लगा देते हैं । एक इकाई के विस्तारीकरण के लिए उपलब्ध धन को दूसरी इकाई के पुनर्जीवन के लिए लगा दिया जाता है जिससे अनार्यिक इकाइयाँ आर्थिक इकाई की कीमत पर जीविन रहती है ।

(v) व्यक्तिगत भ्रष्टा, उत्पादन पर कमोबस, कष्ट माल वर कमोबस, कार्यालय चलाने के लिए घनराशि आदि के रूप में प्रबन्ध अभिकर्ता बहुत बड़ी घनराशि कम्पनियों से प्राप्त करके उनका पोषण करते हैं ।

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के अन्तर्गत उत्तम नीतियों को दूर करने के लिए भारतीय कम्पनी अभिनियम में समय समय पर संशोधन किए गए हैं । सन् 1968 के संशोधन के अनुसार 1 अप्रैल, 1970 से देश के सभी उद्योगों से प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है ।

4 औद्योगिक बैंक (Industrial Banks) उद्योगों की दीर्घकालीन धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सन् 1905 से ही हमारे देश में औद्योगिक बैंकों के स्थापित किए जाने की चर्चा चल रही है । भारतवर्ष में टाटा औद्योगिक बैंक, फलकता औद्योगिक बैंक तथा भारतीय औद्योगिक बैंक क्रमशः सन् 1917, 1919 व 1920 में स्थापित किये गए, परन्तु प्रथम की छोड़कर बाक्य असफल साबित हुए । हमारे देश में ये बैंक औद्योगिक बैंकिंग सिद्धांतों के अनुकूल ठीक प्रकार से कार्य नहीं करने के कारण फल नहीं सके ।

5 देशी महाजन (Indigenous Bankers) देशी महाजनो व बंकरों द्वारा भी उद्योगों की आवश्यकता के समय वित्त प्राप्त होता रहा है । वृत्ति कि इनके साधन सीमित होते हैं अतः ये साधारण छोटे औद्योगिकों को ही वित्त प्रदान कर पाते हैं । जहाँ तक बड़े उद्योगों का प्रश्न है, उनकी आवश्यकताएँ बहुत अधिक होती हैं ।

अतः ये देशी महाबन्धो पर निर्भर नहीं करते। ये लोग सामान्यतः व्यक्तिगत बाण्ड (Personal Bonds) पर ऋण देते हैं तथा व्याज की दर अपेक्षाकृत अधिक लेते हैं। वायुनिक युग में बैंकों के वित्तीय निगमों के प्रादुर्भाव के कारण इनका कार्यक्षेत्र एवं महत्व औद्योगिक वित्त के संदर्भ में काफी कम हो गया है।

6 व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) व्यापारिक बैंक सामान्यतः अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं जिनकी अवधि 1 वर्ष तक की होती है। ये धरोहर रखकर भी ऋण देते हैं। साधारणतः धरोहर के 70 प्रतिशत भाग तक ऋण के रूप में दिया जाता है। गारन्टी पद्धति के कारण, बड़ा उद्योगपति ही इन बैंकों से रुपया प्राप्त कर पाते हैं। ये बैंक अधिकतर कार्यवाहक पूँजी ही प्रदान करते हैं। ये बैंक कम्पनियों के अल्प अवधि ऋण पत्र खरीद कर स्थायी पूँजी की व्यवस्था करने से हमेशा कष्टागते रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से इनकी पूँजी सकट में पड़ सकती है और ये अपनी पूँजी को सकट में नहीं फँसाना चाहते हैं। वित्त कुछ वर्षों से सरकार तथा रिजर्व बैंक ने भारतीय व्यापारिक बैंकों को, उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया है। सन् 1951 में अनुसूचित बैंकों ने अपनी अधिम राशि का 33.6 प्रतिशत उद्योगों को उधार दिया था जो 1961, 1964 व 1966 में बढ़कर क्रमशः 52.7 प्रतिशत, 59.2 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत हो गया। व्यापारिक बैंकों से वित्तीय सहायता के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि का दो तिहाई भाग जिन चार उद्योगों को प्राप्त हुआ, वे हैं, सूती वस्त्र, इजीनियरिंग, चीनी, गूँड़ तथा जूट।

7 बीमा कम्पनियाँ (Insurance Companies) उद्योगों को पूँजी प्रदान करने वाली संस्थाओं में बीमा कम्पनियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व भी जीवन बीमा कम्पनियाँ अपनी पूँजी का एक महत्वपूर्ण भाग उद्योगों में वित्तियोजित करती थीं। सन् 1956 में जीवन बीमा कम्पनियों में राष्ट्रीयकरण के बाद, अब जीवन बीमा निगम भी उद्योगों में पर्याप्त पूँजी लगा रहा है। यह दीर्घकालीन ऋण देने में समर्थ है। जीवन बीमा निगम अपने विविध फण्ड का एक बड़ा भाग तक उद्योगों में लगा सकता है। 31 मार्च, 1970 को निगम की कुल सम्पत्ति लगभग 134.8 करोड़ रु० थी। इस धनराशि में से लगभग 210.4 करोड़ रु० की राशि अक्षरों तथा ऋण पत्रों में वित्तियोजित थी, जो कुल वित्तियोजनों की लगभग 15.6 प्रतिशत होती है।

8 सार्वजनिक जमा (Public Deposits) कुछ कम्पनियाँ सार्वजनिक जमा प्राप्त करके अपनी वित्त सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। यह प्रणाली

अहमदाबाद व बम्बई के सूती-यस्त्र उद्योग में पाई जाती रही है। लोग कारखानों में अपनी पूँजी जमा कर आते हैं तथा इस पर व्याज प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली जोखिम से भरी हुई है, क्योंकि जनता में यदि कम्पनी के प्रति अविश्वास पैदा हो जाय तो जनता अचानक अपनी पूँजी वापस निकालना प्रारम्भ कर देती है। इससे कम्पनी की स्थिति खराब होने लगती है। इस प्रकार की जमा सिर्फ अच्छे मौसम के दिनों के रूप में ही साबित हो सकती है।

केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार बम्बई में सूती यस्त्र मिलों में अपनी कुल पूँजी का 11 प्रतिशत भाग तथा अहमदाबाद की मिलों में 39 प्रतिशत भाग साप्ताहिक जमा के रूप में प्राप्त किया था। लेकिन विगत 20 वर्षों से मासिक जमा का महत्व निरन्तर कम होता जा रहा है।

9 विनियोग प्रभुता (Investment Trusts) ये ट्रस्ट या प्रभुता भी उद्योगों में पूँजी जमा कर उनकी वित्त प्रदान करते हैं। ये संस्थाएँ विनियोजकों के लिए प्रतिभूति की वी सरीहने व खेपने का कार्य करती हैं तथा इन विनियोजकों द्वारा विनियोजकों को लाभ उपलब्ध करती हैं। भारतवर्ष में ये संस्थाएँ सन् 1930 से प्रारम्भ हुई थीं। इन समय भारतवर्ष में इन संस्थाओं की संख्या 600 से भी ऊपर है। इनकी पूँजी अधिकतर साधारण बंधों में लगाई जाती है। औद्योगिक वित्त व्यवस्था में इन संस्थाओं का कोई विशेष महत्वपूर्ण योगदान नहीं है।

10 सरकार द्वारा वित्तीय सहायता। भारतवर्ष में केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारें भी उद्योगों को आवश्यक वित्त प्रदान करने में सहयोग प्रदान करती हैं। राजकीय सहायता अधिनियम (State Aid Industries Act) के तहत राज्य सरकारें उद्योगों को वित्तीय सहायता देती हैं। इस्पात, उर्वरक, सोडेट, कोयला उद्योग आदि उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने पर्याप्त पूँजी लगाई है। सरकार उद्योगों के हिसते खरीद कर या वित्त निगमों के अथ खरीद कर भी उद्योगों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराती है।

11 औद्योगिक सहकारी समितियाँ हमारे देश के प्रायः प्रत्येक राज्य में लघु उद्योगों की आर्थिक गठायता देने का प्रमुख सामन औद्योगिक सहकारी समितियाँ हैं। प्रत्येक राज्य में स्थापित आदी एवं ग्रामीण मण्डल, विभिन्न वर्गों के उद्योगों की औद्योगिक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण व अनुदान देते हैं। सहकारी समितियाँ अथ पूँजी तथा ऋणों के माध्यम से वित्तीय सभन प्राप्त करती हैं तथा संस्था को सस्ती व्याज दर पर धनराशि उधार देती हैं।

12 विदेशी पूँजी - भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों का विकास विदेशी पूँजी की सहायता से ही हुआ है। आजकल पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत हमें विदेशों से काफी पूँजी प्राप्त हो रही है। भारतवर्ष में इस समय विभिन्न क्षेत्रों में लगभग

2000 करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी लगी हुई है। इसमें से 1,200 करोड़ रुपये की पूँजी से कार्वेजमिड क्षेत्र में लगी हुई है तथा बाँप 800 करोड़ रुपये की पूँजी निजी क्षेत्र के उद्योगों में लगी हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम, विदेव बैंक, अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी तथा अन्य सरथाएँ, रुस, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, गुवाटेमाला आदि की सरकारों द्वारा विदेशी सहायता व पूँजी भी हमारे उद्योगों को प्राप्त हो रही है।

13 वित्तीय संस्थाएँ स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ष में उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गई है। ये संस्थायें बड़े व छोटे सभी प्रकार के उद्योगों को ऋण, मध्यम व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करती हैं। ये संस्थायें निम्नलिखित हैं

(प्र) औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation)

इस निगम की स्थापना सन् 1948 ई० में की गई थी।

(1) निगम के वित्तीय साधन इस निगम की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 10 करोड़ रुपये है जो कि 5,000 रुपये के 20,000 अंशों में बँटी हुई है। प्रारम्भ में केवल 5 करोड़ रुपये की पूँजी निर्गमित की गई जो 10,000 अंशों में विभाजित थी। 1960-61 में 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अथवा पूँजी निर्गमित की गई। भारत सरकार ने निगम के प्रारम्भिक 5 करोड़ रुपये के अंशों पर 2½ प्रतिशत वार्षिक वा निम्नतम लाभांश तथा 2 करोड़ रुपये के अनिश्चित अंशों पर 4 प्रतिशत वार्षिक लाभांश तथा मूलधन बुझाने की गारंटी दी है। मार्च 1972 तक निगम की प्राप्त पूँजी (Paid up Capital) 5.35 करोड़ रुपये के बराबर थी। औद्योगिक वित्त निगम में पूँजी केन्द्रीय सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाई जाती है। यह निगम खले बाजार में वाण्ट व ठग पत्र भी जारी कर सकता है। यह विश्व बैंक तथा अिन्सी सातो ॥ मुद्रा प्राप्त करता है। इसे 18 सहोनों के लिए 3 करोड़ रुपय तक िर्च बैंक में भी प्राप्त हो सकत है। मार्च 1972 तक इस निगम ने कुल 159.31 करोड़ रुपये के ऋण लिए थे, जिसमें से 61.25 करोड़ रुपये बॉन्डों तथा ऋण पत्रों द्वारा, 75.67 करोड़ रुपये भारत सरकार से, 22.03 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा में तथा 36 लाख रुपये रिजर्व बैंक से प्राप्त किए थे।

(2) प्रबन्ध नियम का प्रबंध एक निर्देश मण्डल (Board of Directors) द्वारा किया जाता है, जिसमें 12 सदस्य होते हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार व रिजर्व बैंक के 3-3 मनोनीत व्यक्ति होते हैं। बाँप 6 निगम के अन्य भागीदारों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, विनियोग प्रस्थाओं व सहकारी बैंकों द्वारा चुने जाते हैं। निर्देशक मण्डल 5 व्यक्तियों की एक कार्यवाहिणी समिति को अपने अधिकार दे

देता है। इसी से एक प्रबन्ध निर्देशक (Managing Director) भी होता है। यह समिति ही वास्तुतः इस निगम की व्यवस्था करती है। निगम का कार्य देश के उद्योग, व्यापार तथा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक मिष्ठान्तों पर चलाया जाता है। लेकिन वैदेशीय सरकार मण्डल की नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर निर्देश दे सकती है।

(1) कार्य औद्योगिक वित्त निगम के प्रमुख कार्य है, (1) औद्योगिक संस्थानों की ऋण सेवा प्रविष्ट देना तथा उनके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों की क्षीरता गारन्टी भर्तान 25 वर्षों में किया जा सकता है।

(2) यह निगम औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जुके बाजार में जारी किए गए ऋणों तथा अनुसूचित क्षेत्रों व राज्य सहकारी क्षेत्रों से लिए गए ऋणों, जिनका भुगतान 2^५ वर्ष की अवधि में होना हो, गारन्टी दे सकता है।

(3) यह निगम औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ऋणों व ऋण पत्रों की हामी (Underwrite) भर सकता है। लेकिन जो ऋण पत्र व ऋण यह कार्य करते समय इसके पास रहे जाय, वे 7 वर्ष के अन्दर अवश्य बेच दिए जाने चाहिए।

(4) कुछ विद्युत उद्योगों की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में सहायता करना।

(5) विदेशी बैंक व विदेशी संस्थाओं से लिए गए ऋण व साज प्रदत्त पर गारन्टी देना।

(6) औद्योगिक संस्थाओं के रेटाफ व बतों का कर करना।

(7) कुछ स्वीकृत औद्योगिक संस्थाओं द्वारा व्यापार की जाने वाली पूंजी-यन वस्तुओं पर विलम्बित भुगतान (Deferred Payment) के सम्बन्ध में गारन्टी देना।

यह निगम ऋण चाहने वाले संस्थानों के आवेदन पत्रों का ऋण स्वीकृत करने से पूर्व निरीक्षण करता है और ऋण स्वीकृत करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है (1) उद्योग का राष्ट्रीय महत्व, (2) प्रयत्न की सुरक्षा, (3) कार्यक्रम की लागत, (4) उत्पादों की किस्म, (5) प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति की प्रकृति, (6) प्राविधिक कर्मचारियों एवं कर्मियों माल की पूर्ति की पर्याप्त, तथा (7) निमित्त उत्पादों की सेवा के लिए आवश्यकता।

यह निगम 1960 के अधिनियम के बाद से, विदेशी औद्योगिक संस्थानों की हिस्सा पूंजी में सीधे योगदान दे सकता है। यह केवल गार्वेजिनिक संस्थानों व सहकारी संस्थानों को ही ऋण देता है, निजी संस्थानों को व सार्वकारी संस्थानों को ऋण नहीं देता। खान, उद्योग, जहाजरानी व विजली उद्योगों को मध्य व दीर्घकालीन ऋण दे सकता है। यह अधिक से अधिक किसी एक संस्थान को 1 करोड़ रुपये का

ही ऋण दे सकता है तथा ऋण की अधिकतम अवधि 25 वर्ष हो सकती है। पहले ब्याज की दर 7.5% थी, परन्तु मार्च सन् 1965 से देशी ऋणों पर ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत तथा विदेशी ऋणों पर 9 प्रतिशत कर दी गई है। ऋण तथा ब्याज का भुगतान समय से करने पर आये प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(iv) कार्यों की प्रगति मार्च 31, सन् 1971 तक इस निगम के द्वार 363 करोड़ रुपये ऋण के रूप में देने स्वीकार किए तथा 313 करोड़ रु० बाँटे गए। जिन उद्योगों ने इस निगम से ऋण प्राप्त किया, वे ये हैं—साद्य, निर्माण उद्योग, खनिज उद्योग, सर्वरक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट, शीशा, रबर उद्योग आदि। निगम ने सन् 1957 से अधिगोपन कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है, तब से लेकर 31 मार्च 1969 तक उसने 2701 करोड़ रुपये की राशि के अधिगोपन स्वीकार किए। निगम द्वारा लगभग 70 प्रतिशत सहायता, स्वयं बचाव प्राप्त के पश्चात् प्रारम्भ किए गए नए उद्योगों को प्रदान की गई है। निगम द्वारा कुछ राज्यों को अधिक ऋण दिए गए हैं—महाराष्ट्र, प० बंगाल व मद्रास तथा कई क्षेत्र उपेक्षित रह गए हैं। इसी प्रकार ऋण-राशि ने भी पर्याप्त विविधता पाई जाती है। मण्डलि ऋणों की राशि 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ तक रही है तथापि अधिकांश ऋण 40 से 50 लाख रु० के मध्य के ही रहे हैं। निगम द्वारा दिए गए अधिकांश ऋणों की अवधि 12 वर्ष की रही है लेकिन कुछ ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए भी दिए गए हैं। निगम की आय तथा लाभ से संचालित वृद्धि हुई जो इस बात की पुष्टि करता है कि निगम अपने कार्य में आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त कुशल साबित हुआ है।

(v) सामाजिकता औद्योगिक वित्त निगम की कई प्रमुख आलोचनाएँ की गई हैं जैसे, (1) इसने देश के अर्थ विकास क्षेत्रों जैसे राजस्थान, मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास में बहुत कम सहायता पहुँचाई है, (2) निगम ने उद्योगों को जोखिम पूँजी नहीं दी है, (3) ऋण की स्वीकृति में बहुत विस्मय हो जाता है, (4) ऋण देते समय कई नवी शर्तें लगाई जाती हैं, (5) ऋण देने में पक्षपात किया जाता है, (6) केवल सर्वजनिक व सहायरी संस्थाओं को ही ऋण दिया जाता है, (7) निगम संपत्ति वधक के अतिरिक्त, प्रबन्ध-प्रतिकर्ताओं को वैयक्तिक गारन्टी लेता है, तथा (8) अधिगोपन (Underwriting) के क्षेत्र में निगम ने कोई विशेष प्रगति नहीं की, आदि।

उक्त आलोचनाओं में कुछेक तो सचित हैं, शेष सचित नहीं हैं। निगम का कार्य सामान्यतः सराहनीय रहा है। इसके वित्तीय साधन सीमित हैं, अतः इसे सोच-

समझ कर ही दान देना पड़ता है। जोखिम-पूर्ण क्षेत्रों में यह अपने साधनों की नहीं लगा सकता। यही उद्योगों की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए निगम के नाम को पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, तथापि इस क्षेत्र में इसने जो कुछ किया है, वह सराहनीय है। आशा है भविष्य में भी यह उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान करता रहेगा।

(3) राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का कार्य क्षेत्र नीम्नलिखित होने के कारण, भारत सरकार ने लघु व मध्यम उद्योगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिये 28 नवम्बर सन् 1951 को राज्य वित्त अधिनियम पारित किया। अब इस प्रकार के निगम भारत के प्रायः सभी राज्यों में बन चुके हैं। जो सब भारतीय वित्त निगम से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें इन निगमों से ऋण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राज्य वित्त निगम की अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) कम से कम 50 लाख रुपये से लेकर अधिक से अधिक 5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इन निगमों के हिस्सेदार, राज्य सरकारें, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, सरकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ होती हैं। जिससे से तीन चौथाई अब पूंजी सरकारों, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कंपनियों, विनियोग ट्रस्ट तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। शेष एक चौथाई अन्य पक्ष द्वारा। राज्य वित्त निगम किसी एक संस्था को अधिक से अधिक 10 लाख रुपये तक की सहायता दे सकता है। ये अपने साधनों को बढ़ाने के लिए बॉन्डों व ऋण पत्रों का विक्रय कर सकते हैं तथा जनता से 5 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए ब्याज स्वीकार कर सकते हैं।

संरचना—इन निगमों का प्रबंध संचालन औद्योगिक वित्त निगम की ही तरह होता है। जिसमें एक प्रबन्ध संचालक एवं कार्यकारिणी गमिनि होती है। राज्य वित्त निगम राज्य ॥ विधि व स्थानों पर अपने कार्यालय खोल सकते हैं। राज्य सरकार की रिजर्व बैंक की सलाह से निगम को नीति सम्बन्धी निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है।

कार्य—राज्य वित्त निगम निम्नांकित कार्य कर सकते हैं

- (1) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए, किए गए ऋणों पर गारंटी देना, (2) औद्योगिक संस्थाओं के अना, स्टॉक व ऋण पत्रों का अधिगोपन करना, (3) औद्योगिक संस्थाओं की अधिकाधिक 20 वर्ष ॥ लिए ऋण अथवा ऋण देना, (4) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा निर्मित ऋण पत्रों में पूंजी लगाना।

प्रगति - इस समय भारतवर्ष में 18 राज्य वित्त निगम हैं। प्रायः प्रत्येक राज्य में एक वित्त निगम है। मार्च 1972 तक इनकी कुल प्रदत्त पूंजी 23.16 करोड़ रुपये था तथा इन निगमों ने इसी अवधि तक 154.71 करोड़ रुपये की सहायता दी।

आलोचना - राज्य वित्त निगमों की आशानुमूल सफलता नहीं मिल पाई है। मनु उद्योगों की वित्तीय सहायता करने में वे असमर्थ रहे हैं। निजी क्षेत्र को प्रति वर्ष अपने विभाग कार्यों के लिए 300 से 350 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिसका केवल 3/4 प्रतिशत मात्र ही यह प्रदान कर पाते हैं। इन निगमों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है :

(i) इनके पास बहुत बड़ा धन भंडार प्रयोग के पड़ा रहता है; (ii) निगमों द्वारा ऋण की स्वीकृति तथा वास्तविक अदायगी में बहुत समय लग जाता है, (iii) निगमों द्वारा वसूल की जाने वाली व्याज की दर बहुत अधिक है; (iv) लाभार्थी के भगतान के लिए इन्हें राज्य सरकारों पर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि इनके साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, (v) औद्योगिक संस्थानों की आर्थिक स्थिति, उनकी सम्पत्तियों का मूल्यांकन एवं रेहन संबंधों की गटलिताओं के कारण, इनका कार्य कुशलता एवं क्षीप्रता में नहीं हो पाता।

(इ) भारतीय औद्योगिक साख व निवेश निगम (Industrial Credit and Investment Corporation) भारतीय कंपनी कानून के अन्तर्गत इन निगम की स्थापना एक निजी सीमित कम्पनी के रूप में जनवरी सन 1955 में हुई थी। निगम की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 3 करोड़ रुपये है, जो 100-100 रुपये के अंशों में विभक्त है। इनकी प्राप्ति पूंजी में भारतीय बैंकों व बीमा कम्पनियों का 2 करोड़ रुपये, यूनाइटेड निगम व पूंजीपतियों का 1 करोड़ रुपये, अमेरिकी पूंजीपतियों का 5 लाख रुपये तथा भारतीय जनता का 15 करोड़ रुपये है।

निगम का उद्देश्य—इन निगमों के उद्देश्य हैं (i) निजी क्षेत्रों के उद्योगों के निर्माण, विकास तथा उद्योगीकरण में सहायता देना, (ii) उद्योगों में देशी अथवा विदेशी पूंजी के प्रवेश का प्रोत्साहित करना, तथा (iii) विनिवेश बाजार के विस्तार को प्रोत्साहित करना।

निगम के कार्य : यह निगम उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करता है : (i) यह निगम निजी उद्योगों को मध्यम व दीर्घकालीन ऋण देता है; (ii) यह निगम नये वस्तु व प्रतिभूतियों का जमागोपन करता है; (iii) यह निगम निजी साधनों से प्राप्त ऋणों की गारन्टी देता है, (iv) आवश्यकता पड़ने पर

तकनीकी, प्रशिक्षण-सम्बन्धी तथा प्रशासनात्मक परामर्श भी देता है; (४) उद्योगों के विकास और नए आविष्कारों की व्यवस्था करना; तथा (५) नए व्यवसायी तथा विनिर्माणों को प्रोत्साहन देना ।

प्रगति : अपने विगत 17 वर्षों के कार्यकाल में निगम ने औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण काम किया है । जनवरी 1955 से मार्च 1971 तक निगम ने 304 करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति प्रदान की है ।

(ई) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) इस निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा 20 अक्टूबर सन् 1954 में की गई । इस निगम की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपये है तथा प्रवृत्त पूंजी 10 लाख रु है, जो भारत सरकार द्वारा ही प्रदान की गई है । भारत सरकार ऋण व अनुदान के रूप में भी इसे आवश्यक बन देती रहती है । यह निगम सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को वित्त प्रदान करता है । यह निगम मूल्यवत् पुनर्स्थापन एवं मशीनीकरण के लिए तथा मशीन आदि खरीदने के लिए ऋण प्रदान करता है तथा उद्योगों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका सम्बन्ध आवेदनित विकास से है । यह पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देता है । यह निगम ऐसे उद्योगों की स्थापना भी करता है जो निजी क्षेत्र में सहायक उद्योगों की वृद्धि के लिए पथ-प्रदर्शन करे । यह उद्योगों के अर्थो, ऋण-पत्रों का अभिगोपन करता है तथा उनकी गारंटी करता है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने सूची बन्ध उद्योग, जूट उद्योग तथा मशीन उपकरण उद्योग को विशेष लाभ पहुँचाया है । 31 मार्च 1971 तक इस निगम ने इन उद्योगों के लिए 28.02 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी थी, जिनमें से 18.7 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका था ।

(ए) राज्य औद्योगिक विकास निगम नई राज्य सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्र में, औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए 1960 में राज्य औद्योगिक विकास निगम (State Industrial Development Corporation) की स्थापना की है । ये निगम राज्यों में उद्योगों का प्रवर्तन, सुधार तथा विकास करते हैं । ये निगम प्रत्यक्ष विनियोग, ऋण स्थिति गुणतान, ऋणों के लिए गारन्टी, अर्थो, ऋण पत्रों एवं बांडों के निर्माण का अभिगोपन व खरीद आदि के द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को सहायता पहुँचाते हैं । सन् 1971 तक भारत में इस प्रकार के 19 निगम विभिन्न राज्यों में स्थापित थे । महाराष्ट्र तथा गुजरात के निगमों को छोड़ कर बानी राज्यों के निगमों की अध पूंजी पूर्ण रूप से राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारें इन निगमों की आवश्यकतानुसार ऋण, अग्रिम एवं अनुदान देती रहती है । इस निगमों

के कौनों को कुछ बाजार में बाँझे, न्यून पत्रों के निर्माण तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों, देवों व अन्य वित्तीय संस्थाओं या व्यक्तियों के अनुदान, चन्दे, न्यून अधिप, जमाओं आदि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। (1971-72 के दौरान, इन्होंने 20 करोड़ की वित्तीय सहायता दी।

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) देश के औद्योगिक विकास को बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मई 1964 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कार्य प्रारम्भ किया। इसकी स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्य थे, एक ओर तो उत्तरोत्तर औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा दूसरी ओर औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। इन बैंक की अधिकतम पूँजी 50 करोड़ रुपये है, जो 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। इसके द्वारा 10 करोड़ रुपये की पूँजी निर्मित की गई है। निर्मित पूँजी की मात्रा की भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साधनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का व्याज से मुक्त ऋण भी दिया है, जिसका भुगतान 15 वर्ष के पश्चात् 15 समान किश्तों में किया जायेगा। विकास बैंक रिजर्व बैंक में भी अल्प, मध्यम व दीर्घकाल के लिए वित्तीय सहायता से सज्जता है। यह बैंक निजी व सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है तथा खनिज, परिवहन, निर्माण, होटल आदि उद्योग इनकी परिधि में आ जाते हैं।

औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- (1) देश में अन्य वित्तीय संस्थाओं के कौनों से सम्बन्ध करना तथा इन संस्थाओं के लिए दीर्घ संस्था के रूप में कार्य करना,
- (2) उद्योगों के लिए जबकि वित्त (term finance) का प्रवर्ण करना तथा औद्योगिक दृष्टिकोणों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना,
- (3) मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त में पूर्ण व माय सम्बन्धी अनजान-छाओं को दूर करना।

इस बैंक के प्रमुख कार्य हैं (1) भारतीय औद्योगिक वित्त नियम तथा राज्य वित्त नियमों की 3-25 वर्षों तक का पुनर्वित्त प्रदान करना, ताकि वे उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, (2) औद्योगिक संस्थाओं के ऋण पत्र, अथवा अति लघुदस्तावेज, (3) औद्योगिक संस्थाओं के ऋण-पत्रों व अर्थों का मजिगोरन करना, (4) औद्योगिक संस्थाओं को प्रमुख ऋण देना इसके द्वारा प्राप्त ऋणों की गारन्टी करना, (5) औद्योगिक विद्युत की बटोरी तथा पुनर्निर्माण करना, (6) नये उद्योगों की स्थापना व विस्तार की योजना बनाना, (7) वित्तीय वित्तियोग सम्बन्धी शोध

कार्य करता, तथा (8) औद्योगिक संस्थाओं की प्राविधिक व व्यवस्था सम्बन्धी सहयोग प्रदान करना।

31 मार्च सन् 1971 तक औद्योगिक विकास बैंक ने 338.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी, जिसमें से 255.8 करोड़ रुपये वास्तव में वितरित किए गए।

(ए) भारतीय इकाई त्थास (Unit Trust of India) : -यह इकाई त्थास संस्था है जो अपने सदस्य विनियोजकों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करती है। इसने अपना कार्य 1 फरवरी 1964 से प्रारम्भ किया तथा 1 जुलाई 1964 से इसने जनता की इकाइया (Units) बेचनी शुरू कर दी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जनता के बचत व विनियोज की आदत को बढ़ावा देना है जिससे छोटे, मध्यम व बड़े, सभी प्रकार के विनियोजी देश के औद्योगिक विकास में योगदान दे सकें। इस संस्था में उचित प्राप्ति तथा न्यूनतम जोखिम के साथ भविष्य में है, इस त्थास की पूंजी 5 करोड़ रुपये है। इस पूंजी में सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं का योगदान 4 करोड़ रुपये के बराबर है। शेष एक करोड़ रुपये की पूंजी अनुसूचित तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गयी है। इसका प्रमुख कार्यालय बम्बई में है। इसकी प्रत्येक इकाई का मूल्य दस रुपये है और कोई भी व्यक्ति अपनी बचत के अनुसार कितनी भी संस्था में दस रुपये मूल्य वाली इकाइया खरीद सकता है। प्रारम्भ में इकाइया प्रत्येक मूल्य पर बेची जाती थी, लेकिन इसके बाद प्रतिदिन ट्रस्ट द्वारा निश्चिन किए गए मूल्यों पर बेची जाने लगी। इन इकाइयों की ट्रस्ट को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

सामान्यतः यूनिट ट्रस्ट अपने साधनों का तीन-चौथाई भाग उद्योगों में निवि-योजित करता है। 30 जून 1972 तक इसकी इकाइयों की कुल बिक्री 118.94 करोड़ रुपये थी तथा इसके धारकों की संख्या 4,99,533 थी। इसी अवधि तक भारतीय इकाई त्थास ने 63 करोड़ रुपयों का विनियोजन किया था। इसी अवधि तक भारतीय इकाई त्थास ने 48.7 करोड़ रुपये का विनियोजन किया था।

(ई) पुनर्वित्त निगम (Refinance Corporation) : पुनर्वित्त निगम मध्यम आकार के उद्योगों को वित्त प्रदान करने की दृष्टि से 5 जून 1958 को भारतीय राष्ट्रपती अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। इस निगम की समिश्रित पूंजी 25 करोड़ रु० है जो एच-एक लाख रुपये के 2500 अंशों में बटी हुई है। निगम की प्रारम्भिक निर्धारित पूंजी 12.5 करोड़ रु० की होनी थी।

यह निगम उद्योगों को सीधे स्वयं साधन नहीं देते बल्कि औद्योगिक संस्थाएँ उन बैंकों में ऋण प्राप्त करती हैं जो इसके सदस्य हैं और ये सदस्य बैंक निगम से ऋण

लेने हैं। ऋण प्राप्त करने वाले उद्योगों को निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती थी, जैसे (1), ऋण प्राप्त करने वाले उद्योग की प्रवृत्ति पूँजी 5 लाख रु० से 25 करोड़ रु० तक होनी चाहिए, (2) एक औद्योगिक इकाई को 50 लाख रु० से अधिक का ऋण नहीं मिल सकता, तथा (3) ऋण 3 वर्ष से 7 वर्ष की अवधि के लिए ही दिया जाता है। निगम निजी क्षेत्र के उन उद्योगों को जिन्हें पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को पुनः उधार की सुविधाएँ (relending facilities) देता रहा है। 28 मार्च 1961 से यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। इसे 1 नवम्बर 1964 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) में मिला दिया गया था।

(ओ) राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम (The National Small Industries Corporation) इस निगम की स्थापना कोटें फाउण्डेशन के एक विधायक बल की शक्ति पर मई 1950 में की गई। इस निगम का मुख्य उद्देश्य कुटीर एवं लघु-स्वरोच्चा उद्योगों को संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस निगम की अधिकृत पूँजी 10 लाख रुपये थी, किन्तु अब बढ़ा कर 50 लाख रुपये कर दी गई है। यह सभी पूँजी भारत सरकार द्वारा दी गई है। यह निगम ऐसे छोटे उद्योगों को सहायता देता है जो बिना पंक्ति के 100 व्यक्तियों और वार्षिक के प्रयोग के साथ 50 व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं। इसके क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तथा दिल्ली में सहायक निगम स्थापित किए गए हैं। इस निगम के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, (i) लघु उद्योगों द्वारा निमित्त की जाने वाली वस्तुओं के लिए सरकारी आदेश (Order) प्राप्त करना, (ii) ऐसे आदेशों की पूर्ति के लिए लघु उद्योगों की विपरीत, तकनीकी तथा अन्य प्रकार से सहायता करना, (iii) छोटे व बड़े उद्योगों में इस प्रकार समन्वय स्थापित करना कि छोटे उद्योग बड़े उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति बना सकें, (iv) छोटे उद्योगों को बैंकों तथा अन्य खास संस्थाओं से मिलने वाले ऋणों की गारंटी करना। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वास्तव में एक वित्तीय संस्था न होकर एक लघु उद्योग विकास संस्था ही है जो परीक्ष कक्ष से लघु उद्योगों की सहायता करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सम्बन्धित कर रखा है, जो इनकी गारंटी योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देता रहता है। यह निगम लघु उद्योगों को hire purchase के आधार पर देश विदेश से मशीनें प्राप्त करने में सहायता पहुँचाता है।

सन् 1971-72 में इस निगम में 54.40 करोड़ रुपये की सहाय के लघु उद्योगों को गारंटी देकर वित्तीय पूर्ति 20,486 लघु इकाइयों द्वारा की जानी थी। यह

निगम ओखला, राजकोट तथा हवड़ा में प्रोटोटाइप उत्पादन और प्रसिद्धि केन्द्र चला रहा है। इन प्रसिद्धि केन्द्रों से अब तक 5900 व्यक्ति प्रसिद्धित हो चुके हैं।

भारत में औद्योगिक वित्त के अभाव के कारण

भारत के औद्योगिक विकास में पूँजी की कमी सबसे बड़ा बाधा रही है। यही कारण है भारत का अपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। स्वतंत्रता के पश्चात् यद्यपि अनेकों को आवश्यक वित्त प्रदान करने के लिए सरकार ने बड़े खर्च उठाये हैं और इस उद्देश्य के लिए कई निगम व संस्थाएँ बनाई गई हैं, फिर भी देश की शिक्षालया को देखते हुए औद्योगिक वित्त व्यवस्था में कई कमियाँ नज़र आती हैं, जिनके फलस्वरूप हमें दिया में वांछित प्रगति नहीं हो सकी है। भारत में औद्योगिक वित्त के अभाव के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं।

1 **बचत का निम्न स्तर** : भारतवर्ष में सामान्यतः लोग निर्धन हैं। कुछ गिने-चुने व्यक्ति ही सम्पन्नता की ओर भी आते हैं। इस की कमी के कारण बचत नहीं हो पाती। बचत के अभाव में बैंकों के पास भी वित्त की कमी रहती है और वे उद्योगों में पर्याप्त मात्रा में वित्त नहीं लगा पाते।

2 **पूँजी का अमीशान** : भारत में कुछ लोग बचत करने की क्षमता रखते हैं तथा वे पूँजी का समय परके औद्योगिक प्रतिभूतियों में लगा सकते हैं, लेकिन वे पूँजी का इस प्रकार विनियोजन न करके आभूषण आदि खानों में करते हैं। पूँजी के इस अमीशान के कारण उद्योगों में लाभ पूर्ण विनियोग नहीं हो पाता।

3 **संगठित मुद्रा-बाजार व पूँजी बाजार का अभाव** : भारतवर्ष में न ही संगठित मुद्रा बाजार ही पाया जाता है और न ही संगठित पूँजी बाजार। इनके अभाव में औद्योगिक वित्त के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों की वचन को एकत्र करने के साधन प्रायः शून्य के बराबर हैं।

4 **औद्योगिक बैंकों का अभाव** : औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए यद्यपि औद्योगिक बैंकों की स्थापना के लिए प्रयत्न किए गये, तथापि प्रबन्ध अधिकारियों की स्वार्थ नीति के कारण ये बैंक प्रायः सफल नहीं हो पाए। इस समय औद्योगिक विकास में एक अवश्य ही कुछ सफलता से कार्य चल रहा है, अतथा औद्योगिक बैंकों का अभाव देश के औद्योगिक वित्त के मार्ग में बाधा रहा है।

5 **अभियोगन-गृहों का अभाव** : भारतवर्ष में कम्पनियों के हिस्सों व पट्टण पत्रों के अभियोगन की उचित व्यवस्था नहीं है। अभियोगन-गृहों की कमी के कारण औद्योगिक संस्थानों को वित्त प्राप्त करने में बाधाई महसूस होती है।

6 **व्यापारिक बैंकों का सीमित क्षेत्र** : भारतवर्ष में व्यापारिक बैंकों ने अभी तक उद्योगों की अल्पकालीन साह-सम्बन्धी आवश्यकताओं की ही पूर्ति की है।

स्थायी या दीर्घकालीन ऋण देने की व तो उनकी रुचि ही रही है और न क्षमता ही ।

7. फुडल साहसियों एवं प्रबन्धकों का अभाव : फुडल, योग्य व ईमानदार साहसियों व प्रबन्धकों के अभाव के कारण हमारे औद्योगिक संस्थानों में विनियोग करने वाले व्यक्तियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाते । कई बार तो उन्हें प्रायः हानि उठानी पड़ जाती है । फलस्वरूप ऐसे अकुशल एवं बेईमान लोगों को पूँजी देने में अहित एवं संभाव्यें सिलपती हैं ।

8. सट्टेबाजों का प्रभाव : विगत कुछ वर्षों में सट्टाक मण्डलों में सट्टेबाजी होने के कारण अनेक के मूल्या में अधिक उतार-चढ़ाव होखे रहे हैं । इन उतार-चढ़ावों के कारण प्रायः विनियोजक हतोत्साहित हो जाते हैं ।

9. सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि : विगत कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ गया है । सरकार में उद्योगों में नियमन व नियंत्रण के सम्बन्ध में तथा औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम पारित किए हैं, जिससे औद्योगिक विकास में बाधा पड़ी है । अल्प सम्पत्ती वाले लोग फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की लागत बढ़ गई है तथा लाभ कम हो गए हैं । फलस्वरूप पूँजीपतियों में अधिक विनियोजन करने की प्रेरणा तो ठीक पड़ चुकी है ।

10. करों का वज्रता : हुआ भार : विगत वर्षों में सरकार द्वारा करों की मात्रा बढ़ाने के फलस्वरूप पूँजी संचय एवं विनियोजन में बाधा पड़ चुकी है । एक-वर्षीय योजनाओं के कार्यक्रमों की नियमित करने के लिए लगाए गए मरगु कर, सम्पत्ति कर तथा पूँजी लाभकर जैसे करों ने बहुत बड़े विनियोजन दोनों को हतोत्साहित किया है फलस्वरूप उद्योगों को अनिश्चित माया में वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता ।

11. अल्प कारण : उन कारणों के अतिरिक्त अन्य और कई कारण भी हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारे औद्योगिक संस्थानों को उचित मात्रा में वित्त नहीं मिल पाता । ये कारण हैं (i) जनता में जोखिम की प्रवृत्ति का अभाव; (ii) जनता में बैंकिंग आदत का अभाव, (iii) जनता का बैंक में विश्वास का न होना; (iv) सट्टाक एक्सचेंजों की कमी के फलस्वरूप प्रतिभूतियों के मध्य विषय में कठिनाई का होना, तथा (v) सरकार की दोषपूर्ण प्रचलित नीति, (vi) भारतीय मध्यम वर्ग जो दबल के द्वारा पूँजी का मजबूत किया करता था, मुद्रास्फूर्ति के कारण वरबाद हो गया है; (vii) राष्ट्रीयकरण के समय के फलस्वरूप पूँजीपति उद्योगों में पूँजी लगाने में संकोच करते हैं, (viii) देश की औद्योगिक योजनाएँ प्रायः इतनी अस्पष्ट एवं अपूर्ण हैं कि ये विनियोजक का विश्वास प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं ।

औद्योगिक वित्त को सुगम करने के सुझाव : सन् 1953 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने श्री ए० डी० श्रीफ को अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया

या। इस गतिविधि ने औद्योगिक वित्त को सुधारने के लिए जो सुझाव दिये थे, वे महत्वपूर्ण हैं—(i) निजी पूंजीपतियों को उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकार को उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करने का आश्वासन देना चाहिए; (ii) रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह व्यापारिक बैंकों के लिए स्थानान्तरण की सुविधाओं का विस्तार करे, ताकि ये बैंक उद्योगों को वित्त प्रदान कर सकें, (iii) व्यापारिक बैंकों को भरने सक्षम बनाने चाहिए और औद्योगिक संस्थानों के हिस्से में मूल्य पत्र पर्याप्त संख्या में सरोबने चाहिए, (iv) रिजर्व बैंक को बिल बाजार की सुविधाएं कुछ उदार कर देनी चाहिए ताकि व्यापारिक बैंकों को अधिक विश्वीय साधन उपलब्ध हो सकें, (v) देश में व्यापार बैंकिंग का प्रसार किया जाना चाहिए तथा चलते फिरते बैंक खोले जाने चाहिए, ताकि नागरिकों की बचतों को एकत्र किया जा सके, (vi) जमाकर्ताओं को जोखिम से बचाने के लिए जमा बीमा मंडल (Deposit Insurance Scheme) की स्थापना की जानी चाहिए, (vii) व्यापारिक बैंकों के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा बिलों व हूडियों की पुनर्कटौती की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, (viii) देश में निवेशोद्यम ट्रस्ट्स (Investment Trusts) की स्थापना की जानी चाहिए, (ix) राष्ट्रीय विकास निगम तथा औद्योगिक सहाय विनियोग निगम की स्थापना की जानी चाहिए, तथा (x) राष्ट्रीय उद्योगों की वित्तीय सहायता की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए।

उपरोक्त सुझावों में से कई सुझावों को मान कर उन पर कार्य किया जा चुका है, खेप सुझावों पर ध्यान ही अपरक किए जाने की आशा है। उक्त सुझावों के अतिरिक्त निम्नलिखित सुझाव भी महत्वपूर्ण हैं (i) भारतवर्ष में पूंजी-बाजार को सक्रिय बनाया जाय, (ii) वित्त सम्बन्धी वर्तमान संस्थाओं व नियमों के साधन बढ़ाये जायें, (iii) जीवन बीमा कंपनियों व भविष्य निधि कंपनियों की अधिकाधिक धन-राशि उद्योगों को प्राप्त होनी चाहिए, (iv) अभिगोपन के कार्य को बढ़ाया जाय, (v) राज्य वित्त निगमों को परस्पर समन्वय स्थापित करना चाहिए, ताकि कंपनियों का पूर्णतया सहुपयोग हो सके। ऐसा न हो कि कहीं ज्यादा कोष रह जाय और कहीं आवश्यकतानुसार कोष भी न रहे, (vi) वित्तीय संस्थाओं को वित्त देने में विलम्ब नहीं करना चाहिए, (vii) उद्यमकर्ताओं को उत्तम योजनाएं रखनी चाहिए तथा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, (viii) औद्योगिक बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए, (ix) देश में मूल्यों में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि बचत को प्रोत्साहन मिल सके, (x) गाँवों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि गाँवों की वृद्धि को एकत्र करके औद्योगिक विकास की ओर सम्मुख किया जा सके; तथा (xi) देश में निःशुल्क (hoarding) की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और लोगों को उत्पादन कार्यों में धन लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में औद्योगिक वित्त की समस्या को समझा गया है और इसके लिए समय समय पर कई कदम उठाये गये हैं। यदि हमें देश का औद्योगिक उत्थान करना है, तो इस दिशा में अभी और भी बहुत कुछ करना होगा। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् बैंको, वित्तीय संस्थाओं और आम जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। औद्योगिक बैंक की स्थापना गरीब वित्तीय निगमों के प्रादुर्भाव के कारण आदि उद्योगों को वित्त प्राप्त करने में किसी विज्ञापन कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सरकार ने इस दिशा में उत्साहवर्धक नीति अपनाई है। आशा है कि निकट भविष्य में हमारे देश में औद्योगिक वित्त सम्बन्धी अवस्था और भी सुदृढ़ हो जायगी।

प्रश्न

1. उन विभिन्न स्रोतों—प्राथमिक और बाह्य—का वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा बचत पत्रों के उद्योग अपने वित्त की व्यवस्था करते हैं। उन वित्तीय संस्थाओं का वर्णन कीजिए जो भारतीय उद्योगों को वित्त प्रदान करती हैं।

(राज० प्र० व०, टी० डी० सी० क्ला, 1966)

2. औद्योगिक वित्त की समस्याओं को समझाइय। इन देश में औद्योगिक वित्त की समस्या के हल के लिये सरकार द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख कीजिए।

(राज० टी० डी० सी० अन्तिम वर्ष, 1964)

3. भारतवर्ष में औद्योगिक वित्त समस्या पर अपने विचार प्रकट कीजिए और समस्या के निराकरण में विभिन्न निगमों का योगदान विशिष्ट कीजिए।

(राज० बी० ए०, 1960)

4. सशुद्ध टिप्पणी लिखिए—‘औद्योगिक वित्त निगम’।

(राज० बी० ए०, 1963)

औद्योगिक नीति

(Industrial Policy)

"The 1956 Industrial Policy Resolution charts a fresh course permitting a freedom of development in the private sector, but with checks and balances to prevent a detrimental concentration of economic power and wealth. The Resolution has been described by some observers as an economic constitution based upon its political counterpart—the Constitution of India" S C Kuchhal

प्रत्येक देश की सरकार को देश की अप व्यवस्था तथा उसके उस समाज को जिसका हि वह भाग है, उनके साधनों को वास्तविक प्रयोगों में निर्वाह करने तथा देश में औद्योगीकरण की स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना चाहिए। राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के अभाव में न तो देश का कृषि क्षेत्र ही विकसित हो सकता है और न ही देश से एक ऐसा औद्योगिक डाका पैदा हो सकता है, जो उसे स्वावलम्बी एवं समृद्धिवादी बनाने में सक्षम हो सके। यही मूल कारण है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अपनी औद्योगिक नीति स्पष्ट करनी पड़ती है। उस नीति में ही एक ऐसी आर्थिक प्रणाली एवं व्यवस्था की स्पष्ट कर दिया है जो—

(1) समाज के मूल एवं प्रायोगिक विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण में प्रभावकारी परिवर्तन पर जोर देती है, ताकि नयी विधियों का प्रयोग करके उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सके, (2) कृषि एवं उद्योगों के समुचित विकास पर बल देकर एक समतुल्य शक्ति का कार्य करती है, (3) आधारभूत उद्योगों की स्थापना, जनोपयोगी सेवाओं के निर्माण की व्यवस्था तथा आधारभूत उद्योगों और उपभोग उद्योगों के पारस्परिक सम्बन्ध एवं उनके स्थान के सम्बन्ध में सरकार की नीति को परिष्कृत करती है, (4) कार्य की दशाएँ सुधारने की दृष्टि में पूँजी तथा श्रम के मध्य पारस्परिक समतुल्य सम्बन्ध स्थापित करती है, (5) औद्योगिक विकास में कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा जोखिम उठाने की सम्भावना कम होने के कारण निजी (Private) क्षेत्र तथा राजकीय या सार्वजनिक (State or Public) क्षेत्र के संतुल्यत्व

निर्धारित कर देती है, (6) देश में पूर्ण रोजगारी की स्थिति आने तथा देश का समुचित आर्थिक विकास करने के लिए नये उद्योगों तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करती है, (7) आवासायिक समूहों एवं विधियों को इस प्रकार नियमित एवं नियन्त्रित करती है, जिनसे कि उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण न किया जा सके, तथा (8) देश के आर्थिक, विद्युत्, औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक चरण में विदेशी पूँजी, विदेशी सहायता तथा विदेशी प्राविधिक ज्ञान का समुचित प्रयोग के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति निर्धारित करती है।

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशी सरकार की औद्योगिक नीति

(Industrial Policy of Foreign Government in India before Independence)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत की औद्योगिक नीति विदेशी सरकार की नीति थी। लगभग दो सताब्दियों तक ब्रिटिश शासकों ने भारत के प्राकृतिक साधनों का विनाश करने अपने देश-इंग्लैंड के हित में ही किया था। उन्होंने न केवल आधुनिक उद्योगों के विशेषकर आधारभूत उद्योगों, के प्रति उपेक्षापूर्ण एवं विरोधपूर्ण नीति अपनायी थी, तथा उनकी नीति अपने देश की औद्योगिक क्रान्ति के उपलब्धि के लिए भारत के परम्परागत लघु एवं कुटीर उद्योगों को कमजोर करने की ही रही थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप आधुनिक उद्योगों के विकास के पूर्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में भारतीय कुटीर उद्योगों की जीवित रखा गया था, क्योंकि इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ कम्पनी अधिकारियों की आय का साधन थी। इन वस्तुओं का निर्यात होता था, जिससे न केवल भारतीय दस्तकार एवं कारीगर उस समय की राजनयिक अव्यवस्था में अपने उद्योग को जीवित बताये रखने के लिए प्रयत्नशील थे, बल्कि विदेशी प्रशासक जो मुख्यतः व्यापारी थे, इन उद्योगों से अधिकारिक लाभ उठाने के लिए उन्हें अधिक व अनुचित संरक्षण प्रभाव करते थे। परन्तु इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति ने नम्पनी के सवालकों को राष्ट्रीय हित में इस नीति की बदलने के लिए बाध्य किया। उन्हें अपने देश के उद्योग वर्गों के विकास के निमित्त भारत से बच्चे माल के निर्यात तथा भारत में इंग्लैंड में निर्मित माल के आयात पर विरोध ध्यान वेन्द्रित करना पड़ा। फलस्वरूप भारत के विश्व-विख्यात कुटीर उद्योग बन्द हो गये और भारत इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुओं का एक बाजार मात्र तथा उसने उद्योगों के लिए बच्चे माल का उत्पादन करने वाला एक उपनिवेश मात्र रह गया। ब्रिटिश सरकार की राज्य सत्ता स्थापित होने के बाद भी मुक्त व्यापार नीति का ही पालन किया गया। टियर्ने (Tierney) के अनुसार ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति वा यह सामान्य सिद्धान्त था कि "इंग्लैंड का सत्ता माल भारत में बेचा जाय, जिसके बदले में भारतीय वस्तु ली जाय"।

ब्रिटिश सरकार की उपर्युक्त नीति से यह स्पष्ट सकेत मिलता है कि विदेशी सरकार उस समय भारत के औद्योगिक विकास की ओर किसी भी रूप में ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी नीति विद्वेष-पूर्ण थी, क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में भारत में उद्योगों का विकास करने पर उसका औपनिवेशिक बाजार समाप्त हो जाता, उसके उद्योगों के लिए कच्चा माल की पूर्ति रुक जाती तथा वहाँ औद्योगिक विकास का काम रुक जाता। आधुनिक विचारकों का इन सम्बन्ध में यह मत है कि यदि उस समय की पैमानिक खोजों तथा आधुनिक उद्योगों की विकसित करने के प्रयास भारत में भी किए जाते तो आज यह देश अविहसित राष्ट्रों के साथ वर्गीकृत न होकर विकसित राष्ट्रों के साथ वर्गीकृत होता।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में न केवल इंग्लैंड, औद्योगिक देशों में अग्रणी था, बल्कि यह विश्व का 'कारखाना' कहा जाने लगा था। उस समय भी ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी इस उपेक्षापूर्ण नीति के बावजूद भी कुछ विदेशी एजन्सी गृहों तथा प्रबन्ध अधिकारियों ने कलकत्ता में जूट उद्योग तथा भारतीय प्रबन्ध अधिकारियों ने अम्बरई में वस्त्र उद्योग की स्थापना की। इन उद्योगों के स्थापित होने पर इन देश में आधुनिक उद्योगों का समारम्भ हुआ। इन नये उद्योगों तथा रेल यातायात के विकास ने 19वीं शताब्दी में अलग तथा 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य पूँजीपतियों का ध्यान नये उद्योग धर्मों की स्थापित करने की ओर आकर्षित किया तथा उन्हें अन्धधारा उद्योगों को छोड़ कर अन्य उद्योगों की स्थापित करने की प्रेरणा प्रदान की, परन्तु सरकार की तब इस तरफ भी न होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक देश में युद्ध-काल की विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए वहाँ का औद्योगिक ढांचा निरर्थक था। उस समय तक देश में जूट, सूती वस्त्र, कागज, पीपला तथा अन्य उपभोग्य उद्योग ही स्थापित हो सके थे। उन आधारभूत उद्योगों का महा सर्वेया अभाव था, जो मुख्य व्यवसायों की पूर्ति कर सकते थे।

प्रथम युद्ध काल प्रथम विश्वयुद्ध के समय विदेशी सरकार ने इस तथ्य को अनुभव किया कि भारत के औद्योगिक विकास के बिना उनकी उपेक्षापूर्ण नीति उचित नहीं रही है। इस बात को महसूस करने के बाद महायुद्ध के समय तक की पूर्ण नीति में कुछ परिवर्तन हुआ। युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। सन् 1916 में औद्योगिक सम्माननाओं की जांच करने के लिए औद्योगिक आयोग (Industrial Commission) की नियुक्ति की गयी। युद्ध सामग्रियों की पूर्ति करने के लिए सन् 1917 में इण्डियन म्युविजन बोर्ड की भी स्थापना की गयी। इस आयोग ने सन् 1918 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में

उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया तथा इस सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये। परन्तु उस समय तक विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। अब तत्कालीन सरकार ने उन सुझावों के अनुसार देश के औद्योगिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

सरक्षण एवं प्रवृत्ति—

प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश के औद्योगीकरण के प्रश्न पर विशेष ध्यान देने के कारण औद्योगिक शांति में कोई परिवर्तन न हुआ। इस विषय में केवल यह परिवर्तन हुआ कि सन् 1919 में उद्योगों की प्रांतीय विषय बना दिया गया। विश्व में शांति स्थापित हो जाने के बाद भारत को भी विश्वव्यापी मंदी का शिकार होना पड़ा। इसके अतिरिक्त विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण यहां के उद्योगों की दशा खोलीय हो गयी। उसी समय देश में विदेशी आन्दोलन ने और पन्द्रह और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। सर्वप्रथम भारतीय उद्योगों को उचित सरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में मांग की जाने लगी। सन् 1921 में सर अब्राहम रूहीमुतल्ला की अध्यक्षता में नियुक्त प्रमुख आयोग की सिफारिश पर सन् 1923 से विरचनात्मक सरक्षण की नीति अपनाई गयी। जिसके अनुसार पूर्व-निश्चित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुने हुए उद्योगों, जैसे चीनी, कागज, इस्पात, सूती वस्त्र आदि को सरक्षण प्रदान करने की नीति को कार्यान्वित किया गया। परन्तु सरक्षण की यह नीति अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुयी। चीनी, लोहे व इस्पात तथा सूती वस्त्र उद्योगों को इस सरक्षण की नीति से केवल यही लाभ हुआ कि वे अपने अस्तित्व को बचाये रख सके। वास्तव में भारतीय उद्योगों की सरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने जिन सिद्धान्तों को निर्धारित किया था, वे इतने बलशाली थे कि प्रत्येक उद्योग के लिए उनकी पूरा करना बर्तन था। यही कारण है कि भारतीय उद्योग इस सरक्षण नीति का पूरा लाभ न उठा सके। श्री पी० एन० होबनाथन के शब्दों में सरक्षण की यह नीति, 'अवरोधक तथा अपवर्णा की और प्रगति के सम्बन्ध में समय समय पर की गयी जान पड़ताला मोघ उत्पन्न करने वाली बाधा की'।¹

द्वितीय विश्व-युद्ध काल द्वितीय विश्व युद्ध काल के पूर्व देश में आधारभूत उद्योगों का संरक्षण धमका था। श्री आर० पी० दत्त के अनुसार तत्कालीन सरकार की नीति अनीद्योगीकरण की थी। उससे उस समय औद्योगीकरण के सम्बन्ध में जो भी नीति प्रेरित की गयी, वह उल्लास साज्ज थी। इस प्रयत्न नीति को सफल करने तथा देश का औद्योगिक विकास करने के लिए सन् 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने

1 This policy of protection was halting and meagre and the periodical in quest on progress was an irritating assurance.
P S Lohachan

आधारभूत उद्योगों तथा मातायात के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया था। सन् 1935 में कुछ प्रांतों में लोकप्रिय कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों का गठन हुआ। अक्टूबर 1938 में हुए इन मन्त्रिमण्डलों के उद्योग मन्त्रियों के सम्मेलन में देश में औद्योगिक विकास के लिए नेहरूजी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिती का गठन किया गया। इस समिती को सम्पूर्ण देश के लिए एक औद्योगिक योजना तैयार करने का भार सौंपा गया।

सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने पर प्रांतीय कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों को इस्तीफा देना पड़ा। तत्पश्चात् देश के औद्योगिक उत्पादन का संचालन एवं नियमन भारत के सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत किया जाने लगा। उस समय स्थिति यह थी कि आलापिनी, पैको तथा कोलो से लेकर भारी मशीनों तक का आयात विदेशों से किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ होने पर इन सामग्रियों तथा आवश्यक रासायनिक पदार्थों तथा कच्चे-पुर्जों का आयात बन्द हो जाने से चमड़ा तथा तांबे व जैसे उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति न की जा सकी। उस समय पुनः औद्योगिक विकास, विशेषकर आधारभूत उद्योगों की कमी महसूस की गई। तत्कालीन सरकार के लिए औद्योगिक ढांचे में जो ग्मून्ताएँ थी, उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना आवश्यक हो गया। सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अनेक छोटे-मोटे कारखाने स्थापित किए गए। साथ ही विद्यमान भारतीय उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरणाएँ प्रदान की गयीं। इस ऋतु में कुछ नये उद्योग, जैसे भारी रासायनिक उद्योग, लहारा-निर्माण, अल्युमिनियम, बिजली के सामान, साइकिल आदि के उद्योग, स्थापित किए गए तथा मशीनों के कच्चे-पुर्जों और पहा तक शि मशीनों में निर्माण सम्बन्धी उद्योगों के विकास के लिए आधार भी तैयार किया गया। परन्तु इस काल में—जो भी औद्योगिक प्रकार एवं विधाएँ हुआ, वह अव्यवस्थित एवं एकाकी था। वास्तव में औद्योगीकरण की सोचा देश की औद्योगिक सम्भाव्यताओं के अनुकूल नहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की एक रिपोर्ट (1946) के अनुसार, “यह विस्तार एक लम्बे अर्से तक विचार करने के बाद अथवा उचित ढंग से समन्वित योजना के अनुसार नहीं, बल्कि युद्धीय स्थिति की आवश्यक पाव की पूर्ति करने के लिए ही हुआ था।”

“... यह (विकास एवं विस्तार) स्वभावतः अव्यवस्थित था।”¹ सन् 1945 में ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने उस समय की सरकारी नीति की समीक्षा करते हुए लिखा

1. The expansion took place, not in accordance with a long considered or well co-ordinated plan, but in response to the imperative demand of the military situation—“it was necessarily haphazard.”

था, हम लोग फिर भी कुछ नहीं बता सकते थे। हम लोग केवल किसी भी वस्तु तथा प्रत्येक वस्तु की पूर्ति करने वाले थे, इस पृथ्वी पर की सभी वस्तुओं को सुपारने एया उनकी भरमसा भरने वाले, परन्तु किसी भी वस्तु के निर्माता नहीं थे। हम लोगों की कोई पद्धति, कोई योजना नहीं थी। (इसके विपरीत) एक योजना आवश्यक थी, युद्धोत्तर काल के औद्योगीकरण को रोकना।"

परन्तु उस समय देश में नियोजन के प्रति उत्साह होने के कारण राष्ट्रीय योजना एवं आन्दोलन को ध्वस्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारत की औद्योगिक नीति के निर्धारण को बचा में कुछ आश्वासन देना आवश्यक हो गया। युद्धकाल में ही सन् 1944 में सर आर्देयर दत्तल केन्द्रीय सरकार में नियोजन तथा पुनर्निर्माण (Planning and Reconstruction) विभाग के सदस्य नियुक्त किये गये। इस विभाग ने 22 अप्रैल, 1945 को औद्योगिक नीति की घोषणा की। सन् 1945 की नीति द्वारा प्रथम बार स्पष्ट शब्दों में उद्योगों के प्रति सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया। यह नीति बहुत ही उपयोगी थी, परन्तु राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

अक्टूबर 1947 में श्री वि० सी० नियोजी की अध्यक्षता में 'नियोजन सलाहकार मण्डल' (Advisory Planning Board) की नियुक्ति की गई। इस सम्बन्ध में उठाने रिपोर्ट फरवरी 1947 में प्रस्तुत की। बोर्ड ने भारी निमोजन व प्रशासन के सम्बन्ध में सहायपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें एक 'योजना आयोग', एक सलाहकार समिति (Consultative Body), एक केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा एक स्थायी 'प्रगल्भ मण्डल' का संगठन करना प्रमुख था। जहाँ तक राज्य द्वारा उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबन्ध ग्रहण करने का सम्बन्ध है, इस बोर्ड ने यह सुझाव दिया कि तत्कालीन परिस्थितियों की ध्यान में रखते हुए ऐसा करना वांछनीय नहीं होगा। परन्तु कुछ माध्यमगत उद्योगों को राज्य के स्वामित्व एवं प्रबन्ध के अन्तर्गत लाना चाहिए।

युद्धोपरान्त भी ब्रिटिश सरकार ने देश के अनुत्थित औद्योगिक विकास तथा महायुद्ध-काल में अत्यधिक उत्पादन के कारण जो मशीनें पिस गयी थी, उनके मशीनीकरण तथा प्रतिस्थापन की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही उस समय यह भी अनुभव किया गया कि प्रथम महायुद्ध के बाद से द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति का ही यह परिणाम था कि न तो भारत विद्यमान उद्योगों के लिए कच्चे व पुर्जों के निर्माण व पूर्ति के लिए समर्थ हो सका था और न ही वह कच्चे माल तथा शक्ति के स्रोतों की कमी की पूर्ति करने में समर्थ था। यही कारण है कि युद्ध के पश्चात् भारतीय उद्योगों का उत्पादन घिरने लगा।

इन कारकों के अतिरिक्त युद्ध के पश्चात् वे तीन वर्षों की अवधि मकामल की अवधि थी, जिसमें ब्रिटिश राज्य-सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तान्तरित किये जाने तथा देश के विभाजन के सम्बन्ध में आवश्यक वार्तालाप एवं क्रियाएँ की जा रही थी। इन परिस्थितियों में विदेशी सरकार ने देश के औद्योगिक ढांचे की सुधारने की तरफ कोई प्रिय ध्यान नहीं दिया।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार की औद्योगिक नीति—15
अगस्त सन् 1947 का भारत स्वतन्त्र हुआ। जनता में नये विश्वास तथा कई आशा की लहर आयी। परन्तु देश के विभाजन के कारण आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई और राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक स्पष्ट औद्योगिक नीति घोषित न किये जाने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अनीति-जनता का शासकत्व उत्पन्न हो गया। राष्ट्रीयकरण के भय से औद्योगिक विकास एक प्रकार तथा मशीनों के आधुनिकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रियाएँ रुक गयी, जिसने फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन कम हो गया, मूल्य स्तर में वृद्धि हुई तथा अनाति की दूर करने के लिए दिसम्बर 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। उस समय की आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉ० जगन्नाथन पुरुषोत्तम ने कहा, 'आर्थिक परिस्थिति यह युद्ध के समय से गम्भीर है। मशीनों में अब हम औद्योगिक सफट की स्थिति में गिर रहे हैं।' इस सम्मेलन में उद्योग औद्योगिक नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया मन्त्रालय के समक्ष विभिन्न लिखित विचारों के प्रस्तुत की —

(1) देश की सम्पत्ति एवं उत्पादन का उचित वितरण—जिससे भारतीय जनता को सामाजिक न्याय पर आधारीन सुविधाएँ मिलें तथा जीवन-स्तर में तेजी से सुधार हो।

(ii) देश के प्राप्ति का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता—जिससे सभी विद्येय के हाथों में ही सम्पत्ति का वितरण हो सके।

(iii) के औप निधोजन, सामंजस्य तथा निधोजन की आवश्यकता—जिससे अधिकतम कार्यधमना, उत्पादन और देश के विभिन्न भागों में उद्योगों का समुचित वितरण हो सके। साथ ही साथ मजदूरों व काम निधिन करने का न्यायवगत तरीका अपनाया जाए।

(iv) उद्योगों का तीन प्रमुख धर्मियों में विभाजन किया जाए, सन् 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution of 1948)

उपमूर्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए 6 अप्रैल, 1948 को केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉ० जगन्नाथ प्रसाद मुखर्जी ने भारत सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा की। जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(1) औद्योगिक नीति के उद्देश्य—जन 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में यह कहा गया कि—

(i) औद्योगिक नीति का उद्देश्य एक समाज की स्थापना करना है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर—यथाव्यय प्राप्त हो सकें।

(ii) देश की वर्तमान अवस्था में जबकि प्रगतिशील जनता जीवन निरंतर स्तर का जीवन ध्येयोत्तर होती है, उत्पादन वृद्धि पर जोर देना चाहिए।

(iii) वर्तमान धन के पुनर्वितरण मान से जन-साधारण के लिए कोई मौलिक अन्तर नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ केवल निर्भरता का पुनर्वितरण होगा।

(2) उद्योगों का चार श्रेणियों में विभाजन प्रस्ताव में यह कहा गया था कि उद्योगों के विकास में सरकार की सक्रियता धीरे-धीरे बढ़नी चाहिए। परंतु उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपक्षित सीमा तक उद्योगों के विकास में भाग नहीं ले सकती। यह सरकार न उद्योगों को चार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया।

(अ) सरकार का एकाधिकार—इन श्रेणियों के अन्तर्गत तीन उद्योग रखे गए—महान् उद्यम का निर्माण, अल्प मात्रा का उत्पादन—यदि नया तथा देश-परिवह्य। इन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार रखा गया।

(ब) उद्योग विकास के दायित्व भविष्य में केवल सरकार का होगा। इन श्रेणियों के अन्तर्गत यह आचारभूत उद्योग रखे गए—वापला, लोहा व इस्पात, हवाई जहाज निर्माण, समुद्री जहाज निर्माण, टेलीफोन, पारवर्तन यन्त्रों के तारों के सामान का निर्माण (रेडियो रिसेप्टिंग यंत्रों के अतिरिक्त) और खनिज तेल उद्योग। इन उद्योगों के सम्बन्ध में तीन बातें कही गई थी—

(i) इन श्रेणियों के उद्योगों में नई इकाइयों की स्थापना केवल केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों तथा अन्य लोक निकायों (Public Authorities) द्वारा की जा सकती है। परन्तु यदि राष्ट्रहित में आवश्यक समझा गया तो निजी क्षेत्र से भी स्थापना की जा सकती है।

(ii) इन उद्योगों में सम्बन्धित वर्तमान इकाइयों को 10 वर्ष तक विद्यमान होने का पूर्ण अधिकार दिया जायेगा। दस वर्षों के पश्चात् ही इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। यदि किसी इकाई का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया गया तो इसके लिए उचित मुआवजा दिया जायेगा।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था सार्वजनिक निगमों (Public Corporations) द्वारा की जायेगी।

(स) सरकारी नियन्त्रण तथा नियमन के अन्तर्गत उद्योग : इस श्रेणी में वे मूल उद्योग रहें या जिन पर सरकार का नियन्त्रण रखना राष्ट्रीय हित में है। इस श्रेणी के उद्योगों के लिए अधिक विनियोजन तथा प्राविधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा उनकी स्थिति का राष्ट्रीय महत्व होता है। अतः ऐसे उद्योगों पर सरकार का नियन्त्रण होना आवश्यक है। इस श्रेणी के उद्योग निजी क्षेत्र में रहेंगे तथा उनका नियमन एवं नियमन सरकार द्वारा किया जाएगा। इन उद्योगों के राष्ट्रीय परण का कोई अर्थ नहीं है। परन्तु इन उद्योगों में भी सरकार नयी इकाइयां (Units) स्थापित कर सकती है। इस श्रेणी में कुल 18 उद्योग रखे गए, जिनमें से मुख्य ये हैं, नमक, गीतर, टैक्स्टाइल, इलेक्ट्रिकल, इजीनियरिंग, भारी रसायन, औषधि, खाद, रसायन, पावर अल्कोहल, रबर, सीमेंट, चीनी, कागज, सूती वस्त्र उद्योग, हवाई, परिवहन, जल परिवहन, आदि।

(2) अन्य उद्योग : शेष सभी उद्योग साधारणतया निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए जायेंगे। उद्योगों पर सरकार का सामान्य नियन्त्रण रहेगा। परन्तु यदि निजी उद्योग की प्रगति संतोषजनक नहीं हो तो सरकार हस्तक्षेप करने में नहीं हिचकेंगी।

(3) कुटीर तथा लघु उद्योग : औद्योगिक नीति में कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। सरकार इन उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्न करेगी। ऐसे उद्योग स्थानीय साधनों के पूर्ण उपयोग तथा कुछ उपयोग की वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थानीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन उद्योगों का विकास राज सरकारों का दायित्व है। परन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि ये उद्योग किस प्रकार तथा कहाँ तक बढ़ उद्योगों के साथ चलाए जा सकते हैं। सरकार इन सभी प्रकार के उद्योगों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए सहकारिता पर जोर दिया गया।

(4) नष्ट-कार नीति : सरकार की तट कर नीति इस प्रकार की होगी जिसमें अनावश्यक विदेशी प्रतिस्पर्द्धा को रोक जा सके तथा उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार डाले बिना देश के साधनों का उपयोग किया सके।

(5) कर नीति : पूँजीगत विनियोजन व वृद्धि करने के लिए तथा कुछ व्यक्तियों के हाथों में सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए कर प्रणाली में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

(6) थम नीति औद्योगिक विकास के लिए उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध आवश्यक है। सरकार थमिको की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करेगी। उद्योगों में लाभ में थमिको को भी हिस्सा मिलेगा तथा उद्योगों के संचालन में थमिको को भागीदार बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। पूँजी पर भी उचित लाभ का ध्यान रखा जाएगा। थमिको की गृह-जनसंख्या के सर्वांग के लिए आगामी 10 वर्षों में 10 लाख बनाए जायेंगे। औद्योगिक जगहों के फैलने के लिए उचित मशीनरी की स्थापना की जायेगी।

(7) विदेशी पूँजी सरकार विदेशी पूँजी का स्वागत करेगी। इसके लिए सरकार विशेष विधान पारित करेगी। नियमानुसार बहुमत-स्वामित्व नियन्त्रण भारतीयों के हाथों में रहेगा। यदि राष्ट्रहित में आवश्यक समझा जाएगा, तो यह गर्त हटाई जा सकता है। परन्तु प्रत्येक अवस्था में इस ध्यान पर ध्यान दिया जाएगा कि अल्प म धीरे-धीरे भारतीय विद्योपज्ञ विदेशी विद्यमानों का स्थान ग्रहण कर ले। यदि विदेशी पूँजी का राष्ट्रायस्करण किया गया तो उचित मुआवजा दिया जाएगा। किन्तु धीरे-धीरे विदेशी पूँजी का प्रतिस्थापन भारतीय पूँजी द्वारा किया जाएगा।

(8) वितरण . वर्तमान समय में उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया जाएगा और वितरण को समस्या पर पविष्य में विचार किया जाएगा।

(9) योजना आयोग विकास सम्बन्धी योजनाएँ बनाने तथा उनको कार्यान्वित करने के लिए एक 'राष्ट्रीय योजना आयोग' स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार पुष्टी उद्योग आयोगों के विकास के लिए 'कुटीर आयोग बोर्ड' गठित किया जाएगा।

सन् 1948 की नीति की आलोचनात्मक समीक्षा

सन् 1948 की नीति का कुछ क्षेत्रों में स्वागत किया गया तथा कुछ क्षेत्रों में इसकी कुछ आलोचना की गई। श्री मीनू मसानी के अनुसार इस नीति द्वारा 'अज्ञातमानाज समानवाद की नींव डाली गई। प्रोफेसर रंगा के अनुसार यह नीति 'भाषीवाद समाजवाद' का दायज थी।" प्रो० के० टी०शाह के अनुसार, "यह वह नीति नहीं थी जिसे एक प्रगतिशील तथा उन्नति की आस्था रखने वाले देश को अपनाना चाहिए।" कुछ लोगों ने इस नीति की पूँजीपतियों का विरोधी बताया।

(1) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था—भारत सरकार की औद्योगिक नीति मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) की नींव डालने की दिशा में पहला कदम था। वस्तुतः कोई भी अर्थ-व्यवस्था परिवर्तन के समय मिश्रित अर्थ-व्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि

माजबंदिज तथा निजी क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना बड़ा ही मुश्किल कार्य होगा है। दोनों क्षेत्रों में सीमित साधनों को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा हो सकती है। ऐसी अवस्था को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों की आवश्यकता पड़ती है, जिनसे वार्षिक विकास का मार्ग कभी-कभी अवरोध हो सकता है।

निश्चित अर्थ व्यवस्था में हम पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था से समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धीरे धीरे परिवर्तन लाना उचित है, परन्तु हमारे निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी ओर लक्ष्य में परिपक्वता क्या हो सकती है परन्तु हमें अपने कबनों तथा आवासनों को भूलना नहीं चाहिए।

(2) विधवाय का अभाव—इस नीति के कारण उद्योगपतियों में विश्वास क्षयित नहीं हुआ। वे पूँजी विनियोग करने में डरने लगे। वस्तुतः उस समय देश में अधिक विनियोजन की आवश्यकता थी परन्तु औद्योगिक नीति का विनियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सर आर्थर डलर के शब्दों में, “राष्ट्रीयकरण लाभदायी होना, लाभ में हिस्सा लिये जाने तथा 10 वर्षों के पश्चात् पूँजी के विपटन के भय से विनियोजन प्रयत्नीत हो गये।”

(3) राष्ट्रीयकरण का भय—इस नीति के कारण उद्योगपतियों में राष्ट्रीयकरण का भय समा गया। नेहरू द्वारा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कई प्रकार के परस्पर विरोधी विचार प्रगट किये गये। 10 वर्षों के पश्चात् भी राष्ट्रीयकरण का भय बना रहा। वस्तुतः 10 वर्षों में ही कोई औद्योगिक संस्थान लाभार्जन के योग्य हो पाता है। यदि उसी समय इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता तो कोई भी विनिवेश ऐसे संस्थापक की स्थापना नहीं करेगा। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीयकरण से भगमौत न होने की सलाह दी थी तथा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था¹, परन्तु उद्योगपतियों का भय दूर नहीं हुआ, इससे देश की औद्योगिक उन्नति पर बाधा उपस्थित हुई।

(4) उत्पादन अथवा वितरण—औद्योगिक नीति में यह घोषणा की गयी कि उक्त समय देश की प्रमुख समस्या उत्पादन में वृद्धि करने की थी, वितरण की समस्या का समाधान उतना आवश्यक नहीं था। वस्तुतः यह विचार आसक्त है। उत्पादन तथा वितरण दोनों एक ही त्रिधा के दो रूप हैं। उत्पादन ■ पश्चात् वितरण की समस्या उत्पन्न आती है।

(5) अस्पष्ट एवं असन्तोषजनक—वस्तुतः इस नीति द्वारा किसी भी पक्ष को भरोसा नहीं हुआ। राष्ट्रीयकरण, लाभ में हिस्सा, प्रबन्ध में अधिकारी द्वारा मांग लाना

1 “Government's resources were meant to increase production and not supply them or a transfer of ownership.”

आदि आश्वासन देकर सरकार ने सामयिकी होने का दावा किया। साथ ही साथ राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र धीरे-धीरे सीमित कर, ऊँची छत पर करो में छूट देकर तथा करो की थोड़े के सम्बन्ध में दुर्बलता दिखाकर शासकों में पूँजीपतियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। 'एत नीति ने न उद्योगपतियों, न विनियोजकों ॥ लौचो-गिक धार्मिक और न जनमानसों को सन्तुष्ट किया। उत्पादन में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए जिस सक्रिय उद्योग तथा प्रगतिशीलता की आवश्यकता थी उसे लाने में यह नीति अक्षम रही।'⁵

आलोचनाएं असफल—वर्षाव उपर्युक्त आलोचनाएं व्यापकमत तथा उचित प्रतीत होती हैं, किन्तु भी देश की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें अच्छी औद्योगिक नीति की घोषणा नहीं की जा सकती थी। आर्थिक नीति का निर्माण आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। उस समय देश में उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता थी। अतः सरकार ने वितरण पक्ष पर ध्यान न दे कर उत्पादन पर ध्यान दिया। इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भी नीति स्पष्ट थी। 10 वर्षों में पचास प्रतिशत राष्ट्रीयकरण केवल उन्हीं उद्योगों का किया जाना था, जिनकी प्रगति सतोपजनक न होती। अतः उत्पादन एवं औद्योगिक प्रगति की दृष्टि में यह व्यवस्था सर्वथा उपयुक्त थी। उत्पादन वृद्धि के लिए कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया। व्यक्तियों को शोखहूँ दिया गया और उन्हें कोषों में अक्षाने तथा उत्पादन में उचित हिस्सा दिलाने की जो घोषणा की गयी वह सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी पूर्णतया उचित थी।

निश्चित नर्व अवस्था की कटु आलोचना की गयी है, किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में निश्चित नर्व-अवस्था के विद्यमान को जनता के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। मूलभूत उद्योगों के विकास के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है तथा प्रारम्भ में लाभ भी प्राप्त नहीं होता। निजी पूँजीपति उपमोक्ष उद्योगों में ही विनियोजन करते थे। अतः सरकार को आवश्यक उद्योगों के विकास का दायित्व अपने ऊपर लेना आवश्यक था। इसी प्रकार मुरझा सम्बन्धी उद्योगों को भी निजी उद्योगपतियों पर नहीं छोड़ा जा सकता था। सभी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना न तो उचित था और न व्यावहारिक। अतः निश्चित नर्व-

5 The policy satisfied neither the equities of industry, nor the interests nor the industrial workers nor the general public . . . (It) failed to provide the dynamism and positive stimulus which was required for any significant increase in production . . .

व्यवस्था की नीति पूर्णरूपेण उपयुक्त थी। इस प्रकार सन् 1948 की औद्योगिक नीति को सर्वथा उपयुक्त कहा जा सकता है।

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951,

औद्योगिक नीति को कार्यान्वित करने और उद्योगों के नियमन तथा विकास के लिए अक्टूबर 1951 में भारतीय संसद ने उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम पारित किया जो 8 मई, 1952 को लागू किया गया। इस एक्ट में प्रथम अनुसूची में दिये गये उद्योगों के विकास तथा नियमन की व्यवस्था की गयी। प्रारम्भ में इस एक्ट के अन्तर्गत 37 उद्योग सम्मिलित किये गये, जो बढ़कर सन् 1953 में 45 हो गये। मार्च 1947 में इसमें 34 अतिरिक्त उद्योग जोड़ दिये गये। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भोजन/बढ़ विश्वास तथा उद्योगों का नियमन था। इस अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएँ निम्नलिखित थीं :

(1) अनुसूचित उद्योगों की सभी वर्तमान इकाइयों का पंजीयन (Registration) निश्चित समय के अन्तर कराना अनिवार्य है।

(2) केन्द्रीय सरकार में लाइसेंस लिये बिना किसी भी नयी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की जा सकती और न वर्तमान इकाइयों का विस्तार किया जा सकता है।

(3) यदि किसी भी उद्योग का उत्पादन गिर जाय, उत्पादन क्षय में वृद्धि हो, उत्पादित वस्तु के गुणों (quality) में गिरावट आती हो या उपभोक्ताओं को हानि होने की सम्भावना हो अथवा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में अनुसूचित वृद्धि की गयी हो तो सरकार उस उद्योग की जांच कर सकती है और जांच के पश्चात् निम्नलिखित आदेश दिये जा सकते हैं :

(क) वह उद्योग उत्पादन में वृद्धि तथा विकास का प्रयत्न करे।

(ख) वह उद्योग कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे उत्पादन की मात्रा या गुण में गिरावट आये।

(ग) जिस उद्योग की जांच की गयी हो उसके मूल्य तथा वितरण पर सरकार द्वारा नियन्त्रण लगाया जाय।

(4) एसी जांच के पश्चात् उद्योग यदि दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है तो सरकार ऐसे उद्योग को प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है। सन् 1953 के संशोधन के अनुसार सरकार बिना जांच कराये भी उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है।

(5) अनुसूचित उद्योगों के विकास तथा नियमन के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (Central Advisory Council) बनाने की व्यवस्था की गयी।

(6) नये उद्योगों तथा इकाइयों को लाइसेंस देने के लिए एक अनुज्ञादायी समिति (Licensing Committee) नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी।

(7) अनुसूचित उद्योगों या सम्बन्धित उद्योगों की उन्नति तथा विकास के लिए पृथक् पृथक् 'विकास परिषदों' (Development Councils) की स्थापना का प्रावधान किया गया।

केन्द्रीय सलाहकार परिषद्—सन् 1952 में इस परिषद् की स्थापना की गयी जिसमें उद्योग, श्रमिक, उपभोक्ताओं, प्रारम्भिक उत्पादकों तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं। इस समिति में कुल 30 सदस्य हैं। यह परिषद् अनुसूचित उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देती है। सरकार इस एकट के अन्तर्गत नियम बनाते समय, उद्योगों की निर्दोश होने तथा या उनकी प्रत्यक्ष समस्या अपने हाथ में लेते समय भी परिषद् में सलाह लेती है।

विकास परिषदें—इन परिषदों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सम्बन्ध स्थापित करना तथा इस बात पर ध्यान रखना है कि निजी क्षेत्र में उद्योग नियोजन से अनुसार कार्य करते हैं या नहीं। इन परिषदों में उद्योग-पति, श्रमिक, प्रविधिक विभाग तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होते हैं। परिषदों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) उत्पादन के लिये मजदूरी मुताबिक दत्त, उत्पादन योजनाओं में सम्मेलन स्थापित करना तथा समय समय पर योजनाओं की उन्नति की समीक्षा करना।

(2) उत्पादन को अधिकृत करने, उत्पादन क्षमता में कमी करने तथा वस्तुओं के गुण में सुधार करने के लिए सुझाव देना।

(3) कच्चा माल प्राप्त करने तथा निर्दिष्ट कच्चे माल के वितरण में सहायता देना।

(4) प्राविधिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने तथा वैज्ञानिक व औद्योगिक शोध-कार्य को प्रोत्साहित करना।

(5) सरकार द्वारा लीये गये मामलों पर अपनी सलाह देना।

इन परिषदों की निजी मामलों की धारिण्या (Nurses for private enterprise) कहा जाता है। देश के अनेक उद्योगों जैसे चीनी, ऊनी तन्त्र, कृत्रिम रेशमी वस्त्र, साइकिल, बिजली आदि में विकास परिषदें सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

अनुज्ञादायी समिति—इस समिति में योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालय के प्रतिनिधि हैं। समिति नई इकाइयों की स्थापना तथा पुरानी इकाइयों के विस्तार के लिए लाइसेंस देती है। लाइसेंस देते समय पचसदीय योजनाओं के

उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाता है। इस एक्ट के अन्तर्गत उन औद्योगिक संस्थानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं है जिनमें 100 से कम श्रमिक काम करते हों तथा बिजली स्थायी सम्पत्ति 10 लाख रुपये से कम हो।

अधिनियम की समीक्षा—उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके द्वारा निजी क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। भारत का औद्योगिक विकास हम बात का साक्ष्य है कि देश में सुविद्योगित तथा समन्वित रूप पर औद्योगिक विकास नहीं किया गया। उद्योगपतियों ने देश के हित का ध्यान नहीं रखा वस्तु के बजाय उन्हा उद्योगों की स्थापना की, जिससे उन्हें शीघ्र लाभ (quick return) प्राप्त हो सके। इनका परिणाम यह हुआ कि औद्योगीकरण की नींव मजबूत नहीं हुई, जिससे भविष्य में औद्योगिक विकास में कठिनाई हुई। उद्योगागारों द्वारा मूलभूत उद्योगों (Basic Industries) का विकास न करना इस बात का प्रमाण है। अतः देश के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता थी।

इसने, भारत एक विद्यमान देश है जिसके कुछ भाग आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं तथा दूसरे भाग अधिक विकसित हैं। पूरे देश के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय विकास (Regional Development) पर ध्यान दिया जाय। इस अधिनियम द्वारा इस कार्य में सहायता मिली है।

नीचेरे इस अधिनियम के कारण उद्योगपति मनगानी नहीं कर सकते। निरन्तर तथा जांच की व्यवस्था के कारण उद्योग टूट काधार (soured footing) पर चलाने जायेंगे, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी तथा देश के प्राकृतिक संपत्तियों का समचित उपयोग सम्भव होगा। इस अधिनियम द्वारा औद्योगिक विकास की योजनात्मक प्रवृत्तियों को रोका जा सकेगा।

सन् 1956 की नई औद्योगिक नीति

30 अप्रैल, 1956 को भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव अपनाया। इस प्रस्ताव द्वारा सन् 1948 की औद्योगिक नीति को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। पिछले आठ वर्षों (1948-1956) में कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इनमें परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। ये कारण निम्नलिखित हैं।

1) भारतीय संविधान—26 जनवरी, 1950 से गणतन्त्र भारत का नया संविधान लागू किया गया। इस संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई तथा सरकारी नीति विषयक निर्देशक सिद्धान्तों

(Directive Principles of Policy) का उल्लेख किया गया। इन निर्देशक सिद्धान्तों में इस सिद्धान्त का उल्लेख किया गया कि “औद्योगिक साधनों का स्वाभिव्यक्त एवं नियन्त्रण अधिपतम सामुदायिक समानता लाने के लिए हो तथा अर्थ-व्यवस्था का संचालन जन-साधारण के हितों के विरुद्ध न हो और जन तथा उत्पादन के साधनों का सीमित क्षेत्र में केन्द्रीकरण न हो।” अतः सवियोग की इन विशेषताओं के अनुस्यू औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया।

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना—देश का औद्योगिक विकास नियोजन द्वारा किया जा रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ कर दी गयी थी। यह योजना मूल रूप में उद्योग-प्रधान थी। प्रथम योजना के शान्त अनुभवों के आधार पर तथा इस या साधन गति से औद्योगीकरण करने के लिए भी औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना आवश्यक था।

(3) समाजवादी समाज—प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करना था, परन्तु इससे 1954 में समद न दस की अर्थिक तथा सामाजिक नीतियों का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना निर्दिष्ट किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तृत करना आवश्यक हो गया। अतः औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना स्वाभाविक था।

सन् 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ—सन् 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव का उद्देश्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना है। इस औद्योगिक नीति की प्रस्तावना में कहा गया है, “समाजवादी समाज का राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में अपनाया और योजनाबद्ध तथा तीव्र गति से विकास आवश्यकता इस बात की भाव करते हैं कि आभारभूत एवं सामरिक (strategic) उद्योगों और सार्वजनिक हित (public utilities) सम्बन्धी सभी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में हो। अन्य आवश्यक उद्योग भी क्रिश्चन दत्तनी विद्यालय भाषा में विनियोग की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्र राज्य ही पूर्ण कर सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में होने की आवश्यकता है। जन राज्य का अधिक विस्तृत क्षेत्र ॥ उद्योगों के भारी विनियमन या प्रत्यक्ष दायित्व सम्हालना है।” औद्योगिक नीति में इन उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया जिन्हें प्राप्त करना था।

(1) आवश्यक विकास की दर में वृद्धि करना तथा औद्योगीकरण की गति को तीव्र करना,

(2) बड़े उद्योग तथा भवन-निर्माण उद्योग का विकास करना,

(3) सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तृत करना,

(4) बृहत् तथा बढते हुए मूहकारी क्षेत्र (Co-operative sector) का निर्माण करना,

(5) निजी एकाधिकार तथा कुछ ही दायो में आर्थिक क्रान्ति को केन्द्रित होने से रोकना; और

(6) आर्थिक व्यवस्था की असमानता को कम करना ।

इस औद्योगिक नीति की अन्य मुख्य बातें निम्नलिखित थीं ।

(1) उद्योगों का विभाजन—उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी का विभाजन दृष्टि से किया गया, जिससे राज्य का सहयोग निश्चित हो सके ।

(क) अनुसूची 'अ'—इसमें वे उद्योग सम्मिलित किये गये, जिनके विकास का दायित्व एकमात्र सरकार पर होगा । यह श्रेणी सन् 1948 की औद्योगिक नीति की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों को सम्मिलित कर बनायी गयी । इस श्रेणी में तीन प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं, सार्वजनिक हित सम्बन्धी उद्योग आन्तर-भूत उद्योग तथा मातापिता एवं क्षतिग्रस्त बंदाओं सम्बन्धी उद्योग । सूची में 17 उद्योग सम्मिलित किये गये हैं ।¹ इन उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी । परन्तु वर्तमान इकाइयों का विकास निजी क्षेत्र द्वारा किया जा सकता है । यदि राष्ट्र हित में आवश्यक समझा गया तो नयी इकाइयों की स्थापना में भी सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग ले सकती है, परन्तु रेलवे तथा वायु यातायात, अस्त्र-सस्त्र तथा अणुशक्ति के विकास पर सरकार का एकाधिकार रहेगा । यदि निजी क्षेत्र का सहयोग दिया गया तो सरकार पूँजी में आधे से अधिक भाग (Majority participation) लेगी या अन्य विधि अपनायेगी, जिससे उद्योग की नीति-निर्धारण तथा नियन्त्रण सरकार के हाथ में हो ।

(ख) अनुसूची 'ब'—इस अनुसूची में 12 उद्योग² सम्मिलित हैं, जो धीरे-

1. अनुसूचित 'अ' में निम्नलिखित उद्योग हैं—अन्न-जन्तु, लकड़-कान, लोहा व इस्पात, लोहे, व इस्पात की भारी इकाई व लघु, भारी मशीनें भारी बिजली के पम्प, कोयला व लिफ्टाई, खनिज तेल, कच्चा लोहा, वैयक्तिक कोय, विद्युत यन्त्रक, सोना व हीरों का खनन, मत्त, लोहा, अस्त्र-सस्त्र, आदि की कार्गो, कोयला व अस्त्र यन्त्र सुधारना, लकड़-कान उत्पादन से सम्बन्धित मशीन हवाई जहाज बनाना, हवाई यन्त्रायात, रेल यातायात, समुद्री जहाज बनाना टेलीफोन एवं उसके तार, एवं वनार का कामान (रेडियो टेलीफोन सेट जोड कर) और बिजली का उत्पादन एवं वितरण ।

2. अनुसूची व, ॥ उद्योग इस प्रकार हैं—छोटे रॉयको को छोड कर 'अन्न खनिज पदार्थ', लकड़-कान तथा एवं अस्त्र-सस्त्र जहाज की प्रथम श्रेणी में नहीं हैं, मशीन औद्योगिक, फोटो-इलास्टिक एवं टून, रबिड, सामाजिक उद्योगों की आन्तर-भूत सामग्री, बंदापन, छार, कृत्रिम रबर, मोशन का कार्बोनाइडेशन, रासायनिक मोल, सडक यातायात एवं सडकी यातायात ।

धीरे राज्य के अधीन होने तथा आधारभूत ऋण ऋणों की स्थापना सरकार द्वारा ही की जायेगी। निजी माहंगी इन उद्योगों का विकास कर सकते हैं। इसके लिए बाह्य से उद्योगों की स्वयं स्थापना करें या राज्य के साथ भाग लें।

(१) अन्य उद्योग—यह सभी उद्योग राष्ट्रीय स्तर पर रख गये। इन उद्योगों का विकास पूर्णतया निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया। सरकार किसी भी समय इस क्षेत्रों से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना कर सकती है। सरकार इन क्षेत्रों के उद्योगों की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं के अनुसार विकास करने में आवश्यक सहायता देगी।

(२) कृषि एवं लघु उद्योग—औद्योगिक नीति प्रस्ताव में पहले की भाँति ही कृषि एवं लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया। इन उद्योगों द्वारा मुख्यतः खाद्य सामग्री से रोजगार प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आय का सक्रिय वितरण होता है तथा ऐसे माध्यम उत्पादन में योग देने लगते हैं, जो सम्भवतः इन उद्योगों का अनुपस्थिति में प्रमुख नष्ट होते। इन उद्योगों की सहायता के लिए वह पैमाने के उद्योगों से उत्पादन कर कर (Differential Taxation) लगा कर उनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा या प्रत्यक्ष सहायता दी जायेगी। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कृषि तथा लघु उद्योग आत्मनिर्भर हो तथा उनका विकास बढ़ पैमाने के उद्योगों के एक अंग के रूप में हो। उनकी उत्पादन प्रणाली में सुधार किया जायेगा तथा उन्हें मशीन एवं विद्युत प्रदान की जायेगी। इस क्षेत्र में औद्योगिक महत्वपूर्ण समितियों की प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा औद्योगिक बस्तियों के द्वारा इन उद्योगों की अवस्था में सुधार किया जायेगा।

(३) क्षेत्रीय असमानता को दूर करना—देश के विभिन्न भागों में विकास सम्बन्धी असमानता को दूर किया जायेगा जिससे औद्योगिकरण के लाभ देश की पूरी ग्रामीण व्यवस्था को प्राप्त हो। राष्ट्रीय नियोजन का एक अङ्ग विद्युत एवं जल में सक्रिय के माध्यम तथा वास्तविक के माध्यमों का विकास करना होगा। प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक तथा कृषि एवं व्यवस्थाओं के समान विकास पर ध्यान दिया गया, जिससे देश के प्रत्येक भाग को जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।

(४) औद्योगिक शक्ति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों में लब्ध हुए सभी पदों को उचित प्रोत्साहन (Incentives) दिया जायेगा। श्रमिकों को काम करने तथा रहने की दशाओं में सुधार किया जायेगा, जिससे उनकी कार्य-क्षमता में वृद्धि हो सके। औद्योगिक उन्नति के लिए औद्योगिक शक्ति आवश्यक है। ग्रामीण समाजवादी प्रगति

का साजोदार है, अतः उसे विकास के कार्य में सत्पाद से भाग लेना चाहिए। धन-सम्पत्तियों में सुधार तथा धर्मिकों एवं विरोधियों को प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने की नीति का पालन किया जायेगा।

(5) प्राविधिकों तथा प्रबन्धकों का प्रशिक्षण नयी औद्योगिक नीति में यह कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में तथा कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए प्राविधिकों तथा प्रबन्धकों को उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा। विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए प्राप्त सुविधाओं में वृद्धि हो जायेगी।

(6) विदेशी पूँजी - विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में इस नीति में घोषणा नहीं की गयी, जहाँ प्रधानमन्त्री ने अप्रैल 1949 में इस सम्बन्ध में जो घोषणा की थी, उसे ही अपनाया गया। इसमें स्पष्ट किया गया था कि सरकार विदेशी पूँजी में स्वदेशी पूँजी में कोई भेदभाव नहीं करेगी।

(7) निजी क्षेत्र का नियमन तथा सहायता सरकार निजी क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, विशेषकर ऐसी औद्योगिक योजनाओं में जिनमें बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी सहायता का स्वरूप यहाँ या पूँजी में भाग लेना होगा अथवा यह ऋण पत्रों के रूप में होगी। निजी क्षेत्र के उद्योगों को सरकार की आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अनुसार निजी क्षेत्र उद्योग नियमित होंगे। जहाँ तक सम्भव होगा, उद्योगों को पूरी स्वतन्त्रता दी जायेगी। यदि किसी उद्योग में सार्वजनिक तथा निजी दोनों पक्ष रुके हुए हैं, तो ऐसी व्यवस्था में दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

इनके अतिरिक्त उद्योगों का तीन वर्गों में जो विभाजन किया गया है वह उन्हें एक-दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं करेगा। इन क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता (Sectoral inter-dependence) के सिद्धान्त का पालन किया जायेगा।

(8) सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रवृत्ति-व्यवस्था प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ ही साथ इस क्षेत्र के उद्योगों की प्रवृत्ति व्यवस्था का महत्व बढ़ गया है। प्रबन्धकों से सीज़ निर्णय तथा उत्तरदायित्व सभालने की भावना का पाया जाना आवश्यक है। अतः अधिकारों का विकेंद्रित होना तथा सरकारी उद्योगों का वित्तीय विद्वान्ता के अनुसार चलाया जाना आवश्यक है। जहाँ तक सम्भव हो, सरकारी उद्योगों के संचालन तथा प्रबन्ध व्यवस्था में स्वतन्त्रता होगी चाहिए।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अन्त में यह आशा व्यक्त की गयी थी कि इस नयी औद्योगिक नीति का सभी वर्गों द्वारा स्वागत होगा तथा इससे राष्ट्रीय का तीव्र पति से औद्योगीकरण करने में मदद मिलेगी।

सन् 1948 तथा 1956 के प्रस्तावों की तुलना

औद्योगिक नीति विषयक इन दोनों प्रस्तावों में निम्नलिखित अन्तर दृष्टि-गोचर होते हैं

(1) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार—सन् 1948 के प्रस्ताव में उद्योगों को चार वर्गों में विभाजित किया गया था, जबकि सन् 1956 के प्रस्ताव में उन्हें तीन वर्गों में ही बांटा गया। नवी औद्योगिक नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र का काफी विस्तार कर दिया गया तथा सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की संख्या बढ़ा दी गयी। 1948 की नीति के अनुसार केवल तीन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार था और 6 उद्योग ऐसे थे, जिनमें नयी इकाइयों की स्थापना सरकार ही कर सकती थी। इसके अतिरिक्त 18 उद्योगों का सरकार द्वारा नियमन तथा निपन्त्रण होता था। शेष उद्योग पूर्णतया निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिये गये थे। परन्तु सन् 1956 की नीति के अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना सरकार द्वारा की जा सकती है तथा 17 आधार-उद्योगों का विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है।

(2) राष्ट्रीयकरण—सन् 1948 की नीति में यह कहा गया था कि द्वितीय श्रेणी के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर 10 वर्षों के बाद पुनर्विचार होगा। परन्तु सन् 1956 की नीति में राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है, बल्कि एक प्रकार का आश्वासन दिया गया है कि प्रथम श्रेणी से सम्बन्धित निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। इस प्रकार दूसरी औद्योगिक नीति में निजी उद्योगों को राज्य द्वारा लिये जाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

(3) निजी क्षेत्र—एक प्रकार से निजी क्षेत्र का भी नयी नीति में विस्तार किया गया। तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत चल जा रहे निजी उद्योगों का विकास सार्वजनिक उद्योगों के साथ साथ होता रहेगा, परन्तु राज्य द्वारा उनका नियमन होता रहेगा जिसमें अनहित की रक्षा हो सके।

(4) सहकारी क्षेत्र—सन् 1948 की औद्योगिक नीति में सहकारी क्षेत्र पर जोर नहीं दिया गया था, जबकि 1956 की नीति के अनुसार निजी क्षेत्र का विस्तार जहां तक सम्भव होगा, सहकारी रूप में करने की व्यवस्था की गयी है।

(5) शिक्षित विद्यार्थी—सन् 1948 की नीति के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण कठोर ढंग से किया गया था, परन्तु सन् 1956 की नीति में उद्योगों का वर्गीकरण शिथिल है। योजना तथा देश की आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है।

सन् 1956 की नीति की समालोचना

सन् 1956 की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाये जाते हैं। इस नीति की विभिन्न शक्तों में निम्नलिखित आलोचनाएँ की गयी हैं।

(1) ऊपरों तीर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीति निजी क्षेत्र के प्रति अधिक उदार है परन्तु वास्तव इस नीति द्वारा निजी क्षेत्र को संकुचित करने का प्रयत्न किया गया है। इस नीति में राष्ट्रीयकरण की घमकी परीक्षा रूप में दिखाना है। औद्योगिक नीति का यह वाक्य, "inherent right of the state to acquire any industrial undertaking would always remain" इस उद्देश्य की भार पर्याप्त संकेत करता है।

(2) औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में लोच (flexibility) पर जोर दिया गया है परन्तु इसका प्रयोग 'सार्वजनिक क्षेत्र' के ही लिये किया जायेगा क्योंकि सरकार किसी भी उद्योग को प्रारम्भ कर सकती है। इस प्रकार 'अनुसूची त' के उद्योगों में क्षेत्र में निजी क्षेत्र का स्थान गौण रहेगा और नवीय क्षेत्रों के उद्योगों में भी सरकार का दखल रहेगा।

(3) सहकारी क्षेत्र के विस्तार की जो बात प्रस्ताव में कही गयी है वह भी भ्रामक है। वास्तव सहकारी क्षेत्र सरकार के निर्देशन पर ही कार्य करेगा और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का स्थान सर्वोच्च (Subsidary) रहेगा। इस प्रकार भारत में सहकारिता के नाम पर राजकीय पूँजीवाद (State Capitalism) को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(4) औद्योगिकरण के प्रश्न पर सरकार ने सिद्धान्तों (ideology) का ही ध्यान रखा है, आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया है। निजी क्षेत्र के महत्त्व में ओ कमी की गयी, यह अवाञ्छनीय थी। प्रथम योजना-काल से निजी क्षेत्र की सफलता को देखते हुए उसे प्रमुख स्थान प्रदान करना चाहिए था।

विदेशी पूँजी के विषय में प्रस्ताव में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि इसके सम्बन्ध में नीति स्पष्ट होती तथा राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र निश्चित कर दिया होता तो विदेशी पूँजीपति निश्चय होकर भारत में अधिक पूँजी निविद्योजन कर सकते थे।

(1) विद्वत् क्षेत्र के अध्यक्ष श्री यूसुफ खान ने कहा है कि "यदि इस नीति का पालन रचना में किया गया तो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तीर्ण एवं प्रशासनात्मक साधनों पर, जिन पर पहले से ही अधिक भार है और अतिरिक्त भार पड़ेगा तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की गति सीमित हो जायेगी।"

सन् 1956 को औद्योगिक नीति देश के लिए उत्तम है -

उपयुक्त आलोचनाएँ बहुत कुछ एक पक्षीय हैं। वास्तव में, वर्तमान औद्योगिक नीति देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से हो सकता है

(1) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों का विकास नयी औद्योगिक नीति में सरकार द्वारा बहुत बड़ बड़े तथा कुछ सार्वजनिक हित के उद्योग लेने को घोषणा की गयी है। सरकार द्वारा रेल के इजन, दवाइयाँ, खाद, रसायन तेल आदि भारी पूँजी वाले उद्योग के अतिरिक्त कुछ उपभोक्ता समान उत्पन्न करने की इकाइयाँ (सीमेन्ट, चीनी आदि) भी स्थापित की हैं। इनसे निजी साहस को किसी प्रकार कम करने का उद्देश्य नहीं है बल्कि उनके लिए यह बख़्तर है कि वह सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से अधिक कार्यक्षमता प्रदर्शित कर अपने योगदान का अधिकाधिक महत्व प्रमाणित करें।

गत पन्द्रह वर्षों में भारत की सम्पूर्ण उत्पादन सम्पदा में शीघ्र क्षय का भाग को 1950-51 में केवल 15% था 1960-66 में बढ़कर 35% हो गया है।¹ अनेक मफ़्तानों के होने पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से देश में इनीशियरिंग, औषध, रसायन, खाद तथा इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। पिछली चार योजनाओं में सरकारी विनियोग की पूर्ति का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है

उद्योगों में विनियोग²

(करोड़ रुपये में)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चौथी योजना
1 सार्वजनिक क्षेत्र	55	938	1 510	3298
2 निजी क्षेत्र	233	650	1 050	2000

(2) निजी उद्योगों पर नियंत्रण—विकासशील देशों में प्रायः योजनाबद्ध विकास करना होता है और इस कार्य के लिए एक और तो प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी पड़ती है दूसरी ओर सभी उद्योगों का विकास उचित दिशाओं में हो रहा रहे यह ध्यान रखना पड़ता है। इस दृष्टि से भारत में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियंत्रण की जो व्यवस्था की गई है, वह उचित ही नहीं, आवश्यक भी है। इस कार्य के लक्ष्य का प्रभाव इस धृष्टि से मिलता है कि गत वर्षों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कई अनुसूचक एवं वन्द फ़ैक्टरियो और मिलों का प्रबन्ध सम्भाल कर

उन्हें खाल किया गया है। सारे उद्योगों के लिए साझा सेवा वृद्धि विनियोग के लिए पूर्ण अनुमति। उद्देश्य यही है कि देश में पहले बड़ी उद्योग विकसित हों, जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विकास का प्रयोजन सन्तुलन बना रहे। इन सभी दृष्टिकोणों से नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा सब क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना तथा नये-पुराने सभी उद्योगों के विकास का निदमन एवं नियंत्रण करना सर्वथा प्रायसगत है।

(3) एकाधिकार का नियन्त्रण प्रो० जे० पी० ह्यूडन ने अपनी पुस्तक *Quiet Crisis in India* में यह मन प्रकट किया है कि भारत में औद्योगिक एकाधिकार की प्रवृत्ति बहुत प्रबल है। इस मन की दृष्टि राष्ट्रीय आय संकेन्द्रण समिति ने भी की है। इस दृष्टि से भारतीय औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि औद्योगिक साम्राज्य (Industrial Empire) का अन्त हो सके। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस प्रस्ताव की मायना को यथावत् कार्यान्वित करने की दिशा में उचित कदम उठाये। सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए नये-नये उद्योगपतिषों को साद्वर्त देने से औद्योगिक एकाधिकार का अन्त करने में सहायता मिल सकेगी। चीनी, सीमेन्ट तथा बिजलीसारई उद्योगों में इस एकाधिकार के अन्त के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। यह अत्यन्त सन्तोषजनक स्थिति है।

इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि नयी औद्योगिक नीति में एक ओर तो सरकारी हस्त की अधिकधिक विकसित करने का प्रावधान है, दूसरी ओर निजी क्षेत्र को विकेंद्रित रूप में विस्तृत करने की व्यवस्था है। अनेक क्षेत्रों में साधनमय तथा निजी क्षेत्रों का सामनस्य एवं सहयोग कहा जा सकता है। इस प्रकार देश के औद्योगिक विकास के लिए मार्बेनिक एवं वित्री क्षेत्र में एक ओर तो होड़ लग गयी है, दूसरी ओर उनमें सहशेष का नानावरण मन गया है। तीसरे, सहायगी क्षेत्र द्वारा भी औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, उदाहरण के तौर पर, देश के धक्कर (चीनी) उत्पादन का अग्रिम तृतीयांश सहयोगी चीनी फैक्टरियों द्वारा किया जाता है। अतः भारत में समाजवादी प्रमाण का स्थापना करने के लिए नयी औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक विकास करना सर्वथा प्रयोज्य होगा।

भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति : पाचवी पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 2 फरवरी सन् 1973 को भारत सरकार ने अपनी नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की, जो कि 18 फरवरी सन् 1970 की

औद्योगिक नीति की दशा में कुछ सुधार था। नई औद्योगिक नीति में सन् 1956 की औद्योगिक नीति के आधारभूत तत्वों को वही स्थान दिया गया। 'अ' अनुसूची के कारखानों का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में छोड़ा गया, लेकिन सरकार अगर सचित समझे तो इनका विकास निजी क्षेत्र तथा विदेशी पूँजीपतियों के हाथ में भी छोड़ सकती है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई कि इन नमोनों के विकास के लिए छोटे पूँजीपतियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इन नयी औद्योगिक नीति में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास तोष गति से करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया तथा 'सुव्यक्त साहस' को भी एक विशेष महत्त्व दिया गया, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों एक साथ सहयोग करके उद्योगों का विकास करेंगे।

नयी लाइसेंसिंग नीति (New Licensing Policy)

गत वर्षों में निरन्तर यह अनुभव किया जा रहा था, कि भारत में उद्योगों की लाइसेंस देने की प्रणाली दोषपूर्ण है और लाइसेंस व्यवस्था के कारण पसपास और भ्रष्टाचार की प्रतीतिमार्ग मिलना है। डा० आर० के० हजारी की रिपोर्ट में बिजना सहायों की अत्यधिक उदारतापूर्वक लाइसेंस देने के तथ्य प्रकाश में आये हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के लिए औद्योगिक नीति में कुछ उदात्ता करने की आवश्यकता है।

हजारी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, जो कि बहुत कुछ लाइसेंस से छूट से सम्बन्धित थी, संश्लेषण में महत्त्व के दौरान यह निश्चय किया गया कि भारत सरकार एक नयी कमेटी की नियुक्त करेगी, जिसका कि प्रथम कार्य 1956 से 1966 के बीच में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के नवीन स्वरूप को लागू करनी। इन उद्देश्य से 22 जुलाई, 1967 को थी मुद्रिमन्त्रालय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 17 जुलाई, 1969 को प्रस्तुत की तथा इन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 16 फरवरी, 1970 को भारत सरकार ने नयी लाइसेंस-नीति की घोषणा की। वास्तव में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा सिर्फ दत्त कमेटी के सुझावों के आधार पर ही नहीं की गई, बल्कि घोषणा के समय हजारी रिपोर्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) तथा ससद की अनुमान समिति (Estimates Committees) के सुझावों को भी सरकार ने ध्यान में रखा।

नयी औद्योगिक नीति में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन देश के औद्योगिक विकास की ध्यान में रखते हुए, तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के

लिए की गई। चतुर्थ योजना में योजना आयोग ने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है कि मशीन आयातमूल व सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों में जहाँ भारी निविद्योग की माया है, औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा तथा बिन उद्योगों के लिए विदेशी निविद्योग की आवश्यकता न हो, उनको लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त रखा जाए। इसके साथ-साथ लघु सेचो के विकास के लिए सरकार ने 1956 की ही औद्योगिक नीति को अपनाया।

यहां पर सर्वप्रथम औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति आच समिति-दत्त कमेटी (The Industrial Licensing Policy Inquiry Committee-Dutt Committee) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर निष्कष निकाल कर नयी औद्योगिक नीति का वर्णन करेंगे।

औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आकड़ों का विश्लेषण

(1) निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता के लिए लाइसेंस देना : दत्त कमेटी ने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में योजना के निर्धारित क्षमता से अधिक स्वीकृत क्षमता के लिए लाइसेंस दिए हैं। जिससे न तो निर्धारित क्षमता ही के लक्ष्य पूर्ण हो पाते हैं, तथा न ही योजना की प्राथमिकताओं में ही कोई स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित किया जा सका है। इसी कारण दत्त समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि "लाइसेंस प्रणाली वस्तुतः इस प्रकार से काम करने लगी है, कि लाइसेंसों की स्वीकृति और योजना प्राथमिकताओं में कोई स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित न हो सका।"

(2) मार्गदर्शक व विज्ञो क्षेत्र तथा औद्योगिक नीति मन् 1956 में स्वीकृत औद्योगिक नीति प्रस्ताव में वर्णित अनुसूचियों के सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र में भी खोल दिया गया है, क्योंकि अनुसूची में शामिल उद्योग विस्तृत धर्णिया (broad categories) मात्र थी तथा इनका क्षेत्र स्पष्ट नहीं किया गया था। जिस प्रकार कि 'लोहा एवं इस्पात' एक विस्तृत धर्णी है इसका क्षेत्र किस प्रकार के कारखानों तक होगा, स्पष्ट नहीं किया गया, जिसमें निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिला। उदाहरणार्थ मशीनी औजार उद्योग जिन्हें कि 'A' अनुसूची रखा गया, हिन्दुस्तान मशीन टूल को 9 लाइसेंस दिए गए, यहा गैर-सरकारी तंत्र मन् 226 'लाइसेंसिंग पोलिसी' के सम्बन्ध में निर्धारित ने लिखा है कि यह स्पष्ट है कि लाइसेंस नीति अपने आप में इस सम्बन्ध में एक सीमित भाग ही प्रदा कर सकती है। अनुसूची 'A' में कुछ उद्योगों का गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विनियम करने और अनुसूची 'B' में विकास के लिए अधिकतर गैर सरकारी क्षेत्र की प्रोत्साहित करने के निर्णय सरकार के सन्वतः स्तर पर ही किए गए हैं।"

(3) संतुलित क्षेत्रीय विकास : समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि इस लाइसेंस प्रणाली द्वारा कुछ ही राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, गुजरात तथा तामिलनाडु का विकास हो गया क्योंकि शेषके इन राज्यों ने कुल लाइसेंसों का 62.4 प्रतिशत प्राप्त किया। इस प्रकार की सरकारी नीति से देश का सीमित विकास हो पा रहा है। इन सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि लाइसेंस देने वाले अधिकारी लाइसेंस देने से पहले यह देखने हैं कि कच्चे माल की उपलब्धि है या नहीं, तथा अन्य मावज प्राप्त हो या नहीं उल्लेख है या नहीं, लेकिन औद्योगिक नीति में इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं उल्लेख किया गया है।

(4) विदेशी सहयोग - वर्ष 1949 में सरकार ने देश में औद्योगिक विकास के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए विदेशी व भारतीय उद्योगों में कोई भेद स्पष्ट नहीं किया। लेकिन इस प्रकार की उदार नीति ने एक ही प्रकार के उद्योगों में कई विदेशी सहयोग वाली फर्म स्थापित की जाने लगी, जिनकी छतें भी अलग-अलग होती थी। विभिन्न प्रकार के कल-पुर्तों के आयात की मांग बढ़ गयी, रायस्टी का बहुत अधिक मात्रा में भुगतान किया जाने लगा, दस्तूरी का अधिक भुगतान किया जाने लगा आदि। इस प्रकार विदेशी फर्मों को उद्योगों का स्थान दिया गया।

(5) मध्यम एवं छोटे उद्योग : 1948 तथा 1956 दोनों ही औद्योगिक नीतियों में मध्यम उद्योगों को विकास के लिए एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन बड़े औद्योगिक समूहों को ऐसे उद्योगों के लिए लाइसेंस दिए गए, जो कि छोटे एवं मध्यम श्रेणी में आते थे तथा इसके साथ गश् अन्य मुश्किलों जैसे, दिस, बिपज, तकनीकी सहूलता, प्रशिक्षण आदि की भी सुविधाएं नहीं प्रदान की गईं।

अतः उद्योगों के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि सरकार की 1956 की औद्योगिक नीति से देश में अधिक मात्रा के केंद्रीकरण में वृद्धि हुई है। हालांकि इस अवधि में देश में औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई है, लेकिन निजी साहसियों को आर्थिक स्थिति मिला है तथा साथ ही साथ प्रादेशिक असन्तुलन भी बढ़ा है। इस समिति ने एकाधिकार का प्रयोग द्वारा की गयी "बड़े औद्योगिक घराने" (Large Industrial House) की धारणा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार की निम्न प्रकार की लाइसेंस नीति की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया।

(1) प्रमुख तथा भारी निवेश (Core and Heavy Investment) वाले उद्योगों के लिए निम्न प्रकार की नीति की घोषणा की।

(अ) चतुर्थ योजना में प्रमुख उद्योगों की सूची में 9 बड़े समूहों वाले उद्योगों को लिया गया, तथा जिनको कि आवश्यकता के आधार पर अतिविवर्य आदान (Essential Inputs) उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रमुख उद्योगों की सूची (1) कृषि आदान-आदान (नाइट्रोबेन एवं फॉस्फेटिक आद), कोटनाशक दवाइया, ट्रैक्टर और पावर टिलर्स, रॉक फॉस्फेट, वाइराइट्स। (2) लोहा व इस्पात—बस्पा लोहा, पिग लोहा व इस्पात, मिश्र धातु और विशेष इस्पात। (3) व लौह धातु (4) पेट्रोलियम—तेल की खोज व उत्पादन, पेट्रोल शोध कार्य; चुने हुए पेट्रोकेमिकल, (सामग्रीयुक्त पेट्रो रसायन नाम्पलेक्स, डी० एम० डी०, के प्रोलेक्टम, एकी सोलिट्राइट, मिथिल गैस) (5) पेट्रोल कोयला (6) भारी औद्योगिक मशीनरी—पापक, रसायन, विविध मशीनरी औजार, रबर तथा छात्रों की मशीनरी आदि (7) अस्त्र निर्माण और इंजन, (8) लकड़ीकारी कामकाज, (9) इलेक्ट्रॉनिक्स।

(10) प्रमुख क्षेत्रों के अतिरिक्त जिन नए औद्योगिक प्रस्तावों की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक होगी, भारी विनियोग वाले क्षेत्र से समझी जाएगी। 1956 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्र के आश्रित उद्योगों को छोड़ कर शेष के लिए बड़े औद्योगिक संस्थानों तथा विदेशी कंपनियों को भी छूट दी गई।

(2) 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के विनियोग के बीच वाले मध्यम क्षेत्र से बड़े समूहों को छोटका मध्य संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, तथा लाइसेंस देने में उदार नीति की अपनाया जाएगा केवल आवश्यकता इस बात में दखलानी होगी कि कुल मिलाकर मुद्रा व आवश्यक न हो। बड़े तथा विदेशी संस्थानों को सिर्फ विस्तार की छूट प्रदान की गई।

(3) लघु क्षेत्रों के लिए आरक्षण की वर्तमान नीति जिसमें मशीनरी तथा पूर्ण से कुछ विनियोग 7.5 लाख रुपये का हो, जारी रहेगी।

(4) कृषि उद्योगों विद्युत, गन्ना, पटसन आदि का विचार करने वाले उद्योगों में सहकारी क्षेत्र की प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(5) 1 करोड़ रुपये तक के विनियोग वाले उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन निम्न प्रकार के उद्योगों के लिए यह छूट प्रदान नहीं की जाएगी

(क) ऐसे संस्थान जो कि बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

(ख) एसी कंपनिया जिसमें विदेशी स्वामित्व 50 प्रतिशत है।

(ग) ऐसे संस्थान जो एकाधिकार अधिनियम में परिभाषित प्रभुता-सम्पन्न संस्थानों (dominant undertakings) की श्रेणी में आते हैं।

(घ) ऐसे उद्योग जो कि प्रमुख उद्योगों की श्रेणी (Core sector) तथा लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं।

[उ] का उद्घाटन इलाइया मशोनरी और सामान्य के लिए 10 लाख रुपये से अधिक या कुल विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक विदेशी विनियोग के आधार को आवश्यक समझनी है।

उपरोक्त नीतियों के अतिरिक्त सार्वजनिक वित्तीय सम्प्राप्ति के प्रश्न में अधिक मात्रा में हिस्सा, पिछड़े हुए क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के लिए विशेष अनुदान आदि के लिए भी नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अनुमान का विकास, भारतीय टेक्नोलॉजी, डिजाइन व इन्व्हेन्टिविटी वस्तु आदि के विकास के लिए भी समग्र-मध्य पर विचार कार्यक्रम निर्धारित करने का प्रावधान रखा गया है।

सन् 1970 की साइसेंसिग नीति की समीक्षा

जैसा कि लिखा जा चुका है कि देश में बढ़ता हुआ आर्थिक मत्ता का केन्द्रीयकरण, प्रादेशिक असंतुलन, बीमा बर्त में विकास की दर आदि कुछ ऐसे कारण थे, जिसने कि दूर करने के लिए सन् 1970 में भारत सरकार ने नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। ऐसा मसला उठने लगा था कि नयी औद्योगिक नीति बड़े औद्योगिक संस्थानों के एकाधिकार को समाप्त कर देगी, पर इसे उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सका। १ करोड़ रुपये से अधिक विनियोग वाले उद्योगों को कुछ अपवाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़कर, बड़े समूहों द्वारा खोलने की इजाजत दी गई, जो कि समाजवाद की ओर स्पष्ट कदम नहीं है, इसने एकाधिकार की प्रवृत्ति में और बढ़ावरी होगी।

नयी औद्योगिक नीति में प्रमुख क्षेत्रों वाले उद्योगों के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए भी कोई ऐसी एजेंसियां नहीं बनायी गयीं, जो कि इन प्रकार का कार्य करेंगी।

इस औद्योगिक नीति की मांगें बना इन आधार पर भी की गई हैं कि बड़े उद्योगों के विकास से लघु उद्योगों को पर्याप्त रूप में कच्चा माल नहीं उपलब्ध हो पाएगा, जिससे कि इनकी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा और इन प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत से लघु उद्योग बन्द हो जायेंगे।

इसी प्रकार नयी उदार नीति से सारा पैमाने के उद्योगों के हिस्से पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने उत्पादन-समस्या में बिना साध विचार किए लाइसेंस दान की भी नीति अपनाई है। उनका निर्णय करने से पूर्व बड़े पैमाने और लघु-स्तर की इकाइयों में वर्तमान समस्याओं का अनुमान लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि नयी औद्योगिक नीति में सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है, मगर इसके द्वारा देश में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए, प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए, तथा एक

समाजवादी मर्यादा की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने का एक विशेष कार्यक्रम अपनाया गया है। लेकिन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार को प्रशासनिक सुधार के लिए एक विशेष समिति गठित करनी चाहिए जो कि प्रशासन में सुधार लाने का प्रयत्न करेगी।

1970 की औद्योगिक लाइसेंस-नीति में संशोधन

1971 तथा 1972 में औद्योगिक नीति तीसरा पट्ट आने के कारण तथा देश में समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब पाँचवें योजना के लिए एक निश्चित कार्यक्रम की बनाने के लिए करवरी 1973 में सरकार ने 1970 की औद्योगिक नीति में कुछ संशोधन किए, जो कि निम्न है —

(i) आर्थिक स्वायत्तता, आत्म-निर्भरता तथा विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव सरकार को नीतिपत्र बनाने के लिए प्रभावित जारी रहेगी।

(ii) आर्थिक नीति के केंद्रीकरण पर प्रभावित निम्नलिखित करने के लिए ऐसे सम्पान मिलनी पृ 20 करोड़ रुपये से अधिक है, "बड़े औद्योगिक संस्थान" (Larger Industrial Houses) घोषित कर दिए गए। 1970 की औद्योगिक नीति में यह सीमा 35 करोड़ रुपये की थी।

(iii) प्रमुख धातु वाले उद्योगों की संख्या को बढ़ाकर 19¹ कर दिया गया तथा इसमें लौह, अभ्रम, बड़े संस्थान, विदेशी कंपनियां तथा सरकार सब को स्थान दिया गया कि वे इन क्षेत्र बाले उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन 1956 की औद्योगिक नीति के 'A' अनुसूची के उद्योगों का संभावित विकास सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़ा गया।

(iv) 1 करोड़ रुपये वाली लाइसेंसिंग छूट संभावित जारी रहेगी, लेकिन ऐसे संस्थान मिलनी स्थायी पृ 5 करोड़ रुपये में अधिक है, यह छूट नहीं की जाएगी।

-
- 1- These include metallurgical industries besides some prime movers, certain castings of electrical and electronic equipment vehicles & ships, industrial machinery and machine tools agricultural and earth moving machinery industrial and scientific instruments nitrogenous and phosphatic fertilizers heavy and fine chemicals synthetic resins, plastics and rubbers, iron and steel industrial explosives, insecticides etc. Synthetic detergents, and chemicals for industrial use, drugs and Pharmaceutical, paper and pulp automobile tyres and tubes, plate glass, ceramic and cement products.

(v) लघु उद्योगों का आरक्षण सुरक्षित रहेगा, लेकिन इनके विकास को देखते हुए इस आरक्षण को बढ़ाया भी जा सकता है।

(vi) हर एक ऐसे निष्पक्ष जो कि 'मिश्रित क्षेत्र' (Joint Sector) वाले मशयानों पर लागू होते हैं, या निर्णय सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की ध्यान में रखकर किए जाएंगे। मिश्रित क्षेत्र वाले सभी उद्योगों पर सरकार का प्रभावशाली नियन्त्रण रहेगा तथा मिश्रित क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में यह बात विशेष रूप से सोची जाएगी कि कहीं वह औद्योगिक संस्थानों की पिछले दरवाज़ से प्रवेश (Back door entry) न हो जाए।

इस प्रकार पाचवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक उदार नीति की घोषणा की है।

प्रश्न

1 "औद्योगिक नीति का उद्देश्य समाजवादी समाज स्थापित करना होता चाहिए।" भारत की औद्योगिक नीति इस कथन से कहा तक मेल खाती है? आप अपने सुझाव दीजिए। (Raj Second year T D C Arts 1970)

2 "औद्योगिक विकास के लिए एक सुनिश्चित और प्रगतिशील औद्योगिक नीति आवश्यक है।" इस कथन की दृष्टि में रखते हुए भारत की औद्योगिक नीति की जांच कीजिए। (Raj Second year T. D C Arts 1969)

3 स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त भारत सरकार ने अपने औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्तावों में भिन्न औद्योगिक नीति को निर्धारित किया है, उसकी मूल्य में विवेचना कीजिए। देश की वर्तमान औद्योगिक नीति से आप कहा तक सहमत हैं? आप इसमें क्या सुधार करने का सुझाव देंगे? (Raj B A Hons 1967)

4 भारत सरकार की 1970 की घोषित औद्योगिक नीति का एक आलोचनात्मक विवरण दीजिए।

भारत में आर्थिक सत्ता का संकेन्द्रण

(Economic Concentration in India)

पिछले कुछ वर्षों में यह बड़ा विवाद का विषय रहा है कि क्या भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में अधिक सत्ता का संकेन्द्रण हुआ है। इस विवाद का हल पिछले वर्षों के एकाधिकार आच आयोग ने कर दिया है, जिसने यह बताया कि देश में कुछ बड़े बड़े बड़े व्यवसायी समूह (Larger Business Houses) के हाथ में अधिक सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया है। हालांकि इन बड़े-बड़े समूहों में देश के आर्थिक विकास में काफी रुचि दिखाई है, नए उद्योगों की स्थापना भी की गई है, औद्योगिक विकास की दर में भी वृद्धि हुई है, तथा नई तकनीकियाँ आदि का भी विकास हुआ है, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण समाजवाद की विचारधारा के पूर्णरूप से अनुकूल है। आज बड़ा बड़ा बिरला समूहों ने अर्थ-व्यवस्था के हर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना कर रखी है, जिसमें छोट बड़े के व्यवसायियों को पूर्ण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, और इस प्रतिस्पर्धा में उनकी शक्ति इतनी क्षीय हो गई है कि उनका टिकना भी कठिन हो गया है।

आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण में वृद्धि के कारण

आज बड़े बड़े उद्योग समूहों द्वारा पूँजी पर जो एकाधिकार जमा लिया गया है वो निम्न कारणों से है।

1. द्वितीय विश्वयुद्ध में अति जनोपायन द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ उद्योग-पतियों द्वारा असाधारण धन अर्जित किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों को विस्तार देने की नीति अपनाए जाने के कारण इन उद्योगपतियों ने इस धन का उपयोग नए उद्योगों की स्थापना एवं पुराने उद्योगों के विस्तार में किया। फलस्वरूप धनी उद्योगपतियों को अपने धन से वृद्धि करने की सुविधाएँ प्राप्त हुईं।

2. ब्रिटिश संस्थानों का विफल : स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बहुत सी ब्रिटिश व्यापारिक व औद्योगिक संस्थाएँ अपने संस्थानों को भारतीयों के हाथ बँच

कर चली गई। ये संस्थान अत्यन्त कुशलता के साथ संचालित किए जाते थे। परिणाम यह हुआ कि भारतीय उद्योगपतियों को अपना धन सुगमस्थित एवं सुन्दर संस्थानों को कम बचन के लिए उपयोग करने का अवसर मिला। इन संस्थानों की पूर्ण अर्जित सत्ता या लाभ भी इन्हीं उद्योगपतियों ने उठाया जिससे इनकी आर्थिक सत्ता का तीव्र गति से विस्तार हुआ।

3 सांश्रिक विकास स्मृत्यन्तर्गत प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में सांश्रिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि बड़े पैमाने का उत्पादन का काम उठाया जा सके। सांश्रिक विकास देय में बड़े-बड़े उद्योगों में ही मुख्यतः अपनाया गया जिसका सामान्य दृष्टि पूँजीपतियों को ही हुआ और फलस्वरूप सत्ता के केन्द्रीकरण को बढ़ा मिला।

4 अन्तर-कम्पनी विनियोजन एक कम्पनी की पूँजी पर अन्य महादूर कम्पनियों में विनियोजित करने का सुविधा के कारण कुछ औद्योगिक घरानों को अपनी अनेक गृहस्थ कम्पनियों को जोड़ने का अवसर मिला रहा है जिनके परिणामस्वरूप एक प्रमुख कम्पनी (Holding Company) पर नियन्त्रण रखने वाले परिवार अनेक नई कम्पनियों पर नियन्त्रण प्राप्त कर सका। इस प्रवृत्ति ने भी आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को बढ़ा दिया।

5 तीव्र औद्योगीकरण द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इस में आर्थिक विनियोजन के युग का सुनवाई हुआ तो औद्योगीकरण की गति और अधिक तीव्र हो गई। यही तीव्र औद्योगीकरण के लक्ष्य को जका अवधि में प्राप्त करने का उद्देश्य रहा है जब सरकार को औद्योगिक विकास के लिए उन लोगों का सहारा देना पड़ा जो पहले से ही इस क्षेत्र में निरक्षर थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ये लोग और अधिक समर्थता की ओर गए और आर्थिक सत्ता इनके हाथों में केन्द्रित हो गई।

(6) विदेशी संस्थानों पर नियन्त्रण बैंक राष्ट्रीयकरण के पूर्व इन समूहों का देश के बड़े बड़े बैंकों पर नियन्त्रण था, जिससे कि इन संस्थानों को बिल प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होता थी, तथा छोटे पधान के उद्योग इन लाभों से वंचित रह जाते थे और अब भी बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

1 Thus, the period immediately following the capture of the very few men which were harnessed to produce the quick industrial revolution of the country worked at the same time to concentrate power in industry in a few individuals or families who were already wealthy and powerful. Govt. of India Report of the Monopolies Inquiry Commission p. 6

(7) बड़े पैमाने की वस्तुओं के लाभ इन स्थानों को बड़े पैमाने की वस्तुओं के लाभ भी प्राप्त हुए हैं जिससे कि ये उत्पादक अपनी उत्पादन लागत को घटाने में सफल हो जाते हैं, और इस प्रकार से छोटे उद्योग अपने आप बाजार छोड़ देती हैं। फलस्वरूप आर्थिक सत्ता बन्द हथों में ही केन्द्रित होकर रह जाती है।

(8) सरकारी नीति आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण के लिए सरकारी नीति भी जिम्मेदार है। नए उद्योगों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में, तथा इसी प्रकार से कई वित्तीय सुविधाएँ जैसे कर प्रोत्साहन आदि मिलने में इन बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुँचा है। इसके साथ साथ विदेशी विनिमय, आयात लाइसेन्स आदि प्राप्त करने की उधार नीति ने भी इन उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाकर आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण में वृद्धि की है। इस प्रकार की प्रणाली में छोटे व्यवसायियों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। डॉ. मुगाजन के अनुसार, 'लाइसेंस देने की प्रणाली ने दल एकाधिकारी संस्थाओं को औद्योगिक बनाने के लक्ष्य मुद्दे ही बनाया है।'

(9) सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों का कार्य भाग सरकारी वित्तीय संस्थानों ने भी आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण में वृद्धि की है। जीवन बीमा निगम के 70% दीर्घकालीन ऋण तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के 62% ऋण इन बड़े संस्थानों को प्राप्त हुए हैं। फलस्वरूप आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है।

(10) प्रबन्ध अभिवृद्धि प्रणाली ने भी आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण में वृद्धि की है। इस पद्धति के अन्तर्गत एक फर्म का प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक उन्नित प्रतिकूल के खदल सौंप दिया जाता है। इन प्रकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रीकरण हो जाता है। इस पद्धति के आर्थिक दोषों को देखते हुए 3 अप्रैल, 1970 से सरकार ने कम्पनी अधिनियम में संशोधन करके इस प्रणाली को समाप्त कर दिया है।

केन्द्रीकरण के परिणाम

भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पर 45% जनसंख्या जीवन स्तर की न्यूनतम सीमा से भी नीचे निवास करती है, इस अर्थव्यवस्था में इस केन्द्रीकरण के कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं, इसकी कल्पना खुद ही की जा सकती है। सन् 1950 से जब से स्वतन्त्र भारत ने सर्वोच्च को स्वीकार किया है, समाजवाद की स्थापना का ध्येय, व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का वायदा आदि सारे सच्चे सरकार ने एक ताक में रख दिया है और अप्रत्याचार के एक ऐसे रूप को बन-म दिया है, जिसका कि बोझ एवं साधारण नागरिक द्वारा सहन नहीं किया जा सकता और यह धन के केन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप ही हो रहा है।

जैसा कि लिखा जा चुका है, कि हालांकि देश में आर्थिक विकास की दर बढ़ी है, लेकिन इसका लाभ नित्यमें व्यक्तियों को मिला है। इस केन्द्रीयकरण के बड़े भयंकर परिणाम होते हैं, जिससे कि हानि आम उपभोक्ता वर्ग को होती है। एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण वस्तुओं की कीमतों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, वस्तुओं की किस्मों में गिरावट, छोटे उद्योगपतियों का बाजार से निकाल फेंकना आदि प्रवृत्तियाँ बहुत ही तीव्र गति से जन्म ले रही हैं।

केन्द्रीयकरण के बारे में ध्यानपूर्वक गहन चिन्ता नहीं हो रही है, बल्कि महान् की प्रवृत्ति, स्ट्रटेजीजों आदि की प्रवृत्ति भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। गरीब और अमीर के बीच असमानता की खाई बढ रही है।

आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के परिणाम सामान्यतः निम्नलिखित हैं :

1. देश के कुछ चुने हुए बड़े-बड़े व्यापारिक घराने सामान्य जनता के समक्ष राजनैतिक दलों (कांग्रेस व स्तारक दल) को बहुत बड़ी क्षमताओं के रूप में देखते, अनैतिकता एवं निन्द्यताओं को बढ़ावा देते हैं।

2. देश की नयी पीढ़ी में सामाजिक एवं बौद्धिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। वे अब अधिक धनवान लोगों के विलासपूर्ण जीवन एवं उपभोग का अनुकरण करते जा रहे हैं जो निरर्थक हो देश के लिए अहितकर है।

3. आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण ने एकाधिकार सम्बन्धी दोषों की जन्म दिया है। आज बड़े बड़े व्यापारिक समूह समाचार पत्रों पर भी नियन्त्रण रखने लगे हैं तथा विज्ञापन के माध्यम से भी वे छोटे साहसियों को परास्त करने में सफल होते जाते हैं जिससे जन और आम की निपमता में और अधिक वृद्धि होती है।

4. पूँजी निर्माण में भी आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के कई प्रकार के बाधाएँ पैदा की हैं। इनके द्वारा होने वाली नकली का प्रयोग दिखावे के उपयोग में अधिक हुआ है। इन लोगों ने बहुत दिग्गज धन की देख ने आर्थिक विकास में न लगाकर भूमि, सोना-चादी, आभूषण आदि में लगाया है जिससे पूँजी निर्माण की गति मन्द पड़ी है।

5. आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण ने छोटे-छोटे साहसियों का गला घोटकर संस्थादिक कुतन्त्रा की जन्म दिया है। इनके पतनवस्तु छोटे-छोटे उत्पादकों में साहस पड़ा है, उनकी आगे बढ़ने व आर्थिक विकास में योग देने की समता में क्षीयलता आई है। इन सबका परिणाम यह हुआ है कि देश में उत्पादन की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है।

6. आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण ने देश में जन व आम सम्बन्धी विषमताओं में वृद्धि की है जिसके अनेक दुष्परिणाम हुए हैं।

प्रार्यिक संकेन्द्रण को दूर करने के उपाय

आज भारतवर्ष में केन्द्रीयकरण की भावना इस हद तक बढ गई है, कि सरकार हथेला इन्को दूर करने के लिए चिन्तित है। लेकिन इसको दूर करने के सारे उपाय व्यर्थ होंगे जब तक कि प्रशासन में पूर्ण रूप से सुधार नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार के गतिरोध को दूर करना सरकार के लिए एक बड़ी विवादप्रधान विषय बन गया है, लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या सरकार इसको दूर कर सकती है। आज भारतीय नागरिकों ने अपनी नीतिकला को बिल्कुल त्याग दिया है, जिनके शि दिना किमो भी प्रकार की सरकारों नीति बकल नहीं हो सकती है महा पर इन विषय पर विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि भ्रष्टाचार को दूर करना किसी भी राज्य की सरकार के हाथ में नहीं है, अब आर्थिक संकेन्द्रण को दूर करने के लिए नीच कुछ ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं, जो कि सरकार की नीति निर्धारण तत्त्व के रूप में अनिवार्य साबित होंगे।

(1) शार्वजनिक क्षेत्र का विकास सरकार की नावजनित क्षेत्र का विकास करना चाहिए, लेकिन निजी क्षेत्र को इस प्रकार हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, कि देश विकास के कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हो। खासतौर से एने क्षेत्रों में अधिक से अधिक भाषा में प्रविष्ट होना चाहिए, जहां पर कि निजी क्षेत्रों का एकाधिकार है।

(ii) सहकारी क्षेत्र का विकास सहकारी क्षेत्र को चीनी तथा जूट बनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सहकारिता के क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए।

(iii) छोटे उद्योगों का विकास सरकार की अपनी औद्योगिक नीति में इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए कि जहां पर छोट उद्योगपतियों द्वारा कारखाने का विकास किया जा सकता है, वहां पर बड़ उद्योगपतियों को हतोत्साहित करना चाहिए।

(iv) वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की सुविधाएं सरकार को इन वित्तीय संस्थाओं के लिए एक ऐसी नीति बनानी होगी, जिसमें कि ऋण आदि की सुविधाएं इन छोट उद्योगपतियों को प्राप्त हों, तथा एक निर्दिष्ट सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, कि कम सीमा तक ऋण की सुविधाएं उद्योगपतियों को देनी अनिवार्य होंगी।

(v) साक्षरता प्रयासों में प्रशासनिक सुधार सरकार को साक्षरता देने के लिए अपने उच्च स्तर के प्रशासनिक व्यक्तियों को सुधारवा अनिवार्य है, क्योंकि बड़े उद्योगपति अपने 'सम्पर्क' के कारण इन व्यक्तियों को प्रभावित करने में सफल हो पाते हैं, जिससे कि अधिकाधिक साक्षरता प्राप्त कर लेते हैं।

(vi) प्रशासनिक अस्थापार को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक दल अपने चुनाव अभियानों के लिए बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों से चन्दे स्वीकार न करें।

(vii) उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लाइसेन्स देने की विधि को इस प्रकार सरल बनाया जाय कि सहृदयी बिना अधिक धन व्यय किए तथा अधिक प्रतीक्षा किए आवश्यक लाइसेन्स प्राप्त कर सकें।

(viii) उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा जय की जाने वाली वस्तुओं में लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को प्रमत्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आर्थिक विकास की दर बढ़ाना तथा आर्थिक असमानता को दूर करने के बीच एक समन्वय स्थापित किया जा सकता है। एक तरफ तो आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना भी किसी भी राष्ट्र के लिए अनिवार्य होगा, तथा दूसरी तरफ आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयत्न भी अनिवार्य हैं, लेकिन दोनों कदम सरकार के द्वारा एक साथ नहीं स्थापित किए जा सकते, अगर इसके लिए प्रयत्न भी किए जायें, तो सरकारी नीतियों को उभी प्रकार से निर्धारित करना होगा जिससे कि दोनों कार्य एक साथ हो सकें।

एकाधिकार ज्ञान आयोग (Monopolies Inquiry Commission)

इस आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण का दूर करने के लिए सरकार ने 1964 में श्री के. सी. बान गुप्ता की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में पेश की। इस आयोग ने उद्योगों में दो प्रकार के संवेन्द्रण करने के दृष्टि बनाए।

(i) वस्तु के अनुसार केन्द्रीयकरण (Product-wise Concentration)

(ii) देश के अनुसार केन्द्रीयकरण (Country wise Concentration)

(i) वस्तु के अनुसार केन्द्रीयकरण में एक विशेष वस्तु या सबर के उत्पादन या वितरण सम्बन्धी सकल किसी एक या कुछ फर्मों अथवा बहुत सी फर्मों (चाहे वे बहुत ही कमों कुछ सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाए) के पास हों। (ii) जब वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण में मूलतः अनेक फर्मों का नियन्त्रण एक व्यक्ति या एक परिवार के पास हो तो यह देश के अनुसार केन्द्रीयकरण कहलाता है।

आयोग ने उदाहरणानुसार संवेन्द्रण में 100 वस्तुओं की जाच की, जिसमें अनिवार्य आवश्यकताओं वाली वस्तुओं में (जैसे तांबा, दिवागार्ह, जूते, स्टेड,

भारत में आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण

पालकर तथा दवाईयों आदि में) केन्द्रीयकरण की अधिक मात्रा विद्यमान है। करीब 55 वस्तुओं में उच्च भौमा का केन्द्रीयकरण पाया गया तथा तीन उत्पादक 75 प्रतिशत से अधिक मात्रा उत्पन्न कर रहे हैं।

देश के अनुसार केन्द्रीयकरण के लिए आयोग ने 2259 कंपनियों के विस्तृत आकड़े एकत्र किये, जो कि 83 बड़े व्यवसायिक समूहों के अधिकार में हैं, जिसमें से 75 समूहों की परिसम्पत्ति 5 करोड़ रुपये से कम नहीं है। इसमें से प्रथम स्थान टाटा का है, तथा द्वितीय बिरेला का।

अप्रैल 17, 1973 को लोक सभा में सकेन्द्रण के सम्बन्ध में दी गई जानकारी की कुछ मुख्य बातें निम्न तालिका में दी गई हैं —

पदों का नाम	कुल बिजनेस (₹ करोड़ ८०)	आयकर से पहले नफा (₹ करोड़ ८०)
बिरेला	718	62
टाटा	679	54
मफतलाल	165	12
श्रीराम	153	8
बागड	137	6
भापर	127	19
रायभाई	127	8
आई० सी० आई०	105	11
साहूजैन	101	3
बड़े हिस्जर	100	3

देश के प्रमुख 20 उद्योगगतिमें से उपर्युक्त 10 के अलावा अन्य 10 क्रमशः इस प्रकार हैं - बाल चन्द, मिथानिया, ए० सी० सी०, गोयनका, किल्कि, अहिन्दूमूल, सिधिया, बिला चन्द, कार्टिन बर्न तथा सूरजमल नागरमल। उपर्युक्त अणु मार्च 1971 के हैं।

एकाधिकारात्मक व प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार (Monopolistic and Restrictive Pact) :

एकाधिकारात्मक व्यवहार से तात्पर्य ऐसी क्रिया से है, जिसका उद्देश्य एकाधिकारी शक्ति का सुरक्षण, वृद्धि या समेकन होता है।

प्रतिस्पर्धात्मक कार्य प्रतिस्पर्धी शक्तियों के मार्ग में बाधक होते हैं या जो पूँजी या राशियों के उत्पादन में लगाने में स्वतन्त्र प्रवाह में बाधक होते हैं। प्रायः यह गत प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं -

(1) कीमतों का क्षैतिज नियन्त्रण (Horizontal Fixation of Prices)

(2) कीमत का उद्वेग निदयन और पुनः बिक्रय कीमत को कायम रखना (Vertical Fixation of Price and Price Re sale Maintenance) (3) उत्पादकों के बीच बाजारों का बंटवारा (Allocation of Markets between Producers) (4) कर्ताओं के बीच भेदभाव (Discrimination between Purchasers) (5) बहिष्कार (Boycott) (6) एकाधिकार व्यापार संधि (Exclusive dealing Contracts) (7) बंधनबद्ध प्रबंध (Tie up arrangements) एकाधिकार जाच आयोग की सिफारिशों (Recommendations of Monopolies Inquiry Commission)

(अ) गैर वैधानिक (Non legislative) - याचिका केन्द्रीकरण को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए भी जा चुके हैं लेकिन एकाधिकार जाच आयोग ने कुछ सुझाव और दिए हैं, जिनमें से गैर वैधानिक सुझाव निम्न हैं

(1) एक एकाधिकारमय एवम प्राचुर्यवादीक व्यवहार आयोग की स्थापना होनी चाहिये जो कि इनके हमले गति जनता को दूर करने के लिए मुद्राव देगी।

(2) सरकार को लाइसेंस जारी करने में छोट उद्योगियों को लाइसेंस देने में सहारता को नीति को बनाना चाहिये।

(3) विदेशी माल का परिमिति को देखने हुए मापक लाइसेंस प्राप्ति-मता के आधार पर मिलने चाहिये तथा जिन उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से इसकी आवश्यकता है।

(4) सामाजिक लाभ का वितरण किया जाना चाहिये।

(5) सरकारों को के लिए प्राप्तिमता छोट उद्योगों को मिलनी चाहिये।

वैधानिक सुझाव (Legislative Suggestions)

(1) याचिका सत्ता के केन्द्रीकरण का बच अव ही करना चाहिये, यह यह उत्पादन व वितरण के लिए सन्तुष्ट बन जानी है।

(2) एकाधिकारमय व प्रतिस्पर्धात्मक प्रयत्न पर रोक लगानी चाहिये।

(3) एक एसी स्थायी संस्था की स्थापना करनी चाहिये जो एसी समझौतों की परिमितियों का अध्ययन करें। मुद्राव मोदी का अन्व करें तथा कीमतों को स्थिर रखने में मदद प्रदान करें।

सरकारी उपाय

एकाधिकार जाच आयोग की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार व प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार अधिनियम 1969 (The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969) जून 1970 से लागू हो गया था तथा अगस्त 1970, में तीन व्यक्तियों का एकाधिकार व प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार विधि आयोग

स्थापित किया है जिसका प्रमुख कार्य आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकना है तथा प्रभुत्वशाली या बड़े प्रतिष्ठानों की क्रियाओं को नियन्त्रित करता है।

आज सरकार के सामने बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, कि क्या आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोककर आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करके केन्द्रीयकरण को रोका जा सकता है? अब परिस्थिति इतनी विपन्न हो गयी है कि सरकार को अगर आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को पूरा करना है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यकुशलता को बढ़ाना होगा। मुटोर तथा लघु उद्योगों का तीव्र गति से विकास करना अनिवार्य हो गया है, अन्य: उसके लिए वैसी ही परिस्थितियाँ बनानी होंगी जिससे लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

प्रश्न

1. भारत में निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के क्या कारण रहे हैं? भारत सरकार ने इस केन्द्रीयकरण रोकने के लिए क्या उपाय अपनाए हैं?

[राज० वि० वि० द्वितीय वर्ष कला 1973]

भारत में रेल परिवहन

(Rail Transport in India)

"The extraordinary rapidity with which the construction of railways in India was achieved, produced an economic revolution in that country which like all revolutions, was not unaccompanied by sufferings. The obligations to save life in times of drought and the necessity of lines of strategic utility have been the cause of rapidity"

— Loveday

रेलें वास्तव में देश की जीवन रेखाएँ हैं, जिन पर देश के मानियो और सम्पदा का इस प्रकार आवागमन होता रहता है जैसे मानव शरीर में रक्तवाहिनी नालियो ॥ द्वारा रक्त प्रवाह होता है। भारतीय रेल देश का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सम्भवतः सबसे अधिक संगठित सरकारी प्रतिष्ठान है। संगठन की दृष्टि से भारतीय रेलों का एनिवा में प्रथम तथा विश्व में चौथा स्थान है। लम्बाई की दृष्टि से यह विश्व में दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। आज भारतीय रेलें आत्म-निर्भरता एवं प्रगति के स्वयम्भू युग में हैं तथा विश्व के ऐसे गिने-चुने देशों में से एक है, जिन्हें रेल सम्बन्धी प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति जानकारी है। भारतीय रेलें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ विदेशों को भी रेल सामग्री का निर्यात कर रही हैं।

रेलों का विकास : भारतवर्ष में रेल यातायात का प्रारम्भ सन् 1853 ई० से प्रारम्भ हुआ। इसी वर्ष बम्बई से थाना तक 22 मील की दूरी पर प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। सन् 1854 में कलकत्ते में भी एक रेलवे लाइन बनाई गई। विकास के प्रारम्भिक वर्षों में रेल यातायात में बहुत तीव्र गति से विकास किया। इस काल में रेलों के विकास की प्रमुख विशेषता यह थी कि इनका विकास देश में उद्योगों के विकास के साथ-साथ ही हुआ। सन् 1900 ई० तक भारतवर्ष में 25,000 मील

सम्बन्धी रेल मार्ग तैयार हो चुका था। आरम्भ में रेलों का प्रबन्ध विभिन्न कम्पनियों के हस्त में था जिनके मालिक अनेक थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 50 वर्षों में रेलों के विकास की गति बहुत धीमी रही। सन् 1950 ई० तक केवल 34,000 मील से कुछ ही अधिक रेल माले बनाया गया था। आरम्भ में रेल परिवहन के विकास का भार निजी कम्पनियों के हाथ में था, जिन्हें सरकार ने कई सुविधाएँ दे रखी थी : मुक्त जमीन, 'पूँजी पर निम्नतम सस्र या व्याज की गारन्टी' आदि। निजी कम्पनियों द्वारा रेल यातायात का विकास वांछित गति से होने के कारण तथा इनकी प्रबन्ध सम्बन्धी जालोचनाओं के कारण सन् 1925 ई० में भारत सरकार ने पहली रेलवे कम्पनी अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली। सन् 1944 तक बीरे-बीरे सभी निजी रेलवे कम्पनियाँ समाप्त हो गईं और उनका स्वामित्व सरकार के हाथों में आ गया। सन् 1944 में भारतवर्ष में 3 प्रकार की रेल थी : (i) सरकार के अधिकार में प्रबन्ध क्षेत्र की रेलें; (ii) देशी महारजानों के अधिकार क्षेत्र की रेलें; तथा (iii) कुछ छोटी-छोटी रेलें। इनके प्रबन्ध एवं स्वामित्व में निम्नता पाई जाती थी। इनमें से कुछ माहनें इसकी छोटी थी कि उनका सामग्र्य होना असम्भव था। इनकी कार्य विधि भी अन्ध-मूर्ख थी। वारम्भिक प्रतिस्पर्धा एवं डेढ़ जाय के कारण जनता की भी कुशल एवं समोचित सेवा भी नहीं प्राप्त हो पाती थी। रेल-हकाबों की अनेकता के कारण प्रबन्ध में भी कुशलता एवं निरन्तरता नहीं हो पाती थी। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1950 ई० में देशी राजानों के अधीन समस्त रेलों को भारत सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तथा उनके प्रबन्ध में सुधार करने के सङ्केत से इनका पुनर्वर्गीकरण (regrouping) कर दिया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत को जो रेल व्यवस्था विरासत में मिली, वह 1930 के वर्षों की मदी तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेलों के व्यापक उपयोग के कारण जीर्णोद्धार में बहुती हुई थी। फिर देश के विभाजन के परिणामस्वरूप भी भारत की रेल सम्पत्ति और कम हो गई थी।

रेलों के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् अब रेलों के 9 क्षेत्र हैं। सबसे पहले सन् 1951 में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय व उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र बनाये गये। सन् 1955 व 1958 में क्रमशः पूर्वी रेलवे व उत्तरी रेलवे के दो दो टुकड़े कर दिये गये। अक्टूबर 1966 को रेलवे का 9वाँ क्षेत्र 'दक्षिणी केन्द्रीय रेलवे' बनाया गया। इस प्रकार भारतवर्ष में इस समय रेलों के 9 क्षेत्र हैं : (i) दक्षिणी रेलवे; (ii) मध्य रेलवे; (iii) पश्चिमी रेलवे; (iv) उत्तरी रेलवे; (v) उत्तरी-पूर्वी रेलवे; (vi) पूर्वी-रेलवे; (vii) दक्षिणी-पूर्वी रेलवे; (viii) उत्तरी पूर्वी गीमांत रेलवे; (ix) दक्षिणी-केन्द्रीय रेलवे।

रेलो के पुनर्वर्गीकरण से प्रकृत में कुशलता की सम्भावनाएँ बढ़ गई हैं तथा बड़े पैमाने पर प्रवन्ध से प्राप्त होने वाली मितव्ययताएँ भी सम्भव हो गई हैं। पुनर्वर्गीकरण ने पारम्परिक प्रतिस्पर्द्धा को भी समाप्त कर दिया है।

योजनाकाल में रेल परिवहन का विकास : योजना प्रारम्भ होने के 10 वर्ष पूर्व से ही भारतीय रेल व्यवस्था पर कुछ एवं देश विभाजन के परिणामस्वरूप भी बहुत अधिक पड़ गया था जिससे देश की सम्पूर्ण जर्प-व्यवस्था प्रायः अस्त-व्यस्त हो गई थी। अतः योजना के प्रारम्भिक वर्षों में रेलों के बाधुनिकीकरण व प्रतिस्थापन पर बल दिया जाना आवश्यक था। नियोजन काल में रेल परिवहन की बिना में जो प्रगति हुई उसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलें : प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेल परिवहन पर 423.23 करोड़ रु० खर्च किए गये जिसमें से 242 करोड़ रुपये केवल इन्जनों व टिन्डो पर व्यय किया गया। इस योजना के दौरान रेल परिवहन में 16% वृद्धि हुई। प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देश में विभाजन के कारण हुई क्षति को पूरा करना था। इस योजना काल में रेल इजनों, सवारी टिन्डो एवं माल के टिन्डो में क्रमशः 1586, 4758 तथा 61254 की वृद्धि हुई। रेलों का भारम निभैर बनाने के लिए चिस्तरन्जन से इजन बनाने तथा मद्रास के निकट रेल के टिन्डो बनाने का कारखाना लगाया गया। सन् 1955-56 तक रेलों में प्रतिवर्ष 179 इजन्, 14300 माल के टिन्डो तथा 940 सवारी टिन्डो बनाने की क्षमता प्राप्त करली। योजनावधि में 430 मील लम्बे पुराने रेल मार्गों को चालू किया गया तथा 1304 कि० मी० लम्बे नए रेल मार्गों का निर्माण किया गया। 46 माल लम्बे मार्गों को तैरोबज से मीटर गेज में परिवर्तित किया गया। प्रथम योजना के अन्त में कुल हमकी लम्बाई 34,736 मील थी।

द्वितीय योजना में रेलें : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में रेल परिवहन की क्षमता को बढ़ाने, रेल मार्गों, पुनो, इजनों तथा टिन्डो आदि के पुनः स्थापन के कार्य को पूरा करना तथा रेलों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य था। इस योजनावधि में रेलों पर लगभग 1041.69 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस योजनावधि में लगभग 1311 कि०मी० नई लाइनें बिछाई गईं। 1512 किलोमीटर लाइनों का दोहरा कर दिया गया। द्वितीय योजना काल में रेलवे लाइनों की लम्बाई 65,963 कि० मी० हो गई। योजनाकाल में सितेन्वर ट्रैफिक में 27 प्रतिशत तथा माल टुलाई में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई। द्वितीय योजनाकाल में 2216 इजन्, 7718 सवारी टिन्डो तथा 97,959 माकमाडियो के टिन्डो का प्राप्त किया गया। द्वितीय योजना काल में चिस्तरन्जन के कारखाने से 831 इजन तथा टेल्को (Tata Engineering and

Locomotive Works Co. Ltd.,) द्वारा भीटर बेल के 246 इन्जनों का उत्पादन हुआ।

तृतीय योजना में रेलवे: तृतीय योजना में रेल परिवहन के विकास पर 1685.8 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस योजनावधि में यात्रियों के आवागमन में 15 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया तथा 26.40 करोड़ टन माल ढोने की व्यवस्था की गई लेकिन योजनावधि में वृद्धि केवल 20.5 करोड़ टन ही हो सकी। इस योजना में 1801 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बनाई गई, 3228 किलोमीटर रेलवे लाइनों को दोहरा किया गया। योजनावधि में इन्जनों, सवारी डिब्बों एवं मालगाड़ों के डिब्बों में क्रमशः 1864, 8019, 1 44,789 की वृद्धि हुई।

भारतवर्ष में विभिन्न योजनाओं में किए गए व्यय के अलावा रेल परिवहन के विकास में सम्मिलित कुछ माकड़े निम्न सारिका में दिए जा रहे हैं :

योजनाओं के अन्तर्गत रेल परिवहन की प्रगति

विवरण	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	बापिक योजनाए	चतुर्थ योजना
1. नई रेलवे लाइनें (किलोमीटर में)	1304	1311	1,801	1061	1020
2. लाइनों को दोहरा बनाना (किलो- मीटर में)	370	1312	3,228	1268	1800
3. विद्युतीकरण (किलोमीटर में)	—	361.5	1 746	541	1700
4. रोलिंग स्टॉक का निर्माण					
(क) इन्जन	1586	2,216	1,864	877	1260
(ख) सवारी डिब्बे	4,758	7,718	8,019	3793	6500
(ग) मालगाड़ी के डिब्बे	61,254	97,959	1,44,789	55,317	1,01,000

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल परिवहन के विकास पर कुल मिलाकर 1525 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था है। इसमें से रेलवे 520 करोड़ रु० अपनी संचित निधियों से व्यय करेगी तथा शेष 1000 करोड़ रु० की व्यवस्था सरकार द्वारा रेलवे विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई है। इस योजनाकाल में 1020 किलोमीटर मार्ग में नई रेलवे लाइनों का निर्माण

किया जायेगा। 1700 किलोमीटर रेल मार्ग पर बिजली द्वारा तथा 2800 किलोमीटर रेल मार्ग पर डीजल द्वारा गाड़ियां प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है। इस योजनाकाल में 6500 सवारों डिब्बे तथा 101000 मालगाड़ी के डिब्बों के निर्माण करने का लक्ष्य है। यात्रेवापि में सवारों व माल परिवहन की वृद्धि, परिचालन लागत में कमी तथा आपूर्तिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा रेल प्रणाली को कुशलता पड़ाई जायेगी।

वर्तमान अवस्था भारतवर्ष में इस समय रेल परिवहन कुल माल परिवहन का 80% तथा यात्री परिवहन का 70% भाग ले जाता है। रेलों द्वारा प्रतिदिन लगभग 64.5 लाख यात्री यात्रा करते हैं तथा 5.7 लाख टन माल प्रतिदिन बोया जाता है। देश में प्रतिदिन लगभग 10,800 गाड़ियां चलती हैं। इस समय देश में 12000 इंजन, 34700 यात्री डिब्बे तथा 3.84 लाख मालगाड़ियों के डिब्बे हैं। भारत के सांख्यिकीय क्षेत्र में रेलवे सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें 13.60 लाख से अधिक स्थायी और करीब 3 लाख अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। आज भारतवर्ष में रेल मार्गों की लम्बाई 59,684 किलोमीटर है। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयस्त उद्योग है जिसके पास 3928 करोड़ रुपये से भी अधिक की सम्पत्ति है तथा जिसकी वार्षिक आय 1078 करोड़ रुपये से भी अधिक है।

रेल यातायात की समस्याएं भारतीय रेल यातायात के सामने कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं।

1 बिना टिकट यात्रा। भारतवर्ष में एक अनुमान के अनुसार बिना टिकट यात्रा के फलस्वरूप 5 से 7 करोड़ 60 तक की प्रति वर्ष रेलवे प्रशासन को हानि होती है। बिना टिकट यात्रा करने वालों में ग्राम विद्यार्थियों, रेलवे कर्मचारियों व उनके मित्र तथा सम्बन्धियों तथा पुलिस कर्मचारियों, मावुओं व मिसमगों की संख्या अधिक होती है। वे लोग भी जिन्हें भीड़ के कारण टिकट नहीं मिल पाई, बिना टिकट यात्रा करते हैं। बिना टिकट यात्रा के कारण एक ओर तो रेलों की मासिक हानि होती है तथा दूसरी ओर टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को कष्ट होता है।

2 दुर्घटनाओं की अधिकता। गाड़ियों के टकरा जाने, पटरी से उतर जाने आदि से रेल दुर्घटना हो जाती है। इन दुर्घटनाओं के कारण रेल सम्पत्ति को बहुत अधिक हानि होती है तथा बहुत से यात्री घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं, जिनके लिए रेलों को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। रेल कर्मचारियों की असावधानी व अनुशासनहीनता तथा तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के कारण भी आज कुल रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है।

3 कार्यक्षमता का अभाव : भारतीय रेलों की कार्यक्षमता विदेशों की तुलना में बहुत कम है। तेज चलने वाली गाड़ियाँ मात्र बहुत कम हैं। गाड़ियों का समय पर न जाना एक सामान्य बात है। कार्य कुशलता की कमी का नुकसान यात्रियों व माल भेजने वालों का उठाना पड़ता है।

4 यात्रियों की अधिक सुविधा दिलाने की समस्या - रेलगाड़ियों में प्रायः बहुत भीड़-भाड़ होती है। स्थानीय स्तर की यात्रियों की यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। डिब्बों में प्रायः समुचित रोशनी व पखौ का अभाव होता है। निशाम गृह, कैंटीन व्यवस्था, पीने के पानी का प्रदूषण, सोने की व्यवस्था, सफाई, आदि की व्यवस्था का भी प्रायः छोटे छोटे स्टेशनों पर अभाव होता है।

5 रेलवे इंजनों तथा डिब्बों की कमी - यद्यपि देश में रेलवे इंजन व डिब्बों का निर्माण होने लगा है तथापि देश की आवश्यकता को देखते हुए बहुत अधिक संख्या में इंजनों, डिब्बों व बैगनों की आवश्यकता है। आ-तयर्थ में बहुत से इंजन, डिब्बे तथा बैगन पिल चुके हैं जिसके प्रतिस्थापन की समस्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है।

6 रेल मार्गों के विस्तार की समस्या - एक अनुमान के अनुसार भारतवर्ष में एक लाख क्वांटरो के पीछे केवल 96 मील लम्बा रेल-मार्ग चल रहा है, जबकि अमेरिका, कनाडा व इंग्लैंड में प्रति लाख जन संख्या के पीछे क्रमशः 224, 465, व 46 मील लम्बा रेल मार्ग उपलब्ध है। यद्यपि भारतीय रेल-व्यवस्था एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में चौथे नम्बर पर है तथापि अन्य देशों से तुलना करने पर हमें पता चलता है कि हम इस विषय में कितने पीछे हैं। देश का क्षेत्र, जन संख्या तथा पिछाई की सीमाओं को देखते हुए रेल मार्गों के विस्तार की समस्या बड़ी प्रमुख समस्या है।

7 ईंधन की समस्या - भारतवर्ष में अधिकतर इंजन माद से चलते हैं जिसके लिए उचित कोयले की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में इस प्रकार से कोयले की कमी है। विद्युत सक्ति का भी अभी इस क्षेत्र में समुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

8 लाइनों के बदलने की समस्या - भारतवर्ष में आधे से अधिक रेलवे लाइनें मीटर व नैरगज की हैं। रेलों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इन लाइनों को ब्राड गेज में बदलने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में देश में हो रहे कार्य की गति बहुत धीमी है।

9 रेल लाइनों को दोहरा करने की समस्या - भारतवर्ष की अधिकांश रेलें एक-मार्गीय हैं। गाड़ियों के बिना बाधा आने जाने के लिए तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रेल मार्गों को दोहरा किया जाना आवश्यक है। यद्यपि देश में रेल

मार्गों को दोहरा करने का कार्य पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया है, तथापि इसकी गति बहुत मन्द है।

10. रेल सम्पत्ति की क्षति : आन्ध्र प्रदेश के किन्नी हिस्से में राजनीतिक अस्थिरता होने पर रेल सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई जाती है। इन प्रकार की तोड़-फोड़ की बाढ़बाहियों से प्रति वर्ष रेलवे प्रशासन को करोड़ों रुपये की क्षति होती है।

11. याता की असुरक्षा : आधुनिक युग में रेल याता भी असुरक्षित होनी चाहिए। असामाजिक तत्वों द्वारा आये दिन रेल के डिब्बों में लूट-पाट के समाचार मिलते रहते हैं जिससे रेलों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है।

12. छोटी की समाया भारतीय रेलों को, ऊपरी मार्ग के तारों की चोरी चैनलों व माल वाहनों की क्षतिग्रस्त लूटपाट, पैगन फिटिंग व मार्ग फिटिंग की वही पैमाने पर आए दिन होने वाली चोरी से, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति होती है।

13. अल्प समयावध : रेलों के बिजुतीकरण, स्वचालित सिग्नल व्यवस्था, संचालन क्षमता आदि को भी महत्वपूर्ण समयार्थ हैं, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है।

सुम्नाह - रेल यातायात की उपयुक्त समस्याओं को हल करने के लिए निम्नान्वित गुणग महत्वपूर्ण हैं :

(i) रेल दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए, दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लापरवाह कर्मचारियों को बड़ा दण्ड मिलना चाहिये, दुर्घटनाओं से बचने के लिए आधुनिकतम यन्त्रों का प्रयोग किया जाय, 'दुर्घटना बचाओ' सप्ताह मनाये जाएँ, पथोन्मति घोषणा के हिसाब से की जाय, उचित प्रशिक्षण एवं योग्य कर्मचारियों की ही नियुक्ति की जाय, रेल सुरक्षा आयोग की स्थापना की जाए तथा रेल बोर्ड में सुरक्षा संचालक की नियुक्ति की जाय; (ii) बिना टिकट यात्रा को रोकथाम के लिए आवश्यक एवं प्रभावपूर्ण कदम उठाये जाएँ, (iii) भारतीय रेलों को अपने कार्यकारी व्यय में किफायत करनी चाहिए, (iv) रेल यातायात को सुरक्षित व सुविधाजनक बनाया जाय, (v) रेल परिवहन से सम्बन्धित सामान का आयात कम किया जाय तथा देश की स्वावलम्बी बनाया जाय, (vi) रेल यातायात का विस्तार किया जाय तथा रेल प्रशासन की संचालन क्षमता बढ़ायी जाय, (vii) रेलों में आधुनिकीकरण की नीति का सतर्कता से पालन किया जाय, तथा (viii) रेलों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन्हें कम किया जाय।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में रेलों का महत्व : भारतीय अर्थ-व्यवस्था में रेलों के निर्माण एवं विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसने हमारी अर्थ-

व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था पर भी काफी प्रभाव डाला है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में रेलों के योगदान का अनुमान नीचे लिखे हुए विवरण से लगाया जा सकता है।

1. कृषि में योगदान : डा० जॉनसन के मतानुसार कृषि की स्थानीय महत्व को अनेक राष्ट्रीय महत्व का विषय बना देने का श्रेय रेलों को ही है।¹ रेलों के विकास के कारण, कृषि पदार्थों का बाजार विस्तृत हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पदार्थों के मूल्यों का अन्तर कम हुआ है, परिवहन व्यय में कमी हुई है, व्यापारिक फसलों की ओर प्रवृत्ति बढ़ी है तथा नाशवान वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार बढ़ गया है। रेलों के विकास से भ्रमण की प्रेरणा से किसानों के ज्ञान में वृद्धि हुई है। उन्नत खेती के लिए उत्तम बीज, यन्त्र व उर्वरक आसीन क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं। रेलों की ही कारण बहुत से प्राचीन औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के रूप में आ बसे हैं जिसके फलस्वरूप भूमि पर जनसंख्या का भार कम हो गया है।

2. औद्योगीकरण में योगदान : रेलों के विकास के फलस्वरूप कच्चे माल को कारखाने तक तथा बने हुए माल को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा हो गयी है। इससे औद्योगीकरण को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है। आज देश के लगभग बड़े-बड़े उद्योग इन्हीं रेलों पर विरतित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें रेल परिवहन का सस्ता व सुलभ साधन उपलब्ध है।

3. व्यापार में योगदान : रेलों के विकास ने देश के आन्तरिक व बाह्य व्यापार के विस्तार में काफी योगदान दिया है। चाय, जूट, कपास, लोहा, कोयला, खालें, मैंगनीज, अभ्रक, तिनहन आदि वस्तुओं का निर्यात, रेल सुविधाओं के मिलने के कारण ही सम्भव हो सका है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतवर्ष की जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसे बनाने में रेलों का ही योगदान रहा है। मूख, कल, मटली, लकड़ी, अर्धों, आदि क्षीप्त नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं का बेतक्यापी व्यापार रेलों के कारण ही सम्भव हो सका है। इस प्रकार रेलों द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं और विघोषकद भारी एवं नाशवान वस्तुओं के बाजार के विस्तार में सहायता मिली है।

4 अन्य क्षेत्रों में योगदान : (i) रेलों के विकास से सस्ती, नियमित तथा सुदृढ डाक सेवा का प्रसार हुआ है; (ii) रेलों ने सांस्कृतिक दलों के आशान-प्रदान में साध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को शक्तिशाली बनाया है; (iii) रेलों ने स-स विदेशों, छुड़ा-छूत तथा ऊँच-नीच के भेदों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; (iv) रेल उद्योग में देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को

रोजगार मित्रता है; (v) रेलों से वैकिम व बीमा व्यवसाय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; (vi) डा० देसाई के मशानुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से देश में जो राजनैतिक संगठन घुस हुए तथा जो राजनैतिक चेतना जाग्रत हुई उसका श्रेय रेलों को ही है; (vii) ओ० मंडल बॉम के मत में श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ाने में तथा राष्ट्रीय स्तर पर इनके आवागमन में रेलों ने मदद की है, (viii) डाक्टर देसाई के मशानुसार रेलों ने भारतीय गाँवों के स्वावलम्बन तथा एकत्री अस्तित्व को समान्य करके राष्ट्रीय भावना का जन्म दिया है ।

रेलों के दुष्परिणाम (Adverse Effects)

भारतीय जर्प व्यवस्था में रेलों का योगदान सचमुच ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है । अनेक कामों को दिलाते वाला रेल परिवहन देश के लिए कुछ मानो में हानिदाय भी रहा है, यथा (i) रेलों के विकास के कारण भारत के परम्परागत व्यापारों का पतन हुआ, (ii) रेलों के विकास के कारण ही भारत कृषि प्रभाव देश रह गया, (iii) रेलों के विकास में औद्योगिक नगरी को जन्म दिया जहाँ कई प्रकार की बुराईयाँ पैदा होती हैं; (iv) रेल मार्गों के बनाने में सर्वथा भूमि का बहुत बड़ा भाग खर्च हो गया, (v) इनमें मुकुन्दमेखनी को भी बड़ाया; क्योंकि जब गांव के लोग नगरी की सड़कती में सड़कती से पहुँचने लगे और प्रायः पचास प्रायः समान्य हो गई, (vi) रेलों ने गांव के स्वावलम्बी जीवन को समाप्त कर दिया, तथा (vii) देश के विभिन्न भागों में अनेकौ शान्ति को पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी रेलों पर ही ढाला जाता है ।

दुष्परिणत बाधित दुष्परिणाम वस्तुतः रेलों के विकास में प्रत्यक्ष परिणाम नहीं कहे जा सकते । यदि रेलों का विकास सोच समझकर व देश के हित को ध्यान में रखकर किया गया होता तो रेलों के विकास के परिणाम अच्छे ही होते । सब से यह है कि रेलों ने हमारे देश में आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक क्रांति की जन्म दिया है ।

भारत के आर्थिक विकास में रेलों का विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है । वर्तमान समय में रेलों देश के विमोचित आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं । वर्तमान समय में रेल यातायात के सामने कई प्रमुख समस्याएँ पैदा हो गयी हैं, जिनका विवेचन ऊपर किया जा चुका है । इन समस्याओं और कठिनाइयों के परिणामस्वरूप ही पिछले दो वर्षों में रेलों की वित्तीय स्थिति असंतोषजनक रही है तथा बीमबी सभासदी में प्रथम बार रेलों का घाटा उठाना पड़ा है । इन रेलों के विकास एव संगठन की ओर सोच समझकर महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त हो सके, क्योंकि रेल परिवहन की उन्नति के साथ-साथ ही हमारा देश की आर्थिक उन्नति जुड़ी हुई है ।

प्रश्न

1. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 'भारत में रेल सड़क समन्वय' ।
(राज० प्र० व० टी० सी० कला, 1966, 1968)
2. देश की कृषि तथा बड़े पैमाने के उद्योगों पर भारतीय रेलों के आर्थिक प्रभाव बताइये ।
(राज० प्र० व० टी० डी० सी० कला, 1967)
3. भारतीय रेलों ने निम्नलिखित को आर्थिक दृष्टिकोण से कहा तक प्रभावित किया है —
(अ) भारतीय हस्तकलायें ।
(ब) कृषि ।
(स) बड़े पैमाने के उद्योग ।
(द) आर्थिक-व्यवस्था । (राज० प्र० व० टी० डी० सी० कला, 1966)
4. भारतीय रेलों के सामन कौन सी समस्याएँ हैं ? आप इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या-क्या सुझाव देंगे ?
5. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय रेलों की प्रगति पर विचार कीजिए और पिछले कुछ वर्षों से रेलों की आय तथा कार्य क्षमता में गिरावट के विभिन्न कारणों को समझाइए ।
(राज० टी० डी० सी० कला, प्रथम वर्ष 1971)
6. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से भारतीय रेलों के विकास और उन्नति पर संक्षेप में आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए । (Raj T D C final year, 1971)

भारत में सड़क परिवहन

(Road Transport in India)

"Road transport enables industrial enterprises to utilize hitherto untapped sources of labour and significantly contributes to the mobilization of all available resources."

—Alak Ghosh

किसी भी देश के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे कृषि का विकास हो या उद्योग धंधों का अथवा व्यापार का, सड़क परिवहन के सुनिश्चित विकास के अभाव में इनका विकास नहीं हो सकता। सुरेन्द्र भारतीय विद्वान व राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने भी सड़कों के महत्व की स्वीकार किया है तथा देश के प्रांतों के प्रमुख कर्तव्यों में से सड़कों के निर्माण को बहुत महत्वपूर्ण माना है तथा 24 से 48 पीट बोर्डों की सड़कों के निर्माण का सुझाव दिया था।¹ श्री जे० बेंचम ने सड़कों के महत्व के सम्बन्ध में लिखा है, "सड़कें किसी देश की घमनिया व धिरायें हैं जिनके द्वारा सुधार लयी रस्त का परिचलन होता है।"² रस्किन ने भी इस सम्बन्ध में वही महत्वपूर्ण बात कही है, "राष्ट्र की सारी सामाजिक व आर्थिक प्रगति सड़कों के निर्माण में विहित है।"³

सड़क परिवहन का महत्व : राष्ट्रीय समृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सड़कों का बहुत अधिक महत्व है। आज सभार के सभी सन्ध देशों में सड़क यातायात की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा इसका विकास किया जा रहा है। सड़कों के महत्व की इन अप्रतिष्ठित धीरों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं :

1. Shamasastri - Kautilya's Arthashastra, P. 46

2. "Roads are the veins and arteries of a country through which channels every improvement circulates."

3. "All social progress resolves itself into the making of good roads."

—Ruskin

1 कृषि में महत्व - ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क यातायात महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सड़कों के माध्यम से कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकता है। वे कृषि उपज को सड़कों व मंडियों में ले जा कर अच्छे मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। सड़कों के माध्यम से ही किसान को अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं सहित से प्राप्त हो जाती है। साधन के अभाव को दूर कर उन्हें खेती से आसानी से कर पूरा किया जा सकता है और इस प्रकार सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को अफ़स की स्थिति से बचाती हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन के विकास के परिणामस्वरूप कृषकों को कृषि उपज बढ़ाने के प्रयास प्राप्त होते हैं, बाजार-क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है तथा ख़ीम नष्ट होने वाले पदार्थों को भी बाजार की सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। संक्षेप में, ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है।

2 उद्योगों के विकास में महत्व - सड़कों के विकास से कारख़ानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त होता है तथा कारख़ानों का बना हुआ माल दूर-दूर तक फैले हुए उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। सड़कों के विकास से उद्योगों में कोशीलकरण और साथ ही वित्तीयकरण को भी प्रोत्साहन मिलता है। सड़कों की दूरी व सड़कें उद्योगों को भी प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि इनका बना हुआ माल सड़कों में आसानी से पहुँच जाता है।

3 व्यापार में योगदान - आज देश का आंतरिक व्यापार मुख्यतया सड़कों पर ही निर्भर करता है। पहाड़ी व पठारी इलाक़ों में, जहाँ रेल व जल यातायात की सुविधाएँ ख़तरा नहीं हैं, सड़कों का विशेष महत्व है। सड़कें बन्दरगाहों के पृष्ठ-प्रदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में माल बन्दरगाहों की ओर पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और इस प्रकार विदेशी व्यापार की वृद्धि में भी इनका बड़ी योगदान है।

4 देश की सुरक्षा में योगदान - देश की सुरक्षा व्यवस्था में भी सड़कों महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत एक विशाल देश है जिसकी तुलना एक उपमहादीप से की जा सकती है। ऐसी स्थिति में इसकी सीमाओं पर सभी जगहों पर सैनिक रक्षण सम्भव नहीं है। देश पर हमले के समय देश के सिपाहियों व अस्त्र सस्त्रों को इतनी तेज़ी से सीमाओं पर पहुँचाने का कार्य भी सड़कों प्रभावशाली ढंग से कर सकती हैं।

5 सड़कों के अन्य योगदान : (i) सड़कें देश में विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को निम्न लाती हैं तथा उनमें सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग तथा एकता की भावना भरती है, (ii) इनसे सरकार को विविध करों के रूप में

आय प्राप्त होती है। (iii) सड़कों के बनेक उपयोग हो सकते हैं और इस तरह से इनसे विविध प्रकार के लाभ उठाने जा सकते हैं। (iv) अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण व्यय कम होता है; (v) थोड़ी दूर की यात्राओं के लिए रेलों की अपेक्षा सड़कों का महत्व अधिक है, क्योंकि वे यात्राएँ मितव्ययतापूर्ण एवं सुविधापूर्ण होती हैं; (vi) सड़कों के महत्व की एक विशेष बात यह भी है कि इनसे अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा अधिक लोच पाई जाती है क्योंकि यह दर-बाजे तक की सुविधाएँ प्रदान करती हैं, (vii) परिवहन के अन्य साधनों के पूरक साधन के रूप में भी ये लाभदायक हैं, (viii) कुछ क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी पर जहाँ रेलों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, मड़क परिवहन का विद्यमान महत्व है; (ix) सड़क परिवहन अधिक फुर्तीला एवं अधिक सुविधाजनक है, (x) रेल परिवहन के अन्तर्गत एक समय में एक लाइन पर एक ही गाड़ी गुजर सकती है, जबकि सड़क पर निरन्तर मोटरें चलती रहती हैं।

संक्षेप में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रवासन, प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा अन्य किसी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयत्न को अपने पूर्ण रूप में फलीभूत होने और आगे बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन का विद्यमान महत्व है।

भारत में सड़क परिवहन का विकास भारतवर्ष में मड़क निर्माण कार्य में प्राचीन काल से ही रचि ली जाती रही है। सम्प्रति के प्रारम्भिक युग से लेकर अब तक सभी युगों में सड़कों का किसी न किसी रूप में विकास होता आया है। ब्रह्मगुप्त भौर्य, अशोक महान तथा छेरछाह जैसे शासकों के शासनकाल में सड़कों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ था लेकिन ब्रिटिश शासन काल में सड़कों के विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। लार्ड डलहौजी के समय से भारत में मड़कों के निर्माण का एक युग प्रारम्भ हुआ। डलहौजी ने रेल निर्माण की तरह मड़कों के निर्माण पर भी आवश्यक ध्यान दिया था। सन् 1850 ई० में देश में प्रथम बार सड़कों के विकास के लिए केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग खोला गया। उसी वर्ष विभिन्न प्रान्तों में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग खोले गये इनसे देश में सड़क-निर्माण को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। लेकिन इसके बाद रेलों के प्रसार से सड़क निर्माण के कार्य में कुछ रुचिगलता आने लगी। इसके पश्चात् देश में जो कुछ मड़कों का निर्माण हुआ, वह रेलों के प्रसार के परिणामस्वरूप ही हुआ। सन् 1919 में सड़कों को प्रांतीय विषय बना दिया गया। सन् 1927 में सी एम० आर० जयकर की अध्यक्षता में एक सड़क विकास समिति की स्थापना हुई जिसके सुझाव के फलस्वरूप सन् 1929 में केंद्रीय सड़क कोष बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में सड़कों का अभाव सरकार को विचार्य रूप से सटका। अतः सरकार ने दिसम्बर 1943 में विभिन्न राज्यों के मुख्य इञ्जीनियरों का नागपुर में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें १५ की

न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार एक योजना बनाई गई जो भागपुर योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष की अवधि में सड़कों के निर्माण पर कुल 448 करोड़ रुपये व्यय किए जाने से तथा कुल 4 लाख मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया जाना था। इस योजना में सड़क परिवहन के विकास के लिए दस महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे। इस योजना में देश की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर सभी प्रकार की सड़कों के सन्तुलित विकास की व्यवस्था की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि कोई भी विकसित कृषि क्षेत्र में स्थित गांव मुख्य सड़क से 5 मील से अधिक दूर न हो।

भागपुर योजना के अन्तर्गत देश में सड़कों के विस्तार के लिए एक योजना तैयार की गई, जिसमें विविध प्रकार की सड़कों की लम्बाई को बढ़ाकर निम्न प्रकार से करने का आयोजन था

भागपुर सड़क योजना¹

सड़कें	सड़कों की लम्बाई (हजार मील में)	व्यय (करोड़ ₹० में)
राष्ट्रीय सड़कें	25	50
राजकीय सड़कें	65	121
ज़िला सड़कें (बड़ी)	60	62
ज़िला सड़कें (छोटी)	100	80
ग्रामीण सड़कें	150	30
बुढ़ा काल में बिछाये हुए कार्य	—	10
पुलों का निर्माण	—	45
भूमि प्राप्ति करना	—	50
योग	400	448

सरकार ने भागपुर सम्मेलन की खलेक सिफारिशों की स्वीकार कर लिया था तथा देश के राष्ट्रीय मामलों के विकास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। इस योजना के अन्तर्गत 1944 से कार्य प्रारम्भ हो गया सन् 1947 में देश के विभाजन होने पर योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य में 3.11 लाख मील सड़कों का

1 C N Vakil Economic Consequences of Divided India, p 412-16

निर्माण भारतीय क्षेत्र में किये जाने का निश्चित किया गया जिस पर लगभग 373 करोड़ रु० की लागत का अनुमान था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सड़क परिवहन का विकास सन् 1947 ई० में पक्की सड़कों की लम्बाई 88 हजार मील तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई 1 लाख 32 हजार मील थी। सन् 1947 से 1951 तक सड़कों का विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। पक्की सड़कों की लम्बाई 98 हजार मील तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई 1 लाख 51 हजार मील तक ही 1951 हो गई थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास कार्यक्रम पर 135 करोड़ रु० खर्च किए गये। इस योजना में अतर्गत 24 हजार मील पक्की सड़कों का तथा 41 हजार मील कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया। विभिन्न स्थानों को मिलाने वाली 640 मील शुद्धता सड़कें (Road links) बनाई गयीं तथा लगभग 17 हजार मील पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई। इस प्रकार 1955-56 में भारत में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 1,22,000 मील तथा कच्ची सड़कों की कुल लम्बाई 1,95,000 मील हो गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क वातावरण के विकास पर 228 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस योजना अवधि में पक्की व कच्ची सड़कों की लम्बाई लगभग 1 लाख 44 हजार व 2 लाख 50 हजार मील हो गयी। इस योजना अवधि में विभिन्न राज्यों के सड़क कार्यक्रमों के अन्तर्गत 72 हजार मील कच्ची सड़क बनीं। द्वितीय योजना के अन्तर्गत सड़कों की कुल लम्बाई 3,94,000 मील हो गई जो नागपुर योजना के लक्ष्य से कहीं अधिक थी। इस योजनावधि में अत्यधिकित क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। सन् 1960 में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए माडल (Border Roads Development Board) बनाया गया जिसका प्रमुख कार्य इन क्षेत्रों में सड़कों के विकास को तेज करके इन तक पहुँचाने के लिए परिवहन साधनों को विकसित करना था।

सड़क विकास की हैदराबाद योजना सन् 1959 में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य इंजीनियरों का हैदराबाद में सम्मेलन हुआ जिससे 1961 से 1981 तक के लिए एक 20 वर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में 2,52,000 मील पक्की सड़कों व 4,05,000 मील कच्ची सड़कों के बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ लक्ष्य निम्नांकित थे

(1) एक विकसित व कुपि क्षेत्र का साथ पक्की सड़क से 4 मील व ग्रन्थ सड़क से 8 मील दूरी में ला जाय।

(ii) अर्द्ध विकसित क्षेत्र का गांव पक्की सड़क से 8 मील व अन्य सड़क से 3 मील की दूरी में आ जाय ।

(iii) अर्द्धविकसित तथा अर्द्धवि क्षेत्र का गांव पक्की सड़क से 12 मील व अन्य सड़क से 5 मील की दूरी में आ जाय ।

हैदराबाद योजना के नक्शों को प्राप्त कर लेने पर भारतवर्ष में प्रति 100 वर्ग मील के बोधे 52 मील सड़कें हो जायेंगी । इस योजना पर 4700 करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन - राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन के विकास पर 445 करोड़ रु० खर्च किए गये । इस योजना के अन्तर्गत 49 हजार किलोमीटर नयी पक्की सड़कें बनाई गयी । इस योजना के अन्तर्गत पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 2,82,500 किलोमीटर हुई गयी तथा कुन्बी सड़कों की लम्बाई 6,07,500 किलोमीटर हो गई । इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत कुल सड़कों की लम्बाई 8,90,000 किलोमीटर हो गई थी । इस योजना की मुख्य बात यह थी कि सड़क-विकास कार्यक्रम की 20 वर्षीय योजना को प्रथम चरण के रूप में अपनाया गया था । इस योजना के अन्तर्गत अर्द्धविकसित क्षेत्रों व सुरक्षा के लिए आवश्यक क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर बल दिया गया । सन् 1966 से 1969 के वर्षों में तीन एकवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सड़क परिवहन पर 308 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा 1969 के अन्त में पक्की एवं कुन्बी सड़कों की लम्बाई क्रमशः 3,26,000 किलोमीटर एवं 6,39,000 किलोमीटर हो गई अर्थात् सड़कों की कुल लम्बाई 9,65,000 किलोमीटर तक पहुँच गई ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन : चतुर्थ योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 860 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । इस योजनावधि में चौड़ी सड़कों की लम्बाई 3,17,000 किलोमीटर से बढ़कर 3,67,000 किलोमीटर हो जायेगी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा जिसमें राज्य सरकारें कुल निर्धारित राशि का 25 प्रतिशत भाग इन ग्रामीण सड़कों के लिए अलग से खर्चेंगी । बाजार वाले नगरों से सम्बन्धित सड़कों की योजनावधि में प्राथमिकता दी जायेगी ।

रेल व सड़क परिवहन में प्रतिस्पर्धा : भारतवर्ष में यात्री तथा माल ढोने के लिए मोटर वाहियों का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ था । युद्ध काल के पश्चात् कीर्जी मोटर गाड़ियाँ सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होने के कारण मोटर परिवहन का महत्त्व बढ़ने लगा । योरे-योरे मोटरगाड़ियों की संख्या में वृद्धि होने लगी और इनकी रेल परिवहन से प्रतिस्पर्धा होने लगी । सीसा की मन्दी की अवधि में मोटर

तथा वनों के किराओं में भारी कमी हो गई जिससे थोड़े-थोड़े शायिनों ने रेल की बजाय मोटरों द्वारा यात्रा करने प्रारम्भ कर दी। इसका रेल परिवहन पर बुरा असर पड़ा और उनकी आय घटने लगी। इन प्रकार 1929 के बाद से रेल समूहक परिवहन के बीच प्रतिस्पर्धा की समस्या उत्पन्न हो गई। नारतवर्ष में बहुत बड़े रेल परिवहन क्षेत्र एक उपयोग अल्प-प्रत्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी परिवहन के इन दोनों साधनों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। इन प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण हैं : (i) मोटर परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता है; (ii) यह अपेक्षाकृत लचीला है और घर से घर तक सुविधा प्रदान कर सकता है; (iii) इसमें मार्ग परिवर्तन की स्वतन्त्रता ब सुविधा रहती है; (iv) माल चोरी में सुरक्षा रहती है; (v) समूहक परिवहन में माल की किसी भी तमय व किसी भी स्थान पर चढ़ाया या उतारा जा सकता है; (vi) इन माध्यमों को अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है।

वस्तुतः विरोधवादी के कारण अधिकांश उपभोक्ता रेल-परिवहन की बजाय समूहक परिवहन का प्रयोग करते हैं। रेलों की इस प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सन् 1932 व 1937 में क्रमशः 'मैचल किर्कवुड समिति' (Machal Kirkwood Committee) व 'वेजवुड समिति' (Wedge-wood Committee) की नियुक्ति की गई थी। इन दोनों समितियों का मत था कि मोटर परिवहन पर बड़ा नियन्त्रण किया जाय तथा रेल यात्रा को अधिक आकर्षक बनाया जाय। इन समितियों ने रेल व समूहक परिवहन के बीच सम्बन्ध को विचारणीय की थी तथा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—(i) मोटर परिवहन पर नियन्त्रण रखकर प्रतिस्पर्धा समाप्त की जाय; (ii) मोटरों के हस्त निर्यात पर रोक लगाए; (iii) रेलों को अपनी मोटरों खरीदने का अधिकार दिया जाय; (iv) रेलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही मोटरों की लाइसेन्स दिया जाय; (v) मोटरों द्वारा माल चले जाने वाले मार्गों व माल की नीमा निर्धारित की जाय; (vi) टाइम-टेबल व किराये भी निर्धारण कर दिये जाए, तथा (vii) गन्तव्य स्थानों की मोटर व रेलों में संयोजन लाया जाय आदि।

वेजवुड समिति (Wedge-wood Committee) की सिफारिशों को मानकर 1939 में मोटर वाहनों अधिनियम (Motor-Vehicle Act, 1939) पारित किया गया जिसमें बहुत सी बहने पर नियन्त्रण स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इन अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम बार परमिट व्यवस्था की गई तथा संघीय व राज्य परिवहन आयोगों की नियुक्ति किया गया। इस अधिनियम के अनुसार मोटर वाहनों चालान के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक कर दिया गया तथा कुछ शर्तें

वाहन को अनिवार्य बना दिया गया। ये परमिट क्षेत्र विशेष के लिए ही काम में लाए जा सकते थे।

सन् 1945 में सरकार ने राज्य सरकारों को मोटर परिवहन के नियन्त्रण के लिए सिद्धान्त व व्यवहार संहिता (Code of Principles and Practice) जारी की। इस संहिता के अनुसार नाशवान व टूटने वाली वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं 7.5 मील तक की दूरी के लिए किसी भी परिवहन द्वारा ले जाई जा सकती थी लेकिन इसके अधिक दूरी के लिए सड़क परिवहन को खोली ममता प्रमिट दिया जा सकता था जब रेलों माल के जाने में असमर्थता प्रकट करें।

सन् 1950 में गठित मोटर वाहन कर जाच समिति ने रेल-सड़क समन्वय पर विचार किया तथा यह मत व्यक्त किया कि मोटर परिवहन पर जब एक कर का भार अधिक है तब तक रेल यन्त्र प्रसिद्धियों की सम्भावना नहीं रहेगी; अतः यात्रियों व माल भेजने वाले को किसी भी साधन के प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

सन् 1958 में गठित, सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति (थ्रुगैंगी समिति) ने यह विचार व्यक्त किया कि सड़क परिवहन पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। यात्री व सामान भेजने वालों को किसी भी साधन के प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि सड़क परिवहन की श्रेष्ठता एवं लाभों के कारण संचार रेल परिवहन की अनुविधाओं के कारण, सड़क परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। समिति का सुझाव था कि परिवहन के दोनों साधनों को बर्त-व्यवस्था की बढ़ती हुई परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए। इस समिति ने सड़क परिवहन प्रशासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन सुझावों के आधार पर ही अन्तर-राज्य भाषों पर सड़क परिवहन सेवाओं के विकास, समन्वय एवं नियमन के लिए सरकार ने अन्तराज्य परिवहन आयोग (Inter State Transport Commission) की स्थापना की।

सन् 1959 ई० में श्री के० सी० निघोली की अध्यक्षता में परिवहन व समन्वय समिति बनाई गयी, लेकिन श्री निघोली के स्वाम पत्र देने के कारण इस समिति ने श्री तरलोकसिंह की अध्यक्षता में कार्य करके फरवरी 1961 में प्रारम्भिक विचारों तथा जून 1966 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट देवी जिसमें परिवहन के समस्त साधनों के गहनित विकास पर जोर दिया गया तथा समन्वय सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये।

सड़क परिवहन की समस्याएं - भारतवर्ष में जनसंख्या की देखते हुए सड़क परिवहन की स्थिति असन्तोषजनक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर रेल की

अधिकांश जनता विवास करती है, सड़को के विनाश से अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। सड़क यातायात के सामने कुछ समस्याएँ हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं

(i) भारत में उत्तम सड़को का अभाव है, केवल कच्ची सड़को की ही बहूला है, (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में सड़को के विकास की समस्या, (iii) पुरानी सड़कों की मरम्मत की समस्या, (iv) रेलों से प्रतिस्पर्धा की समस्या, (v) देश में मोटरगाड़ियों की अत्यधिकता, (vi) भारत में मोटर गाड़ियों पर अत्यधिक कर लगाये जाने की समस्या, (vii) मोटर वाहन कानून के अधीन भार वाहन मध्यस्थी सीमाएँ अवैधानिक हैं, कठोररूप मोटर गाड़ियों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, (viii) मोटर मालिकों की वार्षिक प्रतिस्पर्धा, (ix) राष्ट्रीयकरण के भय की समस्या। (x) मोटर गाड़ियों में मीड-माड की समस्या, तथा (xi) बुर्पटनाओं की समस्या।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारतवर्ष में सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण की बात प्रायः उठाई जा रही है, पर इनके कुछ व दोषों का विवेचन करना उचित रहेगा।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क (i) किराये की दरों में निश्चितता हो जाने से यात्रियों को घोषण से भुवि मिलेगी, (ii) यात्रियों की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, (iii) मोटर गाड़ियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, (iv) मीड-माड की समस्या से मुक्ति मिलेगी, (v) समय की नियमितता का लाभ प्राप्त हो सकेगा, (vi) पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अन्त होगा, (vii) अलायन्सरी मार्गों में भी परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी (viii) सड़को के निर्माणकर्ता एवं प्रयोक्ताओं में द्वन्द्व समाप्त हो जायेगा (ix) राष्ट्रीय ऋण के साधन में वृद्धि होगी, (x) कर्मचारियों की दरा में सुधार एवं उनके कल्याण में वृद्धि होगी, (xi) समझौतापत्री अर्थ व्यवस्था की भार दण की अव्यवस्था अग्रसर होगी, (xii) राष्ट्रीय सुरक्षा के सूतरे के समय महत्वपूर्ण त्वाय उपलब्ध हो सकेंगी, तथा (xiii) परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय का सम्भावना बढ जायेगा।

सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क (i) निजी मोटर गाड़ियों पर विविध प्रकार की पाबन्दियाँ लग जाने के बाद राष्ट्रीयकरण अनावश्यक हो जाता है (ii) वह निजी मोटर मालिकों के प्रति अन्याय होगा क्योंकि लाभ के समय सरकार राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, जबकि प्रारम्भ में हानि उठाने उठाई है, (iii) राज्य सरकारों के पास राष्ट्रीयकरण करने के लिए पर्याप्त धन की कमी है, (iv) राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप मुआवजा देने के बजाय सरकार उगी घनराशि को अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकती है, (v) निजी चालकों में यात्रियों को रास्ते में देराने व उतारने की जो सुविधा है, वह राष्ट्रीयकरण के बाद समाप्त

हो जायेगी, (vi) सरकारी कर्मचारियों में लगन, सेवाभाव व व्यावसायिक योग्यता का सामान्यतः अभाव पाया जाता है, (vii) प्रतिस्पर्धा के अभाव में सरकार एकाधिकारी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है, (viii) सरकारी संस्थानों में सामान्यतः कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है और वे प्रायः घाटे में चलते हैं, (ix) सरकार व कर्मचारियों के बीच मालिक व मजदूर के से सम्बन्ध हो जानेसे तनाव पैदा हो सकते हैं; (x) प्रतिस्पर्धा के अभाव में हो सकता है कि सरकारी धनो में वे तमाम सुविधाएँ न मिलें जो निजी व्यासको द्वारा प्रदान की जाती हैं, आदि :

उप्युक्त विवेचन राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्षपर काफी रोशनी डालता है। वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि हम समाजवादी ममान को अपनाना चाहते हैं, राष्ट्रीयकरण उचित ही नहीं, अपितु अवश्यक है। यह बात दूसरी है कि राष्ट्रीयकरण की नीति, साधनों को देखकर अपनायी जाए।

यद्यपि भारतवर्ष में सड़क यातायात का महत्त्व बहुत अधिक है, तथापि हमारे विकास के लिये किये गये विविध प्रयत्न सीमित ही रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ग मील सड़क के लिए केवल 1/4 मील लम्बी सड़क पाई जाती है जबकि ब्रिटेन, फ्रान्स व अमेरिका में क्रमशः 3 3/4, 3 व 1 मील लम्बी सड़कें पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे 134 मोटर हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन व फ्रान्स में इसकी ती जनसंख्या के पीछे क्रमशः 41000, 28800, 27000, 15000, व 14000 मोटर हैं। हमारे देश की दो तिहाई सड़कें कच्ची हैं जो वर्ष के कई महीने बेकार हो जाती हैं। देश के आर्थिक विकास में सड़कों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उनके विकास की गम्भीर योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए तथा सड़क परिवहन को विभिन्न समस्याओं से मुक्त किया जाना चाहिये। आसाम के भूतपूर्व गवर्नर श्री कल्लगली की निम्नांकित प्रविष्टिवाणी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है।

“जहाँ तक दृष्टिकोण से रहता है, बढ़ी तक भविष्य में सड़क परिवहन का महत्त्व न ही परिवहन का कोई अन्य साधन ग्रहण करेगा और न वह उसको हटा सकेगा, चाहे वे दूसरे माध्यम कितने ही उन्नत क्यों न हो जाएँ।”

प्रश्न

1 टिप्पणी लिखिये—‘भारत में रेल सड़क समन्वय’।

(राज० प्र० व० टी० डी० सी० कला 1966, 1968)

2 भारत में सड़क यातायात के महत्त्व व विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ है ?

(राज० प्र० व० टी० डी० सी० कला, 1964)

3. भारत में सड़क यातायात के महत्व का वर्णन कीजिए। इन वर्षों में सरकार ने सड़क यातायात के विकास के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(जोधपुर वि० वि० टों डी० सी० अन्तिम वर्ष, 1964)

4. भारत में सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के लाभों व हानियों को समझाकर लिखिए।

(विक्रम वि० वि० बी० ए०, 1963)

5. भारतीय बर्ध-व्यवस्था में सड़कों का महत्व बतलाइए। पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों के विकास का वर्णन कीजिए।

(विक्रम, बी० ए० 1971)

6. रेल-सड़क समन्वय का क्या अर्थ है ? इसे प्राप्त करने के लिए भारत में क्या-क्या किया गया है ?

(बाबरा बी० ए० 1971)

भारत में जल परिवहन

(Water Transport in India)

"A country set like a pendant among the vast continent of the old world, with a coast line of over 4,000 miles and with a productiveness of numerous articles of great use, unsurpassed elsewhere, is by nature meant to be a seafaring country. Her ports are adequate in size and numbers to meet the various requirements of her products."

— S N Hajji

जल परिवहन नदियों में नाव अथवा स्टीमर तथा समुद्र में जहाज चलाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जल परिवहन दो प्रकार का है, (क) अन्तर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport) तथा (ख) समुद्री जल मार्ग।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन (Inland Water Transport)

इन मार्गों के अन्तर्गत नदियों तथा नहरों को शामिल किया जाता है जिनमें नावों तथा स्टीमरों द्वारा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाया, ले जाया जाता है। भारत में अन्तर्देशीय जल परिवहन 19वीं शताब्दी के मध्य तक गंगा, सिन्धु, ब्रह्मा, गोदावरी तथा पद्मा की कुछ नदियों में नावों द्वारा कुछ वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे तक लाई एवं लेवाई जाती थी तथा ये जलमार्गें सदकों के अभाव के कालस्वरूप काफी लोकप्रिय थे।¹

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्योत्तर काल में रेल परिवहन के विस्तार के परिणामस्वरूप तथा नदियों में जल का निचोड़ के लिए बने हुए उपयोग के कारण जल-परिवहन का महत्व घट गया। लेकिन वर्तमान समय में भी जनम, पश्चिमी बंगाल, व बिहार में नावों के जल परिवहन का महत्व है। देश के कुछ अन्य राज्य जहाँ अन्तर्देशीय जल परिवहन का महत्व है, वे हैं उड़ीसा, केरल, आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु।

1. Dr D H Buchanan The Development of Capitalist Enterprise in India p 176

असम एवं कश्मिर के बीच कुल 25 लाख टन यातायात (Traffic) में से धान भी आधा भाग जल परिवहन द्वारा ले जाया जाता है जबकि शेष में रेल एवं सड़क साजीदार है।

गत वर्ष में नियोजन काळ के प्रारम्भिक काल में जातिरिक्त जल परिवहन की उपेक्षा की गई। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर 1 करोड़ रुपए से भी कम धनराशि व्यय की गई। सन् 1959 में प्रथम बार अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर भारत के आन्तरिक जल मार्गों के विनाश की व्यापक योजनाएं बनाई गईं। इस प्रतिवेदन के आधार पर ही तृतीय पंचवर्षीय योजना में साठ लाख करोड़ रुपए की लागत का विकास कार्यक्रम तैयार किया गया। इस योजना काल में गंगा-ब्रह्म पुत्र डेल्टा के द्वारा गुन्वरबन में एक प्रयोगात्मक नाव खींचने की परियोजना (Pilot Towing Project) सम्पन्नित किया गया। सुन्दरबन तथा ब्रह्मपुत्र के लिए ड्रग्स तथा लॉन्चिंग खरीदन का कार्यक्रम रखा गया। केरल में पश्चिमी तटोंय नहर का विस्तार किया गया तथा उडुपी में तालझाड़ा व केन्द्र पावा। नहरों के सुधार के कार्यक्रम रखे गए ताकि पाराझीप बन्दरगाह से कर्णै कोह के निर्यात में सुविधा रहे।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना की अवधि में केवल चुनी हुई निश्चित परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के महत्व में वृद्धि के कारण भारतवर्ष अन्तर्देशीय जल परिवहन के महत्व में 19वीं शताब्दी के मध्य में जो कमी आई है, उसके कई कारण हैं। उनमें से प्रमुख कारण हैं, (i) नावों की गति का मोटर अथवा रेल की गति से अत्यधिक धीमा होना, (ii) नावों की यात्रा का अपेक्षाकृत अधिक खर्चीला होना; (iii) जल मार्गों के उपयोग का प्रकृति की दया पर निर्भर रहना; (iv) जल मार्ग सम्बन्धी सुविधाओं का सर्वत्र उपलब्ध न हो पाना, (v) जल मार्ग में जान व माल की अत्यधिक जोखिम का पाया जाना।

भारतीय जहाज शाली (Indian Shipping)

भारत के लिए, जिसकी तटवर्ती सीमा 4160 मील है।¹ और जहां में वस्तुओं का बहुत बड़ी मात्रा में, विदेशी व्यापार होता है, जहाजरानी का विशेष महत्व है। जहाजरानी के विकास में भारतीय शक्तियों, की अत्यन्त कम रहे। परन्तु वे तथा विदेशी विनिमय में काफी वक्त हो सकती है जिसे हमें विदेशी कंपनियों को देना पड़ता है। देश की रक्षा में भी जहाजरानी का प्रमुख योग्य होना है क्योंकि सड़क

1. पन्द्रहवां डीप लम्बू को सम्मिलित करके।

के समय व्यापारिक जहाज (Mercantile marine) रक्षा की दूसरी शक्ति का कार्य करते हैं। जहाजों द्वारा मण्डियों का विस्तार होता है तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास को बल मिलता है। स्वयं एक व्यापारभूत उद्योग होने के नाते, जहाज निर्माण उद्योग जनक उद्योगों को जन्म देता है। विदेशी व्यापार के भुगतान समुद्रन की सुधारने में भी जहाजरानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसके विकास में विदेशी कम्पनियों को करोड़ों का दिया जाने वाला भाड़ा बच जाता है।

भारतीय जहाजरानी का इतिहास और परम्परायें अत्यन्त पुरानी हैं। भारत में सवियों पहले ही जहाजरानी और जहाज निर्माण उद्योग का जन्म हो चुका था और यहाँ के व्यापारियों ने अपनी प्रतिभा व कर्मठता का परिचय दिया था। यहाँ के नाविकों ने अपना कौशल व उत्साह दिखाया था तथा विदेशी को सदेश पहुँचाने वाले धर्म-प्रचारकों ने अपना उत्साह दिखाया था। भारतीय बौद्ध विविध देशों को भारतीय वस्तुओं का निर्यात और वहाँ की वस्तुओं का भारत में आयात करते थे। अपनी जहाजरानी के कारण भारत का सम्बन्ध-व रोम, मिस्र, चीन तथा अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ था। सदियों तक समुद्री मार्गों पर भारत का प्रभुत्व बना रहा और सते अपने पूर्वी समुद्री मार्गों पर गर्व का अनुभव होता था।

डा० रामाधुमुद मुसुर्की के शब्दों में, “प्राचीन भारतीय सभ्यता सत्तर के कोने कोने में इसकिएँ पहुँच सकी क्योंकि भारत के पास विशाल समुद्री तटिका थी। हमारे सभ्यताशील जन-जहाजी उद्योग के कारण ही सत्तर के कोने हमारे धर्म एवं सभ्यता में प्रभावित हुए।”

भारतीय जहाजरानी का पतन - भारत में अंग्रेजों के आने के बाद यह स्थिति बदल गयी और भारतीय जहाजरानी उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा। भारतीय जहाजरानी के पतन के कई कारण थे जो इस प्रकार हैं -

(i) इस्पात के जहाजों का प्रचलन होना, (ii) भारतीय जहाजों की बीमारी गति, (iii) ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्व नीति, (iv) अंग्रेज व्यापारियों की ईर्ष्या, (v) विदेशी जहाजों कम्पनियों द्वारा भाड़े में खियाएत तथा भुगतान की सरल प्रणाली द्वारा प्रतिस्पर्धा करना, (vi) किराये भाड़े की कटौती आदि।

उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप अन्तीमवी शताब्दी के मध्य से भारतीय जहाजरानी उद्योग का पतन प्रारम्भ हो गया था और आज्ञादो मिलने के समय भारत की कुल जहाजों शक्ति विश्व की जहाजों शक्ति का केवल 2 प्रतिशत भाग ही रह गई थी। भारतीय जहाजरानी के पतन के लिए ब्रिटिश सरकार की नीति ही मुख्यतः जिम्मेदार थी। गाँधीजी ने ठीक ही कहा है, “भारतीय जहाजरानी को समाप्त होना पड़ा ताकि ब्रिटिश जहाजरानी फल-फूल सके।”

भारत में आधुनिक जहाजरानी का प्रारम्भ : भारतवर्ष में आधुनिक जहाजरानी का प्रारम्भ वास्तव में 1919 में हुआ जबकि श्री बालचन्द्र होराचन्द्र के प्रयत्नों से निम्बिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी की स्थापना की गई। यद्यपि इससे पूर्व 1893 में टाटा द्वारा तथा 1906 में चिदम्बरन पिल्लई द्वारा जहाज कम्पनियाँ प्रारम्भ की गई थी लेकिन वे प्रतिस्पर्द्धा के आगे ठहर न सकी थी। 1921 में सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने ब्रिटिश इण्डियन स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार इसे भारतीय तट पर 75 हजार टन के जहाज चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1933 में समझौते की शर्तों में कुछ सुधार किया गया फलस्वरूप इसे भारत व बर्मा के बीच मवारियों के होने का अधिकार भी प्राप्त हो गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय जहाजो कम्पनियों को अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करने का सुप्रसन्न प्राप्त हुआ और इन्होंने ग्यारह तथा छन्दन तक अपनी जहाजी सेवाएं प्रारम्भ कर दी। युद्धोत्तर काल में भारत सरकार ने श्री पी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक जल परिवहन नीति समिति (Shipping Policy Committee) की नियुक्ति की। जहाजो परिवहन के इतिहास पर दिवशी करते हुए समिति ने कहा, "भारतीय जहाजरानी का इतिहास वचन भंग, पूर्ण न किए जाने वाले आश्वासन एवं अवसरों की उपेक्षा की दुःख कहानी है।"¹

इस समिति द्वारा 1947 में प्रेषित प्रतिवेदन में जहाजरानी के विकास में निम्नांकित सुझाव दिए गए : (i) 5-7 वर्षों में 2 मिलियन टन भार का लक्ष्य प्राप्त किया जाय; (ii) भारत का तटीय व्यापार का समस्त भाग भारतीय जहाजरानी के क्षेत्र में आ जाय, तथा (iii) पड़ोसी देशों के व्यापार का 75 प्रतिशत, समुद्र पर व्यापार का 50 प्रतिशत तथा अर्धनी आदि समुद्र देशों के साथ हुए व्यापार का 30 प्रतिशत भाग, भारतीय जहाजरानी के अधिकार में आ जाय; (iv) इस समिति में भारतीय स्वामित्व, नियन्त्रण व प्रबन्ध में एक सुदृढ़ व्यापारिक जहाजी बंदे के विकास का भी सुझाव दिया; (v) बन्दरगाहों की व्यवस्था परिवहन बिम गों से हटाकर वाणिज्य विभाग में करने का भी सुझाव दिया गया।

स्वतन्त्र भार में जहाजरानी : सन् 1947 ई० में भारत स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात् भारत सरकार ने भारतीय जहाजरानी के विकास की नीति अपनाई। इस समय सरकार के सामने जहाजरानी उद्यम के विभाग से सम्बन्धित कई कठिनाइयों सामने आई जिन, (i) पहली कठिनाई जहाजरानी उद्योग में लगे हुई विदेशी कम्पनियों

1. 'History of Indian Shipping is a tragic tale of broken promises, unredeemed assurances and neglected opportunities.'

ये जो इस क्षेत्र में पहले ही कार्य कर रही थी, (ii) जहाजों को प्राप्त करने और चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता थी तथा पूँजीपति इस क्षेत्र में आने से कतराते थे तथा (iii) देश में जहाज निर्माण की क्षमता नहीं थी। हमें अपनी आवश्यकता के सभी जहाज विदेशों से खरीदने पड़ते थे जिससे काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती थी।

इन कठिनाइयों के कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षों में देश में जहाजरानी का विकास छोटे पैमाने पर हुआ लेकिन इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति होती गयी। भारत सरकार ने जहाजरानी उद्योग के विकास के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई कदम उठाये। सन् 1950 ई० में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि टटीय व्यापार केवल भारतीय जहाजों द्वारा ही किया जाय। सन् 1950 तथा 1956 में क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी जहाजरानी निगम स्थापित किये गये। जहाजरानी के विकास के लिए 2 अक्टूबर 1961 ई० को ये दोनों निगम मिलाकर भारत का जहाजरानी निगम बनाया गया।

सन् 1960 ई० में भारत सरकार ने मुक्त साइन जहाजरानी कम्पनी के 80% अंश खरीद लिए। अब यह कम्पनी भी सरकारी प्रतिष्ठान के रूप में कार्य कर रही है।

सन् 1952 ई० में देश में जहाज निर्माण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालपत्तनम का जहाज कारखाना के लिया गया। भारतीय जहाजरानी के इन भार को बढ़ाने के लिए देशी जहाजरानी कम्पनियों को जहाज खरीदने के लिए रियायती दर पर ऋण देने की योजना भी चालू की।

व्यापारिक जहाजों के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न विनियमों को मिलाकर सन् 1958 ई० में एक नया व्यापारिक जहाज अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के पारित होने के परिणामस्वरूप भारतीय जहाजों की रजिस्ट्री अब भारत में होने लगी है। इसी समय राष्ट्रीय जहाजरानी मंडल की स्थापना की गयी तथा भारतीय जहाजों की सहायता के लिए जहाजरानी विकास कोष बनाया गया। इस अवधि में भारत सरकार ने जहाजरानियों के अधिकारियों और नाविकों के प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ाईं। नाविकों की मलाई के लिए मलाई मंडल तथा व्यापारिक जहाजरानी निगम मंडल, आटा ज्वार मंडल, समुद्री जहाज माध्यम, जहाजरानी समन्वय समिति आदि की स्थापना भी की गयी।

पञ्चवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ में जहाजरानी सन् 1947 ई० में मारच के पाठ केवल 1 लाख 92 हजार टन भार के जहाज थे। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के प्रारम्भ में अर्थात् 1951 में भारतीय जहाजों का टन भार 3 लाख 90,707 हो

गया था। इसमें से 2,17,202 हजार टन भार के जहाज तटीय व्यापार में लगे थे तथा शेष 1,73,505 टन भार के जहाज विदेशी व्यापार में लगे थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना: प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2,75,000 टन के जहाज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था तथा इसके लिए 36 करोड़ रु० की धन राशि निर्धारित की गयी थी। पुराने तथा बालू में न आ सकने वाले जहाजों को रद्द ठहराने के लिए 60 हजार टन भार की व्यवस्था करने के बाद मार्च 1956 में 6 लाख टन भार के जहाज प्राप्त करने का लक्ष्य था। मार्च 1956 में वस्तुतः हमारे पास 4 लाख 10 हजार टन के जहाज चालू हाथ में तथा 1 लाख 20 हजार टन भार के जहाज निर्माणाधीन थे। इस प्रकार प्रथम योजना का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया था।

इस योजनावधि में हम यह कर 15.7 करोड़ रुपये व्यय हुआ। योजनावधि में दिया गया वाशिंगटन के समझौते मुक्त 6,00,707 टन (GRT) के जहाज थे जिनमें 3,12,202 तटीय व्यापार; 2,83,505 टन विदेशी व्यापार तथा 5 हजार टन के हँकर जहाज थे। इस योजनावधि में 5500 रेजिस्ट्र, 143 मेरिच इजीनियर तथा 268 मैकेनिकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। बन्दरगाहों एवं पोतालयों के विकास पर योजनावधि में 27.6 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना: इस योजनावधि में वाणिज्य परिवहन के विकास के निश्चित उद्देश्य थे, (i) देश के तटीय व्यापार का प्रधानमध्य विकास करना ताकि इन क्षेत्रों में रेल परिवहन का भार कुछ कम हो सके; (ii) भारतीय विदेशी व्यापार के लिए जहाजों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, (iii) निजी जहाजी कंपनियों को उचित वित्तीय सहायता द्वारा प्रोत्साहन देना तथा प्रशिक्षण केंद्रों में इनके कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना; तथा (iv) रेल तथा पेट्रोल से जाने वाले जहाजों का निर्माण करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 46 करोड़ 25 लाख रु० की लागत से 3 लाख 90 हजार टन भार के जहाज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पुराने व नई जहाजों के लिए 90 हजार टन भार की व्यवस्था करने के बाद, दूसरी योजनाकाल में जहाजरानी में 3 लाख टन वृद्धि का लक्ष्य था। मार्च 1961 में वस्तुतः 1 लाख 57 हजार टन भार के जहाज चालू हाथ में थे और 93 हजार टन भार के जहाज या तो निर्माणाधीन थे या प्राप्त किए जा रहे थे। इस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग 50 हजार टन भार अधिक जहाज थे। इस योजनावधि के अंत में 2,92,000 टन के जहाज तटीय व्यापार में तथा 5,65,000 टन के जहाज विदेशी व्यापार में लगे हुए थे। इस योजनाकाल में जहाजरानी के विकास में 22.7 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

तृतीय पंचवर्षीय योजना : तृतीय पंचवर्षीय योजना में 35 करोड़ रु० की लागत से 3 लाख 75 हजार टन भार के लिए जहाज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इस आवोजित धन राशि में से आधा भाष्यजनिक क्षेत्र में तथा निष्ठी क्षेत्र में खर्च किया जाता था। इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख 81 हजार टन भार के नये जहाज प्राप्त करने तथा 1 लाख 94 हजार टन भार के पुराने जहाज बदले जाने थे। तीसरी योजना के अन्त में भारतीय जहाजरानी में 10 लाख 84 हजार टन भार के जहाज करने का लक्ष्य था, यद्यपि यह लक्ष्य राष्ट्रीय जहाजगर्नी मण्डल द्वारा निर्धारित 14 लाख टन भार से नही कम था। योजना के अन्त में भारतीय जहाजरानी में 1९ लाख 40 हजार टन भार के जहाज हो गये थे और इस प्रकार सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा किया गया। इस काल में और भी अधिक प्रगति होती यदि प्रस्तावित 1 लाख 94 हजार टन भार के स्थान पर 2 लाख 54 हजार टन भार के जहाज रही न किन्ते बने होते।

तृतीय योजना काल में 11 भारी सामान ढोने वाले जहाज, 4 समुद्र पार जाने वाले टैंकर प्राप्त किए गए जिससे आटा, अन्न, पदार्थ तथा पेट्रोल होने में सुविधा हो। इस योजना काल में वस्तुतः जहाजरानी पर 47 करोड़ रुपया व्यय हुआ। तृतीय योजना काल में लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि के कारण थे, (1) स्थिति सुगमता की दृष्टि पर जहाज का खरीदा जाना, (2) पुराने जहाजों का सस्ते भावों में प्राप्त किया जाना, (3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड की अपना का पूरा उपयोग किया जाना आदि।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)¹ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नए जहाजों को खरीदने के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना के अन्त तक जहाजरानी का टन भार लगभग 35 लाख टन हो जायेगा। देश के विदेशी व्यापार में जहाजरानी का अंश लगभग 40 प्रतिशत हो जायेगा। इस योजना-पक्ष में बन्दरगाहों की परिवहन क्षमता 550 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 900 लाख टन हो जायेगी।

प्रशिक्षण जहाज 'टफरिन' के स्थान पर नया जहाज खरीदने, छोटे छोटे जहाजों को खरीदने के लिए अधिक महावृत्ता देने, प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार करने तथा नाविकों के कल्याण कार्य पर 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। इस योजना में बन्दरगाहों के विकास पर भी धन दिया गया है और इस पर योजनाकाल में 180 करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा

वर्तमान स्थिति : जनवरी 1972 में भारतवर्ष में जहाजों की संख्या 256 थी जिनकी क्षमता 25 लाख सकल टन थी ।

भारतवर्ष में इस समय थ्रिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के अतिरिक्त 35 अन्य भारतीय जहाजी कंपनियां हैं । भारतीय जहाज प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं । इस समय भारतवर्ष में जहाज बनाने के दो कारखाने हैं जो विद्यासायनम् व कोचीम में स्थित हैं । इजोनियरी व नाविकों की प्रशिक्षण देने की भी कई संस्थाएँ हैं, यथा, 'रफारन' सेरीस इंजीनियरिंग कालेज, कलकत्ता, नाटिकल एण्ड इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई, आदि । इस समय देश में 8 बड़े बन्दरगाह हैं—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विद्यासायनम्, कोचीम, कांडला मारमा गोवा व प्रवीप । इन बड़े बन्दरगाहों के अतिरिक्त देश में लगभग 225 छोटे बन्दरगाह भी हैं ।

समस्याएँ भारतीय जहाजरानों ने स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् यद्यपि महत्वपूर्ण प्रगति की है, तथापि इसके विकास के बाग में कई कठिनाइयाँ या समस्याएँ हैं जो इस प्रकार हैं

1 जहाजों क्षमता का अभाव भारत जहाजरानी के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है जैसा कि निम्नतालिका से स्पष्ट है—

विश्व की जहाजी क्षमति (जुलाई, 1968)¹

देश	क्षमता लाख टनों में	कुल टन प्रतिशत
1 लाइबेरिया	257	19.25
2 ग्रेट ब्रिटेन	219	17.29
3 संयुक्त राज्य अमेरिका	197	16.13
4 जावा	197	16.13
5 जापान	196	16.09
6 ग्रीस	74	5.82
7 इटली	66	5.41
8 पश्चिमी जर्मनी	65	5.36
9 फ्रांस	58	4.99
10 नीदरलैंड्स	53	4.71
11 भारत	20	1.00
अन्य देश	539	47.82
योग	1941	100.00

1 स्रोत : इकोनॉमिक टाइम्स, 17, अगस्त, 1967

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय जहाजों समता विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। अतः इसे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

■ विदेशी प्रतिस्पर्द्धा भारत को जहाजरानी के क्षेत्र में ब्रिटेन, अमेरिका तथा जापान से तीव्र प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ा रहा है। अभी कुछ वर्षों से जर्मनी तथा इटली ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है और भारतीय जहाजरानी से प्रतिस्पर्द्धा करने लगे हैं। सरकार को चाहिए कि इस प्रतिस्पर्द्धा से भारतीय जहाजरानी को बचाए। भारतीय तटीय व्यापार का शत प्रतिशत तथा विदेशी व्यापार का 50% भाग भारतीय जहाजरानी को मिलना ही चाहिए। सरकार को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

3 रेल परिवहन से प्रतिस्पर्द्धा भारतीय रेलें भी तटीय क्षेत्रों में जहाजरानी से तीव्र प्रतिस्पर्द्धा कर रही हैं। तटवर्ती सामुद्रिक मार्गों द्वारा कबाड, सीमेंट, तेल, चावल, तिन्हन आदि की लाने से जाने में अपेक्षाकृत कम व्यय पड़ता है। लेकिन भारतीय रेलें भी इन वस्तुओं को कम भाड की दर पर ले जाने व लाने के लिए तैयार नहीं हैं जिससे इन दोनों परिवहन साधनों में अनुचित प्रतिस्पर्द्धा होती है तथा जहाजरानी को अनावश्यक क्षति उठानी पड़ती है। 1955 में Rail Sea Co-ordination Committee, को कि इस दोनों परिवहन साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गठित की गई थी, भी इस दिशा में अधिक सफल नहीं हो सकी है। इस समस्या का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए।

4 जहाजों की ऊँची लागत विश्व में जहाजों की भाँति बृद्धि होने के फलस्वरूप जहाँ जहाँ के मरम्मत में अत्यधिक बृद्धि हो गई है। 1945 की तुलना में इस समय ब्रिटेन में 36% जहाजों मरुप अव गए हैं। भारत में तो यह बृद्धि 20% तक पहुँच गई है। सरकार को चाहिए कि वह जहाज निर्माण कार्य को अधिकाधिक आर्थिक गह्रायता प्रदान करे।

5 अब समस्याएँ उपर्युक्त वर्णित समस्याओं के अतिरिक्त भारतीय जहाजरानी को कुछ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, वे हैं —

(i) माल बाहक, तेल बाहक एवं यात्री जहाजों की अब भी बहुत कमी है और हमें प्रतिवर्ष भाड के रूप में करोड़ों रुपये व्यय करने पड़ते हैं, (ii) तटीय जहाजों की सख्या निरन्तर कम होती जा रही है, (iii) भारत में जहाज निर्माण की गति का अत्यन्त मन्द होना, (iv) विदेशों से जहाज खरीदने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का अभाव, (v) देश के समुद्रगट की विचालता के अनुरूप प्राकृतिक बन्दरगाहों का न होना, (vi) स्वदेशी जहाजों कम्पनियों के पास यथोचित पूँजी का अभाव, (vii) दन्दरवाहों पर काम करने वाले श्रमिकों द्वारा दिये दिन हड़ताल, (viii) पाला सम्बन्धी अभाव, (ix) बढ़ते हुए संचालन व्यय की समस्या, तथा (x)

भारतीय जहाजों की भाड़ा दरों का कम होना; (ख) जहाजों की संरम्भों की समुचित व्यवस्था का देश में न होना ।

भारतीय जहाजरानी के तीव्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि उपर्युक्त समस्याओं का निराकरण किया जाय ।

योजना आयोग में प्रारम्भ से ही जहाजरानी के महत्व पर बल दिया है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश के लिए जिसका समुद्र-सड़ बहुत लम्बा है तथा समुद्री मार्गों से बड़े पैमाने का व्यापार होता है, जहाजरानी का विशेष महत्व है । सरकार ने भी बड़-बड़ महसूस कर लिया है कि जहाजरानी के विकास एवं विस्तार की प्रापमिकता देश आवश्यक है, क्योंकि देश के विदेशी व्यापार में जहाजी भाड़े के रूप में विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि व्यय की जाती है, वह बच सकेगी । पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि समुद्र पर अधिकार रखने वाले ही व्यापार पर अधिकार रखते हैं और जिनकी मुट्ठी में विश्व का व्यापार होता है, वही के पास समृद्धि आती है और अन्तोनगरवा वही विश्व का नेतृत्व करते हैं । प० नेहरू की यह उत्कट अभिलाषा थी कि भारत का झण्डा फहराते हुए, भारतीय जहाज समुद्र-पार दूरदर्शी देशों के माथे पर जाएं । हमें इन दिशा में निरन्तर बढ़ते रहने का संकल्प करना चाहिए, ताकि देश को समुद्र बनाने तथा गौरव दिलाने में भारतीय जहाजरानी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके ।

प्रश्न

1 भारतवर्ष में जहाजरानी के विकास का विवेचन कीजिए तथा इसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिये ।

2 भारतीय जहाजरानी के विकास की बाधाओं की चर्चा करते हुये, तब वहाँ में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की विवेचना कीजिये ।

3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ष में जहाजरानी के विकास के लिए पदावधि महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं ? संक्षेप में विवरण दीजिए ।

4 देश की वर्तमान व्यवस्था में जहाजरानी के महत्व की विवेचना कीजिए । देश में जहाजरानी के विकास की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सुलझाने के लिये सुझाव प्रस्तुत कीजिए ।

5 भारत में जल-परिवहन का महत्व समझाइए और इसके विस्तार के लिए अपनाए गए उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।

(वि. क्रम वि० वि० की० ए० 1965)

भारत में वायु परिवहन

(Air Transport in India)

“मनुष्य को उपलब्ध विभिन्न साधनों में से वायु परिवहन सबसे नवीनतम, सबसे अधिक विकासशील, सबसे अधिक चुनौती देने वाला तथा हमारे आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सबसे अधिक क्रांति लाने वाला है।”

— फॉयर व विलियम्स

भारतवर्ष के प्राचीन घमं ग्रन्थों में अनेक ऐसे वृत्तांत पढ़ने में आते हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि वायुमार्ग भारतवर्ष में अति प्राचीन काल में भी उपयोग में आते थे। वर्तमान वायु यातायात की घटना यातायात के इतिहास में नवीनतम घटना है। वायु यातायात के विकास में यातायात के इतिहास में क्रांति का बीड़ा और हमसे एक बड़े युग का सूत्रपात होता है। मानव की परिश्रम की भांति गगन में उड़ने की इच्छा की पूर्ति, वायु यातायात के मादुं भाव से पूरी हो गयी है। श्री फॉयर एवं विलियम्स के शब्दों में, ‘मनुष्य को उपलब्ध विभिन्न साधनों में से वायु परिवहन सबसे नवीनतम सबसे अधिक विकासशील, सबसे अधिक चुनौती देने वाला एवं हमारे आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन में सबसे अधिक क्रांति लाने वाला है।’

भारत में वायु परिवहन का विकास

भारतवर्ष में सन् 1911 ई० में प्रयोगात्मक उड़ान प्रारम्भ हुई थी जबकि बम्बई व कराची के बीच प्रथम बार उड़ान की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु विमान परिवहन का वास्तविक उपयोग सन् 1920 से किया गया जब सरकार द्वारा कुछ हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। सन् 1927 ई० में वायविक विमान परिवहन विभाग स्थापित किया गया और कई उड़दयन क्लब (Flying clubs) स्थापित किये गये। विमान चालकों, प्राविधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 1928 में दिल्ली, ललकता, बम्बई तथा कराची में उड़दयन क्लब शारम्भ किए गए। इसी वर्ष इम्पीरियल एयरवेज के द्वारा भारत तथा लंदन के बीच नियमित रूप से हवाई परिवहन प्रारम्भ हुआ।

सन् 1932 में टाटा एयरवेज ने इलाहाबाद, कलकत्ता व कोलम्बो के मध्य तथा बाद में कराची व मद्रास के बीच जाल्वारिक वायु सेवाएं प्रारम्भ कर दीं। सन् 1938 में एम्पायर एयर मेल स्कीम प्रारम्भ की गई, लेकिन युद्ध के छिड़ जाने के फलस्वरूप इसे स्थगित कर दिया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय तथा इसके बाद नागरिक विमान परिवहन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सन् 1946 ई० में भारत सरकार ने विमान परिवहन नीति की घोषणा की। इस घोषणा में निजी कंपनियों को सह्यता देने का आश्वासन दिया गया। इसी वर्ष वायु परिवहन लाइसेंस बोर्ड बनाया गया। यह निर्धारित कर दिया गया कि लाइसेंस लेते समय बोर्ड निर्धारित बातों का ध्यान रखेगा।

(क) कंपनियों की वित्तीय स्थिरता; (ख) कार्य प्रचालन की दक्षता के स्तरों (Standards) की उचित देखभाल, तथा (ग) कंपनी की वायु परिवहन सेवाओं को जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की सामर्थ्य।

बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त थी कि लाइसेंस प्राप्त वायु कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले किराए और भाड़े की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित करे। फलस्वरूप इस समय बहुत-सी निजी वायु-परिवहन कंपनियां बन गयीं। इन कंपनियों की अधिकता के कारण इन्हें घाटा हुआ।

विदेशी वायु सेवाओं के लिए भारत सरकार ने टाटा कंपनी के सहयोग पर एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की स्थापना की। स्थापना के समय यह तय किया गया था कि इस कंपनी की हिस्सा पूजा में सरकार का अंश 49 प्रतिशत रहेगा और यह विकल्प रहेगा कि सरकार इसमें वृद्धि करके इस 51 प्रतिशत करदे। सरकार 5 वर्ष के समय तक होने वाली हानि की क्षति पूर्ति करेगी, जिसकी अदायगी भावी लाभों में से की जा सकेगी।

स्वतंत्रता के पश्चात् वायु परिवहन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वायु परिवहन के विषय में लिए आवश्यक कदम उठाये। सन् 1950 ई० में श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में एक वायु परिवहन जांच समिति बनाई गई। वायु परिवहन के क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए समिति ने सभी कंपनियों को सम्मिलित कर चार बड़ी कंपनियों के संगठन की सिफारिश की। इस सिफारिश की अन्य सिफारिशें थी, (i) अवधि समाप्त होने पर अस्थाई लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाए, (ii) भाड़ की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाए, (iii) सरकारी आर्थिक सहायता 1952 तक जारी रखी जाए, (iv) वायुयान कंपनियों के लाभ पर सरकार नियन्त्रण रखे, तथा (v) अगले 5 वर्षों तक वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण न किया जाए।

2 वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में तर्क

(1) पक्ष में तर्क वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में वायु परिवहन समिति ने जो-जो विचार प्रस्तुत किए थे, वे हैं (i) एकाकी संचालन से उपलब्ध भाषनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा, (ii) सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीयकरण आवश्यक है, (iii) राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप नागरिक उड्डयन विभाग व भारतीय वायु सेवा के प्रतिष्ठित कार्य में सामंजस्य स्थापित हो जायेगा; (iv) जनता को सरती व अच्छी सेवाएँ प्राप्त होगी, (v) अन्तर्राष्ट्रीय कानून व प्रतिस्पर्धा का सामना अच्छी तरह से किया जा सकेगा, (vi) सेवाओं में दुर्घटनाएँ समाप्त हो जाने से मित-व्ययता होगी, तथा (vii) यह उद्योग सरकारी सहायता के बिना चल नहीं सकता, अतः सरकार ही इसे चलाये तो अच्छा रहे।

(ii) विपक्ष में तर्क वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण में विपक्ष में निम्नांकित तर्क दिए गये थे (i) सभी देशों की सरकारें वायु परिवहन को आर्थिक सहायता देती हैं, अतः भारत को भी ऐसा चाहिए, (ii) सरकारी प्रबन्ध में लोचनीयता पाई जाती है, (iii) प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों के अभाव में सरकार के हाथों कठिनाई होगी, (iv) सन् 1948 की औद्योगिक नीति से वायु परिवहन को 10 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के लिए छोड़ा गया था, अब इस समय का राष्ट्रीयकरण का कार्य सरकार द्वारा अपने वाकडे से विमुक्त होना था, तथा (v) राष्ट्रीयकरण करने पर सरकार को भुनावना देना पड़ेगा, जिससे सरकार के आर्थिक वास्तव्य में दृष्टि हो जायेगी।

सरकार ने कुछ समय तक के लिए राष्ट्रीयकरण को स्थगित कर दिया। परन्तु चूँकि निजी कम्पनियाँ स्वेच्छा से विलयन के लिए तैयार न थी, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीयकरण करना उचित समझा। मार्च 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर लिया तथा इनके संचालन के लिए, वायु परिवहन निगम अधिनियम के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स कॉर्पोरेशन (Indian Air-Lines Corporation) व एयर इंडिया इन्टरनेशनल कॉर्पोरेशन (Air-India International Corporation) की स्थापना की गई, जिन्होंने 1 अगस्त 1953 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

3 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत वायु परिवहन

प्रथम पंचवर्षीय योजना : प्रथम पंचवर्षीय योजना में वायु परिवहन पर ₹ 5 करोड़ २० लाख करने का प्रावधान था, लेकिन योजना काल में केवल 7 24 करोड़ रुपये ही व्यय किये जा सके। योजनावधि में दुवाई लड़हो आधुनिकीकरण, निर्माण,

सधार सुविधाओं एवं परिवहन उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया गया। योजनावधि में 9 हवाई अड्डे बनाए गए तथा पुराने हवाई अड्डों को सुधारा गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस योजना काल में 30.53 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान था। इसमें से 16 करोड़ रुपये इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन पर तथा 14.53 करोड़ रुपये एयर इण्डिया इन्टरनेशनल पर व्यय किये जाने की व्यवस्था थी। योजनावधि में 8 नए हवाई अड्डों के निर्माण की भी व्यवस्था की गई थी। इस योजनाकाल में माँग के अनुसार सुविधाएं बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। योजनावधि में सामान्य, दमदम एवं पाल्म हवाई अड्डों का विकास किया गया तथा उन्हें जेट वायुयानों के सेवा-योग्य बनाया गया। इस योजनाकाल में देश के सभी नगरों को वायु सेवाओं द्वारा मिला दिया गया। योजनावधि में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया। योजनावधि में 15.9 करोड़ रुपये वायु परिवहन पर वस्तुतः व्यय किए गए।

तृतीय पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय नागरिक उड्डयन के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 25.5 करोड़ रुपये नागरिक उड्डयन के विविध कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने थे। इस धनराशि में से 18.50 करोड़ रुपये भवन व हवाई अड्डों के निर्माण पर, 5.00 करोड़ रु० विमान हार, एयर व्यवस्था पर, 1.00 करोड़ रु० हवाई मार्ग व अड्डों पर, 0.84 करोड़ रु० प्रशिक्षण दल व उपकरणों पर तथा 0.16 करोड़ रु० धनरेपण व विज्ञान पर व्यय किए गए थे। इस योजना काल में वायु परिवहन पर वस्तुतः 47 करोड़ रु० व्यय हुए।

1966-69 की अवधि में क्रियान्वित की गई तीन एक-एक वर्षीय योजनाओं पर कुल लगभग 60 करोड़ रु० व्यय किए गए। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया की क्षमता बढ़ कर क्रमशः 224 मिलियन टन किलोमीटर तथा 437 मिलियन टन किलोमीटर तक पहुंच गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-70) चतुर्थ योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में असेमित वायु परिवहन के विकास के लिए 202 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि में से नागरिक वायु-परिवहन विभाग पर 72 करोड़ रु०, इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन पर 53 करोड़ रु०, एयर इण्डिया पर 60 करोड़ रु० तथा मिडिलीरोरॉर्गेनाइज्ड विभाग पर 15 करोड़ रु० व्यय किए जाएंगे। इस योजनावधि में दिल्ली, कलकत्ता, गद्वांस तथा बम्बई-इन चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में सुविधाएं बढ़ाई जायेंगी ताकि वे जूम्रो जेट जैसे भारी तथा अधिक लम्बा चलने वाले विमानों की उपयोगिता के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकें। योजनावधि में एयर इण्डिया 4 बोइंग 747 जेट प्राप्त करेगा। इस योजना के अन्त तक इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की

क्षमता 392 मिलियन टन किलोमीटर तथा एयर इण्डिया की क्षमता 990 मिलियन टन किलोमीटर तक पहुँच जाने की सम्भावना है।

वर्तमान स्थिति : इस समय दोनों परिवहन विभागों की व्यवस्था सतोपजनक है। भारत में इस समय वायु परिवहन प्रतिक्षण के लिए 23 स्थानों पर उड़ान चल रही हैं। हवाई अड्डों की संख्या इस समय भारतवर्ष में 85 हैं, जिनमें से शांता-मन, वसुदेव व पालम अन्तर्राष्ट्रीय अड्डे हैं। भारत में वायुयान तथा मध्यमविवर सामान ढालने की कई कंपनियाँ काम कर रही हैं, जैसे, हिन्दुस्तान एयर लाइन्स, नगरा, वायुयान उत्पादक डिपो, कानपुर; वायुयान ढालने बनाने की कंपनी; नासिक; एयरो इन्जिन कंपनी, कोरापुट (उड़ीसा) तथा विद्युत पदार्थ उत्पादक कंपनी, हैदराबाद। 'निग' वायुयान के उत्पादन का कार्य भी इसी सहयोग में प्रारम्भ हो गया है। इस समय इण्डियन एयरलाइन्स के पास 7 कारबेल जेट, 14 वाइकास्ट, 3 स्काइमास्टर, 15 कोनर फ़ोर्गशिप, 19 डेकोटा तथा 3 एच० एल० 748 विमान हैं, जिनके माध्यम से भारत के प्रायः सभी बड़े नगर वायु सेवा द्वारा जुड़े हुए हैं। एयर इण्डिया के पास इस समय 9 बोइंग जेट विमान हैं, जिनके द्वारा 24 देशों को भारत से वायु सेवाओं प्रदान की जा रही हैं। सन् 1970 में भारतीय विमानों ने कुल मिलाकर 7.23 करोड़ किलोमीटर लम्बी उड़ानें पूरी की तथा वे 28.93 लाख यात्री तथा 547.5 किलोग्राम माल एक ठाक लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को गए।

4 वायु परिवहन का महत्व -

वायु परिवहन का परिवहन के माध्यमों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके महत्व को निम्नांकित विवरण से समझा जा सकता है।

1. **भौगोलिक क्षेत्र में महत्व -** सीमा नष्ट होने वाली वस्तुएँ जैसे अन्ध, मछली, दूध तथा बहुमूल्य वस्तुओं जैसे हीरा, जवाहरात आदि वायु परिवहन द्वारा भेजना सुविधाजनक व निरापद रहता है। समाचार-पत्र-विकास भी वायु यातायात के द्वारा सीमातिथीय एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा सकती है। इस प्रकार नावान, मूलवान, कोमल व कठोर वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने में वायु परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है।

2. **कृषि क्षेत्र में महत्व -** वर्तमान समय में कृषि विकास के क्षेत्र में भी वायु परिवहन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। टिडियों तथा फसल के अन्य कीटारणुओं को नष्ट करने के लिए भी दवा छिड़कने के काम में वायुयानों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हवाई जहाजों द्वारा एक निश्चित ऊँचाई पर एक रासायनिक द्रव्य से जाकर उम्रे बादलों पर फेंकने से आगे न बढ़ कर वहीं पर दबा कर देते हैं। अमेरिका में कपास की चुनाई से पूर्व हवाई जहाज से सेत में एक रासायनिक द्रव्य डाल देते हैं, जिससे पत्तों अठ काते हैं तथा कपास की चुनाई सरल हो जाती है।

3. देश की सुरक्षा के क्षेत्र में महत्व : विदेशी आक्रमण के दौरान वायु परिवहन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से सेना की टुकड़ियों को प्रभावित क्षेत्रों में बहुत कम समय में भेजा जा सकता है। यही तही वायु फोटोग्राफी द्वारा खत्रू सेना तथा उनके गुप्त सैनिक बड़ों का पता लगाया जा सकता है। सीमान्त क्षेत्रों पर निरोक्षण रखने में भी वायुयान उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

4 आसानीसे महत्व . भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में प्रायः बाढ़ ला जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ये क्षेत्र देश के अन्य भागों से अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों को आवश्यक वस्तुएं केवल विमानों द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है। अोजन, वस्त्र तथा दवाइयों के पंखों को विमान द्वारा बिना रुक-रुक कर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की रक्षा की जा सकती है। सहायक बीमारियों की स्थिति में दवाइयां तथा चिकित्सक वीडा-ग्रस्त क्षेत्रों में भेजे जा सकते हैं। आधुनिक समय में शक्ति प्रसूत क्षेत्रों से जनता को बचाने में हेलीकॉप्टर बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं।

5 औद्योगिक नगरों की भीड़-भाड़ की समस्या का निराकरण . वायु परिवहन के विकसित हो जाने पर नगरों में भीड़-भाड़ की समस्या को हल किया जा सकता है। उन्नत देशों में विविध उद्योगों के बास-वास ही अधिको व अन्य कर्मचारियों को बसाना आवश्यक नहीं है क्योंकि हवाई परिवहन द्वारा वे प्रतिदिन औद्योगिक नगर आ जा सकते हैं।

6 अन्य महत्व (i) वायु परिवहन सांस्कृतिक एकता व सम्पर्क बनाने में योगदान देता है, (ii) इसके कृतु विज्ञान की सहायता मिलती है; (iii) वायु फोटोग्राफी से विविध कार्यों के लिए विस्तृत क्षेत्रों का सर्वेक्षण सुविधाजनक हो जाता है; (iv) वायु परिवहन में सड़कें, रेलों अथवा अन्य मार्गों की मांग घटती-निर्माण में व्यय नहीं लगता; (v) अत्यन्त व्यस्त रहने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों व राजनीतिज्ञों के लिए यह माध्यम एवं संबंधित साधन है क्योंकि यह अत्यन्त दुरुपयोगी साधन है; (vi) जन स्वास्थ्य पर अच्छर व अन्य विषयों की टांगुओं में प्रभावों को वायुयानों द्वारा देवाई छिड़क कर समाप्त किया जा सकता है; (vii) डाक लाने व ले जाने में वायु परिवहन का विषय महत्व है; (viii) मूल्यवान वस्तुओं को वायुयान द्वारा से आकर चोरी, धक्का आदि के खतरे से बचि पाई जा सकती है।

वायु परिवहन की सीमाएं - वायु परिवहन की सीमाएं निम्नलिखित हैं:—

- (1) इस साधन द्वारा सीमित यात्रा व नवन भर माल के बोया जा सकता है।
- (2) संचालन व्यय अधिक होने के कारण इसका भाड़ा बहुत अधिक होता है, इसलिए न तो सामान्य यात्री ही इस ओर आकर्षित होता है और न ही लोग वायु-मान द्वारा सामान ही भेजते हैं।

(3) काहरे व बुरे मौसम पर वायु परिवहन अब तक विजय नहीं प्राप्त कर सका है।

(4) रात्रि उड़ान (Night Flying) आज भी किसीराज्य में है व अधिकतर दुर्घटनाएँ रात्रि यात्राओं से ही होती हैं।

5 वायु परिवहन की समस्याएँ

भारतवर्ष में वायु परिवहन के विकास के मार्ग में अनेक समस्याएँ हैं, यथा—
(i) भारतवर्ष की अब भी अधिकांश विमानों की प्राप्ति के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, (ii) भारतीय वायु परिवहन को विदेशी कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ये कम्पनियाँ भाड़ की दूरी में रियायतें तथा विलम्बित भुगतान की सुविधायें देकर यात्रियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं, (iii) वायु परिवहन की सेवाएँ पेट्रोल की ऊँची लागतों के कारण अपेक्षाकृत बहुत महंगी पड़ती हैं, (iv) वायु दुर्घटनाओं के कलस्वरूप प्रायः जन जन की अपार क्षति हो जाती है, (v) प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ अपेक्षाकृत कम हैं, (vi) भारतीय वायु परिवहन निगमों के पदाधिकारियों की व्यावसायिक योग्यता अपेक्षाकृत कम है, (vii) तकनीकी प्रगति के जमाने में पुराने विमानों का उचित उपयोग नहीं हो पाता, (viii) भारत में सवारी वाले जहाज तो पर्याप्त हैं, पर भार वाहक विमानों की कमी है, (ix) भारतीय हवाई अड्डे आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न नहीं हैं (x) दक्ष व योग्य विमान चालकों व कर्मचारियों की कमी है।

6 सुझाव

भारतीय वायु परिवहन की विविध समस्याओं का धीर्घातिधीर्घ निराकरण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव महत्वपूर्ण हैं (i) उच्चकोटि के नवीन हवाई अड्डों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिनसे वे सभी सुविधायें प्राप्त हो सकें, जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पाई जाती हैं, (ii) कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का विकास किया जाना चाहिए तथा नये प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए, (iii) भार वाहक विमानों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, (iv) वायु परिवहन की दुर्घटनाओं की कम करने के प्रयत्न करने चाहिए, (v) पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न बीचकारिकता कम की जानी चाहिए, (vi) पराइन व ग्लाइडिंग क्लबों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, (vii) वायु परिवहन सम्बन्धी जोष कार्य किये जाने चाहिए, (viii) विमान यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उपयुक्त सफाया किये जाने चाहिए तथा देश में अनियमित सेवाओं (Non Scheduled) के लिए पर्याप्त सज हैं, अब और अनुसूचित सेवाओं की प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और देश के उन जगहों को वायु मार्गों द्वारा मिलाया जाना चाहिए, जो अब तक वायु मार्गों से नहीं मिलते जा सके हैं।

वायु परिवहन का वार्षिक महत्व तो है ही, राजनैतिक एवं सामरिक महत्व भी है। अतः इसके विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। वायु परिवहन की अनेकानेक समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन क्षेत्र में स्थान बनाने के लिए भारतीय वायु परिवहन को आवश्यक बढम उठाने चाहिए। सतोप का विषय है कि भारत सरकार अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग है और इसके विकास के लिए आवश्यक बढम उठा रही है :

प्रश्न

1. भारतवर्ष में वायु परिवहन के महत्व तथा विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए। (राज० प्रथम वर्ष टी० डी० सी० कक्षा 1965 and 1968)

2. भारतवर्ष में वायु परिवहन के पिछड़ेपन के कारण बताइये। इसके विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

3. भारतवर्ष में कौन-कौन से आधुनिक परिवहन हैं? संक्षेप में इनके सापेक्षिक लाभ व हानियों की विवेचना कीजिए। (राज० बी० ए० 1962)

भारत में औद्योगिक श्रम

(Industrial Labour in India)

"The alleged inefficiency of the Indian labour is largely a myth granting more or less identical conditions of work, wages efficiency of management and of the mechanical equipment of the factory, the efficiency of the Indian labour generally is no less than that of workers in most other countries"

—Rege Committee

श्रम उत्पत्ति का सत्रिय एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि उत्पत्ति की कोई भी क्रिया इसके बिना संचालित नहीं की जा सकती। इसका महत्व ससार के सभी देशों में खीर सभी कालों में रहा है। वास्तव में आज वे ही देश आर्थिक समृद्धि के क्षिपार पर पहुँच पाये हैं, जिन्होंने देश की परिस्थितियों ■ अनुकूल, अपनी श्रम शक्ति का यथोचित उपयोग किया है। आने वाला भविष्य भी उन्हीं देशों में सम्पन्नता का प्रसार करेगा जो अपनी श्रम शक्ति का समुचित उपयोग करेंगे। औद्योगिक क्रान्ति के बाद से श्रम शक्ति का संगठित शक्ति औद्योगिक क्रान्ति की ही शक्ति है।

भारत में औद्योगिक श्रम का उदय

औद्योगिक श्रम का उदय औद्योगिक विकास के साथ-साथ हुआ। इंग्लैंड में सत्रारतवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में संगठित उद्योगों का प्रादुर्भाव होने पर औद्योगिक श्रम के एक नये सामाजिक वर्ग का विकास प्रारम्भ हुआ। भारत में यो तो उद्योग शब्द अति प्राचीन काल से अपनी गुणवत्ता के लिए ससार भर में ख्याति रखते थे, लेकिन सामुहिक युग के बड़ एवं संगठित उद्योगों का विकास उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार भारत में संगठित श्रम शक्ति का उद्भव बी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही मानना चाहिए। हमारे देश का औद्योगिकरण अपेक्षाकृत धीमी गति से हुआ है। फलस्वरूप यहाँ भी श्रम शक्ति या औद्योगिक श्रम का विकास एवं विस्तार भी धीमे गति से ही हुआ है। सन् 1971 की जनगणना के

अनुसार देश की कुल धनशक्ति 28 करोड़ थी। कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 70 लाख थी। भारत एक कृषि-प्रधान देश रहा है। जब भी कृषि हो यहां के लोगों का मुख्य धंधा है और अधिकांश लोग (लगभग तीन चौथाई) कृषि से ही अपना खेनमार पाते हैं। परन्तु देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा आर्थिक सतुल्य प्राप्त करने के लिये उत्तरोत्तर औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है जिससे धन शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि जा रही है। भारतवर्ष में औद्योगीकरण के फलस्वरूप प्राचीन कुटीर उद्योगों का पतन होता गया तथा उनमें लगे हुये कारीगर औद्योगिक धमिक के रूप में कार्य करने को बाध्य होते गये हैं। यही कारण है कि भारत में औद्योगिक धन शक्ति में धीरे-धीरे वृद्धि होती चली गई। उत्तरोत्तर वृद्धि का अनुमान निम्नांकित तालिका से चलता है —

धन शक्ति में वृद्धि

वर्ष	धमिक सहाय (लाख में)
1900	5 0
1920	14 0
1940	22 0
1950	29 6
1961	33 0
1964	45 6
1965	47 0
1966	47 0
1266	70 0

भारतीय श्रमिकों की विशेषताएँ (Characteristics of Indian Labour)

धमिक एक सामाजिक प्राणी है। अन्य सामाजिक प्राणियों की भाँति वह भी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। भारतीय समाज की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। धमिक वर्ग इनसे बचूँ नहीं रह सका है, अतः यहां के धमिकों में भी कुछ विशेषताएँ पाई जाती हैं जो अन्य देशों के धमिकों में सामान्यतया नहीं पाई जाती। संक्षेप में ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

I. प्रवासी प्रवृत्ति (Migratory Character) भारतीय धमिक मुख्यतया गांवों से नगरों की ओर जाते हैं। उनका गांव व कृषि से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध अवश्य बना रहता है। अधिकतर धमिक औद्योगिक नगरों के पास के गांवों

के होते हैं। इसमें प्रवासी प्रवृत्ति कई कारणों से पाई जाती है, यथा : (i) भारतीय श्रमिकों का कार्य स्थायी होने के कारण उन्हें कभी भी कार्य से अलग किया जा सकता है। विवश होकर उन्हें गांव से सम्बन्ध बनाए रखना पड़ता है; (ii) भारतीय उद्योग-धंधों में कार्य की दयाएं असन्तोषजनक हैं, रहने की बच्छी व्यवस्था नहीं है तथा रहन-सहन का व्यय अधिक है। इसलिए आव-हुवा बदलने के लिए अनाज, धी, सब्जी आदि चीजों से काने के लिए तथा अपने आश्रितों की सम्भालने के लिए प्रायः यह गांव को खोर खाता रहना है और जमकर कार्य नहीं करता; (iii) श्रमिकों के मित्र, भातेदार आदि गांवों में ही रहते हैं, अतः उन्हें गांवों की ओर प्रायः जाना ही पड़ता है; (iv) फसलों को बीने तथा काटने के समय भी श्रमिक गांव चले जाते हैं; तथा तो यह है कि यदि उसे उसके गांव में ही उचित रोजगार सम्बन्धी सुविधाएं मिल जाय तो सम्भवतः अधिकांश श्रमिक कारखानों में काम करना छोड़ कर गांवों को चले जायेंगे।¹ भारतवर्ष में श्रमिक सहर जाने के लिए आकर्षित ही नहीं वरन् बाध्य हो जाते हैं।² प्रवासी प्रवृत्ति में कई दोष हैं, जैसे (i) श्रमिकों के जीवन में स्थिरता नहीं आ पाता; (ii) उनकी कार्यकुशलता कम हो जाती है, (iii) बेकारी की समस्या जटिल हो जाती है; (iv) मासिक व श्रमिक के बीच सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता; (v) धन संग्रहण की उन्नति में बाधा पड़ती है; (vi) श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तथा (vii) श्रमिकों की आर्थिक हानि होती है।

2 अनुपस्थिति में अधिकता (Greater Absenteeism) : भारतवर्ष में श्रमिकों को काम से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके कई कारण हैं जैसे—श्रमिकों का गिरा हुआ स्वास्थ्य, बुरी आदतों का होना, प्रदूषक कारखानों का दुर्गन्धहार, गृह-वातावरण का भय, रात्रि की पालियों में काम होना, काम के प्रति निष्ठा का अभाव, अंग कटाव व सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की कमी, आवास व्यवस्था का अभाव, धार्मिक व सामाजिक उत्सव, मुकदमेबाजी तथा प्रामी से सम्बन्धी आदि। इन सब परिस्थितियों के परिणामस्वरूप श्रमिक प्रायः अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है। यह अनुपस्थिति न तो श्रमिकों के हित में होती है और न उत्पादक के हित

1 S. K. Bose Some aspects of Indian Economic Development Vol II P 131

2. "Few industrial workers would remain in industry if they could secure sufficient food and clothing in the village, they are pushed not pulled to the city."

—Report of the Royal Commission on Labour in India p. 16

में।¹ इससे कई चुकसान होते हैं, जैसे (i) कर्मनुसार मजदूरी मिलने के कारण काम से अनुपस्थित रहने के कारण श्रमिकों की आर्थिक हानि होती है, (ii) इससे अनुशासनहीनता बढ़ती है; (iii) उत्पादन कम हो जाता है; (iv) श्रमिकों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है; तथा (v) पालकों व श्रमिकों के बीच मधुर सम्बन्ध बंधा नहीं हो पाता।

3. विभिन्नता अथवा असमानता (Heterogeneity) : भारतवर्ष के औद्योगिक क्षेत्रों में देश के विभिन्न भागों से काम करने वाले श्रमिक आते हैं। इनमें रहन-सहन, धर्म, जाति, भाषा-बोली, वैद्यभूषा, खानपान आदि में विभिन्नता एवं असमानता पाई जाती है। प्रांतीय एवं क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण वे न तो आपस में नज़दीक आ पाते हैं और न ही एक दूसरे की कठिनाइयों व आवश्यकताओं की समझ पाते हैं। वे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में सहयोग भी नहीं कर पाते। इस विशेषता का परिणाम यह होता है कि मजदूरी की मोल-भाव की क्षमता (Bargaining Capacity) कम हो जाती है तथा इसका असर उनकी मजदूरी पर पड़ता है।

4 शिक्षा का अभाव एवं अज्ञानता (Illiteracy and Ignorance) : भारतीय श्रमिक अशिक्षित और अज्ञानी हैं। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों से कारखानों में काम करने के लिए आते हैं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है इसलिए अधिकांश श्रमिक भी अशिक्षित रह जाते हैं। ग्रामीण वातावरण एवं परिस्थितियों में पले होने के कारण वे भोले-भाले एवं सरल प्रकृति के होते हैं। इस अशिक्षा एवं अज्ञानता के फलस्वरूप भारतीय श्रमिक न तो अपनी समस्याओं की सही भाँति समझ पाते हैं और न ही उनका निराकरण कर पाते हैं। उन्हें कानून द्वारा दिये गए सम्बन्धी व सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जो सुविचार मिलनी चाहिए, उनके बारे में भी वे अनभिज्ञ रहते हैं। इसी कारण हमारे देश के श्रमिक अपने हितों की रक्षा भी नहीं कर पाते।

5 संगठन का अभाव (Lack of Organisation) : भारतीय श्रमिक पारिवार्य वेष्टों के श्रमिकों की भाँति सुसंगठित नहीं हैं। भारतीय श्रम सभ्य अभी भी अपनी संगठन आवश्यकता में है। उचित नेतृत्व का अभाव, दल-मत राजनीति, सभी

1. 'The loss due to absenteeism is two-fold. Firstly, there is a direct loss to the workers, because the irregularity in attendance reduces their income when "no work no pay" is the general rule. The loss to the employers is still greater as both discipline and efficiency suffer.'

—Labour Investigation Committee Reports, p.100

की अनेकता, मालिकों का विरोध, सरकार की उदासीनता, श्रमिकों की अशिक्षा, सहयोग की कमी, धनान्धता, काम के घटो की अधिकता, श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति, आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप भारतीय श्रमिक अब भी असंगठित हैं। इस संगठन के अभाव के कारण श्रमिक के मोल-भाव करने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे उसे आर्थिक हानि होती है। संगठन के हट न होने के कारण ही वे शोषण से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाते। इसी संगठन की कमी का कारण उनकी व्यापकित मांगों पर भी कोई ध्यान नहीं देता।

6. भाग्यवादिता एवं रूढ़िवादिता (Fatalism and Conservatism) : भारतीय श्रमिक रूढ़िवादी, प्रथाओं एवं परम्पराओं से जकड़ा हुआ है। भाग्यवादी होने के कारण वे अकर्मण्य एवं आलस्य होते जाते हैं। धार्मिक अंधविश्वास उनके प्रगति के कार्य में बाधक है। वे रूढ़िवादी एवं भाग्यवादी होने के कारण सत्तोषी बन गये हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान के प्रति उदासीन हो गये हैं।

7. अकार्यकुशलता (Inefficiency) : भारतीय श्रमिकों की अल्प उन्नत-शील देशों की अपेक्षा कार्यकुशलता कम है। उनकी कार्यकुशलता की कमी जन्मजात न होकर परिस्थितियों के प्रतिकूलता के परिणामस्वरूप है। भारत की गर्म जलवायु, कम वेतन, निम्न रहन-सहन का स्तर, रूढ़िवादिता, सामान्य व तकनीकी शिक्षा का अभाव, दोषपूर्ण भ्रम संगठन, उत्तरदायित्वहीनता, परिव्रहीनता, कार्य करने की प्रतिकूल दशाएँ, मशीनों का पुरानी होना आदि अनेक कारण हैं, जिनसे भारतीय श्रमिक की कार्यकुशलता पर बुरा असर पड़ता है। कार्यकुशलता के अभाव के कारण ही श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति प्रायः शोचनीय रहती है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय श्रमिक जिस तन्मयता से काम करते हैं, यह सराहनीय है।

8. निम्न जीवन स्तर (Low standard of living) : भारतीय श्रमिक प्रायः काल से सावकाल तक कठिन परिश्रम करता है। एग्री-छोटी का पसीना एक बर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती, न उसे भर पेट न पौष्टिक भोजन मिल पाता है और न पहनने के लिये पर्याप्त वस्त्र। रहने के लिए गन्दी बस्तियाँ में छोटी-छोटी कोठरियाँ होती हैं, जिनमें दिन को भी अंधेरा छाया रहता है। सड़क के साम्य ही किसी देश के श्रमिकों की स्थिति इससे अधिक दयनीय हो। निम्न जीवन-स्तर उसकी कार्यक्षमता पर बुरा असर डालती है और परिणामस्वरूप वह और भी निर्धनता की ओर बढ़ जाता है।

9. ग्रामीण प्रकृति (Rural Nature) : यद्यपि भारतीय श्रमिक अब नगरीय में विद्यमान होते हैं, तथापि प्रकृति से वह अभी भी देहमती है। उसका ध्यान-मान,

रहन-सहन, बोल चाल सभी आसीन हैं। विविध त्वाँहारे व सामाजिक उत्सवों में वे अपने ही लोगोत जाते हैं और लोक-मूल्यों में भाग लेते हैं।

10 औद्योगिक श्रमिकों को की अपेक्षाकृत कमो (Relatively Small Number of Industrial Workers) - भारतवर्ष की कुल जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। भारत कृषि-प्रधान देश है। उद्योगों का विकास अभी पूरी तरह नहीं हो पाने का कारण बड़े उद्योगों में रूगे हुये श्रमिकों का अनुपात आज भी कार्यशील जनसंख्या के 4 या 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

11 गतिशीलता का अभाव (Lack of Mobility) - भारतीय श्रमिक एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में अपने की असमर्थ पाता है। परिवर्तनमूलक उसे उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता। अल्प स्थान में प्रेम, अविद्या, भाषा सम्बंधी मिल्मता, निर्धनता, जातीयता के बाधनों की कमी आदि कारण प्रेम की गतिशीलता को घटाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय श्रमिकों की जो दशा कम थी, वह आज नहीं है और जो आज है, वह सम्भवतः कम नहीं होगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय श्रमिकों की दशा में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। आधा है कि वर्षों 5-10 वर्षों में भारतीय श्रमिक समार के किसी भी देश के अधिक के समान उन्नतिशील हो जायेगा।

भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता

श्रमिक की कार्य-कुशलता से आशय यह है कि एक श्रमिक में एक निश्चित समय में एक विशेष प्रकार की वस्तु का कितना उत्पादन कितनी बख्शी तरह कर लेने की क्षमता है। कार्य-क्षमता मापक (relative) होती है, भारतीय श्रमिक के बारे में प्रायः यह कहा जाता है कि वह अपेक्षाकृत कम कार्यकुशल है। सर अलेक्जेंडर मैक-रॉबर्ट (Sir Alexander Mac Robert) के अनुसार एक अमेरिकी श्रमिक, एक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा 3.5 गुना अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। सी. क्लेमेंट सिम्पसन (Clement Simpson) के अनुसार लंदनशहर के सूती वस्त्र उद्योग का एक श्रमिक भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग में काम करने वाले 2.67 श्रमिकों की कार्य-कुशलता के बराबर है। दाह्री ग्राम बायोग के अनुसार कोयला खान उद्योग में प्रति श्रमिक गोपेले का वार्षिक उत्पादन अमेरिका में 780 टन, इंग्लैंड में 250 टन, ट्रान्सवाल में 426 टन है, जबकि भारत में केवल 131 टन ही है। ऐसा कहा जाता है कि जापान के शिपबे के कारखाने में एक श्रमिक 240 तकियों, इंग्लैंड में 540 से 600 तकियों तथा अमेरिका में 1120 तकियों की देखभाल करता है, लेकिन भारत एक मजदूर केवल 180 तकियों की देखभाल करता है। एक रुपया मूलने

जाता दृगसैंड में 4 से 6 खड्डियों, अमेरिका में 9 खड्डियों लेकिन भारत में 2 केवल खड्डियों की देखभाल करता है ।

उद्युपक्ष विवेचन से पता चलता है कि भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता इंग्लैंड अथवा अमेरिका के श्रमिक की तुलना में बहुत कम है । पर कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इन बातों को नहीं मानते । सर वागस हॉलैंड ने भारतीय श्रमिकों की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । इनके मतानुसार भारतीय श्रमिक किसी भी उद्योग में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है । द्वितीय विश्व युद्धकाल में आये हुए, प्रेसी शिफ्ट मशीन के अनुसार, ' पैमठ सेट प्रतिदिन जाने वाले भारतीय श्रमिक अघेरे वातावरण में अच्छी मशीनों का उत्पादन कर रहे थे । गम्बई के फायरस्टोन के कारखाने में भारतीय श्रमिक डेट्राइट (Detroit) स्थित फायरस्टोन के कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के बराबर काम करते थे । टाटा लोहे एवं इस्पात के कारखाने में प्रति श्रमिक की उत्पादन क्षमता पिट्सबर्ग के कारखानों से कम नहीं है ।'' इस प्रकार हम देखते हैं कि योरोप तथा अमेरिका की तुलना में भारतीय श्रमिक अकुशल नहीं हैं । और यदि यह मान भी लिया जाय कि भारतीय श्रमिक अपेक्षाकृत अकुशल हैं तो यह उनका दोष नहीं है बरस इसके लिए वातावरण, प्रशिक्षण की अकुशलता भी असा उत्तरदायी है ।

भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता कम होने के कारण भारतीय श्रमिक जन्मजात अकुशल नहीं है । केवल परिस्थितिया ही उसे अकुशल बनाती हैं । ये परिस्थितिया का कारण दो श्रमिकों को अकार्यक्षुल बनाती हैं, संक्षेप में निम्नो-कित हैं ।

1. प्रतिकूल जलवायु : भारतीय जलवायु गर्म एवं शुष्क है । अधिक गर्मी से श्रमिक शीघ्र ही थकावत महसूस करने लगता है । गर्मजलवायु श्रमिक की कार्य-क्षमता को भी कम कर देती है ।

2. कार्य के घंटों की अधिकता : भारतीय श्रमिक को प्रतिकूल जलवायु में अधिक घण्टे काम करना पड़ता है । योरोप के अनेक देशों में जलवायु की अनुकूलता के बावजूब भी श्रमिकों से अधिक घण्टे काम नहीं लिया जाता । अधिक घण्टी तक काम करते-करते श्रमिक थक कर चूर हो जाता है और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है ।

3. मजदूरी प्रवृत्ति : भारतीय श्रमिक एक स्थान या एक कारखाने में बस कर काम नहीं करते जिससे उनकी कार्यक्षमता घट जाती है । (इस सम्बन्ध में पहले प्रकाश टाला जा चुका है ।)

4. रहन-सहन का मोबा इतर : भारतीय श्रमिक के रहन-सहन का स्तर अत्यन्त निम्न है । उसे पीस्टिक पदाथों की कील कहे, साधारण भोजन भी भर पेट

नहीं मिल पाता। स्वाभाविक है कि दुबल श्रमिक की कार्यक्षमता अपेक्षाकृत कम होती है।

5 शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं की कमी भारतीय श्रमिकों में सामान्य व तकनीकी, दोनों प्रकार की शिक्षा का अभाव पाया जाता है। वे नई-नई मशीनों के प्रयोग तथा नई-नई विधियों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। शिक्षा के अभाव में उनकी कुशलता का विकास नहीं होता।

6 प्रतिकूल कार्य की दशाएँ भारतवर्ष के अधिकांश कारखानों में सर्वाँ, योशनी, तापक्रम, साफ पानी, आराम आदि की सुविधाएँ सतोषजनक नहीं हैं। इन प्रतिकूल दशाओं में कार्य करने से श्रमिक का स्वास्थ्य गिर जाता है और कार्यक्षमता भी कम हो जाती है।

7 प्रदूषण की अकृच्छता भारतीय उद्योगपतियों में शायद दूरदर्शिता का अभाव पाया जाता है। वे श्रमिकों से काम लेना नहीं जानते। अपना ध्वज ध्वज भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता। श्रमिकों में वे उत्तरदायित्व की भावना भरने में राक्षस की असमर्थ रहे हैं। कर्मस्वरूप श्रमिकों की कार्यक्षमता कम है।

8 कल्याणकारी कार्यों का अभाव श्रमिकों के आवास तथा कल्याण के क्षेत्र में बहुत कम काम किया गया है। कल्याणकारी कार्यों से श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ती है और इनके अभाव में कार्यक्षमता का ह्रास होता है।

9 महत्वाकांक्षा का अभाव : महत्वाकांक्षी होने पर व्यक्ति में काम के प्रति रुचि पैदा होती है तथा वह कुशलतापूर्वक कार्य करता है। भारतीय श्रमिक दुर्भाग्यवश भाग्यवादी है। उसमें महत्वाकांक्षा का अभाव है। कर्मस्वरूप उसकी कार्यक्षमता भी कम है।

10 प्रतिकूल की स्वल्पता : भारतीय श्रमिक की उसकी मेहनत का न्यायोचित पुरस्कार नहीं मिलता। कारखानों में काम करने वाले कुछ उच्च पदाधिकारी हजारों रुपय मासिक वेतन पाते हैं, जबकि श्रमिक कठो मेहनत के बावजूद भी क्षयमान वेतन पाते हैं। अतः उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। प्रतिकूल की स्वल्पता एक ओर उनका काम के प्रति उत्साह कम करती है तथा दूसरी ओर उन्हें उचित रहन सहन का स्तर प्रदान नहीं करती।

11 अन्य कारण : उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त कई और कारण भी हैं जो श्रमिकों की कार्यक्षमता घटाते हैं, जैसे श्रमिकों की गहन-प्रशिक्षण, दोषपूर्ण भर्ती प्रणाली, पुरानी व चिथो-पिटी मशीनों का प्रयोग, आदि।

सुझाव : इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता परिस्थिति-बल गिरी हुई है। यदि इन परिस्थितियों में सुधार कर दिया जाय, तो भारतीय

श्रमिक की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये ये सुझाव महत्वपूर्ण हैं (i) भोजन, वस्त्र, निवास तथा कार्यक्षमता को बढ़ाने वाली अन्य सुविधाओं की व्यवस्था, (ii) सामान्य व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, (iii) कारखानों में कार्य करने की दशाओं में तथा आन्तरिक प्रबन्ध में आमूल परिवर्तन करके इन्हें सुधारना, (iv) नये व अच्छे औजारों व मशीनों की व्यवस्था, (v) सामाजिक सुरक्षा व श्रम वल्याज कार्यों का विस्तार, (vi) कार्य का उचित विभाजन एवं कामों की अवधि में कमी, (vii) भर्तों के शोषों को दूर करने की व्यवस्था, (viii) श्रमिकों की श्रमप्रसन्नता को सुपाठ करना, (ix) श्रमिकों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, (x) श्रमिकों का नैतिक व शैक्षिक विकास करना, तथा (xi) श्रमिक उत्पादन करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करना जैसे उत्पादन के अनुसार मजदूरी आदि।

जैसा कि पहले कहा चुका है श्रमिकों की कार्यक्षमता में कमी जन्मजात नहीं है। अतः परिस्थितियों की प्रतिकूलता से कारण है। समयानुसार सुधार पाकर जब ये परिस्थितियाँ अनुकूल हो जायेंगी, श्रमिकों की कार्यक्षमता भी बढ़ जायेगी। इस सम्बन्ध में श्रम-लाभ मण्डल के विस्फोटित विचार उल्लेखनीय हैं, 'जो भी प्रशासित प्रमाण पत्र है तथा अपनी जाँच के दौरान इस विषय पर आवे हैं कि भारतीय श्रमिक की तथाकथित अकार्यक्षमता एक कोरी कल्पना है। यदि हम अपने श्रमिकों को वैसी ही कार्य करने की दशाएँ, मजदूरी, उचित व्यवस्था, मशीनें, पत्र लाबि प्रदान करें जो दूसरे देशों के श्रमिकों को मिलती हैं, तो भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता भी अन्य देशों के श्रमिकों से कम न होगी। इतना ही नहीं, बल्कि जिस कार्य में भी बाह्य सामान और सुव्यवस्था की व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि भारतीय श्रमिक ने दूसरे देशों के श्रमिकों की अवस्था अधिक कार्यक्षमता का प्रमाण दिया है।'

प्रश्न

1 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये, 'भारतीय श्रमिकों की अक्षमता'

(राज० बी० ए० 1962)

2 भारतीय औद्योगिक श्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए यह बतलाइये कि ये विशेषताएँ उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं?

3 भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता कम क्यों है? इसे बढ़ाने के लिए जाय वया सुझाव दोगे?

4 भारतीय श्रमिक की अक्षमता के बीच कौन से कारण उत्तरदायी हैं?

श्रम की कुशलता को बढ़ाने के लिए जाय कौन कौन से सुझाव दोगे?

(राजस्थान प्र०ब० टी० डी० सी० कला, 1969)

भारत में औद्योगिक संघर्ष

(Industrial Disputes in India)

"Laws and libraries are full of statutes and court cases and decisions on the conduct of married life, but they have not made a marriage happy and successful. This is true in industrial relations. It is just as hard and impractical to prescribe iron-bond rules of behaviour of dealings between Labour and Management, as it would be to prescribe them for husbands and wives."

—H S Kirkaldi

औद्योगिक संघर्ष से तात्पर्य मेधा वैज्ञानिक तथा श्रमिकों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों से है, जिनके परिणामस्वरूप हड़तालें, ताले-बन्दिवा, काम की धीमी गति, पेशाव, छंटनी आदि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। एक ओर श्रमिकों के पास 'हड़ताल' नाम का सैनिकतावादी अस्त्र है। श्रमिक इसके द्वारा उस समय तक काम बन्द कर देते हैं जब तक कि उनकी मांगें स्वीकार न कर ली जाएं। दूसरी ओर सेवा-योजकों के पास भी अपना ही अस्त्रवाली अस्त्र है, जिसे ताले-बन्दी कहते हैं। ताले-बन्दी के अन्तर्गत सेवायोजक कारखानों को उस समय तक बन्द रखता है, जब तक कि श्रमिक उसकी शर्तों पर काम करने को सैन्धार नहीं हो जाते। हड़ताल एवं ताले-बन्दी दोनों ही औद्योगिक संघर्ष के दो पहलू हैं। एक ओर तो श्रमिकों में यह भावना पाई जाती है कि मिल मालिक उनका शोषण कर रहा है और दूसरी ओर मिल मालिक यह सोचता है कि श्रमिक संघ उनकी सत्ता को हथियाना चाहते हैं। परिणामस्वरूप श्रमिकों व मालिकों में वैमनस्य पैदा हो जाता है, जो औद्योगिक संघर्ष के रूप में समाज में दिखाई पड़ता है। डॉ० राधाकृष्णन मुन्शी के शब्दों में, "यू.जी. वादी उद्योग के विकास ने, जिसका अर्थ बोहो से साहसियों के वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण हो जाता है, विश्व भर में प्रबन्ध और श्रम के बीच संघर्ष की बड़ी समस्या को हमारे सम्मुख ला दिया है।"

भारत में औद्योगिक संघर्ष—ऐतिहासिक समीक्षा

भारत में औद्योगिक विकास के प्रथम चरण में कोई महत्वपूर्ण हड़ताल नहीं हुई; क्योंकि श्रमिक संगठित नहीं थे। 19वीं सताब्दी में सन् 1877 व सन् 1882 में 'जयश' एम्प्रेस मिल नागपुर तथा बम्बई की एक सूती मिल में औद्योगिक संघर्ष हुए। प्रथम महापुट्ट के पश्चात् ही श्रमिकों ने हड़तालों का सहारा लेना प्रारम्भ किया। सन् 1920 में 200 हड़तालें हुईं, जिनमें 15 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। सन् 1922 में 396 हड़तालें हुईं, जिनमें 6 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। सन् 1928 में भारी के कारण श्रमिकों की मजदूरी में की जाने वाली कटौती के परिणामस्वरूप हड़तालों की एक लहर सी फैल गई, किन्तु सरकार के पास इनके निपटारे के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण वह हस्तक्षेप न कर सकी। सन् 1929 में शाही भाग मायोग नियुक्त हुआ, जिसकी रिपोर्ट ने केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों को कुछ वैधानिक कार्यवाहियां करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन् 1930 में 1937 तक मामान्यतः औद्योगिक क्षेत्र में शांति थी। सन् 1937 में कांग्रेसी मनिमण्डल बनने के कारण श्रमिकों में वर्षों सेतना के विकास हुआ। फलस्वरूप सन् 1937 से 1942 तक कई हड़तालें हुईं। सन् 1937 में 379 हड़तालें हुईं, जिनमें 6 लाख 38 हजार श्रमिकों ने भाग लिया। सन् 1942 में 694 हड़तालें हुईं, जिनमें 7 लाख 73 हजार श्रमिकों ने भाग लिया।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार ने हड़तालों व ताले धर्मियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया, ताकि युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन के बिना बाधा के चलता रहे। इन दिनों होने वाले औद्योगिक संघर्षों को समझौता एवं अनिवार्य वचन-निर्णयों द्वारा हल किया जाता था।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही महागाई के प्रश्न को लेकर पुनः औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि हुई। सन् 1947 में 1,800 औद्योगिक विवाद हुए, जिनमें 18 लाख श्रमिक प्रभावित हुए। बाद में 1951 तक अपेक्षाकृत कुछ शांति रही। सन् 1951 में तथा सन् 1955 में भी हड़तालें हुईं। सन् 1955 में कानपुर के सूती मिलों में अमिनबीकरण के प्रश्न को लेकर 80 दिनों की सम्बन्धी हड़ताल हुई। सन् 1957 के पश्चात् संघर्षों की संख्या में कमी हुई। 1962-63 में राष्ट्रीय संकट के कारण स्थिति कुछ शांतिमय रही, लेकिन भारत के पाकिस्तानी आक्रमण के मोर्चे 'समय को छोड़ कर औद्योगिक सम्बन्ध 1964 व 1965 में फिर से बिगड़ गये। औद्योगिक बसान्ति की स्थिति खनिज व अन्य रोजगारों की तुलना में, निर्माण उद्योगों में अधिक सराव थी। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की तुलना में श्रमिक हड़तालें हुईं।

भारतीय जर्ण-व्यवस्था

कीमतों में वृद्धि के कारण जीवन-निर्वाह कठिन हो गया तथा चीन एवं पाकिस्तानी आक्रमणों द्वारा पैदा हुआ उत्साह धीरे-धीरे समाप्त होन लगा। वास्तविक गणदूरी के क्षेत्र में, 1951 से 1963 तक के 12 वर्षों में निर्माण उद्योगों में वास्तविक मजदूरी केवल 14 प्रतिशत बढ़ी, जबकि कोयला खान तथा अन्य खानों में औद्योगिक मजदूरी क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत बढ़ी। इस तरह मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप निर्माण उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग अशान्त हो गया। सरकार सामंजसिक क्षेत्र के उद्योगों में औद्योगिक अनुदानों सहित और श्रम कानूनों को उचित रूप से कार्यान्वित न कर सकी। 1967 में औद्योगिक विवादों में 'घराब' का भी प्रारुर्भाव हुआ। इन सब कारणों के फलस्वरूप औद्योगिक विवादों की संख्या 1967 में 2815 तथा 1968 में औद्योगिक संघर्षों की संख्या 2477 तक पहुँच गई। 1968-69 में हड़ताल, राल्ट वगैरहों के कारण आदि से कुल 134 लाख मजदूरों की क्षति हुई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारतवर्ष में हुए औद्योगिक संघर्षों का अनुमान नीचे दिये गये आंकड़ों में लगाया जा सकता है —

वर्ष	औद्योगिक विवादों की संख्या	औद्योगिक विवाद में भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या (लाखों में)	थक दिनों की हानि (लाखों में)
1947	1,811	18	166
1951	1,071	7	38
1956	1,203	9	69
1961	1,357	5	49
1966	2,556	14	138
1967	2,615	12	171
1968	2,477	12	138
1969	2,607	18	190
1970	2,889	18	205
1971	2,137	12	127

औद्योगिक संघर्षों के कारण (Causes of Industrial Disputes)

औद्योगिक संघर्षों में औद्योगिक व्यवस्था में आर्थिक-मजदूरी के हिसों में असन्तुष्टि विरोध का परिणाम है। इन संघर्षों के कारण अनेक हैं। कुछ आर्थिक कारण हैं, कुछ सामाजिक, कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ राजनैतिक तथा कुछ प्रशम्य सम्बन्धी कारण हैं। ये कारण संक्षेप में अधोलिखित हैं।

(1) अधिक मजदूरी की मांग (Demand for higher wages) : श्रमिक संघर्षों का सबसे महत्वपूर्ण कारण अधिक मजदूरी की मांग है। भारतीय नियोजक मजदूरी के सम्बन्ध में उदार नीति नहीं अपना सके हैं। वे नए मजदूरी देकर अधिक काम उठाना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मजदूरी में महंगाई के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, फलस्वरूप बहुत से औद्योगिक विवाद अधिक मजदूरी की मांग को लेकर हुए हैं।

(2) बोनस व महंगाई भत्ते की मांग (Demand for Bonus and D.A.) : बोनस सम्बन्धी मांग भी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। मजदूरी में महंगाई बढ़ गई है कि उद्योगों के लाभ में से उन्हें भी एक हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए कई बार बोनस न मिलने अथवा कम बोनस मिलने के कारण भी हड़तालें हो जाती हैं। बढ़ती हुई महंगाई के साथ-साथ, महंगाई भत्ता भी बढ़ाना चाहिए। प्रायः महंगाई तो बढ़ जाती है, परन्तु महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाता, जिससे श्रमिक हड़ताल पर उतरा हो जाते हैं।

(3) सुविधाओं की मांग (Demand for amenities) : कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को नकद मजदूरी के अतिरिक्त प्रायः अन्य सुविधाएँ देने की प्रथा चली आ रही है। इन सुविधाओं से श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। सेवानियम जब इन सुविधाओं में कमी करते हैं, या इन सुविधाओं को किसी कारण-वश बाधते हैं, तो श्रमिकों में असंतोष पैदा हो जाता है और फलस्वरूप हड़तालें हो जाना पड़ती हैं।

(4) काम के घण्टे (Hours of work) : मिल-मालिक श्रमिकों से अधिक से अधिक घण्टे तक काम लेना चाहते हैं। वे समझते हैं कि इससे उनके लाभ में वृद्धि हो जायेगी। श्रमिकों से अधिक काम के घण्टे के प्रति असंतोष पैदा हो जाता है और वे हड़तालें कर दिया करते हैं।

(5) कार्य की शर्तें (Conditions of work) : प्रायः कई कारखानों में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होता। गर्मी, स्वच्छ हवा का अभाव, मशीनों की अधिकता आदि वातावरण को दुश्प्रति किये रहते हैं। कई जगह स्नानगृह, पित्रागृह, कैंटीन आदि की समुचित सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती। अतः कभी कभी काम करने के स्थान के दुश्प्रति वातावरण के कारण भी हड़तालें हो जाती हैं।

(6) श्रमिकों की छंटनी (Retrenchment) : जब कभी श्रमिकों को अनुशासन या अन्य कारणों से काम से निकाला जाता है तो इस बेरोजगारी में दुःख में श्रमिकों को नयी मुनोबत का सामना करना पड़ता है। इसके विरुद्ध वे अपनी नोकरी को रखा के लिए हड़ताल करते हैं।

(7) विवेकीकरण (Rationalisation) - औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने तथा मितव्ययता के दृष्टिकोण से कई कारखानों में विवेकीकरण की योजना लागू की गई, जिससे बहुत से श्रमिकों को काम में हाथ धोना पड़ा। श्रमिकों ने विरोध होकर इसका विरोध करने के लिए हड़तालें कीं। सन् 1955 में कानपुर के भूती मिलों में इसी बात को लेकर 80 दिनों की हड़ताल हुई थी।

(8) प्रबंधकों का दुर्व्यवहार (Ill-behaviour of managers) भारतीय प्रबंधक एवं निरीक्षक (Supervisors) श्रमिकों के साथ अनुचित एवं अशुभमानपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिससे श्रमिकों के सम्मान की ठेस लगती है और वे इसके प्रतिबोध लिए हड़तालें कर देते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार सन् 1921 से सन् 1928 तक के काल में कुल 976 संघर्ष हुये थे जिनमें से 425 संघर्ष निरीक्षकों के दुर्व्यवहार से सम्बन्धित थे।

(9) श्रमिकों की दोषपूर्ण भरती प्रणाली (Defective recruitment system) : श्रमिकों की भरती भारतवर्ष में ठेकेदारों, मिस्त्रियों, जमादारों आदि विश्ववासियों या मध्यस्थों के द्वारा होती है। ये विश्वसनीय कारखाने विधाय को, अपने आप की सर्वेक्षा समझते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये श्रमिकों का दोषपूर्ण मनमाने ढंग से करते हैं। इन विश्ववासियों के दुर्व्यवहार तथा शोषण से पीड़ित होकर भी कभी-कभी श्रमिक हड़तालें कर देते हैं।

(10) श्रम-संघों की मान्यता न देना (Non-recognition of Trade Unions) : निपोजन प्रायः श्रम-संघों को अपना प्रतिद्वन्द्वी समझते हैं और उन्हें मान्यता नहीं देते। मजदूरों को विवश होकर अपने संघ को मान्यता दिलाने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है।

(11) छुट्टियों के लिये तग करना (Refusal of Leave with pay) : जब श्रमिकों की घामिक व सामाजिक अवसरों पर छुट्टी की मांग ठुकरा दी जाती है या उन्हें वेतन सहित अवकाश नहीं दिया जाता, तो वे हड़ताल कर बैठते हैं।

(12) सामूहिक सीदेबाजी का अभाव (Absence of Collective Bargaining) भारतीय श्रमिकों व सेवा-योजकों के बीच प्रायः सम्पर्क नहीं हो पाता, अतः श्रमिकों की कठिनाइयों को वे समझ नहीं पाते। परिणाम यह होता है कि छोटी-छोटी बातों पर हड़तालें हो जाती हैं, क्योंकि जन बातों को सामूहिक सीदेबाजी के अभाव में सुलझाया नहीं जा सकता।

(13) राजनैतिक कारण (Political causes) . भारतवर्ष में श्रमिक संघों का नेतृत्व राजनैतिक नेताओं द्वारा किया जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व राजनैतिक बन्धियों की रिहाई के लिए हड़तालें भी जाती थीं। आजकल श्रमिक अपने राज-

नैतिक नेताओं के चक्कर में फँस कर उनके राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये हड़ताल कर बैठते हैं।

(14) साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव (Effect of Communism) - साम्यवादी, पूँजीपति वर्ग का शत्रु शक्ति है। धर्मिकों के शोषण के कारण, धर्मिकों के बीच इनका काफी प्रभाव है। ये धर्मिकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में हिंसा दिखाने के लिये धर्मिकों को उकसाते रहते हैं। फलस्वरूप साम्यवाद की प्रभाव के माध्यम हमारे देश में हड़तालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

(15) अन्य कारण (Other Causes) - अन्य कारणों के अतिरिक्त अन्य कई और कारण भी हैं जो हड़तालों को जन्म देते रहते हैं जैसे, भारतीय धर्मिक संघों का विध्वन्नात्मक दृष्टिकोण, काम की अवधि सुरक्षा की मांग, धर्मिकों की शिक्षा एवं भोलापन, आदि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक संघर्षों के अनेक कारण हैं। इन कारणों का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर विदित हो जाता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण है। जाही धर्म आयोग का भी यही विचार था।¹ आग की तालिका में औद्योगिक संघर्षों का कारण के अनुसार महत्व दिखाया गया है।

कारणों के अनुसार औद्योगिक संघर्ष

कारण	1959	1960	1961	1962	1964
1 मजदूरी एवं भत्ता	27.1%	37.1%	30.4%	30.2%	34.9%
2 श्रमिक	10.3%	10.5%	6.9%	12.3%	7.6%
3 रोजगार एवं छुट्टी	29.1%	24.7%	29.3%	25.2%	27.4%
4 अवकाश एवं कार्य के घंटे	3.7%	2.4%	3.0%	7%	2.0%
5 अन्य कारण	29.8%	25.3%	30.4%	30.6%	27.8%

औद्योगिक संघर्षों के प्रभाव या परिणाम औद्योगिक संघर्षों से कुछ अच्छे परिणाम अवश्य निकलते हैं लेकिन सामान्यतः इसके दुरे परिणाम ही अधिक होते हैं। धर्मिकों में हड़ताल के कारण एकता व सहयोग की भावना जागृत होती है, वे अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकते हैं तथा अपने काम की दक्षता बहालों में सुधार करा लेते हैं। धर्मिकों को संवेदन झुट्टिया, काम के घंटों में कमी आदि की

1 'Although workers may have been influenced by persons with nationalist, communist or communal ends to serve, we believe that there has been rarely of any importance which has not been done entirely or largely to economic reasons' —Royal Commission on Labour.

सुविधाएँ प्राप्त होने लगती हैं। साथ ही वे प्रबन्धों के दुर्ब्यवहार व क्षोषण में भी बच जाते हैं। औद्योगिक संघर्षों के अन्तर्गत ये अच्छे परिणाम हैं, तथापि इनके दुष्परिणाम बहुत भयंकर व गम्भीर हैं। संक्षेप में औद्योगिक संघर्षों के बुरे परिणाम निम्नांकित हैं।

1. उत्पादन में कमी। जब-जब हड़ताल या तालेबन्दिया होती हैं, तब-तब उत्पादन कार्य में रूकावट पड़ती है, जिससे उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है, राष्ट्रीय लाभांश व प्रति व्यक्ति आय घट जाती है।¹

2. उपभोक्ताओं की कट्टर औद्योगिक संघर्षों के कारण, उत्पादन में कमी हो जाने से वस्तुओं की पूर्ति घट जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तथा गोर बाजारी जैसी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। उपभोक्ताओं को वस्तुओं के ऊँच मूल्य देने पड़ते हैं तथा कभी भी आवश्यक वस्तुओं का मिलना भी कठिन हो जाता है।

3. श्रमिकों की हानि। औद्योगिक संघर्ष का सबसे बुरा असर श्रमिकों पर पड़ता है। उन्हें हड़ताल के समय वेतन नहीं मिलता। मजदूरी के अभाव में उनके व उनके आर्थिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इनमें निराशा की भावना पैदा होती है तथा अनैतिथ्यता फैलने लगती है। श्रमिकों को कभी-कभी छोटियों व गोल्फों का भी सामना करना पड़ता है। अतएव हड़तालों से और भी अधिक घातक होती हैं, क्योंकि इनके परिणामस्वरूप श्रमिकों की अपने संगठन के प्रति आस्था कम हो जाती है।

4. उद्योगपतियों की हानि। उद्योगपति हड़ताल या तालेबन्दी के दौरान काम नहीं बना पाते। यही नहीं, उन्हें सहायक खर्च, जैसे-कारखाना भवन का किराया, पूँजी पर व्याज, ऊँच बंदी पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन आदि भी देना ही पड़ता है। इससे बिना लाभ प्राप्त किये, इन व्ययों के कारण उनकी हानि में वृद्धि हो जाती है।

5. सामाजिक वातावरण का दूषित होना। हड़तालों व तालेबन्दियों के फल-स्वरूप सामाजिक वातावरण दूषित हो जाता है। समाज में अनिश्चितता का वाता-

1. "When labour and equipment in the whole or many part of an industry are rendered idle by a strike or lockout national dividend must suffer in a way that injures economic welfare"

वरण तथा जनसाधारण में गलतफहमी की भावना पैदा होती है। कई दिनों तक कपड़ों लगने से सारा जन-जीवन टप्प हो जाता है।¹

6. जखोशो में अनुशासन व्यवस्था का समाप्त हो जाना : हड़ताल पर्वत उद्योग में अनुशासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। दंगे, फसाद, मारपीट का असामाजिक वातावरण पैदा हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में चारों ओर उधल-धुलन व अशांति फैल जाती है। असामाजिक तत्व औद्योगिक अशांति का लाभ उठाकर शरा-जकता का वातावरण पैदा कर देते हैं।

7. जनसाधारण की कष्ट : रेल, डाक-तार, पानी, बिजली आदि से सम्बन्धित सुस्थापना में हड़ताल हो जाने के कारण जनसाधारण का दैनिक जीवन कष्टमय हो जाता है, क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक सेवाएँ हैं और इनके अभाव में जनसाधारण का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

8. सरकार की हानि : औद्योगिक संघर्ष में सरकार को भी हानि व असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। एक ओर तो देश में अशान्ति फैलती है, जिसे रोकने के लिए इसे काफी व्यय करना पड़ता है। दूसरी ओर उत्पादन कम हो जाने के कारण कर के रूप में मिलने वाली आयदनी घट जाती है। कई बार हड़तालों व तालेबन्दियाँ इसकी गम्भीर स्थिति पैदा कर देती हैं कि सरकार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक संघर्षों से श्रमिक, मालिक तथा राष्ट्र को अपार नुकसान होता है। इससे देश की वार्षिक प्रगति को भारी घबका पहुँचता है। श्री सान्द्रु भाई देसाई के शब्दों में “व्यस्क मताधिकार पर आधारित जनतन्त्र में, हड़तालों व तालेबन्दियाँ, न केवल कालातीत हो गई हैं, बल्कि वे जिन संदेहों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, उनके लिए भी हानिप्रद हैं।”² श्री हॉन्सत के विचार भी इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय हैं, “हड़ताल और तालेबन्दियाँ का अधिकार बिल्कुल ही खतरा पैदा करता है। यह जनसाधारणों के, क्योंकि औद्योगिक संघर्षों की दशा में यह शान्ति के प्रयोग पर निर्भर है। श्रमिकों की दुर्बला के सर्वार्थे ॥

1 “Often the strike menaces the public safety, infringes upon property rights and becomes malicious in its effects, if not in its purpose.”

Cultin - The Labour problems, p 416

2. “In a democracy based on franchise, strikes and lockouts have not only become outdated but are positively harmful for the very purpose for which they are used.”

यह अमानवीय है। यह धर्म और पूँजी के साधनों का अपव्यय है। यह मृणा को जन्म देता है, अतः पृथ्वी है। चूँकि यह समाज में अस्तव्यस्तता पैदा करता है, इसलिए यह अमानवीय है।¹

औद्योगिक झगड़ों की रोकथाम (Prevention of Industrial Disputes)

औद्योगिक सघर्षों की रोकथाम उनके उपचार से बेहतर होती है, अतः मजदूरों और मालिकों में सघर्षों की नींव ही न आये, हमें ऐसे प्रयासों पर विचार करना चाहिए। भारत सरकार ने भी इसी दिशा में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जो निम्नलिखित हैं।

1. कारखाना समितियों का गठन (Formation of Works Committees): कारखाना समितियों में सेवायोजकों एवं श्रमिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होते हैं। इन समितियों के मुख्य कार्य सेवा योजना और श्रमिकों के मध्य शांति एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देना, पारस्परिक हितों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना तथा ऐसे मामलों के सम्बन्ध में यदि कोई परामर्श मतभेद हो तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करना है। इन समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव उनके श्रमिक वर्गों से परामर्श लेकर किया जाता है। सरकार ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, इन कार्य समितियों के गठन का आदेश दे सकती है।

2. श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of Labour Welfare Officers) औद्योगिक सघर्षों की रोकने एवं श्रमिकों की शिकायतों को कारखानों के अन्दर ही दूर कराने में श्रमिक कल्याण अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फौजदारी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक कारखाने में श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गयी है, जहाँ 500 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। उन कारखानों में जहाँ श्रम कल्याण अधिकारियों ने सकलता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य किया है, औद्योगिक नीति को बढ़ावा मिला है।

1. "The absolute right to lock out or to strike must go. It is unjust, in that it is an appeal to force, in a matter of disputed right, it is injurious, because of the misery it causes to the workers, it is wasteful of the resources of capital and labour, it is wicked because it stirs up hate—it is anti-social, in that it denies and disrupts the solidarity of the community."

3 स्वस्थ एवं शक्तिशाली श्रमिक संघ (Strong Trade Unionism) -

एक स्वस्थ एवं शक्तिशाली श्रमिक संघ, जो प्रजातांत्रिक ढंग से चलाया जा रहा हो तथा जिसे नियोजकों द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, औद्योगिक जगहों में काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मिल मालिकों एवं सरकार को यह बात पूर्णतया भाननी होनी चाहिए कि मजदूर संघ आर्थिक जीवन की एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण संस्था हैं और देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा देश में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए एक स्वस्थ एवं सकल श्रमिक संघ आवश्यक अनिवार्य है। मिल मालिकों को श्रमिक संघों के प्रति अपनी द्वेष भावना का त्याग करना चाहिए तथा उन्हें उचित सम्मान एवं मान्यता प्रदान करने चाहिए।

4 संयुक्त प्रबंधपरिषदें (Joint Management Councils) सन् 1948

की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अर्णत उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों के सहयोग की महत्ता को स्वीकार किया गया है। कलस्वरूप संघों में संयुक्त प्रबंध परिषदें (Joint Management Councils) संगठित की गई हैं। इनमें नियोजकों व श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इन परिषदों में प्रतिनिधित्व पाने के कारण श्रमिक अपने को कारखाने का भागीदार समझने लगता है। इन परिषदों का मुख्य यह है कि धीरे-धीरे श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने की प्रोत्साहित किया जाय। ऐसा करने से श्रमिकों व उद्योगपतियों के बीच सहभावना का विकास होगा तथा श्रमिक औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने में रुचिष्ट रहेंगे। इस समय 97 इकाइयों में, 36 सार्वजनिक क्षेत्र व 61 निजी क्षेत्र में—संयुक्त प्रबन्ध परिषदें काम कर रही हैं।

5 वैच्छिक विवादों का पक्ष निर्णय (Voluntary Arbitration) .

एच्छिक विवादों का पक्ष-निर्णय में दोनों पक्ष, सर्वप्रथम अपने मतभेदों को आपस में सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें असफल होने पर मध्यस्थ एवं समझौताकार पक्ष के माध्यम से दागडों को सुलझाने की व्यवस्था की जाती है। यदि इसमें भी असफलता ही मिलती है तो दोनों पक्षों का अपना-आपसा एक विवाचक के समुख प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अनिवार्यतः स्वीकार करना पड़ता है। अम मन्त्रालय तथा INTUC (भारतीय राष्ट्रीय कामकाज श्रमिक संघ) का मत है कि ऐच्छिक विवादों को औद्योगिक संघर्षों को कम करने तथा अपार्टे को रोकने का सर्वोत्तम साधन है।

6 अनुशासन संहिता (The Voluntary Code of Discipline) सन्

1957 के 15वें भारतीय श्रमिक सम्मेलन ने एक औद्योगिक अनुशासन संहिता बनाई, जिसे सन् 1958 में लागू किया गया। इस संहिता का लक्ष्य मालिकों एवं मजदूरों पर ऐच्छिक दबाव डालना है कि वे अपने समस्त दावद पारस्परिक बातों, समझौता

और ऐच्छिक विवाचन द्वारा निपटायेगे। इस सहिता के अन्तर्गत निम्न बातों पर जोर दिया गया है -

- (1) नोटिस दिवस बिना हटताल या ठाढेबन्दी न की जाय।
- (2) किसी भी औद्योगिक मामले में एक तरफ़ा कार्यवाही न की जाय।
- (3) 'कार्य चीरे करो' नीति का सहारा न लिया जाय।
- (4) कारखाने की सम्पत्ति को ज़ब्तबूझ कर क्षति न पहुंचाई जाय।
- (5) हिंसा, धमकी, उत्फ़सने एवं अराजक के लिए भट्ठाने के कार्य न किये जायें।

(6) औद्योगिक सघर्षों को निपटाने के हेतु वर्तमान व्यवस्था का पूर्णतया उपयोग किया जाय।

(7) निर्णय एवं समझौते को औद्योगिक कार्यस्थल पर किया जाय।

(8) ऐसा कोई कार्य न किया जाय जिससे औद्योगिक सम्बन्धों में बिगाड़ हो।

उपरोक्त अनुसामन सहिता को पुष्टि यम के प्रमुख केन्द्रीय सघर्षों एवं सेवा-योगकों के सभी प्रमुख सघर्षों में कर दी है। इससे औद्योगिक शांति में लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है, जिससे सन् 1958 के पदचात औद्योगिक सघर्षों में कमी हुई है।

7 संयुक्त विचार-विमर्श मण्डल (Joint Consultative Board) : संयुक्त विचार-विमर्श द्वारा एक पक्ष दूसरे के दृष्टिकोण से गंभीरता से परिचित हो जाता है तथा एक दूसरे की रचनात्मक आलोचना करने का अवसर दोनों पक्षों को प्राप्त हो जाता है। फलस्वरूप पारस्परिक द्वेष व संदेह की भावना समाप्त हो जाती है। मिलजुल कर पारस्परिक विचार-विमर्श से जो निर्णय लिये जाते हैं, उन्हें भावना से कार्य रूप में परिचित किया जा सकता है। योरोप में इन प्रथा ने औद्योगिक शांति बनाये रखने में काफी योगदान दिया है। भारतवर्ष में सन् 1952 में केन्द्रीय सरकार ने Joint Consultative Board of Industry and Labour की स्थापना एक निपक्षीय समिति के रूप में की। सन् 1954 में इसे द्विपक्षीय समिति का रूप दिया गया। अब यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सघर्षों को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रही है।

8. सामूहिक छेदेकारी (Collective Bargaining) : श्रमिक सघर्ष एवं निपोजकों के बीच सामूहिक छेदेकारी की विधि औद्योगिक क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय या किसी भी स्तर पर अपनायी जा सकती है। इसमें मजदूरी की दरों, कार्य के घण्टे तथा अन्य सम्बन्धी मागधों पर दो पक्षों के बीच छेदेकारी के द्वारा फंमला कर लिमा जाता है, ताकि मन-मुटाव या सघर्ष के कारण दूर हो जाए। इससे पारस्परिक

तनाव कम हो जाता है तथा उद्योगपतियों व श्रमिकों को लाभ पहुंचता है। जिन उद्योगों में सामूहिक सौदेकारी की व्यवस्था है, वहां श्रमिक संघ अपने उत्तरदायित्व को समझते सकते हैं। बम्बई, अहमदाबाद एवं जमशेदपुर तथा अन्य जिन नगरों में सामूहिक समझौते हुए हैं, वहां औद्योगिक शांति के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ है।

9 **मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन समितियाँ (Implementation and Evaluation Committee)** - कम्पेन्समी निर्णयों एवं समझौतों को उचित रूप से लागू न कराने पर उद्योगपतियों एवं श्रमिकों के मध्य तनाव पैदा हो जाता है। 1958 में श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय ने एक केन्द्रीय मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन समिति बनाई जिसमें मालिकों व श्रमिकों के 4-4 प्रतिनिधि तथा 4 सरकारी प्रतिनिधि रखे गये हैं। कुछ प्रान्तों में भी ऐसी समितियाँ बनाई गयी हैं। ये समितियाँ निर्णयों एवं समझौतों के पालन में त्रुटि का पता चलने पर सम्बन्धित पक्ष का ध्यान आकर्षित करती हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए अनुरोध करती हैं। इन समितियों में मालिकों एवं श्रमिकों के बीच भ्रान्तिय दूर होती तथा औद्योगिक शांति को और गहन मिलेगा।

10 **मजदूरी मंडल का संगठन (Formation of Wage Boards)** औद्योगिक सत्ता का मुख्य कारण मजदूरी, बत्ते बोझ आदि में सम्बन्धित मार्ग हैं। मजदूरी सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के लिए मजदूर मण्डल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन दृष्टि से निम्नलिखित मजदूरी मण्डलों का गठन बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता है। प्रत्येक उद्योग के लिए अलग-अलग मजदूरी मण्डल बनाये जा सकते हैं। इसमें सेवा योजनाएँ एवं मजदूरी के प्रतिनिधि तथा एक स्वतन्त्र चेयरमैन होता है। ऐसे औद्योगिक संघर्षों को कम करने में मदद मिलती है। ये मण्डल जीवन निर्वाह व्यय, उद्योग की अवस्था आदि की देखरेख हुए सम्बन्धित उद्योग मजदूरी के विषय में सम्मति देते हैं।

11 **औद्योगिक तनाव के कारणों को दूर किया जाय (Removal of the causes of grievances)** इसके लिए यह आवश्यक है कि तनावपूर्ण सम्बन्धों और संघर्षों के कारणों की जाच-पड़ताल की जाय, तथा उनके उपचार खोजे जाए। योजना आयोग ने भी इस प्रकार की जाच की उपयोगिता को महत्वपूर्ण बताया है। इस सम्बन्ध में जाच का कार्य उन दोनों प्रकार के उद्योगों में होना चाहिए जहाँ संघर्ष कम होते हैं और जहाँ संघर्ष अधिक होते हैं। इससे सुलभात्त्य अध्ययन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकेगा कि कौन सी शक्ति औद्योगिक शांति को बढ़ावा देती है और कौन सी इसके मार्ग में बाधक है।

12 **औद्योगिक शांति प्रस्ताव (Industrial Truce Resolution)** - जून 1962 में चीनी हमले में समय नवम्बर सन् 1962 में श्रीमूलजरोराल नन्दा की

अध्यक्षता में केन्द्रीय श्रम संगठनों व मालिकों के संगठनों की एक समझौता गयी जो जिसने देश की सुरक्षा के लिए अखिरतम उत्पादन में लक्ष्यों की स्वीकार किया था और औद्योगिक शांति प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव के स्वीकार करने से सन् 1963 में बहुत कम श्रम दिवसों का नुकसान हुआ और औद्योगिक शांति की स्थापना में आश्चर्यचकित सफलता प्राप्त हुई। अन्त. अविध्य में भी ऐसी ही औद्योगिक शांति प्रस्तावों के द्वारा औद्योगिक शांति स्थापना के लिए दिल से प्रयत्न किये जाने चाहिए।

13 स्थायी व्यवस्था (Standing Orders) इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार रोजगार के नियम या छत्तें निश्चित कर देती है, जिनका श्रमिकों व सेवा-योजकों दोनों को ही पालन करना पड़ता है। इन नियमों को निश्चित कर देने से श्रम अपना-अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। फलस्वरूप औद्योगिक संघर्ष की सम्भावना कम हो जाती है।

उपयुक्त प्रयत्न श्रम संघर्षों को रोकने के लिए किये जाते हैं। लेकिन यदि संघर्ष एक नहीं जाता और हड़ताल या तालेबन्दी हो जाती है तो उसके निपटारे के लिए कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। वत अब हम, भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्षों के निपटारे के लिए जो कानूनी व्यवस्था पाई जाती है, उसका अध्ययन करेंगे।

औद्योगिक विवादों का समाधान (Settlement of Industrial Disputes)

1 श्रम विवाद अधिनियम, 1929 (Trade Disputes Act, 1929)। भारतवर्ष में औद्योगिक झगड़ों की रोकथाम व उनका निपटारा करने के लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था सबसे पहले सन् 1929 में 'व्यापारिक संघर्ष अधिनियम, 1929' के अन्तर्गत की गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक संघर्षों को निपटाने के लिए निम्न व्यवस्था की गयी है —

1. जांच अदालत (Court of Enquiry),
2. समझौता बोर्ड (Conciliation Board),
3. सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के लिए व्यवस्था (Provision for Public Utility Concerns)।

1 जांच अदालत इस अदालत का कार्य औद्योगिक झगड़े से सम्बन्धित बातों की जांच करके अपनी रिपोर्टें समझौता बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना था।

2 समझौता बोर्ड इसका काम दोनों पक्षों को निकट लाकर परस्पर समझौता कराना होता था। समझौता बोर्ड अपने कार्य में असफलता पाने पर तालेबन्दी संघर्ष की सूचना और अपनी रिपोर्टें सरकार को भेज देता था।

3. **सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित व्यवस्था :** इस अधिनियम में सार्वजनिक हित सम्बन्धी सेवाओं यथा रेल, डाक-सार, विद्युत एवं अरु-भूति आदि में हस्तक्षेप करने से 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि यह ऐसे किसी भी औद्योगिक अगड़ों को अवैधानिक घोषित कर सकती है, जो सामाजिक दृष्टि से महत्त्वकारी हैं।

उक्त अधिनियम की यह अच्छाई थी कि इसमें ऐच्छिक पंच-निर्णय के सिद्धांतों को अपनाया गया था। इस अधिनियम का दोष यह था कि इसमें झगड़ा रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार को अदालत या बोर्ड के फैसले को लागू करने के अधिकार नहीं थे। स्थायी औद्योगिक न्यायालय के गठन का भी कोई प्रावधान नहीं था, अतः व्यवहार में यह अधिनियम प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ।

उक्त अधिनियम में सन् 1938 में लखनऊ किया गया जिसके अनुसार सरकार को समझौता अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार मिला। ये अधिकारी औद्योगिक संघर्षों में माध्यस्थता के द्वारा झगड़ों को निपटारने का प्रयत्न करते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत सरकार ने औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए, भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा 81-ए के द्वारा हड़तालों व हानिकारियों को अवैधानिक घोषित कर दिया।

2. **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)** इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएँ की हैं : (क) जाल्तरिक व्यवस्था, तथा (ख) बाह्य व्यवस्था।

(क) **जाल्तरिक व्यवस्था :** कार्य समितियाँ (Works Committees) : उक्त अधिनियम 100 या 100 से अधिक मजदूरों वाले कारखानों में कम समितियों की स्थापना अनिवार्य है। इस समिति में श्रमिकों व निरीक्षकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होते हैं। इन समितियों का उद्देश्य श्रमिकों एवं निरीक्षकों के मध्य दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाले छोटे-मोटे अगड़ों को रोकना है। इनका मुख्य कार्य निरीक्षकों एवं श्रमिकों में पारस्परिक मतभेदों को दूर करके अच्छे सम्बन्ध उत्पन्न करना है। जून 1970 के अन्त में केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में 876 कार्य-समितियाँ कार्य कर रही थी।

(ख) **बाह्य व्यवस्था :** औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक अगड़ों के निपटारे के लिए अग्रलिखित व्यवस्था की गयी है :

1. **समझौता अधिकारी (Conciliation Officer):** इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी विशिष्ट जिले या क्षेत्र के लिए एक समझौता या सुलह अधिकारी नियुक्त कर देती है। जब कभी औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है या इसके उत्पन्न होने का भय होना है तो इसे समझौता अधिकारी के सुपुर्दे कर दिया जाता है। समझौता अधिकारी संघर्ष की सुलझाने का प्रयास करता है तथा उसे 14 दिन के अन्दर अपने रिपोर्ट सरकार को देनी पड़ती है। यदि दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो दोनों पक्ष इस पर हस्ताक्षर कर बैठते हैं और यह समझौता दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। यदि यह अपने कार्य में असफल हो जाता है तो यह इस बारे में सरकार को रिपोर्ट न करता है, जिसमें अपने असफलता के कारण एवं अपने द्वारा किए गये प्रयत्नों का उल्लेख करता है। तत्पश्चात् सरकार झगड़े को समझौता मंडल या जाँच न्यायालय को सौंप देती है।

2. **समझौता या सुलह मंडल (Board of Conciliation):** समझौता मंडल में एक स्वतन्त्र प्रधान तथा भागान सख्या में दोनो दलों के दो अथवा अधिक प्रतिनिधि होते हैं। समझौता मंडल को दो महीने के अन्दर ही समझौते के अपने प्रयास समाप्त करने होते हैं। इसके द्वारा किये गये समझौते दोनों पक्षों की राय में कम 6 महीने या दोनो पक्षों की सहमति से अधिक दिनों के लिए लागू होते हैं। असफलता की दशा में समझौता बोर्डों को अपने कार्य की रिपोर्ट सरकार को भेजनी पड़ती है।

3. **जाँच न्यायालय (Court of Inquiry)** समझौते की असफलता की स्थिति में सरकार संघर्ष का मामला जाँच न्यायालय को सौंप सकती है। इस अदालत में एक या दो स्वतन्त्र व्यक्ति होते हैं। इस न्यायालय को केवल झगड़े के बारे में आवश्यक तथ्य एकत्रित करने पड़ते हैं तथा 6 महीने के भीतर ही अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देनी होती है। 6 महीने की अवधि याच आरम्भ करने के दिन से लगायी जाती है।

4. **औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal)** अन्त में, सरकार शमले पर अपना निर्णय देने के लिए गावला औद्योगिक ट्रिब्युनल को सौंप सकती है। इनमें हाइकोर्ट या निम्न जज पद के दो अथवा अधिक सदस्य होते हैं। जब विवाद में सम्बन्धित दोनों पक्ष अपना अपना औद्योगिक न्यायाधिकरण से सौंपने के हेतु सरकार से अनुरोध करें या जब सरकार स्वयं ही यह उपयुक्त समझे कि झगड़ा औद्योगिक न्यायालय को सौंप देनी चाहिए, तो यह ऐसा कर सकती है। न्यायालय का निर्णय दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। सरकार को 30 दिनों

के भीतर हम निर्णय को अस्वीकार करने अथवा इसमें संशोधन करते जब अधिकार होता है।

सन् 1947 के अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल के लिए हड़ताल से 6 सप्ताह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। यदि विवाद पर विचार चल रहा है या न्यायिक कार्यवाही चालू है या निर्णय दिये हुए हो याह नहीं दीते हैं, तो ऐसी अवस्था में हड़ताल अथवा तान्त्रिकी अवैध होगी।

औद्योगिक संघर्ष श्रम-अपील अदालत अधिनियम, 1950 (*Industrial Disputes Labour Appellate Courts Act, 1950*) : इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील अदालत की स्थापना व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना इसलिए आवश्यक हो गई कि औद्योगिक अदालतें विभिन्न राज्यों में परस्पर विरोधी निर्णय देने लगीं। 'अपील अदालत' मजदूरी, बोनस, ग्रेजुटी-भुगतान व छुट्टी आदि के मामलों पर अपील सुनने के लिए खड़ा बनी थी।

औद्योगिक संघर्ष (संशोधन एवं मिश्रित प्रावधान) अधिनियम, 1956 (*Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provision) Act*) : इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्न हैं—

1. जब 500 से प्रतिग्राह गाये वाले समस्त व्यक्ति (टेकनीकल कर्मचारी व प्रदत्त करने वाले कर्मचारी आदि) 'मजदूरों' की श्रेणी में आने आवेंगे।

2. इस अधिनियम में 'श्रम अपील अदालत' को समाप्त कर दिया।

3. इस अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरणों को बनाये रखा गया है तथा नई संस्थाएँ—श्रम न्यायालय व राष्ट्रीय न्यायाधिकरण—स्थापित की गयी हैं। ये तीन संस्थाएँ अलग-अलग काम करेंगी। एक संस्था से दूसरी संस्था में अपील नहीं की जा सकती, किन्तु सम्बन्धित पक्षों को हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है।

1. श्रम न्यायालय (Labour Courts) राज्य सरकारों ने इस नियम के अन्तर्गत नियोजकों के विवादारपद वादेशी, प्रबन्धकों द्वारा मिलभित एवं पदच्युत होने गये श्रमिकों, हड़ताली और तालाबन्दी के वैधानिक या अवैधानिक होने के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए, श्रम न्यायालय स्थापित किये गये हैं। श्रम न्यायालय इन विवादों के बारे में छीत्र निर्णय करके सरकार को रिपोर्ट भेज देते हैं। ऐसे न्यायालय में केवल उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें कम से कम 7 वर्षों का न्यायिक अनुभव प्राप्त हो।

2. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (National Tribunals) : राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। उन एवं विवाद साध जाते हैं

जो या तो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं या ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित होते हैं, जो एक से अधिक राज्यों में स्थित हों। इनका निर्णय दोनों पक्षों को मानना ही पड़ता है।

सन् 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत तीन प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गयी है। इन तीन न्यायालयों के अतिरिक्त औद्योगिक शांति को बनाये रखने की जो पहले से ही व्यवस्था चली आ रही है, उन सबको मिला कर वर्तमान समय में भारत में निम्न व्यवस्थाएँ हैं

- 1 नार्स समितिवा (Works Committees),
- 2 समझौता अधिकारी (Conciliation Officer),
- 3 समझौता मण्डल (Conciliation Board),
- 4 जाँच न्यायालय (Court of Inquiry),
- 5 श्रम न्यायालय (Labour Courts),
- 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial or State Tribunals), तथा
- 7 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (National Tribunals)।

इन प्रकार वर्तमान समय में भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्षों को निपटाने के लिए सफलतम व्यवस्था में ऐच्छिक समझौता (Voluntary Conciliation), मध्यस्थता (Mediation), अनिवार्य समझौता (Compulsory Arbitration) तथा अदालती निर्णय (Adjudication) सब सम्मिलित हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में नवम्बर, 1965 में संशोधन किया गया, जिसके अन्तर्गत मजदूरों को नोकरी से पदच्युत व मूखल किये जाने के विषय में और अधिक सुरक्षा प्रदान की गई तथा इसकी अवहेलना करने पर जुर्माने को और बढ़ा कर दिया गया। जुलाई 1966 में पुन औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया। इसका उद्देश्य अधिक अदालतों और औद्योगिक अधिकारियों को आन्तरिक जाँच के बाद ही पदच्युत व सामंती पर निर्णय देने का अधिकार प्रदान करना है।

श्री मन्मथगडकर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय श्रम-आयोग ने अपनी अवस्था 1969 में दी गई रिपोर्ट में औद्योगिक संघर्षों को निपटाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। संक्षेप में निम्नांकित हैं

1. जांचोप जांच एव यमिकों के आपसी झगड़े निपटाने के लिए केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य में स्थायी औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया है। यह आयोग किसी अधिक मूनिशन को मान्यता दे सकेंगे और उनके उद्योग

के साथ समझौते तथा पंच नियुक्ति आदि के बारे में निर्णय कर सकेंगे। केन्द्रीय मायोग राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सम्मति प्रकट करेगा और राज्यों के मायोग राज्यीय महत्त्व के क्षेत्र में व्यवहार करेंगे।

2. आयोग ने अनिवार्य और कम अनिवार्य जमका समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण उद्योगों में भेद किया है। समाज की उपयोगी सेवाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। इन उद्योगों में हड़ताल की अनुमति नहीं दी जायेगी। कम महत्वपूर्ण आयोगों में भी तीस दिनों से अधिक हड़ताल नहीं चल सकेगी। इससे अधिक चलने पर यह आयोग हड़ताल में हस्तक्षेप कर सकेंगे और कोई न कोई विराम देंगे। दोनों पक्षों को यह निर्णय माननीय होगा। इस सिफारिश को अमल में लाने के लिए यह आवश्यक है कि सब मजदूर-दल इन निर्णयों को स्वीकार करें और इनके विरुद्ध कोई आचरण न करें। इस सिफारिश के द्वारा आयोग ने श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार को तो स्वीकार किया है, किन्तु उन्हें अधिक समय तक उद्योगों की हानि पहुँचाकर राष्ट्र की हानि करने के अधिकार की स्वीकार नहीं किया है।

3. आयोग की सम्मति में यदि कोई हड़ताल मुक्तिसंगत नहीं है तो उस स्थिति में श्रमिकों को वेतन लेने का अधिकार नहीं होगा। तालाबन्दी मुक्ति संगत न होने पर उन्हें पूर्ण वेतन लेने का अधिकार होगा।

भारत के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनी रहे तथा श्रमिकों और नियोजकों के मध्य संघर्षों की संख्या कम से कम हो। औद्योगिक संघर्षों की जटिल समस्या केवल नारेबाजी, प्रवचन या भावणा से नहीं मुलज सकती। औद्योगिक संघर्षों को दूर करने के लिए हमें इन संघर्षों के प्राथमिक कारणों को ढूँढ निकालना होगा तथा उनका विराकरण करना होगा। हमें श्रमिकों की अनेक माँगों को दूर करना होगा। उन्हें कानून द्वारा चुप नहीं किया जा सकता और न ही दबाया जा सकता है। उन्हें तो उचित मजहूरी देकर, कार्य की दशाएँ सुधार कर और प्रबंध में भागीदार बना कर संघर्षों में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, ताकि संघ के नव-निर्माण में वे सहूल्य योगदान दे सकें और औद्योगिक स्थिति दूर हो सके। इस सम्बन्ध में प्रो० के० एन० ओषवस्तव के निम्नलिखित शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं।

“यदि जनता की सरकार, जो जनता के लिए हो और जनता द्वारा शासित होती हो, श्रमिकों के हितों को उपेक्षा करती है, तो उसे जनता की सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं। वस्तुतः भूख मरने वालों से यह कहना कि तुम अपना मुँह बन्द करलो और अपने प्रति होने वाले अन्याय का विरोध न करो, केवल इसलिए कि इससे दूसरों को पोंछा पहुँचती है, यही और समुद्रिच्छाली व्यक्तियों के सुख चैन में

बाधा पहुँचती है, सरासर बन्धाय हुआ। यदि कोई रोखी छीन पीसा से कराह रहा है, तो उम्मीद यह बत कर चुप रहो दिया जा सकता कि उसके बराबरने स जमरो की ताटी नोद स बाधा पहुँची है औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए धर्मिक वर्ग की पीना का कारण टूटना होगा और उप नर करना होगा। धर्मिक वर्ग को चुप् कराने स अथवा दबान से नाम नहीं चलेगा।¹

प्रश्न

1 Discuss industrial disputes in India. What measures have been adopted in recent years to promote industrial peace in the country? (Raj B A, 1960)

2 भारत में औद्योगिक संघर्षों के प्रमुख कारण क्या हैं? औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

(आगरा बी० काम० 1960, 61)

* 3 औद्योगिक संघर्ष के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए इन्हें दूर करने के सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

भारत में श्रम संघ आन्दोलन

(Trade Union Movement in India)

"It is only one of the great social and economic weapons, that industrial worker has to emancipate itself from its present dependence upon capitalism and to win for it, 'a co-operation with the other sections of toilers, complete political and economic power in modern society.'"

—Prof N G Ranga

औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप विशालकाय उद्योगों का जन्म हुआ, जिनमें महुंगी श्रमिक काम करने लगे। समाज, फलस्वरूप दो वर्गों में बंट गया—एक वर्ग था सम्पन्न पूँजीपतियों का और दूसरा वर्ग उन लोगों का जो कारखानों में काम करते थे। पूँजीपतियों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उत्पादन के निरीह वर्ग—श्रमिक-वर्ग का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में बहुत दिनों तक श्रमिकों का शोषण होता रहा। लेकिन कुछ समय बाद विचारकों एवं समाज सुधारकों ने श्रमिकों को शोषण से अपनी रक्षा करने के लिए संगठित होने को कहा। इस सम्बन्ध में आधुनिक समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मजदूरों के श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए कहा, “विश्व के श्रमिकों संगठित हो जाओ, तुम्हें अपनी अजीब (दासता की) के अतिरिक्त कुछ नहीं खाना है।”

अतः मजदूर घर में जहाँ नहीं भी श्रमिक बहुत नहीं सख्या में कारखानों में काम करते थे, उन्होंने शोषण से अपनी रक्षा करने के लिए अपने संघठन बनाए। इस प्रकार समस्त के विभिन्न देशों में श्रमिक संघों का उद्भव एवं विकास हुआ।

श्रम संघ की परिभाषा श्रम संघ श्रमिकों का संघटन है, जो उद्योगपतियों के शासन में बचने तथा श्रमिकों के अधिकारों व हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाए जाते

है। सिटनी व वेब के शब्दों में "अधिक मजदूरों के ऐसे स्थायी संगठन को कहते हैं जिसका उद्देश्य काम की दशाओं को बनाए रखना और सुधारना होता है।"¹

प्रसिद्ध अर्थ-सच नेता एच भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री बी० पी० गिरि ने अर्थ-सच को इस प्रकार परिभाषित किया है, "अर्थ-सच अधिकों के ऐच्छित संगठन है जो संगठित कार्य द्वारा अधिकों के आर्थिक हितों की रक्षा तथा सुधार हेतु बनाए जाते हैं।"²

अर्थ-सच के उद्देश्य . अधिक मजदूरों के सम्बन्ध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्राथमिक व ऐच्छित के अनुसार अर्थ-सच पूँजीवादी को दबाव फेंकने, शासन सत्ता हथियाने तथा वर्गहीन समाज बनाने के साधन हैं। सिडनी व वेब अर्थ-सचों को उद्योग के क्षेत्र में अनतन्त्र के सिद्धान्त को फैलाने का साधन मानते हैं। साधारणतः अधिक मजदूर निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्रिय किए जाते हैं :

(1) अधिक एव मालिक के बीच अच्छे सम्बन्धों को बनाने के लिए, जिससे औद्योगिक शांति बनी रह सके, (2) अधिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए; (3) अधिकों में पारस्परिक भेदभाव समाप्त करने तथा उनमें आई-बाँरे की भावना पैदा करने के लिए जिससे अधिकों में आपसी सहयोग की भावना बढ सके, (4) कठिनाइयों के समय अधिकों का मार्ग-दर्शन करने, उन्हें सलाह देने तथा सुपरन्त या बीमारी के समय उनकी आर्थिक उत्थापकता करने के लिए, (5) अधिकों के कार्य करने के दृष्टि, मजदूरी की दरें तथा कार्य के स्थान के अस्वास्थ्य को सुधारने के लिए; (6) अधिकों व उनके परिवार के सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक व नैतिक विकास के लिए, (7) समयानुसार अधिकों को वैधानिक सलाह देने के लिए; (8) अधिकों के लिए हितकर योजनाएँ प्रारम्भ करने के लिए जैसे सहायकारी छात्र, बिज्ञा, शिक्षिका एव मनोरंजन की सुविधाएँ आदि। (9) अधिकों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे उद्योगवृत्तियों से लड़ने व बराबर के स्तर पर सौदा-कर सकें; (10) औद्योगिक तयार के समय सार्वजनिक से मित्रता रखकर समाधान बनाने के लिए तथा समाधान के अनपेक्ष होने पर हड़ताल की घोषणा करने तथा उसे सफलतापूर्वक

1. "A continuous association of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their working "

—Sidney and Webb

2. "Trade Unions are voluntary organisations of workers formed to promote and protect their interest by collective actions "

—V. L. Giri.

चलाने के लिए, (11) श्रमिकों में कार्यों के प्रति निष्ठा एवं अनुशासन पैदा करने के लिए, (12) श्रमिकों को सञ्चोगों के प्रबन्ध में हिस्सा दिलाने का प्रयास करने के लिए ।

श्रम सघों के कार्य श्रम सघों के कार्यों को तीन भागों में बांटा जा सकता है

- 1 आन्तरिक कार्य,
- 2 बाहरी कार्य, तथा
- 3 राजनैतिक कार्य ।

1 आन्तरिक कार्य औद्योगिक संस्थानों के अन्दर श्रमिक सघ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो कार्य करते हैं, वे आन्तरिक कार्य कहे जाते हैं । उचित मजदूरी विलाना, काम के घटे कम करना, प्रबन्ध में श्रमिकों को हिस्सा दिलाना, सञ्चोग के लाभ में श्रमिकों को हिस्सा विलाना आदि कार्य आन्तरिक कार्य कहे जाते हैं ।

2 बाहरी कार्य श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम सघनों द्वारा कार्य करने के स्थान के बाहर जो कार्य किये जाते हैं उन्हें बाहरी कार्य कहे जाते हैं । श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उनके निवास स्थानों की सफाई की व्यवस्था करने के लिए तथा उनमें एकता, अनुशासन, आदर-सम्मान व ईमानदारी की भावना भरने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, बाहरी कार्य कहलाते हैं । इन कार्यों में हड़ताल व तालेबन्दी के समय आर्थिक सह्यता, बच्चों की शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा, पुस्तकालय एवं वाचनालयों की व्यवस्था तथा श्रमिकों के लिए मनोरंजन सम्बन्धी किये गये सभी कार्य आ जाते हैं ।

3 राजनैतिक कार्य वर्तमान युग के श्रमिक सघ राजनैतिक कार्यों की ओर भी विरोध बंधि रखते हैं । सरकारों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जाग्रत करना, स्वाधीनता व समानता की भावना का विकास करना, चुनावों में भाग लेकर श्रमिकों के लाभ के लिए आवश्यक अधिनियम बनवाना और यदि अवसर मिले तो श्रमिकों को सरकार बनाना इत्यादि कार्य इस श्रेणी में आते हैं ।

भारत में श्रम सघ आन्दोलन की प्रगति उद्भव एवं विकास भारतीय श्रम सघ आन्दोलन को अल्पमन की सुविधा की दृष्टि से चार कालों में विभाजित किया जा सकता है—

- 1 श्रम सघ आन्दोलन का प्रादुर्भाव—(1875-1900 ई० तक),
- 2 श्रम सघों की धीमी प्रगति का युग—(1900 से 1918 ई० तक),
- 3 श्रम सघों की तेज प्रगति का युग—(1918 से 1947 ई० तक), तथा
- 4 श्रम सघों की वर्तमान अवस्था—(1947 से अब तक) ।

1 **अर्थ संघ आन्दोलन का प्रादुर्भाव :** अन्य देशों की भांति भारतवर्ष में भी श्रमिक संघ आन्दोलन का जन्म एवं विकास औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप हुआ। सर्वप्रथम सन् 1875 ई० में दम्बई में सोराबजी सापुरजी ने श्रमिकों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकषिप्त किया था। सन् 1884 ई० श्री नारायण मेघाजी लोसाडे ने दम्बई के मजदूरों का एक सम्मेलन बुलाया था तथा उन्होंने ही सन् 1890 ई० में 'बाम्बे मिल हेल्थ एंथोसियेसन' की स्थापना की थी। सन् 1897 ई० में रेलवे कर्मचारियों की एक समिति बनी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में अन्तिम अर्धशताब्दी तक भारतवर्ष में श्रमिक संघों का जन्म एवं प्रारम्भिक विकास हो चुका था। इस समय के श्रम संघ समुचित रूप से संगठित नहीं थे।

2 **श्रम संघों की धीमी प्रगति का युग :** सन् 1905 ई० में स्वदेशी आन्दोलन के फलस्वरूप श्रमिकों में राजनैतिक चेतना का विकास हुआ। फलस्वरूप विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम संघों की स्थापना हुई, जैसे सन् 1903 में 'वेस्टर्न यूनिन कलकत्ता', 1907 में 'पोस्टल यूनिन', 1909 में 'कामगार हितवर्धक मता' और 1910 में 'सोशल सर्विस लीग' आदि की स्थापना हुई। इन श्रमिक संघों के अतिरिक्त 'इण्डियन लेबर यूनिन', 'सोमन यूनिन' आदि श्रम संघ भी संगठित किये गये।

प्रथम विश्व युद्ध में कीमतों की वृद्धि के फलस्वरूप उद्योगपतियों ने बहुत लाभ कमाया, लेकिन मजदूरों में बहुत कम वृद्धि की गई। परिणामस्वरूप श्रमिकों में असन्तोष की भावना फैल गई। सन् 1917 ई० में इस की राजनैतिक भावना ने श्रमिकों को मोरचाह्वित किया तथा श्रम संघों के विकास के लिए सक्रिय वातावरण तैयार किया।

इस काल में श्रम संघों ने केवल वैधानिक तरीकों पर ही ध्यान दिया। वस्तुतः इस समय तक के श्रमिक संघ सही माने में श्रमिकों के संगठन नहीं थे, वरन् श्रमिक नेताओं के संगठन थे जो समाज सुधारक होने के नाते श्रमिकों के कल्याण के लिए तथा श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील थे।

3 **श्रम संघों की तेज प्रगति का युग :** प्रथम महायुद्ध के परिणाम श्रमिक संघ आन्दोलन का विकास बड़ी तेजी से प्रारम्भ हुआ। सन् 1918 ई० में र्ब वाटिया ने मद्रास के सूती-वस्त्र मिल मजदूरों को लेकर 'मद्रास श्रम संघ' की स्थापना की। सूती मिलों में काम करने वाले प्रायः अधिकांश स्थानीय श्रमिक इसके सदस्य बन गए। भारतवर्ष में सम्भवतः श्रमिक संघ आन्दोलन का यह पहला सफल प्रयत्न था। सन् 1920 ई० में श्रम संघों का प्रथम अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन बना जिसका नाम "आल इण्डिया ट्रेड यूनिन कांग्रेस" (All India Trade Union Congress) था। सन् 1922 ई० में तीन महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना हुई—

श्रमिक समिति, बाल इण्डिया रेलवेमें फेडरेशन तथा बाल इण्डिया पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ यूनियन ।

सन् 1921 ई० में व्यापार्य के द्वारा 'मद्रास श्रम-संघ' को अवैध घोषित कर दिये जाने पर श्रमिक नेताओं में असंतोष की छहर फेंक गई । श्री एन० एम० जोशी ने विधान सभा में श्रमिक तथ्यों के लिए वैधानिक संरक्षण की मांग उठाई । सन् 1926 ई० में श्रमिक संघों की संपादेयता को संघसत्ते हुए सरकार ने श्रम-संघ अधिनियम पास किया तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक संघों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई । इस अधिनियम के पारित होने से श्रमिक संघ विकास को बहुत बल मिला ।

सन् 1928 ई० में श्रमिक नेताओं में फूट पड़ जाने के परिणामस्वरूप श्रम संघ दो वर्गों में बंट गया । एक वर्ग का नेतृत्व उदारवादियों तथा दूसरे वर्ग का नेतृत्व उग्र श्रम पथियों के हाथ में चला गया । इस फूट के परिणामस्वरूप श्रमिक आन्दोलन की गति कुछ भिन्न पड़ गई । सन् 1933 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन (National Trade Union Federation) की स्थापना हुई जिसमें सामान्यियों के प्रतिनिधित्व अन्वय दोष सभी श्रमसंघ में सम्मिलित हो गए । सन् 1924 से सन् 1934 ई० तक श्रमिक संघों पर साम्यवादियों का प्रभाव छाया रहा ।

सन् 1933 ई० श्रमिक संघ आन्दोलन में एकता लाने की बहुत कोशिश की गई, किन्तु इसमें सफलता मिलने से पहले ही द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ हो गया ।

4 बर्तमान काल द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त होते ही देश गुलामों की जखीरो में हड़ता हलेशा के लिए मुक्त हो गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् भारत के विभिन्न राजनैतिक दलों ने श्रमिक संघों पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की । सन् 1947 ई० में बलिव भारतीय कांग्रेस पार्टी ने सरकार बलमाई पटेल के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, (I. N. T. U. C.) बनाई । सन् 1948 ई० में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 'हिन्दू मजदूर संघ' (H. M. S.) की स्थापना की । मई सन् 1949 में प्रो० के० टी० साहू के नेतृत्व में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (U. T. U. C.) की स्थापना की गई । साम्यवादियों का बाल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर पहले से ही अधिकार था । इनमें से सबसे बड़ी 'इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (I. N. T. U. C.) है । यद्यपि इसकी स्थापना सन् 1947 में ही हुई तथापि अब इसका प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है तथा केन्द्रीय संस्थानों की कुल सदस्यता में से आधे से भी अधिक इसके सदस्य हैं । इसके बाद साम्यवादियों से प्रभावित 'बाल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (A. I. T. U. C.) है जिसके लगभग ७ लाख सदस्य हैं । इस समय भारत में बलिव भारतीय स्तर पर चार श्रमिक

संगठन पाए जाते हैं, जिनसे सम्बन्धित सघों की संख्या तथा जिनकी सदस्य संख्या का ज्ञान निम्नतालिका से प्राप्त हो सकता है

अखिल भारतीय अर्थ सघों की संख्या (31 मार्च 1968)

केन्द्रीय संगठन का नाम	सम्बद्ध मजदूरों के सघों की संख्या	सदस्यता (लाख में)
1 इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काउंसिल (INTUC)	1165	13.26
2 आल इण्डिया ट्रेड यूनियन काउंसिल (AITUC)	1008	6.35
3 हिन्दू मजदूर संघ (HMS)	248	4.64
4 यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काउंसिल (UTUC)	216	1.26
योग	2637	25.51

सन् 1968 में भारतवर्ष में 584 केन्द्रीय अर्थ सघ तथा 15128 राज्य अर्थ सघ थे जिनमें से सरकार विवरण देने वाले सघों की संख्या क्रमशः 162 तथा 3926 थी। विवरण देने वाले इन अर्थ सघों की सदस्य संख्या क्रमशः 4,04,636 तथा 17,79,211 थी।

अर्थ सघ संघ की कानून अर्थ सघ सम्बन्धी प्रथम अधिनियम सन् 1926 ई० से बना। इसके अन्तर्गत अर्थ सघों को संगठन व हड़ताल का अधिकार दिया गया। सन् 1947 ई० में इस अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इस संशोधन के अनुसार संघोपपत्तियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे अर्थियों के सघों को मान्यता प्रदान करें। सन् 1964 ई० में इस नियम में पुनः संशोधन हुआ, जिसके अनुसार अर्थ सघों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे अपनी रिटर्न कैलेंडर वर्ष के आधार पर भेजें तथा ऐसे पत्रिकाओं को अर्थ संगठन का अधिकारी न बनाए जो नैतिक अवस्था के लिए दण्डित किये गये हों।

अर्थियों सघों से तब अर्थ सघों के स्वतंत्र संगठन का प्रयास देश के औद्योगिक विकास पर बड़ा अनुकूल पड़ता है, जिससे सभी वर्गों को लाभ पहुंचता है, संक्षेप में इस प्रकार है —

(i) अर्थियों में एकता बढ़ती है, (ii) अर्थियों को उचित वेतन भत्ता मिलने लगा है, (iii) अर्थियों की शोषण से रक्षा होती है, (iv) अर्थियों के काम के घण्टे कम व काम की दशा सुधर जाती है, (v) अर्थियों को सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण के अनेकानेक लाभ मिलने लगते हैं, (vi) अर्थ सघ औद्योगिक शान्ति की स्थापना में सहायक होते हैं, (vii) अर्थ सघ उत्पादन में वृद्धि तथा

उत्पादन के स्तरों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, (vii) थमिक सघों की स्थापना से समाज में थमिक वर्ग का स्तर ऊँचा उठ जाता है, (ix) थमिक सघ राजनैतिक क्षेत्र में प्रगति कर थमिकों के हितार्थ कानून बनवाते हैं, (x) थमिक सघों से थमिकों की सामूहिक सोझकारी की शक्ति बढ जाती है ।

थमिक सघों से हानियाँ थमिक सघों के विकास का कई लोथों में विरोध दिया है, क्योंकि इनके से विकास कई प्रकार की हानियों की सम्भावना रहती है, यथा (i) थमिक सघ प्रायः ताथिक सुधार (त्रिवेकीकरण) आदि का विरोध करते हैं, (ii) थमिक सघ हस्तालों को प्रोत्साहित करते हैं, (iii) थमिक सघों के कारण थमिकों में अनुवासनहीनता बढती है, (iv) थमिकों में काम करने के प्रति उन्माह कम हो जाता है, (v) थमिक सघ की रनिमिधियों के कारण ही आज-कल बराह की प्रवृत्ति की बढावा मिलता है, (vi) अलग-अलग राजनैतिक दलों से सम्बन्धित होने के कारण थमिक सघ राजनैतिक तन्माय पैदा करते हैं, (vii) विभिन्न दलों से सम्बन्धित होने के कारण थमिक सघों में पार्टीबादी का बोलबाला हो जाता है तथा पारस्परिक एकता समाप्त हो जाती है ।

थमिक सघों की ये कमियाँ मस्तुत हानियाँ नहीं बही जाती बाहिए, क्योंकि ये हानियाँ उसी समय दृष्टिगोचर होती हैं, जबकि थमिक सघ का नेतृत्व स्वार्थी व दलगत राजनीति में फसे हुये व्यक्तिवों के हाथ में आ जाता है । सघ बात तो यह है कि एक शक्तिशाली थमिक सघ जो स्वस्थ आधार-शिलापर खड़ा हो, किसी भी देश में लिए बरदान स्वरूप है ।

भारतवर्ष में थमिक सघ आन्दोलन की समस्याएँ, कठिनाइयाँ व दोष . यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् तथा मुख्यतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् थमिक सघ आन्दोलन में हमारे देश में बड़ी प्रगति की है तथा इसके थमिकों को बड़ा लाभ पहुचा है, तो भी यदि अन्य देशों के थमिक सघों के विकास की ओर देखा जाय तो एसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में थमिक सघों में उतनी प्रगति नहीं की है जितनी प्रगति इन्हें अमेरिका में । इसीलिए श्री रॉबर्ट्स (Roberts) ने कहा है, 'भारत में थमिक सघ आन्दोलन इतना सुदृढ नहीं है जितना उसे होना बाहिए था ।' प्रसिद्ध थम सघ नेता वी० बी० गिर के विचार भी कुछ इसी प्रकार के हैं, "भारत में थमिक सघ आन्दोलन अभी अपन शोभन काल में ही है ।" अतः अब हम भारतवर्ष में थमिक सघ आन्दोलन की विविध कठिनाइयों व दोषों का विवेकन करेंगे । सध में ये दोष या कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं—

1. थमिकों की प्रभासी प्रवृत्ति भारतीय थमिक स्वभाव से प्रभासी है । वे दूर-दूर के गाँवों से शहरो की ओर कारखानों में काम करने आते हैं और थके जाते

है। वे अपना कार्य और उत्प्रेय भी परिवर्तित करते हैं। फलस्वरूप वह अम-मध के बापों में सम्बन्धित मान नहीं हो सके।

2 श्रमिकों की निर्धनता, भारतीय श्रमिक कम वेतन पाने के कारण निर्धन है। फलस्वरूप वह श्रम सघ का चन्दा देने में असमर्थ है। आवश्यक धनराशि के अभाव में श्रम सघ प्रगति नहीं कर सकते।¹ वित्तीय आधार के कमजोर होने के कारण श्रमिक सघ अपने कर्तव्यों एवं उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते।

3 श्रमिकों की अनिष्ठा एवं अज्ञानता : भारतीय श्रमिक अज्ञात हैं तथा अज्ञानी हैं। वे संगठन एवं अनुशासन के महत्त्व को नहीं समझते, फलस्वरूप श्रम संगठन के कार्य में रुचि नहीं लेते। यही कारण है कि हमारे श्रम सघ उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने कि पाश्चात्य देशों के श्रमिक सघ।

4 काम करने की बहाल शहरी में श्रमिकों को कारखाने व गृहस्थी के कार्यों में इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि संगठन आदि कार्यों के लिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिल पाता। वे सामारणतः कारखानों में 8-10 घण्टे तक काम करके आते हैं और खा-पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार अवकाश का अभाव भी श्रमिक सघों की प्रगति में बाधक सिद्ध होता है।

5 श्रमिकों में एकता की कमी भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म, ज्ञान-पान, रहन-सहन आदि की विभिन्नताओं के कारण श्रमिकों में प्रायः एकता की भावना पाई जाती है, जो संगठन के मार्ग में बाधक है फलस्वरूप हवाई श्रमिक सघ नहीं बन पाते।

6. श्रमिकों में अतीव प्रणाली भारतवर्ष में श्रमिकों की अतीव प्रायः मध्यमवर्ग के द्वारा होती रही है। मध्यमवर्ग श्रमिकों से धन आदि लेकर उन्हें काम खिलाते रहे हैं। ये मालिकों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे हैं तथा मालिकों के इशारे पर श्रमिकों के संगठित होने के रास्ते में रोड़ा बटकाते हैं। जबकि श्रमिक सघों द्वारा प्रत्यक्ष श्रमिक अतीव की व्यवस्था में मध्यमवर्ग का कार्य-व्यवहार समाप्त हो जाता है, इसलिए मध्यमवर्ग ने अपनी स्वायत्तता से प्रेरित होकर श्रमिक सघों के मार्ग में रोड़े बटकाए हैं।

7 मालिकों का विरोध भारत में मिल मालिकों की दमन नीति भी श्रमिक सघों के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। श्रम सघ आन्दो-

1 "Indian workers oppressed by poverty and heavy debt and receiving low wages, have neither the means to pay union subscriptions regularly nor the inclination and leisure to take part in trade union activities."

सन के प्रभाववाली बन जाने पर श्रमिकों को श्रमिकों की भाँसे मानने के लिए विवश होना पड़ता है। फलस्वरूप ये श्रम सघों को संचित तथा अनुचित सभी प्रकार के साधनों से हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं तथा उनके विकास के मार्ग में रोड़े अटकते हैं।²

8 रचनात्मक कार्यों का अभाव भारतीय श्रम सघ अभी अपनी शैक्ष्य अवस्था में होने के कारण केवल सचपत्तिक कार्यों पर ही बल दे रहे हैं। रचनात्मक या कल्याणकारी कार्यों जैसे शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन की ओर उनका ध्यान अभी नहीं गया है जिनके अभाव में ये श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहे हैं।

9 उचित नेतृत्व का अभाव भारतवर्ष श्रमिक सघों के संचालन करने वाले श्रमिक नेता न होकर बाहरी व्यक्ति हैं, जो दलगत राजनीति में लगे हुए हैं और अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए श्रमिकों का मूलतः पथ-प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने एक प्रकार से अपना एकाधिकार कायम कर रखा है तथा कई श्रमिक सघों को एक साथ नेतृत्व करते हैं।⁴

10 जनताधिकार भावना का अभाव बहुत अधिक समय तक सोपन के सिंहावर रहने के फलस्वरूप, भारतीय मजदूर अपनी बला में सुधार के प्रति उदासीन हो गए हैं। इनके अपने अधिकारों के प्रति सजग करना तथा स्वयं जनताधिकार भावना का विकास करना कठिन कार्य है। इसलिए भारतवर्ष में श्रम सघों में जनताधिकार भावना का अभाव पाया जाता है। प्रायः बड़े-बड़े निर्णय श्रमिकों की राय जाने बिना ही ले लिए जाते हैं। इसलिये इन सघों को पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता।

11 पूर्णकालिक एवं वृत्तनिक अधिकारियों की कमी भारतवर्ष में श्रम सघों के कार्यों का संचालन करने वाले लोग श्रमिकों की समस्या की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि न तो उन्हें इस कार्य के लिये वेतन मिलता है और न ही वे इस कार्य के लिए अधिक समय दे पाते हैं।

1. They turn up to scold us (the trade union movement) then try to put it down and lastly, if the movement persists to exist then recognise it.

—N. M. Joshi, Trade Union Movement in India p. 17

2 "The leadership is interested in keeping a sort of leadership monopoly and for that reason perhaps, it has not been able to train up new cadre of leadership that will be able to shoulder the responsibilities of trade union leadership. A good number of leaders are also handling the affairs of several unions simultaneously."

—O. P. Bhatta AICC Economic Review, July 1, 1968

12 **सीमित सदस्यता :** भारतवर्ष में श्रम सघों का आकार बहुत छोटा है। लगभग दोन-चौथाई श्रमिक सघों की सदस्यता 500 से भी कम है। ग्रामीण श्रमिक तो इसकी परिधि के पूरक बाहर हैं। नगरों में भी सभी श्रमिक सघों के सदस्य नहीं हैं। फलस्वरूप श्रमिकों का संगठन दृढ़ नहीं हो पाता तथा वित्तीय आधार भी मजबूत नहीं हो पाता।

13 **राजनैतिक दलों से सम्बन्ध :** भारतीय श्रम सघ किसी भी किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित हैं। इन दलों के विचारों में जमीन आसमान का अन्तर पाया जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसे संगठनों से श्रमिकों की उचित मार्ग दर्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि वे प्रायः अपने बलगत मामलों में ही श्रमिकों की कसाए रखता चाहते हैं।

14 **अनेक ध्येय सघों की समस्या :** भारतवर्ष में एक ही उद्योग या कारखाने में दो या दो से अधिक श्रम सघ पाए जाते हैं जो परस्पर प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। इससे सेवा नियोजकों को लाभ होता है और श्रमिक एकता की कति पहुँचती है। श्रम सघ किसी रचनात्मक कार्य को भी इसीलिये नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें मतभेद नहीं होता है।¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में श्रमिक सघों का विकासदृष्ट आकारों पर नहीं हो सका है। योजना आयोग के दृष्टो से, “श्रमिक सघों की अभावता, राजनीतिक मनमुटाब, सघनों की कमी एवं श्रमिकों में एकता का अभाव, भारत में श्रमिक सघ आन्दोलन की प्रधान त्रुटियाँ हैं।”²

श्रम सघों के स्वस्थ विकास के लिए सुझाव

भारतवर्ष में श्रम सघों के स्वस्थ विकास के लिए निम्न सुझाव दिए जा रहे हैं :

1. एक उद्योग में एक ही संगठन थी बी० बी० पिरि का सुझाव है कि एक उद्योग में एक सघ की भावना का प्रसार किया जाए। यह उद्देश्य सभी पूरा

1. “In our country, the main difficulty in labour assuming constructive and responsible role is the one created by the existence of multiplicity of trade unions”

Shree G. Ramaswami—General Secy., INTUC, AICC Economic Review, July 1, 1968

2. Multiplicity of trade unions, political rivalries, lack of resources and disunity in the ranks of the workers are some of the major weakness in a number of existing unions”

—Planning Commission, Second Five Year Plan

हो सकेगा, जबकि श्रमिक सघों को राजनैतिक दखनदी से छुटकारा मिल जाए। राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा जून 1969 में दी गई अपनी रिपोर्ट में यह मथ प्रकट किया है कि प्रत्येक उद्योग में उसी यूनियन को मान्यता दी जाय, जिसका उस उद्योग में बहुमत हो। जिस उद्योग में 100 भा अधिक कर्मचारी काम करते हों, अथवा एक नियत मात्रा से अधिक पृथी सघों हों उसमें बहुसंख्यक यूनियन ही अधिकारियों से कोई बातचीत या संपर्कता कर सकेगा। श्रम अल्पसंख्यक यूनियन अपने सदस्यों को शिक्षित या बर्खास्तगी आदि के कारण प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। यदि आयोग के इस सुझाव को मान लिया गया तो अधिकारियों की बहुत सी समस्याएँ हल हो जायेंगी। इन्स्टीट्यूट (INTUC) के जनरल सेक्रेटरी, श्री बी० रामानुजम का भी यही मत है कि केन्द्र में केवल एक प्रतिनिधायी श्रम सघ बनाया जाए जिससे सभी छोटे सघ सम्बन्धित हो सकें जिसका नेतृत्व एक योग्य व्यक्ति द्वारा हो।¹

2 अनिवार्य सदस्यता श्रमिक सघ की सफलता उसके आकार पर निर्भर करती है। सभ श्रमिक सघों को प्रभावशाली बनाने के लिये यह प्रयत्न किया जावे कि सभी श्रमिक सघों के सदस्य हो जाए।

3 श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार : श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि वे संघठन के महत्व को समझ सकें और संघठन के कार्य स्वयं कर सकें। शिक्षित हो जाने पर श्रमिक, श्रम सघों के कार्यों के प्रति उदासीन न रहेंगे बल्कि स्वेच्छा से संघटक कार्यों में सक्रिय सहयोग देंगे।

4 योग्य नेतृत्व श्रमिकों का नेतृत्व जहां तक संभव हो, श्रमिकों के हाथ में ही होना चाहिए। श्रमिक नेता यदि श्रमिक वर्ग से ही आएय हों वे श्रमिकों को उचित नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे। योग्य नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

5 रचनात्मक कार्यों को और श्रम श्रम सघों को श्रम कल्याणकारी कार्यों व अन्य ऐसे कार्य भी करने चाहिए जिससे श्रमिकों का शैक्षिक, शारीरिक एवं वित्तीय विकास हो सके। केवल दृष्टान्त भा बेराम तक ही उन्हें अपनी प्रतिनिधियों को सीमित नहीं रखना चाहिए।

1 It is not merely desirable but even necessary to have a single strong national centre for trade unions in the country to which all the unions at the plant level are affiliated so that the trade union movement in the country will be genuine and will have one objective, one method and one leadership which would enable them to march forward in an orderly and disciplined way taking the nation too along with it

6. **अर्थिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था :** अर्थिक आन्दोलन का सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अर्थ संघों का संचालन करने वाले अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। कलकत्ता में अर्थ संघों के सिद्धान्तों के विषय में शिक्षा देने के लिए खोला गया एसिपन ट्रेड यूनिवर्सिटी कालेज इस दिशा में सही कदम है।

7. **सेवायोगजों द्वारा मान्यता :** सेवायोगजों को चाहिए कि वे श्रमिक संगठनों को मान्यता देने में अग्रगण्य न हों, क्योंकि स्वयं अर्थ संघों से संयोजनों के लिए भी इतना ही लाभदायक है जितना कि अधिकारियों के लिए। एक शक्तिशाली अर्थिक संगठन के रहने से औद्योगिक संघों में कमी आ सकती है जिससे उत्पादन में घृष्टि होगी।

8. **पूर्णकालिक एवं सर्वतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति :** अर्थ संघों को अपना कार्य नियमित रूप से चलाने के लिए पूर्णकालिक एवं सर्वतनिक व प्रशिक्षित कार्यकर्ता रखने चाहिए जिसमें विचार-स्वातन्त्र्य उत्साह एवं ईमानदारी के गुण हों।

9. **हड़ताल कोषों की स्थापना :** असिद्ध अधिक नेता श्री बी० पी० गिरि का सुझाव है कि अर्थिक संघ कम्पान कोष व हड़ताल कोष रखें जिससे कि हड़ताल के समय वे संघों अपने सदस्यों को वार्षिक भत्ता दे सकें और उनका नैतिक स्तर बनाए रखें।

10. **जनमत को अनुकूल बनाना :** अर्थसंघों को समय-समय पर अपनी गतिविधियाँ जनता को बताना चाहिए तथा अधिकारियों की मध्यस्थता की ओर जन-साधारण का ध्यान आकषिप्त करना चाहिए, ताकि अर्थिक संघ आन्दोलन को जन-सहयोग प्राप्त हो सके।

11. **दलगत राजनीति से मुक्ति :** अर्थिक संघ आन्दोलन को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि राजनैतिक वातावरण बड़ा घुसित है तथा राजनैतिक दल अधिकारियों की भलाई के बजाय अपना राजनैतिक प्रभुत्व बढाना चाहते हैं। अर्थिक संघ आन्दोलन एक पवित्र संगठन है। अतः इसे दलगत राजनैतिक से दूर बनाया चाहिए तथा केवल अधिकारियों के हितों के लिए ही कार्य करना चाहिए।

12. **लोकतन्त्रीय भावना का विकास :** राजकीय अर्थ आयोग ने अर्थसंघों के स्वतंत्र विकास के लिए यह सुझाव दिया है कि अर्थसंघ लोकतन्त्रीय भावना को संचालित बनाकर अपने कार्यों का संचालन करें। इससे अर्थसंघों को भी कार्य करेंगे उन्हें एकसहयोग प्राप्त होगा।

13. **उचित सरकारी दृष्टिकोण :** सरकार को भी अर्थसंघों के विकास के लिए स्वतंत्र नीति बनानी चाहिए। अर्थसंघों को उचित प्रोत्साहन देना चाहिए।

भाषादेश में लकर इनके प्रति अन्यायपूर्ण पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे उनमें प्रगतिशीलता बढ़ेगी और संगठन बलबोरो हो जायेगा ।

14 सघों की वित्तीय स्थिति सुधारो जाय - भारतवर्ष में श्रमिकों के वेतन को बढ़ाकर उन्हें अपना चन्दा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि सघों के पास अपने कार्य संचालन के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हो जाए ।

15 एकता को भावना का विकास - विभिन्न के द्रीय संस्थाओं से सम्बन्धित धार्मिक सघों को सामान्य लक्ष्यों के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित करके मिलजुलकर कार्य करना चाहिए तथा अपना वार्षिक विरोध समारोह करना देना चाहिए ।

उपरोक्त सुझावों के माध्यम से साथ अनुशासन बढ़ाना व श्रमसघों को मान्यता देने व लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका समुचित रूप से पालन होना चाहिए । योग्यता आयोग ने श्रमसघों के समुचित विरासत के सम्बन्ध में कहा है, "श्रमिक सघों की शारीरिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण को अनिवार्य ठाढ़ कर रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारियां उठाने लिए सैन्य विद्या जाना चाहिए । श्रमिकों में शिक्षा के कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए जिससे सुखा का नतीजा श्रमिकों के हाथ में ही रहे । अनुशासन बढ़ाना व श्रम सघों को मान्यता देने व लिए बनाए गए नियमों का समुचित रूप से पालन होना चाहिए । देश में सर्वोत्तम तथा स्वस्थ श्रम सघ आन्दोलन का विकास के लिए यही आवश्यक है ।"

भारतवर्ष में श्रमिक सघों का स्वस्थ विकास की परमा आवश्यकता है । देश में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए तथा देश में उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिक सघों का विरासत स्वस्थ व उचित दिशाओं में किया जाए । जब तक श्रमिक सघों को हमारे देश में उचित नतीजा प्राप्त नहीं हो सकेगा, हमारे श्रमसघ विकास नहीं कर सकेगें । अब श्रम सघों के लिये निम्नांकित, उपायों, सुझावों, ईमानदार, लक्ष्यशील एवं उत्साही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जिनके नेतृत्व में श्रमसघ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा है ।¹

1. 'Like the cognate field of the co-operative movement in the Indian villages, the labour movement in our cities and towns calls for a devoted band of intellectuals who have to live unknown among the working folk for a long time to organise them and to train them for constructive union work. Correct leadership is essential for a leadership which is not preoccupied to sacrifice the interest of the workers to imported doctrinaire or 'hurry on'."

प्रश्न

1 भारतवर्ष में श्रमिक संघ आन्दोलन के जन्म तथा विकास का विवरण दीजिये। इसकी क्या कमजोरियाँ हैं ?

(राज० प्र० ष०, टी० डी० सी० बला 1964, 1967)

2 भारत में श्रम संघ आन्दोलन के प्रादुर्भाव एवं विकास का वर्णन कीजिये। इसे सुदृढ़ बनाने के लिये क्या किया जाना चाहिये ?

(राज० प्र० ष० टी० डी० सी० बला, 1966)

3 भारतवर्ष में श्रमिक संघों के कार्यों का विवरण करते हुए उनकी कमियों को बतलाइये। इन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत कीजिए।

4 Survey briefly the development of Trade Union Movement in India. What are the main obstacles of their growth?

(Raj B A, 1962)

5 भारतवर्ष में श्रम संघ आन्दोलन (मजदूर आन्दोलन) का संक्षेप में विवरण दीजिए और बताइए कि भारत में मजदूरों का संगठन बल क्यों नहीं है ?

(Raj B A, Hons, 1967)

6 Discuss the growth of the Trade union Movement in India and point out its main weaknesses ? (R A S 1968)

भारत में सामाजिक सुरक्षा

(Social Security in India)

"Each country must create, conserve and build up the intellectual, moral and physical vigour of its active generation, prepare the way for its future generation that has been discharged from productive life. This is social security, a genuine and rational economy of human resources and values."

First Inter-American Conference on Social Security

सोशलीकरण एवं सहरीकरण के परिणामस्वरूप आधुनिक समाज का जो स्वरूप हमारे सामने उभर रहा है, उसमें परम्परागत भारतीय समुक्त परिवार प्रथा प्रायः लुप्त होती जा रही है। अब परिवार का क्षेत्र संकुचित होकर स्त्री-वस्त्रों तक ही सीमित रह गया है। समुक्त परिवार व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को जो कुरे दिने ने असह्य अवस्था का अनुभव नहीं होता था, किन्तु अब ऐसी बात नहीं रह गयी है। आज बीघकाभीन बीमारी, वृद्धावस्था, बेकारी, अश्वयंता व मृग्यु जैसी सबटापन्न अवस्थाओं में धर्मिकों व उनके परिवारों की देखभाल करने वाला चलन समुक्त परिवार नहीं है। आज इन अवस्थाओं में धर्मिकों की रक्षा का भार समाज अपना राष्ट्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है।

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ एवं परिभाषा

सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज अपनी प्रतिनिधि मस्था, राज्य के द्वारा अपने सदस्यों को उनके जीवन में आने वाली बेकारी, बीमारी, दुर्घटनाओं, औद्योगिक रोग, प्रसूति अपरधा, वृद्धावस्था, परिवार में जीविका आने वाले की मृग्यु आदि आर्थिक विघातों से उनकी रक्षा करने तथा एक वाछनीय आर्थिक, शारीरिक एवं नैतिक स्तर को बनाये रखने के हेतु प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा विभिन्न व्यक्तियों एवं मस्थाओं ने इस प्रकार की है :

(i) अन्तर्राष्ट्रीय असंघ के अनुसार. "सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है, जो

समाज के किसी संपूर्ण संगठन द्वारा अपने सदस्यों को उन अनिश्चित खतरों के लिए, जिनसे वे कभी भी प्रभावित हो सकते हैं।¹

(ii) सर विलियम बेवरिज के शब्दों में, “सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय पाँच दानों—अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गन्दगी और बेकारी—के ऊपर आक्रमण है।”

(iii) श्री मॉरिस स्टैंक के शब्दों में, “सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय हम समाज द्वारा दी गई उस सुरक्षा की समझने है, जो कि आधुनिक जीवन से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक विपत्तियों, जैसे बेकारी, वृद्धावस्था, परावलम्बन, औद्योगिक दुर्घटना तथा अप्रगता के विरुद्ध प्रदान की जाती है, जिनसे अपने तथा अपने परिवार की अपनी क्षमता या दूरदर्शिता के आधार पर रक्षा करने की आशा एक व्यक्ति से नहीं की जा सकती।”²

मर्सेरी हेबर तथा फाहेन ने सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है, “सामाजिक सुरक्षा जनता की आर्थिक कठिनाइयों से रक्षा करने के लिए लगातार स्थापित तथा सतत प्रयत्न है, जिनके अभाव में बीमारी, बेरोजगारी अथवा वृद्धावस्था में तथा मृत्यु के संभाव्य आय में बाधा पड़ती, जिनसे बिक्रिया सम्बन्धी सुविधाएँ तथा परिवारों में बच्चे के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता उल्लब्ध हो जाती है।”³

1 Social security is the security that society furnishes through appropriate organization against certain risks to which its members are exposed
— *Approaches to Social Security* I L O p 83

2 'Social security is an attack on five giants: VIZ Wants Disease Ignorance, Squalor and Idleness
— *Sir William Beveridge*

3 'By Social Security we understand a programme of protection provided by society against those contingencies of modern life—sickness unemployment, old age dependency industrial accidents and invalidity—against which the individual cannot be expected to protect himself and his family by his own ability or foresight
— *Maurice Stuck*

4 'Social security is the result achieved by a comprehensive and coordinated series of measures for providing the public (or a large sector of it) from the economic distress that in the absence of such measures could be caused by the stoppage of earnings in sickness, unemployment or old age and after death for making available to that same public medical care as needed, and for subsidizing families bringing up young children'

— *Haber and Cohen. Readings and Social Security*, 74

प्रो० कोल के शब्दों में, "सामाजिक सुरक्षा का अर्थ यह है कि सरकार जो समाज का प्रतीक एवं प्रतिनिधि है अपने समस्त नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन-स्तर कायम करने के लिए उत्तरदायी है। इस स्तर में जीवन से लेकर मरण तक की मारी मुविधायें एवं आवश्यकताएँ सम्मिलित होगी।"¹

सामाजिक सुरक्षा के रूप

सामाजिक सुरक्षा के मुख्यतः दो रूप हैं—(i) सामाजिक बीमा, तथा (ii) सामाजिक सहायता। सामाजिक बीमा के अन्तर्गत सहायता पाने वाले व्यक्ति को सम्य-समय पर असेशन के रूप में योगदान देना पड़ता है जैसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना आदि। सामाजिक सहायता के अन्तर्गत लाभ पाने वाले व्यक्ति को कोई असेशन नहीं देना पड़ता। सहायता के रूप में तब की जाने वाली कुल धन राशि सरकार अपने खजाने से व्यव करती है, जैसे—पूजापस्था पैशन, पारिवारिक भत्ता, आदि।

सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत जिन सुरक्षाओं अथवा मुविधायों को सम्मिलित किया जाता है, वे हैं, (i) अश्वस्थता के समय चिकित्सा का प्रबंध, (ii) कार्य करते समय थोटा लगने पर निश्रिमा एवं मुद्रा लाभ, (iii) अश्वस्थता के समय भ्रमकाश एवं भेदन छाय, (iv) मातृत्व काल में भ्रमकाश अथवा चिकित्सा मुविधा एवं मुद्रा लाभ, (v) प्रसूति के समय भ्रमकाश एवं भेदन, (vi) वृद्धापस्था देखभाल, (vii) मृत्यु होने पर अन्तिम सम्पत्ति सम्बन्धी व्यय, (viii) आश्रितों को लाभ, (ix) बेकारी के समय आवधिक सहायता, तथा (x) पारिवारिक भत्ते परिवार के बच्चों के लिए आदि। संक्षेप में सामाजिक सुरक्षा उचित गठन द्वारा सदस्यों की गर्भ से मृत्यु तक रक्षा करती है।²

सामाजिक सुरक्षा की भारतवर्ष में प्राप्ति

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता विश्वी देशों की अपेक्षा भारत में कहीं अधिक है। भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा का महत्व इसलिए अधिक है, क्योंकि (i) भारतीय व्यक्ति बहुत निर्धन है और निर्धनता के कारण अपनी सुरक्षा

1 The idea of social security is that the State shall make itself responsible for ensuring a minimum standard of material welfare to all its citizens on a basis wide enough to cover all the main contingencies of life of an individual from birth to death.
—D G H Cole

2 Social security saves up members from work to the same the high appropriate organisations.

स्वयं नहीं कर सकते, (ii) भारतीय श्रमिक अधिष्ठान एवं रुढ़िवादी हैं तथा भविष्य के बारे में ध्यान नहीं दे पाते, (iii) भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाय, (iv) भारतीय श्रमिकों व उद्योगपतियों के सम्बन्ध मधुर नहीं है उन्हें मधुर करने के लिए तथा औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए, (v) भारत में श्रमिकों में मृत्यु दर बहुत ऊँची है, इसे कम करने के लिए, (vi) भारतीय मजिधान में शिकारी मुद्दाबन्ध, रोग तथा अंग भंग के झहझरो के लिए अधिक बग के लिए सरकारी महाश्रुता जो मान्यता प्रदान की गई है। राक्षस में, सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों के जीवन की मुखी और मध्य न बनायेगी और वे औद्योगिक केन्द्रों में स्थायी रूप से बस जायेंगे। इससे औद्योगिक मध्यम तम होग तथा आर्थिक व सामाजिक विषमता घटेगी।

भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षा के दान में भारत इतनी प्रगति नहीं कर सका है जितनी कि संसार के अन्य उद्योग प्रधान देशों ने की है। इस समय भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा को जो व्यवस्था है, उसका अध्ययन हम निम्नलिखित अनुच्छेदों में करेंगे।

1 श्रमिक क्षतिपूर्ती अधिनियम, 1913 (Workmen's Compensation Act 1913) भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भ इसी अधिनियम से लागू होने से माना जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवायोजकों की मजदूर के काम करते समय घोट आ जाने पर या काम से सम्बन्धित बीमारियों से पीड़ित होने पर मुआवजा देना पड़ता है। इसके लिये यह जरूरी है कि श्रमिक ने सम्बन्धित कारणों में 6 महीने से अधिक कार्य किया हो अथवा दस दिन से अधिक हो तथा घोट लगने में श्रमिक की स्वयं कोई त्रुटि न हो। यह नियम बड़े बड़े कारखानों में लागू होता है जिन्हें 500 रु० से अधिक परिश्रमिक नहीं गिनता तथा रोजगार आकस्मिक नहीं है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, मृत्यु, स्थायी एवं पूर्ण असमर्थता स्थायी-वास्तविक असमर्थता एवं अस्थायी असमर्थता के लिए विभिन्न दरों से क्षतिपूर्ति निर्धारित की गयी है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर क्षतिपूर्ति की रकम उनके आश्रितों को दी जाती है। इस अधिनियम में अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। वर्तमान समय में मृत्यु की दशा में क्षति पूर्ति की रकम 500 रु० से 4,500 रु० तक दी जाती है। पूर्ण अपंगता की स्थिति में हरजाने की

रकम 700 रु० से लेकर 6,300 रु० तक होती है। श्रमिकों की क्षतिपूर्ति की रकम, उनकी औसत मजदूरी और दुर्घटना की सम्भोरता पर निर्भर करती है। आर्थिक अथवा हानि की स्थिति में क्षतिपूर्ति की विभिन्न मात्राओं, हानि के अनुपात में भी जाती है। सन् 1948 में वर्तमान राज्य बोमा योजना के लागू होने से अब जिन उद्योगों में यह योजना लागू हो चुकी है, वहाँ में श्रमिक क्षतिपूर्ति नियम हटा दिया गये हैं।

आलोचना श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में कई दोष हैं, जैसे (i) इसका क्षेत्र अत्यन्त सीमित है, बहुत से व्यवसाय इसके अन्तर्गत नहीं आते, (ii) क्षतिपूर्ति देने से बचने के लिए भ्रष्टाचार प्रवर्तन करते हैं, (iii) क्षतिपूर्ति की रकम एक मास मिला देने के कारण श्रमिक या परिवार के लोभ कुछ ही दिनों में खर्च कर डालते हैं, (iv) श्रमिक दुर्घटनाओं की सूचना कई बार नहीं देने, (v) श्रमिक अधिक्षित व निर्धन होने के कारण शालिर के हजाना न देने पर शान्ति कार्यवाही नहीं कर पाने, (vi) श्रमिक अधिक्षित होने के कारण बरत कानूनी अधिकारों को नहीं रक्षते, (vii) कर्मचारियों प्रशासनिक अधिकारों सामलों के निरन्तरता में देर लगा देते हैं, तथा (viii) इन अधिनियम का क्षेत्र भी बहुत सन्कुचित रहा है क्योंकि इसमें बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे आदि जोखिमों की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

2 मातृत्व हित लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Acts) भारत-भर में सन् 1961 में पहले मातृत्व या प्रसूति लाभ कानून की कोई केन्द्रीय अधिनियम नहीं था, जो सभी श्रमिक श्रेणियों पर लागू होता है। प्रांतों सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में अधिनियम पारित किये थे, पर उनमें एकस्यता का अभाव था। सर्वप्रथम यम्बई प्रांत में 1929 में, मातृत्वहित लाभ अधिनियम पारित हुआ था। बाद में मद्रास प्रदेश में 1930 में, बंगाल में 1934 में मू. पी. ने 1938, बंगाल में 1939 में पंजाब में 1943 में, मद्रास में 1944, बिहार में 1945 में और छत्तीसगढ़ में 1952 में तथा उड़ीसा में राजस्थान में 1953 में मातृत्वहित-लाभ अधिनियम पारित किये। भारत सरकार ने 1941 में यान में काम करने वाली स्त्रियों के लिये, 1948 में वर्तमान राज्य बोमा योजना के अन्तर्गत तथा 1951 में बायोमेट्रिक श्रमिकों के लिए मातृत्व हित लाभों की व्यवस्था की।

यह अधिनियमों में एकरूपता का अभाव है। इनके क्षेत्र, लाभ पाने वाली स्त्रियों, पात्रता अवधि आदि में भिन्नता पाई जाती है। भारत सरकार ने इन अनेक अधिनियमों में एकरूपता के लिए 1961 में मातृत्वहित-लाभ अधिनियम पारित

कोषकर), जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तथा विद्युत का प्रयोग होता है। इस योजना के अन्तर्गत अब वे सभी श्रमिक व कर्मचारी लाभ के अधिकारी हैं जिनकी मजदूरी 500 रुपये प्रति मास तक है। ठेके पर काम करने वाले श्रमिक भी अब इस योजना की परिधि में आ जाते हैं।

(अ) प्रशासन : इस योजना का प्रबन्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम करता है, इस निगम में 38 सदस्यों पर आधारित एक प्रबन्ध समिति है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, कोषधर्मा, नियोजकों, कर्मचारियों तथा चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह समिति ही निगम का प्रबन्ध करती है। केन्द्रीय श्रम-मन्त्री इस प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री उपाध्यक्ष होता है। निगम का कार्य चलाने के लिए दो समितियाँ होती हैं (क) चिकित्सा परिषद जिसमें चिकित्सा सम्बन्धी विशेषज्ञ होते हैं और इनका नाम चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श देना होता है तथा (ख) स्थायी समिति जो सामान्य प्रशासन व निर्देशन का कार्य करती है।

(इ) वित्त व्यवस्था एवं अशदान : इस अधिनियम के अन्तर्गत 'कर्मचारी राज्य बीमा निधि' बनाई गई है, जिसमें मजदूर मालिकों का अशदान तथा अन्य सूची में प्राप्त अनुदान शामिल हैं। जिन श्रमिकों को प्रतिदिन 1 रुपये में कम मजदूरी मिलती है उन्हें कोई अशदान नहीं देना होता। जिन श्रमिकों की औसत मजदूरी 1 रुपये से 1.50 रुपये के बीच में है उन्हें 12 पैसे देने पड़ते हैं तथा 8 रु० या इससे अधिक मजदूरी पाने वालों को 1.25 रु० अशदान के रूप में देना पड़ता है। यह श्रमिकों द्वारा दिये जाने वाले अशदान की अधिक से अधिक वसूलाई है। मालिक सबसे कम वेतन पाने वाले श्रमिक के लिए 44 पैसे तथा सबसे अधिक वेतन पाने वाले श्रमिक के लिए 2.50 रु० के हिसाब से चन्द देता है।

निम्नलिखित तालिका में श्रमिकों व मालिकों द्वारा दिये जाने वाले अशदान की विस्तारिता ममा है

श्रमिकों का औसत दैनिक वेतन	श्रमिकों का औसत अशदान	मालिकों का अशदान	कुल अशदान
1.00 रु० से कम	—	0.44	0.44
1.00 रु० से 1.50 रु० तक	12	0.41	0.56
1.50 रु० से 2.00 रु० तक	0.25	0.50	0.75
2.00 रु० से 3.00 रु० तक	0.37	0.76	1.13
3.00 रु० से 4.00 रु० तक	0.50	1.00	1.50
4.00 रु० से 6.00 रु० तक	0.69	1.37	2.06
6.00 रु० से 8.00 रु० तक	0.94	1.87	2.81
8.00 रु० से अधिक	1.25	2.50	3.75

योजना काल के प्रथम 5 वर्षों के कुल प्रशासनिक व्यय का $\frac{2}{3}$ भाग वेंग्रीय सरकार ने तथा $\frac{1}{3}$ भाग राज्य सरकारों ने दिया था। अधिको को बीमारी अथवा मातृत्वहित लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्होंने कम से कम 26 सप्ताहों तक चन्दा दिया हो।

(ई) योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ द्रुप योजना के अन्तर्गत अधिकों व उनके परिवारों को निम्नांकित 3 प्रकार के लाभ प्राप्त होने हैं :

1. बीमारी लाभ (Sickness Benefit) : बीमारी अधिक को, निगम के डाक्टर के प्रमाण-पत्र पर 56 दिनों तक का बीमारी सम्बंधी लाभ मिल सकता है। बीमारी के अवकाश के समय प्रथम दो दिन को छोड़कर बाद के दिनों में मजदूरी का $\frac{1}{2}$ भाग बीमारी लाभ के रूप में दिया जाता है। अब, कोड सैनिक व अन्य बीमारियों की स्थिति में 309 दिनों के लिए बीमारी की विस्तृत सहायता मिलती है।

2. चिकित्सा लाभ (Medical Benefit) : बीमारी अधिक व उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है। साधारण चोट अथवा बीमारी के अतिरिक्त अब क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मानसिक रोग आदि की भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है।

3. प्रसूती-लाभ (Maternity Benefit) : प्रसूती स्त्री-अधिक को बारह $\frac{1}{2}$ के लिए नई सहायता दी जाती है। यह वन राशि या तो बीसत मजदूरी की दर से मापी, अथवा 75 पैसे, जो जो अधिक हो, की दर से दी जाती है।

4. अयोग्यता लाभ (Disablement Benefit) : यह लाभ अधिको को बुर्सेटना या चोट की हाजिरी में दी जाती है। स्थायी असमर्थता की शर्त में बीमारी मजदूर को नई बीमारी साप्ताहिक मजदूरी का भाग बीमारी-अयोग्यता दिया जाता है। स्थायी असमर्थता के लिए, असमर्थता की अवधि तक इसी दर से लाभ मिलता है। आंशिक असमर्थता की अवस्था में लाभ असमर्थता के स्थायित्व के अनुसार क्षति-पूर्ति प्रतिनिधियों की दरों के अनुसार दिया जाता है।

5. आश्रित लाभ (Dependent's Benefit) : कारखाने में काम करने के समय यदि बीमारी अधिक की मृत्यु हो जाती है तो अधिक के आश्रितों को आंशिक सहायता दी जाती है। मृतक अधिक की विधवा को अपने जीवन भर के लिए या पुनः शादी करने तक पूर्ण दर ($\frac{1}{2}$ भाग) का $\frac{1}{2}$ दिया जाता है। प्रत्येक आश्रित पुत्र व पुत्री को पूर्ण दर का $\frac{1}{2}$ भाग आश्रित लाभ के रूप में दिया जाता है।

बच्चों को यह लाभ 15 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है लेकिन यदि वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हों तो यह लाभ 18 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है।

(3) योजना की प्रगति यह योजना सर्वप्रथम फरवरी 1952 में दिल्ली व जालपुर में लागू हुई। धीरे धीरे इस योजना का विस्तार किया गया। जनवरी 1953 में इसे बम्बई में चालू किया गया। तोपरी योजना के अन्तर्गत इस योजना में सम्मिलित 30 लाख अधिकारी को लाने में सहाय्य रखा गया था तथा उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाना था जहाँ 100 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों। 31 मार्च 1972 तक 39.76 लाख अधिकारी को 318 औद्योगिक क्षेत्रों पर इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त हुए।

आलोचना राजकीय बीमा योजना में कई दोष भी पाये जाते हैं, जैसे (i) इस योजना का दायित्व सीमित है, (ii) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं अपर्याप्त हैं, (iii) अवकाश लाभ की अवधि कम है, (iv) वायव्य शास्त्रों का अभाव है, (v) छोटे उद्योग प्रायः नियमों को अवहेलना कर जाते हैं, (vi) लाभ कुछ महत्वपूर्ण जोखिमों तक ही सीमित है, तथा (vii) सहायता की मनराशि अपर्याप्त है।

4 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (Employees Provident Fund Act, 1952) सन 1952 ई० में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम पारित हुआ था। पहले इसे 6 प्रमुख उद्योगों सीमेंट, विगरेट, इन्जीनरिंग लोहा व इस्पात कागज तथा वस्त्र उद्योग में लागू किया गया। बाद में यह अधिनियम अन्य उद्योगों पर भी लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारियों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि के लाभ की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम उन्नत उद्योगों के उन कारखानों में लागू होता है जिनमें स्थापित हुए 3 वर्ष हो चुके हों तथा अधिकारियों की संख्या 50 या इससे अधिक है। यह अधिनियम उन कारखानों में भी लागू होता है जिनमें 3 वर्ष पूरे हो गये हों तथा जिनके अधिकारियों की संख्या 20 से अधिक तथा 50 से कम है।

इस योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मूल (दूरी व महगार्द मत्ता मिलानर) हजार 8 या इससे अधिक न हो तथा जिनको 1 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो अथवा 12 महीने या कम की अवधि में 240 दिन वस्तुतः कार्य किया हो। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी को 6% प्रतिशत की दर से तथा कर्मस्थान के मालिकों को भी इसी दर से बन्दा देना पड़ता है। 30 सितम्बर 1969 तक 81 उद्योगों में अदायग की दर बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई। 15 वर्ष की नौकरी के बाद, कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर मूल्य हो जाने, रखाई

सम्बन्धित एक स्थाई योजना बनाई जानी चाहिए; (viii) भविष्य निधि को एक वैधानिक पेंशन योजना में परिणत कर दिया जाना चाहिए, तथा (ix) न्यूनतम मजदूरी नीति खोद्योतिशील बनाई जाना चाहिए।

धन पर राष्ट्रीय आयोग के अनुसार अगले कुछ वर्षों में धमिकों के असमान वृद्धि भी बृद्धि करके कुछ और जोड़िये सम्मिलित की जा सकती है। काम पर लगे हुए, बेकार हो जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयोग ने बेरोजगारी बीमे का सुझाव दिया है।

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात हो जाता है कि भारत सरकार ने धमिकों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इस दिशा में होने वाले कार्य अभी तक अपर्याप्त है। अभी तक जो भी सुविधाएँ दी गई हैं, वे अलग-अलग कानूनों के अन्तर्गत हैं जिससे इनमें दोहराव पाया जाता है तथा कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वस्तुतः भारत में एक ही सस्था के अधीन विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के एकीकरण की आवश्यकता है क्योंकि एक ओर तो मितव्ययता बढ़ेगी तथा दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को सम्मिलित विकास कार्यक्रमों के साथ सम्बन्धित किया जा सकेगा। एक अर्द्ध-विकसित देश होने के नाते सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सुविधा दिलाने में व्यापक कार्यक्रम नहीं अपना सक्ता।¹ तथापि इसे अपने उपलब्ध साधनों का उपयोग सामाजिक सुरक्षा के कार्यों में इस प्रकार करना चाहिए कि इससे धमिकों की अधिकधिक सुरक्षा प्राप्त हो।

जब तक देश के भूमि निर्धन, अभाव-ग्रस्त, समस्या-ग्रस्त, रोग-ग्रस्त, तथा भुजमरी के शिकार बने रहें, जब तक न तो हमारी औद्योगिक प्रगति हो सकेगी और न ही देश का आर्थिक विरास सम्भव हो सकेगा। अतः सर विलियम बेवेंगन द्वारा वर्णित, अभाव, बीमारी अज्ञानता, गरीबी एवं बकारी नामक पाँचो खानों पर आक्रमण कर विजय पाना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए।

प्रश्न

1 भारत में धमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है, उसकी 'सोवनामय' व्याख्या कीजिये। भारत में सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को व्यापक बनाने के लिए अपने सुझाव भी दीजिए।

1. "A poor underdeveloped country cannot, in the early stages of economic development, really afford much of the type of redistributive measures which in advanced countries are known under the label of 'Social Security'.

2. 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम' के प्रावधानों का बालोचनात्मक विवेचना कीजिए ।'

3. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

(ख) मातृत्व हित-लाभ अधिनियम

(ग) श्रमिक सतिपूर्ति अधिनियम, 1923

4 भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिये ।

१. सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं ? भारत सरकार ने सन् 1923 से सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कौन-कौन से कदम उठाये ?

(राज० टी. डी. सी. प्रथम वर्ष, 1970)

खण्ड पाच

- 1. भारत का विदेशी व्यापार**
India's Foreign Trade
- 2. विदेशी सहायता**
Foreign Aid

Alonso Jimenez

भारत का विदेशी व्यापार

(India & Foreign Trade)

"What is prudence in the conduct of every private family can scarcely be folly in that of a great kingdom. If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it from them with some part of the produce of our own industry employed in a way in which we have some advantage."

—Adam Smith

वर्तमान युग में विश्व के किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी व्यापार की अनति अत्यन्त आवश्यक है। पहले तैयारी देश स्वावलम्बन प्राप्त करता अच्छा समझते थे, लेकिन अब वह स्थिति नहीं रही है। लोग विदेशी व्यापार के महत्व एवं गुणों से उत्तरोत्तर प्रभावित होते जा रहे हैं। आज बहुत सी वस्तुएँ हैं, जो एक देश द्वारा पैदा नहीं की जाती हैं, क्योंकि प्राकृतिक एवं अन्य कारणों से उन्हें उचित लागतों पर पैदा करना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में विदेशी व्यापार के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर सम्बन्धित देश लाभ उठा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय धन विभाजन विनिष्पन्न एवं विनिमय के आर्थिक लाभों को पाने के लिए विदेशी व्यापार को विकसित किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक स्रोतों के समुचित शोषण के लिए देश के औद्योगीकरण का बड़ा बाधा देने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्भावना बढ़ाने के लिए, दुर्लभ विदेशी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देश के उत्पादकों को उत्पादन विधियों में सुधार लाने की प्रेरणा देने के लिए, आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता आने के लिए एवं मकट काल की स्थिति में पारस्परिक सहायता प्रदान करने के लिए भी विदेशी व्यापार का पर्याप्त महत्व है।

भारत के विदेशी व्यापार का इतिहास

भारतवर्ष अतीत काल से ही अपने विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। बहुत हीन काल में भी, भारत ने अनेक तत्कालीन सभ्य देशों से अपने व्यापारिक सम्बन्ध

बना रखे थे। भारत से मिय, रोम, चीन, अरब आदि देशों को सुती वपटा धातु के बर्तन, सुगन्धित द्रव, गरम मसाला, हथौड़ी दात, हथियार, ग्य एवं वस्त्रात्मक सामान जैसी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इनके बदले में हमारा देश सामान्यतः पीतल, तांबा, टीन, सोडा, सरसब, घोड़ों आदि का आयात करता था। हमारे निर्यात, आयात से अधिक होते थे, जिसके फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन (Balance of trade) हमेशा ही हमारे पक्ष में होता था। व्यापार सन्तुलन की अनुकूलता के कारण हमें सोना-चाँदी जैसी बहुमूल्य धातुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती थी।

विभिन्न देशों में की गई खुदाई और उनमें बाई गई वस्तुओं से यह प्रमाणित होता है कि ईसा से 300 वर्ष पहले भी भारत से सीपियो, बर्तनों तथा अन्य कई वस्तुओं का निर्यात मिस्र, ईराक तथा ईरान को नियमित रूप से किया जाता था। मुगल काल में भी भारत का पश्चिम में योरोप के कई देशों के साथ तथा पूर्व में चीन के साथ व्यापार निरन्तर चलता था। योरोप के कई देशों ने अपनी व्यापारिक कंपनियों भारत में स्थापित की थी, जो भारत से सूती वस्त्र, मसाले आदि बहुत बड़ी मात्रा में ले जाती थी। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल तथा नीदरलैंड के व्यापारी भारत में व्यापार के लिए सदैव तालाबित रहते थे। मुगलों के पतन के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी (East India Company) का आपिपत्य स्थापित हुआ। ईस्ट इण्डिया कंपनी भारतवर्ष से सूती कपड़े, मसाले तथा मसाले इंग्लैंड को निर्यात करती थी।

मठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक-क्रान्ति ने भारत के विदेशी व्यापार को बहुत प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय विदेशी व्यापार का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। सन् 1857 के बाद ईस्ट इण्डिया कंपनी का ह्रासो न भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई। ब्रिटिश हिंदो की रक्षा के लिए औद्योगिक क्रान्ति से इंग्लैंड को पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए, विदेशी सरकार ने समय-समय पर जो नीतिमा अपनाई उनका स्पष्ट परिणाम यह निकला कि भारत इंग्लैंड के निमित्त भारत का सामान करने वाला तथा कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बन गया। अन्तीमवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रेलों के विकास ने इन प्रवृत्तियों को और भी अधिक बढ़ावा दिया।

दोसवीं शताब्दी में भारत के विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक (सन् 1914 ई. तक) भारत का विदेशी व्यापार सदैव ही भारत के अनुकूल रहा, तथापि इसकी संरचना की देखने से यता चलता है कि यह प्रगतिशील दिशा में नहीं बढ़ रहा था। आयातों से पहले इंग्लैंड का

उपनिवेश होने के कारण भारत का विदेशी व्यापार भी औपनिवेशिक ही था। भारत योरोप के औद्योगिक देशों, विशेषकर इंग्लैण्ड को कच्चे माल तथा साधानों का निर्यात करता था तथा विदेशों से, विशेषकर इंग्लैण्ड से घनी हुई सामग्री का आयात करता था। निर्यात माल के निरन्तर आयात का प्रभाव हमारे देश के आर्थिक विकास पर बहुत प्रतिकूल पड़ा, क्योंकि इसके कारण भारत का औद्योगीकरण सही दिशा में नहीं हो सका। देश कृषि अवस्था में रह कर ही आधुनिक आर्थिक प्रगति को दौड़ में बिछड़ गया। यही नहीं बल्कि सदियों से चले आ रहे हस्त-शिल्प का भी पतन हो गया, जो किसी समय विश्व में भारत की प्रसिद्धि का कारण था।

वस्तुतः स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व यद्यपि व्यापार जब आसतौर पर हमारे अनुकूल था, तथापि यह समय भारत की समृद्धि का नहीं था। क्योंकि सस्ते दामों पर हमारा कच्चा माल विदेशों को भेजा जाता था, जो स्वयं हमारे अपने औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत का विदेशी व्यापार

पन्द्रह अगस्त सन् 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया। उस समय यह आशा की गयी कि देश के विदेशी व्यापार में समुचित वृद्धि की जा सकेगी तथा भूगतान संतुलन की गत दो वर्षों से चली आ रही प्रतिकूलता समाप्त की जा सकेगी। लेकिन आजादी मिलने के साथ-साथ देश का विभाजन हुआ और कुछ ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ उपस्थित हो गईं कि यह आशा पूरी न की जा सकी। देश के विभाजन के फलस्वरूप देश में साधानों तथा जूट व कपास की बहुत अधिक कमी हो गई थी। जिस कारण इनका आयात करना आवश्यक हो गया था। सितम्बर, सन् 1949 में इंग्लैण्ड ने अपनी मुद्रा अक्षमत्वित कर दी। विवश होकर भारत को भी अपनी मुद्रा का 30.5 प्रतिशत से अक्षमत्वित करना पड़ा। इनके आयातों में गमी हुई तथा निर्यातों में गड़बड़ी हुई। इनसे होने के बावजूद भी हमारे विदेशी व्यापार की प्रतिकूलता समाप्त न की जा सकी। इससे बड़ी अवस्था हो गई, परन्तु अवसम्पदन का प्रभाव अधिक समय तक प्रभावशाली न रहा। सन् 1950 तक हमारा विदेशी व्यापार अनियोजित व्यापार पर ही चलता रहा। सरकार ने यद्यपि इस अवधि में निर्यातों को बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए, अपनी आयात व निर्यात नीतियों से भी समय-समय पर कई परिवर्तन किये तथा विश्व के प्रायः सभी प्रमुख देशों में व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किए एवं व्यापारिक शिष्ट मंडल गेजे, तथापि व्यापार संतुलन की प्रतिवृत्ता बनी रही। सन् 1949-50 में व्यापार संतुलन 80.9 करोड़ रुपये में प्रतिकूल था।

पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी व्यापार

सन् 1951 ई० से भारत ने अपनी विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए तथा देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया। तब से अब तक तीन पञ्चवर्षीय तथा तीन अष्टवर्षीय योजनाएँ क्रियान्वित की जा चुकी हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत, भारत के विदेशी व्यापार की ओर प्रगति हुई है, उसका अध्ययन हम नीचे के अनुच्छेदों में करेंगे।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में पूर्ण संचित षोण्ड पावने की उपलब्धि, मुख्य-स्तर में सुधार तथा योजना के अन्तिम तीन वर्षों में लालाओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण व्यापार संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ तथा प्रतिकूलता की मात्रा में कमी हुई। प्रथम योजनाकाल में भारत के कुल आयात 3,650.5 करोड़ रुपये तथा कुल निर्यात 3108.6 करोड़ रुपये के हुए अर्थात् औसतन प्रति वर्ष 730 करोड़ रु० के आयात तथा 622 करोड़ रुपये के निर्यात हुए। व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता योजना के पांच वर्षों में औसतन 108 करोड़ रुपये रही।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में आयात, निर्यात व व्यापार-क्षय की विपति का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है

प्रथम योजना काल में आयात निर्यात व व्यापार क्षय (करोड़ रु० में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार-क्षय
1951-52	962.9	730.1	- 232.8
1952-53	633.0	601.9	- 31.1
1953-54	591.8	539.7	- 52.1
1954-55	689.7	596.6	- 93.1
1955-56	773.1	640.3	- 132.8
	3650.5	3108.6	- 541.9
वार्षिक औसत	730	622	- 108

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में विकास की गति तीव्र हो गई। परिणाम-स्वरूप आयातों में वृद्धि हो जाना स्वाभाविक था। द्वितीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए मशीनों, यन्त्रों एवं कच्चे पदार्थों का बड़ा पैमाने पर आयात किया गया। दूसरी योजना में निर्यातों को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाये गये,

परन्तु निर्यातों में विशेष वृद्धि न की जा सकी। इसके कई कारण थे, जैसे (1) हमारी घरेलू मांग की अविकसितता के कारण, हमारे निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में निर्यात-पदार्थ उपलब्ध न हो सके, (2) विदेशी बाजारों में हमारे माल की मांग पर्याप्त नहीं थी, तथा (3) हमें इस काल में विदेशों से बड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ा था। द्वितीय योजनाकाल में भारत के कुल आयात 5402.6 करोड़ रु० तथा कुल निर्यात 3063.6 करोड़ रु० के हुए थे, अर्थात् औसतन 1050 करोड़ रु० के आयात तथा 613 करोड़ रु० के निर्यात प्रतिवर्ष हुए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत का व्यापार में एकल पहली योजना की तुलना में और भी अधिक प्रतिकूल हो गया। इस योजनाकाल के पांच वर्षों में व्यापार समुलभ की प्रतिकूलता औसतन 467 करोड़ रु० रही।

द्वितीय योजना काल में आयात, एवं निर्यात व्यापार छग की स्थिति निम्न प्रकार रही

द्वितीय योजना काल में आयात, निर्यात व्यापार छेव (करोड़ रु० में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
1956-57	1102.1	635.2	- 466.9
1957-58	1233.2	594.2	- 639.0
1958-59	1029.3	576.3	- 453.0
1959-60	932.3	627.4	- 304.9
1960-61	1105.7	630.5	- 475.2
	5402.6	3063.6	- 2338.1
वार्षिक औसत	1080.0	613	- 467

तृतीय योजनाकाल में भारत का विदेशी व्यापार

तृतीय योजनाकाल में तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में निर्यात में मामूली वृद्धि हुई। 1963-64 व 1964-65 में निर्यात और भी बढ़े, लेकिन योजना का अन्तिम वर्ष में निर्यात में पूर्व वर्ष की अपेक्षा कमी हुई। 6 जून, 1966 को निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से ही भारतीय रुपये का 36.5 प्रतिशत से अवमूल्यन किया गया। योजनाकाल की सम्पूर्ण अवधि में व्यापार शेष देश के प्रतिकूल रहा और यह प्रतिकूलता योजना के अन्तिम वर्ष में सर्वाधिक थी। योजनाकाल में आयात, निर्यात व व्यापार शेष सम्बन्धी आंकड़ निम्न तालिका में दिए गए हैं

तृतीय योजना में आयात, निर्यात एवं व्यापार शेष (करोड़ रु० में)

वर्य	निर्यात	आयात	व्यापार-शेष
1961-62	1041	1720	- 679
1962-63	1080	1783	- 703
1963-64	1250	1927	- 677
1964-65	1286	2126	- 840
1965-66	1269	2216	- 949
	5926	9774	- 3848
वार्षिक औसत	1185.2	1955	- 769.6

वार्षिक योजनाओं में विदेशी व्यापार-तृतीय योजना के वार 1966-67, 1967-68 एवं 1968-69 के तीन वर्यों में एक-एक वर्य की वार्षिक योजनाएँ लागू की गईं। इन योजनाओं के दौरान आयात, निर्यात व व्यापार शेष की स्थिति निम्न प्रकार की थी

वार्षिक योजना में विदेशी व्यापार- (करोड़ रु० में)

वर्य	निर्यात	आयात	व्यापार-शेष
1966-67	1157	2078	- 921
1967-68	1199	2008	- 809
1968-69	1355	1909	- 554

समर्पण तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम वार्षिक योजना के प्रथम वर्य में वहाँ व्यापार सतुलन 921 करोड़ रु० था, वहाँ अन्तिम वार्षिक योजना में घट कर 554 करोड़ रु० रह गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार-चतुर्थ योजना के अन्त तक भारतीय निर्यात 1900 करोड़ रु० तक पहुँचाने का लक्ष्य है तथा आयात 2030 करोड़ रु० तक पहुँच जायेगा। योजनावधि में 7 प्रतिशत वार्षिक मिश्रित दर से निर्यातों के बढ़ाए जाने की सम्भावना है। इस योजनाकाल में निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाए जायेंगे वे हैं (i) देश के निर्यातित वस्तुओं की उत्पादन आधार का विस्तार, (ii) जब तक यथेष्ट आन्तरिक उत्पादन न हो,

1 Commerce 19 Aug 72

2 Ibid

तब तक स्वयं पर अस्थायी नियन्त्रण लगाना; (iii) क्रिसम-नियन्त्रण को कड़ाई से लागू करना; (iv) उत्पादन लागत में कमी करना; (v) उत्पादन प्रणाली में सुधार करके विदेशी भास की आवश्यकता को कम करना; तथा (vi) निर्यात के लिए नए-नए बाजारों की खोज करना तथा पुराने बाजार में स्थिति को सुधारना ।

चतुर्थ योजना में विदेशी व्यापार¹ (करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार संघ
1969-70	1413.21	1582.67	-169.46
1970-71	1535.16	1625.17	-90.01
1971-72	1567.00	1853.00	-286.0

योजनावधि में भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएँ

यदि हम सम्पूर्ण योजनावधि की विदेशी व्यापार सम्बन्धी गतिविधियों का अवलोकन करें, तो हमें अपने विदेशी व्यापार की विम्बल्लिखित प्रमुख विशेषताएँ दिखाई देंगी :

1 कुल व्यापार की मात्रा में वृद्धि : हमारे देश के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि होती रही है । एक ओर हम निर्यात यन्त्रों का प्रयत्न करते रहे हैं, जिनसे निर्यातों में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर, आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिये उठाये गये कदमों के फलस्वरूप आयातों में भी स्वभावतः वृद्धि हुई है । इस प्रकार कुल आयात एवं निर्यात में बढ़ोतरी होती रही है । सन् 1951-52 में हमारे आयात व निर्यात क्रमशः 662.9 व 730.1 करोड़ रु० के थे, जो सन् 1971-72 में बढ़ कर क्रमशः 1853.00 व 1567.00 करोड़ रु० के हो गए ।

चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों में विदेशी व्यापार की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक रही किन्तु तीसरे वर्ष स्थिति पुनः विचल गई, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :

2 व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता : 1950-51 में भारत का व्यापार सन्तुलन देश के प्रतिकूल था । यह प्रतिकूलता न केवल आज भी बनी हुई है, अपितु यह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है । सन् 1950-51 में भारतीय विदेशी व्यापार की प्रति कूलता 232.8 करोड़ रु० थी, यह बढ़कर 1971-72 में 286.00 करोड़ रु० तक

पहुँच गई। यदि हम व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता को ऐतिहासिक रूप में देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें काफी उतार-चढ़ाव रहे हैं। कभी व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता बहुत अधिक थी, तो किन्हीं वर्षों में इसमें कमी भी रही है, लेकिन इस सम्पूर्ण अवधि में प्रतिकूलता निरन्तर बनी रहती है।

3 कच्चे माल तथा पूंजीगत माल के आयात में वृद्धि सम्पूर्ण योजनावधि में आयातों में जो वृद्धि हुई है, उसमें कच्चे माल व पूंजीगत सामान की प्रधानता रही है। खाद्यान्नों को छोड़ कर सब उपभोग पदार्थों के आयातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। कच्चे माल तथा पूंजीगत सामान के आयात में वृद्धि होने का प्रमुख कारण यह था कि देश के औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने के लिए इन दोनों ही वस्तुओं की आवश्यकता थी।

4 भारत का आयात मुख्यतः अमेरिका से तथा निर्यात मुख्यतः इंग्लैण्ड को हुए। भारत ने देश के औद्योगिक विकास के लिए, यद्यपि पूंजीगत सामान रुस, प० जर्मनी, जापान आदि देशों से भी मंगाया, परन्तु मुख्यतः इस प्रकार के सामान की खरीद अमेरिका से ही की गई। इस प्रकार योजनावधि में भारत के आयात अमेरिका से बढ़े। जहाँ तक निर्यात का प्रश्न है, भारत ने इस अवधि में अपने अधिकांश निर्यात इंग्लैण्ड को ही किये।

भारत के विदेशी व्यापार की साधुनिक प्रवृत्तियाँ

किसी भी देश के विदेशी व्यापार की साधुनिक प्रवृत्तियों को जानने के लिए हमें सामान्यतः सम्बंधित देश की निम्नलिखित बातों का अवलोकन करना चाहिए—

- 1 व्यापार की मात्रा (Value of Trade),
- 2 विदेशी व्यापार की रचना (Composition of Foreign Trade), तथा
- 3 विदेशी व्यापार की दिशा (Direction of Foreign Trade)।

1 व्यापार की मात्रा (Value of Trade)

व्यापार की मात्रा देश के आयात व निर्यात के कुल योग द्वारा ज्ञात की जाती है। भारतवर्ष के विदेशी व्यापार के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गत वर्षों में इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है, क्योंकि गत वर्षों में भारत के आयात व निर्यात दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। हम इनका अलग अलग विवेचन करेंगे

(क) आयात—भारतवर्ष में औद्योगिक उन्नति एवं वार्षिक विकास के साथ-साथ आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है। जैसा कि निम्न सारिणी में दिखाया गया है।

आयात में वृद्धि

वर्ष	आयात (करोड़ रु० में)
1951-52	962 90
1955-56	773 10
1960-61	1105 70
1965-66	1269 00
1966-67	2078,00
1967-68	2008 00
1968-69	1909 00
1969-70	1582 67
1970-71	1625 17
1971-72	1853 00

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पञ्चवर्षीय योजनावधि में औसत प्रति वर्ष आयात क्रमशः 730, 1080 व 1955 करोड़ रु० का हुआ।

(ख) निर्यात भारत में सत्र वर्षों में निर्यात व्यापार में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि आयातों की तुलना में पिछड़ी रही है। प्रथम योजना में प्रतिवर्ष औसत निर्यात 622 करोड़ रु० का था तथा दूसरी योजनावधि में यह औसत 613 करोड़ रु० तक ही पहुँच पाया। तृतीय योजना काल में हमारे देश का प्राधिकृत औसत निर्यात 1185 करोड़ रु० का था। भारत में नियोजनकाल में होने वाले निर्यात सम्बंधी प्रवृत्ति का अन्तर्गत निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है।

निर्यात में प्रवृत्ति

वर्ष	निर्यात
1951-52	730 1
1955-56	640 3
1960-61	690 5
1965-66	1269
1966-67	1157
1967-68	1199
1968-69	1358
1969-70	1413 21
1970-71	1535 16
1971-72	1567 00

उपरोक्त विवेचन से यह पता चलता है कि यह वर्षों में हमारे आयात व निर्यात दोनों ही तीव्रगति से बढ़े हैं। आयातों में होने वाली वृद्धि निर्यातों में होने वाली वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक रही है। यही कारण है कि व्यापार सतुल्यता की प्रतिकूलता निरन्तर बनी हुई है।

भारत के विदेशी व्यापार की रचना (Composition of India's Foreign Trade)

किसी देश की 'व्यापार रचना' से तात्पर्य उस देश द्वारा आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से होता है। भारत के विदेशी व्यापार की रचना का अवलोकन करने से पता चलता है कि हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद काफी परिवर्तन हुवा है।

भारत के आयात की रचना (Composition of India's Imports)

यह वर्षों में आयातों के आकार से परिवर्तन के साथ साथ आयातों में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं के आकार में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सन् 1951 ई० में पूँजीगत वस्तुओं के आयातों का मूल्य लगभग 24 प्रतिशत था जो तृतीय योजना के मध्य तक बढ़ कर 35.1 प्रतिशत हो गया—पूँजीगत वस्तुओं के आयात में होने वाली इस वृद्धि का कारण नियोजनकाल में देश की विकास योजनाओं के लिए बढ़ती हुई पूँजी उपकरणों की मांग की पूर्ति करना था। पूँजीगत उपकरणों के आयात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजना में क्रमशः 1,154,2,283 तथा 2,500 करोड़ रु० के हुए।

प्रथम योजनावधि में 1061 करोड़ रु० के कच्चे माल का आयात किया गया था जो कुल आयात का 24.4 प्रतिशत था। दूसरी योजनावधि में कच्चे माल का आयात अपेक्षाकृत कम हुआ, अर्थात् यह घट कर 919 करोड़ रु० रह गया। यह कुल आयात का 17.7 प्रतिशत था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कच्चे माल की मांग बढ़ जाने के कारण आयात में पुनः इनका भाग बढ़ गया जो कुल आयात का 22.2 प्रतिशत था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् साधारणों के आयात में भी वृद्धि हुई। प्रथम तथा द्वितीय योजना काल में क्रमशः 156,149 प्रतिशत आयात साधारणों का था। तृतीय योजनावधि में साधारणों का आयात बढ़ कर 24.5 प्रतिशत तक पहुँच गया।

निम्नांकित सारिणी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनावधि में भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के वार्षिक औसत आयात पर प्रकाश डालती है।

आयात का वर्गीकरण (कुल आयात के मूल्य का प्रतिशत)

वस्तु	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
पूँजी पदार्थ	28.8	42.2	35.1
कच्चा माल	24.4	17.7	21.2
उपभोग्यता पदार्थ	22.5	19.8	15.5
साधन	15.6	14.9	24.5

उपरोक्त सारिका से स्पष्ट है कि नियोजन काल के प्रथम पन्ध्र वर्षों में आयातों का स्वरूप बदल कर पूँजीगत वस्तुओं व कच्चे माल के पक्ष में हो गया है तथा उपभोग्यता वस्तुओं का आयात धीरे धीरे कम होता गया है। आयातों का यह बदला हुआ स्वरूप हमारी अर्थ व्यवस्था के बढ़ते हुए औद्योगीकरण का प्रतीक है। खाद्यान्नों का आयात हमारे खाद्य समस्या की खोजबीज स्थिति का दिग्दर्शन करती है।

भारत को प्रमुख आयात—भारत में आयात किए जाने वाले प्रमुख पदार्थ निम्नांकित हैं—

1. मशीनें व परिवहन का साधन—भारतवर्ष के नियोजन के 21 वर्षों के बाद भी, मशीन बनाने वाले उद्योगों का अभी तक पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है। देश के पुराने कारखानों को निरन्तर चालू रखने के लिए तथा नए-नए कारखानों को प्रोत्साहित कर औद्योगीकरण की गति को तेज करने के लिए, भारत को विगत पञ्चवर्षीय योजनाओं के दौरान, अपनी दुर्लभ विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा भग्न मशीनों के आयात पर खर्च करना पड़ा है। हमारा देश सामान्यतः ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत रूस, जापान एवं पूर्वी योरोप के अन्य देशों से मशीनों का आयात करता है। सन् 1969-70 ई० में भारत ने 403 करोड़ रु० की मशीनों का आयात किया था। सन् 1970-71 में 393.8 करोड़ रु० की मशीनों का आयात किया गया।

2. खाद्यान्न—भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी खाद्यान्नों के मामले में मे सात्म निर्भर नहीं है। प्रथम योजना के अन्तिम वर्षों को छोड़ कर, हमें

संदेह ही विदेशों से घट्टे व चावल का आयात करना पड़ता रहा है। घट्टे का आयात भारत में मुख्यतः अमेरिका, कनाडा व आस्ट्रेलिया से किया जाता है, जबकि चावल मुख्यतः बर्मा, थाईलैण्ड तथा समुद्र तटवर्ती गणराज्य से मंगाया जाता है। सन् 1967-68 में हमारे देश में 518.2 करोड़ रु० का आयात किया गया सन् 1970-71 में भारत ने 213 करोड़ रु० का आयात किया। सन् 1971-72 में आयातों का आयात और कम हुआ है।

3 लोहा व इस्पात भारतवर्ष में विगत कुछ वर्षों में लोहे व इस्पात की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि देश का तेजी से औद्योगीकरण हो रहा है। निर्माण के विगत वर्षों में हमने सार्वजनिक क्षेत्र में तीन बड़े लोहे व इस्पात के कारखाने चालू किए हैं तथा निजी क्षेत्र को भी इस दिशा में प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, तथापि भारतवर्ष अब तक भी लोहे व इस्पात के मामले में स्वावलम्बी नहीं हो सका है और हमें लोहे व इस्पात का विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में सामान्यतः इंग्लैंड, अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी से लोहे व इस्पात का आयात किया जाता है। सन् 1970-71 में भारत ने 147 करोड़ रु० का इस्पात विदेशों से मंगाया था।

4 पेट्रोलियम भारत की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि यह पेट्रोल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु की मांग का केवल 17 प्रतिशत भाग ही पैदा करती है तथा अब 83 प्रतिशत आवश्यकताओं के लिए हमें विदेशों द्वारा की गयी पूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। गत कुछ वर्षों में भारत में तेल साफ करने के लिए कई कारखाने खोले गए हैं, लेकिन क्रूड ऑयल (Crude Oil) का आयात आज भी करता ही पड़ता है। भारतवर्ष में परिवहन के साधनों की वृद्धि के साथ-साथ पेट्रोलियम की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, अतः पेट्रोलियम का उत्पादन बढ़ाना देश के लिए आवश्यक हो गया है। भारत सामान्यतः बर्मा, ईरान, ईराक तथा अमेरिका से बड़ी बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम का आयात करता है। सन् 1967-68 ई० में हमारे देश में 59.73 करोड़ रु० का पेट्रोलियम विदेशों से मंगाया गया। सन् 1969-70 में 138 करोड़ रु० के खनिज तेल (पेट्रोल व मिट्टी का तेल) का आयात किया गया।

5 कपास विभाजन के पश्चात् से भारत में कपास की कमी भी महसूस की जाने लगी, क्योंकि कपास पैदा करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र, अर्थात् के पन्धरवर्ष, पाकिस्तान में चला गया। भारत में अच्छे वस्त्रों के निर्माण के लिए, बड़े देश वाली कपास की जरूरत है, जो देश में पैदा नहीं की जाती, अतः इसे अमेरिका, समुद्र तटवर्ती गणराज्य, मूडान एवं पाकिस्तान से मंगाया पड़ता है। भारत में सन्

1969-70 में 82.8 करोड़ रु० की कपास का आयात किया गया तथा 1970-71 में 98.8 करोड़ रु० की कपास का आयात किया गया।

6. **उर्वरक एवं रासायनिक पदार्थ** : भारत में उद्योगों, रको एवं दवाइयों के लिए विविध प्रकार के रासायनिक पदार्थों का आयात करना पड़ता है तथा खेतों को खाद देने के लिए उर्वरकों का आयात किया जाता है। सामान्यतः अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन से इनका आयात किया जाता है। 1970-71 में लगभग 216.5 करोड़ रु० के रासायनिक पदार्थ एवं उर्वरक का आयात किया गया था।

7. **जूट** : विशासन के बाव भारत में जूट की बहुत कमी महसूस की जाने लगी थी, क्योंकि जूट के प्रायः सभी कारखाने तो भारत में था गए थे तथा कच्चा जूट पैदा करने वाले अधिकतर क्षेत्र पाकिस्तान में रह गए थे। चीरे-चीरे भारत में कच्चे जूट की कमी पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ मात्रा में जूट का पाकिस्तान से आयात करना पड़ता है। सन् 1969-70 में भारत ने केवल 1.1 करोड़ रु० का कच्चा जूट मंगाया था। सन् 1970-71 में 0.1 करोड़ रु० का ही कच्चा जूट विदेशों से मंगाया गया।

अन्य वस्तुएँ : उपर्युक्त वर्णित वस्तुओं से अतिरिक्त भारत विदेशों से तौबा, सीसा, रासा, आदि अनेक पदार्थों का आयात करता है। इनके अलावा सोपावीन, तेल, गेहूँ की चर्बी, कच्चा रानू, दूध का पाउडर, खोपरा, सुन्दी रखड़, पेपर, पेपर बोर्ड तथा कच्चे ऊन का भी आयात करते हैं।

भारत के निर्यात की रचना (Composition of India's Exports) : आयातों की भाँति भारत के निर्यात व्यापार में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् परिवर्तन हुए। भारत के निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ तीन श्रेणियों में बाँटी जा सकती हैं, यथा (i) उपभोग वस्तुएँ; (ii) कच्चा माल; (iii) अन्य वस्तुएँ। नीचे दी हुई तालिका में प्रत्येक श्रेणी के निर्यातों में हुए परिवर्तनों को दर्शाया गया है :

वस्तुएँ	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
उपभोग वस्तुएँ	41.0%	33.0%	37.0%	42.0%
कच्चा माल	36.0%	41.0%	36.0%	36.0%
अन्य वस्तुएँ	23.0%	26.0%	27.0%	22.0%
योग	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

उपयुक्त तालिका से हम वस्तुओं के वर्गों की निर्यात स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं के औसत वार्षिक निर्यात का ज्ञान हमें अपरिचित तालिका से प्राप्त हो सकता है—

योजना काल में औसत वार्षिक निर्यात (करोड़ रु० में)

वस्तु	प्रथम योजनावधि में	द्वितीय योजनावधि में	तृतीय योजनावधि में	1966-67 से 1970-71
चाय	106	132	120	151
निर्मित जूट	149	120	157	209
सूती कपड़ा	81	76	55	85
कापड़ों (खालें)	32	35	35	72
धान्य (लोहा, अन्नक, जस्ता आदि)	30	37	50	112
कपास	27	18	16	17
सम्बाकू	15	16	20	30
वनस्पति तैल	27	16	10	6

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कच्चे लोहे, चीनी, लोहे व इस्पात, हाथ करण की वस्तुओं तथा अभियांत्रिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ गया। इसके विपरीत चाय, जूट की वस्तुओं एवं सूती कपड़े के निर्यात में पहले की तुलना में कमी हुई। सन् 1960-61 में निर्यात में इन वस्तुओं का भाग 48 प्रतिशत था जो 1965-66 में घट कर 43 प्रतिशत रह गया। इस योजना काल में रासायनिक तथा अभियांत्रिक क्षेत्रों में कुछ नई वस्तुओं का निर्यात प्रारम्भ किया गया। वस्तुतः भारत का निर्यात ढाँचा एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था का प्रतीक है जिसका अभि-कतर भाग उपभोग वस्तुओं, कच्चे मालों और कृषि उत्पादों का है। पूँजीगत वस्तुओं का भाग 1966-67 व 1970-71 के मध्य कुल निर्यात में केवल 8.6 प्रति-शत था। निर्यात वस्तुओं का भाग 37.7 प्रतिशत, कच्चे मालों का 17.3 प्रतिशत तथा खाद्य पेष व सम्बाकू का भाग 30 प्रतिशत था।

भारत के प्रमुख निर्यात भारत के निर्यात की प्रमुख वस्तु निम्नो-रिक्त हैं —

1. **जूट का सामान** जूट के सामान का भारत के निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। जूट के टाट, चटाइयाँ, बोरे, गजीचे, सुतली आदि बनाये जाते हैं। ब्रिटेन से पहले जूट के सामान की पूर्ति में भारत की प्रायः एकाधिकार-भा प्राप्त था, लेकिन देश के विभाजन के बाद यह स्थिति नहीं रही। पाकिस्तान हमारा प्रतिस्पर्धी बन गया तथा कई बाजार करने वाले देशों ने इसकी म्यादापन्न बनाता

प्रारम्भ कर दिया, फिर भी खूट के सामान को बाहर भेज कर भारत बहुत बड़ी मात्रा में खालर जमाता है। भारत सामान्यतः अमेरिका, इंग्लैंड, संयुक्त अरब गणराज्य, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों को खूट का सामान भेजता है। सन् 1970-71 में खूट के निर्यात से भारत ने 190 00 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

2 चाय खूट के सामान ही चाय भी भारत के परम्परागत निर्यात की वस्तु है तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण पदार्थ रहा है। इंग्लैंड भारतीय चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और प्रायः हमारी चाय के कुल निर्यात का दो तिहाई भाग इंग्लैंड को ही भेजा जाता है। शेष एक तिहाई भाग के खरोददार देशों में अमेरिका, कनाडा, ईरान, संयुक्त अरब गणराज्य, मूबान, रूस तथा पश्चिमी जर्मनी आदि देश आते हैं। आजकल भारत को चीन, ल्हा तथा इन्डोनेशिया से चाय के निर्यात में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सन् 1970-71 में भारत ने 184 3 करोड़ रु० की चाय का निर्यात किया था।

3. सूती वस्त्र . सूती वस्त्र तथा सूत के निर्यात में भारत का प्रमुख स्थान है। औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व, भारत की उच्चकोटि की मलमल यूरोप के देशों में बहुत रुचाति प्राप्त कर चुकी थी। जापानी से पूर्व अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण व्यापिक नीति के कारण भारत को इंग्लैंड से सूती वस्त्रों का आयात करना पड़ता था, लेकिन अब यह बात नहीं रही है। इस समय भारत इंग्लैंड, बर्मा, मलेशिया, ल्हा, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान एवं मध्य पूर्व के अनेक देशों से सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। इस समय चीन, जापान तथा ब्रिटेन से इसे प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है। अतः इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए समुचित उपाय वाञ्छनीय है। भारत ने सन् 1970 71 में 75 3 करोड़ रु० के वस्त्र का निर्यात किया था।

4 कच्चा लोहा भारत में कच्चे लोहे के अनुत्पन्न भण्डार उपलब्ध हैं और सम्भवतः विश्व के किसी भी देश में उनका इतना अधिक भण्डार नहीं है। देश के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों की कच्चे लोहे सम्बन्धी मांग को पूरा कर लेने के बाद भी हमारा देश वह पैमाने पर कच्चे लोहे के निर्यात करने की स्थिति में है। वर्तमान समय में भारत का कच्चा लोहा मुख्यतः जापान को भेजा जाता है। सन् 1970 71 में भारत ने 117 3 करोड़ रु० का कच्चा लोहा निर्यात किया था।

5 चमड़ा तथा चमड़े का सामान भारत में विश्व के सर्वाधिक पशु पाये जाते हैं, अतः हमारे देश में प्रतिवर्ष काफी चमड़ा निकलता है। भारतवर्ष चमड़े तथा चमड़े की वनी हुई अनेक वस्तुओं का निर्यात करता है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस,

रूस, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी तथा हॉलैंड हमारे देश के चमड़े तथा चमड़े के सामान के प्रमुख आयात करने वाले देश हैं। सन् 1970-71 में भारत द्वारा 72.2 करोड़ रु० का चमड़ा व चमड़े का सामान विदेशों को भेजा गया था।

8 अन्नक विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत अन्नक भारत में ही उत्पन्न होता है। भारत के जो देश अन्नक आयात करते हैं, उनमें प्रमुख देश अमेरिका, इंग्लैंड तथा पश्चिमी जर्मनी हैं। सन् 1969-70 में भारत ने 15.2 करोड़ रु० का अन्नक विदेशों को भेजा था।

9 तम्बाकू भारत कच्चे तम्बाकू के निर्यात करने वाले देशों में प्रमुख स्थान रखता है। गत कुछ वर्षों से रोडेजिया एष दक्षिणी अफ्रीका हमारे साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। भारत मुख्यतः इंग्लैंड, जापान, स्वीडन, हॉलैंड, मलेशिया आदि देशों को तम्बाकू का निर्यात करता है। सन् 1970-71 में भारत ने 32.6 करोड़ रु० की तम्बाकू का निर्यात किया था।

8 मँगनीज मँगनीज भी भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वर्तमान समय में भारत अपनी उपज का तीन चौथाई भाग विदेशों को निर्यात कर देता है। भारत अपनी मँगनीज को अमेरिका, योरोपीय देशों व जापान को बेच कर विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सन् 1969-70 में भारत ने 1100 करोड़ रु० मँगनीज विदेशों को भेजा था।

9 वनस्पति तेल भारत में मूँगफली, बिल्ली, सरसों का तेल काफी पैदा किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हमारा दम तिलहनो का निर्यात करता था, लेकिन अब तेल मिष्ठो की समस्या में वृद्धि हो जाने के कारण अब भारत तिलहनो की बजाय वनस्पति तेल का निर्यात करता है। भारत से सामान्यतः बर्मा, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों को वनस्पति तेल का निर्यात किया जाता है। सन् 1970-71 में भारत ने लगभग 10.8 करोड़ रु० वनस्पति तेल के निर्यात से प्राप्त किए। इसी वर्ष तेल की खली (oilcakes) का निर्यात 5.4 करोड़ रुपये का हुआ।

10 विविध वस्तुएँ उपर्युक्त वर्णित वस्तुओं के अलावा भारत कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का भी निर्यात करता है। जैसे मसाले, काजू, लाख, बिजली के पखे, कपड़ा, कीने की मशीनें, साइकिलें तथा अन्य इलेक्ट्रिक वस्तुएँ। हाल ही में भारत चीनी का भी निर्यात करने लगा है।

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा

(Direction of India's Foreign Trade)

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार में इंग्लैंड तथा उसके साम्राज्य के देशों का साग सर्वाधिक रहता था और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि

रतन्त्र होने के नाते भारत अपने हितों के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र व्यापार नीति रही अपना सक्ता था। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अब ब्रिटेन तथा उसके साम्राज्य के देशों का भारत के विदेशी व्यापार में भाग उत्तरोत्तर कम हो गया है। भारत के विदेशी व्यापार की यह प्रवृत्ति अब भी विपरीत है। भारत के व्यापारिक सम्बन्ध अमेरिका, जापान, रूस तथा पूर्वी योरोप के अन्य देशों के साथ अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में होने वाले परिवर्तनों की कुछ तथ्यों द्वारा पुष्टि की जा सकती है, उदाहरणस्वरूप सन् 1951 में भारत अपनी सम्पूर्ण आयातकताओं का 11 प्रतिशत इंग्लैण्ड से आयात करता था, लेकिन 1966-67 से 1970-71 में यह भाग घट कर केवल 7.7 प्रतिशत हो रह गया। इसी तरह हम अवधि में भारत के निर्यात व्यापार में इंग्लैण्ड का भाग 21.6 प्रतिशत से घट कर 11.1 प्रतिशत हो रह गया।

भारत के विदेशी व्यापार में अमेरिका, पूर्वी योरोप के देशों के साथ व्यापार तथा मध्य-पूर्व क्षेत्रों के देशों का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व भारत के आयात में अमेरिका का भाग प्रायः 7 प्रतिशत के बराबर ही रहता था, जो 1950-51 में बढ़ कर 18.0 हो गया और 1966-67 से 1970-71 में 27.4 प्रतिशत तक पहुँच गया। इसी प्रकार भारत के निर्यातों का भी एक बहुत बड़ा भाग अमेरिका की ओर होता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भारत के निर्यात व्यापार में अमेरिका का 9 प्रतिशत भाग था, जो 1950-51 से 1966-67 व 1970-71 में उत्तरोत्तर बढ़ कर क्रमशः 17.8 प्रतिशत तथा 19.5 प्रतिशत हो गया। भारत के विदेशी व्यापार की बदलती दिशा का ज्ञान हम निम्न-तालिका से भिन्न करवाते हैं।

भारत का अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार

(प्रतिशत)

देश	आयात			निर्यात		
	1950-51	1960-61	1966-67 से 1970-71	1950-51	1960-61	1966-67 से 1970-71
अमेरिका	18	29.6	27.4	17.8	16.3	13.5
इंग्लैण्ड	11	19.6	7.7	21.6	27.2	11.1
ए. जर्मनी	2	11.0	6.5	1.7	3.1	2.1
सोवियत संघ	0.0	1.4	6.4	0.2	4.6	13.6
जापान	1.5	5.5	5.1	1.6	5.6	13.2
ऑस्ट्रेलिया	5	1.6	2.2	4.7	3.5	1.6

तालिका से स्पष्ट है कि भारत के विदेशी व्यापार में एक ओर इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया के हिस्से में कमी होती जा रही है, जबकि अमरीका, रूस तथा जापान का भाग बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रूस के साथ हुई छवि के परिणाम-स्वरूप रूस के साथ हमारे व्यापार के बढ़ने की ओर भी अधिक सम्भावनाएं हैं।

भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ

(Chief Characteristics of India's Foreign Trade)

भारत के विदेशी व्यापार के विरुद्ध विवेचन से हमें इसकी कुछ विशेषताओं का ज्ञान होता है, जो संक्षेप में निम्नांकित हैं -

1. भारत के आयात व निर्यात निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा में सत्र वर्षों में पचास प्रतिशत वृद्धि हुई है।

2. यद्यपि भारत के आयात एवं निर्यात दोनों बढ़ रहे हैं, तथापि आयातों में निर्यातों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है।

3. भारत का व्यापार सतत रूप से वृद्धि के पथ पर चल रहा है और विशेषकर नियोजित अर्थ-व्यवस्था के प्राग्भूत होने से प्रतिकूल चल रहा है। अब भी व्यापार सतत रूप से वृद्धि के पथ पर चल रहा है और विशेषकर नियोजित अर्थ-व्यवस्था के प्राग्भूत होने से प्रतिकूल चल रहा है।

4. सत्र वर्षों में भारत के आयात में पूँजीगत वस्तुओं एवं कच्चे माल का महत्व बढ़ रहा है तथा निर्यात में माल की वृद्धि बढ़ता जा रहा है।

5. भारत के बड़ा भाग देशी स-गाप र विकसित न होने के कारण, भारत का अधिकांश व्यापार, अर्थात् 68 प्रतिशत व्यापार, समुद्री मार्ग से होता है।

6. भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः अमेरिका, रूस तथा जापान के मध्यस्थता से ही होता है, अब इन मध्यस्थता पर व्यापार का काफी दबाव रहता है।

7. भारत के विदेशी व्यापार का काम आज भी विदेशी फर्मों, जहाँ की कम्पनियों, विभिन्न बैंकों व गैर-कम्पनियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि विदेशी व्यापार का अधिकांश लाभ इनकी ही प्राप्त हो रहा है।

8. भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। ब्रिटेन का महत्व हमारे विदेशी व्यापार से धीरे धीरे घटता जा रहा है तथा अमरीका, रूस, पूर्वी योरोप एवं जापान का महत्व बढ़ता जा रहा है।

9. भारत का प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार अब भी बहुत कम है। यदि हम विश्व के अन्य विकसित देशों से इसकी तुलना करें तो प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार का मूल्य बहुत ही कम है।

10 भारत सरकार द्वारा निर्यात सम्बंधन की दिशा में किये गये प्रयत्नों का कुछ सफलता प्राप्त हुई है तथा कुछ नई वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जा रहा है।

11 भारत के प्रमुख आयात में मशीनों, खाद्यान्नों, कपास, पेट्रोल आदि का प्रमुख स्थान है तथा निर्यात में चाय, सूती वस्त्र एवं जूट के सामान प्रमुख हैं।

12 विदेशी व्यापार में द्विपक्षीय समझौते (Bilateral Trade Agreement) का महत्व बढ़ रहा है। मुद्रा (Soft Currency) क्षेत्रों से आवश्यक सामान प्राप्त करते तथा भारतीय माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये इस प्रकार के समझौते किए जा रहे हैं।

13 राजकीय व्यापार (State trading) की महत्ता हमारे विदेशी व्यापार में बढ़ रही है। राजकीय व्यापार नियम साम्यवादी देशों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

14 वर्तमान समय में निर्यात की वस्तुओं जूट, मैंगनीज, काजू, सूती वस्त्र, खनिज पदार्थों में वृद्धि हुई है, लेकिन चाय, बीनी, आदि वस्तुओं का कम निर्यात हुआ है। खाद्य पदार्थों, कपास, इस्पात व लोहा, मशीनों तथा रासायनिक खाद्य के आयात में वृद्धि हुई है।

भारत सरकार की व्यापार नीति

किसी भी देश का विदेशी व्यापार, सम्बन्धित देश की अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालता है। सुनियोजित आयात एवं निर्यात व्यापार सन्तुलन को दक्ष में लाकर देश को प्रचुर वनराशि प्रदान करते हैं, जिन पर देश के औद्योगिक विकास की रूढ़ नींव रखी जा सकती है। व्यापार नीति के दो पहलू होते हैं, आयात एवं निर्यात नीति। इनके अनुच्छेदों में हम भारत की आयात व निर्यात नीति की आलोचनात्मक विवेचना करेंगे।

1. भारत सरकार की आयात नीति स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत सरकार की व्यापार नीति का प्रमुख आधार, देश हित के साथ-साथ इम्प्लेंट के दिनों की रक्षा करना था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस नीति में परिवर्तन किया गया, जो स्वाभाविक था। सन् 1948 ई० में वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक सामान सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। यह परिषद आयातकर्ताओं को आयात के लिए अनुज्ञापन (लाइसेन्स) प्रदान करती है। आयात की मरम्मत वस्तुओं को तीन भागों में रखा गया है—(i) ऐसी वस्तुएँ जिनके लिए लाइसेन्स नहीं दिये जा सकते, (ii) ऐसी वस्तुएँ जिनके आयात के लिए केवल सीमित अर्थ तक ही लाइसेन्स दिये जाते हैं, तथा (iii) ऐसी वस्तुएँ जो खुले मार्गस्थ लाइसेन्स के अन्तर्गत

आती हैं। यह परिपक्व आयात के लिए कच्चे माछ, मछीन तथा स्टर्निंग और की वस्तुओं को प्राथमिकता देती है। *कच्चे माछ* तथा *मछीन*

सन् 1950 ई० में, भारत सरकार ने एक 'आयात नियन्त्रण आन समिति' बनाई, जिसने आयात नियन्त्रण नीति के तीन उद्देश्यों पर बल दिया। ये उद्देश्य ये: (1) आयात, अतिरिक्त विदेशी विनिमय तक सीमित हो, (2) उपलब्ध विदेशी विनिमय का हम प्रसार उपयोग किया जाय कि एक ओर तो उपभोक्ताओं को अधिकतम सस्तेप प्राप्त हो तथा दूसरी ओर निर्योजित विहाम की उन्नति हो, तथा (3) जहाँ तक सम्भव हो कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव रोकें जाए।

हम समिति ने आयात सम्बन्धी कुछ निश्चितियों भी की थी जिनमें से प्रमुख ये हैं, (1) लाइसेन्स केवल वास्तविक उपभोक्ताओं स्थापित आयातकर्ताओं जहाँ तथा समुचित नए व्यापारियों को दिये जायें, (2) लाइसेन्स प्रदान करने की नीति इस प्रकार की होगी यदि कि अन्तःराष्ट्रिय उद्योगों में अभी वस्तुओं का जाए, (3) समिति ने जो प्राथमिकता क्रम सुझाया था वह इस प्रकार है (क) आवश्यक कच्चा माछ (ख) मछीनों के पुर्जे (ग) कृषि में सम्बन्धित वस्तु (घ) सर्वसाधारण उपयोग के लिये मछीन, (2) आवश्यक उपभोक्ता सामान (ब) सर्वसाधारण उपयोग के लिए आवश्यक सामान (3) अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक सामान, तथा (4) अन्य आवश्यक सामान। (4) खुले सामान्य लाइसेन्स (Open General Licences) की सूची का विस्तार उस समय तक न किया जाय जब तक कि इसे दीर्घकाल तक बनाये रखना सम्भव न हो, (5) व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रशासनिक सुदृढता में वृद्धि की जाए। भारत सरकार ने उपर्युक्त सभी निश्चितियों स्वीकार कर ली थी। केवल प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन किया गया। नवीन प्राथमिकता क्रम इस प्रकार रहा गया - (क) आवश्यक कच्चा माछ, (ख) पुर्गी मछीनों के पुर्जे एवं भाग, (ग) उपभोक्ताओं एवं स्वदेश के लिए आवश्यक वस्तुओं, (घ) अन्य कच्चा माछ तथा मछीन, (2) अन्य आवश्यक सामान, तथा (ब) आवश्यक सामान।

इस समय भारत सरकार की आयात नीति के अन्तर्गत देश के औद्योगिक विकास के लिये मछीनों, वन्य एवं आवश्यक माछ सामान के आयात की वृद्धि जा रहा है। कच्चे माछ के आयात में भी वृद्धि हो आ रही है। अनेकानेक कम महत्व की वस्तुओं का आयात कम किया जा रहा है। आयात की वस्तुओं के आयात को ऊँचे सीमा करने द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है। सरकार आयात के लिये लाइसेन्स देती है, परन्तु कुछ आयात वस्तुओं के कोटे निर्धारित कर दिये गये हैं। विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने विदेशी सरकारों

से प्राथमिक सहायता ली है। 6 जून, 1966 को सरकार द्वारा रुपये के अवमूल्यन किये जाने के परिणामस्वरूप आयात नीति में भी परिवर्तन किया गया और इसे उदार बनाया गया। इस उदार नीति के अंतर्गत देश के 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को कच्चे माल, मशीनों एवं उनके पुर्जों के आयात के लिये विशेष लाइसेंस दिये गए। यह आशा की गई थी कि इससे देश का आंतरिक उत्पादन बढ़ेगा तथा आयातों पर दबाव कम होगा। 1967-68 में सरकार द्वारा घोषित आयात नीति की मुख्य उद्देश्य उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि करना था।

जून 1972 के भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्री ने मसदा में 1972-73 जिस आयात नीति की घोषणा की उसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं।

(i) नई नीति का लक्ष्य आत्म निर्भरता तथा निर्यात में वृद्धि करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये आयात नीति के अंतर्गत 160 वस्तुओं के आयात पर पूर्ण तथा 87 वस्तुओं के आयात पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। (ii) नई आयात नीति के अंतर्गत 46 नई वस्तुओं का आयात सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा (iii) प्राथमिकता प्राप्त कुछ उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता के आधार पर ही आयात कर सकें (iv) विदेशों से सोरने वाले भारतीयों को उद्योग लाइसेंस पर 5 लाख रु० की मशीनें व 2 लाख रु० तक का कच्चा माल आयात करने की सुविधा मिलेगी, (v) निर्यात संस्थानों की अनुदान की सुविधाएं बढ़ाई जायेंगी, (vi) नई वस्तुओं के निर्यात करने वाले निर्यात संस्थानों की अधिक कच्चा माल आयात करने की छूट दी जायेगी, (vii) नई नीति के अनुसार कुछ बाद पड़ इजीप्टी उद्योगों और संस्थानों को सोरने के लिए विशेष सहायता दी जायेगी, (viii) ऐसे उत्पाद आयात करने वालों को विदेशी मुद्रा की सुविधा दी जायेगी, जो अपने उत्पादन का निर्यात करते हैं, (ix) लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन पत्रों को तेजी से निबटाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है आदि।

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई आयात नीति की विद्वानों द्वारा समय समय पर जो समीक्षा की गई वह है निम्नलिखित है

(क) अनिवार्यता सरकार की आयात नीति में इसकी जल्दी जल्दी परिवर्तन जैसे जते हैं कि देश में व्यापारिक अनिवार्यता का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

(ख) सरकार की आयात नीति का आधार विदेशी विनिर्माण की उपलब्धता है, जबकि इसका आधार देश की व आर्थिक औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिये था।

(ग) सरकार द्वारा जारी की गई लाइसेन्स व कोटा प्रणाली इतनी जटिल एवं अचैतनिक है कि इससे भ्रष्टाचार की प्रोत्साहन मिल सकता है।

2 भारत की सरकार निर्यात नीति : भारत सरकार की निर्यात नीति का आधार निर्यात नियन्त्रण व होकर निर्यात-प्रोत्साहन है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सेही सरकार निर्यात बढ़ा कर भुगतान समतुल्य की प्रतिकूलता को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करती चली आ रही है, लेकिन कई कारणों से सरकार अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पाई है। यही कारण है कि भुगतान सम्बन्धी समस्या का समुचित निराकरण नहीं किया जा सका है। गत कुछ वर्षों में तो भारत के निर्यात प्रायः स्थिर रहे हैं। सरकार द्वारा निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न ढंगों में जो निर्यात नीति अपनाई गई है तथा जो कदम उठाये गये हैं, उनका मक्षिण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(1) सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात प्रोत्साहन परिषदें (Export Promotion Councils) बनाई हैं, जो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार को समय-समय पर सुझाव देती हैं। इन परिषदों के कार्यों में कृषि-उत्पाद, रेशम, रेशम, तम्बाकू, मसाले, लाल व इन्जीनियरिंग के सामान आदि के निर्यात को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

(2) सरकार ने निर्यातकर्ताओं की जोखिम को कम करने के लिए जोखिम बीमा निगम (Export Risk Insurance Corporation) की स्थापना की है।

(3) भारतीय माल के बारे में विदेशियों को आवश्यक जानकारी प्राप्त होती रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने समय-समय पर विदेशों में व्यापारिक मेले तथा पर्यटनियों का आयोजन किया है।

(4) निर्यात प्रोत्साहित ही सके इसलिये निर्गत होने वाली अधिकतम वस्तुओं पर से निर्यात कर समाप्त कर दिये गये हैं।

(5) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को यातायात सम्बन्धी सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाती रही है।

(6) भारत सरकार ने 'राज्य व्यापार निगम' (State Trading Corporation) की स्थापना की है, जो सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के अन्ध साम्यवादी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील है। कुछ वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने में इस निगम ने बड़ा सहायनीय कार्य किया है।

(7) निर्यात बढ़ाने के ही उद्देश्य से सरकार ने निर्यात वस्तुओं के उत्पादन करो में छूट दे दी है तथा निर्यात वस्तुओं के निर्यात में प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर दिये गये सट कर या उत्पादन कर को वापस कर देने की नीति अपना रही है, ताकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की उत्पादन लागत घटाई जा सके।

(viii) रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं वित्त निगम, निर्यात व्यापार को शोषाहित करने के लिए निर्यात करने वालों को अल्प एवं मध्यम-कालीन साख सुविधायें भी देते हैं।

(ix) सरकार ने निर्यात व्यापार की वृद्धि के लिये सुझाव देने तथा सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को उचित परामर्श देने के लिये समय-समय पर कई प्राच समितियाँ नियुक्त कीं, जिनके सुझाव निर्यात-सम्बद्ध क्षेत्र में बड़े सहायक हुये हैं। इन समितियों में 'खोरवाला समिति' 1949, 'डी सूजा समिति' 1957 तथा 'मुदा-लियर समिति' 1961 के नाम उल्लेखनीय हैं।

(x) निर्यात सम्बद्ध क्षेत्रों को गुच्चार रूप से चलाने के लिये, सरकार ने कुछ अन्य सम्भागल सशक्त बनाये हैं जिनके कार्यों का विवरण इस प्रकार है : (क) व्यापार मण्डल 1962 इसका कार्य व्यापार के सभी पहलुओं पर विचार करके उनके सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना है। (ख) निर्यात सम्बद्ध निदेशालय 1957 : इसका प्रमुख कार्य निर्यातकर्ताओं को आवश्यक सूचनाएँ तथा सहायता देना है। (ग) क्षेत्रीय निर्यात सम्बद्ध गलाहकार समितियाँ : इन समितियों का प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र के निर्यात में सम्बन्धित समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। (घ) निर्यात सम्बद्ध परिषद् भारत में इस समय 15 परिषदें हैं तथा ये विविध वस्तुओं के निर्यात सम्बद्ध समस्याएँ चर्चा कर रही हैं। (ङ) वस्तु-मण्डल : ये वस्तु-मण्डल भी निर्यात-सम्बद्ध परिषदों की भाँति ही निर्यात बढ़ाने के ढाँचे में लगे हुये हैं। (च) निर्यात साख गारन्टी नियम 1957 : यह नियम निर्यातकर्तों को उन जोखिमों के लिये बीमा सुविधायें दिता है, जो साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं। (छ) खनिज व धातु व्यापार नियम 1963 यह राज्य व्यापार नियम से भिन्न है तथा इसका प्रमुख कार्य खनिज व धातुओं का आयात व निर्यात करना है। इस नियम में कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के निर्यात में बड़ा सराहनीय कार्य किया है। (ज) निर्यात निरीक्षण एजेंसी 1963 यह एजेंसी किस्म निर्यात का कार्य करती है, ताकि निर्यात किये जाने वाला सामान घटिया न हो।

(xi) निर्यात सम्बद्ध मध्यस्थी सुविधाओं के विस्तार के लिये सरकार ने कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं, (क) निर्यात सदन—निर्यात व्यापार में विशिष्टीकरण का विकास करने तथा निर्यातों के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिये, सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत प्रसिद्ध व्यावसायिक पधों को निर्यात सदनो के रूप में मान्यता दी जायेगी तथा इन्हीं निर्यात सम्बन्धी वृत्तिपर्य सुविधायें दी जायेंगी। (ख) विपणन प्रोत्साहन निधि 1963—भारत में निर्यात पदार्थों एवं निर्यातकर्ताओं व उत्पादकों के लिये विदेशी बाजारों के विकास की योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये इसका गठन किया गया है। (ग) निर्यात अधिनियम 1963—

इसके अन्तर्गत बाहर भेजे जाने वाले माल पर अनिवार्य निर्यात-नियन्त्रण तथा जहाज पर माल लाने से पूर्व निरीक्षण व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है।

(xii) 6 जून 1966 को सरकार ने निर्यात वटान के लिए 1966 का अधिनियम पारित किया, ताकि भारतीय वस्तुओं विदेशी बाजारों में समी होकर अधिक बिक सकें।

उपरोक्त प्रयत्नों के बावजूद भी हमारे निर्यात अभी तक यथासंभव बने हुए हैं और हममें कोई विशेष बढ़ि नहीं हुई है। 1967-68 में सरकार ने कई निर्यात वस्तुओं पर हमने पहले फ़ोरे में बन्नी कर भी, जैसे चाय तथा जूट के सामान पर निर्मात कर घटा। ऐसे गेहूँ तथा चमड़े पर निर्मात कर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यही नहीं, कुछ चीजों हुई और परम्परागत वस्तुओं पर दिये जाने वाले नक़द अनुदान की मात्रा बढ़ायी गई।

जुलाई 1970 में भारतीय संसद में पारित निर्यात नीति प्रस्ताव में कुछ निम्न दर से निर्यात अर्जन के लिए निर्यात मूल्य उत्पादन से घटाने पर और दिया गया है। उत्पादन में विकास के साथ साथ वार्षिक कुशलता में वृद्धि उत्पादन का बहु मूल्यकरण तथा कुशल एवं अनुसंधान जनसंख्या का अधिक लाभ उपयोग करने पर बल दिया गया है। कृषि तथा विभिन्न उद्योगों में उत्पादन वृद्धि के प्रयत्नों के साथ-साथ निर्माण करने वाले उद्योगों की सहायता के लिए 1970-71 में भी विनियोग औद्योगिक क्षमता उत्पन्न या विकसित करने के लिए लाइसेंस तथा मशीनरी आदि के माल के आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में उपयुक्त सुधार की भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार ने समय-समय पर निर्धारित वृद्धि के लिये आवश्यक कदम उठाये हैं। हमी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यद्यपि विविध प्रकार के मापदण्ड एवं पाँपों की भी स्थापना की गई है, फिर भी इस दिशा में और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। ऐसा होना पर ही हमारा देश भूतान असन्तुलन की स्थिति से छुटकारा पा सकेगा। इस विषय में निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हैं :—

- (1) निर्यात करने वाले व्यापारियों को और अधिक सुविधायें दी जायें, (2) निर्यात वस्तुओं की उत्पादन लागत घटाई जाये, (3) कृषि उद्योग एवं खनिज पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाये, (4) सरकार, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों द्वारा समर्थित एवं सुनियोजित ढंग से निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया जाये, (5) भारतीय व्यापारियों एवं उत्पादकों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बनाय रखने के प्रयास किये जायें (6) नये-नये विदेशी बाजारों की खोज की जाये तथा इनमें यथोचित प्रचार दिया जाये, (7) विदेशों में औद्योगिक प्रदर्शनियाँ एवं व्यापारिक मेले आयोजित जायें, (8) माल भेजते समय व्यापारियों द्वारा ईमानदारी बरती जायें, (9) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की निर्यात की सुधारा जायें, (x)

यदि निर्यातकर्ता राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करें तो विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये; तथा (x) निर्यात सम्बन्धी वस्तुओं की घरेलू खपत पर यथोचित नियन्त्रण रखा जाये।

प्रश्न

1 भारतवर्ष के प्रमुख आयातों व निर्यातों का वर्णन कीजिये तथा गत कुछ वर्षों में इन्हें बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

2 भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिये।

3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का व्यापार संतुलन सदैव ही प्रतिकूल रहा है आक्यों द्वारा इस वर्णन की पुष्टि कीजिये। व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव भी दीजिए।

4 भारत के विदेशी व्यापार की रचना, मात्रा व दिशा का संक्षेप में विवेचन कीजिए।

5 भारत में गत वर्षों में निर्यात सम्बर्द्धन की दिशा में सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं तथा इन प्रयत्नों को कहाँ तक सफलता उपलब्ध हुई है ?

6 भारत के विदेशी व्यापार के स्वरूप की संक्षेप में विवेचना कीजिए। पिछले वर्षों में सरकारने निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किए हैं ? उनकी प्रभाव कीजिए।

(Raj B A Hons, 1967)

7 हमारे आज के आयात और निर्यात को मुख्य वस्तुओं का वर्णन कीजिए। क्या हमें औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से विदेशी व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ? प्रमाण डालें। (Raj T.D C. Final Year 1967)

विदेशी सहायता

(Foreign Aid)

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विश्व में विदेशी सहायता की आवश्यकता बहुत ही तीव्र गति से समझी जाने लगी। हालांकि जिस समय द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका द्वारा जापान तथा जर्मनी को बहुत अधिक मात्रा में मार्शल योजना के अन्तर्गत विदेशी सहायता दी गई, लेकिन यह भी नज़र भूलना चाहिये कि एक समय ऐसा भी आया था, जब कि अमेरिका ने भी अपने आर्थिक विकास के लिए इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस समय विश्व के जितने भी समृद्धिवादी राष्ट्र हैं, उन्होंने अपने आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी सहायता का आश्रय लिया था।

विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 प्रतिशत भाग गरीबी की जमीरो में फसा हुआ है और वह एक अच्छे ज़िन्दगी के लिए तरस रहा है। अल्प-विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों में यह गरीबी, उस देश की कम उत्पादकता (Low level of productivity) तथा कम उत्पादन स्तर (low level of production) का परिणाम है। किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के वित्तीय आन्तरिक साधनों से प्रभावित होता है। इन राष्ट्रों में आन्तरिक साधनों का सर्वथा से ही अभाव पाया गया है तथा इन्होंने विदेशी सहायता की ओर अपने हाथ फैलाये हैं।

विश्व के विकसित राष्ट्रों की विकास-दर ने इन अल्प-विकसित राष्ट्रों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज विश्व में तकनीकी तथा औद्योगिक क्रान्ति ने एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थिक सहभाग को बढ़ावा दिया है। इसी समय में पियरसन कमिशन (Pearson Commission) ने अपनी रिपोर्ट में जो विश्व बैंक को 1969 में पेश की थी, यह बतलाया कि "अल्प-विकसित राष्ट्रों में विदेशी सहायता द्वारा विकास किए जाने से यह नहीं समझना चाहिए कि वो कोई एक विशेष विचारधारा को ही अपनायेंगे तथा इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि उस देश में राजनैतिक स्थिरता

भी रहेगी। यह भी आवश्यक नहीं है कि ये राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए शान्तिप्रिय तथा उत्तरदायित्व भावना को अपनाए।" इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि विदेशी सहायता का प्राप्त हो जाना इस बात का प्रतीक नहीं है, कि वह राष्ट्र आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होया।

विदेशी सहायता की आवश्यकता

(i) अल्प विकसित राष्ट्रों में सर्वथा से ही पूँजी का अभाव पाया जाता है, जो कि आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इन राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, जिसके कारण आन्तरिक संचयों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। आन्तरिक संचयों के अभाव में इन राष्ट्रों में पूँजी निर्माण (Capital Formation) की भी बहुत नीची दर पायी जाती है।

(ii) आज के बढ़ते हुए वैज्ञानिक युग में देश में उद्योगों की स्थापना को भी एक विशेष महत्त्व दिया गया है। उद्योगों की स्थापना के लिए पूँजी की आवश्यकता बहुत ही अधिक मात्रा में पड़ती है तथा पूँजी के अभाव में इन अल्प विकसित राष्ट्रों को विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

(iii) विकसित तथा अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के बीच आर्थिक असमानता को खाई को कम करने के लिए भी विदेशी सहायता की आवश्यकता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही देश में आर्थिक विकास का भार बढ़ गया। योजना निर्धारित करने वाले अर्थशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने राष्ट्र के पुनः निर्माण तथा विकास की आवश्यकता को समझा तथा जिसके बिना देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग अवरोध हो गया था। स्वतन्त्रता के बाद से ही राष्ट्रीय सरकार ने भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की योजना की तथा पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी इसी उद्देश्य की लेकर की गई। यही कारण है कि भारत की इसी पंचवर्षीय योजना में देश के आन्तरिक संचयों का विदेशी सहायता के साथ समन्वय स्थापित किया गया और भारत को पिछले 25 वर्षों में बहुत ही मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हुई है।

पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता की मात्रा

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। पहली योजना में नुल विनियोग का 5.8%, दूसरी योजना में 13.1%, तीसरी योजना में 19.4%, तीन वार्षिक योजनाओं में 34.2% तथा चौथी योजना में 8.7% विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त किया गया है। पिछले

बोस वर्षों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई सहायता तथा उसके उपयोग में निम्न तालिका में दिखाया गया है

कुल विदेशी सहायता		(रुपये करोड़ में)
वर्ष	स्वीकृत की गई विदेशी सहायता (Authorisation)	प्रयोग में आई गई विदेशी सहायता (Utilization)
तृतीय योजना के अन्तर्गत	5730.8	4508.8
1966-67	1419.0	1054.9
1967-68	717.9	1195.7
1968-69	942.3	902.6
1969-70	634.3	866.3

इस प्रकार उक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत की 1951 से 1970 तक करीब 10,000 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से 8500 करोड़ रुपये का प्रयोग किया जा चुका है। इस सहायता का प्रयोग करने की गति भारत में शुरू में बहुत धीमी रही, लेकिन जैसे-जैसे विकास के बीज बोये जाने लगे, जैसे-जैसे विदेशी सहायता का प्रयोग भी तीव्र गति में किया जाने लगा है।

वर्ष 1971 तक कुल प्रमुख सहायता में बांग्लादेशी सहायता का अंश 53.4% पश्चिम जर्मनी व फ्रैंक रिटेन प्रत्येक का 7.2%, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों¹ का 12.9%, सोवियत रुम का 5.7% तथा अन्य राष्ट्रों का 13.6% था।

प्रथम योजना का अवधि में भारत का लगभग 382 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता स्वीकृत हुई, जिसमें से इस योजना में 197 करोड़ रुपये प्रयुक्त किए गए। दूसरी योजना में 2539 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई, जिसमें से 1320 करोड़ रुपये प्रयोग किए गए तथा तृतीय योजना में 2810 करोड़ रुपये में से 2673 करोड़ रुपये प्रयुक्त किए गए। तथा चौथी योजना में विदेशी सहायता का अंश 2134 करोड़ रुपये का रखा गया है।

विदेशी सहायता का वर्गीकरण—भारत को विदेशी सहायता कई प्रकार से प्राप्त हुई है, निम्न वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

1. विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आदि के नाम प्रमुख हैं।

(1) ऋण (Loans) विदेशी सहायता में ऋणों का एक विशेष महत्व है। इस प्रकार की विदेशी सहायता को ब्याज पर प्राप्त किया जाता है, अर्थात् इस धन की वापसी एक निश्चित ब्याज दर पर की जाती है। भारत को अभी तक प्राप्त कुल विदेशी सहायता का 60% सहायता ऋणों के रूप में मिली है।

(ii) अनुदान (Grants) अनुदान के अन्तर्गत प्रप्त राशि पर किसी भी प्रकार से ब्याज नहीं देना पड़ता तथा न ही इस धन के अन्तर्गत प्राप्त सहायता की वापसी की जाती है। इस प्रकार की सहायता का अंश कुल सहायता का 9% है।

(iii) खाशानों के रूप में आर्थिक सहायता इस प्रकार की सहायता भूमिहीन सार्वजनिक कानून (PL 480 तथा PL 663) के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। इसके अन्तर्गत प्राप्त ऋणों का गुणस्तर रुपये में किया जाता है। इस राशि का उपयोग विशेषतया भारत में ही निजी क्षेत्र में विनियोजित करके किया जाता है। इस प्रकार की सहायता का अंश 31 प्रतिशत है।

विदेशी सहायता का वर्गीकरण दोधो हुई (tied) अथवा 'स्वतन्त्र' (untied) में आधार पर भी किया जाता है। बँधी हुई सहायता या तो देश के अनुसार होती है, या विशेष परियोजना (project) के अनुसार होती है, अर्थात् उसी राष्ट्र से मात्र खरीदना पड़ता है, जिसने सहायता की है। इस प्रकार की सहायता में अगर निर्धारित समय में धन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो सहायता भी उपयुक्त हो रह जाती है तथा दूसरी तरफ स्वतन्त्र सहायता में किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं होता है। इसीलिए आजकल इसी प्रकार की विदेशी सहायता को एक विशेष महत्व दिया जाने लगा है।

इस विदेशी सहायता के अलावा भारतवर्ष में विदेशी निजी पूँजी का विनियोग भी अधिक मात्रा में होता है। इसका वर्गीकरण भी दो आधार पर किया गया है —

(a) प्रत्यक्ष विनियोग (Direct Investment) इस प्रकार के विनियोग के अन्तर्गत सम्पूर्ण नियन्त्रण विदेशी स्वामित्व में होता है।

(ii) पोर्टफोलियो विनियोग (Portfolio Investment) इस प्रकार के विनियोग के अन्तर्गत सम्पूर्ण नियन्त्रण भारतीय स्वामित्व में रहता है तथा विनियोग पर या तो ब्याज या साधारण आदि का भुगतान कर दिया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि विदेशी सहायता विभिन्न राष्ट्रों से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। भारत की पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में विदेशी पूँजी ने एक बहुत ही

महत्वपूर्ण योगदान किया है। अर्थ-व्यवस्था के हर क्षेत्र में चाहे वह कृषि हो अथवा उद्योग वही माया में विदेशी पूँजी विनियोजित है।

विदेशी सहायता की सम्भावित कठिनाइयाँ

निजी भी राष्ट्र को विदेशी सहायता का प्रयोग करने से कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ व्याज के बोझ तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कई प्रकार के राजनैतिक कारण भी विदेशी सहायता को मात्रा निर्धारित करते हैं।

(1) किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र को विदेशी सहायता प्राप्त करने से उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता का हनन होता है, क्योंकि इस प्रकार की पूँजी राजनैतिक कारणों से प्रभावित होती है। आज विश्व के दो महान राष्ट्र भोवियत रूस तथा अमरीका द्वारा जितनी भी विदेशी पूँजी, ऋण अथवा अनुदान के रूप में दी जा रही है, राजनैतिक कारणों से प्रभावित है। इस प्रकार इन राष्ट्रों से विदेशी पूँजी प्राप्त करने के लिए देश की आर्थिक नीतियों में उसी प्रकार से परिवर्तन करना पड़ता है, जिस आधार पर इसकी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

(ii) अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त करने से देश की आर्थिक निर्भरता भी ऋण तथा अनुदान की सुविधाएँ देने वाले राष्ट्र की तरफ बढ़ जाती है। इस निर्भरता से कोई भी अस्थविक्रमिष्ठ राष्ट्र अपने आन्तरिक साधनों को विस्तार करने की कोशिश नहीं करता। फलस्वरूप वह राष्ट्र बुलामी की रेडियो में जकड़ा रहता है।

(iii) विकसित राष्ट्रों द्वारा विकसारील राष्ट्रों को जो सहायता दी जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य अपने पूँजीगत उत्पादन को यथेष्ट विपणन सुविधा प्रदान करना होता है। ऋणदाता देश अतिसुक्त सहायता प्रदान करते हैं जिसके अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश को सहायता प्रदान करने वाले देश से पूँजीगत प्रसाधन एवं कच्चा माल आदि प्राप्त करना होता है। दूसरी ओर, विकसित राष्ट्र विकसारील राष्ट्रों से उपभोग्यता एवं प्रविधिकृत (processed) वस्तुएँ आयात करने को तैयार नहीं रहते जब तक कि ये वस्तुएँ उन्हें न्यूनतम मूल्य पर न दी जाय। इसका परिणाम यह होता है कि सहायता प्राप्त करने वाला देश ऋण शक्ति खोदने में प्रयास असमर्थ रहते हैं और उन्हें पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण लेने पड़ते हैं जिससे उनका प्रतिकूल भुगतान क्षय तथा विदेशी ऋण-दायित्व बढ़ जाता है।

(iv) इस आर्थिक निर्भरता अथवा राजनैतिक दबाव के अलावा विदेशी सहायता के परिणामस्वरूप देश पर व्याज तथा ऋण के भुगतान का बोझ निरन्तर बढ़ता रहता है। आधे दो बर्षों तक से भारत के कुछ ऋण सम्बन्धी अदायगियाँ स्पष्ट हो जाती हैं।

कुल ऋण सम्बन्धी अदायगियाँ

(करोड़ रुपये में)

	मूलधन की अदायगी	व्याज की अदायगी	कुल ऋण सम्बन्धी अदायगियाँ
प्रथम योजना	10.5	13.3	23.8
द्वितीय योजना	55.2	64.2	119.4
तृतीय योजना	305.6	237.0	542.6
1965-67	159.7	114.8	274.5
1967-68	210.7	122.9	333.0
1968-69	236.2	138.8	375.0
1969-70	268.5	144.8	412.3
1970-71	282.5	152.2	434.7

Source : Economic Survey 1970-71

इस प्रकार सम्पूर्ण तालिका से स्पष्ट है कि भारत के ऊपर मूलधन व व्याज की चुकाने का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह बात राखि ली कि 23.8 करोड़ रुपये जो कि पहली योजना से थी, बढ़कर 1970-71 में 434.7 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। इस बढ़ती हुई ऋण अदायगी से भारत में विदेशी सहायता (Net foreign aid) का अर्थ काफी कम हो गया है और यह 1971-72 में कुल सकल विदेशी सहायता (Gross foreign aid) का 43% था, अतः स्पष्ट है कि कुल विदेशी सहायता का 57% ऋण सम्बन्धी अदायगियों के रूप में पावित किया जा रहा है।

इस बढ़ती हुई ऋण सम्बन्धी अदायगी का मुख्य कारण एक तो निर्मात को प्रोत्साहन न मिलने के कारण तथा दूसरा ऋणों का ठीक प्रकार से उपयोग न करने के कारण विदेशी मुद्रा की सहा से ही भारत में कमी महसूस की गई।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पिछले 23 वर्षों में भारत की बहुत ही अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हुई है और यह भी स्पष्ट है कि अगर इस प्रकार से विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होती तो भारत में औद्योगिक तथा कृषि के विकास के लिए जो विस्तृत कार्यक्रम बनाये गये हैं, अपूर्ण रहते। आज भारत के हर औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूँजी किसी न किसी रूप में लगी हुई है।

लेकिन उनके लाभ-गाथ यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर विकास के लिए विदेशी पूँजी की ओर पूर्ण निर्भरता रखी गई, तो देश का विकास विदेशियों के हाथ में फँस जाएगा तथा देश की स्वतन्त्रता को सबसे सतत खतरा लगेगा, जैसा कि 1971 के भारत-पाक युद्ध से स्पष्ट हो गया है। अमेरिका द्वारा दी जाने वाली विदेशी

सहायता ने पाकिस्तान उसके नियन्त्रण में रहा, लेकिन इस प्रकार के श्रृण की सुविधायें भारत को बन्द हो जाने से भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। घत जिस प्रकार की नीति अमरीका ने 1971 में दक्षिणी पूर्वो एशिया में अपनायी, उससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि अमरीका सिर्फ अपना राजनैतिक प्रसुत्व जमाने के लिए इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्रदान कर रहा है।

जहाँ तक प्रश्न भारतीय अर्थ-व्यवस्था का है भारत के ऊपर इन विदेशियों का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और अब सरकार प्रयत्नशील है कि सन् 1980 तक भारत पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर हो जाए। ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि सभी देश अपनी नीतियों में स्वतन्त्रता बनाए रख सकते हैं।

प्रश्न

1. भारतीय योजनाओं में विदेशी सहायता के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
2. विदेशी सहायता से किसी भी राष्ट्र को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका सविस्तार वर्णन कीजिए।
3. विगत नियोजन काल में भारत को जो विदेशी सहायता मिली है उसका उल्लेख करते हुए उन समस्याओं पर प्रकाश डालिए जो इसके भुगतान से सम्बन्धित हैं।

खण्ड छठा

- 1 भारत की राष्ट्रीय आय
(National Income of India)
- 2 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य एवं ग्रहण रचना
(Objectives and Strategy of India's Five Year Plans)
- 3 भारतीय योजनाओं की अर्थ व्यवस्था
(Financing of Indian Plans)
- 4 भारत में नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक प्रगति
(Economic Progress under Planning in India)

भारत की राष्ट्रीय आय

(National Income of India)

**National Income Statistics provide a wide view of the Country's entire economy, as well as of the various groups in the population who participate as producers and income receivers, and that if available over a substantial period, they reveal clearly the basic changes in the Country's economy in the past and suggest, if not fully reveal trends for the future*

—National Income Committee

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition)

राष्ट्रीय आय किसी देश की किसी वर्ष विद्यमान वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के कुल योग के बराबर होती है। किसी देश की अर्थ व्यवस्था में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा सम्पन्नित रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है, उसे राष्ट्रीय आय के नाम से पुकारा जाता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति के अर्थों के अन्तर को रुझान देना भी अनुपयुक्त न होगा। राष्ट्रीय आय प्रायः देश के एक वर्ष में होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन को कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय सम्पत्ति से आशय है कि समय विषय पर देशवासियों के पास होने वाली समस्त सम्पत्ति से है।

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में प्रो० मार्शल, पीगू तथा फिशर ने अलग-अलग मत दिए हैं। प्रो० मार्शल के अनुसार, “एक देश का भूमि एवं पूँजी इसके प्राकृतिक साधनों की सहायता से प्रति वर्ष भौतिक एवं अर्थोत्पत्तिक वस्तुओं (जिनमें सेवाएँ भी सम्मिलित हैं) की एक निश्चित शुद्ध उत्पत्ति करता है। इसे ही वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं।”¹ प्रो० पीगू ने राष्ट्रीय आय को इस

1 The Labour and Capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial including services of all kinds. This is the true Net Annual Income or Revenue of the country or the National Dividend.²

है (विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित करते हुए), जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है।¹ इस प्रकार पीगू राष्ट्रीय आय में केवल उस उत्पात्ति को सम्मिलित करते हैं, जो मुद्रा में नापी जा सकती है। फिर इन दोनों विचारधाराओं से सहमत नहीं है उनके मतानुसार राष्ट्रीय आय सम्पूर्ण उत्पत्ति वा वह भाग है जिसे किसी वर्ग उपभोग में लिया जाता है। प्रो० फिशर के ही शब्दों में, "राष्ट्रीय आय वा लभभावा में केवल प्रकार परिभाषित किया है, "राष्ट्रीय आय समाज की भौतिक आय का वह भाग वही सेवाएँ, चाहे वे उनके भौतिक बातावरण से प्राप्त हों या मानवीय बातावरण से, सम्मिलित होती हैं जोकि अन्तिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं।"² प्रो० साइमन कुजनेट्स का विचार बहुत कुछ फिशर की धारणा से मिलता-जुलता है। कुजनेट्स के शब्दों में, "राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं की विशुद्ध उत्पत्ति है जो अन्तिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुँचती है जयवा देश के पूँजीगत नाश के स्टॉक में वृद्धि करती है।"³

उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रो० मार्शल की परिभाषा व्यावहारिक है, क्योंकि (i) कुल उत्पत्ति की गणना करना शक्ति है, तथा (ii) राष्ट्रीय आय की वस्तुओं व सेवाओं के रूप में प्रगट करने पर इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। पीगू की परिभाषा गणवि निश्चित एवं व्यावहारिक है लेकिन यह तर्क सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता जो मुद्रा के माध्यम में नापी नहीं जा सकती हैं। प्रो० फिशर की परिभाषा भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपभोग में प्रयोग हुई वस्तुओं की गणना करना और भी कठिन काम है। अतः तर्कमग्न न होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से पीगू की ही परिभाषा को उपयुक्त माना जा सकता है।

1949 की भारत की राष्ट्रीय आय समिति (Indian National Income Committee) ने भी यह ही आय को परिभाषित किया है। इसके अनुसार "राष्ट्रीय आय वह निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं की माप है। इसमें देश

1. "National Dividend is the sum of the objective income of the community, including, of course, income derived from abroad, which can be measured in terms of money." — Pigou
2. "National Dividend or Income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environment." — Irving Fisher
3. "National income is the net output of commodities and services flowing during the year from the country's production system into the hands of the ultimate consumers or into net additions to the country's stock of capital goods." — Kuznets

की सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, चाहे इनका सम्बन्ध खूने या गहराओं के निर्माण करने से हो या चिकित्सा एवं न्याय सम्बन्धी सेवाओं से।"²

राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व (Importance of the Study of National income) :

किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। ये कारण अप्रतिष्ठित हैं :

1. देश के आर्थिक विकाश की माप : किसी देश के आर्थिक कल्याण में हुए परिवर्तनों की मापने में राष्ट्रीय आय के अनुमानों का सहारा लिया जा सकता है। प्रो० मार्शल के मतानुसार, "अन्य बातें समान रहने पर, किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है, उस देश का आर्थिक कल्याण उतना ही अधिक समझा जाता है।"

2. जीवन-स्तर सम्बन्धी ज्ञान : किसी देश की राष्ट्रीय आय से उस देश के नियासियों के रहन-सहन के स्तर का गहरा सम्बन्ध होता है। सामान्यतः देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। लेकिन देश में यदि आर्थिक असमानता पाई जाती है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद जीवन-स्तर में कोई अंतर नहीं आता है। राष्ट्रीय आय के वितरण सम्बन्धी आँकड़ों से हमें मालूम पड़ सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कितनी बड़ी है जगहा पड़ रही है।

3. देश की आर्थिक अवस्था का ज्ञान : देश के आर्थिक विकास की अवस्था सम्बन्धी जानकारी भी हमें राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से प्राप्त हो सकती है। ये आँकड़े देश की अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक प्रगति की दर पर प्रकाश डालते हैं। इन आँकड़ों को देखकर ही यह निश्चय किया जाता है कि देश विकसित है अथवा अल्प-विकसित। इन आँकड़ों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि अर्थ-व्यवस्था सुधार की दिशा में ऊँच है या नहीं।

4. आर्थिक नियोजन में महत्व : राष्ट्रीय आय का अध्ययन आर्थिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। योजनाओं को बनाने एवं उनके लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इन आँकड़ों पर ही वस्तु एवं विनियोजन की दर निर्भर करती है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत देश की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न वर्गों, लोगों एवं वर्गों में से किसकी प्राथमिकता दी जाए, इसका निर्धारण राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के आधार पर ही किया जाता है। स्वयं आर्थिक नियोजन का मूलभूत उद्देश्य भी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना ही होता है।

5 सरकारी नीति के निर्धारण में महत्व : राष्ट्रीय आय सरकार की आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण आधार का काम करती है। उचित मौद्रिक, राजस्व तथा रोजगार सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित करने के लिए ये आँकड़े आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन इनकी उपयोगिता बहुत कुछ व्यापकता एवं विवरणनियता पर निर्भर करती है।

॥ विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना में सहायता : राष्ट्रीय आय ॥ आँकड़ों से हम विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना करने में सहायता मिलती है। विभिन्न देशों की कुल खपत, प्रतिशक्ति, राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से हम उन देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की ही जानकारी से यह मालूम किया जा सकता है कि विभिन्न देशों में उद्योग, उद्योग, कृषि, परिवहन में प्राप्त आय कुल आय का कितना भाग है। इन प्रकार के तथ्यों की जानकारी से सम्बन्धित क्षेत्रों की प्रगति का ठाक एवं तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) का यह कथन उचित ही है, "राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ें देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का एक व्यापक दृश्य प्रस्तुत करते हैं और साथ ही देश की जनसंख्या के उन वर्गों पर भी प्रकाश डालते हैं जो या तो उत्पादक के रूप में भाग लेते हैं अथवा आय प्राप्त करने वाले के रूप में। यदि राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ें एक सम्बन्धी अवधि के उपलब्ध हैं, तो इनसे देश की अर्थ-व्यवस्था में हुए आधारभूत परिवर्तनों का पता चलता है और यदि पूरी तरह से रजिस्ट्रोड्वाउन न भी करे तो भी ये आँकड़ें, प्रविध्य की प्रवृत्तियों की ओर संकेत देते हैं।"¹

राष्ट्रीय आय और आर्थिक उन्नति

(National Income and Economic Progress)

सामान्यतः किसी देश की राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय को देश की आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तथा देश की उत्पादन क्षमता एवं उपभोग सम्भावनाओं में भी वृद्धि

1. 'National Income statistics provide a view of the country's entire economy, as well as of the various groups in the population who participate as producers and income receivers and that if available over a substantial period they reveal also the basic changes in the country's economy in the past and suggest, if not fully reveal, trends for the future.'

हो जाती है। लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता। निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि, देश की समृद्धि का संकेत नहीं बतती है :

(1) देश के निवासियों की भौतिक आय के बढ़ जाने के बावजूद भी यदि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाय तो उनका वास्तविक उपभोग वही बढ़ पाता।

(2) राष्ट्रीय आय के बढ़ने से यह तो शायद होता है कि देश में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है। युद्ध काल में यदि देश में युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि होती है तो इससे राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो ही जाती है, लेकिन देश के लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं उठता। इसी प्रकार यदि भविष्य-काल में गाँजा, शराब, ताराम जैसी नशीली वस्तुओं का ही उत्पादन बढ़ता है तो इससे भी सामान्य जनता के वास्तविक जीवन स्तर में कोई उन्नति नहीं होती।

3 राष्ट्रीय आय की वृद्धि, जादि लोगों के आराम रहित परिणाम का परिणाम है तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने के बावजूद भी लोगों का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। राष्ट्रीय आय के आंकड़ इस तथ्य को नहीं प्रकट करते कि इसे प्राप्त करने के लिए देश की अमत्ता को कितना कष्ट उठाना पड़ा है।

4 यदि देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि देश के प्राकृतिक साधनों के अथवा अल्पकाल में अत्यधिक अतिव्ययित साधनों के फलस्वरूप हुई है, तो ऐसी आय वृद्धि के दूरमायी परिणाम देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं होंगे।

5 देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हो जाती है। लेकिन इस जीवन आय की वृद्धि के साथ साथ देश में आय के वितरण की विषमता भी बढ़ती जाती है, तो जनसाधारण का रहन सहन का स्तर ऊँचा होने की बग़ाय नीचा भी हो सकता है।

6 यदि राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को बराबर वितरित करने में वृद्धि की जाती है, तो इससे देश के सभी वर्गों के विकास पर ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है लेकिन देश के निवासियों के वर्तमान उपभोग व जीवन स्तर पर बुरा असर पड़ता है।

राष्ट्रीय आय की गणना की रीतियाँ निम्न लिखित हैं
(Methods of Calculating National Income) —

1 उत्पादन गणना प्रणाली (Census of Production Method) — इस प्रणाली के अन्तर्गत हम एक वर्ष की अवधि में उत्पादित या विनिर्मित मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। इसी बात करते समय हम कुल उत्पादित के मूल्य में से विदेशी के कारण हुआ

मूल्य-हास तथा बच्चे माल का मूल्य निर्धार देते हैं। सभी उद्योगों का विस्तृत मूल्य मालूम करके योग कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें विस्तृत घरेलू उत्पादन मालूम हो जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली विस्तृत आय को जोड़कर विस्तृत राष्ट्रीय आय प्राप्त कर ली जाती है।

2. आय गणना प्रणाली (Census of Income Method) : इस प्रणाली के अनुसार उत्पत्ति के विभिन्न स्तरों को प्राप्त होने वाली आय को जोड़ लिया जाता है। इन सभी व्यक्तियों का जो आय कर देते हैं, तथा जो आय-कर नहीं देते हैं उनकी आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त कर ली जाती है। इसमें सरकारी और घर प्राकृतिक सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय को भी जोड़ लिया जाता है। आय की गणना करने में यह साधनी रखनी चाहिए कि एक आय को दो बार न जोड़ लिया जाय।

3. उत्पादन गणना तथा क्रय गणना प्रणाली का सम्मिलित उपयोग—कई बार इन दोनों प्रणालियों को मिलाकर राष्ट्रीय आय को मालूम किया जाता है। 210 बी० के० आर० बी० राय ने इन दोनों प्रणालियों के सम्मिलित उपयोग का सफलता से किया है। भारत जैसे पिछड़े हुए देश में यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने में इन दोनों विधियों का सम्मिलित उपयोग किया है। कृषि, पशु-पालन, वन-उद्योग, शिकार, मछली पकड़ने, खान खोदने तथा औद्योगिक उत्पादन के अनुमानों के लिए उत्पादन गणना प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। व्यापार, परिवहन, वसाहन, मत्तित कलाओं तथा घरेलू सेवाओं के अनुमान लगाने के लिए व्यय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय के अनुमान (National Income Estimates of India) भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनुमान लगाए गए हैं। इस सम्बन्ध में सबसे पहले सन् 1868 ई० राष्ट्रीय आय का पता दादा भाई नौरोजी ने लगाया। उनके अनुमान के अनुसार उस वर्ष देश की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। तब से लेकर आज तक अनेक विद्वानों द्वारा राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में अनुमान लगाए गए हैं।

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाए गए थे, उनमें से प्रमुख अनुमान पृष्ठ 473 पर दी गई तालिका में दिए आ रहे हैं।

स्वतंत्रता-पूर्व-काल में प्रति व्यक्ति आय के अनुमान

अनुमानकर्ता	अनुमान का वर्ष	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (रु० में)
दादा भाई नोरोजी	1868	20
कोमर तथा बारबर	1881	27
विलियम डिग्बी	1899	18
सांडे वॉलन	1900	30
फिशले सिराज	1911	49
बाठिया और जोषी	1922	116
राहु एच सम्बत	1913-14	74
बी. के. शार बी. राय	1921	65
थार सी. ऐन्साई	1913-14	85
ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट	1931-32	72
	1913-14	
	1939-40	

उपरोक्त अनुमानों में से अधिकतर अनुमानों का केवल ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि वे या तो व्यक्तिगत प्रयासों के परिणाम थे या फिर प्रकाशकीय आवश्यकताओं के फलस्वरूप लगाए गए थे। इनमें से अधिकांश अनुमानों में गम्भीर त्रुटियाँ थी क्योंकि एक तो इन व्यक्तियों के साधन अत्यन्त सीमित होने के कारण उनके लिए सनस्त देश के उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करना सम्भव नहीं था तथा दूसरे, अलग-अलग अनुमानकर्ताओं ने भिन्न-भिन्न विधियों का उपयोग किया था, जिससे इन अनुमानों की उपयोगिता अत्यन्त कम हो गई। इन आँकड़ों से अनुमान या ही भ्रम अधिक होने के कारण इन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। चूँकि स्थिर मूल्यों पर कम-अनुमान (series estimate) तैयार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, अतः इन आँकड़ों के आधार पर हम विभिन्न समयों के राष्ट्रीय आय अनुमानों में तुलना नहीं कर सकते।

इन अनुमानों की एक त्रुटि यह भी है कि वे निष्पक्ष नहीं थे। ये अनुमान या तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रवादी विचारों वाले व्यक्तियों द्वारा तैयार किये गये थे या स्वयं सरकार द्वारा अपनी नीतियों के समर्थन के लिए या अपना पक्ष प्रबल करने के लिए तैयार किए गए थे।

इन त्रुटियों के बावजूद भी इन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने का गम्भीर सोचाओं के बावजूद भी इन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने का

यह काम हाथ में लिया, जो साधारणतः देश की सरकार को करना चाहिए था। उपर्युक्त अनुमानों में डा० बी. के. जार बी. राम के अनुमान अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। डा० राम ने ज्ञान सर्वोत्तम से सम्बन्धित उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ वैयक्तिक तथ्यें आज भी थीं।

(ख) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् किए गए अनुमान - सन् 1947 ई० में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय गण सम्बन्धी मध्य ज्ञान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, भारत सरकार ने 4 अगस्त, 1949 ई० को कानूनी स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute) के प्रो० प्रतापचन्द्र महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष प्रो० डी. आर. गाडगिल तथा प्रो० बी. के. जार बी. राम थे। इस समिति के लिए पेरिसमें निवासी विश्वविद्यालय के प्रो० साइमन कुजनेट्स तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० रिचर्ड स्टोन और राष्ट्रीय संघ के ज्ञान कार्यालय के डा० जे. बी. डी० चर्र्सन जैसे विशेषज्ञों से परामर्श लेने की भी व्यवस्था की गई।

इस समिति के लिए अग्रलिखित कार्य निर्दिष्ट किए गए

- (1) राष्ट्रीय आय एवं सम्बन्धित तथ्यों पर रिपोर्ट तैयार करना,
- (2) प्राप्त आँकड़ों में सुधार करना तथा नए आँकड़ों के संग्रह के सम्बन्ध में सुझाव देना, तथा
- (3) राष्ट्रीय आय सम्बन्धी शोध-कार्य को प्रोत्साहित देना।

राष्ट्रीय आय समिति की पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल, 1951 को तथा अन्तिम 14 फरवरी, 1954 को प्रकाशित हुई। भारत के आर्थिक इतिहास में राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इससे पहली बार सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रीय आय के आँकड़े उपलब्ध हुए थे। इस समिति के अनुसार 1948-49, 1949-50 तथा 1950-51 में हवाई राष्ट्रीय आय, बालू मूल्यों में क्रमशः 8650, 90% तथा 9030 करोड़ रुपये थी तथा प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 246 9, 253 9 तथा 265 2 रु० प्रति वर्ष थी।

राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय को थालूम करने के लिए उत्पादन गणना एवं आय गणना दोनों ही रीतियों का प्रयोग किया था। समिति को कुछ क्षेत्रों में आय ज्ञान करने के लिए अनुमानों का सहारा लेना पड़ना था, क्योंकि उन क्षेत्रों सम्बन्धी आँकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट की प्रमुख बातें अग्रलिखित हैं।

भारत की राष्ट्रीय आय

(i) राष्ट्रीय आय में कृषि लगभग आधा योगदान देती है, (ii) राष्ट्रीय आय का लगभग छठा भाग खनिज, निर्माण व हस्त-शिल्प से होता है, (iii) यानिज्य, परिवहन व संचार का योगदान राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय के छठवें भाग से कुछ अधिक है, (iv) सेवाओं व्यवसायों, प्रशासनिक व घरेलू सेवाओं आदि का वंश राष्ट्रीय आय का 15 प्रतिशत है, (v) कृषि, खनिज, कारखानों व हस्तशिल्प से राष्ट्रीय आय का लगभग दो तिहाई भाग प्राप्त होता है, (vi) कुल राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की सेवाओं का योगदान लगभग एक तिहाई है, (vii) घरेलू उद्योगों व भाग आन्तरिक उत्पादन में लगभग दो-तिहाई है जबकि कारखाना उत्पादन से आन्तरिक उत्पादन का 10 से 11 प्रतिशत उत्पादन प्राप्त होता है, (viii) देश की कुल श्रम शक्ति कुल जनसंख्या की 39.8 प्रतिशत थी, (ix) वर्षाव कुल श्रम शक्ति का 72.4 प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ था, तथापि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान केवल 51.3 प्रतिशत ही था, जो कृषि के रुपये कम उत्पादक व्यवसाय होने का सूचक है, (x) लगभग उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों का संख्या लगभग 140 लाख थी, जिसमें से 110 लाख छोटे उद्योगों में थे, जब 30 लाख बड़े कारखानों में, (xi) 1950-51 में छूट घरेलू उत्पादन में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का भाग क्रमशः 7.6 प्रतिशत व 92.4 प्रतिशत था (xii) राष्ट्रीय आय में सरकार का भाग 1950-51 में 820 करोड़ रुपये अर्थात् राष्ट्रीय आय का 8.2 प्रतिशत था।

योजनाकाल में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति आन्तरिक से सन् 1965-66 तक अपनी हीम पचवर्षीय योजनाएँ पूरी कर ली है। भारतीय नियोजन का प्रभाव राष्ट्रीय आय पर क्या पड़ा, इसे समझने के लिए 1950-51 के 1965-66 के काल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अध्ययन करना आवश्यक है।

योजनाकाल में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति

वर्ष	घट गष्टीय आय (आगतो रुपयो मे)		प्रति व्यक्ति आय (रुपयो मे)	
	आलू मूल्यो पर	1948-49 के मूल्यो पर	आलू मूल्यो पर	1948-49 के मूल्यो पर
1950-51	95.3	104.5	266.5	247.5
1955-56	99.1	104.8	255.0	267.8
1960-61	141.4	127.3	306.1	293.2
1965-66	203.4	146.1	425.0	301.8
1966-67	231.2	149.5	482.7	300.8
1970-71	342.5	N/A	633.1	N/A

विश्व के अन्य देशों से तुलना

(Comparison with other countries)

भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय विश्व के प्राय सभी सुसम्पन्न देशों से कम है। आय की यह कमी हमारी निधनता की निशानी है। भारत की प्रति व्यक्ति आय की अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय से तुलना निम्न तालिका में की गई है, जो विश्व बैंक के एक प्रकाशन पर आधारित है। इस तालिका में दिए गए एक अव-मूल्यन (1966) के पूर्व से हैं।

प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (अमरीकी डॉलर में)

देश	आय	देश	आय
1 अमरीका	१,२४०	७ ययुन अरब गणराज्य	१५०
२ आस्ट्रेलिया	१,७००	८ श्रीलंका	१४०
३ फ्रान्स	१,६२०	९ भारत	९०
४ इंग्लैण्ड	१,५५०	१० पाकिस्तान	८५
५ जापान	७६०	११ नाइजीरिया	८०
६ इर्की	२३०	१२ बर्मा	६५

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल ९० डॉलर प्रति वर्ष है। अवमूल्यन के पश्चात् तो यह केवल ६० डॉलर ही प्रति वर्ष रह गई है।

राष्ट्रीय आय वितरण की अन्य देशों से आय वितरण से तुलना (Distribution of National Income and its comparison with other countries) राष्ट्रीय आय के वितरण से सम्बन्धित आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में वितरण सम्बन्धी अधिक समानता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा प्रकाशित आँकड़े इस सम्बन्ध में यथोचित प्रकाश डालते हैं। भारत-वर्ष में (सन् १९०३-०४ से लेकर सन् १९५६-५७ तक) नीचे के २० प्रतिशत व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय आय का ८ प्रतिशत तथा नीचे के ६० प्रतिशत व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय आय का ३६ प्रतिशत भाग था। अमेरिका में (१९५० ई० में) उपर्युक्त दोनों वर्गों के पास क्रमशः ४८ व ३२ प्रतिशत राष्ट्रीय आय थी तथा इंग्लैण्ड में (१९०१-५२) में क्रमशः ५४ व ३३ प्रतिशत राष्ट्रीय आय थी। इनो प्रन्जर ऊपर के ५ या १० व्यक्तियों के पास, भारत की तुलना में, इन देशों में, आय का अधिक भाग प्राप्त था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में इन पूँजीवादी देशों की तुलना में, आय के वितरण में अपेक्षाकृत कम असमानता थी।

राष्ट्रीय आय का विभिन्न राज्यों में वितरण (Distribution of National Income in different States) सन् 1960-61 में National Council of Applied Economic Research, (NCAER) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से, भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय आय के वितरण व प्रति व्यक्ति आय की स्थिति के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार थी

भारतीय राज्यों में आय का वितरण

राज्य	कुल उत्पत्ति (करोड़ रु० में)	प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)
1 दिल्ली	232	871 6
2 महाराष्ट्र	1,853	468 5
3 पश्चिमी बंगाल	1,623	464 6
4 पंजाब	917	451 3
5 गुजरात	812	393 4
6 तामिलनाडु	1,125	394 1
7 आसाम	396	333 3
8 त्रिपुरा	38	329 9
9 हिमाचल प्रदेश	42	328 4
10 केरल	532	314 9
11 मैसूर	719	304 7
12 उत्तर प्रदेश	4,193	297 4
13 जम्मू एवं कश्मीर	103	289 0
14 आन्ध्र प्रदेश	1,063	287 0
15 मध्य प्रदेश	924	285 4
16 तटीय	486	276 2
17 राजस्थान	539	267 4
18 बिहार	1 025	220 7

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध परिषद (NCAER) के सर्वेक्षण के अनुसार देश के प्रति व्यक्ति की आय 1960-61 में 251 5 रुपये थी। उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि केवल 4 राज्यों में, अर्थात् महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब व गुजरात में, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है, मद्रास व आसाम की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से थोड़ी ही कम है, शेष 12 राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी यह असमानता इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि इतने वर्षों के नियोजन के बावजूद भी राज्यों के मध्य आर्थिक समानता नहीं लाई जा सकी है, जो राज्य पहले से ही समृद्ध थे, वे इन वर्षों में और समृद्ध हो गए हैं। आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्यों

में आर्थिक विकास के फलस्वरूप कुछ सुधार अवश्य हुआ है, पर राज्यों की असमानता में विशेष अन्तर नहीं आ सका है। इन बातों से यह भी पता चलता है कि कृषि प्रधान व ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में, उद्योग प्रधान एवं नागरिक जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक निर्धनता है।

भारत की राष्ट्रीय आय की विशेषताएँ (Main features of National Income of India) भारत की राष्ट्रीय आय के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से भारत की राष्ट्रीय आय के निम्नलिखित प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश पड़ता है -

1 भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय, विश्व के अन्य सुसम्पन्न देशों की तुलना में बहुत कम है।

2 कृषि, भारतवर्ष में, राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसकी दशा पिछड़ी हुई है।

3 भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, औद्योगिक एवं नागरिक क्षेत्रों में, ग्रामीण व कृषि क्षेत्रों की अपेक्षा आय अधिक है।

4 राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ जनवृद्धि हो जाने से, राष्ट्रीय आय की वृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति की आय में विशेष वृद्धि नहीं हो पाती।

5 राष्ट्रीय आय में देश के कम उद्योगों का अस्तित्व, बड़े उद्योगों की अपेक्षा कम गुना अधिक है।

6 अल्प विकसित होने के नाते भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग (लगभग 53 प्रतिशत) साक्षरों पर व्यय कर दिया जाता है।

7 ग्रामीण क्षेत्रों में, नागरिक क्षेत्रों की तुलना में प्रथम दुरुती निर्धनता है।

भारत में राष्ट्रीय आय का कम होना के कारण (Causes of Low National Income of India) भारत में, अन्य सुसम्पन्न नये जन्मे वाले देशों की तुलना में, राष्ट्रीय आय बहुत कम है, जिसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे (i) भारतीय अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है, फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गति अत्यंत शिथिल है, क्योंकि कृषि प्राकृतिक तत्त्वों के अधीन है, (ii) भारत में अन्य देशों की अपेक्षा वस्त्र व विनियोजन की दरें बहुत नीची हैं, (iii) भारत औद्योगीकरण की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, (iv) महा जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ऊँची है, (v) देश के विभिन्न भागों का असंतुलित विकास हुआ है, (vi) परिवहन व पत्राचार का यथोचित विकास नहीं हुआ है, (vii) बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थाएँ अपेक्षाकृत कम हैं, (viii) सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा आर्थिक प्रगति

में प्रायः बाधा उपस्थित की गई है, (ix) दीर्घकालीन विदेशी सासन में अर्थ-व्यवस्था को व्यर्थ बना दिया था, जिसे सुधारने में समय का लगना स्वाभाविक है; (x) शिक्षा के अभाव में देशवासियों में महत्वाकांक्षा की भावना नहीं पाई जाती, यरन् वे भाग्यवादी अधिक बन गए हैं, जिससे विकास सम्बन्धी उत्साह का अभाव पाया जाता है।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के सुझाव (Suggestions for increasing National Income of India) भारत की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं

1 उत्पादन में वृद्धि भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए सभी दिशाओं में प्रयत्न किए जाने चाहिए। कृषि कुटीर एवं लघु-उद्योग, साग, व्यापार, परिवहन आदि सभी को उन्नत करके उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए।

2 बचत व विनियोग की दर में वृद्धि भारतवर्ष में बचत व विनियोग दोनों की दरें कम हैं। देश के निवासियों को कष्ट उठा कर भी बचत व विनियोग की दरो में वृद्धि करने की चेष्टा करनी चाहिए।

3 जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण परियाट-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों को लोकप्रिय बना कर जनसंख्या की वृद्धि को रोकना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई न हो।

4 जन व वितरण की असमानता में कमी करना देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिए तथा देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए उनमें उत्पादक तथा पैदा किया जा सकता है व्यक्ति बढ़ने का उपायन में उन्हें सशक्त हिस्सा मिले। इस देश में व्याप्त आर्थिक विषमता का कम करने के प्रयास करने चाहिए।

5 समुचित आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए, एक तो, देश में औद्योगीकरण की गति को तेज करके अर्थ-व्यवस्था की छप पर निर्भरता कम की जानी चाहिए तथा दूसरे, विकास की प्रक्रिया देश के सभी भागों में समान रूप से गतिशील हानी चाहिए। निछे हुए क्षेत्रों को भी विस्तार दिया जाना चाहिए।

6 सामाजिक सुविधाओं में वृद्धि देश के नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित नहीं रहने चाहिए, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके तथा वे अपने धन का उचित उपयोग करके देश में उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

राष्ट्रीय आय की आकलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ (Difficulties of National Income Estimation in India) : किसी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करना बड़ा कठिन कार्य है। भारत जैसे अल्प-विकसित देश में तो आकलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ और भी अधिक हैं। प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं :

1 असेंसेडिड एवं अमोनिज्ड क्षेत्रों की विद्यमानता भारतीय अर्थ-व्यवस्था का अधिकांश भाग असेंसेडिड एवं अमोनिज्ड (Non-monetised) है। राष्ट्रीय आय की गणना के समय साधारणतः यह मान लिया जाता है कि उदात्त वस्तुओं व सेवाओं का मुद्रा से विनिमय होता है। लेकिन भारत जैसे अ-विकसित एवं कृषि प्रधान देश में वजन का बाकी भाग किसी के लिए बाजार में नहीं आया जाता। या तो उत्पादक उसे निजी उपयोग के लिए रख लेते हैं या वस्तुओं अथवा सेवाओं से विनिमय में दूसरे उत्पादकों को दे देते हैं। उन्मूलन के उद्देश्य के, जो कि महा में विनिमय नहीं किया जाता, असेंसेडिड व अमोनिज्ड पैदा हो जाते हैं।

2 छोट्टे उत्पादकों की आय में सम्पूर्ण सौ सामग्री का उपलब्ध न होना भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अनेक छोटे-छोटे उद्योगों से इनके उत्पादन के सम्बन्ध में अनेक विभिन्न व विश्वव्यापी सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि इन उत्पादकों में अनेक गैर-विकसित व अस्थिर व अस्थिर रहने वाले होते हैं। यही कारण है कि इनकी आय-व्ययता का ही अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि इनके उत्पादन के सूचकांक में अनुमान नहीं कर सकते।

3 आर्थिक नियामकों के सामान्य वर्षांकण का न अपनाया जा सकना - भारत में वार्षिक वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत विभिन्न अवधियों के आधार पर, देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति विभिन्न समयों पर विभिन्न काम करता है। उदाहरणार्थ ग्रामीण क्षेत्र में किसान कुछ समय खेती में कुछ समय उद्योगों में तथा कुछ समय कृषि कार्य में लगाता है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की आय का अनुमान लगाना कठिन होता है तथा राष्ट्रीय आय के आकलन में बड़ी-सी दिक्कत पैदा हो सकती है।

4 विश्वव्यापी बाजारों का अभाव - राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन, उपभोग, वचन कार्यशील जनसंख्या आदि से सम्बन्धित सभी आकड़े उपलब्ध होना आवश्यक है। पर इनमें सम्बन्धित विश्वव्यापी बाजारों उपलब्ध नहीं हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों एहन करने वाले या तो बटवारी होते हैं या ग्राम-सेवक, जिनका न तो गणना करना मुख्य कार्य है और न ही वे इस कार्य के लिए अधिकारी होते हैं। कृषक इनके द्वारा प्राप्त किए गए जीविक विश्वव्यापी नहीं होते।

5. क्षेत्रीय विभिन्नताएं : भारत एक विशाल देश है, जिनके विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियाँ एक-दूसरी नहीं हैं, फलस्वरूप किसी एक क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी का प्रयोग दूसरे क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता।

6. शिक्षा एवं अन्व-विश्वास : शिक्षा एवं अन्व-विश्वास के कारण, अधिकांश लोग अपनी मातृ भाषा, व्यापार आदि से सम्बन्धित जानकारी देने में आना-जानी करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मातृ सम्बन्धी आँकड़ों का आकलन बड़ा कठिन कार्य है। प्रायः जहाँ से नमूने को अनुमान पर ही आधारित करना पड़ता है। इसलिए कई वर्ष-शास्त्रियों का विचार है कि इन आँकड़ों को बख्तर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें अटकलवाजी का बड़ा बहुत अधिक होता है। राष्ट्रीय मातृ समिति ने हनोविए अपने अनुमानों से 10 प्रतिशत अनिश्चयता का बख्तर (margin of error) माना है।

सुझाव के लिए सुझाव (Suggestion for Improvement) : भारत की राष्ट्रीय मातृ सम्बन्धी आँकड़ों की उत्पत्ति के लिए राष्ट्रीय मातृ समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सुझाव के लिए निम्नलिखित उपाय प्रयुक्त किये जाने चाहिए।

1. कृषि : कृषि क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण किये जाने चाहिए तथा हर एक गाँव में कृषि उपज सम्बन्धी आँकों का हिसाब देना जाना चाहिए। कृषि की फसलों से सम्बन्धित आँकों की जानकारी के लिए फसल कटाई प्रयोग रीति (Crop cutting experiment method) का प्रयोग किया जाना चाहिए। विगत वर्षों में फसलों की वैज्ञानिक कटाई के वैकल्पिक आकलन किये गये थे, लेकिन वे भी पूर्ण रूप से सतोषजनक नहीं हैं, क्योंकि वे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की सामग्री पर आधारित उत्पत्ति के आँकड़ों से काफी भिन्न हैं। कृषि सम्बन्धी आँकों के आकलन के सम्बन्ध में डा० बी के आर की राय द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :

(क) भूमि उपयोग के सम्बन्ध में सारी कृषि भूमि की गणना करके सत बिन्दु गणना (Bench Mark Census) करना, (ख) उपज के अनुमानों के लिए आक-
रिणक नमूना (Ratdou Sampling) फसल कटाई पद्धति, सब कृषि फसलों के बारे में अनाई जाए, (ग) फसलों के बारे में सही आँकड़ों प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन होना चाहिए, जिनके अन्तर्गत इनकी समय-समय पर नमूना-चौक (Sample Checkmate) की व्यवस्था हो सके; (घ) दूरे गाँवों की नमूना जाँच पर न-विह गणना की जानी चाहिए, जिनमें सभी परिवारों के उत्पादन, उपभोग सम्बन्धी आँकड़ें शामिल हों।

2 पशु-गणना . पशुओं की गणना का कार्य वार्षिक होना चाहिए तथा इसके लिए प्रति वर्ष केवल चने हुए 20 प्रतिशत सन्धों को ही चुना जाना चाहिए। इस गणना के आधार पर घूरे पशुओं की संख्या की गणना की जा सकती है।

3 निर्माण उद्योग (लघु एवं बड़े उद्योग) . राष्ट्रीय आय समिति ने लघु एवं बड़े उद्योगों से सम्बन्धित आकलन कार्य को अलग-अलग करने का सुझाव दिया है तथा वार्षिक आकलन का सुझाव दिया है। प्रत्येक राज्य में प्रति एक एक या दो लघु उद्योगों का वार्षिक अध्ययन किया जाना चाहिए तथा इस अध्ययन का वार्षिक वितरण व घोष विभागों को दिया जाना चाहिए।

4 खनिज उद्योग . राष्ट्रीय आय समिति ने समिष्ट उद्योग सम्बन्धी आंकड़ों को अलग-अलग द्वारा ही आकलन कर प्रकाशित करते रहने की सिफारिश की है।

5 व्यापार . व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों के आकलन में राज्य के किसी क्रय-विभाग से सहायता ली जा चाहिए, लेकिन प्राप्त आंकड़ों को प्रयुक्त करने से पहले उनमें यथोचित संशोधन कर लेना चाहिए।

6 भवन-निर्माण . चूँकि भवन निर्माण से पूर्व निर्माणकर्ताओं को नगर पालिकाओं अथवा पंचायतों से अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए ये आँकड़ उन्हीं सहायित कराये जाने चाहिए।

7 परिवहन . रेल परिवहन से सम्बन्धित आंकड़े तो उपलब्ध होते हैं, केवल मोटर परिवहन सम्बन्धी आंकड़ों के आकलन की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य को केन्द्रीय परिवहन मन्त्रालय व राज्य परिवहन नियम कुशलता से कर सकते हैं। इन मोटर परिवहन सम्बन्धी तथ्य एकत्रित कर प्रकाशित करने चाहिए।

8 आय कर . समिति का आय कर के सम्बन्ध में सुझाव है कि आय-कर विभाग को चाहिए कि वह आय कर न देने वाले व्यक्तियों की आय के भी सर्वे कराए।

9 स्वतंत्र व्यवसाय . समिति ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया है कि स्वतंत्र व्यवसायों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन, भत्ते, ध्यात, लाभान, सति-भूति आदि के आंकड़ अलग-अलग संग्रह कराए जाए।

10 सामूहिक व्यवसाय . इस समिति का सुझाव है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन सरकारी व अर्द्ध-सरकारी संस्थानों के प्रेषित विवरण अर्थात् उत्पादन व्यय से सम्बन्धित आंकड़ प्रकाशित करे।

11. राष्ट्रीय आय इकाई : वित्त मन्त्रालय में स्थापित राष्ट्रीय आय इकाई (National Income Unit) के सम्बन्ध में समिति ने सुझाव दिया है कि इसे केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन में स्थानान्तरित कर दिया जाय तथा इसके द्वारा राष्ट्रीय आय सम्बन्धी घोष कराई जाय।

राष्ट्रीय आय समिति उपर्युक्त के बर्णन सभी सुझावों का सरकार ने मान लिया है फलस्वरूप अब राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आँकड़े अधिक विश्वसनीय होने लगें हैं।

प्रश्न

1 राष्ट्रीय आय न आय बरा समान है ? भरन की राष्ट्रीय आय के कम होने के कारणों का उन्मुख कर्न हू। हवे इड ने के स्त्रि सुनाव प्रस्तुत कीजिए।

2 राष्ट्रीय आय क्या है ? भारत न इनहा माप कैस होता है ?

(आगरा बी ए 1967)

3 परम्परागत बाजनामा क जमान भारत मे राष्ट्रीय आय क विकास की विवेकन कीजिए।

(बनारस बी ए 1962)

4 What do you understand by National Income ? What is the National Income of India ? (Raj T D C Final, 1967)

5 What are the main difficulties in estimating India's national Income (Delhi, B A, 1961, 1965)

6 What do you understand by National Income ? How has it been calculated for India from time to time and how far it be taken to be an index of her economic prosperity ?

[Punjab B A, 1963]

7 Give an estimate of India's National Income indicating the proportion derived from different sectors How has the position changed during the Five Year Plans ?

(Bhagalpur U B A, Honours 1966)

भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ :

उद्देश्य एवं व्यूह-रचना

(Objectives and Strategy of India's Five Year Plans)

'If we want to accelerate the rate of economic development then the volume of state expenditure on right type of projects has to be stepped up, the flow of new investment has to be increased, social structure has to be properly adjusted and floodgates of popular enthusiasm have to be opened up'

Alak Ghosh

नियोजन के उद्देश्य तथा व्यूह-रचना

(Objectives and Strategy of Planning)

आर्थिक नियोजन या प्रमुख उद्देश्य पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की निश्चित समय में प्राप्त करना होता है, अतः अर्थ-स्थिति को इस प्रकार सर्वांगीण एवं संचालित किया जाता है कि देश में उपलब्ध समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का पूर्ण तथा कुशलतम उपयोग किया जा सके। भारत में भी, जब से आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, तब से इसी प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के योजनावद्ध आर्थिक विकास के लिए मन् 1950 ई० में योजना आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का प्रमुख कार्य देश के भौतिक, मानवीय एवं पूंजीय साधनों की जाँच करना तथा इनके सर्वाधिक प्रभावपूर्ण तथा सतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना है। भारतीय योजना आयोग ने अपनी सर्वप्रथम योजना की रूपरेखा दिसम्बर 1952 में भारतीय संसद के सम्मेलन प्रस्तुत की। तब से अब तक इसने तीन पंचवर्षीय योजनाएँ एवं तीन एक-एक वर्षीय योजनाएँ बनाई हैं, जो विधानसभा की जा चुकी हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अप्रैल, 1969 से लागू मान ली गई है।

इस अध्याय में हम भारत की विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों का विस्तृत विवेचन करेंगे तथा योजनाकाल में अपनाई गई आर्थिक विचारों की स्पष्ट रचना की समीक्षा करेंगे।

स्वतन्त्रता से पूर्व की दशान्दिशों में विदेशी अर्थ, खोसल व विक्रियता ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को निर्धनता, बकारी, तथा आर्थिक विचरता से भुक्त करके दिया था। तत्कालीन सरकार की उपाय एवं स्वार्थपूर्ण नीतियों ॥ परिणाम-स्वरूप भारत विश्व के एक पिछड़ हुए देश के रूप में अपनी अर्थ-व्यवस्था की किसी प्रकार घोषित हुए चल रहा था। देश में न तो कृषि की ही अवस्था ठीक थी और न ही उद्योग प्रयोग की। आधारभूत उद्योग पम्पों का अभाव था तथा उन विभागों में उन्नति के कोई प्रयत्न नहीं किये गये थे, जो एक देश को आर्थिक विकास का एक हड़ आधार प्रदान करती है, अथवा आजादी दिलाने के बाद योजना आयोग द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए जा कार्यक्रम बनाया गया, उसका प्रमुख ध्येय भारतीय अर्थ-व्यवस्था से विकास, अक्षयता तथा अनिश्चिन्ता की स्थिति दूर करना था तथा देश ॥ आर्थिक विकास की एमी आधारभूत रखना था जिससे देश - आर्थिक विकास स्वाभाविक एवं निरन्तर रूप में हो सके। हमारी आर्थिक योजनाओं का उद्देश्य स्पष्ट एवं देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निर्धारित किये गये हैं। अब एक देश की विभिन्न आर्थिक योजनाओं के जो उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं —

- 1 राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना।
- 2 आद्यजनो के मामलों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि उत्पादन में अधिकारिक वृद्धि करना।
- 3 देश के औद्योगीकरण के विवहण को दूर करके उद्योग क्षेत्रों का विकास एवं विकास करना।
- 4 देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
- 5 आय एवं धन सम्बन्धी व्याप्त असमानताओं को कम करना।
- 6 मूल्य वृद्धि को रोकना।
- 7 जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखना।
- 8 देश की अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनाना तथा देश का सर्वांगीण विकास करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखने पर स्पष्ट चिन्तित हो जाता है कि ये उद्देश्य परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। राष्ट्रीय आय तथा व्यक्तिगत आय में वृद्धि

उसी समय सम्भव है जबकि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों में पर्याप्त मात्रा में निवेश-योजना किया जाय। अर्थात् देश की कृषि व्यवस्था को सुधारा जाय तथा आधारभूत संरचना का विकास किया जाय, अर्थ व्यवस्था के इन दोनों महत्वपूर्ण अंगों के विकास के लिए देश में उपलब्ध जन-सम्पत्ति तथा प्राकृतिक साधनों का अधिकतम व लाभप्रद उपयोग किया जाना आवश्यक है। भारत जैसे घनी जनसंख्या वाले देश में, जहाँ अल्प-शक्ति के अधिपत्य के कारण, बेकारी व अर्द्ध-बेकारी का साम्राज्य है, रोजगार के अभावों को दूर करना एक स्वाभाविक एवं आवश्यक उद्देश्य हो जाता है। देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि देश के उन करोड़ों लोगों को योजना से होने वाले लाभों में हिस्सा मिले, जो जी-नोड मेहनत के बावजूद भी निर्धन होते हुए ही शीघ्र निम्नतम जीवन-स्तर अपनी कमाने के लिए परिस्थितियोंवश बाध्य हैं। अतः आर्थिक विषयमात्रों को कम से कम कमाने का उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश के विविध क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ यदि मध्य-स्तर की बढ़ते चले गये तो देश की वास्तविक प्रगति की दर कम हो जायेगी, अतः मूल्यों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। जनसंख्या की वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास की योजना की प्रगति पर पानी डाल सकती है। जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि ही हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है, अतः योजनाओं में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित करने का उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इस समस्या का निराकरण किये, किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रगति सम्भव नहीं है। इस प्रकार हम दखते हैं कि हमारे आर्थिक नियोजन के अन्तः परस्पर सम्बन्धित व सम्मिलित हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। इन उद्देश्यों को नियोजन में निर्धारित करके तो देश सचचीन विकास के मार्ग की प्रशस्त कर सकता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य (Objectives of the First Five Year Plan)

प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan)—प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ जुलाई 1951 में प्रकाशित किया गया था, पर इसका अन्तिम रूप अप्रैल, 1952 में ही उपलब्ध हो गया। इस योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956 तक की थी। इस योजना में वास्तविक रूप 1960 करोड़ रुपया हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि-प्रधान योजना थी।

योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन में इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा था—“राष्ट्रीय योजनाकरण का केन्द्रीय उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा करना तथा उनके अच्छे जीवन के लिए अवसर प्रदान करना है, इसलिए योजनाकरण का लक्ष्य एक तरफ तो देश के उन मानवों और भौतिक

क्रम बनाये व श्रियान्वित किये जाएं जिससे जाने वाले वर्षों में विशाल विकास-योजनाओं की नींव ढाली जा सके। भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में विकास के आधारभूत साधनों का अभाव था, यथा पिचार्ड, कृत्रिम खाद, विद्युत, लोहा-इस्पात, मशीन, परिवहन के साधन आदि की कमी थी। आधारभूत उद्योगों का अभाव था, जिनके अभाव में आर्थिक विकास की किसी भी योजना को कार्यान्वित करना कठिन था। अतः प्रथम योजना में इनके विकास पर पर्याप्त बल दिया गया था।

(iv) इस योजना का एक यह भी उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर में कृषि हो तथा आर्थिक विपन्नता को जहाँ तक सम्भव हो कम किया जाए। सविधान के निर्देशक सिद्धान्तों (Directive Principles) के अनुसार विस्तृत रूप में सामाजिक न्याय के उपायों को लागू किया जाए, लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जाए।

(v) इन योजना का एक उद्देश्य यह भी था कि ऐसी प्रशासनिक व अन्य सम्पदाएँ बनाई जायें जो भारत के भावी विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहाँ हम बान का ध्यान रक्खा गया था कि पूँजी का विनियोग इस प्रकार किया जाय कि जिनसे उपलब्ध साधनों द्वारा तत्कालीन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, वहाँ दूसरी ओर हम बान का भी ध्यान रक्खा गया था कि भविष्य में इन साधनों का समोचित विकास हो सके तथा वे अधिकाधिक गतिशील बन सकें। यह सब एक दीर्घवादी दृष्टिकोण के आधार पर किया गया था। योजना में वस्तुवादी सिद्धान्तों पर आधारित एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के निर्माण को आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया था।

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना की व्यूह रचना (Strategy of the First Five Year Plan)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मंदों पर सरकारी क्षेत्र में 2069 करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे, लेकिन कुछ मध्य वस्त्रात् देख नी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यह घनराशि घटाकर 237½ करोड़ रुपये कर दी गई, पर अस्तुतः योजनापथ में केवल 1916 करोड़ रुपया व्यय किया जा सगा। प्रथम योजनापथ में विभिन्न मंदों पर होने वाला व्यय अवलिखित तालिका में दिखाया गया है :-

मद	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
1. कृषि तथा सामुदायिक विकास	291	15
2. बढी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएँ	310	16
3. संचालन शक्ति (Power)	260	13
4. ग्रामीण तथा रघु उद्योग	43	2
5. उद्योग एवं खनिज	74	4
6. परिवहन एवं संचार	523	27
7. सामाजिक सेवाएँ एवं विविध मद	459	23
कुल व्यय	1960	100

उपसृत तालिका में विभिन्न मदों पर किए गए व्यय की वनराशि हम योजना की ध्येय रचना का स्पष्ट आभास देती है। प्रथम योजना में कृषि विकास कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस योजना में 861 करोड़ रुपये अर्थात् कुल व्यय का 44 प्रतिशत भाग कृषि विकास पर व्यय किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उद्योगों के विकास की ओर वष ध्यान दिया जा रहा। मार्केटनिक क्षेत्र का केवल 4 प्रतिशत भाग ही उद्योग व खनिज विकास कार्यक्रम पर व्यय किया गया। सवाल उठता है कि प्रथम योजना में कृषि पर अधिक और उद्योगों के विकास पर कम बल दिया गया? इस बात पर प्रकाश डालने हुये प्रथम योजना में इस प्रकार की नीति को उचित ठहराते हुए कहा गया है।

“पहले पाँच बरों के लिए हमारे विचार से कृषि, जिसमें सिंचाई तथा संचालन शक्ति भी समाविष्ट हैं, को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन्ने महत्व देने का उद्देश्य बालू योजनाओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त हमारा यह उद्देश्य है कि उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा साधन के उत्पादन में भारी दृष्टि दिये बिना औद्योगिक विकास की तीव्रगति को कायम रखना सम्भव न होगा।”

—योजना आयोग

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह नीति (Strategy) अपनाई गई थी कि देश के औद्योगिक एवं उर्वाशील विकास के लिए पहले कृषि विकास की ओर ध्यान दिया जाए। एक अर्द्धविकसित देश में, कृषि को उद्देश्य करके, उद्योगों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे औद्योगिक विकास का मार्ग अपरुद्ध होवेगा। जब तक देश में साधनों एवं कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ाया नहीं जाता, कृषि उपज

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित थे —

1. राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि करना ताकि देशवासियों का जीवनस्तर ऊंचा बढ़ सके। प्रथम योजनावधि में राष्ट्रीय आय 9110 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,800 करोड़ हो गई थी, अर्थात् योजनाकाल में 18.4 प्रतिशत की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि पर्याप्त नहीं थी, अतः जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए और अधिक आर्थिक विकास आवश्यक था। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में 25% राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, अर्थात् राष्ट्रीय आय को 10,800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,480 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया। इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति औसत उपभोग व्यय में 8% की वृद्धि का उद्देश्य था जोकि देशवासियों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक था।

2. लोहा पत्ति से औद्योगीकरण को बढ़ावा देना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दूसरा प्रमुख उद्देश्य आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष और तेज हुए, लोहा-पत्ति से उद्योग-व्यवस्था का विस्तार करना था। लोहा औद्योगीकरण के लिए मशीन बनाने वाली मशीनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता आवश्यक था। लोहा व इस्पात, कोयला, सीमेंट, भारी रसायन आदि की प्राथमिकता देना जरूरी था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, द्वितीय योजना में, औद्योगीकरण को, खास कर, आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई।

3. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। जनसाधारण को समाजवादी अर्थ-व्यवस्था अथवा नियोजित अर्थ व्यवस्था के महत्व का बोझास तभी मिल सकता है जबकि देश की बेरोजगारी व अर्द्ध बेरोजगारी समाप्त हो जाय। भारतवर्ष में प्रथम योजना के बावजूद भी यह समस्या न हल हुई सकी, अतः उल्टे प्रथम योजना में अन्त में बेरोजगारी की समस्या पहले से अधिक बढ़ गई। अतः दूसरी योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रमुख उद्देश्य सामने रखा गया। योजना आयोग ने इस दिशा में दीर्घकालीन अणवहारी नीति द्वारा 1966-67 तक देश में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने का हक निश्चय किया। इस योजना के अन्तर्गत कृषि में अतिरिक्त अन्य उद्योगों में 80 लाख अतिरिक्त रमकितियों तक के लिए रोजगार के अवसर दिलाने की व्यवस्था की गई थी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कम प्रचाल-उद्योगों (Labour Intensive Industries) पर बल देने में साथ-साथ औद्योगिक इन्फें में विविधता लाने पर जोर दिया गया। वही उद्योगों के साथ कुटीर व लघु उद्योगों पर जोर दिया गया ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

4. आर्थिक विषमताओं को दूर करना : द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य आय तथा सम्पत्ति की असमानताओं को कम करना तथा आर्थिक जीवन का अधिक समान वितरण करना था। पूर्णजादी अर्थ-व्यवस्था में सम्पत्ति एवं आय का वितरण बड़ा ही दोष पूर्ण होता है, अतः जन-व्यवस्था के उद्देश्य से आय के वितरण की इन असमानता को दूर करना आवश्यक होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन उद्देश्य पर अधिक बल नहीं दिया जा सका, लेकिन समाज के समाज-वादी ढाँचे के आदर्शों को अपनाये जाने के कारण, दूसरी योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इस उद्देश्य की सफलता के लिए एक ओर ती सामान्य जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना जरूरी होता है तथा दूसरी ओर सम्पत्ति के सकेन्द्रण (Concentration) को रोकना आवश्यक होता है। एकाधिकारी सवित के द्वारा, विभिन्न तरीकों से ज़मता का दोषण किया जाना है, अतः समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में एकाधिकार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

उपथ में, योजना आयोग के शब्दों में, - "हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्रामाण्य भारत का पुनर्निर्माण करना, भारत की औद्योगिक प्रगति की गुरुत्व नीय रचना, जनता के सवित-हीन एवं अधिकार-हीन वर्ग की समुन्नति का व्यवसर प्रदान करना तथा देश के सभी भागों का समुचित विकास करना है।"

2. (स) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विकास शैली या व्यूह-रचना (Strategy of the Second Five Year Plan)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सरो पर, सरकारी क्षेत्र में 4800 करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे, परन्तु वास्तुतः इस योजनाकाल में सरकारी क्षेत्र में केवल 4600 करोड़ रुपये का ही विनियोग किया गया। इस योजना पर विभिन्न सरो पर होने वाला व्यय विन्यासित शालिका में दिखाया गया है।

सद	वारसविक व्यय करोड रुपयों में	वारसविक व्यय का प्रतिशत
1. कृषि तथा सामुदायिक विकास	530	11
2. गृह्य तथा मध्यम सिपाई-योजनाएं	420	9
3. संचालन शक्ति	445	10
4. ग्रामीण तथा रघु उद्योग	175	4
5. उद्योग एवं धनिक	900	20
6. परिवहन एवं संचार	1300	28
7. सामाजिक सेवाएं एवं विविध सद	830	18
कुल व्यय	4600	100

उपयुक्त सांख्यिकी के देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस योजना में कृषि को उतना महत्व नहीं दिया गया, जितना की प्रथम योजना में दिया गया था। प्रथम योजना में कृषि तथा मिर्चार्थ पर कुल व्यय का 31 प्रतिशत व्यय किया गया था, लेकिन द्वितीय योजना में इन कृषि विपक्षी भागों पर कुल व्यय का 20 प्रतिशत व्यय किया गया। इस योजना में उद्योग एवं सैनिकों को उच्च प्राथमिकता दी गई और कुल पर व्यय का आवेक्षित प्रतिशत प्रथम योजना में 4 से बढ़ कर द्वितीय योजना में 20 हो गया। परिवहन एवं संचार को दोनों योजनाओं में लगभग समान महत्व मिला जबकि सामाजिक सेवाओं का प्रतिशत प्रथम योजना में 23 से बढ़कर द्वितीय योजना में 18 रह गया। द्वितीय योजना में व्यय सम्बन्धी अधिक इस योजना में अपनाई गई पैली पर प्रकाश डालते हैं, जिसका अध्ययन अब हम नीचे के अनुच्छेदों में करेंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मूल शैली औद्योगिक क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं से प्रभावित है। प्रथम योजना में कृषि विकास पर बड़ा ध्यान व्यय नहीं जापारगित रखा जा चुकी थी। अतः इस आधारभिता पर औद्योगिक विकास के लक्ष्यों को निर्दिष्ट करना द्वितीय योजना का लक्ष्य था। यह शैली आधुनिक एवं उन्नत-मगन भी है, आर्थिक विकास के सिद्धांत हमें बताते हैं कि आर्थिक प्रगति की प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक विकास की गति तथा बाजार में अतिरिक्त मांगों की पूर्ति इस में प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में, जब तक देश में सामाजिकी की उपस्थिति व पूर्ति को बढ़ावा दिया जायेगा, तब तक देश में औद्योगिक विकास की गति का भी तेज नहीं किया जा सकेगा। चूंकि भारत में प्रथम योजना अवधि में आधुनिकी पूर्ति में आवश्यक वृद्धि नहीं जा चुकी थी, अतः द्वितीय योजना में योजना व निर्माण-कार्यों में भारी व मूकभूत उद्योगों में निर्माण पर ध्यान देकर उचित सौदा को अपनाया। दूसरी योजना में लोहा व इस्पात, भीरे, भारी रासायनिक तथा अश्विन निर्माण उद्योग जैसे आधारभूत एवं भारी उद्योगों में विकास पर ध्यान दिया गया। इनके कारण से पीछे मूल उद्देश्य यह था कि देश में एक औद्योगिकरण की विशाल आधारभिता हमें कम समय में निर्मित हो जा सके। इन उद्योगों के विकास पर ध्यान देने का औचित्य इसलिए भी है कि इन उद्योगों में बड़े पैमाने से सम्पन्नित सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं तथा बड़े पैमाने के उद्योग परस्पर एक दूसरे का तोयगति से प्रगति की ओर ले जाते हैं और देश के आर्थिक विकास की गति को अत्यधिक बढ़ा सकते हैं, जो दूसरी योजना में इन उद्योगों को उच्च प्राथमिकता देना न केवल उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक एक आवश्यकता भी था।

चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अतः कल्याण सम्बन्धी लक्ष्यों में कटौती नहीं की जा सकती थी, अतः योजना के निर्माताओं ने कल्याणकारी कार्यों

पर व्यय के लिए एक बहुत बड़ी घन-राशि (कुल व्यय का 22.6 प्रतिशत) का प्रावधान दिया था । इस योजना में स्यामावन, स्वस्थ, शिक्षा, अनुपधान, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगभग 830 करोड़ रुपये खर्च किए गये जो कुल व्यय का 18 प्रतिशत था ।

द्वितीय योजना में बहुत उद्योगों के साथ-साथ ग्रामीण व लघु उद्योगों के विकास पर भी समुचित धन दिया गया था । आधारभूत उद्योगों के विकास से देश में उपभोक्ता पदार्थों की कमी आ जाने की सम्भावना थी, एक ओर श्रमिकों के वेतन बढ़ जाने से तथा दूसरी ओर उपभोक्ता पदार्थों की कमी समाज में विविध स्थिति पैदा कर सकती है तथा इससे आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं । इसी-लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण व लघु उद्योगों के विकास पर समुचित धन दिया गया था । इन उद्योगों के विकास से देश में एक ओर तो उपभोक्ता पदार्थों की कमी दूर की जा सकती थी और दूसरी ओर देश के अधिकाधिक लोगों को रोजगार की सुविधाएं दिलाई जा सकती थी । यही नहीं, इसका विकास समाजवादी धर्म-न्याय के अनुकूल भी था । इस प्रकार द्वितीय योजना में बहुत उद्योगों के साथ-साथ ग्रामीण व लघु उद्योगों के विकास की प्रेरणाहित करना इस योजना की महत्वपूर्ण शैली थी ।¹

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य नीति या शैली को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है । द्वितीय योजना में पूर्णोत्पन्न विकास पर धन दिया गया तथा अर्थ-व्यवस्था को दृढ़ आधार पर रखने का प्रयास किया गया । इस मूल नीति को पूरक शैली रूप में समाज कल्याण सम्बन्धी सेवाओं पर धन दिया गया । उसने दोनों मूल-भूत एवं पूरक शक्तियों के अवनति से लोगों के पास क्रय-शक्ति बढ़ जायेगी जिनसे वे अधिकाधिक उपभोक्ता सामान की मांग करेंगे । इस समस्या का हल करने के लिए

This means that at the one end we have deep capital-intensive investment with low employment potentiality and high overhead expenditures, at the other end we have labour intensive investments with high employment potentiality and low overhead costs. The former effectively prepares the ground for industrialisation and accelerated growth and the latter endeavours to solve simultaneously the problems of consumption and employment."

दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं रूध् उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया गया।¹ इससे उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति बढ़ने से लोगों की दहतो हुई उपभोक्ता वस्तुओं की माँग पूरी की जा सकेगी, साथ ही अधिक लोगों को कार्य दिलाया जा सकेगा।

द्वितीय योजना में आर्थिक विकास को जिन क्षेत्रों को अपनाया गया है उसमें कुछ कमियाँ अवश्य होच रह गये हैं जो इस प्रकार हैं, (1) भारी उद्योगों के परिमाणत्मक (Quantitative) लक्ष्यों पर ध्यान तो दिया गया, लेकिन गुणात्मक पहलु की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उत्पादन की तकनीक सुधारने व थम-कृशला बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। (2) कुटीर एवं रूध् उद्योगों में होने वाली धन को एकत्र करने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इसमें पूँजी का एक बहुत बड़ा भाग, जो देश के आर्थिक विकास में विनियोजित हो सकता था, विनियोजित नहीं किया जा सका। (3) इस योजना में अपनाई गई विकास शैली न लागती को कम करने एवं सम्पूर्ण कार्यक्षमता बढ़ाने की समस्या की ओर यथाचित ध्यान नहीं दिया। (4) यद्यपि नियोजित अर्थ व्यवस्था में धीरे-धीरे कृषि की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ावा चाहिए, लेकिन भारत में कृषि क्षेत्र में यथाचित विकास न होने के बावजूद भी द्वितीय योजना में इसके विकास की अपेक्षा की गई। फलस्वरूप देश में भुगतान संतुलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ, मुद्रा प्रसार सम्बन्धी दोष, बेकारी की समस्या आदि बड़ी आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा हो गई।

सार्वजनिक क्षेत्र में 7500 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान था किन्तु पाँच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुतः 8631 करोड़ रुपये व्यय किए गए, अर्थात् 1131 करोड़ रुपये निर्धारित घनराशि में अधिक खर्च किये गये।

3. तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि-अवस्था को सुदृढ़ बनाने, विद्युत एवं परिवहन का विकास करने, औद्योगिक एवं प्राथमिक परिवर्तन की गति को तेज करने, स्वयं-सहायता एवं समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में तीव्र गति से बढ़ते तथा रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से निश्चित की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वावलम्बी और स्वयं-सकृति अर्थ-व्यवस्था (Self-reliant and self-generating Economy) रखा गया। इस योजना के मुख्य-मुख्य उद्देश्य निम्नांकित थे :

1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना : योजना काल के पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। विनियोग रूप प्रकार में करने की व्यवस्था की जानी थी कि आगामी योजनाओं में भी इस विकास की दर को बनाये रखा जाय। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में 42.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तृतीय योजना में कुल 25 प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय आय 19000 करोड़ रुपये हो जाने की आशा थी। प्रति व्यक्ति आय का भी 390 रुपये से बढ़ाकर तृतीय योजना के अन्त तक 385 रु० प्रति वर्ष की जायी थी।

2. खाद्यान्न की उपज में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना : तृतीय योजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न की उपज में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि-उपज में इतनी वृद्धि करना था कि एक ओर देश के उद्योगों की कच्चे माल सम्पन्धी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें तथा दूसरी ओर इनका कुछ निर्यात भी हो सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के महत्व को कम करने के कारण योजनाकाल में खाद्यान्नों का अभाव हो गया था, इसलिए तृतीय योजना में कृषि विकास पर पुनः जोर दिया गया। योजनाकाल में कुल कृषि उत्पादन में 34%, तरु खाद्यान्नों के उत्पादन में 26 प्रतिशत वृद्धि का आशोधन था। ऐसी आशा की जानी थी कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात् देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

3. आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना : इस योजना में बुनियादी उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। इस्पात, रिबनी, तेल, ईंधन, रासायनिक उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीन निर्मित करने वाले कारखानों की स्थापना करना सार्वजनिक क्षेत्र में 10 वर्षों में देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनें देश से ही प्राप्त की जा सकें। द्रुतगति से अधिक विकास के लिए औद्योगीकरण निरन्तर आवश्यक है, इसीलिए इस योजना में आधारभूत उद्योगों के विकास पर पर्याप्त जोर

दिया गया। योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन में 69 प्रतिशत वृद्धि करने का आयोजन था।

4. **रोजगार के साधनों में वृद्धि करना :** इस योजना का चौथा प्रमुख उद्देश्य रोजगार के साधनों को बढ़ाना था ताकि देश की मानव शक्ति का अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सके। इस योजना के सम्मिलित कार्यक्रमों के फलस्वरूप योजनावधि में 140 लाख अनिश्चित लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था का आयोजन था। इनमें से 30 लाख व्यक्तियों को कृषि-क्षेत्र में तथा शेष 105 लाख व्यक्तियों को गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

5. **आर्थिक विषमता को दूर करना :** तृतीय पंचवर्षीय योजना का पाठना उद्देश्य धन एवं आय के वितरण की विषमता का सम कर् आर्थिक गतिविधों का अधिक व्यापक वितरण करना था। इन योजना में तमब के साथ साथ आर्थिक-शिक्षण, शिक्षा में जनता में समान अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।

3 (ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना को विकास शत्रो या प्लूह रचना (Strategy of the Third Five Year Plan)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न महीने पर, वार्षिक विकास क्षेत्र में 7000 करोड़ रुपये व्यय किए जाने थे, परन्तु 8631 करोड़ रुपये खर्च हुए, अर्थात् अनुमानित 3133 करोड़ रुपये निर्धारित राशि से अधिक व्यय किए गए। इस योजना पर विभिन्न महीने पर होने वाला व्यय निम्न तालिका में दिया है।

महीना	वास्तविक व्यय करोड़ रुपये में	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
1. इंधन एवं तानुदायक दिनाय	1103	12.8
2. कृषि एवं मत्स्य दिनाय योजनाएं	675	7.6
3. शिक्षा का महालय दिनाय	1262	14.6
4. सामान्य एवं अन्य दिनाय	220	2.6
5. संगठित उद्योग एवं खनिज	1735	20.1
6. परिवहन एवं संचार	2116	24.5
7. आर्थिक विकास एवं विविध	1538	17.8
कुल	8640	100.0

उपयुक्त तालिका के देखने से स्पष्ट है कि तृतीय योजना में कृषि, सिंचाई, एवं ससजन यन्त्र पर बूट ब्यय का 35.0 प्रतिशत व्यय किया गया जबकि द्वितीय योजना में इन मदों पर 30 प्रतिशत व्यय किया गया था। इस प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में पुनः कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। परिवहन एवं संचार जोषाकृत इस योजना में उपेक्षित रहा, क्योंकि इस योजना में इस पर 20 प्रतिशत घनराशि ही रखी गई, जबकि दूसरी योजना में इस मद पर 28 प्रतिशत व्यय किया गया था। अन्य मदों के व्यय स्वल्प में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। यह स्पष्ट है कि इन योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, पर ऐसा उद्योगों के स्थान पर नहीं किया गया। आधारभूत उद्योगों के विस्तार को अधिक विकास की दृष्टि से आवश्यक समझा गया, फलस्वरूप इन योजना में भी इस महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

तृतीय योजना में आर्थिक विकास की जो ज़ेरी अपनाई गई, उसमें कृषि विकास को देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक समझा गया। प्रथम दो योजनाओं, खास कर दूसरी योजना, में जो कमजोरि प्राप्ति हुआ, उसमें यह स्पष्ट हो गया कि इस समय कृषि-उत्पादन की जो मन्द गति है, वह देश की मय व्यवस्था की प्रगति की भीमति रखने वाले प्रमुख कारणों में से एक है। इसीलिए तृतीय योजना में कृषि उत्पादन को यथा सम्भव उठाने पर बल दिया गया और कृषि के विषय में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मापदंडों की व्यवस्था की गई। ग्रामीण जर्घ-व्यवस्था को विभिन्न दिशाओं में मोड़ने के प्रयत्नों पर जोर देकर कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों के अनुपाल की कम करने का प्रयास किया गया। योजना में निर्वाणकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि कृषि जर्घ-व्यवस्था का मानव माधनो के उपयोग और अग्र प्राधोण क्षेत्रों के छाधनो में अनिष्ट सम्बन्ध है, अतः यदि कृषि के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया तो इससे सम्पूर्ण प्राधोण जर्घ-व्यवस्था में सुधार होगा। कृषि क्षेत्र में विकास कार्यों के अभाव में भारत जैसे जनघनत्व वाले देश में औद्योगिकरण की गति तीव्र नहीं की जा सकती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना में ग्रामीण जर्घ व्यवस्था के पिविधीकरण के अति सहायक लघु एवं कुटीर उद्योगों में मानव शक्ति का उपयोग करके कृषि पर से मानव भार कम करने का प्रयास किया गया। बगेजगारी को दूर करने के लिए, अधिक जनसंख्या के दबाव वाले क्षेत्रों में श्रम प्रदान (labour intensive) कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। वहना न होगा कि कृषि व्यवस्था भारत में सर्वाधिक महत्व रखती है और इस पर दिया गया बल उचित ही था। इस योजना में कृषि विषयक जो कार्यक्रम अपनाए गए, उनमें से प्रमुख ये हैं - (1) सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, (2) भू-संरक्षण, सूखा खेती एवं नई भूमि का कृषि के अन्तर्गत लाने के कार्यक्रमों को गहन

किया गया (III) खाद एवं उर्वरकों के वितरण करने की समुचित व्यवस्था की गई; एवं (IV) अपेक्षाकृत उन्नत हल एवं उन्नत निरम क यन्त्रों के प्रयोग को समुचित प्रोत्साहन दिए गया।

कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भी मूलभूत उद्योगों के विकास के महत्त्व को भी पर्याप्त ध्यान दे स्वीकार किया गया। इन योजना में ऐसे उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जहाँ अर्थ व्यवस्था को स्वयं स्फूर्ति हासिल बनाने में सहायक हो सकने में, यथा इस्पात व मशीन निर्माण उद्योग, ईंधन, मत्स्यजन शक्ति, रसायन उद्योग आदि, दुर्गापुर, गिराई व राउरकेला के स्टील बनाने के कारखानों को विस्तृत करने एवं एक सार्वजनिक खनन में चौथे बारखाने को खोलने की व्यवस्था औद्योगिक आधार को मजबूत बनाने पर बल दिया गया।

योजना आयोग ने परिवहन व संचेन-वाहन के साथ के आर्थिक विकास में महत्त्व को समझते हुए इसके विकास पर भी पर्याप्त ध्यान की व्यवस्था की कृषि एवं उद्योगों का विकास तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक इस प्रकार की सेवाओं का समुचित विस्तार न किया जाय। अतएव, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की जो शैली अपनाई गई वह कृषि एवं उद्योग दोनों के समुचित विकास की ऐसी अवस्था तक ले जाने वाली थी, जहाँ अर्थ व्यवस्था स्वावलम्बी व स्वयं स्फूर्तिमय हो जाती है।

सन् 1962 तथा 1965 में क्रमशः चीन एवं पाकिस्तान के आक्रमण के कारण इस योजना की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन वितात आवश्यक हो गए थे। योजना को देश की प्रतिरक्षा के लिए प्रतिरक्षा परक (Defence Oriented) बनाना पड़ा। औद्योगिक अनुसंधान व कृषि विकास तथा युवसंगठन के साथ साथ प्रतिरक्षा में धन में अनुसंधान की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया।

4 (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य (Objectives of Fourth Five Year Plan)

इन योजना का प्रावधान श्री जी आर मेडगिल द्वारा अप्रैल 1969 में मसुदा में प्रस्तुत किया गया था परन्तु अन्तिम रूप इसे मई 1970 में दिया गया। इन प्रावधानों में योजना के उद्देश्य भी बतलाये गये थे। उद्देश्यों के बारे में लिखा था कि "योजना का दुनियावी उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले सपाटी द्वारा जनता के जीवन-स्तर को तेजी से ऊँचा उठाना है। कम-माध्यम, निराले वर्गों तथा कम अधिकार प्राप्त लोगों पर विशेष ध्यान देना है।" परन्तु योजना के दो ही वर्ष पूरे हुए हैं कि श्री मेडगिल एवं उनके मार्गदर्शक योजना आयोग की स्थापना दे दिया। इसके पश्चात् दस में योजना मन्त्री ने नये योजना आयोग का

गठन किया जिसमें श्री सी सुब्रामान्यम योजना मन्त्री नियुक्त किये गये, जो अप्रैल 1971 के तीसरे सप्ताह में इसके उपाध्यक्ष बना दिये गये। श्री सी सुब्रामान्यम एवं उनके साथियों ने प्रो गैडगिल द्वारा बताये गये उद्देश्यों पर पुन विचार किया और इस योजना के निम्नलिखित तीन उद्देश्य बताये —

(1) आत्म निर्भरता प्राप्त करना (To achieve Self Reliance)

इस योजना का प्रथम एवं प्रमुख लक्ष्य आत्म निर्भरता प्राप्त करना रखा गया। इसमें विदेशी सहायता को बांधी कर देने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पी एन 480 के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता की 1970-71 तक बिल्कुल समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस विदेशी निर्भरता को समाप्त करने के लिये नियंत्रितों में 7 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार नियंत्रितों से आय 1360 करोड़ रुपये में बढ़ा कर 1973-74 तक 1900 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया।

(2) क्षेत्रीय समानता (Regional balance)

इस योजना का दूसरा उद्देश्य योजना के विस्तार में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना रखा गया अर्थात् विज्ञान के लाभों को सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। प्रो गैडगिल इस विचार के समर्थक थे कि देश का विकास करने के लिये सभी क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक है। पिछली सभी योजनाएँ क्षेत्रीय असमानता के आधार पर बनाई गई थी जिनमें प्रथम योजना कृषि विकास के लिये, द्वितीय योजना शीशी एक विनाम के लिये इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम कृषि में 5 प्रतिशत एवं उद्योगों में 8 से 12 प्रतिशत तक वार्षिक विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी आधार पर सम्पूर्ण देश के वार्षिक विकास की दर 5.5 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

(3) स्थिरता के साथ विकास (Growth with Stability)

इस योजना का अन्तिम लक्ष्य देश का स्थिरता के साथ विकास करना रखा गया, परन्तु यह इस योजना का नया लक्ष्य नहीं था। यह लक्ष्य जो अब से योजना बनती प्रारम्भ हुई है, तभी से है। परन्तु पिछले तीन वर्षों में मूल्यों में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें यह अनुभव हुआ है कि देश के सम्पत्ति विनाम के लिये मूल्य स्थिरता उन से रचना आवश्यक है, क्योंकि यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति बिना यदि अन्य सभी लक्ष्य पूरे में कर दिये जाएं तो वे बेकार सिद्ध होंगे। इसलिए इस उद्देश्य को योजना का प्रमुख उद्देश्य कहना अनिश्चित नहीं होगी।

4 (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की विरासत शैली (Strategy of the Fourth Five Year Plan)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मार्गदर्शित क्षेत्र में 1509 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा उक्त लागू होने वाले चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर व्यय के वितरण का अनुमान लगाया जा सकता है :

मह	अनुमानित वितरण	(करोड़ रुपये में) कुल परिवर्धन का प्रतिशत वितरण
1 कृषि व सम्बन्धित क्षेत्र	2728.3	17.1
2 मिचाई व डाढ़ निरन्त्रण	1046.6	6.8
3 शक्ति	2447.5	15.4
4 ग्रामीण व लघु उद्योग	293.1	1.8
5 उद्योग व खनन	3317.7	21.0
6 वातावरण व संचार	3237.3	20.3
7 सामाजिक सेवाएँ व अन्य	2771.6	17.6

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में देश के कृषि विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उत्पादन के लिए भी 5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, तथा अनाज परत इत्यादि में विदेशों को अधिक से अधिक मुविष्टा प्राप्त कराने का भी लक्ष्य सरकार ने रखा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसन्धान कार्य को अपनाना, सामाजिक खाद आदि का प्रयोग करना तथा वितरण व्यवस्था में सुधार करना, आदि विधियाँ (strategies) निर्धारित की गईं।

औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि का अनुमान भी 8-10% लगाया गया है, तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त कारखानों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करके, नए कारखाने बना कर, खाद द्वारा पूरा करने की बात सोची गई।

इसके अलावा विद्युत विकास, परिवहन तथा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को भी विस्तृत रूप में प्रावधान देने का लक्ष्य निर्धारित किया।

5 पाँचवी योजना के उद्देश्य

योजना आयोग द्वारा पाँचवी योजना की परिचालना पर 30 और 31 मई, 1972 को प्रधानमंत्री श्रीपती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद ने विचार किया जिसमें करीब वर्षों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएँ

उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, दूसरी एवं तीसरी योजनाओं में औद्योगिक विकास पर और चौथी योजना में सामाजिक स्थिरता के विकास पर जोर दिया गया था। इन योजनाओं के दौरान यद्यपि कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन बढ़ती हुई बेरोजगारी और समाज के एक वर्ग की बढ़कर गरीबी ने देश के सामने गंभीर सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। यह निर्वनतम वर्ग देश की पूरी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें प्रत्येक पांच भारतीयों में से दो आते हैं। इस प्रकार भयंकर गरीबी का जीवन जीने वाले ये लोग भारत के समस्त नागरिकों का 2/5 में लेकर 1/2 हिस्सा तक है। इसलिए पांचवी योजना का प्रमुख लक्ष्य व्यापक स्तर पर रोजगार की सुविधाओं की व्यवस्था कर बेरोजगारी की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रसार करना और लोगों की अत्यन्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर 'गरीबी हटाओ' के वादों को पूरा करना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य "लक्ष्य में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों के विस्तार, माघ एवं सम्पत्ति की समानताओं में बमी, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण की रोकथाम और एक स्वतन्त्र तथा समानता पर आधारित समाज के मूल्यों और दृष्टिकोणों के निर्माण के लिये समाजवादी आधार पर विकास करना है।"

इस योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

(1) आत्म निर्भरता : इस योजना की अवधि में आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को और पूरा करना है। सन् 1978-79 तक शुद्ध विदेशी सहायता को शून्य कर देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना में अनाज में आत्म निर्भरता को और मजबूत बनाना, हथपात एवं अमीह धातुओं, उर्वरकों, बिना साफ किये तेल, पैट्रोलियम के सामान, इन्जीनियरी सामान और मरिमादी रसायनों का उत्पादन बढ़ाना होगा। अनाज में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के बाद गरीबी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सपन योग्य वस्तुओं के पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जायगी। मध्यम और उच्च आय के लोगों को अपनी संपत्ति के सम्बन्ध में खय रखना होगा, विशेषकर ऐसी वस्तुओं और सवाओं के बारे में जिनका आयात करना आवश्यक है। शेरू टक्कालाओं का भी देख के विकास सम्बन्धी प्रयासों और आत्मनिर्भरता के अधिदान में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें विदेशी टेक्नालाजी को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जायगा, बरिफ़ आयातित तथा विदेशी टेक्नालाजी का मिला-जुला प्रयोग इस प्रकार किया जायगा कि धीरे धीरे देशी टेक्नालाजी का हिस्सा बढ़ता जाय।

आत्म निर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में लिए निर्यातों में वृद्धि की जायगी। इस योजना में निर्यातों में 7 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात की

वृद्धि से देश में कीमतों को भी स्थिर रखा जायगा। इसमें उन वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबंध रखा जायगा जिनका देश के मुक्तान सन्तुलन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु आयातों में उन वस्तुओं को महत्व दिया जायगा जो देश के निर्यातों में वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

(2) विकास की दर एक स्वल्प पाँचवी योजना की अवधि में विकास की दर और स्वरूप का निर्धारण योजना के लक्ष्यों एवं कार्य विधि के आधार पर किया गया है। अनेक विकास दरों पर विचार करने के बाद इन निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत की औसत विकास दर हो सही होगी। यह विकास दर देश के निर्धन वर्गों की खपत के स्तर को पर्याप्त ऊँचा नहीं उठा सकती, परन्तु इससे आवासीय के 30 प्रतिशत निम्नस्तर लोगों को रहने रहने का अधिक सुतोपजनक स्तर प्राप्त करने में सहायता हो सकेगी।

अ. विकास के स्वरूप में कृषि, महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य उद्योगों और आवश्यक खपत का सामान बनाने वाले उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया है। योजना आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से निर्यात वृद्धि के लिए प्रयत्न किया जायगा। असमानता में कमी करने आयात होने वाले सामान के स्थान पर देश में बने सामान के अधिक उपयोग और निर्यात वृद्धि के प्रयासों में इन योजना के अन्तर्गत कुछ विदेशी सहायता की समर्पित की स्थिति में पटुप जायगी।

योजना के लक्ष्यों ने अनुसूच वर्गीयों की समाप्ति करने के लिये असमानता में कमी की जायगी। वन 1978-79 तक देश की 30 प्रतिशत अधूनतम खपत वाली आवासीय की खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह बढ़कर देशी इलाकों में 36 64 रु० और ग्रामीण इलाकों में 39 60 रुपये हो जायगी इन प्रकार पूरे देश के लिये 37 10 रु० औसत बँटव। 1973-74 के वनिकासी स्तर से पाँचवी योजना की अवधि में गाँवों के गरीब लोगों के लिए यह वृद्धि 60 प्रतिशत और ग्रामीण गरीब लोगों के लिए यह वृद्धि 50 प्रतिशत बँटनी है। पिछड़ हुए क्षेत्रों एवं इलाकों के विकास पर विशेष रूप से जोर देकर समाज के निम्न वर्गों की आय में निश्चय ही वृद्धि की जा सकती है।

3. निरन्तर अनुसूच पाँचवी योजना का निष्कर्ष यह है कि सबसे अधिक गरीब लोगों का स्तर ऊँचा उठाया जाय और इन प्रकार देश आर्थिक स्वाधीनता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़े। गरीबी समाप्ति करने के मार्ग में एक महत्वपूर्ण अवरोध सेजी से या ऊँची दर से आयातों में वृद्धि होता है। इन अवरोध को समाप्ति करने के लिये उचित एवं उत्पादन रोज़गार देना आवश्यक

है। रोजगार नीति इस प्रकार की होगी कि वेतन पर अधिक से अधिक काम देने की व्यवस्था के साथ ही साथ लोगों को स्वयं अपने धन से कुछ करने का भी प्रोत्साहन दिया जायगा। इस नीति से उत्पादकता वृद्धि में सहायता मिलेगी। इस योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में वेतनमोयी कर्मचारियों की समस्या में पर्याप्त वृद्धि की सम्भावना है। ये गैर-कृषि क्षेत्र निर्माण, खनन एवं उत्पादन, बिजली का उत्पादन, बिजलीघरों से सुदूर स्थानों पर उसे पहुँचाना और वितरण की व्यवस्था, परिवहन और संचार, व्यापार, मण्डारण, बैंक-व्यवस्था, बीमा कम्पनियाँ और सामाजिक सेवाएँ हैं।

पाचवी योजना की अवधि में वेतन पर काम करने वाले लोगों के लिये अधिक मर्यादा में रोजगार की जो सम्भावना है, वह काम चाहने वाले लोगों की संख्या के अनुषंग नहीं है, इसलिए लोगों को स्वयं धन जुट कराने के प्रोत्साहन देने की गुंजाइश है।

रोजगार की सम्भावनाओं के विस्तार की सामान्य नीतियों के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों को उत्पादक कार्यक्रमों में लगाने के लिये विशेष कार्यक्रम भी शुरू करने होंगे। इस उद्देश्य से कुशल व्यक्तियों एवं सामान्य व्यक्तियों के बीच अन्तर करना होगा। उष्ण रक्त दावटरी एवं चिरिस्मकी की सहायता का सम्बन्ध है इनके रोजगार की समस्या अपेक्षाकृत सरल है। वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों और तकनी-शियनों की पूर्ण रोजगार देने का सम्पादन अल्पकाल में अनुपदान और विकास की तीव्र-प्रतिविधियों और औद्योगिक विकास में निहित है इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का इस प्रकार नियमन करना होगा ताकि युवकों के लिये उपलब्ध रोजगार की सम्भावनाओं के अनुसार ही स्नातक तैयार हो सकें।

कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये खेती के काम में मशीनों का अन्वाधुनिक प्रयोग नहीं किया जायगा। केवल उन्हीं मशीनों का उपयोग किया जायगा जो जूमि की प्रति इकाई उपज बढ़ाने में सहायक हो सकें। पाचवी योजना में कृषि क्षेत्र में सफल खेती कार्यक्रम को लागू करने के लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

4 सामाजिक खपत का मासिक निर्धारित करना - गरीबी को समाप्त करने के सम्बन्ध में समाज के निर्धन वर्गों को अधिक राजस्व एवं आय देने की आवश्यकता के साथ-साथ किसी एक न्यूनतम स्तर तक सामाजिक खपत की व्यवस्था करनी होगी। यह सामाजिक खपत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषक आहार, पीने के पानी, मकान संचार, और बिजली के रूप में होगी।

जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है इस योजना में 6-11 उम्र वर्ग के सब बच्चों और 11-24 उम्र वर्ग के 60 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा देने की व्यवस्था करना सम्भव होगा। प्रत्येक गांव के एक-एक पांच कि०मीटर के भीतर एक प्राइमरी स्कूल और पांच किलोमीटर के भीतर एक मिडिल स्कूल होगा। इस योजना में लड़कियों की शिक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की जायगी। इस योजना में प्राथमिक शिक्षा को सफल बनाने के लिये प्रस्तावित धन-राशि चौथी योजना के चार गुने से भी अधिक है।

इस योजना में गांवों में पीने के पानी की पूर्ण और निरन्तर पहुँचाने के कार्यक्रमों की भी छाह दे दिया जायगा। इसके लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की तरह ही ग्रामीण पानी सप्लाई निगम की स्थापना की जायगी।

गावों के स्वास्थ्य कार्यक्रम में रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन, पीटिक आहार तथा बच्चों के रोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गावों के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप-केन्द्रों के लिये डाक्टर एवं पारिवारिक सहायक तैयार किये जायेंगे। बिनके लिये तीन वर्ष के वैकिक शिक्षाओं में भी फिर से प्रारम्भ किया जायगा और स्वास्थ्य शिक्षा को सामान्य शिक्षा प्रणाली का अंग बनाया जायगा। पीटिक आहार के अभाव को मजबूत मजदूरी के लिये गन्धर्वी मिश्रण एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा निर्धन बच्चों के स्कूल न जाने वाले बच्चों के पीटिक आहार की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा।

गावों के भूमिहीन लोगों के लिये मजदूरी बनाने के लिये जमीन प्रदान की जायगी गावों में जमीन को बेहतर और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये इस योजना के अन्तर्गत 1000 की आबादी के प्रत्येक गांव तक हर मौसम में उपसाय योजना सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में 30-40 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

5. क्षेत्रीय समन्वयन को दूर करना। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय समन्वयन को दूर करने के प्रयत्न विदे संघ, परन्तु उसका पर्याप्त प्रभाव दिखाई नहीं देता। इस योजना में पिछड़े इलाकों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है स्थानिक आबादी के 10 प्रतिशत निर्धनतम लोगों को रहने महान का स्तर ऊपर उठाया है। पिछड़े हुए इलाकों का विकास वन के लिये पूरे इलाके को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाया जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में पहला कदम यह होगा कि पिछड़े हुए इलाकों का मापन किया जाय और बाद में उपर्युक्त साधनों का मूल्यांकन किया जाय और इस समय जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं उनकी व्यापकता

एक प्रभावशालिता का पता लगाया जाय। इन कार्यक्रमों में सिंचाई, संचार, श्रृण, हाट, बिजली, शिक्षा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। इस योजना में पिछड़ हुए वर्गों के विकास की कार्य-प्रणाली के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्र की प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तुत करने की भूमिका पर अधिक जोर दिया जाएगा।

(6) वेतन, दाम और आय के मध्य उचित समुलन स्थापित करना। वेतन, दाम और आय के बीच उचित समुलन कायम करने और उक्त समुलन को बनाये रखने की आवश्यकता है। 150 विनिर्णय के कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक माग की स्थिति बच जाय। योजना में ऐसी वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था है जिनकी दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। अनिवार्य खपत की वस्तुओं की नियमित पूर्ति के लिए सार्वजनिक स्तर पर इन वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने और वितरण करने की प्रणाली चालू की जायेगी और यह व्यवस्था कम से कम निर्धन वर्गों के लिए अवश्य की जायेगी। खेती की उपज के बारे में माग और पूर्ति के बीच समुलन स्थापित रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर मानसून का बहुत अधिक असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त विना माफ की हुई कपास, परमन, तिलहन और दलहन ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें माग के अनुसार बहुत उत्पन्न-बढ़ान करना है। निरन्तर प्रगति बनाये रखने तथा उत्पादन तथा उपभोक्ता दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि माग के इस उत्पन्न-बढ़ान को बचा सभ्य नियमित किया जाय। इस योजना में दामों को कम करने के लिए लागत घटाने को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि तकनीकी, प्रबन्ध सम्बन्धी और अन्य उपायों से लागत घटाई जा सकती है।

इस योजना में हम बात पर विशेष जोर दिया जायगा कि उत्पादकता में सुधार के बिना वेतन वृद्धि से बचा जाय। क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि करते हुए यदि वेतन में वृद्धि की जाती है तो इससे प्रति इकाई उत्पादन की दृष्टि से वेतन और लागत का अनुपात बढ़ जाता है। इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायसंगत वेतन प्रणाली तैयार करनी होगी जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों पर लागू होगी। साथ ही उन लोगों को भी उचित अनुदान रखने की आवश्यकता है जिन्हें सम्पत्ति एवं उपजों से आय प्राप्त होती है।

प्रश्न

1 'भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समाजवाद जैसी अर्थ-व्यवस्था करन का होता चाहिए।' भारत की योजनाओं के क्या उद्देश्य हैं? वे कहाँ तक इस कथन से मेल खाती हैं।

(राज टी डी सी द्वितीय वर्ष कक्षा 1969)

2 आर्थिक नियोजन के विविध उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये। हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं में ये उद्देश्य कहाँ तक अपनाए गए हैं?

3 भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए?

4 भारत में आर्थिक विकास के लिए योजनाओं में अपनाई गई शैली का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए।

भारतीय योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था

(Financing of Indian Plans)

Unless the habits of consumption and saving, the institutions and legal framework for accumulation lending and investing can be adopted to the building and maintenance of capital, foreign aid can bring only transitory benefits. A permanent basis for higher living standards must be created within the society, indeed this is the very meaning of economic development. Unless the chief nature of growth is indigenous the society is constantly exposed to retrogression.

—N S Buchanan and H S Ellis.

आर्थिक नियोजन का उद्देश्य पूर्व निर्धारित मूल्यों को निश्चित काल में प्राप्त करना होता है। इसके लिए आवश्यक वित्तीय साधनों को जुटाना पड़ता है, क्योंकि बिना वित्तीय साधनों के देश के आर्थिक विकास की कल्पना करना प्रायः बिना अस्त्र शस्त्रों के युद्ध जीतने की कल्पना के समान हो होगा। बिना पर्याप्त वित्तीय साधनों के देश के आर्थिक विकास की गति को वांछित रूप में गति नहीं प्रदान की जा सकती, इसीलिए देश की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के समय यह प्रयत्न किया जाता है कि योजनावधि में आवश्यक वित्तीय साधनों को किसी न किसी प्रकार व्यवस्थापित किया जाय। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के लिए वित्तीय साधन जुटाना एक सतत प्रक्रिया है। इस अध्याय में हमें भारतवर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय साधनों का अध्ययन करेंगे।

भारतीय नियोजन के लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोत

भारतवर्ष में योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आन्तरिक व बाह्य दोनों प्रकार के वित्तीय साधनों का सहारा लिया जाता है। आन्तरिक वित्तीय साधन वे साधन हैं जो देश में ही उपलब्ध हो जाते हैं यथा बालू, खनिज से बचत, रेलों का

योगदान, सार्वजनिक ऋण, अल्प बचतें, सार्वजनिक उपक्रमों से होने वाली बचतें, भविष्य निर्धियां अतिरिक्त कर, उत्पात समीकरण-कोष, हीनार्थ प्रबंधन आदि। देश के आन्तरिक साधनों से प्राप्त होने वाले वित्तीय साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाला वित्त तथा परोक्ष रूप से प्राप्त होने वाला वित्त। प्रत्यक्ष रीति से वित्तीय साधनों के अन्तर्गत घाटे की अर्थ-व्यवस्था को छोड़ कर उपर्युक्त वर्गित सभी साधन आ जाते हैं, क्योंकि इन सभी साधनों में वित्त की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप में होती है, लेकिन आधुनिक समय में केवल प्रत्यक्ष वित्तीय साधनों पर ही देश की सरकार निर्भर नहीं रहती। देश के प्रचुर प्राकृतिक साधनों का विदीहन आवश्यक होता है, अतः यदि प्रत्यक्ष साधनों से नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है, तब सरकार अप्रत्यक्ष रीति से वित्तीय साधन जुटाती है, अर्थात् सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाती है। इस प्रकार वित्तीय साधनों की कमी को अधिक मोटों को छाप कर पूरा किया जाता है। थाजवल, भारत में ही क्या, संसार के सभी देशों में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन के रूप में अपनाया जा रहा है।

अल्प विकसित अथवा विकसशील देशों में आर्थिक विकास की प्रारम्भिक दशा में पूँजा निर्माण की गति बहुत धीमी होती है, फलस्वरूप देश के आर्थिक विकास के लिए आन्तरिक साधनों से वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। भारत भी एक विकासशील देश है। भारत में भी पूँजी निर्माण की गति बहुत मन्द रही है, अतः यहाँ भी आन्तरिक साधनों के साथ-साथ बाह्य साधनों में भी वित्त प्राप्त करने के प्रयत्न सदैव किए गए हैं। भारत में तकनीकी ज्ञान एवं उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनें तथा अन्य माज-समान विदेशों से आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की अत्यधिक आवश्यकता थी, लेकिन व्यापार सतुल्यता की प्रतिकूलता के कारण देश विदेशी मुद्रा अर्जित करने की स्थिति में नहीं था और अतः भी नहीं है। इसीलिए भारत प्रारम्भ से ही, नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता लेता रहा है और आज भी विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर रह रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत ने अपनी योजनाओं के लिए आवश्यक वित्त जुटाने के लिए आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के वित्तीय साधनों का सहारा लिया है। हम अब इनमें से प्रमुख वित्तीय साधनों का अलग अलग वर्णन करेंगे और कुल वित्तीय साधनों में इनके योगदान की समीक्षा करेंगे।

(क) आन्तरिक वित्तीय स्रोत (Internal Financial Resources)

1 करारोपण द्वारा (Taxation) आन्तरिक वित्तीय स्रोतों में करों का प्रमुख स्थान है, आर्थिक और सामाजिक नीति के व्यापक सदम में करारोपण निजी

क्षेत्र के लोगों से खपता लेने का एकमात्र उपाय ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख साधन है। हमारे देश में करारोपण के प्रमुख उद्देश्य हैं, (i) सरकारी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए साधन जुटाना, (ii) सम्पत्ति एवं आय की विपरीतों को कम करके आर्थिक न्याय में ध्येय की आगे बढ़ाना, तथा (iii) व्यक्तिगत वचन और उत्पादक पूँजी विनियोग को प्रोत्साहन देना।

भारत में आयकर, व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, धनकर, घन कर आदि करोड़ों द्वारा राष्ट्रीय आय का लगभग 14 प्रतिशत भाग कर के रूप में लिया जाता है।¹ योजना के आरम्भ से ही, सरकारी क्षेत्र के अतर्गत विकास व्यय को पूरा करने के लिए हर वर्ष कर राजस्व में वृद्धि की जाती रही है। इसीलिए कुछ आलोचकों का मत है कि करा की दर अधिक होने के परिणामस्वरूप उत्पादन और वचन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परन्तु यह आलोचना उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि नियोजन के दौरान किसी क्षेत्र में पूर्ण निर्माण अधिक तीव्र गति से हुआ है। 1951 के वर्ष में निजी क्षेत्र में पूँजी निर्माण की दर 6 प्रतिशत थी जो सन् 1956-57 में बढ़ कर 16.5 प्रतिशत हो गई। नये करो के आय के बावजूद भी पूँजी विनियोग के योग्य धन में वृद्धि कमी नहीं हुई।

यदि हम कुल राष्ट्रीय आय में करारोपण से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जायेगा कि हमारे यहाँ करारोपण कुल राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में अधिक नहीं है। गत 18 वर्षों में राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में कर से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी यह प्रतिशत 1970-71 तक 17 प्रतिशत से भी कम रहेगा। विकसित देशों में कर से प्राप्त राजस्व कुल राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में इस प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ अल्प विकसित देशों में भी करो से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में भारत के मुकाबले में कहीं अधिक है। उदाहरणार्थ, सन् 1962 में पश्चिमी जर्मनी में राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व 43.5, जापान में 35.1, ब्रिटन में 31.7, आस्ट्रेलिया में 27.4, अमेरिका में 24.9, रूस में 21.7 तथा वर्ष 1978 में 17.8 था।

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय 1960 करोड़ रुपये था, जिसमें से 752 करोड़ रुपये करो तथा रेडो के वसूली से प्राप्त

1 श्री मोरारजी देसाई आदिना विकास के लिए साधन, आर्थिक समीक्षा, 26 जनवरी, 1965।

2, प्रो० पी० सी० सिंह द्वारा भारत में नये करो की सीमा, आर्थिक समीक्षा 5 मई, 1967।

हुआ था। यह कुल व्यय का 38 प्रतिशत भाग था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, अनिश्चित करो से 1,052 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये। यह धन राशि कुल वित्तीय साधनों की उपलब्धि (4,600 करोड़ रु०) का 22.9 प्रतिशत थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नये करो से 2,680 करोड़ रु० प्राप्त किये गये। यह धन-राशि कुल वित्तीय साधनों (8,630 करोड़ रु०) का 33.6 प्रतिशत भाग थी। 1966 से 1969 तक की तीन एक-एक वर्षीय योजनाओं में अनिश्चित करो से 910 करोड़ रु० प्राप्त किये गये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में करो से 2,455 करोड़ रु०, अर्थात् कुल वित्तीय साधन (13,08 करोड़ रु०) का 17 प्रतिशत भाग, करो द्वारा प्राप्त करने का आग्रहान किया गया है। हम प्रचार हम दबते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में करो का आन्तरिक वित्तीय साधनों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है।¹

2 **अल्प संचित (Small Savings)** आर्थिक नियोजन के लिए वित्तीय साधनों में अल्प संचितों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में राष्ट्रीय आय औसतन तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ती रही है साथ ही देश की जनसंख्या भी लगभग 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है। अधिकांश व्यक्तियों की आय का स्तर अल्पतम निम्न होने के कारण संचय की साधना बहुत कम हो जाती है। लेकिन छोटी छोटी संचितों को जब मिलाया जाता है तो इससे काफी धन राशि एकत्र हो जाती है। व्यक्तिगत अल्प संचितों कई धानों पर निर्भर है यथा (i) वर्तमान आय में वृद्धि अथवा कमी की सम्भावना (ii) उणाज की वर्तमान दर और व्याज की दरों में होने वाले परिवर्तनों की सम्भावना (iii) आय का वितरण एवं विपणन का स्वरूप, (iv) मूल्य-स्तर और अद्विष्ट मूल्य स्तर रहने या घटने की सम्भावना (v) मुद्रा के मूल्य में स्थिरता (vi) ऋण और देनदारियों की स्थिति (vii) अभीष्ट वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि (viii) जीवन स्तर की प्रवृत्ति (ix) परिवार के सदस्यों की संख्या, (x) राजनैतिक स्थिरता (xi) धर्म और व्यवस्था की स्थिति तथा जाति-माल की सुरक्षा, (xii) परिवार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, एवं (xiii) संचय की सुविधाओं का होना, आदि।

अर्थ-नियोजन सम्बन्धी योजनाओं के लिए विदेशी सहायता की तुलना

- 1 भारतवर्ष में 1051-52 से 1955-56 तथा 1956-57 से 1960-61 तक, तथा 1961-62 से 1965-66 तक करो से प्राप्त कुल अल्प संचय रु० 5,593 0, 5 599 1 तथा 11195 0 करोड़ रुपये थी। इससे प्रत्यक्ष करो से आय वनश 1214 4, 1719 7 तथा 3144 9 करोड़ रु० थी जबकि परोक्ष करो से आय क्रमशः 2348 6 3849 4 तथा 8050 0 करोड़ रु० थी। योंत, रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, मार्च तथा अगस्त 1967

मे यह माधन अधिक अच्छा है। विदेशी गहायता राजनैतिक दृष्टि से अवाञ्छनीय होने के बतिरिक्त, अनिश्चित भी रहती है और इस अनिश्चितता के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया को हानि हो जाने की सम्भावना बनी रहती है। अतः एक अल्प-रिक्तित्व देश मे निर्धनता और अल्प-विकास के कुचक्र को तोड़ने के लिए, परेछू अल्प-बचतें, पूर्ण विनियोग वा अधिक उपयोगी साधन हैं।

भारतवर्ष मे डाकखाना बचत विभाग, सहकारी ऋण समितियाँ, राष्ट्रीय बचत योजना मर्टीफिकेट, राष्ट्रीय योजना मर्टीफिकेट, आदि कई माध्यमों से अल्प बचतें प्राप्त की जाती हैं। धूमि इन प्रकार की अल्प बचतों का वित्तीय साधन के रूप मे काफी महत्व है। अतः इन बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, यथा (i) पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक तथा सहकारी समितियों का विस्तार किया जाय। (ii) अल्प बचत करने वालों के लिए विनियोजन के आसान माध्यम सुकृभ किए जाय। (iii) देश मे दिखावटी तथा विकसिता सम्बन्धी उपयोग की वस्तुओं के उपयोग-वृद्धि की कम से कम 10-15 वर्षों तक के लिए सम्भावनाएँ कम कर दी जाय। (iv) कीमतों मे होने वाली वृद्धि पर रोक लगाई जाय।

भारत मे प्रथम पंचवर्षीय योजना मे अल्प बचत योजनाओं एवं चालू ऋण के रूप मे 39२ करोड रुपये प्राप्त किए गए थे, जो कुल वित्तीय साधनों का 16 प्रतिशत था। द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं मे अल्प बचतों से क्रमशः 400 करोड रु० व 585 करोड रु० की धन-राशि प्राप्ता हुई, जो कुल वित्तीय स्रोतों की क्रमशः 9 व 63 प्रतिशत थी। 19६6-69 के बीच की एक एक वर्षीय योजनाओं मे अल्प-बचत द्वारा 355 करोड रुपये प्राप्त किए गए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे अल्प बचतों से 1,000 करोड रुपये की धन-राशि, जो कुल वित्तीय स्रोत का 6.3 प्रतिशत है, प्राप्ति की आशा की गई है।

3 सार्वजनिक ऋण (Public Debts) भारत जैसे विकासशील व अर्ध-विवर्धित देश मे सरकार को सभी अवधि के सार्वजनिक ऋण लेने पड़ते हैं, ताकि योजनायुक्त विकास के कार्यक्रमों को सफरतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। गणराज्य विधायित्व देशों के सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता अल्प अवधि के लिए होती है।

विकासशील देशों मे ना, कर लगाने अथवा पुराने करों की दरों मे वृद्धि करने का सामान्यतः भारी विरोध किया जाता है। यदि यह पद्धति ज्यादा व्यापक क्षेत्र मे लागू की जाय तो भी यह की चोगी भारी मात्रा मे होती है। इस प्रकार, इन देशों के वित्त-राज्य के सीमित होने के कारण सरकार को देशवासियों से दोष-

कालीन ऋण लेने पसन्द हैं। सरकार की इस प्रकार मार्गजनिक ऋण लेने की नीति देश में पूँजी निर्माण की प्रक्रिया को बल पहुँचाने तथा सरकार के लिए आवश्यक राजस्व जुटान में सहायक होती है।

भारत में प्रथम पञ्चवर्षीय योजना की अवधि में भारत सरकार के ऋण-पत्रों के खरेदने की ओर काफी लोग आकर्षित हुए और बाजार में इनके द्वारा 205 करोड़ रुपये एकत्र कर लिए गए, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 90 करोड़ रुपये अधिक था। इस योजनावधि में अगस्त 1951 में 7-वर्षीय ऋण-पत्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर जारी किए गए। जून 1953 में भारत सरकार ने ब्याज दर बढ़ा कर 3½ प्रतिशत कर दी और 8-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बाण्ड जारी किए, जिनसे 75 करोड़ रुपये सार्वजनिक ऋण के रूप में प्राप्त हुए।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में सरकार को अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता थी, क्योंकि यह योजना पहली योजना की अपेक्षा बहुत बड़ी थी। सरकार प्रारम्भिक वर्षों में अपनी ऋण नीति को और दिखाए गए, जन उत्साह का पूरा उपयोग करना चाहती थी। अतः उसने बाजार ऋण, सार्वजनिक ऋण का लक्ष्य 700 करोड़ रुपये रक्खा था। मग 1958 के वर्ष को छोड़कर (उस वर्ष वर्षा जल्दी नहीं हुई थी)। बाजार में सरकारी ऋण पत्रों की माग अच्छी रही और दूसरी योजना की अवधि में भारत सरकार में 780 करोड़ रुपये ऋण पत्रों से प्राप्त किए। इस योजनावधि में 1 अप्रैल 1960 में पांच वर्षीय इनामी बाण्ड बालू किए गए। सन् 1963 में प्रथम इनामी बाण्ड की योजना बालू की गई।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना काल में सार्वजनिक ऋणों द्वारा 800 करोड़ रु० प्राप्त करने का लक्ष्य रक्खा गया था, लेकिन अक्टूबर 1962 में भारत पर चीनी हमले के कारण तथा सन् 1963 में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण सरकार की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएँ बढ़ती गईं। उसने नवम्बर 1962 में दस वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा बाण्ड और पन्द्रह वर्षीय रक्षण बाण्ड, क्रमशः 4½ प्रतिशत और 6½ प्रतिशत की दर पर जारी किए तथा इन्हें गारंटी कर व पुनीयत लाभ कर से मुक्त रक्खा गया।¹ 1963-64 में बाण्डों के दो बार दोहराए गए अतिरिक्त अर्थात् योजना लागू की गई। सन् 1964-65 में इनकी जगह पर 15,000 रु० से अधिक आय पाने वास्ते के लिए वार्षिक अर्थात् योजना लागू की गई। 1968-69 में इसे समाप्त कर दिया गया। तृतीय योजना काल में मार्गजनिक ऋणों से 915 करोड़ रु० प्राप्त हुए। तीन एक-एक वर्षीय योजनाओं में इस मद से 719 करोड़ रु० प्राप्त किए गए। चतुर्थ

1 केवल 10 000 से अधिक के बाण्डों पर आय-कर लगाया गया।

योजना में इस स्रोत से 1,800 करोड़ रु० प्राप्त होने की आशा की गई है जो कुल वित्तीय साधनों का 5.5 प्रतिशत है।

अल्प-निकसित देशों में सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त होने वाले वित्तीय साधनों में प्रायः कुछ रुकावटें आती हैं। इन देशों में जनता अपनी वचत, आभूषणों के रूप में या जमीन के नीचे छिपा कर रखती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में यह प्रवृत्ति बनी हुई है। रुपये जमा करने की इस आदत का नतीजा यह होता है कि सम्पूर्ण वचत का उपयोग उत्पादन में नहीं हो पाता। इनके अतिरिक्त इन देशों में नुशा प्रसार की प्रवृत्ति से जनता की वचत करने की क्षमता और दृष्टा नम हो जाती है।

4 सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त अवशेष (Surpluses from Public Undertakings) भारत में स्वायत्तता के बाद देश की लोकप्रिय सरकार ने मिश्रित अर्थ व्यवस्था की, देश के आर्थिक विकास के लिए, नीति के रूप में शोकार दिया है। सन् 1948 की औद्योगिक नीति में इस प्रकार की नीति की स्पष्ट घोषणा की गई थी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को चालू करने का क्रम प्रारम्भ किया। सन् 1956 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक व्यापक किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले लाभ भी सरकार को योजनाओं के लिये एक वित्तीय स्रोत प्रदान करते हैं। भारत में इस समय सरकारी क्षेत्र में 80 से ऊपर औद्योगिक संस्थान हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में, केन्द्रीय सरकार के अधीन कारखानों एवं व्यापारिक उद्यमों में इस समय कुल बिला कर देश की 3500 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। इनके अतिरिक्त रेल परिवहन, भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। डाक तार, संचार, सिंचाई तथा बिजली। मन्दी योजनाएँ भी सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं। रेलों को छोड़ कर, प्रथम तथा द्वितीय योजना में, सार्वजनिक उद्योगों से योजना के कार्यक्रमों के लिए, कोई वित्त पलब्ध न हो सका। तीसरी योजना में सार्वजनिक उपक्रमों में 395 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो कुल वित्तीय साधनों का 4.5 प्रतिशत था। 1966-69 के दौरान लागू हुई एच-एच पर्याय योजनाओं में सार्वजनिक उपक्रमों से 409 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। अनुषंग वित्तवर्षीय योजना में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वचत से 1,730 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो कुल वित्तीय साधनों का 12.0 प्रतिशत है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से वांछित वचतों की प्राप्ति प्रायः संदिग्ध है, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश सरकारी उद्यम घाट पर चल रहे हैं। हेवी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड तथा माइनिंग एंड एन्ड्रस मनीनरी कॉरपोरेशन आदि घाटे पर चल रहे

हैं। इंडियन ऑयल कम्पनी, हिंदुस्तान ऐरोनाटिक्स, फर्टिलाइजर ऑरपारेन्स, भारत इल्कमिनिक्स, तत् और प्राकृतिक गैस कमीशन आदि सरकारी उद्यम भी अभी तक घटा उठा रहें हैं। देश के तीनों इन्फ्रास्ट्रक्चर कारखानों का प्रारंभ से लेकर 1964-65 तक कुल मिला कर 127 करोड़ रुपये का खर्च हुआ। इन प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी उद्यमों में कई कमियाँ हैं, जिन्में इन्फ्रास्ट्रक्चर होना है और ये भारत में अच्छे वित्तीय मान, नहीं बन पा रहे हैं। इनकी निम्नलिखित समस्याएँ हैं, (i) कार्य प्रवर्धन में किलमिल होना, (ii) प्रवर्धन अकुशलता, (iii) दोषपूर्ण योजना का होना (iv) व्ययभ्रम, (v) दिलावदों खर्चों पर अधिक व्यय, (vi) बच्चे माल व धर्मिका को आवश्यकता से अधिक लगाया जाना। सरकार इन समस्याओं के प्रति जागरूक है और उसने सरकारों उद्यमों की कार्य विधि का सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं—यथा, उत्पादन में विविधता का समावेश, प्रशामनिक तथा वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, योग्य व्यक्तियों का प्रवर्धन। कल्प में नियुक्ति, और फिजूल खर्चों को रोकना एवं क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए सचाई लेखा परीक्षण की व्यवस्था आदि।

3 अन्य प्रत्यक्ष आन्तरिक वित्तीय स्रोत (Other Direct Financial Resources) आन्तरिक प्रत्यक्ष वित्तीय स्रोतों में, जिनका नियोजन के वित्तीय साधना में महत्वपूर्ण स्थान है, अनिवार्य निक्षेप योजना, निवृत्ति निधि योजना विविध पूँजीगत आय आदि हैं। ये साधन कुल वित्तीय स्रोत में अपेक्षाकृत छोटा अंश रखते हैं। 1960 भी वित्तीय साधन के रूप में इनका महत्व है और गन पंचवर्षीय योजना में इनमें आशाजनक धनराशि की उपलब्धि हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में पूँजी स्रोतों की विविध प्राप्ति में 1 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो कुल वित्तीय साधनों का 5 प्रतिशत था।

लिया जाता है। डा. बी. के. लार की राय के अनुसार, 'घाटे की वित्त व्यवस्था एक ऐसी स्थिति है, जब सरकार कूँ और दूसरी प्राप्ति से होने वाली आय से अतिरिक्त सरकारी खर्च करने की नीति अपनाती है।' पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि 'घाटे के वजह द्वारा, चाहे यह घाटा राजस्व खाते के वजह में रखा जाय या पूँजी खाते के वजह में, कुल राष्ट्रीय व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि को घाटे की वित्त व्यवस्था बढ़ा जाता है।' भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ रिजर्व बैंक द्वारा सरकार से आदेशानुसार अधिक्त धन राशि के नीट छापना है।

भारत के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था परदान सिद्ध हुई है और हमारे प्रायोजकों के लिए राजस्व और व्यय के बीच की खाई को पाटने के लिए हमने आदू का सा काम किया है। यदि घाटे की वित्त व्यवस्था का महारा नहीं लिया गया होता तो पंचवर्षीय योजनाओं में रखे गए लक्ष्यों को प्राप्ति में वर्तमान सीमा तक हम सफल नहीं हुए होते।

भारतभर में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः 420, 948 व 1150 करोड़ रुपय की वित्त व्यवस्था को अपनाकर ही की गई, जो कुल वित्तीय उपलब्धियों का क्रमशः 21.20% तथा 12.2 प्रतिशत थी। 1960-69 के दशक लगू की गई तीन एक एक वर्षीय योजनाओं में 682 करोड़ रुपय हीनार्थ प्रबन्धन से प्राप्त किए गए। चौथी योजना की प्रारम्भिक रूप से तैयार करने वालों ने कहा कि चौथी योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं की जायगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी मोड में न दिखाए गए व्यय के लिए 60 करोड़ रुपयें जमा दिसाया गया था, जिसके धन में अधिकतम मुद्रा जारी रहा। तमौन पंचवर्षीय योजना (1969-74) के हीनार्थ प्रबन्धन से 2709 करोड़ रुपे प्राप्त होने की आशा है जो कुल प्रस्तावित वित्तीय साधनों का 18.7% तराट है।

हीनार्थ प्रबन्धन के फलस्वरूप बढ़ती हुई कीमतें इ नकारक होती हैं, क्योंकि वे मुद्रा स्वीति की प्रतिया प्रारम्भ होती जाती हैं और योजना के लिए रखे गए धन खर्च होने लगते हैं। धन और वेतन में वृद्धि हो जाने से ही योजना की गत, अनुमानित समय से बढ़ जाती है। इसके लिए और अधिक मुद्रा का प्रसारना पड़ता है, फलस्वरूप स्तब्ध और भी बढ़ने लगते हैं। इन बढ़ते हुए मूल्यों के कारण श्रमिकों द्वारा हड़तालें की जाती हैं। सामान के वेतन श्रमी वर्ग पर बहुत बगर पड़ता है। भारतवर्ष में गत तीन योजनाओं में घाटे की अवस्था का अधिक महारा लिए जाने के कारण देश में मुद्रा प्रसार अत्यधिक बढ़ गया है, और नीय पथ व्यवस्था के लिए यह एक चिन्ताजनक विषय बन गया है। लेकिन आज

आज विदेशी सहायता लेना व देना ससार के किसी भी देश के लिए सामान्य बात है, क्योंकि पारस्परिक सहायता से ही देशों का आर्थिक उत्थान स्थायी रूप से हो सकता है। आज एक देश की समस्याएँ धीरे धीरे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ बन जाती हैं। यही कारण है कि अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देशों की सहायता का कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चला रहे हैं। अल्प विकसित देशों के पास सामान्यतः पूँजी की कमी रहती है, क्योंकि ऐसे देशों में वस्तु कम होती है, आय कम होती है और औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में वे आत्म निर्भर नहीं होते हैं। इन देशों में तकनीकी ज्ञान व प्रशिक्षित श्रम भी कमी रहती है, अतएव ऐसे देशों में प्रचुर प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी उनका समुचित विद्योहन नहीं हो पाता। विदेशी सहायता से पूँजी, तकनीकी ज्ञान, उन्नत मशीन प्राप्त करके ऐसे देश अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। विदेशी विनियोग से आर्थिक सहायता के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान, व आधुनिकतम मशीनों के रूप में सहायता प्राप्त होती है। साधारणतः अल्प विकसित देश नए उद्योगों की प्रारम्भ करने में व पूँजी लगाने में हिचकते हैं, परन्तु विदेशी सहायता की प्राप्ति के फलस्वरूप यह स्थिति नहीं रहती। भारतवर्ष में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता का गर्वद ही स्वागत किया गया है।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों में मिला कर १ (00 करोड़ रुपया व्यय हुआ, इसमें से 194 करोड़ विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुआ जो कुल विनियोजन का 5.8 प्रतिशत तथा सरकारी विनियोजन का 10.1 प्रतिशत था। सहायता देने वाले प्रमुख देश अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, नार्वे, न्यूज़ीलैंड इत्यादि थे। विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त राशि में इन देशों का प्रतिशत भाग क्रमशः 69.3 प्रतिशत, 10.1 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत, 0.3 प्रतिशत 0.2 प्रतिशत तथा विश्व बैंक का भाग 17.4 प्रतिशत था।

द्वितीय योजना काल में विदेशी सहायता का मात्र 1422 करोड़ रु० रहा। प्रथम योजना काल में प्राप्त रकम में से जिसका उपयोग प्रथम योजनावधि में नहीं हो सका उसका उपयोग भी द्वितीय योजना काल में हुआ। यह योजना उद्योग-प्रधान थी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए इस योजना काल में काफी बड़ी मात्रा में मशीनों का आयात करना पड़ा इसलिए विदेशी पूँजी वा अधिक विनियोजन हुआ। सहायता प्रदान करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, रुस, कनाडा, तथा जापान प्रमुख थे। इन देशों का कुल विदेशी सहायता में क्रमशः 54.1, 8.9, 8.6, 5.4, 5.3, 1.1 प्रतिशत भाग था। इस योजना में विश्व बैंक का सहयोग कुल विदेशी सहायता का 15.8 प्रतिशत था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में 10,400 करोड़ रुपये व्यय हुआ, जिसमें विदेशी सहायता का भाग लगभग 25 प्रतिशत था। इस योजना में विदेशी सहायता से 2,455 करोड़ रु० प्राप्त हुए। अनुषंग पंचवर्षीय योजना में 2,514 करोड़ रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त किए जाने का अनुमान है जिसमें से 380 करोड़ रुपये P. L. 480 के अन्तर्गत तथा बाेष 2,134 करोड़ रु० अन्य स्रोतों से प्राप्त किए जायेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी सहायता हमारे वित्तीय संकट का एक प्रमुख जग धन गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो इतना भार बढ़ा अधिक रहा है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए क्रमशः 18,81,090, और 2,455 करोड़ रु० की विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई।

तीन एक-एक धर्मीय योजनाओं ने सार्वजनिक कालून 480 के अन्तर्गत 919 करोड़ रु० तथा अन्य स्रोतों से 1517 करोड़ रु० प्राप्त किए गए।

भारत को वित्तीय सहायता कई स्तरों में प्राप्त हुई है यथा (i) विदेशी निजी व्यक्तिगत, संस्थाओं या व्यापारियों में ऋण, (ii) विदेशी सरकारों से ऋण, (iii) विदेशी सरकारों में अनुदान, (iv) निजी व्यक्तिगत, संस्थाओं द्वारा अनुदान-जैसे रॉकफेलर संस्थान, फोर्ड फाउंडेशन आदि, (v) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से, यथा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि से सहायता।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विदेशी सहायता का प्रोत्साहन देने की नीति देश के हित में नहीं है और इसके सम्भीत परिणाम हो सकते हैं। इससे कुछ हद तक देश में आर्थिक विकास की गति तेज हो सकती है, लेकिन इस योजना-बद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामाजिक उद्देश्य को अनिश्चित करने की सम्भावना है तथा इसमें भुगतान संतुलन की कठिनाईयाँ भी पैदा होने की सम्भावना है। इस प्रकार की नीति ऐसा उग्र रूप धारण कर सकती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिरता क्षति में पड़ सकती है। निजी विदेशी पूँजी के अत्यधिक प्रभाव से भारत में एकाधिकारवादी, पूँजीवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है, जिससे हमारे विकास का स्वल्प छिन्न भिन्न हो सकता है। सम्पत्ति के वितरण में विषमताएँ बढ़ सकती हैं तथा भारतीय उपभोक्ताओं के भोजन का प्रोत्साहन मिल सकता है। विदेशी सहायता में सामान्यन परमार्थ की भावना साम नहीं करती। विदेशी सहायता, ऋणदाता देश की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का एक मात्र हुआ हथियार है। उसके अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे-व्यापार क्षेत्र बनाए रखना और उसे विकसित करना, लाभ बँटाना, सामान्य विचारों आदर्शों और राजनैतिक प्रणालियों को पुष्ट करना, अपनी सत्त्वृति, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, साहित्य, शिक्षा

आदि के प्रचार द्वारा पिछले देश पैदा करना, जो उनका झट्टा लेकर चल सके, आदि प्रमुख उद्देश्य होते हैं। कौन देश सहायता देते समय किस उद्देश्य को प्रमुख मानता है, यह उसकी अपनी नीति होती है, आन्तरिक विदेशी सहायता के पीछे ये सब उद्देश्य मिले रूप से चलते हैं।¹

अब विदेशी पूँजीगतियों व सरकारों से विदेशी सहायता लेते समय, इसमें तिहित, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक उद्देश्यों की ओर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। विदेशी सहायता का सर्वश्रेष्ठ विकास, स्वदेशी साधनों का पूर्ण उपयोग व आत्म-निर्भरता है। हमें यदि अपनी योजनाओं को यफल बनाना है तो अन्ततोगत्या हमें अपने साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ना।

योजनाधार वित्तीय साधनों का विवरण (Planwise Financial Resources)

जमी तब हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उपलब्ध प्रमुख वित्तीय स्रोतों का अध्ययन किया है और उनके सापेक्षिक महत्त्व तथा उनकी वांछनीयता की समीक्षा की है। अब हम योजनाधार वित्तीय साधनों की संक्षेप में विवेचना प्रस्तुत करेंगे।

1 प्रथम योजना के वित्तीय साधन

भारतवर्ष योजना १। प्रथम पंचवर्षीय में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 1,960 करोड़ २० अरब किए गए। प्रथम योजना के विभिन्न वित्तीय स्रोत निम्नानुसार हैं—

प्रथम योजना के वित्तीय साधन

साधन	धन राशि (करोड़ ₹० में)	कुल वित्तीय साधन का प्रतिशत
1 कर तथा रेलवे से बचन	752	38
2 बाजार से उधार ली पूँजी	245	10
3 रघु बचत एवं बाल पूँजी	304	16
4 अन्य पूँजीगत साधन	91	5
5 विदेशी पूँजी एवं सहायता	148	10
6 घाट की निधि व्यवस्था	420	21
कुल	1,960	100

इन स्रोतों में यह भी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न स्तरों से प्राप्त वित्तीय साधनों का ध्यान रखा है। प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 1,960 करोड़

- 1, श्री त्रिमूर्ति चतुर्वेदी विदेशी सहायता और आर्थिक विकास, आर्थिक समीक्षा 20 सितम्बर, 1967

₹० का ही विनियोग किया जा सका। इस योजना में चालू राजस्व से बचत पर अधिक जोर दिया गया। योजना के लिए चालू राजस्व (करोड़) तथा रेलों के असादान से 752 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि अंतर बचत से 304 करोड़ ₹० अविष्य निधि में 91 करोड़ तथा जनता द्वारा ऋणों से 205 करोड़ रुपये को धन राशि प्राप्त हुई। इस योजना में सार्वजनिक ऋणों से कुल मिलाकर 600 करोड़ ₹० प्राप्त हुए। इस योजना में न तो एक करोड़ द्वारा वित्त प्राप्त करने की चेष्टा की गई और न ही घाटे की वित्त व्यवस्था की ही अत्यधिक कोशिश बनाया गया, विदेशी सहायता भी कम ही प्राप्त हुई। घाटे की वित्त व्यवस्था तथा विदेशी सहायता में केवल 420 व 188 करोड़ ₹० ही व्यय प्राप्त किए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस योजना के अधिकांश वित्तीय साधन अर्थात् 1352 करोड़ ₹० प्रत्यक्ष आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त हुए। इसका प्रभाव यह हुआ कि देश की अर्थ-व्यवस्था पर कम दबाव पड़ा तथा योजना को वांछित सफलता प्राप्त हुई।

2 द्वितीय योजना के वित्तीय साधन

प्रथम योजना की तुलना में यह योजना काफी गृहस्वाकांक्षी एवं बड़ी थी। इस योजना में प्राप्त वित्तीय स्रोत निम्न तात्त्विक थे स्पष्ट होते हैं -

द्वितीय योजना के वित्तीय साधन

(करोड़ ₹० में)

साधक	प्रस्तावित धन राशि	उपलब्ध धन राशि	कुल उपसर्ग का प्रतिशत
1 चालू राजस्व से बचत (1955-56 के वर्ष की दर पर)	350	-50	-13
2 रेलों द्वारा योगदान	150	150	32
3 जनता से ऋण	700	780	174
4 अंतर बचत	500	400	90
5 अविष्य निधि		170	34
6 इस्पात समीकरण का वि	250	38	08
7 विभिन्न प्रान्तियाँ (पूँको खाते में)		22	5
8 अतिरिक्त कर	400	1052	229
9 विदेशी ऋण एवं मदद	800	1092	231
10 घाटे की वित्त व्यवस्था	1200	948	204
कुल	4800	4,600	100

कारण विदेशी सहा का सफट भी पैदा हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय साधनों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह योजना सतोपजनक नहीं रही।

3 तृतीय पंचवर्षीय योजना के वित्तीय साधन

तृतीय पंचवर्षीय योजना में मार्गजनिब खोन में कुल 7,500 करोड १० ध्यय करने का प्रावधान था किन्तु वास्तविक ध्यय 8,630 करोड २० हुआ। इस योजना के लिए प्रस्तावित तथा उपर्युध वित्तीय साधन अधलिखित तालिका से स्पष्ट है।

तृतीय योजना के वित्तीय साधन (करोड १० में)

साधन	प्रस्तावित धन राशि	उपर्युध धन राशि	कुल प्राप्त धन का प्रतिशत राशि
1 वर्तमान कर्णों के आधार पर राजस्व से बचत	५50	470	5.4
2 रेलों द्वारा योगदान	100	80	0.9
3 मार्गजनिब उपक्रमों द्वारा बचत	450	395	4.3
4 मार्गजनिब ऋण	600	915	10.6
5 अल्प बचत	600	565	6.3
6 भविष्य निर्धि आदि में मिलने वाला धन	५40	५2०	6.1
7 अनिवार्य जमा एवं धापिकी		115	1.3
8 अतिरिक्त कर	1710	2880	33.8
9 विदेशी ऋण एवं सहसहा	2200	2155	28.5
10 घाट की विस व्यवस्था	५50	1150	13.4
मूल	7,५00	8,630	100.0

उपर्युधन तालिका के अध्ययन से पता चलता है कि इस योजना में वित्तीय साधनों की स्थिति प्रत्यधिक तटिल रही है। प्रशासनिक खर्चों में बढोत्तरी के फल स्वरुप बालू राजस्व में प्राप्ति की अगह हानि रही। घाट की विस व्यवस्था भी लक्ष्य की तुलना से दुगुनी करने पडा। इस योजना में प्रत्यक्ष बा तरिक वित्तीय स्रोतों से 5,02० करोड २० तथा निवेशी सहायता एवं घाट की विस व्यवस्था से 3,605 करोड की धन राशि उपलब्ध हुई। प्रत्यक्ष आन्तरिक वित्तीय स्रोत में अतिरिक्त करों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसी मद से सर्वाधिक धन राशि प्राप्त हुई। वित्तीय स्रोतों की प्राप्ति के इस स्वरुप का देश की अर्थ व्यवस्था पर भारी दबाव पडा।

1 इस धनराशि में P. L. 480 उपनवी के व तपट प्राप्त 880 करोड २० भी सम्मिलित हैं।

मूल्य स्तर उत्तरोत्तर बढ़ते गए और जन साधारण की वास्तविक आय कम हो गई। योजनावधि में चीन एवं पाकिस्तान से युद्ध के कारण तथा रणतार दो वर्ष सूखे की स्थिति के कारण आन्तरिक माघनों पर अधिक दबाव पड़ा। भुगतान संतुलन की निरन्तर प्रतिकूलता के कारण विदेशी मुद्रा का भयंकर संचट उत्पन्न हो गया था, फलस्वरूप भारत को विश्व बैंक द्वारा मुद्रा अवधूत्यन की सलाह दी गई थी। तृतीय योजनावधि में एक नई प्रकार की अनिवार्य वचत योजना का कार्यक्रम लागू किया गया जिसे धातु में वार्षिकी अंश के रूप में बदल दिया गया। योजना साल में इस सय से 115 करोड़ रु० की धन राशि प्राप्त हुई।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966 to 1969)

तीसरी योजना की समाप्ति के बाद भारत में योजना इतिहास में तीन वर्ष का योजना अवकाश हो गया, अर्थात् इस अवधि में वार्षिक नियोजन दण्ड-सा हो गया। लेकिन वार्षिक नियोजन के कार्य को लागू रखने के लिए वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित करके योजना कार्य को जारी रखा गया।

सन् 1966-67 की अवधि में 2137 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिसकी वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की गई है : (i) सार्वजनिक उपक्रमों से वचत 151 करोड़ रुपये (ii) अतिरिक्त करों से वचत 153 करोड़ रुपये (iii) जनता में ऋण 204 करोड़ रुपये (iv) अल्प वचत 118 करोड़ रुपये (v) विदेशी सहायता 788 करोड़ रुपये (vi) घाट की वित्त व्यवस्था 169 करोड़ रुपये तथा अन्य अन्य राशियों में। इस योजना अवधि में विदेशी सहायता का महत्वपूर्ण हाथ रहा।

सन् 1967-68 में 2205 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिसमें से (i) सार्वजनिक उपक्रमों से वचत 148 करोड़ रुपये, (ii) अतिरिक्त कराधान 299 करोड़ रुपये, (iii) जनता से ऋण 200 करोड़ रुपये, (iv) अल्प वचत 110 करोड़ रुपये, (v) घाट की वित्त व्यवस्था 14 करोड़ रुपये, (vi) विदेशी सहायता 991 करोड़ रु तथा (vii) अन्य शेष अन्य माघनों से प्राप्त किए गए।

सन् 1968-69 में 2337 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिसमें से (i) सार्वजनिक उपक्रमों से वचत के रूप में 179 करोड़ रुपये, (ii) अतिरिक्त कराधान से 499 करोड़ रुपये, (iii) सार्वजनिक ऋण से 150 करोड़ रुपये, (iv) अल्प वचत से 120 करोड़ रुपये, (v) घाटों की वित्त व्यवस्था से 307 करोड़ रुपये, तथा (vi) विदेशी सहायता से 876 करोड़ रुपये तथा शेष अन्य माघनों से प्राप्त किए गए।

4. चौथी संवर्धन योजना के द्वितीय चरण चौथी योजना का निर्माण तृतीय योजना की निराशाजनक प्रगति के वातावरण में हुआ। इस योजना में सार्व-

जनिक क्षेत्र में 15902 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में व्यव को पूरा करने के लिए निम्नलिखित साधन निर्धारित किए गए हैं।

(करीब रुपये)

1	वर्तमान करो के आधार पर राजस्व से बचत	1673
2	रेल्वे द्वारा योगदान	265
3	सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बचत	1764
4	रिजर्व बैंक के रख लिए गए लाभ	202
5	सार्वजनिक ऋण	1415
6	व्यय व्ययों	769
7	वार्षिक जमा, अनिवार्य जमा, इत्यादी बॉण्ड	-104
8	भविष्य-निधि	560
9	कुटुंब कुरु जीवन वृद्धि	1685
10	L I C तथा सरकारी धन-धन के बाजारी करने कुल	506
11	सरकारी वित्तीय सहायकों से लिए गए ऋण	405
12	अतिरिक्त कर	3198
13	विदेशी ऋण	2614
14	छाट की व्यवस्था	850

कुल 15902 करोड़

उपरोक्त मातिका में स्पष्ट है कि चौथी योजना में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक धन सरकार में कर आदि पर दिया है। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति में भी वृद्धि की गयी है। इस योजना में विदेशी ऋण के ऊपर सरकार की निर्भरता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। सन् 1971 में चौथी योजना में कुछ परिवर्तन किए गए तथा सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग बढ़ाकर 15 898 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भारत में वित्तीय समस्याओं की समस्याएँ भारतवर्ष के आर्थिक नियोजन के 18 वर्षों की गतिविधियों की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि हमारे देश के आर्थिक विकास के मार्ग में वित्तीय साधनों का अभाव एक महत्वपूर्ण बाधा रही है। जब तक देश की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्त साधन उपलब्ध न हों तब देश का आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए नए-नए उद्योगों की स्थापना, देश के प्राकृतिक

साधनों का गोपण और व्यापार में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के विनियोग करने पड़ते हैं, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय साधनों के अभाव में सभी विकासवात्मक कार्य रुक जाते हैं और देश, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाना है। भारत के नियोजन के मार्ग में भी कई समस्याएँ हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं —

1. **अव्यक्तित्व बचतों से कठिनाई** . भारत में राष्ट्रीय आय एक अव्यक्तित्व लाभ बहुत कम है, परिणामस्वरूप बचत की कौन कहे, सामान्य जीवन स्तर बनाए रखना भी, जनसाधारण के लिए नठिन हो रहा है। इच्छा रखते हुए भी लोग बचत नहीं कर पाते हैं। निधोजित आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग उपभोग में समाप्त हो जाता है। इसके अलावा देश में बढ़ते हुए मूल्य स्तरों का प्रभाव भी बचत करने की क्षमता पर विपरीत पड़ रहा है। घाटे की अवस्था के कारण लोगों को मोर्दिह आय तो बढ़ गई है पर वास्तविक आय नहीं बढ़ी। प्रो० जिनाय (Prof. Sheany) के मत में मूल्य वृद्धि के इस चक्र में वास्तव में बचतें केवल घटी ही नहीं हैं, अर्थात् पिछली बचतों का उपयोग वतनाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लिया गया है। यही कारण है कि भारत में घरेलू बचतों से अधिक वित्त प्राप्त नहीं किया जा सकता।

2. **करो में वृद्धि की सम्भावना का अभाव** . भारतवर्ष में गत तीन योजनाओं में करो द्वारा बहुत बड़ी धन राशि वित्तीय-साधन के रूप में एकत्र की गई है। कुछ वर्षावधिओं का मत है कि भारत में कर-ह्रासमान प्रतिकूल नियम की स्थिति तक पहुँच गए हैं जिनमें अब बढ़ोत्तरी करना सम्भव नहीं है, क्योंकि अब ऐसा करना हानिकारक होगा। कर-भार की अधिकता के परिणामस्वरूप बचत पर भी बुरा असर पड़ता है और इस प्रकार देश में पूँजी निर्माण के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

3. **प्रशासनिक व्यय में भारी वृद्धि** . मूल्य स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने पड़ते हैं, महंगाई भत्ते में वृद्धि करनी पड़ती है। प्रशासनिक व्यय में होने वाली वृद्धि, योजना के समस्त अनुमानों को छिन्न-भंग्न कर देती है। गत द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में चालू राजस्व से मिलने वाले वित्तीय साधन इसी कारण घाटे में परिवर्तित हो गए। अब बढ़ते हुए प्रशासनिक व्यय भी वित्तीय साधनों की प्राप्ति के मार्ग में समस्या पैदा कर रहे हैं।

4. **घाटे की रित-व्यवस्था की सीमा** देश के आर्थिक विकास के लिए भारतवर्ष में विभिन्न तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में घाटे का वित्त-व्यवस्था अपनाई गई है, इसके परिणामस्वरूप द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में मूल्य स्तरों में

क्रमशः 30 व 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इससे देश की साधारण जनता को अपनी अपनी आवश्यकताओं की सतुष्टि के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है, अतः सामान्य दचत की आघात पहुँचता है। अल्प वृद्धि में जमाखोरी, चोर-जालारी, अनुचित सट्टाबाजी जैसे असामाजिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। सम्पूर्ण भारत बढते हुए भूखों से तंग आ चुका है, अतः अब इस साधन से वित्त प्राप्त करना न तो सम्भव है और न वाछनीय ही।

5 सरकारी उद्यमों में हानि भारत में केन्द्रीय सरकार के आधीन उपक्रमों में, अब तक 3,500 करोड़ रु० का विनिमोचन किया जा चुका है लेकिन फिर भी ये धनमे पैरों पर नहीं खड़े हो सके हैं। इनमें से अधिकांश उपक्रम घाटे में चल रहे हैं जिसके लिए अनुपम प्रबंध, तीव्रताही व्यवस्था अधिक उत्पादन लागत, भ्रष्टाचार, निर्णय लेने में देरी, राजनीतिज्ञों का अनुचित हस्तक्षेप, बरखाणकारी दृष्टिकोण आदि कई कारण जिम्मेदार हैं। अतः भावी नियोजन के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए इस साधन से भी वित्त की प्राप्ति मरिध है।

॥ विदेशी सहायता की अनिश्चितता भारतवर्ष में गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में विधान कार्यक्रमों के लिए उदात्तापूर्वक विदेशी ऋण लिए ॥ जिनके लिए हमें सृष्टिक के साथ साथ व्यापक पुँकाना पड़ रहा है। यह कुछ वर्षों में भारत की जिननी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है, उसमें अधिक विदेशी मुद्रा पुँगने ऋणों की निरुत्त चुकाने के लिए आवश्यक है जो नहीं लगी, विदेशी सहायता में अब उत्तरोत्तर सहायता का अल वम होता जा रहा है और ऋण का अल बढ़ता जा रहा है। कई विदेशी ऋणों के उपपान के बारे में ऋण लेने वाले राष्ट्र स्वल्प नहीं होत। यह कहना अनुचित न होगा कि विदेशी ऋणों की अपयोजना एवं अनिश्चितता के कारण ही भारत को अपनी वस्तु पंचवर्षीय योजना का स्थान करना पड़ा। अब भी यह समस्या बनी हुई है।

7. भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता भारतवर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी गत 10-15 वर्ष से भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता से पीडित है। हमें कई कारणों से आघात अधिक करने पड़ रहे हैं। न हम केवल वृत्तीय मात्र ही विदेशों से मंगाले अपितु हमें आयातना का भी बहुत बड़ी लादाव में आयात करना पड़ता है। फलस्वरूप हमारे वित्तीय आन प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, बजाव करने के, पड़ रहे हैं। हम भुगतान संतुलन को पक्ष में लाकर आवश्यक विदेशी मुद्रा द्वारा देश के वित्तीय आन का बढान में अग्रगण्य हैं।

8. अन्य समस्याएँ : भारत में वित्तीय साधनों की समस्याओं के उपर्युक्त वर्णित कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो इस समस्या को और भी

जटिल बना रहे हैं, तथा (1) बंक व अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का अपर्याप्त होना, (11) परिवहनघटील, लम्बाई व अनिश्चित व्यावसायिक औद्योगिक व वित्तीय नीतियाँ, (111) जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि, (1IV) सतृकृत आर्थिक विकास का अभाव; (V) योग्य, अनुभववी एवं कुशल शास्त्रियों की कमी आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो वित्तीय नीतों की उपलब्धि के मार्ग में बाधक हैं ।

सुशासक भारत में वित्तीय साधनों को बढ़ाना, एवम करना, तथा उनका उचित उपयोग करना देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है, अतः वित्तीय नीतों की वृद्धि के मार्ग में जो कठिनाइयाँ या समस्याएँ हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए । इन समस्याओं को हल करने के लिए निम्नांकित सुझाव महत्वपूर्ण हैं

(1) प्रशासनिक व्यय सम्बन्धी फिजूलखर्ची को दूर करके प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि की जाय ।

(2) अल्प बचत सम्बन्धी कार्यक्रम को और अधिक व्यापक बनाया जाय । इसके लिए पोष्ट आकृतियों, सहकारी समितियों एवं बँकों की सहाय में वृद्धि की जानी चाहिए तथा इनका विस्तार उन क्षेत्रों में किया जाय, जहाँ इनकी राख्या अभी कम है । यूनिट ट्रस्ट जैसी वित्तीय संस्थाओं को विकसित किया जाय ।

(3) भारत में कुल राजस्व दर का लगभग 72 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों से तथा शेष 28 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त होता है । यह कुछ वर्गों में ग्रामीण क्षेत्रों की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है, सासकर सम्पन्न किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है, जिसे कर द्वारा वसूल करके वित्तीय साधनों में यथोचित वृद्धि की जा सकती है ।

(4) विदेशों से तथा सम्पन्न कम से कम ऋण लिए जाय और देश की योजनाओं को यथामाध्य माधनों के अनुरूप बनाया जाए ।

(5) उत्पादन तथा उपयोग पर उचित नियन्त्रण रख कर घाटे की वित्त-व्यवस्था सम्बन्धी कुप्रमायों को रोका जाए । साथ ही घाटे की वित्त व्यवस्था की उसी सीमा तक से जाया जाय जहाँ तक इसे ले जाना वांछनीय हो ।

(6) कर राजस्व से वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए अनावश्यक उपयोग पर नियन्त्रण रखा जाए, ऋण आय पर कर लगाया जाय तथा कर से वनाय की गृ जाइय ॥ रक्षणी जाय, परोक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों को बढ़ाया जाय ।

(7) गार्वन्मनिक शक्त में उद्यमों को दिसावटी व प्रतिष्ठा-मूलक खर्चों में रचना चाहिये तथा इन्हे उद्यु व्यावसायिक आधार पर चलाया जाना चाहिए । व्युत्प निर्धारित करते समय, लाभ के दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा जाय ।

(8) आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात सब्सिडी नीतियों के द्वारा देश के भूग-
ज्ञान सतुल्यता को पक्ष में लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। लोगों को स्वदेशी
वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये तथा कृषि क्षेत्र में छाछानों
की उत्पत्ति बड़ा वर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रभावशाली प्रयत्न किए जाने
चाहिए।

(9) सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण बहुत सोच-विचार कर किया जाना
चाहिए तथा किसी भी ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ नहीं करना चाहिये, जिसे बीच में
छोड़ना पड़े। यदि सरकार अपनी फिजूलखर्ची को रोकने में समर्थ हो जाय तो पर्याप्त
धन बचाया जा सकता है और निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

अन्त में, यह कहा जा सकता है कि वित्तीय संकट किसी देश की मर्द-व्यवस्था
के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भवा करते हैं। हमें इन मोती को सभी सम्भव
संशोको से बचाना चाहिए ताकि इनके अभाव में देश के आर्थिक विकास की गति
धीमी न पड़े जाए। साथ ही हमें इनका विवेकपूर्ण उपयोग भी करना चाहिये, ताकि
देश को इनके लिए शिक्षा का पात्र लेकर घबरा-उत्तर न भटकना पड़े। कोई भी देश
दूसरों की मदद पर हमेशा नहीं रह सकता। अतः हमें अपने पैरों पर खड़े होने की
चेष्टा करनी चाहिये तथा आन्तरिक साधनों को वहाँ तक सम्भव हो, बढ़ाना
चाहिए।

प्रश्न

1 शिक्षण टिप्पणी लिखिए।

भारत की पञ्चवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय साधन।

(राजस्थान वि वि द्वितीय वर्ष, दो बी बी कला, 1969)

2 भारत के विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाने के
लिए किन किन साधनों का सहारा लिया गया है? तथा ये साधन पर्याप्त मात्रा में
वित्त प्रदान करने में सफल रहे हैं?

3 भारतीय योजनाओं के निम्न आवश्यक वित्त जुटान में किन किन सम्-
स्याओं का सामना करना पड़ा है? इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने
सुझाव भी दीजिए।

4 भारतीय नियोजन के मदर्भ में निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -

(क) ऋण की वित्त व्यवस्था, (ख) विदेशी ऋण एवं सहायता,
(ग) अल्प दृष्टि योजनाएँ, (घ) सार्वजनिक ऋण

5 भारत की चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना (1969-74) के वित्तीय साधनों की
समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए।

भारत में नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक प्रगति

(Economic Progress under Planning in India)

सन 1950-51 से 1970-71 की अवधि में भारतवर्ष में आर्थिक नियोजन के बीस वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि के दौरान हम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ तथा तीन एक-एक वर्षीय योजनाएँ पूरी कर चुके हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि भी धीरे-धीरे अब समाप्त होने जा रही है। लोकतन्त्रोप राजनीतिक ढाँचे की सीमाओं, योजना के निष्पादन में भावनात्मक एवं संचालन सम्बन्धी कमजोरियों तथा समन्वित नीतियों के एक सिलसिले की कमी होते हुए भी 1950-51 से लेकर 1970-71 तक के दो दशकों में भारत का विकास कार्य अत्यन्त प्रभावशाली रहा है तथा इसकी तुलना विवक्षित देशों द्वारा अपने विकास की समान स्थिति में की गई प्रगति में की जा सकती है। सच तो यह है कि 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में जिन परिवर्तनों में योजना कार्य प्रारम्भ किया था, उसकी तुलना में भारत को अधिक बाधाओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस अध्याय में हम योजनाकाल में हुई आर्थिक प्रगति एवं असफलताओं तथा कमियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति एवं सफलताएँ

(Progress and Achievements under Economic Planning)

राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में जुड़ राष्ट्रीय आय में लगभग 69 प्रतिशत वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय 1950-51 में 9850 करोड़ रुपये से बढ़ कर सन् 1965-66 में 15441 करोड़ रुपये (1960-61 के मूल्यों पर) हो गई। सन् 1970-71 में राष्ट्रीय आय बढ़ कर 18755 करोड़ रुपये हो गई। दूसरे शब्दों में, 1950-51 की तुलना में 1970-71 में राष्ट्रीय आय लगभग दूनी हो गई। पहली योजनावधि में राष्ट्रीय आय 3.5 प्रतिशत, दूसरी में 4 प्रतिशत और तीसरी में औसतन 2.9 प्रतिशत की दर से बढ़ी। सन् 1966-67, 1967-68 व 1968-69 की एक-एक-वर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्रमशः 1.5 प्रतिशत, 9.3 प्रतिशत व 2.4 प्रतिशत रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में अर्थात् 1969-70 व 1970-71 में राष्ट्रीय आय

क्रम 53 व 55 प्रतिशत की गति से बढ़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन के काल में हमने राष्ट्रीय आय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसमें समग्र रूप से विगत बीस वर्षों में लगभग 94 प्रतिशत अवस्था प्रति वर्ष चक वृद्धि दर पर लगभग 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सन् 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो 1971 में बढ़ कर 54.7 करोड़ रुपये हो गई, अर्थात् विगत 20 वर्षों में 18.6 करोड़ व्यक्ति की वृद्धि हुई। जनसंख्या की इतनी तीव्र गति के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में लगभग सवा गूनी वृद्धि हुई है जो निश्चय ही सतोषजनक कही जा सकती है। सन् 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 270 रुपये थी, जो 1970-71 में बढ़ कर 347 रुपये (सन् 1960-61 के भावों पर) हो गई। इस प्रकार विगत 20 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 28 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 1.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

कृषि में प्रगति गत 20 वर्षों के नियोजन काल में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषिगत उत्पादन का सूचकांक जो सन् 1950-51 में 95.6 था, (सन् 1949-50 = 100), वह सन् 1970-71 में 182.2 हो गया। इस प्रकार विगत 20 वर्षों में कृषि उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन सन् 1950-51 में 55 मिलियन टन था, जो बढ़ कर 1970-71 में 107.8 मिलियन टन तक पहुँच गया और सीमावर्ष में हम खाद्यान्नों के आयात के बोझ से प्राप्त मुक्त हो गए। नियोजनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में तो कृषि उपज को बढ़ाने के लिए कृषिगत उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की गई, लेकिन बाद में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। तृतीय एवं चतुर्थ योजना के अन्तर्गत जल, रासायनिक खाद, कीटनाशक बरसाई, उर्वरक कोटि के बीच, तथा सिंचाई आदि की सुविधाओं के विस्तार से कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए गए। कृषि क्षेत्र में इस हरित क्रांति में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि को प्राप्त किया है। विगत 20 वर्षों में कुछ चुनौती हुई कृषिगत पशुओं के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उनका अनुमान निम्न तालिका में लगाया जा सकता है

कृषि उत्पादन में वृद्धि

क्रम	1950-61	1960-71	1970-71
खाद्यान्न (मिलियन टन)	55.0	82.2	107.8
निरहन (मि० टन)	5.0	6.9	9.2
गन्ना (गुड) (मि० टन)	7.0	11.4	13.2
कपास (मि० बॉल)	2.9	5.2	4.6
जूट (मि० बॉल)	3.5	4.1	4.9

औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति —

औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में विगत 20 वर्षों में जो प्रगति हुई है, वह अद्वयन महत्व की है। विद्यान इस्पात के कारखाने, केमिकल्, सूती वस्त्र, दवाईयों के उद्योग, इन्जिनियरिंग, फर्टिलाइज़र, मशीन टूल तथा हेवी इलेक्ट्रिकल्स के कारखाने स्थापना के बाद हमारी उपलब्धियों के चमकते उदाहरण हैं। आज हमारे उद्योगों में तकनीकी और विज्ञान का उपयोग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हमने अनेक वस्तुओं के उत्पादन में आत्म-निर्भरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। विगत 20 वर्षों में देश औद्योगिक उत्पादन में लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई है। आज हमारा देश विश्व के दस-बारह औद्योगिक राष्ट्रों में गिना जाने लगा है। देश में नए-नए आधुनिक उद्योग स्थापित किए गए हैं और इनके कारण उद्योगों और एजिनियों का शुद्ध उत्पादन 170 प्रतिशत बढ़ गया है। पहले हमारे देश में उत्पादित वस्तुएँ व सूनी कपड़े व कृषि पर आधारित छोटे-मोटे उद्योग ही थे। घरेलू आवश्यकता के लिए अधिकतर पूँजीगत सामान विदेशों से मंगाया जाता था, लेकिन अब यह सब सामान देश में ही तैयार हो रहा है।

नियोजन-काल में यद्यपि सरकारी व गैर सरकारी, दोनों क्षेत्रों में बहुत अधिक धन का निवेश किया गया है तो भी सरकारी क्षेत्र का क़िलाब अपेक्षाकृत और अधिक तेज़ी से हुआ है। सरकारी क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण एवं जटिल परियोजनाओं को स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान मशीन टूल, इन्डियन टेलीफ़ोन इन्डस्ट्रीज़, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोसाइकल्स हिंदुस्तान एम्प्लॉयमेंट्स लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रानिक्स, हिंदुस्तान केमिक्स, आदि प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के जागृन्मस्थान उदाहरण हैं। प्रारम्भ में तो नए उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक पूँजी आयातित संपत्तियों, कल-पुर्जों तथा निरक्षरों की आवश्यकता पड़ी जिसके कारण देश के विदेशी मुद्रा के साधनों पर असाधारण दबाव पड़ा लेकिन धीरे-धीरे देश की विदेशी पर आभिनय कम होती चली गई। अब औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के लिए उत्तरोत्तर आन्तरिक साधनों की ही अपनावे पर बल दिया जा रहा है।

घनित एवं पक्वहन की दृष्टि से घनित विगत 20 वर्षों में घनित की प्रस्थापित क्षमता में लगभग 7 गुनी वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 में बिजली की प्रस्थापित क्षमता 23 लाख किलोवाट थी जो 1970-71 में बढ़ कर 165.3 लाख किलोवाट हो गई। बिजली लगे गांवों एवं कस्बों की संख्या 3700 से बढ़ कर 1,09,438 हो गई।

नियोजन-काल में भारतीय रेलों में आत्म निर्भरता और प्रगति का एवं स्वर्णिम

सुग रखा है। आज भारत विश्व ऐसे दिग्गज देशों में पहुँच गया है, जिन्हें रेल सम्बन्धी प्रत्येक चीज की जानकारी है। भारतीय रेल अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के साथ साथ विश्वों की भी रेल सामग्री का निर्यात कर रही है। पहले हम रेल के दिग्गजों तक का विद्वानों से जायात करत थे, लेकिन अब देश में ही अधिकांश माध्यमों के निर्माण का जाला हम इनका निर्यात भी कर रहे हैं। विगत 20 वर्षों में रेलों की माल होने की क्षमता 93 मिलियन टन से बढ़ कर 199 मिलियन टन अर्थात् दूने से भी अधिक हो गई है। जहाजरानी के क्षेत्र में भी हमनो प्रगति रही है। 1250-51 में विश्व की कुल टन भार क्षमता 872.4 लाख टन (बी और टी) की जिसमें भारत का भाग केवल 3.9 लाख टन अर्थात् केवल 0.45 प्रतिशत था। 31 दिसम्बर, 1971 को यह टन भार क्षमता बढ़ कर 25 लाख टन हो गई। हम प्रकाश टन भार क्षमता में 6 महीने में भी अधिक वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 के अन्त तक केवल 6.8 प्रतिशत विश्वों व्यापार में भारतीय जहाजरानी का योगदान था, जो अब 20 प्रतिशत में अधिक हो गया है।

सामाजिक सेवाओं में प्रगति नियोजन के विगत 20 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, परिवार नियोजन, विद्युत आपूर्ति के विकास, औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था आदि की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों व विश्वविद्यालयों के प्रवेश में प्रगति 59, 96 तथा 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए प्रवेश क्षमता में 9 में 11 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। अस्पतालों में डॉक्टरों और बिस्तरों की संख्या में प्रगति 3.5 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। साक्षरता की दर 16.5 प्रतिशत से बढ़ कर 29.4 प्रतिशत हो गई है, जबकि जन्म के समय जीवनकाल की सम्भावना 32.5 वर्ष से बढ़ कर 52 वर्ष हो गई है।

जीवन-स्तर में भी सुधार आयोजना के दो दशक में जीवन-मानक स्तर में भी सुधार हुआ है। आज आम व्यक्तियों के भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक जीवन में नया परिवर्तन दिखाई देता है। विद्युत, सड़कों, सार्वजनिक, रेडियो, टेलीविजनों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के प्रादुर्भाव से सामान्य व्यक्ति पहले से कहीं अधिक खुशहाल है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दिशा में उन्नति दिखाई पड़ती है, जैसा कि आम की गई तालिका से अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रतिव्यक्ति उपलब्ध वस्तुएं

	1951	1971
खाद्यान्न (ग्राम) प्रति दिन	394 9	456 8
पाने का तेल (किलोग्राम)	2 7	3 3
चीनी (किलोग्राम)	3 0	7 3
सूती वस्त्र (मीटर)	11 0	13 6
घास (ग्राम)	257 0	383 0
कापी (ग्राम)	51 0	64 0
घर के लिए बिजली (किलोवाट)	1 6	7 0

स्रोत 1971-72 आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार

योजना के विगत 20 वर्षों में उपयुक्त वर्णित श्रेणी के अतिरिक्त कई अन्य अनेक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सन् 1950-51 में बरेलू वस्त्र राष्ट्रीय आय का 5.5 प्रतिशत था, जो 1968-69 में 8.4 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार वित्तियोग की दर सन् 1950-51 में 5.5 से बढ़ कर 1968-69 में 9.5 प्रतिशत हो गई। यद्यपि नियोजन काल में बरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सका है तो भी राजगार की मात्रा में विगत वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। नियोजन काल में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को कम करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निर्धन व पिछड़ी हुई जनता तथा पिछड़े इलाकों के लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए।

भारत में आर्थिक नियोजन की कमियाँ एवं असफलताएँ

(Shortcomings and Failure of Planning in India)

योजनाबद्ध आर्थिक विकास के विगत 20 वर्षों में भारतीय अवस्था ने कई दृष्टियों में उत्तरेलनीय प्रगति की है। लेकिन यदि हम अपनी योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियों की तुलना योजना में निर्धारित किए गए प्रश्नों व उद्देश्यों से करें तो हमें एक निराशाजनक स्थिति का आभास मिलता है। आवश्यक वस्तुओं की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कमी महंगाई गल्लों में व्यापक वृद्धि, विदेशी मुद्रा संकट, निर्धनता, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी आदि हमारी योजनाओं की असफलताओं को उजागर करती हैं। देश विदेश के अनेक विद्वानों ने समय समय पर इन असफलताओं की चर्चा की है जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1. आर्थिक विकास की दर का अक्षान्तीकरण होना भारतवर्ष में विगत नियोजन के 20 वर्षों में प्रति वर्ष औसत विकास की दर 3 से 4 प्रतिशत रही है।

जो उन्तोपजनक नहीं कही जा सकती। इसी अवधि में जापान, साइलैण्ड, राष्ट्रवादी चीन, मलेशिया व कोरिया में क्रमशः 6, 7, 8, 6, 6 प्रतिशत की गति से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया के तमाम देशों की तुलना में ही हमारी आर्थिक विकास की दर बहुत कम है विकसित देशों की तुलना में तो यह और भी अधिक निम्नस्तर पर स्थिति है।

2 मूल्य-स्तर में निरन्तर वृद्धि हमारे आयोजन की सबसे बड़ी बनी बसवा असफलता यह है कि हमसे देश के मूल्य स्तरों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सामान्यतः 3 से 5 प्रतिशत तक की वार्षिक मूल्य वृद्धि सामान्य स्वाभाविक मानी जा सकती है। जबकि विशाल पूंजीगत परियोजनाओं में जितनी अधिक मात्रा में पूंजी लगाई जाती है, उतनी मात्रा में उत्पादन इतनी जल्दी नहीं मिल पाता, इसलिए इतनी मूल्य वृद्धि से बचना सम्भव नहीं है। लेकिन भास्करवर्ष में नियोजन-काल के दौरान यह वृद्धि विनाशजनक बन गई। केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में मूल्य स्थिति लगभग स्थिर रही या उसमें थोड़ी कमी आई। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि से पूंजीगत साधन के उत्पादन पर और दब के कारण लगातार मूल्य में वृद्धि हुई है। 1952-53 को आधार वर्ष मानने पर शोक सूचकांक 1962-63 में 127.9 और 1963-65 में 210.2 था। 1939 को आधार वर्ष मानने पर यह सूचकांक क्रमशः 446 और 800 आता है। 1961-62 को आधार वर्ष मानने पर जून 1972 में शोक सूचकांक 197 में, अर्थात् तीन के वर्षों में 6 प्रतिशत के वृद्धि दर से, मूल्य में वृद्धि हुई। इस मूल्य वृद्धि का परिणाम यह हुआ कि देश में महंगाई बढ़ गई और लोगों के जीवन-निर्वाह व्यय बहुत बढ़ गए। मूल्य वृद्धि के कारण कृषि-क्षेत्रों के कर्षकों व भूमि में समय-समय पर वृद्धि की गई जिसमें किसानों में और वृद्धि हुई। इस प्रकार नियोजन के पदचरित्र अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-वृद्धि के बुझक से जल साधारण दुखी हो गया और उसका आर्थिक नियोजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विश्वास उठने लगा है।

3 बेरोजगारी में वृद्धि भारतीय आयोजन की एक बड़ी असफलता यह भी है कि यह बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेरोजगारी की समस्या सुलझने में असफल रहा है। यह समस्या इस समय देश के नियोजनकर्त्ताओं के लिए सबसे बड़ी चिन्ता बनी हुई है। यह वर्षों से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जिस मरदा में रोजगार के अवसरों का विकास हुआ, उससे भी बड़ी अधिक देश में अम शक्ति तथा फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या का प्रादुर्भाव हुआ। आज एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगार व्यक्तियों की संचार हो गई है। इन रोजगार निर्हीन लोगों में जिसमें लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। 1970 में एक कराट में भी अधिक ऐसे व्यक्ति थे जो

मेट्रिक य या स्नातक) बेरोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में अनुमान है कि ये जन-संख्या के 3 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक है। स्पष्ट है कि योजनाकाल में श्रम शक्ति की वृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसरों में बहुत कम वृद्धि हुई है। 1970-71 व 1971-72 में यह समस्या और भी गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। एक अनुमान ¹ अनुसार यदि जनसंख्या 2.5 प्रतिशत वार्षिक दर में बढ़ती रही तो चौथी योजना के अन्त में अर्थात् मार्च 1974 में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ 80 लाख तक पहुँच जायेगी।

4. धन व आय की असमानता में वृद्धि - हमारी योजनाओं की एक वृद्धि यह भी रही है कि ये देश में धन व आय की विषमताओं को दूर करने में असमर्थ रही है। डा० के० एन० राज के अनुसार, "श्रम श्रम व धन की असमानताएँ नियोजित विकास की अवधि के प्रारम्भ की तुलना में अधिक हो गई हैं। यद्यपि अर्थ-व्यवस्था आज भी स्थिर हो चली हुई है तथापि विषय के तत्त्व इसे समाजवादी प्राक्क की अपेक्षा पूँजीवादी प्राक्क के ही अधिक समीप के जाते हैं।"² वस्तुतः योजनाकाल में धनी अधिक धनी तथा विधेन और अधिक विधेन हुए हैं। नियोजन-काल में अर्पण हुई नीतियों के कारण आय का हस्तांतरण जनसाधारण व श्रम श्रेणी मध्यम वर्ग की ओर स ऊँचे व्यवसायी वर्ग की तरफ लगातार होता गया है जिससे देश में धन व आय की असमानताओं में वृद्धि हुई है। प्रा योजना के मतानुसार आर्थिक विषमता की वृद्धि के तीन कारण हैं, प्रथम, वार्षिक निष्पन्न, द्वितीय घाटे की वित्त व्यवस्था, तथा तृतीय जग्यात लाडवस व्यवस्था।

5. आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण में वृद्धि - हमारे नियोजन की एक प्रमुख असफलता यह भी है कि इसके होने हुए भी आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। देश की उत्पादक पूँजी और परिसम्पत्ति टाटा, बिरला, डालमिया, साङ्ग्रेन, आदि कुछ गोटे में पूँजीवतियों एवं औद्योगिक घरानों के हाथों में आ गई है। इन घरानों की सम्पत्ति नियोजनकाल में काफी बढ़ी है। कतलरूप हम अपने नियोजन के प्रमुख उद्देश्य समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना से विमुख हो गए हैं।

6. विदेशी सहायता पर निर्भरता में वृद्धि—यद्यपि प्रथम योजना की रूप-रेखा से ही हमने सदा आत्म-निर्भरता का लक्ष्य मेंद्वान्तिर रूप देखा निधिरित किया था तो भी व्यवहार में हम निरन्तर विदेशी सहायता पर अधिप्रापित निर्भर होते चले गए। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः 201, 1430, व

1. K. N. Raj, *Indian Plough* of 'A Critique and An alternative Approach', in *Ministry* Dec. 14, 1978, p. 14

2877 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का उपयोग किया गया। 1966-67, और 1969-70 के तीन वर्षों में 4020 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का उपयोग किया गया। 1970-71 में 769 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे विदेशी ऋणों पर निर्भरता कम करने के प्रायः सभी उपाय किया असफल रहे। विकास के लिए विदेशी सहायता के नामों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भौतिक ऋणों के साथ साथ श्रमिक, ज्ञान व कार्य-क्षमता भी आवश्यक होती है जिसका कि एक विद्युत देश में निम्नलिखित अभाव पाया जाता है। विद्युत विदेशी सहायता के द्वारा ही कभी-कभी बड़ा दुर्लभायी है। उद्योगों में वृद्ध उत्पादों में बाधा होना, आर्थिक नीति निर्धारण में विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी राजनीतिक दबाव, व्यापार, मूल धन के रूप में भारी सुव्ययन, अस्मान निर्माण की उर्ध्व की प्रतिकूलता, विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा आदि अनेक उल्लेखनीय बाधाएँ हैं, जो विदेशी सहायता से ही प्राप्त कठिनी रहती है।

7 विविध क्षेत्रों में असफलताएँ आर्थिक नियोजन के 20 वर्षों में कई अन्य क्षेत्रों में भी असफलताएँ व कमियाँ रह गई हैं, जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं। (i) नियोजन काल में हमारे सुव्ययन धन के घाट में वृद्धि हुई जिससे देश में विदेशी ऋण बढ़ा उठाना ही मिला। (ii) परिवार नियोजन के क्षेत्र में आवश्यक सफलताएँ नहीं मिल सकी फलस्वरूप देश में जनसंख्या के विस्फोट की समस्या उत्पन्न हो गई है। (iii) देश में कानूनकारी की भूमि का परिवर्तन अधिकतर दिलाने के सम्बन्ध में तथा भूमि सुधार के क्षेत्र में कानून तो अनेक बना दिए गए हैं लेकिन उनकी लागू से लापरवाह व अन्याय के कारण उनसे सम्भावित लाभ पूरी तरह से नहीं उठाए जा सके, (iv) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार तो उत्तरोत्तर होता जा रहा है, लेकिन उसके प्रबन्ध एवं कुशलता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्न सफल नहीं हो सके हैं, फलस्वरूप अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थान घाटे में चल रहे हैं, (v) मासुवायिक विकास कार्यक्रम में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जो प्रगति हुई वह प्रायः सिरासजानक रहती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आगतवर्षों में पिछले लगभग दो दशकों में अनेक क्षेत्रों में महान् सफलताएँ प्राप्त की हैं। कृषि, उद्योग परिवहन सामाजिक सेवा आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र गति में वृद्धि हुई है। इन सब उपलब्धियों को देख कर हम गौरव एवं सतोष का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे सामने वे अनेक चुनौतीपूर्ण समस्याएँ खड़ी हैं जिनका समाधान सोचने में हमारी नियोजन प्रणाली असफल रहती है। जब तक देश की इन समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल नहीं कर लिया जाता तब तक नियोजन का लाभ देख ॥ कोटि कोटि जन को नहीं प्राप्त हो सकेगा।

समाजी आयोजन के सम्बन्ध में सुझाव

(1) समाजवादी समाज की स्थापना हेतु सच्चे दिल से प्रयत्न किया जाय, क्योंकि समाजवाद के नाम की बार-बार रट लगाने मात्र से इनकी स्थापना होना सम्भव नहीं है। प्रयासन में सुरुजता के अभाव से भूमि सुधार कानून, सहकारी कृषि आदि क्षेत्रों में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। श्री टी. टी. कृष्णा-माचारि के अनुसार इसकी स्थापना १९१९ अथवा सम्बन्धी नीतियों एवं दिन-प्रति-दिन की नीतियों में परिवर्तन तथा देश में हो रहे परिवर्तनों को समाजवादी दृष्टि से समझना आवश्यक है। वह कार्य किसी एकाधिकारी को समाप्त करके भी करना सम्भव नहीं है। इसकी स्थापना हेतु उपयोग पर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि इसे छिपाया नहीं जा सकता। अतः अर्थ कर को पुनः लागू करना चाहिये। सरकार द्वारा अन्न का व्यापार, आयात-निर्गत कार्य, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि कदम उठाये जाय ताकि इससे लाभ को पुनर्वितरित किया जा सके एवं यह लाभ कति-पय अर्थितमियों की ही न मिल सके। कांग्रेस सम्मेलन की निर्देशिकाओं के अनुसार हमारा लोकतन्त्रीय समाजवाद भारतीय परम्पराओं, विचारों, भावनाओं तथा परिस्थितियों के अनुसार हो तथा इसमें सभी लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं को उचित-व्यवहार कराना आवश्यक है।

(2) कृषि विकास सम्बन्धी सुझाव : कृषि क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया जाय। दश हेतु उत्तम बीजों, उर्वरकों, सिंचाई, सस्थागत परिवर्तनों आधुनिक-सकनीक आदि की व्यवस्था की जाय। कुछ अर्थशास्त्रियों की राय में पम्पिंग सेटो, उर्वरकों तथा कृषि सम्पत्ति पर कर लगाना इनके विकास के लिये हानिकारक है। कृषि व्यवस्था में उचित संगठन किया जाय।¹ सिंचाई की व्यवस्था के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय, क्योंकि इससे अधिक भूमि खेत का उपयोग सम्भव हो सकेगा तथा क्षीण फलोत्पादन होने से मुद्रा प्रसार की सम्भावना नहीं रहेगी। भूमि विज्ञान के प्रख्यात विद्वान प्रो० जे० पी० बोप से अनुसार इससे भूकम्प का खतरा भी दूर होगा। 'सीस बनाने तथा भूकम्प को नियंत्रण दो,' जीपें लेख में उन्होंने बताया कि बड़े बड़े बांध एवं छोटे नहरों के पार के पट्टे भागों में भूकम्प आये हैं, क्योंकि 100 फुट से अधिक गहरा पानी होने पर भूमि की सतह उन भार को सहन नहीं कर सकती है तथा फटने को विवश हो जाती है।

1. It is not finance but proper organisation which is the main obstacle in the path of agricultural progress in India."

उनकी राय में महाराष्ट्र में कीटना के भूकम्प का कारण प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित भारी जालें हैं। कृषि विकास से उद्योगों की वच्चा माल मिलेगा, सामान्य सुलभ होना तथा रोजगार में वृद्धि होगी।

(3) रोजगार सम्बन्धी प्रयत्न बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना आवश्यक है। इस हेतु यम सविन्य आयोजन की ओर ध्यान देना चाहिये। लक्ष्यका वृद्धि की दर कम करने हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार करना आवश्यक है। विराम की दर तीव्र करनी आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

(4) आत्म स्वावलम्बन का दृढ़ संकल्प योजना में स्वावलम्बन का दृढ़ संकल्प रखकर इस ओर भरपूर प्रयत्न करना आवश्यक है क्योंकि कहा गया है 'कष्टमेव ही सिद्धयस्ति कार्याणि न च सम्भरथ।' इस हेतु कृषि, उद्योगों, वातावरण, तटनीकी ज्ञान आदि का विकास करना आवश्यक है, ताकि प्राकृतिक प्रभावों का अधिकतम उपयोग हो सके। अकार्यकुशलता को दूर करना, शीघ्र फलदायक इकाइयों को प्रारम्भ करना, जायिक भाषनों पर मर्यादा नियन्त्रण रखना, विदेशी गठबन्धन समाप्त करना, अनावश्यक नियन्त्रणों व नियमों को कम करना, निजी व सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, राज्यों का आर्थिक आचार पर पुनर्गठन करना, प्रशासन में अप्रवृत्त को कम करना, कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करना, आयोजन को लचीला बनाना आदि बातें हमें स्मरण करनी हैं।

(5) विदेशी साधनों सम्बन्धी सुझाव इन सम्बन्ध में विदेशी सहायता पर निर्भरता कम कर आन्तरिक साधनों में आश्रय देना आवश्यक है। सावधानी से कार्य करने पर सुरक्षा पर व्यय कम करके, घरेलू वस्तु उत्पादक, सरकारी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के ठीक मंचालन द्वारा खर्च पर रोक लगाकर तथा प्रशासन में अप्रवृत्त को रोक कर घरेलू साधनों से आश्रय बढ़ाया जा सकती है। बायात प्रतिस्थापन अथवा निर्यात आदि द्वारा बाजारों को कम करके तथा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों द्वारा निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। सरकार को विदेशी गठबन्धन कम करने चाहिये। तीन योजनाओं में लगभग 3000 विदेशी गठबन्धनों के कारण लाभार्थी रूप में भारी घन राशि विदेशों को जा रही है। सन् 1956-57 से सन् 1967-68 के मध्य लगभग 388.2 करोड़ रुपया लाभार्थी के रूप में बाहर भेजा गया। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्रम एवं मावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाय।

(6) आर्थिक असमानताएँ दूर करना . इस हेतु क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने काय एवं सम्पत्ति की असमानता नो दूर करके एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण स्थापित करने की आवश्यकता है। आर्थिक विवास में अधिकसित क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण ही मुख्यतः उलगाणा की समस्या उत्पन्न हुई है। श्री निर्जलिगम्भा के अनुसार आर्थिक हितों के आधार पर राज्यों का पुनर्समूहन किया जाना चाहिये अथवा क्षेत्रीय असंतुलन से उत्पन्न असन्तोष भयंकर विस्फोट के रूप में प्रकट होकर विनाश का कारण बनेगा। उद्योगों का विकेन्द्रीकरण तथा बड़े व छोटे उद्योगों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।

(7) आयोजना की विधि . आयोजना सचीला हो, सुदृढ़ नीतियों की अपनाना लाभ तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय हो।

(8) सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था . शिक्षा, चिकित्सा, आदि सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को लाभ ताकि जनसाधारण का जीवन सुखी हो। नि शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने, सक्तामक रोगों को समाप्त करने आदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ करना शेष है। शिक्षा का माध्यम हिन्दी तथा मातृ भाषा में हो, ताकि भारतीय विद्वान विदेशी लेसकों द्वारा प्रस्तुत विचारों का अध्यानुकरण न कर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार स्वतन्त्र चिन्तन कर आर्थिक विनाश के उपाय सुझा सकें।

9) आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता . प्रो० जे० ए० गजरेखा के अनुसार योजना आयोग को मुख्यतः आर्थिक नीतियों की निर्धारित कर इन नीतियों के अन्तर्गत लोगों को उनकी दैनिक आर्थिक प्रवृत्तियों को स्वतन्त्र रूप से चलने देना चाहिये। राज्य का ध्यान केवल महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर हो केन्द्रित हो, अन्यथा प्रत्येक छोटी-छोटी बात को महत्वपूर्ण मानने पर सम्भव है कि बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान न दिया जा सके। योजना आयोग को चाहिये कि उन सभी कारणों को समाप्त कर दे जिनसे आर्थिक प्रणाली के तगठन में अकार्य समता का जानी है।

निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि असफलताओं से न घबरा कर इसके कारणों के प्रति भविष्य में सजग रहना आवश्यक है। देश में आयोजित आर्थिक विकास के मार्ग को बहुत मोच विचार कर चुका है तथा भविष्य के प्रति निराशा-वादी होने का कोई कारण नहीं है।

प्रश्न

1. भारत में आर्थिक नियोजन के दोस्त वर्षों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए ।
 2. निम्नले 20 वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
 3. भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता के मुख्य कारणों का विवरण कीजिए, तथा इसकी सफलता के लिए बचने सुझाव दीजिए ।
-

राजस्थान—एक नजर में

(1972 की जनगणना पर आधारित)

1 जनसंख्या	कुल	25,7,65,806
	पुरुष	13,484,383
	स्त्रियाँ	12,281,423
2 क्षेत्र	342,214 वर्ग किलोमीटर	
3 वृद्धि दर 1961-71	27.83 प्रतिशत	
4 जन-संख्या का घनत्व	75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर	
5 लिंग-अनुपात	911 स्त्रियाँ प्रति सहस्र पुरुष	
6 कुल जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत	कुल	19.07
	पुरुष	28.74
	स्त्री	8.46
7 शहरी जनसंख्या में साक्षरता	43.47 प्रतिशत	
8 ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता	13.85	"
9 शहरी क्षेत्रों की संख्या	157	
10 कुल जनसंख्या में शहरी जन संख्या का अनुपात	17.63 प्रतिशत	
11 कुल गाँवों की संख्या	बसे हुए	33,305
	घेर बसे हुए	2,490
12 कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात	82.37 प्रतिशत	
13 कुल जनसंख्या में धर्मिकों का प्रतिशत	कुल	31.24
	पुरुष	52.09
	स्त्री	8.34
14 कुल जनसंख्या में अनु० जाति के लोग (> castes)	15.82 प्रतिशत	
15 कुल जन संख्या में अनु० जन० जाति के लोग (S tribes)	12.13	"
16 अनु० जातियों में साक्षरता	9.14 प्रतिशत	
17 अनु० जन जातियों में साक्षरता	6.47	"

राजस्थान : एक परिचय

(Rajasthan An Introduction)

"Rajasthan is the collective and classical denomination of Western India, which for centuries remainde of the territory controlled, ruled and predominantly inhabited by (Rajput) princes"

स्वतन्त्र भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की विशालता के आधार पर वर्तमान राजस्थान का द्वितीय स्थान है। इस राज्य का वर्तमान स्वरूप एवं आकार ब्रिटिश शासन-कालीन राजपूताना क्षेत्र के कई छोटी-छोटी देसी रियासतों एवं ठिकानों के विलयन का परिणाम है। 'राज्य पुनर्गठन एक्ट, 1956,' (State Reorganisation Act, 1956) के अन्तर्गत यह 1 नवम्बर, सन् 1956 को भारत के संघारमक एवं गणराज्य का एक अभिन्न अंग बन गया।

इस राज्य के उद्गम (Origin) के सम्बन्ध में प्रमुखतः दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं। प्रथम के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज के राजस्थान का संपूर्ण भू-खण्ड प्रागुऐतिहासिक काल में 'टायथिस सागर' (Tythes Sea) का एक भाग था। धीरे-धीरे इस सागर के वहाँ से हटने के कारण एक विस्तृत भू-खण्ड उदय होने लगा। सागर, डीढ़वाला, पक्षपद्मा, बापरिन तथा लूनकरणसर की नमक की सीलें तथा भरतपुर में नमकीन जल के कुछ इस तथ्य के प्रमाण हैं। इस क्षेत्र में जिप्सम या खडिया मिट्टी का होना भी इस विचारधारा को प्रमाणित करता है। पृथ्वी के भीतर बड़े हुए पत्थर के अस्थिपत्थर (Fossils) भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। द्वितीय विचारधारा के अनुसार, विद्वानों का यह मत है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ तथा विनिर्मित था। ऋग्वेद के अनुसार यहाँ सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, जिसका प्रमाण आधुनिक घग्घर नदी का मूलमूल है। मोरार जिले में हर्षागव के निकट 'चतुर्धारा' नामक स्थान भी इस तथ्य की पुष्टि करता

है। परन्तु धीरे-धीरे भू-तत्वों के अभ्युत्थान के कारण इस क्षेत्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया।

1. स्थिति (Situation) : राजस्थान राज्य के उत्तर-पश्चिम में 23°3 तथा 30°12 उत्तरी अक्षांश रेखाओं (North Latitudes) तथा 69°30' और 78°17' पूर्वी देशान्तर रेखाओं (East Longitudes) के मध्य स्थित है। देश के विभाजन के बाद इसकी पश्चिमी सीमा के अन्त से पाकिस्तान की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। इसके उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में दिल्ली तथा हरियाणा, पूरब में उत्तर-प्रदेश, दक्षिण में गुजरात तथा दक्षिण-पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य स्थित हैं।

2. क्षेत्रफल तथा जन-संख्या (Area and Population) : क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारतीय संघ का मध्यप्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है। इस राज्य का क्षेत्रफल 1,32,147 वर्गमील या 3,12,251 वर्ग किलोमीटर है, परन्तु 'सर्वेयर जनरल ऑफ इण्डिया' (Surveyor General of India) के अनुसार इसका क्षेत्रफल 3,41,732 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सम्पूर्ण देश के क्षेत्रफल का 10.14 प्रतिशत है। सन् 1971 की जन-गणना के अनुसार सम्पूर्ण राजस्थान की जनसंख्या 2.94 करोड़ है तथा जनघनत्व का प्रतिशत 75 है। इस प्रकार भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का दूसरा स्थान है, परन्तु जनसंख्या के आधार पर इसका दसवाँ स्थान है।

3. सामान्य लक्षण (General Features) : इस राज्य की आकृति एक असमान एवं अनियमित समचतुर्भुज के समान है। अरावली की पर्वत-श्रेणियाँ राजस्थान को दो भागों में बाँटती हैं—उत्तरी-पश्चिमी भाग, सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 3/5 भाग है तथा दक्षिण-पूर्वी भाग, सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 2/5 भाग। दक्षिण-पूर्व में अम्बाल नदी मध्यप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों की विभाजन-रेखा है। इनका क्षेत्रफल विस्तृत होने के कारण, यह राज्य विभिन्न प्राकृतिक विषयताओं का प्रदेश है। जहाँ इसके एक ओर शृङ्खलाबद्ध पर्वत श्रेणियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर इसके पश्चिमी भाग में मीलों तक 'थार मरुभूमि' (Thar Desert) के रेगिस्तानी मैदान भी हैं, जहाँ या तो वर्षा होती ही नहीं, और यदि होती भी है तो बहुत कम। सबसे अधिक विषय-गता तो यह है कि इस क्षेत्र में कहीं-कहीं तो सूखे पठार हैं, तो कहीं-कहीं कई प्राकृतिक झीलें भी हैं। इन विषयताओं के कारण ही, इस राज्य के स्थल या भूमि की आकृति, जलवायु तथा मिट्टियों में विभिन्नता है।

4. प्राकृतिक लक्षण (Physical Features) : राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन चार भागों में किया जा सकता है : (i) मरु प्रदेश या रेगिस्तानी भाग; (ii) अरावली पहाड़ियाँ, (iii) मैदान, तथा (iv) पठारी भाग। राजस्थान की

वर्ष-व्यवस्था में इन प्राकृतिक भागों का अलग-अलग योगदान है। अतः इनका सक्षिप्त पन्थि प्राप्त करना आवश्यक है।

(1) रेगिस्तानी भाग (The Desert) भारत में 'थार का मरुप्रदेश' सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल से सिन्ध तक 300 से 380 मील तक फैला हुआ है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा शेखावाटी के घेरे इस रेतिले क्षेत्र में ही स्थित हैं। जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर की तरफ तो मीलों तक बालू के टीले ही टीले (Sand dunes) नज़र आते हैं। इन क्षेत्रों में कहीं पर भी हरियाली नज़र नहीं आती। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो दिक्कत ही निर्जन हैं। गर्मियों के मौसम में ये क्षेत्र काफी गरम रहते हैं तथा सूख चरकी है। प्रायः इन स्थानों पर धूल-भरी आंधियाँ आती हैं। उत्तर में पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है और कहीं तो वर्षा 15"-20" तक तो कहीं 10" से 5" के बीच ही होती है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम कुएँ हैं, जिनका जल-स्तर भूमि की गहराई से 200-300 मीटर होता है। कुछ क्षेत्रों में तो पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। माताघाट के माधवों का अमाव होने के कारण, ऊँटों के द्वारा ही पानी पहुँचाया जाता है। इसी क्षेत्र में साबर, कुचावन, डीडवाना तथा डेमाना की नमक की झीलें हैं।

राजस्थान का यह मरुप्रदेश मृगु-प्रदेश कहलाता है। यहाँ की आबादी घनी नहीं है। यहाँ के निवासियों को अपनी जीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वर्षा-ऋतु में लूनी नदी, जो इस क्षेत्र की एकमात्र नदी है, लोगों को नवजीवन प्रदान करती है, अन्यथा इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए अब कोई माध्यम नहीं है। जहाँ वर्षा 15 से 20 तक हो जाती है, वहाँ बाजरा, गवार, मोठ, तिल तथा सूग की खेती की जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में खरीफ की फसल ही बाँगी जाती है। किसानों को बहुधा अपने जानवरों के लिए चारे तथा जल की व्यवस्था करने के लिए दूसरे क्षेत्रों की ओर जाना पड़ता है। इस क्षेत्र का विकास करने के लिए एच 'केन्द्रीय मूला क्षेत्र अनुसंधान संस्था' (Central Arid Zone Research Institute) स्थापित की गयी है। एच 'केन्द्रीय रेगिस्तान विचार बोर्ड' भी रेगिस्तान की उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने के लिए बना है।

(2) बरावली की पहाड़ियाँ (Aravalli Hills) राजस्थान प्रदेश में बरावली की पहाड़ियाँ गिरौली से खेतड़ी तथा दिसनी तक फैली हुयी हैं। इन पहाड़ियों का प्रदेश अरावली का पठारी भाग कहलाता है। दक्षिण-पश्चिमों में इन पर्वतमालाओं का विस्तार गुजरात के मैदानों तक है। इस प्रकार यह पठारी प्रदेश 430 मील या 692 किलोमीटर लम्बा है और पर्वत-मालाओं की औसत ऊँचाई 3,000 फीट है।

इसकी मदसे ऊँची चोटी माउन्ट जाबू की गुरुशिखर चोटी है (3,650 फीट)। इनमें वतिरिक्त सांभर-सिरोही पर्वत-मालाओं के क्षेत्र में कुछ अन्य प्रमुख पर्वत चोटियाँ भी हैं : गोरम, जो उदयपुर जिले में कुम्भलगढ के निकट है, 3,075 फीट, अजमेर में तारागढ 2,85 फीट (873 मीटर)। सांभर-सैतड़ी क्षेत्र की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं रघुनाथगढ (1,055 मीटर), लोहारगल आदि।

राजस्थान के अरावली पर्वत-मालाओं के क्षेत्र को उनमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं

1. नदियाँ इन पर्वत-श्रेणियों के कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे—जमना, माही, काकनी, सूणो आदि जो वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों का पानी एकत्र करके तथा बाध बना कर मिचाई की व्यवस्था की जा सकती है।

2. इन तथा सौराष्ट्र इन पर्वत-मालाओं की ढाल पर घने जंगल हैं, जिनसे कई लकड़ों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इन वनों के कारण ही इस क्षेत्र में वर्षा भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन पर्वत-शृङ्खलाओं की ढालों पर चारा-गाह है।

3. खनिज : पर्वत-श्रेणियों के कारण खनिज में राजस्थान काफी सम्पन्न है और महा विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। अगर हम राजस्थान की खनिज पदार्थों का अज्ज्ञासपूर्ण कहे तो गलत न होगा। यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में जलोढ़ धातुएँ, जैसे—फ्लिनाइट, चूना, जिप्सम, ताम्रक, संगमरमर आदि पाई जाती हैं तथा अरावली के उत्तरी भाग में ताँबा, सीसा, जस्ता, लोहा, संगमरमर आदि पाये जाते हैं। कुछ खनिज तो ऐसे हैं कि भारी देश में केवल राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं, जैसे—सीसा, जस्ता, बुलफाम और टंगस्टन। सैतड़ी, अलवर तथा जयपुर जिले में ताँबे के नये भण्डार मिले हैं। कोयले और लोहे की यहाँ कमी है। उदयपुर से 14 मील दूर इधोक में बिक स्मैल्टर का कारखाना खुला है, जो जस्ते को अन्य खनिजों, जैसे सीसा और चाँदी से अलग करेगा।

4. वर्षा इस क्षेत्र में पहाड़ी तथा जंगली के कारण वर्षा की मात्रा अधिक है। महा सागम्य वर्षा होती है तथा घाटीय क्षेत्र में, वहाँ खेती भी की जाती है। राज्य की 90 में 95 प्रतिशत वर्षा वर्षा-ऋतु में जुलाई से नवम्बर तक होती है। राजस्थान के विभिन्न भागों में वर्षा का वितरण बहुत अधिक असमान है। वर्षा की मात्रा दक्षिण-पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर से कम होती जाती है। उत्तर-पश्चिम राजस्थान के चार मरुस्थल में वर्षा सबसे कम होती है। दक्षिण-पूर्वी भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर के बास-मास होती है जबकि पार के रेगिस्थान में यह 25 सेंटीमीटर से भी कम है।

(iii) मैदान (Plains) : राजस्थान प्रदेश - मैदानी भाग अरावली के पुरब से प्रारम्भ होकर गंगा घाटी के मैदान तक विस्तृत है। राजस्थान राज्य के अन्तर्गत पूर्वी मैदान का प्रदेश दो भागों में बांटा जा सकता है—(i) बनास घाटी का मैदान तथा (ii) उदयपुर का दक्षिण-पूर्वी भाग और वासवाडा और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग। प्रथम के अन्तर्गत खलनगर, भरनपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बीकानेर, झुझम् तथा बीकानेर के जिले आते हैं। दूसरे क्षेत्र में उदयपुर, बांसवाडा तथा चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में कई नदियाँ बहती हैं, जैसे बनास (मेवाड़ में) तथा उसकी सहायक नदियाँ, तथा बाही और उसकी सहायक नदियाँ। बनास नदी घाटी का मैदान काफी उपजाऊ।

आर्थिक दृष्टि में राजस्थान का मैदानी प्रदेश काफी विकसित है। सामान्य बरपा होने से यहाँ रबी तथा खरीफ दोनों की ही फसलें बोई जाती हैं। कुजों से सिंचाई की भी व्यवस्था की जाती है। अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस क्षेत्र में पशु-पालन व्यवसाय भी अर्थिक विकसित है। उद्योग-धन्यों में सूती-बस्त्र, शमशेर तथा तैल के कारखाने भी कहीं-कहीं स्थापित किये गये हैं। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूँ, चना, ज्वार, मक्का, ज्वार, मूँग, मोठ, बाजरा, जौ, सरसो, तिल, तथा मूँगफली हैं।

(iv) पठारी भाग (Plateau) राजस्थान के मेवाड़ के मैदानी भाग के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ पठारी भाग 'हादोती' (Hadoti) कहलाता है। इसमें कोटा, डूँदी, जालावाड तथा चित्तौड़गढ़ के जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में अधिक बरपा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ चम्बल, नाथगंगा, बनास, काशी सिन्ध तथा पारवती हैं। वर्षा और नदियों के कारण यह भाग कृषि की दृष्टि से सम्पन्न है तथा यहाँ चावल, मक्का, ज्वार तथा मूँगफली की उपज काफी मात्रा में होती है।

■ मिट्टी (Soil) राजस्थान जैसे राज्य की अर्थ-व्यवस्था में, जहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, मिट्टी की विरल वा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की मिट्टी या मैदानी भू-भाग भाग के विस्तृत मिश्र-भूभाग में मैदान का ही एक भाग है। परन्तु सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न भागों में मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं

लाल मिट्टी (Red Soil) - इस प्रकार की मिट्टी अजमेर, जिनतगढ़, उदयपुर, झुझपुर, वासवाडा तथा अरावली के पूर्व में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोह की अधिकता होती है तथा इसमें खून और पाटल का प्रचुरता भी अधिक होता है, परन्तु नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा नमों की कमी होती है। इस प्रकार की मिट्टी सामान्यतः उपजाऊ होती है।

(ii) काली मिट्टी (Black Soil) कोटा, जालावाड़, मालवा, बसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के कुछ थोड़े से क्षेत्रों में यह मिट्टी पायी जाती है। इसमें नमी को बनाये रखने की क्षमता अधिक होती है, परन्तु इसमें 'फॉस्फोरिक एसिड' का अभाव रहता है। इसमें पोटाश तथा चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है।

(iii) कछारी मिट्टी (Alluvial Soil) भरतपुर, अजमेर तथा गंगानगर जिले के कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। इसमें पोटाश, फॉस्फोरस, चूना तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में होते हैं, परन्तु नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। कृत्रिम तथा नहरों से सिंचनी की व्यवस्था करके इस प्रकार की मिट्टी से गेहूँ, बाजरा, ज्वार तथा तन्बाखू की फसलें प्राप्त की जाती हैं।

(iv) लेटराइट मिट्टी (Laterite Soil) इस प्रकार की मिट्टी बानसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा कुलगढ़ में पायी जाती है। इसमें चूने, नमी तथा नाइट्रोजन के तत्वों की कमी होती है।

(v) बलुही मिट्टी या रेत (Sand) जोगपुर क्षेत्र, बीकानेर के दक्षिण में, जैसलमेर जिसे तथा जयपुर क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में यह मिट्टी पायी जाती है। इसमें भूमि की उपजाऊ बनाने वाले तत्वों का अभाव होने तथा बहुतहील दमक का आधिक्य होने के कारण, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। जिन स्थानों पर 10" से 15' तक वर्षा होती है, वहाँ बाजरा, मूंग, मोठ आदि फसलें होती हैं और जहाँ पर सिंचनी की व्यवस्था है, वहाँ पर नाइट्रोजन साध देकर चावल, गेहूँ, चन्ना, कपास आदि की अच्छी फसलें उत्पन्न की जाती हैं।

6 जलवायु (Climate) राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, अर्थात् यहाँ ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। वर्षों के मौसम में इसके उत्तरी-पश्चिमी भाग में दक्षिण-पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक सर्दी पड़ती है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान के तीन मौसम हैं—(i) ग्रीष्म ऋतु (The Hot-weather Season), (ii) सामान्य वर्षा ऋतु (The Season of General Rains), तथा (iii) शरद ऋतु (The Cold Weather Season)। भारतीय ऋतु विभाग में इस राज्य की शरद ऋतु को भी दो उप-विभागों में विभाजित कर दिया है—(अ) सौतनी हुण्डी मानसून का मौसम, जनवरी से दिसम्बर तक, तथा (ब) सर्दी का मौसम, जनवरी से फरवरी तक।

उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में (i) ग्रीष्म ऋतु मार्च-अप्रैल में प्रारंभ होती है तथा सितम्बर तक रहती है। इस ऋतु में मई तथा जून के सहोनी

मे अधिकतम तापमान होता है। जून-भरी आधियाँ भी प्रायः इसी ऋतु में जाती हैं। परन्तु इस ऋतु की विशेषता यह है कि इसकी रात्रियाँ ठण्डी तथा शुष्क होती हैं।

(ii) वर्षा ऋतु की अवधि जून के मध्य से सितम्बर तक है। 90 प्रतिशत वर्षा मानसून की अवधि में जून से सितम्बर तक होती है। शरद-ऋतु अर्थात् सर्दी के मौसम में भी थोड़ी-बहुत वर्षा हो जाती है। सामान्य वर्षा-ऋतु में भी, अधिक राजस्थान के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी भागों में उसकी मात्रा कम होती है। अरावली पर्वत की षेलियाँ मानसूनी हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देती, जिससे इनके निकट तो 40" वर्षा हो जाती है, परन्तु इस राज्य के उत्तर-पश्चिमी कोने पर इसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी तथा भारतीय महासागर (Indian Ocean) में आने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यही कारण है कि मेवाड़, हाड़ोती पठार तथा अरावली की पर्वत षेलियों के पूर्वी ढालों पर तथा झुगरपुर और बांसवाड़ा में अच्छी वर्षा हो जाती है। इस राज्य में औसत वर्षा 6" से 40" तक होती है।

(iii) शरद-ऋतु . राजस्थान में शरद-ऋतु अक्टूबर से प्रारम्भ होती है और फरवरी तक सर्दी पड़नी रहती है। अक्टूबर से दिसम्बर तक की अवधि मानसूनी हवाओं के लीटने की अवधि होती है जिससे राजस्थान के लगभग आधे भाग में 20-4 cm से कुछ ही कम वर्षा हो जाती है, जिससे गह्रा का मौसम काफी अच्छा हो जाता है अक्टूबर-महीने में सर्जन तापक्रम समान ही रहता है। नवम्बर में अपेक्षा-कृत कुछ सर्दी पड़ने लगती है। दिसम्बर से फरवरी तक अच्छी सर्दी पड़ती है। अत्यधिक सर्दी पड़ने पर मरुस्थलीय प्रदेश में कहीं-कहीं तापक्रम प्रायः शून्य से भी नीचे गिर जाता है। पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से इस मौसम में कभी-कभी वर्षा हो जाने पर गह्रा तथा चने की फसल को काफी लाभ पहुँचता है।

7 राजस्थान की पशु-सम्पदा राजस्थान पशु-सम्पदा में सम्मिलित है। पशु-पालन यहाँ की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, जिससे जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को स्वतन्त्र सहा महामक रोजी-रोजी का माध्यम प्रदान किया है। वर्तमान समय में राजस्थान में पशु-समुदाय (Livestock) की संख्या लगभग 390 लाख है, जिसका मूल्य 76 करोड़ रुपये है। प्रति वर्ष पशु-समुदाय या इससे सम्बन्धित उत्पात के निर्यात में लगभग 20 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है। भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाली ऊन का 40% भाग राजस्थान के पशुओं में ही प्राप्त होता है।

देश की उत्तम किस्म की पशुओं की मूल्य में से अनेक नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं। 'राथी' (Rathi), थारपारकर (Tharparkar), गिर (Gir) व नागौरी (Nagauri) यहाँ की उत्तम कोटि की नस्लें हैं। विगत 12 वर्षों के दौरान अकाल की भयनरता के कारण राजस्थान के पशु-समुदाय पर बुरा असर पड़ा है।

लोगों ने पशुओं की अकाल के कारण घटती हुई सराया से सुरक्षा के लिए उन पशुओं को भी पाल रखा है, जिन्हें आर्थिक दृष्टि में रखना उपयुक्त नहीं है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है, साथ ही उनकी पशु-पालन की प्रेरणा हतोत्साहित हुई है।

राज्य सरकार पशु-सम्पदा की सुरक्षा एवं विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है। राज्य में चारे के विकास कार्यक्रम को पशु सम्पत्ति के विकास एवं दूध वितरण योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। सरकार देशस्तरीय स्तर पर पशुओं के स्थिरीकरण, उनकी नस्ल के विकास, आर्थिक दृष्टि में अनुपयोगी पशुओं के उपयोग आदि की योजनाओं को प्रियान्वित करने के प्रयत्न कर रही है। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बप्तर, भरतपुर व बांटा में 8 डरियाँ खोले जा रही हैं, ताकि वर्तमान योजना के अन्तर्गत दूध की पूर्ति 20000 लिटर प्रति दिन से बढ़ कर 3 लाख लिटर प्रति दिन की जा सके। राज्य से दिल्ली को दूध व दूध से बने पदार्थों को भेजने की भी योजना बनाई जा रही है। राज्य में पशु पध की आधुनिक सुविधाओं का निरधार किया जा रहा है ताकि राज्य के 2 करोड़ भेड़ व बकरियों के स्वामी अधिक लाभ कमा सकें। इस समय राज्य में 120 लाख किलोग्राम गोشت व 108 लाख किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष पैदा होती है, जिसे क्रमशः 150 लाख कि ग्राम तथा 120 लाख किलोग्राम तक निर्यात अवधि में बढ़ाने की योजना है। राज्य मृगी पालन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। वहाँ पहले राज्य से 5000 अण्डे प्रति दिन बाहर भेजे जाते थे, वहाँ अब प्रति दिन 1 लाख अण्ड बाहर भेजे जा रहे हैं।

राज्य की पशु-सम्पदा का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है :

राजस्थान की पशु सम्पदा (1971)

पशु	संख्या (1000 में)
गाय, बैल	12470
भैंस, भैंसे	4593
भेड़	5556
बकरी	12162
घोड़े व टट्टू	45
अल्पर	1
गर्ध	586
ऊँट	745
मुँजर	117
मुँग, मुँगियाँ	1235

8 ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या (Rural and Urban Population)

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का 3/5 से अधिक भाग 82.7 प्रतिशत गाँवों में निवास करता है, जबकि लगभग 16.3 क्षेत्र प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। इस प्रकार मूल रूप से राजस्थान कृषि प्रधान तथा ग्रामों का प्रदेश है। यहाँ औद्योगिक विकास के कार्यक्रम अभी कुछ वर्ष पहले में ही प्रारम्भ किये गये हैं, परन्तु इतना विकास इतना अधिक नहीं हुआ है, जिससे कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के प्रतिशतों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सके।

निम्नलिखित तालिका ग्रामीण जनसंख्या के विवरण तथा विभिन्न आकार के गाँवों की संख्या को व्यक्त करती है।¹

गाँवों का प्रकार तथा ग्रामीण जनसंख्या का वितरण 1971

गाँवों का आकार	कुल ग्रामीण जनसंख्या मिनिमम में	गाँवों की कुल संख्या	जनसंख्या का प्रतिशत	गाँवों का प्रतिशत
200 से कम	0 936	8,771	4.41	26.33
200-499	3 687	11,010	17.37	33.06
500-999	5 523	78,17	26.03	23.47
1,000-1,999	5 494	4,108	25.69	12.03
2,000-4,099	4 390	1,514	21.69	4.58
5000	1 076	16	5.07	0.50
10,000 से अधिक	0 116	10	0.54	0.03
योग	21 222	33 305	100.0	100.0

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण जनसंख्या 33,305 गाँवों में निवास करती है। उपरोक्त आँकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि 83.0 प्रतिशत गाँव ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 1,000 व्यक्तियों से भी कम है। ऐसे गाँवों में 48 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इन गाँवों के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करने पर यह ज्ञान होता है कि अधिकतर पश्चिमी रेगिस्तान संघान तथा अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण इनके आकार में विस्तार नहीं हुआ है। अधिकतर किसान अपनी भूमि के निकट ही ओपड़ियों में निवास करना पसन्द करते हैं। 10,000 से अधिक व्यक्तियों वाले बड़े गाँवों में निवास करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत केवल 5.4 ही है।

1 Source: Census of India 1971, Rajasthan Population Statistics

परन्तु इस राज्य में शहरीकरण की योजना का प्राथमिक जनसंख्या पर काफी प्रभाव पड़ा है। कई क्षेत्रों से शहरी केन्द्रों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रवास हुआ है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या का विकास रुक गया है। इसके अतिरिक्त राज्य की औद्योगिक विकास की योजनाओं ने भी शहरी जनसंख्या में वृद्धि की है। वास्तव में सन् 1921 में ग्रामीण जनसंख्या में अधिक कमी होती रही है। सन् 1921 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 86.7 था। सन् 1932 में 86.3 प्रतिशत तथा सन् 1941 में 85.7 प्रतिशत। अकाल तथा महाभारिखों के कारण भी ग्राम-दर कम रही है, जिसमें भी ग्रामीण जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हो सकी। सन् 1961 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में कुछ वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि ऐसे 74 कस्बे गाँवों के वर्ग में सम्मिलित कर दिए गए, जिनकी जनसंख्या 400 हजार थी। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत को सन् 1901 में 71.5 प्रतिशत था, सन् 1961 में बढ़कर 83.7 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त उन समय तक कृषि क्षेत्र भूमि का विस्तार तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाने से ग्राम-क्षेत्रों में रोजगार के साधन भी उपलब्ध होने लगे थे। सन् 1971 में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 21,222,045 थी, जबकि शहरी जनसंख्या केवल 4,543,761 थी।

शहरी जनसंख्या सन् 1941 तक राजस्थान में शहरी जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। सन् 1901 में सन् 1941 के मध्य यह केवल 13.0 प्रतिशत से बढ़कर 14.0 तक ही पहुँच सकी थी। सन् 1901 में यह प्रतिशत बढ़कर 17.3 तक पहुँच गया था, परन्तु सन् 1961 में शहरी जनसंख्या पुनः बढ़कर 16.3 प्रतिशत हो गयी। इस राज्य में शहरी जनसंख्या में वृद्धि कई कारणों से हुई है। गाँवों की ओर निर्भर जर्म-व्यवस्था के टूट जाने, कई गाँवों के शहरी बाजार-केन्द्रों में परिवर्तित होने तथा गाँवों में एम सदन बाहुल्य के सामने, बाजियर तथा व्यापार का विकास होने के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। सन् 1901-61 के मध्य ग्रामीण जनसंख्या में 29.65 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या में 11.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि सन् 1961-71 के मध्य वृद्धि का यह प्रतिशत क्रमशः 20.77 व 38.47 था। अगल बूझ की ताकिका शहरी जनसंख्या के वितरण तथा विभिन्न आकार के शहरों की संख्या को व्यक्त करती है -

राजस्थान में सन् 1941 से कुछ बड़े शहरों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। मध्यम आकार के शहरों की संख्या बढ़ शहरों में लाने लगी है। जयपुर शहर का विकास तो उसके राजधानी होने तथा इधर कुछ बर्षों में औद्योगिक विकास के कारण हुआ है। अजमेर के विस्तार का अर्थ उस क्षेत्र में कृषि के विकास को

शहरी का आकार तथा शहरी जनसंख्या का वितरण (न)

शहर का आकार	कुल शहरी जनसंख्या मिलियन में	शहरी की कुल संख्या	जनसंख्या का प्रतिशत	शहरी का प्रतिशत
100,000 से अधिक	1 902	7	41.87	4.46
50,000-99,999	.488	7	10.75	4.46
20000-49999	930	31	20.47	19.75
10000-19999	898	67	19.77	42.67
5000-9999	308	41	6.78	26.11
5000 से कम	017	4		
योग	4,543	137	100.00	100.00

है। कोटा में जनसंख्या राजस्थान के अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि इस जिले में औद्योगिक विकास-कार्यक्रमों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजस्थान शहरीकरण की ओर अधिक अग्रसर हो रहा है। अधिकांश शहरी में अच्छी आवास-सुविधाओं, बिजली की पूर्ण आपूर्ति-प्रमोद, शिक्षा, चिकित्सा तथा यातायात की सुविधाओं और सुरक्षा ने लोगों को नगरों में बसने की प्रेरणाएँ प्रदान की हैं।

9. **कृषिगत ढाँचा (Agrarian Structure) :** यहाँ के लगभग 80 प्रतिशत लोगों का धंधा कृषि ही है। राज्य की लगभग आधी आर्य कृषि से ही आती है। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी, यहाँ की कृषि अवस्था सन्तोषजनक नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि यहाँ कृषि-क्षेत्र के केवल 13 प्रतिशत पर ही सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं—क्षेत्र 87 प्रतिशत भू-भाग को सातसून की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान में 8 करोड़ 47 लाख एकड़ भू-भाग कृषि योग्य है। लेकिन सुविधाओं के अभाव में केवल 4 करोड़ एकड़ भू-भाग में ही कृषि की जाती है। पानी एवं सिंचाई की सुविधाओं की कमी से प्रति एकड़ उत्पादन भी कम ही है, परन्तु गत कुछ वर्षों से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। अब राजस्थान खाद्यान्नों में निर्धारित कर्ता की स्थिति में है। व्यावहारिक, आर्थिक एवं अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् ने 8 लाख टन खाद्यान्नों के वार्षिक अतिरिक्त का अनुमान लगाया है।

10. **औद्योगिक ढाँचा (Industrial Structure)** राजस्थान भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक कच्चा माल व विभिन्न खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध

हैं परन्तु व्यक्ति व परिवहन के साधनों के अभाव में राज्य का औद्योगीकरण नहीं हो सका है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले राज्य में बहुत ही कम बड़े पैमाने के उद्योग थे। सात सूती कपड़ों की मिलों के अतिरिक्त राज्य का एक मात्र मुख्य उद्योग लाहौर में सीमेंट का ही था।

वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, शीशा उद्योग, नमक उद्योग, उर्वरक उद्योग, ठान उद्योग आदि महत्वपूर्ण हैं। इन उद्योगों के अलावा राज्य में प्रयोगशाला यन्त्र शिबिर टोर्न मौजार, टेक्सी मीटर्स, गृह कार्य हेतु विद्युत एवं पानी के मीटर आदि के कारखाने भी राज्य में प्रारम्भ हो चुके हैं।

कोटा में कैम्पियस कारखाना, बाइलोन तथा रेवन के कारखाने स्थापित किये गये हैं। य सभी कारखाने निजी क्षेत्र में सरकारी सहभाव व सहयोग से चलाये जा रहे हैं। राजस्थान में सन् 1970 में पञ्जीकृत कारखानों की संख्या थी।

राजस्थान के जल साधन (Water Resources of Rajasthan)

राजस्थान के जल स्रोतों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, (क) भूमि की ऊपरी सतह का जल स्रोत, (ख) भूमिगत जल स्रोत।

(क) भूमि की ऊपरी सतह या भरावलीय जल स्रोत—इन जल स्रोतों के अन्तर्गत राजस्थान की प्रमुख नदियाँ एवं झीलें आती हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ राजस्थान में बिम्बलसिंह प्रमुख नदियाँ हैं।

1 **बम्बल नदी** यह नदी मध्यप्रदेश में निकलकर राजस्थान के बाटा, बूंदी व सर्वाईसाधोपुर जिलों में बहती हुई उत्तरप्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी के पानी को एक बहुउद्देशीय योजना द्वारा रोक कर राज्य में जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है तथा सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है।

2 **बनास नदी** आर्षिक नदी व की दृष्टि से इन नदी का स्थान राज्य में बम्बल के बाद दूसरा है। यह नदी उदयपुर जिले में कुम्भलगढ़ दुर्ग से 3 किलोमीटर पूर्व अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी के ऊपरी क्षेत्र पहाड़ी है, जहाँ भारी वर्षा होती है। इसकी लम्बाई 483 किलोमीटर है और इसके दोनों ओर घाट बने हैं।

3 **लूनी नदी** यह नदी पूर्णतः बरगाती नदी है जो जयमेर के जानामगर के पास नाथ पहाड़ियों से निकल कर 320 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जोधपुर, नाडमेर तथा जालौर के सुन्ताबस्त जिलों में बहती है।

4 **माही नदी** यह नदी मध्यप्रदेश में विष्णुगन्धर्व पर्वत से निकल कर राजस्थान के बासवादा व डूंगरपुर जिलों में बहती है।

5. **छप्पर नदी** : यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकल कर राजस्थान के गंगानगर जिले में भूमि में विलीन हो जाती है। इस नदी के जल से राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है।

6. **वेयच नदी** : यह नदी वनास की सहायक नदी है, जो उदयपुर के उत्तर-पश्चिम में बरावली पहाड़ियों से निकल कर उदय सागर झील में गिरती है। इस नदी की पृष्ठ भूमि में गन्ना, चावल व गेहूँ की अच्छी खेती होती है।

7. **बाघ गंगा** : यह नदी जयपुर व सीकर जिलों की सीमा के पास धरौठा की पहाड़ी से निकल कर भरतपुर जिले में बहती हुई आगरे के पास जमुना में मिल जाती है। इस नदी घाटी के क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, फलस्वरूप यह क्षेत्र उपजाऊ है।

8. **अन्य नदियाँ** : उपर्युक्त नदियों के अलावा राजस्थान में पारवती, काली-सिंध, कोठारी नदी, सागी नदी, सावरमती नदी आदि नदियाँ भी बहती हैं, जिनकी घाटियों में अच्छी फसलें उपजाई जाती हैं।

राजस्थान की प्रमुख झीलें व तालाब :

वर्षा के अभाव के कारण राजस्थान में वर्षा के जल को गिराई व पौने के लिए झीलें व तालाबों में एकत्र कर लिया जाता है। यही पानी मुख्यतः पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में रोक लिया जाता है। राजस्थान में अधिकांश झीलें सूखे पानी की हैं, लेकिन मरु-क्षेत्र की कुछ झीलें खारे पानी की भी हैं।

(अ) **राजस्थान की सूखे पानी की झीलें** : राजस्थान की सूखे पानी की प्रमुख झीलें निम्नलिखित हैं।

1. **अमरसमन्त झील** : यह उदयपुर नगर से 45 कि० मी० दूर पूर्व में स्थित है। इस झील से लगभग 1800 वर्ग कि० मी० क्षेत्र का पानी एकत्र होता है। इस झील की परिधि 145 कि० मी० है। इस झील से नहरें निकाली गई हैं, जो सिंचाई के काम आती हैं।

2. **राजसमन्त झील** : यह उदयपुर नगर से 59 कि. मी. उत्तर में काकरोली के पास है। इसकी लम्बाई 6.44 कि. मी. व चौड़ाई 2.50 कि. मी. है। इसमें लगभग 513 वर्ग कि. मी. का पानी एकत्र होता है। इस झील से खारे पानी को पानी दिया जाता है तथा इसका जल भी सिंचाई के काम आता है।

3. **पिछोला झील** : यह झील 7 कि. मी. लम्बी तथा 2 कि. मी. चौड़ी है।

4. **फतेह सागर झील** : यह झील पिछोला झील के उत्तर में है तथा नहरों द्वारा उससे जुड़ी हुई है। इसकी लम्बाई 2.50 कि. मी. तथा चौड़ाई 1.61 किलोमीटर है।

5 अनासलर झील यह झील जजमेर नगर के दक्षिण में दर्रावली की पहाड़ियों पर स्थित है। यह लगभग 13 कि. मी. की परिधि में फैली हुई है।

॥ अन्य झीलें उपर्युक्त झीलों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण छोटी पानी की झीलें भी हैं जैसे बलसर के पास गिल्लिसेड नदी की दाहिनी ओर, बीकानेर के निकट कोलायन झील, जू घरपुर में गैब सगर चित्तौड़ की भोमताल, दीग का पहाड़-ताल जोधपुर का बाल सयन गाउन्ट बाबू की निचली झील आदि।

(ख) राजस्थान की खारे पानी की झीलें राजस्थान की प्रमुख खाट पानी की झीलें निम्नलिखित हैं

1 सांवर झील भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की यह झील कुलेरा जखान से 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी लम्बाई लगभग 3¹ किलोमीटर तथा चौड़ाई 3.25 से 11.25 कि. मी. तक है। इसका औसत गहराई 234 वर्ग कि. मी. है जिसमें 5720 वर्ग कि. मी. क्षेत्र का पानी एकत्र होता है। इस झील में मैद, हपनगर तथा साहसा नदियाँ आकर मिलती हैं। इसकी गहराई 4 मीटर तक रहती है। एक अनुमान के अनुसार इसमें 650 लाख टन तक भरा पड़ा है। इस झील का उपयोग नमक निकालने के लिए किया जाता है। इसमें से प्रतिवर्ष देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7 प्रतिशत नमक प्राप्त होता है।

2 डीडवाना झील यह झील नागीर जिले में डीडवाना कस्बे के पास स्थित है। इसका औसत 10 वर्ग कि. मी. है। इस झील में से वर्ष भर नमक निकालने का काम चलता रहता है।

3 झूम करमसर झील यह झील बीकानेर जिले में झूम करमसर कस्बे के पास स्थित है। यह भी एक खाटे पानी की झील है, जिसमें से नमक निकालकर स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।

4 पञ्चगंगा झील यह झील बाड़मेर जिले में है। इस झील में 1040 वर्ग कि. मी. क्षेत्र का पानी आकर एकत्र होता है। इस झील में से भेषवेधियन लवण निकाला जाता है।

राजस्थान के भूगर्भिक जल स्रोत राजस्थान में सदैव बढ़ते पानी की नदी के अभाव में खोखे की सिन्हाई एवं बहुत बड़ी समस्या रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रान्त में भूगर्भिक जल स्रोतों का उपयोग प्रारम्भ किया गया। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में भूगर्भिक जल के उम्मी प्रकार पर्याप्त स्रोत हैं जिस प्रकार उत्तर के बड़े मैदानी क्षेत्र में हैं क्योंकि राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग मैदानी हैं और नदियों की सहाय मद मिट्टी से बने हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पानी की खोज कभी रहती है। सामान्य 15 से 20 मीटर की गहराई में पानी उपलब्ध हो जाता है। इन क्षेत्रों

मे सिंचाई के लिए कुओं से पानी, चरख, रहट तथा ट्यूब वेल द्वारा निकाला जाता है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर बीकानेर आदि जिलों में भूमि के नीचे अथाह जलराशि के पाये जाने का अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार राज्य में हुए 149 लाख एकड़ फीट भूगर्भिक पानी के स्रोत होने की सम्भावना है।

12 राजस्थान की खनिज सम्पदा (Mineral Wealth of Rajasthan)
खनिज सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान काफी सम्पन्न है। वहाँ विविध प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। अगर हम राजस्थान की खनिज पदार्थों का अजायबघर कहें तो वह गलत न होगा। यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में अलौह धातुएं, जैसे लिग्नाइट, चूना, जिप्सम, समक, मगमरमर आदि पाई जाती हैं तथा अरावली के उत्तरी क्षेत्र में तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, मैंगनीज आदि पाये जाते हैं। कुछ खनिज तो ऐसे हैं जो देश में केवल राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं, जैसे सोडा, जस्ता, गुल्फाम, स्टगस्टन आदि। इस समय देश का 88% जिप्सम, 67% सोड स्टोन, 67% फ़ैल्सपार तथा 72% एम्बरगट्स यहाँ निकाला जा रहा है।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजस्थान में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों को बर्गों में रखा जा सकता है। (क) धात्विक खनिज, (ख) गैर धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को भी दो बर्गों में रखा जा सकता है। (1) लोह धातु खनिज जिनमें लोहा एक मैंगनीज मुख्यतया आते हैं, (2) अलौह धातु खनिज जिनमें तांबा, जस्ता, सीसा, चादो, बेरेलियम, मूरेनियम, थोरियम, टंगस्टन आदि। अधात्विक खनिज पदार्थों में अभ्रत, जिप्सम, शिवा पत्थर, समक, चूना, हीरा, पार्शरॉइट, सिलीका, एम्बरगट्स, काप की बालू, फ़ैल्सपार आदि आते हैं।

राजस्थान में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज निम्नलिखित हैं

(1) खनिज लोहा (Iron Ore) राजस्थान में लोहा अन्य लोहा उत्पादक राज्यों की तुलना में कम लोहा मिलता है। अधिकतम यह लोहा हेमेटाइट किस्म का होता है। बड़ी-कड़ी क्वार्टजाइट व मैग्नेटाइट किस्म का भी लोहा प्राप्त होता है। यहाँ लगभग सभी लोहे के खनिज क्षेत्र अरावली पर्वतों अथवा इसके दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ सर्व प्रथम 1953 में लोहा निकाला गया था। राजस्थान में सन् 1970 में 3.2 हजार टन लोहे का उत्पादन हुआ।

2 मैंगनीज (Manganese) राजस्थान में मैंगनीज का उत्पादन भी अन्य राज्यों की तुलना अपेक्षाकृत कम है। राज्य के जयपुर, उदयपुर एवं बालनगढ़ जिलों में मैंगनीज का खनन किया जाता है। बरैसवाड़ जिले के खनिज क्षेत्र सर्वाधिक

है। एक अनुमान के अनुसार राज्य में लगभग 300 करोड़ टन चूने पत्थर के भंडार हैं। सन् 1970 में लगभग 28 लाख टन चूने पत्थर का खनन किया गया था।

10 सपत्तमरमर (Marble) सपत्तमरमर के उत्पादन में भी राजस्थान का क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में मकराना के सपत्तमरमर के पत्थर श्रेष्ठकोटि के गिने जाते हैं। जयपुर, अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, नागौर जिलों में सपत्तमरमर का बहुतायत में खनन किया जाता है। सन् 1970 में राज्य में लगभग 50 हजार टन सपत्तमरमर का खनन किया गया।

11 पिया पत्थर (Scap Stone) पिया पत्थर के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में प्रमुख स्थान है और प्रायः देश के कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत पिया पत्थर राजस्थान में ही निकाला जाता है। इसका प्रयोग अनेक प्रकार की वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। राज्य के जयपुर, झुगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर जैसे पिया पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में प्रति वर्ष प्रायः 2 लाख टन पिया पत्थर का उत्पादन होता है।

12 भूरा कोयला (Lignite) राजस्थान में घटिया किस्म का भूरा कोयला भी सीमित मात्रा में निकाला जाता है। इसकी खानें बीकानेर जिले में पाई जाती हैं। राजस्थान में इस प्रकार के कोयले का वार्षिक उत्पादन 8 से 10 हजार टन होता है।

उपरोक्त स्थानों के प्रतिरिक्त राजस्थान में अन्य अनेक खनिज भी पाये जाते हैं। राज्य में कुनोराइट फ़ैल्सपार, टंगस्टन, बेरनाइट, इंगार्ली पत्थर, पन्ना सेल्फाइट आदि अनेक प्रकार के खनिज भी व्यापारिक स्तर पर निकाले जाते हैं। राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र में खनिज तेल की भी प्राप्ति होने की सम्भावना है। भारतीय तेल एवं गैस भागीय, भारतीय भू सर्वेक्षण, इंडियन इयूरो शॉफ माइन्स आदि द्वारा किये गये समग्र-समग्र पर सर्वेक्षणों में यथा चलाया है कि जैमलमंडल क्षेत्र में ही लगभग 1½ लाख बर्रल तिलोपीडर क्षेत्र में खनिज के भंडार उपलब्ध हैं।

सन् 1971 में तीसरा, जस्ता व चांदी को छोड़कर निकाली गई प्रमुख धातुओं का विक्रय मूल्य 783 करोड़ रुपया था जबकि छोटी धातुओं का विनियम मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपया था। प्रमुख धातुओं के क्षेत्र में 25 हजार व्यक्ति तथा छोटी धातुओं के क्षेत्र में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। आज-कल धात्विक क्षेत्र से राज्य सरकार को लगभग 139 लाख रुपये की प्रति वर्ष आय होती है।

प्रश्न

1. राजस्थान के प्राकृतिक विमानों का विवरण देते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उनका उसके आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
2. राजस्थान की मिट्टियाँ उसके कृषि-विकास में कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुई हैं ?
3. राजस्थान की जलवायु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए ।
4. राजस्थान की पशु-सम्पदा पर प्रकाश डालिए ।
5. राजस्थान के जल-साधनों पर यथेष्ट प्रकाश डालिए ।
6. राजस्थान की खनिज-सम्पदा का उल्लेख कीजिए और यह बताइए कि राज्य खनिज की दृष्टि से यथेष्ट सम्पन्न है ।

राजस्थान में कृषि

(Agricultural in Rajasthan)

जिम प्रकार भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार राजस्थान एक कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ के लगभग 80 प्रतिशत लोगो का धन्धा कृषि ही है। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी यहाँ की कृषि-व्यवस्था थोड़ा-बहुत नहीं है, क्योंकि लगभग 90 प्रतिशत भू-भाग को मानसून की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। मानसून की अनिश्चितता राजस्थान को भी उसी प्रकार प्रभावित करती है, जिस प्रकार देश के अन्य राज्यों को। राजस्थान में वर्षा का औसत, अन्य राज्यों की तुलना में, बहुत कम है। फलस्वरूप राज्य के अधिकांश भागों में केवल एक फसल खरीफ ही उगाई जाती है। राजस्थान में 8 करोड़ 47 लाख एकड़ भू-भाग कृषि-योग्य है लेकिन सुविधाओं के अभाव में केवल 4 करोड़ एकड़ भू-भाग में ही कृषि की जाती है।

राजस्थान की कृषि-विषयक विशेषताएँ : कृषि के क्षेत्र में राजस्थान की कुछ अपनी विशेषतायें हैं जो अन्य राज्यों में नहीं पाई जाती हैं। ये विशेषतायें प्रमुखतः निम्नलिखित हैं

1. प्राकृतिक वातावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ राज्य की कृषि को बहुत बड़ी भीमा तक प्रभावित करती हैं। चूरु, बीकानेर, जंसेलमेर, बाड़मेर, निरोही, पाली, झुनझुनू एवं सीकर जिले राज्य के सूखे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा अत्यधिक कम होती है। दूसरी ओर अलवर, जयपुर, भरतपुर टोंक, मवाई माधोपुर, कोटा आदि जिले वर्षा की दृष्टि से सम्पन्न हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, दासवाड़ा, चित्तौड़ आदि जिले भी सूखे क्षेत्रों की अपेक्षा, वर्षा की दृष्टि से सम्पन्न कहे जा सकते हैं। फलस्वरूप कृषि के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र सम्पन्न हैं। राजस्थान के पश्चिमी मह व अर्द्ध मह क्षेत्रों में केवल 25 सेंटीमीटर औसत प्रति वर्ष पानी बरसता है, जबकि पूर्वी भाग के कई क्षेत्रों में वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर है।

उपयुक्तता पड़ती है। राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, टोंक, जयपुर, भीर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर व गगानगर के जिलों में ही लगभग 90% जौ की खेती होती है। राजस्थान में सन् 1971-72 में 456000 हेक्टर भूमि पर जौ की खेती की गई तथा 590000 टन जौ का उत्पादन हुआ।

5 गेहूँ गेहूँ की खेती के लिए उपजाऊ भूमि, वर्षा तथा सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे प्रायः अक्टूबर के मध्य से नवम्बर के मध्य तक बोया जाता है। दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसे अप्रैल के प्रारम्भ से लेकर मई के मध्य तक काट लिया जाता है। गेहूँ को बोते समय सर्वे जलवायु और काटते समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गगानगर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर व कोटा में गेहूँ की खेती की जाती है। कुल गेहूँ पैदा करने वाले कृषि क्षेत्र का 11% भाग गगानगर जिले में है। सन् 1971-72 में 1524000 हेक्टर भूमि पर गेहूँ बोया गया तथा 1904000 टन गेहूँ पैदा हुआ।

6 चना यह लगभग कुल कृषि क्षेत्र के 11.2% भाग पर अर्थात् 16 मि. हेक्टर क्षेत्र में बोया जाता है। इसे 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बोया जाता है तथा मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल के मध्य तक काटा जाता है। राज्य के चना पैदा करने वाले कुल भू-क्षेत्र का 3 भाग गगानगर जिले में है। गगानगर के अलावा चूरु, झुझनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर व अजमेर में भी चने की खेती की जाती है। झुझनू व बांसवाड़ा भी चने की खेती के लिए उपयुक्त हैं। राजस्थान में सन् 1971-72 में 1644000 हेक्टर भूमि पर चना बोया गया तथा 886000 टन चना पैदा हुआ।

7 चावल राजस्थान के कुछ भागों में चावल की भी खेती की जाती है। चावल की उपज के लिए पानी की अधिकता की आवश्यकता होती है। इसीलिए राज्य के उन भागों में, जहाँ या तो अधिक वर्षा होती है या सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, केवल चावल पैदा किया जाता है। झुझनू, बांसवाड़ा, उदयपुर, वूरी, कोटा व गगानगर जिलों में अधिक बोया जाता है। राजस्थान में चावल की खेती सन् 1971-72 में 133000 हेक्टर भूमि पर की गई तथा 159000 टन चावल पैदा हुआ।

8 दालें राजस्थान में चने को छोड़ कर बरहर, मूँग, उद, मोठ आदि लगभग 1.7 मि. हेक्टर भूमि पर अर्थात् कुल कृषि-क्षेत्र के 12.1% भाग पर बोई जाती है। यदि चने को भी गिना लिया जाए, तो राज्य के कुल कृषि भूमि के 1/5 भाग पर दालें पैदा की जाती हैं। जयपुर, झुझनू, भीर, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर

तथा चूर जिलों में कुल दाल उपजाने वाले क्षेत्र का 85% क्षेत्र पाया जाता है। सन् 1971-72 में जने ममन 3714000 हेक्टर भूमि पर दालें बोई गईं तथा 1319000 टन दाल पैदा की गई।

9 कपास - राजस्थान में लगभग 2,36,300 हेक्टर भूमि पर कपास उगाई जाती है जो कुल कृषि-क्षेत्र का 17% भाग है। मूल कपास उगाने वाले जिलों का 30% भाग अफ़्केने गगानगर जिले में तथा लगभग 25% भाग उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर व झालावाड़ में पाया जाता है। कपास बोने का कार्य अप्रैल से जून के मध्य तक तथा बुनने का काम सितम्बर के अंत से दिसम्बर के अंत तक चलता रहता है। कपास की राखी के लिए वर्षा अथवा सिंचाई के अन्य मासों की अत्यन्त आवश्यकता होती है। सन् 1971-72 में 33000 हेक्टर भूमि पर कपास बोई गई तथा 394000 गॉठ कपास का उत्पादन हुआ।

10 गन्ना - राज्य के जिन भागों में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ गन्ने की खेती की जाती है। यह परबरी से अजमेर तक बोया जाता है तथा नवम्बर से इसकी कटाई शुरू हो जाती है। राज्य के गन्ना उत्पादन क्षेत्र हैं - गगानगर, भरतपुर, मवाई माधोपुर, टोंक, कोटा तथा उदयपुर। सन् 1971-72 में 8000 एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती की गई 1203000 टन गन्ने का उत्पादन हुआ।

11 तिलहन - तिलहन में मूँगफली राजस्थान में मुख्यतः पैदा की जाती है। यह प्रति वर्ष 2 लाख हेक्टर भूमि में बोई जाती है तथा प्रति वर्ष लगभग 1 लाख टन से कुछ अधिक पैदा होती है। राज्य के जिन जिलों में मूँगफली पैदा की जाती है, वे हैं चित्तौड़, कोटा, झालावाड़ व मवाई माधोपुर। मूँगफली के अलावा राज्य के प्रायः सभी भागों में तिल उगाया जाता है। तिल का उत्पादन लगभग 6 लाख हेक्टर भूमि में किया जाता है और प्रति वर्ष लगभग 75 हजार टन तिल पैदा किया जाता है। इन दोनों फसलों के अलावा सरस, बलसी, तोरिया आदि भी राज्य के सभी भागों में तिलहन के रूप में पैदा किये जाते हैं। सन् 1971-72 में राजस्थान में 1348000 हेक्टर भूमि पर तिलहन उगाया गया तथा 387000 टन तिलहन पैदा हुआ।

राजस्थान में विभिन्न फसलों की पैदावार में भी दिग्गज कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सन् 1966-67 व 1967-68 के वर्षों में कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई, जैसा कि आगे दी गई तालिका से स्पष्ट है।

प्रमुख फसलों का उत्पादन (हजार टनो में)

उत्पादन	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
बाजरा	940	1229	1423	448	801	2676	1371
उवार	792	346	428	201	392	573	255
गेहूँ	785	872	1319	1175	1258	1951	1904
मक्का	642	614	1026	423	517	930	752
जौ	448	474	766	575	510	764	590
चावल	24	12	95	57	99	135	159
तिछहन	214	201	328	152	218	534	360
गन्ना	940	393	312	52	670	1230	1203
कपास ¹	165	184	226	172	119	229	394

1. कपास का उत्पादन हजार गँठों में दिया गया है। प्रत्येक गाँठ में सामान्यतः 180 स्त्रोणाम कपास होती है।

भूमि का उपयोग

(हजार हेक्टर में)

वर्गीकरण	1951-52	1951-52 म कुल भौगो लिक क्षत्रफल का प्रतिशत	1966-67	1966-67 म कुल भौगो लिक क्षत्रफल का प्रतिशत
कुल भौगोलिक क्षत्रफल	34280	100 00	34023	100 00
1 वन	1159	3 4	1145	3 4
2 कृषि के लिये प्राप्त	8980	26 2	6010	17 9
3 अन्य बिना बोया गया क्षत्र (चालू पट्ट के अतिरिक्त)	9003	26 3	8244	24 2
4 पट्ट	5825	17 0	4027	11 8
5 वास्तविक वासा गया क्षत्र	9313	27 1	14597	42 9
6 एक से अधिक बार बोया गया क्षत्र	442	1 3	249	~ 1
7 (5 + 6) - कुल बोया गया क्षत्र	9755	28 4	15446	45 4

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन 1966-67 में कुल भौगोलिक क्षत्रफल का 45.4% कुल बोया गया क्षत्र था जबकि 1951-52 में यह केवल 28.4% ही था। यह वषों में कृषि के लिए अप्राप्त भूमि की मात्रा में काफी कमी आयी है जिससे वास्तविक बोये गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो गयी है।

कृषिगत विकास की दर

1952-53 से सन 1964-65 की अवधि में राजस्थान में क्षेत्रफल की वृद्धि प्रतिवर्ष 2.9% रही जो भारत में सबसे अधिक थी। लेकिन इस राज्य के सम्बन्ध में एक चिन्ता का विषय यह रहा है कि इसमें उत्पादन में गिरावट आई है। इस अवधि में यह प्रतिवर्ष 0.11 प्रतिशत घटी है।

राजस्थान में इसी अवधि में खाद्यान्नों में उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर 2.42 प्रतिशत रही है और जनसंख्या की 2.68 प्रतिशत रही है। इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि की दर खाद्यान्नों की वृद्धि की दर से 0.26 प्रतिशत कम रही है।

कृषिगत विकास में नई नीति का उपयोग :

अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी कृषिगत विकास की नई नीति सन् 1965-66 में प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत पुने हुए क्षेत्रों में कृषिगत विकास के कार्यक्रम अपनाये जाये लगे। सऊर बाजरा, सऊर ज्वार, सऊर मक्का व मैक्किन गेहूँ के अन्तर्गत नया क्षेत्र हाथा जाये लगा। अधिक उपज देने वाली किस्मों का विस्तार सन् 1968-69 में लगभग 3 लाख हैक्टर पर कर दिया गया। सन् 1968-69 में रासायनिक खादों का उपयोग 1.50 लाख टन कर दिया गया। इसी प्रकार सिंचाई के विस्तार से खाद्यान्नों, कपास व तिलहन तथा गन्ने में उत्पादन की गई क्षमताएँ उत्पन्न की जा रही हैं। इसी के साथ गजपतन राज्य में भी हरित क्रांति प्रारम्भ हो गई है। इससे उत्पादन में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होने की आशा है।

राजस्थान में पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में : कृषि सम्बन्धी मसौ पर कुल 210.88 लाख रु०, अर्थात् कुल योजना का 81% भाग, व्यय किया गया था इस योजना के अन्तर्गत 7 हजार 50 कुओं का निर्माण किया गया था। एक हजार 'पशुधन गृहील' तथा 348 वस्त्रिग सेट लगाये गये थे। कृषि उपज को बढ़ावे के लिए 7 हजार 123 टन अमोनियम सल्फेट तथा 0.25 टन सुपर फॉस्फेट खाद तथा 9 हजार 142 टन उन्नत किस्म के बीजों का वितरण किया गया था। 290 लाख रु० की कीमत की फसलों के बीजों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। कृषि में यन्त्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 199 ट्रैक्टरों की खरीदने हेतु 14.1 लाख रु० उधार दिए गये थे। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण काम उठाये गये थे। कोटा में एक अनुसंधान क्षेत्र तथा सवाई माधोपुर व उदयपुर में दो बुनियादी पाठशालाएँ खोली गई थी। इन सब कार्यों के परिणामस्वरूप कृषि-उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई थी और राज्य साधान के मामले में अन्य राज्यों पर निर्भर रहने के बजाय आत्म-निर्भर हो गया था।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में : कृषि कार्यक्रमों के लिए 31555 लाख रु० के व्यय करने का प्रावधान किया गया था। सन् 1969-71 तक खाद्यान्नों में 21%, तिलहन में 60%, गन्ने में 149% तथा कपास में 82% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई जमिनो को खेती के अन्तर्गत लाने दोहरी फसल उगाने तथा गहरी कृषि को अपनाने के लिए सिंचाई, मृत्तुरक्षण, उन्नत बीज, उन्नत कृषि-यन्त्र, पोष-सुरक्षण आदि की विधियों पर बल दिया गया था। इस योजना काल में 38 बीजों के कार्य तथा 174 बीज-गोदाम बनाये गये थे, 16.75

साथ भूमि पर उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया था, 10 हजार 465 टन नाइट्रोजन की खाद तथा 2 हजार 540 टन फॉस्फेट की खाद 1960-61 में वितरित की गई थी। इसी वर्ष 13.35 लाख टन कम्पोस्ट की खाद भी बांटी गई थी। 41 लाख हेक्टर भूमि पर हरी खाद का प्रयोग किया गया था। 20 हजार कृषि-यन्त्रों का भी वितरण किया गया था। 11.47 लाख हेक्टर भूमि पर पीछे की सुरक्षा प्रणाली की गई थी तथा नवम्बर सन् 1960 से राज्य के पाकी जिले में 'पैकेज कार्यक्रम' चालू किया गया था। इस योजना में कृषि-विषयक प्रशिक्षण एवं शिक्षा का भी विस्तार किया गया था।

4.05 लाख हेक्टर भूमि पर दोहरी फसलों की खेती की जाती थी। 45 लाख हेक्टर नई जमीन कृषि के अन्तर्गत लाई गई थी तथा 7.9 लाख हेक्टर भूमि में चकन्दों की गई थी। राज्य में 319.57 लाख रु० कृषि-कार्यों पर व्यय किये थे। इस योजना के अन्तर्गत साधान, कपास, गन्ना व तिलहन के उत्पादन के लक्ष्य 11.30 लाख टन, 60 लाख गैलन, 27 लाख टन तथा 64 लाख टन की वृद्धि हुई थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि-कार्यों पर 639.35 लाख रुपया व्यय दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत कृषि-उत्पादन में 32% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में न केवल 3 वर्षों में अनाज की स्थिति रहने के कारण इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो गया। योजना अवधि में साधानों में केवल 11.97 लाख टन की ही वृद्धि हुई। कपास, गन्ना तथा तिलहन में भी क्रमशः 1.46 लाख गैलन, 61 लाख टन तथा 4.9 लाख टन की ही वृद्धि हुई, जबकि साधानों, कपास, तिलहन व गन्ना के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य क्रमशः 16.26 लाख टन, 1.52 लाख गैलन, 1.12 लाख टन तथा 9.1 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तृतीय योजना के अन्तर्गत 51.30 लाख हेक्टर भूमि तक पीछे की सुरक्षा प्रणाली की गई। उन्नत बीज एवं यन्त्रों का भी वितरण किया गया। 1.69 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई गई तथा 4.20 लाख हेक्टर भूमि पर चकन्दों के उद्योगों की सुविधाओं का विस्तार दिया गया। 11.72 लाख हेक्टर भूमि पर चकन्दों की गयी। कृषि मध्यम स्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं का भी विस्तार किया गया। कृषि-क्षेत्रों में निचाई, खाद, भू-सुरक्षण आदि सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

तीन वार्षिक योजनाएं एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना :

राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पहले 43.4 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गयी थी और अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य रखे गये थे। 17 लाख टन साधान, 1.62 लाख टन तिलहन, 8.55 लाख टन गन्ना और 1.97 लाख टन

पाट नपास। लेकिन विदेशी सहायता की अनिश्चयता के कारण योजना स्थगित हो गयी और 1966-67 से 1968-69 तक की अवधि में केवल वार्षिक योजनाएँ ही बनाई गईं, बिनाका न्योरा निम्न तालिका में दिया जा रहा है

राजस्थान में योजनामार्गत धन्य (1966-69)

(लाख रु में)

क्षेत्र	1966-67	1947-68	1968-69	कुल धन्य
कृषि कार्यक्रम	265.47	594.91	551.15	2011.53
सहकारिता एवं सामुदायिक विकास	74.33	147.47	115.26	508.06
मिनाई एवं विद्युत्	2943.83	2286.86	3023.88	8254.57
योग	4054.63	3029.24	3690.29	10774.16

वार्षिक योजनाओं में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम लागू किए गए, जिनमें चक्य बी, प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार, कृषि इमेन्सलाओं का विकास, धरौक की कमली में न्यार, मक्का, धानरा और ताईचु म धान तथा रबी की कमल में मैक्सिमम गत की अधिक पैदावार देने वाली किम्पों का प्रचलन शामिल था। इसके अतिरिक्त राजस्थान महूर पोम बाँध आदि जैसी सिचाई की छोटी और बड़ी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया। इन उपायों से 1966-67 में उत्पादन क्षमता में वृद्धि 7 म प्रचार रही—साधान 52 हजार मीट्रिक टन निरहुन 4 हजार टन, पचाग 19 हजार गांठे और गन्ना 3 लाख टन। दमा अवधि में 4 69 लाख हैक्टर अतिरिक्त जमीन में मिचाई की भी व्यवस्था हुई। 1966-67 में 42,500 एकड़ जमीन में अधिक उपज देने वाले बीन बोए गए और 24 3 हजार हेक्टर भूमि की चक्य बी पूरी की गयी। 1967-68 में उत्पादन क्षमता में वृद्धि इस प्रकार रही—साधान 2 08 लाख मीट्रिक टन निरहुन 9 हजार मीट्रिक टन, गन्ना 5 हजार मीट्रिक टन और पचाग 13 हजार गांठे। अधिक उपज देने वाले बीजों की गुजार्ई का धन बड़ा कर 4 10 लाख एकड़ ही गया। 1968-69 की वार्षिक योजना में अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य जेष्ठ रखल गये हैं परन्तु अकाल की स्थिति के कारण उनके पूरे होने में बाधा है।

बीसी योजना के निर्देशपर में योजना आयाय ने गुजारा दिया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की न्यूनतम मिथ्य दर 3 प्रतिशत सालाना रखी जाए। राज्य सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, वे आधे से गेई तालिका में दिए गये हैं—

**कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण तथ्य
वृद्धि की दर**

फसल	आधार वर्ष का उत्पादन	प्रतिवर्ष	चौथी योजना	चौथी योजना में अनिश्चित उत्पादन	चौथी योजना के अन्त में वृत्त उत्पादन
	(लाख टन)	(प्रतिवर्ष)	(प्रतिवर्ष)	(लाख टन)	(लाख टन)
खाद्यान्न	64 30	6	32 60	21 00	83.30
तिलहन	3 30	9	48 40	1 60	4.20
गन्ना	21 50	6	33 00	7 10	28.60
	लाख गाँठें			लाख बर्तें	लाख गाँठें
कपास	4 00	8 5	50 00	2 00	6.00

विभिन्न शाखान्तों और व्यापारिक पक्षों की उपरोक्त वृद्धि दरों की प्राप्ति ■ लिए कृषि कार्यक्रमों के वास्ते 24 03 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं। चौथी योजना में पैदावार बढ़ाने वाले वस्तुओं के प्रमुख लक्ष्य निम्न तालिका में दिये जा रहे हैं

कार्यक्रम	लक्ष्य
अधिक उपज वाले बीजों की बुआई	45 00 लाख एकड़
उर्वरकों की खपत का स्तर	9 65 लाख टन
पौध संरक्षण उपाय जहाँ किये गये	125 00 लाख एकड़
भू संरक्षण	5 00 लाख एकड़

निर्धोजन के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में उपलब्धियाँ—

तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास और सिंचाई पर कुल मिला कर 202,74 करोड़ रुपये (कुल वास्तविक व्यय का 54 90 प्रतिशत) खर्च हुए। इसके परिणामस्वरूप तीनों योजनाओं में कृषि विकास की उपलब्धियाँ इस प्रकार रही—

(क) खाद्यान्न की वितरित उत्पादन क्षमता लगभग 26 36 लाख टन बढ़ी है।

(ख) राजस्थान की राष्ट्रीय धाम में कृषि तथा उससे सम्बद्ध गतिविधियों का योगदान जो 1954-55 में 40 12 प्रतिशत था, 1965-66 में बढ़कर 46 92 प्रतिशत हो गया।

(ग) 1950-51 में 15.72 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो रही थी, जबकि 1965-66 में 30.80 लाख हेक्टर की होने लगी। इसी तरह कुल कृषि भूमि के मुकाबले सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 9 से बढ़कर 13 हो गया।

(घ) 18.71 लाख हेक्टर से अधिक भूमि में चक्रवर्ती का काम पूरा हो गया।

1966-67 और 1967-68 की वार्षिक योजनाओं में खेती, सहकारिता और सामुदायिक विकास पर 17.6 करोड़ रुपये तथा सिंचाई और बिजली पर 52.3 करोड़ रुपये खर्च हुए। 1968-69 में इन क्षेत्रों के लिए क्रमशः 6.28 करोड़ और 21.19 करोड़ रुपये रखे गये थे।

विकलताएँ —

इस प्रगति के बावजूद, कृषि में क्षेत्र में हमें अपनी विकलता दो दृष्टियों से स्वीकार करनी होगी।

(1) राजस्थान 15 साल के आयोजन के बावजूद, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। खाद्यान्न का अभाव बराबर बना हुआ है और भारत के बचत वाले राज्यों और विदेशों से खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर रहना पड़ा है। यह देखते हुए कि आबादी का काफी बड़ा भाग खेती में लगा हुआ है, अभाव की स्थिति एक विडम्वना प्रतीत होती है। यह स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है —

वर्ष	अनुमानित आबादी (लाख में)	खाद्यान्नों की कुल अनुमानित आवश्यकता (लाख टनो में)	वास्तविक उत्पादन (लाख टनो में)	(+) बचत या (-) कमी
1961-62	205.1	49.86	54.61	(+) 6.75
1962-63	228.7	50.54	50.48	(-) 0.06
1963-64	232.4	51.28	40.11	(-) 11.17
1964-65	216.2	52.07	53.08	(+) 1.01
1965-66	220.4	52.91	37.77	(-) 15.14
1966-67	224.3	53.71	42.55	(-) 11.16

(2) राजस्थान में मुख्य फसलों की पैदावार राष्ट्रीय स्तर से केवल नीचे ही नहीं है, बल्कि विश्व के लगभग देशों में होने वाली प्रति हेक्टर पैदावार की एक औसत से पछमास भर है। कृषि भूमि के अनुपात में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल भी अखिल भारतीय स्तर से कम है।

इस निराशाजनक स्थिति में कारण ये हैं — कृषि वर्षा पर निर्भर, मशीनों से होने वाली खेती लोकप्रिय नहीं है। सरचनात्मक और संगठनात्मक कमियाँ हैं तथा कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाएँ अपूर्वाप्त हैं।

सुझाव :

चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार कृषि विकास कार्यक्रम पर निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखते हुए पुनः विचार करें, ताकि वांछित विकास की गति प्राप्त की जा सके :

(1) राज्य में कृषि विभाग को चाहिए कि वह उदयपुर विद्वत्विद्यालय के कृषि सहाय के सहयोग से खेती के तरीकों, अधिक उपज देने वाले नये पौधों की बीजों और रोगों से बचाने के उपायों, जल व्यवस्था की विधियों, मक्खन विधियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित कृषि अनुसंधान कार्य को बढ़ाये । इस अनुसंधान कार्य से खेती के प्रकार से प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में सहायता मिल सकती है । कृषि के और-और तरीकों में परिवर्तन से अधिक सफल विस्तार सेवा की मांग होगी । इसे सम्भव बनाने के लिए राज्य सरकार को जिस पर पर्याप्त धन खर्च करना चाहिए, जिससे कृषि अनुसंधान कार्य और विस्तार सेवा के लिए प्रशिक्षित लोग मिलते रहें ।

(2) राज्य की योजना बनाने वाले अधिकारियों को चाहिए वे पैदावार बढ़ाने वाली कुछ आवश्यकताएँ जैसे अधिक उपज बढ़ाने वाले बीज, आधुनिक रसायनिक खाद, निपाई से लिए बर्बाद पानी की व्यवस्था, पौधों को रोगों और कीड़ों से मुक्त रखने के लिए बीटनाशक दवाएँ प्राप्त करें । सबसे बड़ी बात यह है कि खेती के मुद्दे हुए गाज-समान और ट्रैक्टर आदि मशीनों किसानों की ओर अधिक, सस्ते में उपलब्ध कराई जाय, जिनसे वे बड़े पैमाने पर मशीनों से खेती हो सके । राजस्थान सरकार को खेती में मान्यता, मुफ्त उपकरण, रूट और डबलरो आदि के उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए । उन उद्योगों का एक काम यह होना कि औद्योगिक, आधार व्यापक होगा, य मशीनों की बरोबरवागी घटती और रोगों की गांधी से सड़क की ओर जाने की दान कम होगी ।

खेतिहरों को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में गजस्थान में कृषि विभाग, जिसका बटन उल्टा ही किया जाने वाला है, और सामाजिक विकास के आधीन वर्गज्य बैंक हमारे किसानों के सीमित साधनों को बढ़ाने में बहुत सहायक हो सकते हैं ।

हमारी दृष्टि में यदि राजस्थान में कृषि विकास को योजना बनाते समय संपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखा जाय तो सरकार के लिए विकास की प्रस्तावित वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होगा । इस प्रकार इस नयी राह राज्य को दृढ़त वाला राज्य बनाया जा सकता है ।

राजस्थान में उद्योग

(Industries in Rajasthan)

राजस्थान में उद्योग (Industries in Rajasthan) राजस्थान भारत-वर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य है। यद्यपि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल व विभिन्न खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और यहाँ के उद्योगपति अपनी योग्यता के लिए विख्यात हैं, तथापि इन विशेषताओं के उपरान्त भी राजस्थान एकीकरण के समय औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय राज्य में बहुत कम दंड पैमाने के उद्योग थे। सत सूती कपड़ों की मिलों के अतिरिक्त राज्य का एकमात्र मुख्य उद्योग लाखेरी में सीमेन्ट का ही था। इस प्रकार राज्य में बड़े पैमाने के उद्योग प्रायः नागण्य ही थे। सन् 1949 तक राज्य के समस्त कच्चे माल को अन्य राज्यों के कारखानों के लिए भजा जाता था तथा अन्य राज्यों से बचा हुआ माल ममाया जाता था। राज्य की औद्योगिक क्षमता का न तो पता लगाया गया था और न राज्य के औद्योगिक विकास के लिये कोई ठोस कदम ही उठाये गये थे। राज्य के औद्योगिक विकास के लिये बड़े व छोटे, उद्योगों का प्रथम बार उचित रीति से सर्वेक्षण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया जा सका। इस प्रकार राज्य के औद्योगिक विकास का श्रीगणेश उस समय हुआ, जबकि अन्य राज्यों में उद्योग अपनी स्थिति काफी मजबूत कर चुके थे।

राजस्थान के प्रमुख उद्योग राज्य के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन राज्य के औद्योगिक विकास की स्थिति के ज्ञान के लिए परमावश्यक है। अतः अब हम राज्य के कुछ उद्योगों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं

1. सूती वस्त्र उद्योग :

राज्य के उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस उद्योग के विकास के लिये कच्चे माल के रूप में कपास की आवश्यकता होती है सोभाय-

यथा राजस्थान में छोटे व मध्यम रेखे वाली कपास की पर्याप्त होती है। लम्बी रेखा वाली कपास के उत्पादन के लिये भी प्रयास जारी है तथा देश के अन्य भागों से भी कपास प्राप्त की जा रही है। सस्ते धमिकों की पूर्ति भी आवश्यक सहाय्य से संपन्न है। आम-याम के क्षेत्र के स्त्री-पुरुष जापानी सब काम मजदूरी पर काम करने के लिए कारखानों में जा जाते हैं। अविद्याज कारखानों में धमिक के सामान के रूप में कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बाहर से भगा कर पूरा किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग व विकास के लिये विस्तृत बाजार की भी सुविधा की जरूरत होती है। राज्य की विशालता, इस उद्योग को बाजार सम्बन्धी बट्टियादों से भी मुक्त रखती है। जहाँ तक जलवायु का प्रश्न है साजबज सूती वस्त्र उद्योग के केन्द्रित होने में यह बाधा महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि कुश्मिड़ इन में जलवायु की उद्योगों के विकास के अनुकूल बनाया जा सकता है। जिन स्थानों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किया जा रहा है, उन्हें सस्ती भूमि व अन्य सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्राप्त हैं।

सीमरी योजना के तहत में राज्य में 17 सूती मिलें थी, जिन में 3,09,456 तन का उत्पादन हुआ। इन कारखानों के अनिश्चित राज्य में अन्य कई कारखानों की खोलने की स्वीकृति भी राज्य सरकार को दी जा चुकी है। जयपुर, खजूरपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, विजय नगर, कोटा, गजानगर में एक-एक सूती मिलें हैं। भीलवाड़ा और व्यावर में 3-3 सूती मिलें सूती वस्त्र उत्पादन में लगी हुई हैं। इन नगरों के अलावा झुगरपुर, हुसैनगढ़, मुसम्, जोधपुर, मोहर, बिस्ती, जलसर, पोलपुर में भी सूती कारखाना की योजना चलाने जा रहे हैं। सन् 1970 में सूती वस्त्र का उत्पादन 647 लाख मीटर व मूल्य का उत्पादन 334 लाख करोड़पाव हुआ। सन् 1971 व 1972 में सूती वस्त्र का उत्पादन क्रमशः 549 व 497 लाख मीटर तथा मूल्य का उत्पादन 290 व 266 लाख करोड़पाव हुआ। इस उद्योग का वार्षिक मूल्य की निरन्तर वृद्धि होती रही इसलिए राज्य सरकार ने ग्वालनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ जिलों में सूती की सुविधाओं का विस्तार करके कपास के उत्पादन वृद्धि का प्रोत्साहित किया है। सन् 1971-72 में राजस्थान में 3,94,000 गाँव कपास का उत्पादन हुआ।

राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी अपनी शैशव अवस्था में है। सूती वस्त्र उद्योग के सामने निम्न समस्याएँ हैं (1) राज्य में केवल देश के कुल धमिकों का 1.4% भाग ही पाया जाता है, जबकि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में क्रमशः 21.3, 26.4 व 29.2% तक पहुँच जाते हैं। इसके प्रकार राज्य में देश के कुल धमिकों की सहाय्य का केवल 1.4% भाग ही पाया जाता है, जबकि इन राज्यों में धमिकों की सहाय्य क्रमशः 26.3, 39.39 व 39.7 है। राज्य में केवल 6 बड़ी सूती मिलें हैं। अन्य मिलों का बाजार छोटा है।

(2) राज्य की अधिकांश पुरानी मिलों में मशीनें घिस चुकी हैं तथा पुरानी किस्म की हैं। इनकी उत्पादन क्षमता कम है।

(3) सूती कपड़ की मिलों को चलाने के लिए राजस्थान में कोयले की कमी तो है ही, साथ ही विद्युत बलिन का भी अभाव पाया जाता है।

(4) आगे दिन हड़तालों के कारण राज्य के सूती कपड़ों के मिलों के उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती रहती है।

(5) राज्य में पैदा होने वाली कपास छोटे रेडो वाली एवं बटिया किस्म की है।

(6) कच्चा माल की दृष्टि से भी राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। राज्य में केवल कपास की 18-19 लाख मटि ही पैदा होती हैं, जो राज्य के सूती वस्त्र उद्योग के विकास को देखते हुए अपर्याप्त है। पारखानों की स्थिति की दृष्टि से भी सूती वस्त्र उद्योग का विचार अनुकूलतम परिस्थितियों को ध्यान में रख कर नहीं किया गया है। जिस क्षेत्रों में कपास का उत्पादन किया जाता है या कपास के उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना है, उन क्षेत्रों में से कई क्षेत्रों में अभी तक सूती मिलें स्थापित नहीं की गयी हैं।

सुझाव राज्य में सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए नीम्नाति-
 शास्त्र कई कदम उठाये जाने चाहियें, यथा (i) उत्तम कोटि की कपास को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। (ii) उद्योगों में लिए सस्ते व्यक्ति में साधन अर्थात् सस्ती बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए। (iii) पुरानी मिलों में असीमबीकरण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 5 करोड़ रु० की पूंजी से राज्य द्वारा प्रस्तावित राज्य निगम बहुव्यपूर्ण योगदान दे सकता है। (iv) राज्य में काते जाने वाले सूत की क्षमता के लिए सूती वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित अन्य सहायक उद्योग जैसे होजरी उद्योग का विकास किया जाना चाहिए। (v) राज्य सरकार को उद्योग के विकास के लिए उदारतापूर्ण अर्थात् व मुक्तिपूर्ण दी जानी चाहिये, ताकि राज्य के प्रमुख उद्योगपति राज्य के औद्योगिक विकास के प्रति आकर्षित हो सकें। (vi) राज्य में औद्योगिक शक्ति की स्थापना के लिए राज्य सरकार, उद्योगपतियों एवं श्रमिक मजदूरों को मिल कर प्रयास करना चाहिए।

2. चीनी उद्योग

राजस्थान में भी गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। गन्ने के अतिरिक्त इस उद्योग के लिए ईंधन, चूने के पत्थर व सल्फर की आवश्यकता होती है। सामान्यतः गन्ने के बजन का 9 से 12% भाग चीनी के रूप में प्राप्त होता है। राजस्थान में उदयपुर, भरतपुर, भोलवाडा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जालावाडा, कोटा, मयानगर, सवाई माधोपुर तथा टोंक में मुख्यतः गन्ने की खेती की जाती है। राज्य के सम्पूर्ण गन्ने

का उत्पादन एवं निहाड केवल उदयपुर व भरतपुर जिलों में पैदा किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन, अर्थात् 17%, बगानगर में किया जाता है। इस समय राज्य में चीनी उद्योग भोलवाहा, बगानगर, भोपाल सागर (उदयपुर) तथा विजय नगर (अजमेर) में केन्द्रित है।

तृतीय योजना के अन्त में राज्य में दो छोटी मिलें बगानगर व भोपाल सागर में चल रही थी। इनकी वार्षिक क्षमता क्रमशः 1 हजार मीट्रिक टन एवं 8 हजार मीट्रिक टन है। तृतीय योजना के अन्त में चीनी का उत्पादन 13 हजार मीट्रिक टन था। सन् 1966 ई० में राजस्थान में चीनी का उत्पादन 18 हजार मीट्रिक टन हुआ। सन् 1970 में 28.5 हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ। सन् 1971 व 1972 में चीनी का उत्पादन क्रमशः 11 हजार व 10 हजार टन हुआ। मिथाइ की सुविधाओं के बिनागर के साथ-साथ गन्ने की फसल में सुधार एवं बढ़ि होनी आ रही है। राज्य के बगानगर, बगहा भाघोपुर, बूंदी, कोटा एवं भरतपुर जिलों में और अधिक चीनी मिलें स्थापित किये जाने से मुम्बईसर राज्य में विद्यमान है। बूंदी जिल में कैलाशराय पाटन नामक स्थान पर सहकारिता के आधार पर निकट भविष्य में एक चीनी फैक्ट्री स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

राजस्थान की जलवायु एवं मिट्टी होने की वजह से लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। मिथाइ की सुविधाओं का अभाव तथा जमीनी कमी के कारण गन्ने के उत्पादन को नहीं बढ़ने दत। राजस्थान में गन्ने की किराई भी अच्छी नहीं है। सन् 1961-62 में राजस्थान में गन्ने का उत्पादन 8.1 लाख टन था, जबकि 1963-66 व 1969-70 में इसका उत्पादन क्रमशः 5.4 व 6.7 लाख हुआ। बगानगर व भोपाल सागर की मिलों में गन्ने में प्रत्यक्ष हानि वाली चीनी की मात्रा क्रमशः 9.66 व 9.8% है। गन्ना बढ़ती हानि व कारण तथा सूख के कारण चीनी कारखानों की स्थापना गन्ने उत्पादन क्षेत्र में ही सम्भव रहती है। राजस्थान में चीनी उद्योग के विकास की सम्भावनाएं पर्याप्त हैं। चीनी की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। मिथाइ की सुविधाओं व बिस्तार के साथ साथ गन्ने की खेती का भी विस्तार हो रहा है। जल आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में या तो अतिसान चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाय अथवा पूर्वी गंगा उत्पादक क्षेत्रों में जैसे भरतपुर व बूंदी में चीनी उत्पादन की नई मिलें खोली जाय। पूर्वी क्षेत्रों में ही 20 से 30 टन गन्ना घेरन की क्षमता वाले, चीनी उद्योग के लघु स्तरीय कारखानों को भी विकसित किया जाना चाहिए।

3 सीमेण्ट उद्योग

सीमेण्ट उद्योग आधारभूत उद्योगों में प्रथम स्थान रखता है। सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए सीमेण्ट की आवश्यकता पड़ती है। देश के औद्योगिक विकास

के साथ-साथ इस उद्योग के विकास की भी आवश्यकता है। इस उद्योग के लिये कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर (Limestone) व सडिया (Gypsum) की मुख्यतः आवश्यकता पडती है। कच्चे माल को सीमेण्ट में परिणत करने के लिए शक्ति के साधन के रूप में कोयले की भी आवश्यकता पडती है। चूने के पत्थर व सडिया को एक निश्चित अनुपात में मिला कर 2400° फारेनहाइट से 3000° फारेनहाइट ताप भाग तक गर्म किया जाता है। सामान्यतः एक बैरल (Barrel) सीमेण्ट बनाने के लिए 120 घण्ट कोयले की आवश्यकता पडती है तथा 2 टन कच्चे माल के प्रयोग से 1 टन सीमेण्ट प्राप्त की जा सकती है।

राजस्थान में इस समय सीमेण्ट के तीन कारखाने हैं। एक सवाई माधोपुर में है, दूसरा साखेरी (खूदी) में तथा तीसरा चित्तौडगढ़ में। सवाई माधोपुर का सीमेण्ट का कारखाना देश का ही नहीं अपितु समस्त एशिया का सबसे बड़ा सीमेण्ट का कारखाना है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 8.49 लाख मेट्रिक टन है। साखेरी के सीमेण्ट के कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.52 लाख मेट्रिक टन है। सन् 1966 ई० में राज्य में 11.24 लाख टन सीमेण्ट का उत्पादन किया गया। सन् 1965 ई० में सीमेण्ट का उत्पादन 11.48 लाख टन था। तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में चित्तौडगढ़ में सीमेण्ट का तीसरा कारखाना प्रारम्भ किया गया। सन् 1972 में राज्य में 16.14 लाख टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ।

सीमेण्ट उद्योग की समस्याएँ राज्य के सीमेण्ट उद्योग को विन्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड रहा है :

- (1) उद्योग को यथेष्ट मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है। राज्य में तो कोयले का उत्पादन कम है, बाहर से भी परिवहन खर्च अधिक एवं अंगणों की कमी की समस्या के कारण कोयला पर्याप्त मात्रा में उद्योग का नहीं मिल पा रहा है;
- (2) इस उद्योग को उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता है, जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;
- (3) उद्योग में काम करने के लिए कुशल श्रमियों का अभाव है। श्रमिकों को उद्योग में सम्मग्नित प्रशिक्षण दिलाने की सुविधाएँ भी नहीं हैं;
- (4) उद्योग में लाभ का प्रतिशत कम है, अतः बाह्य पूँजी इस उद्योग की ओर आकर्षित नहीं हो पाती;
- (5) साखेरी के कारखाने की मशीनें पुरानी पड चुकी हैं, जिनके नवीनीकरण की समस्या है;
- (6) राज्य में इस उद्योग पर सरकारी हस्तक्षेप इसके स्वतन्त्र रूप से नहीं चलने देता। सरकार की वितरण व मूल्यों सम्बन्धी नीति समय समय पर बदलते रहने के कारण उद्योग में प्रायः अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है।

4 शीशा उद्योग

राजस्थान शीश की रेत के लिए काफी प्रसिद्ध है। शीश की रेत को प्रचुर उपलब्धि से लाभ उठाने के लिए राज्य में शीशों के उद्योग का विकास किया जा रहा है। इस समय राज्य में शीशों के दो कारखाने हैं, जो भरतपुर जिले के पोलपुर नगर में स्थापित किये गये हैं। सारा एच मणिक, मेकनीज, ऑक्साइड आदि कच्चे माल की आवश्यकता इस उद्योग को पड़ती है, जो प्रायः पोलपुर के निकट ही उपलब्ध है। कच्चे माल की शुद्धता एवं कोयले की उपलब्धि भी इस उद्योग के लिए आवश्यक है। कोयले की पूर्ति प्रायः मध्य प्रदेश व बिहार से मंगा कर की जाती है। पोलपुर के कारखाने में शीशों की दोस्तलै बैलानिक ऊकरण, प्लास्म व अन्य विविध प्रकार की शीश की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मन् 1965 व 1966 ई० में राज्य में क्रमशः 3,86,000 व 2,88,000 टन शीशों का निर्माण किया गया।

5 नमक उद्योग

राज्य के बड़े उद्योगों में नमक उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साधारण रेश में पैदा होने वाले नमक का लगभग 100% भाग राजस्थान में ही पैदा किया जाता है। सागर, डीडवाना, और बचमदा सोल नमक उद्योग के लिए, राज्य में प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त पलौड़ी, कुआसन, पोकरण, एवं सुझानगड क्षेत्रों से भी नमक बनाया जाता है। मन् 1965, 1966 व 1972 ई० में राज्य में नमक का उत्पादन क्रमशः 544.7, 410.8 व 564.5 हजार टन हुआ था।

6 उर्वरक उद्योग

कृषि विकास के लिए रासायनिक उर्वरकों की मांग की पूर्ति के लिए कोटा में एक पारंपारिक सोला गया है। इस कारखाने की प्रति वर्ष लगभग 221285 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उत्पन्न करने की क्षमता है। मन् 1971 व 1972 में क्रमशः 259583 व 254014 मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन हुआ।

7 ऊन उद्योग

राजस्थान उत्तम कौटि के ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में लगभग 7.5 मिलियन मर्चे बाई जाती हैं, जिनमें प्रति वर्ष लगभग 29 मिलियन पाउण्ड ऊन प्राप्त होती है। राज्य के दुग्धू, चोखेर, जिले, अलाहाबादपुर, धूलू व नागौर के कुछ भागों में उत्तम कौटि की ऊन प्राप्त की जाती है। बीकानेर, गजानगर, ओचपुर, जलपुर, भरतपुर, सर्वाई माधोपुर व जयपुर जिले के क्षेत्र में उत्तम व मध्यम किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। टोंक व कोटा में मध्यम व घटिया किस्म की तथा उदयपुर जिले में अल्पिक घटिया किस्म की ऊन बाई जाती है। राज्य में पाई

जाने वाली अधिकांश ऊन कालीन बनाने के काम में जाती है तथा अन्य राज्यों को भेज दी जाती है। ऊन से कुछ अन्य सामान जैसे भफ़लर, कम्बल, जर्सी आदि राज्य में घनाये जाते हैं। सन् 1968-69 व 1969-70 में क्रमशः 15 60 व 18 70 लाख बगं भींदर ऊन प्राप्त की गई।

8 खनिज पर आधारित उद्योग

भारतवर्ष की जस्ता, जिंक, एमरेल्ड एवं मनाइस की वृत्ति अधिकतर राजस्थान से ही होती है। जिप्सम, सोपस्टोन आदि के भण्डार भी राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उदयपुर के समीप देवारी नामक स्थान पर एक जिंक स्मेल्टर समन की स्थापना की गयी है। कारखाना प्रतिदिन दो हजार टन के लगभग चूरा तथा 18 हजार टन सैल्फ़र साइडिक जिंक के उत्पादन की क्षमता रखता है। खतडी में ताम्र के विशाल भण्डारों का बहुप्रयोग करने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में एक विशाल कारखाने की स्थापना की है।

9 ग्राम्य उद्योग

उपयुक्त उद्योगों के अलावा राज्य में प्रयोगशाला यन्त्र, स्विच बोर्ड जोशार, टैक्सी मोटर, गृह कार्य हेतु विद्युत एवं पानी के मोटर, हाईटैण्डलो टैन्क इ. छुलेटर्स तथा जी० आई० थार० के बस्त्र बनाने के कारखाने भी राज्य में प्रारम्भ हो चुके हैं। कोटा में कृत्रिम वारीवाइज माइलिंग तथा रेबन के कारखाने स्थापित किये गये हैं। ये सभी कारखाने निजी क्षेत्र में सरकारी सहायक व सहयोग से चलाये जा रहे हैं।

1951 से सन् 1972 की अवधि में राज्य में विभिन्न उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है, जिसका परिचय निम्नलिखित तालिका से लग जाता है

प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि

वस्तु का नाम	इकाई	1951	1966	1968	1970	1971	1972
1 सीमेण्ट	हजार मीट्रिक टन	258	1124	1346	1392	5 1398	8 1614
2 चीनी	हजार मीट्रिक टन	1	5	18	6	18	5 11
3 सूती वस्त्र	लाख मीटर	301	625	535	647	549	497
4 सूत	लाख किलोग्राम	120	345	306	334	290	266
5 बालविपरीण	लाख मस्था	—	56	60	71	7	72 6
6 बिजली के मोटर	हजारों में	—	170	298	556	5 491	4 380

1965 में राजस्थान में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 765 कारखानों में सूचना दी। इनमें 63 करोड़ रु० की उत्पादन पूंजी लगो हुई है और औसत दैनिक रोजगार 72283 व्यक्तियों को मिला हुआ था। कुछ उत्पादों का मूल्य 47 करोड़ रु० था।

राजस्थान में औद्योगिक विद्युद्देयन के कारण

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य के चेलावादी क्षेत्र के अनेक सहस्रो उद्योगपति, देश के कोने-कोने में फँसे हुए हैं और उम्होने इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परन्तु यह एक अद्भुत विडम्बना ही है कि इन उद्योगपतियों द्वारा राज्य का औद्योगिक विकास नहीं किया जा सका। राज्य के औद्योगिक विकास के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ जो राज्य की इस पिछड़ी हुई औद्योगिक स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं :

(1) सिंचाई के साधनों का अभाव राज्य का अधिकतर भाग रेतीला एवं सूखा है। वर्षा की अनियमितता, अवर्षावृत्तता और अनिश्चितता के कारण कृषि विकास नहीं हो पाया है। एवं अध्ययन के अनुसार सन् 1949 से अब तक केवल सन् 1960 के अलावा कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है, जबकि राज्य के कुछ क्षेत्रों को सूखा और अभाव प्रस्तुत क्षेत्र घोषित नहीं किये गये हैं और सरकार की राहत कार्यों पर खर्च नहीं करना पड़ा हो। जैसलमेर जैसे शहर में सात वर्षों की आयु के बच्चों में यह नहीं देखा कि वर्षा कैसे होती है ? तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बावजूद भी विविध क्षेत्र बहुत कम हैं। आज भी कुल कृषि क्षेत्र का केवल 15% भाग ही सिंचाई के अन्तर्गत आ पाया है।

सन् 1968-1969 के अकाल ने राजस्थान की संपूर्ण ग्राम-व्यवस्था को झटकोर दिया। पिछले 17 वर्षों में इतना बुरा अकाल नहीं पड़ा। इन अकाल से लगभग डेढ़ करोड़ आबादी तथा बीस लाख पशु प्रभावित हुए हैं। राजस्थान का आर्थिक विकास उसी समय सम्भव होगा, जबकि सिंचाई व जल पूर्ति की व्यवस्था ॥ पर्याप्त सुधार हो जायेगा।

(2) शक्ति के साधनों की अपर्याप्तता : राज्य में कोयला एवं जल विद्युत का प्रयोग सम्भारण्यः शक्ति के साधनों के रूप में किया जाता है। कोयले की कमी के अभाव में इसे विहार राज्य से कोयला मगाना पड़ता है जो काफी महंगा पड़ता है। कोयला और विद्युत शक्ति के अभाव में औद्योगीकरण सम्भव नहीं है। यद्यपि यत कुछ वर्षों में जल विद्युत शक्ति के विकास की दिशा में कुछ प्रगति हुई है, तथापि राज्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप जल शक्ति उपलब्ध नहीं है।

(3) परिवहन साधनों का अभाव : यहाँ एक लाख की आबादी पर राटकों की कुल सड़वाई लगभग 150 मील है जो पर्याप्त नहीं है। परिवहन के साधनों के अभाव में कृषि, उद्योग, व्यापार तथा खनिजों का विकास नहीं होने पाया है। रेलों भी राज्य में कम हैं। बासवाड़ा जिले के तो किसी भी भाग में रेल नहीं पहुँची है।

(4) कच्चे माल का अभाव : राजस्थान का अधिकांश भू-भाग मरुस्थल है, जिसमें कपास, तिलहन, गन्ना आदि व्यापारिक फसलें नहीं उगाई जा सकती। कुछ क्षेत्रों में जहाँ वर्षा हो जाती है या सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, व्यापारिक फसलें होती हैं; परन्तु राज्य के औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं की देखते हुये इनका योगदान बहुत कम है। फलस्वरूप कच्चे माल के अभाव के कारण औद्योगिक विकास सम्भव नहीं हो सका।

(5) कुशल श्रमिकों का अभाव : राजस्थान के श्रमिक सामान्यतः प्रवासी प्रकृति के हैं। राजस्थान के श्रमिक गांधी के निवासी होते हैं। वे राज्य के औद्योगिक केन्द्रों में केवल कृषि से प्राप्त अपनी आय में वृद्धि करने के लिये ही आते हैं। इस सम्बन्ध में शाही श्रम आयोग (Royal Commission on Labour, 1931) का यह कथन राजस्थान के श्रमिकों के सम्बन्ध में पूर्णतया सही है "यदि औद्योगिक श्रमिकों को गाँव में ही भोजन और नन्द प्राप्त हो जाये, तो शायद ही उद्योगों में काम करना पसन्द करेंगे।" वास्तविकता तो यह है कि श्रमिक प्रारम्भ में असुल होते हैं। साखेरी और मवाई बांधोपुर की सीमेंट फैक्टरियों में नियुक्त किये गये श्रमिकों की आवश्यक प्रशिक्षण देने के बाद बर्द-कुशल तथा कुशल श्रमिकों के रूप में महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाता है। कुशल श्रमिकों के अभाव में यहाँ उद्योग-धंधों का समुचित विकास नहीं हो सका है।

(6) श्रमीण तथा सघु उद्योगों की प्रभावता : राजस्थान में अधिकांश औद्योगिक कार्यक्रम प्राचीन तथा सघु उद्योगों तक ही सीमित है। ये उद्योग परम्परागत पद्धति के अनुसार चलाये जाते हैं, जिनमें न केवल उत्पादन-लागत अधिक होती है, बल्कि श्रम, कच्चे माल व समय का उपयोग भी होता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त श्रमिकों की कुल संख्या का 65.2 प्रतिशत भाग घरेलू उद्योगों में रखा हुआ है, जबकि सम्पूर्ण भारतवर्ष का यह औसत 54.5 प्रतिशत है।

(7) केन्द्रीय परिविशेष का अभाव : अन्य राज्यों के औद्योगिक विकास में केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया है, परन्तु राजस्थान में इस दिशा में केन्द्रीय सरकार ने कोई महत्वपूर्ण सहयोग नहीं मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी

निर्माण योजनाएँ जिसकी केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिली हो, नहीं के बराबर है।

31 मार्च, 1966 तक इस राज्य में केन्द्रीय सरकार से कुल दिनियोग का 0.86 प्रतिशत भाग ही इस राज्य को प्राप्त हुआ था, जबकि मध्य प्रदेश को 25 प्रतिशत उद्योगों को 22 प्रतिशत तथा बंगाल को 17.6 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था।

(8) कुशल प्रशासन का अभाव राजनीतिज्ञों के आगे दिन हस्तक्षेप के कारण प्रशासन अत्यधिक विचलित एवं घट्ट हो चुका है। प्रशासन की अकुशलता एवं झट्टाचार के कारण उद्योगपतियों के प्रार्थना पत्र पर समय से विचार नहीं किया जाता है और प्रायः आर्थिक विकास की अनेक परियोजनाएँ लागू होती-जाती हैं के बचकर में फँस कर समाप्त हो जाती हैं।

(9) सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता भारत सरकार ने विविध अर्थ-व्यवस्था को अपनाकर यह आशा की थी कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देंगे। दुर्भाग्यवश हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग असा-नुकूल कार्य न कर सके। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उद्योग घाटे में चल रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की निराशाजनक प्रगति से एक ओर तो साधनों का दुरुपयोग हो रहा है और दूसरी ओर निजी क्षेत्र के साहसियों को अपनी कुशलता दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता है। कुछ निदागों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि सरकार ने निजी क्षेत्र को समुचित प्रोत्साहन दिया होता तो अब तक राज्य की कमाई ही गलट जाती और सरकार द्वारा किया गया अपभ्रम न हो जाता।

राजस्थान के कुटीर तथा लघु उद्योग

(Cottage and Small Scale Industries of Rajasthan)

राजस्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योगों के लिए विख्यात रहा है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग कटाई व बुनाई रहा है। साडी-उत्पादन का राजस्थान एक महत्वपूर्ण केन्द्र माना जाता है। यहाँ के अन्ध घरेलू उद्योगी में लम्बड़ा कमाई, पानी सेल, रस्सी बनाने, कम्बल बनाने आदि के उद्योग प्रमुख हैं। राजस्थान के नव उद्योगों में रत्ना उत्पादन भी चरेतू उद्योग का नाम में आता है।

राजस्थान के प्रमुख घरेलू उद्योग निम्नलिखित हैं

1. चरेतू वस्त्र उद्योग (Textiles) यह सबसे पुराना उद्योग है और सभी गाँवों में समान रूप से चलाया जाता है। इस उद्योग में गाँवों के खनिजाश व्यक्ति लगे हुए हैं। इस उद्योग के द्वारा केवल मोटे कपड़ों का ही उत्पादन नहीं किया जाता,

एतकि सु दर रेशमी साडियों का भी उत्पादन किया जाता है। मयूरिया कपड तथा कोटा की साडिया और जरी वस्त्र इतने आनंदक होते हैं कि उन्होंने इस घरेलू उद्योग की प्रतिष्ठा को बनाये रखा है। जयपुर तथा उदयपुर में पगड़ी के लिए सु दर मन्मल तैयार की जाती है।

2 छपाई व रंगाई कपडों को रंगाई तथा छपाई का काम गाँवों तथा शहरों-दोनों ही जगह किया जाता है। सहरो में फुहार रोगन (Spray printing) का प्रयोग किया जाता है। उनके रंग की छपाई बहुत ही आकर्षक होती है। सागानेर की छोट या छपाई उनके रंग तथा डिजाइन के लिए विख्यात है। जोधपुर की नूनरी तथा साफा उदयपुर का लसरिया, बाइमेरी घोटा तथा गर्दे इस उद्योग की ही देन हैं। बघन का काम केवल सहरो में ही किया जाता है। यह उद्योग जयपुर, सीकर, सुझुनू तथा जोधपुर में प्रायः सुसम्मान कारीगरों के हाथों में ही है।

3 जरी तथा निवार राजस्थान की दरियाँ अधिक टिकान, बन्धी किस्म तथा उनके रंग की होती है। दरियाँ तथा निवार प्रायः जलो में ही तैयार कराये जाते हैं।

4 गोटा उद्योग गोटा सुनहला तथा स्पष्ट होता है या उसमें दोनो रंगों का मिश्रण होता है। यह बाइला सोने या चांदी के तार से तैयार किया जाता है। सोने या चांदी के तार का गोटा हाथ से हथ करके द्वारा तैयार किया जाता है। गोटा नकली या भस्मी दोनों ही प्रकार का होता है। जयपुर का गोटा पूरे देश में विख्यात है। गोटा निर्माण का दूसरा केंद्र जोधपुर भी है।

5 चमड़ा तथा फेल्ड (Namdas and Felts) द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व चमड़ा तैयार करने का काम गाँवों में किया जाता था परन्तु युद्ध काल में ही शहरों में भी इसका उत्पादन किया जाने लगा। इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर हैं।

6 चमड़ा उद्योग चमड़ा कमाने का घरेलू उद्योग अब भी अधिकतर गाँवों में ही चल रहा है। वहा चमड़ा कमाने का काम पुराने तरीकों से किया जाता है। भारत में राजस्थान का चमड़ा आयर तथा मयूरा भण्ड दिया जाता है जहा उसकी कमाई आधुनिक तरीके से की जाती है। देशी सूते गाँवों में ही तैयार किये जाते हैं। कामदार जूतिमाँ जोधपुर तथा जयपुर में तैयार की जाती हैं। जालोर में भीनमाल भी एसी जूतिमाँ का एक अच्छा उत्पादन केंद्र है। जोधपुर में चमड़ा के कामदार पैले भी तैयार किये जाते हैं।

7 कागज हाथ से कामज सामानों के सवाई माघोपुर उदयपुर तथा कोटा

में तैयार किया जाता है। यह सबसे पुराना घरेलू उद्योग है। साबानेर में यह उद्योग जयपुर राज्य के सरक्षण के कारण ही बन रहा है।

8. कागज की लुगदी के सिलौने (Papier Mache) - कागज की लुगदी से अनेक प्रकार के सिलौने तैयार किये जाते हैं। इस उद्योग के मुख्य केन्द्र सवाई माधोपुर तथा उदयपुर हैं।

9. सगमरमर वायर का काम - सगमरमर से अनेक वस्तुओं तथा मूर्तियों का निर्माण जोधपुर, सावनोर, उदयपुर तथा रिलखदेव में किया जाता है। दू. गरपुर में घरेलू वस्तुओं, जैसे—प्याले, चकटा, बेलन आदि का निर्माण किया जाता है। इसे आकार की सफेद सगमरमर की मूर्तियाँ जोधपुर तथा मकराना में तैयार की जाती हैं।

10. साल की नूटियाँ - इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र जयपुर है। यहाँ बहुत ही सुन्दर तथा कलात्मक नूटियाँ तैयार की जाती हैं, जिनकी काफी अधिक मांग है। सवाई माधोपुर, ल डेला, जयपुर तथा उदयपुर में सुनहरी बानिख और लकड़ी के से (Laquer) सिलौने, मोमबत्ती दान, फूलदान, विजली के लैंप आदि भी बनाये जाते हैं।

11. हाथी-दाँत तथा चन्दन की लकड़ी का काम - यह भी जयपुर की विशेषता है। ये दोनों वस्तुएँ (हाथीदाँत तथा चन्दन की लकड़ी) मैसूर से प्राप्त की जाती हैं और यहाँ इनसे अनेक सुन्दर और कलात्मक वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। पाली तथा जोधपुर इन वस्तुओं के निर्माण केन्द्र हैं।

12. मिट्टी के बर्तन तथा सफेद बर्तन - इस प्रकार के बर्तन जयपुर में बनाये जाते हैं। यहाँ इनके बनाने के लिए अच्छा माल प्राप्त हो जाता है। फूलदान, कटोरे तथा अन्य इसी प्रकार की सुन्दर वस्तुएँ यहाँ तैयार की जाती हैं।

13. पीतल का काम - जयपुर पीतल की सुन्दर और कलात्मक वस्तुओं के लिए विख्यात है। नावझरा तथा प्रतापगढ़ में भी पीतल पर 'एनैमल' का काम किया जाता है। इस उद्योग में हजारों श्रमिक काम करते हैं।

खासी तथा ग्राम उद्योग

सन् 1957 में ब्रिटिश भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग (All India Khadi and Village Industries Commission) ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में स्थापित किया था। राजस्थान सरकार ने भी अपनी 'राजकीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड' स्थापित किया है। तेल, चमड़ा, गह खाड़खारी, ताड़-बूट, साबुन, मधुमक्खी पालन, माटा-चककी, हाथ से बना कागज आदि घरेलू उद्योगों को यह बोर्ड समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 1970-71 में इन उद्योगों की उत्पादन मात्रा नीचे दी गयी तालिका में दी गयी है .

ग्राम-उद्योग उत्पादन-मात्रा व मूल्य

उद्योग	उत्पादन की इकाई	(उत्पादन 1970-71)	
		परिमाण	मूल्य, 000, ₹० में
1 घाभी लेख	क्विन्टल	29577	14,450
2 गुड़ व साहसारी	"	67053	5,845
3 हाथ का बना कागज	कि० ग्राम	2329	789
4 अक्षरा लेख	"	7511	1,923
5 मिट्टी के बर्तन	सक्या	N A	1599
6 मधुमक्खी पालन (शहद)	कि० ग्राम	250	3 54
7 हाथ से कुटा हुआ चावल	क्विन्टल	8126	851

लघु उद्योग (Small Scale Industries)

राजस्थान में निम्नलिखित लघु उद्योग विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये हैं .

राजस्थान के लघु उद्योग

उद्योग	राजस्थान, जहाँ पर वे स्थित हैं
1 इन्जीनियरिंग	जयपुर तथा जोधपुर
2 छाते बनाने वाली फैक्ट्रियाँ	जोधपुर तथा कालका
3 गहर फॅक्टरी	कोटा
4 साबुन फॅक्टरी	मन्थी बस्ती तथा तनखरी में
5 रासायनिक उत्पादन तथा औषध-निर्माण	" " " "
6 कार्पेट फॅक्ट्रियाँ	वीकानेर तथा जोधपुर
7 लकड़-बाद की फॅक्ट्रियाँ	उदयपुर
8 रुतमा तथा गोत्रा फॅक्ट्रियाँ	जयपुर
9 चावल मिलें	बनारगढ़, विजयनगर तथा हिन्डोब
10 होथरी फॅक्टरी	जयपुर तथा मोलवाड़ा
11 शनिज फॅक्टरी	दीसा ।

उत्पन्न उद्योगों के विकास के लिए योजनामूलक में पर्याप्त वार्षिक सहायता प्रदान की गयी । राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना में 32.50 लाख रुपये देनी

रियासतों में चल रहे लघु उद्योगों के पुनर्संगठन के लिए प्रदान किये गये थे। दोबारा-काल में सांख्यिक क्षेत्र के अन्तर्गत कोई महत्वपूर्ण लघु उद्योग नहीं स्थापित किया गया।

द्वितीय योजनाकाल में लगभग 2,0000 नयी लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गयीं। इनमें से 640 इन्जीनियरिंग उद्योगों, 62 लोहमय अपारभूत धातुओं के उद्योग, 150 रासायनिक उद्योग तथा 1,100 से अधिक साबुन, आदि की इकाइयाँ थीं। इस योजनाकाल में 56 83 लाख रुपये लघु, माझ, हाथ-करघों तथा दस्तकारी उद्योगों पर व्यय किये गये। कार्यशील पूँजी, कच्चा माल खरीदने, भूमि, भवन तथा मशीनों के लिए ऋण आदि के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। कई नगरों में औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गयीं। सरकार ने इन उद्योगों को समय-समय पर अनुदान (Subsidy) भी प्रदान किया गया। कई स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र तथा नगरों में वित्तीय केंद्र भी खोले गये।

तृतीय योजनाकाल में इन उद्योगों के लिए 260 24 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी। इस योजना के अन्तर्गत पञ्चायत समितियों में अन्तर्गत सामाजिक सुविधा केंद्रों को स्थापित करने की योजना चालू की गयी। अब तक ऐसे 27 केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं।

राजस्थान में लघु उद्योग निगम (Small Industries Corporation) भी स्थापित किया गया है जिसकी अधिकृत पूँजी 25 लाख रुपये है। इस निगम द्वारा लघु उद्योगों की आवश्यकतानुसार कच्चा माल प्राप्त किया जाता है तथा उसकी पूर्ति से आती है। यह निगम विपणन सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

राजस्थान सरकार ने 59 लाख रुपये की लागत में 11 औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया है। 5 लाख रुपये डिजाइन विस्तार केंद्रों (Design Extension Centres) स्थापित करने के लिए प्रदान किये गये हैं। ऐसे 16 केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। दस्तकारी उद्योगों के उत्पादन के किस्म निर्धारण की योजना भी कार्यान्वित की गयी है। केन्द्रीय सरकार की सहायता में 330 खंजर द्वारा बुनने वाले करघे (Powerlooms) लगाये गये हैं। ऐसे 1 100 करघे लगाने की योजना है। नागौर तथा बरू जिलों में लघु उद्योगों के गहन विकास की योजना बनायी गयी है। इस कार्य के लिए 20 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

राजस्थान वित्तीय निगम (Rajasthan Financial Corporation) ने जिसकी स्थापना 1955 में की गई, अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक 848 इकाइयों को 17 52 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान किया है, जिसमें से 5 19 करोड़ रुपये की सहायता 414 इकाइयों को निगम दो वर्षों, अर्थात् 1971 व 1972, में

प्रदान की गई। सन् 1970 से 1972 के मध्य इजीनियर-ग्राहिसिबो को लघु-उद्योगों के लिए 5.54 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। अभी हाल ही में एक योजना चालू की गई है जिसके आधीन वारीगरो को नाम मात्र की ग्राज दर पर कच्चा माल, बीजार, रासायनिक पदार्थ आदि खरीदने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई है। राज्य सरकार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जूनीकर, विश्वीकर आदि में भी छूट प्रदान कर रही है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य सरकार ने लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है।

सन् 1966-67, 1967-68 व 1968-69 में क्रमशः 14.76 लाख, 43.51 लाख तथा 59.33 लाख रुपये बृहत् एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए व्यय किए गए। ग्रामीण एवं लघु आकार के उद्योगों के विकास के लिए इसी अवधि में क्रमशः 11.48, लाख रुपये, 8.57 लाख रुपये तथा 11.38 लाख रुपये व्यय किए गए। इस प्रकार 1966 से 1969 की अवधि में बृहत् एवं मध्यम आकार के उद्योगों पर कुल मिला कर 149.03 लाख रुपये व्यय किए गए।

चतुर्थ योजना के प्रथम दश में अर्थात् 1969-70 में बृहत् एवं मध्यम आकार के उद्योगों के विकास पर 45.96 लाख रुपये तथा कुटीर एवं लघु उद्योग पर 10.48 लाख रुपये व्यय किए गए।

जो बिना किसी तैयारी तथा पूर्व विचार के बनायी गयी थी। इस योजना का एक-मात्र उद्देश्य जल्दी से निर्वाहिकी की कई प्रोजनाओं (Projects) तथा योजनाओं का आधार तैयार करना था, क्योंकि यह योजना राज्य के वित्तीय साधनों का अनुमान लगाने बिना ही तैयार की गयी थी। यही कारण है कि जबकि अन्य राज्य अपनी प्रथम योजना को क्रियान्वित करने में लगे हुए थे, यह राज्य केवल उपभुक्त सम-स्याओं के समाधान में व्यस्त था। अतः राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना मार्ब-जनिव वित्त की कुछ निश्चित परियोजनाओं ही सामूहिक रूप था, जिसे बाह्यिक नियोजन की भूमिका कहना असम्भव न होना।

1 प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्रमुखतः राज्य तथा लोगों की प्रारम्भिक या आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र ही था, न कि राज्य की आय तथा लोगों की मावैजिनिक सुविधाओं में वृद्धि करना। प्रारम्भ में (वर्ष 1951-52 में) इसके अन्वर्तन व्यय का प्रावधान 15.26 करोड़ रुपये के द्वारा निर्धारित किया गया था, परन्तु वर्ष 1955-56 में इसे बढ़ा कर 27.68 करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्रारम्भ करने के लिए आधार तैयार करने में सहायता मिली।

उपभुक्त प्रावधान में भावना तथा चन्दल की उद्गुहृष्टीय प्रायोजनाओं के लिए निर्धारित रकमे सम्मिलित नहीं की गयी थी। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए 37.22 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया। इन प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय का प्रावधान 64.50 करोड़ रुपये के बराबर था, जो राष्ट्रीय योजना के 27 प्रतिशत के बराबर था। इस निर्धारित प्रावधान में वास्तविक व्यय 54.14 करोड़ रुपये के बराबर ही किया गया, जो नियोजित प्रावधान के 84 प्रतिशत के बराबर था। विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित रकमों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय राज्य सरकार आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार नहीं थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्रावधान तथा वास्तविक व्यय का ब्योरा अपने ही सजी तालिका में दिया गया है।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में प्रावधान तथा व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	प्रस्तावित प्रावधान	प्रस्तावित कुल प्रावधान का प्रतिशत	प्रस्तावित व्यय	कुल वास्तविक व्यय का प्रतिशत
1 कृषि तथा सामान्य विकास	6 64	10 29	6 99	12 92
2 सिंचाई	29 84	46 25	30 24	55 86
3 शक्ति	9 58	14 86	1 23	2 27
4 उद्योग तथा खनन	1 55	0 85	0 46	0 85
5 सड़क	6 27	9 72	5 55	10 25
6 सामाजिक सेवाएँ	11 06	17 16	9 12	16 84
7 विविध	0 56	0 87	0 55	1 01
योग	64 50	100 00	54 14	100 00

2 द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना (1956-1961)

राजस्थान में वास्तविक आर्थिक नियोजन का मूल द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में ही प्रारम्भ होता है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के पांच वर्षों में तो केवल कुछ ऐसी आवश्यक दशाओं के निमाण करने में ही सफलता मिली थी जिनके आधार पर भावी विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जा सकता था तथा उनके विस्तार की योजनाएँ बनायी जा सकती थी। प्रथम योजना काल में प्राप्त अनुभव के आधार पर ही एक बड़ी तथा अपेक्षाकृत माहसी द्वितीय योजना तयार की गयी। राजस्थान के सार्वजनिक विकास कार्यक्रमों के लिए उस द्वितीय योजना में 105 27 करोड़ रुपये का 2 3 प्रतिशत ही था। इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की द्वितीय योजना के लिए भी किया गया अनुषासित प्रावधान अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही था। द्वितीय योजनाकाल में वास्तविक व्यय 102 74 करोड़ रुपये के बराबर ही हुआ जो प्रस्तावित प्रावधान का 97 60 प्रतिशत ही था। इस व्यय में प्रतिशत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय योजना काल में आर्थिक नियोजन की प्रगति पूर्ण योजना की अपेक्षा सतोपजनक थी।

प्रावधान तथा वास्तविक व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

योजना	प्रस्तावित प्रावधान	वास्तविक व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना	64 30	54 14
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	105 27	102 74
तृतीय पंचवर्षीय योजना	236 00	212 63
योग	415 77	369 51

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास

राजस्थान में 15 वर्षों के आर्थिक नियोजन काल में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ है

(i) बिजली: तीनो योजनाओं में मिला कर निचाई पर 369.51 करोड़ रुपये में से 129.60 करोड़ रुपये केवल निचाई पर व्यय किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थापित क्षेत्र 11.74 लाख हेक्टर (1950-51 में) से बढ़ कर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में 20.80 लाख हेक्टर तक पहुँच गया है।

(ii) व्यक्ति: व्यक्ति के साधनों पर कुल व्यय की गयी रकम 55.02 करोड़ रुपये के बराबर है। वर्ष 1950-51 में बिजली उत्पादन क्षमता 7.48 मेगावाट थी, 1967-68 में यह बढ़ कर 163 मेगावाट हो गयी। वर्ष 1950-51 में केवल 32 बिजली घर थे तथा 112 स्थानों की ही बिजली की सुविधाएँ प्राप्त थी। परन्तु 1967-68 में बिजली घरों की संख्या बढ़ कर 70 हो गयी तथा 1,837 स्थानों को बिजली की सुविधा प्राप्त होने लगी। प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग भी 1960-66 तक 3.06 किलोवाट से बढ़ कर 15.37 किलोवाट हो गया।

(iii) सामाजिक सेवाएँ: तीनो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र पर 75.46 करोड़ रुपये व्यय किए गए, अर्थात् कुल व्यय का 20.42 प्रतिशत अंश शिक्षा, चिकित्सा तथा श्रम कल्याण की विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा पुरानी सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किया गया। इससे सितन सस्त्राओं की संख्या 6,026 (वर्ष 1950-51 में) से बढ़कर 32,826 (वर्ष 1960-66 में) हो गयी। चिकित्सालयों तथा दवाखानों की संख्या भी 366 से 535 हो गयी। जल पूर्ति की योजनाएँ भी 72 ग्रामीण तथा महरी केन्द्रों में पूरी की जा चुकी हैं। राज्य में तीन विश्वविद्यालय, 5 मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज,

4 कृषि कॉलेज स्थापित किये जा चुके हैं। पचायती राज्य सस्थाओं के विभिन्न सदस्यों को सामुदायिक विकास एवं पचायती राज्य सस्थाओं के अधिकार, वर्तमान एवं उत्तरदायित्व का ज्ञान कराने के लिए 10 स्थानों पर पचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं। विस्तार सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किये गये। राज्य में 5 ग्राम-सेवक प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

पशु पालन क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया। वीकानेर में पशु-पालन महाविद्यालय में स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है। राज्य में मछली-पालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना उदयपुर में की गई है। जोधपुर में इन प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया है। इन विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 2 वन-गाल प्रशिक्षण विद्यालय अलवर व बीसवाड़ा में चालू किये गये हैं।

11v) कृषि राजस्थान में आर्थिक नियोजन ने फलस्वरूप इन 15 वर्षों में कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि कार्यक्रमों पर 73 09 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं जिससे राजस्थान आज छायाओं का निराकरण करने के लिए समर्थ है। प्रथम योजना के अन्त में यहां खाद्यान्तों की उत्पादन मात्रा 41 70 लाख टन थी, द्वितीय योजना के अन्त में 44 81 लाख टन थी तथा तृतीय योजना के अन्त में प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों से यह थोड़ी घटकर 44 69 लाख टन हो गई थी।

कृषि क्षेत्र में किये गए प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों के बावजूद भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुयी है, जैसे कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है

कृषि-उत्पादन में वृद्धि

(चार साल के उत्पादन के औसत के आधार पर)

पदार्थ	इकाई	1952-53 से 1955-56 तक वार्षिक औसत उत्पादन	1957-58 से 1960-61 तक वार्षिक औसत उत्पादन	1962-63 से 1965-66 तक वार्षिक औसत उत्पादन
आद्यान्न	लाख मेट्रिक टन	30 88	46 37	45 40
तिलहन	" "	2 06	2 12	2 61
फसल	लाख गांठें	1 32	1 64	1 74
गन्ना (गुड़)	लाख मेट्रिक टन	1 45	0 69	0 74

मौन राजस्थान सरकार, तृतीय पंचवर्षी योजना प्रतिवेदन, 1961-66

1 **सूती-वस्त्र उद्योग** तृतीय योजना में राज्य में 17 सूती मिलों की क्षमता 3,09,456 की हो गयी। भीलदाहा, भवानी मण्डी तथा चित्तौड़गढ़ में नयी सूती मिलें स्थापित की गयी। गंगानगर, भीलदाहा, चित्तौड़गढ़ एवं झालवाड़ जिलों में मिर्चाई सुविधाओं में वृद्धि होने से कपास के अल्पतः क्षेत्र में वृद्धि हुयी है, जिससे इस उद्योग के विकास की पर्याप्त क्षमता राज्य में है।

2 **चीनी उद्योग** तृतीय योजना के अंत में राज्य में दो चीनी मिलें की सी गंगानगर व भीपाल सागर में स्थित हैं। तृतीय योजना के अंत में चीनी का उत्पादन 13 हजार मेट्रिक टन था। मिर्चाई सुविधाओं के विस्तार से राज्य में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुयी, जिससे गंगानगर, मर्चाई माधोपुर, बूंदी कोटा एवं भरतपुर जिलों में अग्रिम चीनी मिलें स्थापित की जा सकती हैं। बूंदी जिले में केशवराय पाटन स्थापन पर सहकारिता के आधार पर भी एक चीनी फैक्टरी स्थापित करने की योजना बनायी गयी है।

3 **सीमेंट उद्योग** राज्य में सीमेंट की पुरानी फैक्टरियाँ मर्चाई माधोपुर तथा लाहरी (बूंदी) में है। एक सीमेंट फैक्टरी चित्तौड़गढ़ में भी तृतीय योजनाकाल में शुरू की गयी है, जो सन् 1968-69 से चालू हुई है। इन तीनों कारखानों का वार्षिक उत्पादन 14 लाख टन है।

4 **उर्वरक** रासायनिक उर्वरकों की मांग की पूर्ति के लिए कोटा में एक सर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता 2,21,285 मेट्रिक टन होगी।

5 **खनिज पर आधारित उद्योग** राज्य ने अपने खनिज भण्डारों के समुचित प्रयोग द्वारा अपनी अर्थ व्यवस्था को दृढ़ बनाने के प्रयत्न किये हैं। खनिज पर आधारित उद्योग निम्न स्थानों पर स्थापित किये गये हैं

(i) उदयपुर के पास देवारी नामक स्थान पर ज़िंक शोधक (स्मेल्टर) घर।

(ii) खेतड़ी में भारत सरकार द्वारा सर्वजनिक क्षेत्र में तांबा शोधक कारखाना (कापर स्मेल्टर)।

6 **अन्य उद्योग** राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य में अन्य कई उद्योग भी स्थापित किये गये हैं, जैसे

(i) कोटा नगर कैल्शियम कार्बाइड, नाइलोन (जे० के० सिंथेटिक्स) एवं रेयन (रेयन लिमिटेड के कारखाना), अलुमिनियम का विखंडी घर, केबल तार (Oriental Power Cables) तथा साइ फैक्टरी।

(ii) सोडपाणा (वाणौर) सोडियम सल्फेट का कारखाना।

(iii) बीतपुर दो शीशा फैक्टरियाँ।

(i) भरतपुर : रेल रींगन फैक्टरी ।

(v) जयपुर : (i) पानी के मोटर का कारखाना, कंपटन कंपटरी ।

(ii) विद्युत्-मोटर का कारखाना, जयपुर मेटल्स तथा इलेक्ट्रिकल्स ।

(iii) इंजीनियरिंग के सामान - मान इण्डस्ट्रियल ।

(iv) वाल इरियरिंग मेशिनल इंजीनियरिंग वर्क्स ।

7 ग्रामीण तथा लघु उद्योग . वरुं उद्योगों के विकास के साथ-साथ राज्य ने ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया है । राज्य के नागौर एवं चूरू जिलों में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएँ भी तृतीय योजना में प्रारम्भ की गयी । लघु उद्योग सेवा निगम भी लघु मस्त्राओं के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ है । इन उद्योगों को विकसित करने की दिशा में 11 औद्योगिक वस्तियों का निर्माण किया गया है, जिनकी स्थापना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, सुमेरपुर, श्री गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, साखपुरा (अजमेर), भरतपुर एवं कोटा में की गयी है । इन वस्तियों में 379 उत्पादन केन्द्र (यूनिट्स) का निर्माण किया गया है, उनमें से 310 यूनिट्स बाट दिये गये हैं व 229 में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

औद्योगिक विकास के लिए लिये गये विभिन्न उपर्युक्त प्रयासों के परिणाम-स्वरूप यह आशा की जा सकती है कि राज्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित होकर अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ करने में सक्षम हो सकेगा ।

3 वार्षिक योजना (1966-67)

सन् 1966 में तृतीय पञ्चवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में व्याप्त आपत्तिनाशीन स्थिति के कारण चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना को स्थापित करना पड़ा । योजना आयोग ने, जब तब चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना को चालू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हो जाती, उस समय तक वार्षिक योजना का समावेश ही देश के लिए हितकर समझा । राज्य सरकार को प्राप्त आदेशानुसार राजस्थान के लिए भी 1966-67 की वार्षिक योजना तैयार की गयी तथा इस विषय पर धर्म में योजनान्तर्गत विभिन्न नर्तक्यों के सङ्गत कर्मचिन्मन के लिए प्रारम्भ में 36 06 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसे बाद में बढ़ा कर 46 87 करोड़ रुपये कर दिया गया ।

वर्ष 1966-67 में सर्वाधिक प्रावधान सिचाई एवं विद्युत क्षेत्र के लिए रखा गया था । इस क्षेत्र के लिए 29 72 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया, जो कि कुल प्रावधान की राशि का 60 81 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रों

वार्षिक योजना 1967-68 में प्रावधान एवं व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

मह	प्रावधान	व्यय
1 कृषि कार्यक्रम	6 19	5 9०
2 नदी-कारिता व सामुदायिक विकास	1 47	1.47
3 मिर्चाई एवं शक्ति	24 07	22.87
4 उद्योग तथा खनन	0.95	0 73
5 यातायात एवं संचार	1.2०	1.29
6 सामाजिक सेवाएं	9 18	7.14
7 विविध	.54	.42
योग	43.65	39.88

वर्ष 1967-68 में वार्षिक प्रावधान मिर्चाई एवं शक्ति की रखा गया था। इस क्षेत्र के लिए 21 82 करोड़ का प्रावधान रखा, जो कि कुछ प्रावधान की राशि का 55.95% है। भारत में हरित क्रांति (Green Revolution) के पुनारम्भ के माध्यम से राजस्थान में मक्का खेती कार्यक्रम को विस्तृत करने के लिए पर भी कृषि की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि के लिये कृषि प्रारम्भ की गई। योजना में कुल 39 ११ करोड़ रु० व्यय हुए जिसमें सर्वाधिक व्यय मिर्चाई एवं शक्ति पर 22 85 करोड़ रु० का कि प्रस्तावित व्यय से 1 03 करोड़ रु० अधिक था।

उपचरित्रधर्मा

राजधानी 20 8 लाख मीट्रिक टन, तिलहन 9 हजार मीट्रिक टन, गन्ना 3 हजार मीट्रिक टन और कपास 15 हजार मीट्रिक टन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। अधिक उपज देने वाले बीजों की बुवाई का क्षेत्र बढ़कर 4 010 लाख एकड़ हो गया। पुरु तथा लकड़ों में भी ऊनी कटाई मिले लगाई गयी, इसके माध्यम से। औद्योगिक विकास के लिए सहकारी बीजों मिल व सहकारी स्पिनग मिल में लगाई गई। वर्ष 1967-78 में 100 वसतिग तथा 4000 कुत्तों का विद्युतीकरण किया गया। 1967-68 में 264 किलो मीटर सड़कों का निर्माण हुआ। वर्ष 1967-68 के अन्त तक 81 नगर जन प्रदाय की योजनाएँ तथा 169 ग्राम्य जन प्रदाय की योजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं। पिछले जातिगों के नष्टगण के अन्तर्गत 16,000 टाको की छात्र-वृत्तियों से लाभान्वित किया गया।

आर्थिक योजना 1968-69

राजस्थान की आर्थिक योजना 1968-69 में बजटानुसार 37 33 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान रखा।

आर्थिक योजना 1968-69 का अनुमानानुसार व्यय विवरण
(करोड़ रुपये में)

वर्ग	प्रस्तावित व्यय
1 कृषि कार्यक्रम	5.28
2 सहकारिता एवं सामुदायिक विकास	1.20
3 गिराई व क्षति	22.44
4 उद्योग तथा खान	1.13
5 परिवहन एवं संचार	1.07
6 सामाजिक सेवाएँ	8.34
7 विविध	0.42
योग	40.08

इस योजना में भी गिराई व क्षति का सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। इस क्षेत्र के लिये 22.44 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया जो कि कुल योजना व्यय का लगभग 57 प्रतिशत है।

इसके बाद सामाजिक सेवाओं को फिर कृषि कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई।

योजना में लगभग 40 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है।

उत्पत्तिधियाँ —

इस समय अकाल प सूख की स्थिति के कारण कृषि उत्पादों की छोट कर, शिक्षा, सहकारिता, सड़कें व जलपूर्ति के लक्ष्यों में सफलता मिलने की आशा है। आयातों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में घिर गया है। इस योजना में महान कृषि कार्यक्रम 10 और सड़कों में कराया गया जिससे महान कृषि कार्यक्रमों के अधीन खेतों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। फसलों का क्षेत्रफल 3.09 लाख हेक्टर वर्ष 1967-68 के वर्ष में यह वृद्धि 1.64 लाख हेक्टर हो गई। 1968-69 के वर्ष में 1.20 लाख टन नाइट्रोजन व 0.39 लाख टन फास्फोरस खाद कृषकों में बाँटी गई।

सहकारी क्षेत्र में मन् 196-69 की योजना अवधि में 1426 प्राथमिक कृषि समितियों का पुनर्गठन, 19 करोड़ रुपये का उत्पादालीन व व्यवसायीक व

2.20 करोड़ रु० की दीर्घकालीन ऋण वितरण करना व केन्द्रीय सहकारी बैंक व भूमि बन्धक बैंक प्रत्येक की 5 अतिरिक्त शाखाएँ स्थापित करना उल्लेखनीय है। 1968-69 में लगभग 234 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है, जिसमें राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 31365 किलोमीटर हो गई है। बिछा के क्षेत्र में 1968-69 की योजना में 194 प्राथमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों, 92 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में तथा 9 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में वर्गित किया गया है। साथ ही तीन नए कलिय खोले गये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम दुग्ध टैंकमटाइल मिल श्रीकापूर में स्थापित की गई है।

शिक्षण में तीन वार्षिक योजनाओं में कुल सम्भावित व्यय 138 करोड़ रु० हुआ है। तीन वार्षिक योजनाओं में कुल सम्भावित व्यय का लगभग 75% कृषि, मिचार्डी व शक्ति पर व्यय होगा और सामाजिक सेवाओं पर 15.5% व्यय होगा। इस प्रकार कृषि, मिचार्डी व शक्ति को पहले से ही जाने प्राथमिकता में और भी वृद्धि कर दी गयी है। सामाजिक सेवाओं पर किये जाने वाले प्रतिशत व्यय में द्वितीय व तृतीय योजनाओं की तुलना में कमी की गयी है। इन तीन वार्षिक योजनाओं में दो वर्ष सन् 1966-67, 1967-68 बकाया व सुखे के वर्ष रहे जिससे धर्म व्यवस्था को काफी क्षति पहुची। 1968-69 में व्यय वितरण इस प्रकार है

1968-69 का व्यय का वितरण

महत्त्व	(लाख रुपये में)
	व्यय
1 कृषि कार्यक्रम	551.15
2 सार्वकारी एवं सामुदायिक विकास	115.26
3 मिचार्डी एवं	
4 शक्ति	3023.88
5 उद्योग व खनन	97.44
6 परीक्षण व मन्दोद्धार	110.42
7 सामाजिक सेवाएँ	856.65
8 विविध	43.05
योग	4797.85

राजस्थान की नियोजन के 20 वर्षों में वार्षिक प्रगति

राजस्थान राज्य तीन पंचवर्षीय योजनाएँ और तीन वार्षिक योजनाएँ समाप्त

करके तथा चौथी योजना के 2 वर्ष पूरे करके 1971 में योजना के 20 वर्ष पूरे किये। इससे राज्य का पिछड़ापन पहले की अपेक्षा कम हुआ है और विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार हो गया है, जिसका उपयोग करके चतुर्थ योजना के अग वषों में एक भावी योजनाओं में कृषि व उद्योगों के विकास के लिए नये प्रयत्न किये जा सकेंगे। राज्य की 20 वर्षों की प्रगति का उत्तेजक निम्न प्रकार से है

1 राज्य की आय में परिवर्तन

राजस्थान राज्य की आय के अर्बिड सन् 1954 व 1955 की अवधि में उपलब्ध है। स्थिर मूल्यों (1954-55) के भावों पर राज्य की कुल आय व प्रति व्यक्ति आय की स्थिति चुने हुए वर्षों में इस प्रकार रही है

राज्य की आय (सन् 1954-55 के स्थिर भावों पर

1955-55 1960-61 1965 66 1966 67 1967-68 1970 71

1 कुल आय

(करोड़ रु० में) 413 2 467 1 533 0 549 0 614 3 748

2 प्रति व्यक्ति

आय (रुपयों में) 236 237 241 243 265 302

तालिका से स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में राज्य की कुल आय में 13% की वार्षिक वृद्धि हुई। तृतीय योजना के अन्त में सन् 1965 66 में मूल्यों की स्थिति के कारण राज्य की आय 533 करोड़ रु० थी, जबकि सन् 1964-65 में यह लगभग 555 करोड़ रु० थी। इस प्रकार तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में राज्य की आय पूर्व वर्ष की तुलना में घटी, लेकिन योजना के प्रारम्भ की तुलना में यह 14% बढ़ी है।

सन् 1966-67 में आय में 3% वृद्धि ही हुई तथा 1967-68 में राज्य की आय पूर्व वर्ष की तुलना में 12% बढ़ी है। अनुमान है कि 1968 69 में राज्य की आय में वृद्धि नहीं होगी।

जहाँ तक प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न है, द्वितीय योजना काल में यह स्थिर रही एक तृतीय योजना की अवधि में इसमें केवल 1 6% वृद्धि हुई जो नगण्य थी। सन् 1966 67 में भी प्रति व्यक्ति आय में भूमिकल से 1% की वृद्धि ही पायी लेकिन सन् 1967 68 में लगभग 9% बढ़ा सन् 1968-69 में इसमें गिरावट की स्थिति आई। सन् 1970-71 में (1954-55 के मूल्यों के आधार पर) राज्य की कुल आय व प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 748 करोड़ रु० व 302 रु० थी।

अतः स्पष्ट है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में बहुत धीमी रफ्तार से वृद्धि हो रही है, जो वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति है।

2 कृषि उत्पादन व निर्यात

1963-64 में समस्त फसल का उत्पादन का सूचकांक सन् 1953-54 से कम तथा सन् 1969-70 का भी कम था। मौसम की अनिश्चितता के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव उत्पन्न करते रहते हैं।

खाद्यान्ना का उत्पादन सन् 1950-51 के अन्त में 29.46 लाख टन से बढ़ कर सन् 1967-68 में 66 लाख टन हो गया। इस अवधि में राज्य में 29.21 लाख टन अनिरिक्त खाद्यान्नों के उत्पादन की क्षमता उत्पन्न हो गयी। विमुक्त मिश्रित भूतल लगभग दुगुना हो गया। सन् 1971-72 में कुल मिश्रित सान बढ़ कर 22.3 लाख हैक्टा था गया। सन् 1970-71 में राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 88 लाख टन हुआ। सन् 1951-52 में केवल 324 टन ज्वार का उत्पादन होता था, जो कि 1970-71 में बढ़ कर 3.54 लाख टन तक पहुँच गया।

3 विद्युत क्षमता व विकास

योजनाकाल में विद्युत क्षमता के विकास में विशेष रूप से प्रगति हुई है। सन् 1959-60 के अन्त में क्षमता की उपलब्धि 7500 किलोवाट थी, जो बढ़ कर सन् 1970-71 के अन्त में 97 करोड़ किलोवाट हो गया। बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग 2.4 इकाई (K W H) से बढ़ कर लगभग 35 इकाई (K W H) से भी अधिक हो गया।

4 औद्योगिक विकास

योग्य वर्ष में राज्य में बड़े नये कारखाने खोले गये हैं। राज्य में सीमेंट का उत्पादन 1951 से 1971 में लगभग पाँच गुण से भी अधिक हो गया। मृत्ती बरत का उत्पादन 35 अंश में वृद्धि हुई तथा हो गया और गूल का तिगुना हो गया। राज्य का 7 मृत्ता वस्त्र मिल का मस्य विन क्षमता 2.92 लाख तन से बढ़ कर 4.2 लाख हो गई है। राज्य में बाल विद्युत व बिजली के मीटर बन्दे रूप, जिसकी संख्या सन् 1960 में लगभग 90 लाख व 298 हजार से भी अधिक रहे हैं। राज्य में नमक का उत्पादन पहले से बढ़ा है। सन् 1969 में राज्य सरकार की सन्निधि उद्योगों से आय का 4.5 प्रतिशत तथा अव्ययित उद्योगों से 11.3 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

5 सड़कों का विकास

राज्य में सन् 1950-51 के अन्त में सड़कों की लम्बाई लगभग 17339 किलोमीटर थी, जो बढ़ कर सन् 1971-72 के अन्त में 32052 किलोमीटर हो

गयी। 4000 व ऊपर की जनसंख्या वाले समस्त गांव राज्य के सड़क के नक्शों पर प्रा गये हैं।

6 शिक्षा की प्रगति

3000 व ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों में प्राथमिक स्कूल खोल दिये गये हैं। सभी पंचायत समितियों में एक या अधिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं। सभी जिलों में कॉलेज-स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है। सामान्य शिक्षा के लिए कॉलेजों की संख्या 27 में बढ़ा कर 70 कर दी गयी है। 6-11, 11-14 व 14-17 वर्ष के लड़के-लड़कियों के स्कूल जाने वालों का अनुपात सन् 1950-51 में क्रमशः 16.6, 5.4 व 1.8 प्रतिशत से बढ़ कर सन् 1968-69 के अन्त में 56.5, 23.3 व 11 प्रतिशत पर आ गया है। 6 से 11 वर्ष के लड़के व लड़कियों का प्रतिशत सन् 1971-72 में बढ़ कर 58.1 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

7 चिकित्सा व जल-पूर्ति के क्षेत्र में प्रगति

मलेरिया व चेचक आदि पर काफी ध्यान में निगन्धन स्थापित किया गया है। रोगियों के लिए विस्तारों की संख्या लगभग तिगुनी में भी अधिक हो गयी है। मेडिकल संस्थाओं (एलोपैथिक व आयुर्वेदिक) की संख्या सन् 1951-52 में केवल 732 थी जो कि 1971-72 में 2200 हो गई। इन संस्थाओं की संख्या 1973-74 में 2493 हो जाने की आशा है। झालवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में इस समस्या को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

143 नवरी में से 78 नवरी में जल पूर्ति के कार्यक्रम लागू किए जा चुके हैं और ग्रामीण जल पूर्ति के 189 कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 नल्लूनी के कार्यक्रम में से 130 नल्लूप चालू किये जा चुके हैं, जिससे उन क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या कुछ सीमा तक हल हो पायी है। चतुर्थ योजना के अन्त तक लगभग 1673 गांवों में राज्य द्वारा पानी पहुंचाने की योजना लागू हो जायेगी।

नियोजन के 20 वर्षों की आर्थिक प्रगति का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अवधि में राजस्थान में विकास के लिए आधार ढांचा काफी सुदृढ़ किया गया है। मिर्चार्ड, बिजुत, सड़क, पीने के जल, शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओं के बढ़ते में भावी आर्थिक विकास के लिए उत्तम षष्ठ भूमि तैयार हुई है।

राजस्थान का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

भारत सरकार की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में जो 1968 में राष्ट्रीय विनाम परिषद (NDC) और समद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था,

राजस्थान के लिए 239 करोड़ रु० की धन राशि प्रस्तावित की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह स्पष्ट राय प्रकट की गई थी कि इस आकार की योजना कतई मान्य नहीं है और यह मांग की गई थी कि चौथी योजना के मतविदे पर देश के पिछले राज्यों में विकास की गति तीव्र करने की दृष्टि से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह मंजूर किया गया कि पाचवें वित्तीय आयोग की निष्कारियों के बाद राज्य की योजनाओं पर विचार किया जायगा। राज्य सरकार के पाचवें वित्तीय आयोग की निष्कारियों के फलस्वरूप वित्तीय साधनों पर विचार करके और सहायक स्रोतों से अग्रिम साधनों की उपलब्धि क्षमता और पर ध्यावर्माधिक स्रोतों के राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखकर योजना आयोग के समुच्च 316 करोड़ रु० की योजना प्रस्तुत की।

यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में मुख्यतः इस बात पर मतभेद था कि अतिरिक्त साधन जुटाने में होने वाली लागत को किस प्रकार खर्च किया जायें। योजना आयोग की यह राय थी कि साधारण बजट में घाट को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त साधनों से होने वाली आय को योजना में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। उपर राज्य सरकार की यह पक्षी राय थी कि गैर-योजना साधनों में जो कमी रह जाती है, उसे केन्द्र सरकार विशेष सहायता से पूरा करे, और अनुर्थ योजना के अतिरिक्त साधनों को जुटाने से जो लाभ हो उसे विकास कार्यों में खर्च करने की अनुमति दी जायें। निदानतः योजना आयोग ने हमारी बलीक मान ली है कि अतिरिक्त साधनों से जितनी आय होवी, उस पूरी धन राशि को चौथी योजना के लिए साधनों के रूप में मान लिया जायेगा। अब नौ सहायक स्रोतों से प्राप्त होने वाले साधनों की मात्रा के बारे में कुछ मतभेद हैं। राज्य सरकार और योजना आयोग के मध्य 14 करोड़ रु० का अंतर है। इस प्रकार योजना आयोग की राय में राजस्थान की चौथी योजना 302 करोड़ रु० की होनी चाहिए। वास्तव में राष्ट्रीय विकास परिषद में भी राजस्थान की योजना का आकार 308 करोड़ रु० स्वीकृत कर दिया है।

अनुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1969-70 की वार्षिक योजना

राज्य की नयी अनुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1969 से प्रारम्भ हो गयी है। नव सरकार ने 1969-70 की वार्षिक योजना का आकार 49 60 करोड़ रु० रखा है।

“इसमें ऊर्ध्व, सिंचाई व खनिज पर कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग 73% व्यय किया जायेगा और मानसिक सेवाओं पर लगभग 19% व्यय किया जायेगा। इस प्रकार राजस्थान की योजनाओं में प्रारम्भ से ही सिंचाई व खनिज को जो प्राथ-

मिकता दी गई है, वह सन् 1969-70 की योजना में और भी बढ़ गई है। गहन कृषि की नयी विधियों का प्रयोग करने के लिए सिंचाई के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए विद्युत की सुविधाओं का भी समुचित विकास होना चाहिये। सिंचाई व शक्ति पर अधिक राशि का प्रावधान करने से खन्य मद्यों पर व्यय की राशि कम करनी पड़ी है।

लेबिन अब 1969-70 की योजना में सरकार के प्रावधान में वृद्धि करके 49.60 करोड़ रु से बढ़ा कर 53.47 करोड़ रु कर दिया। इसका मुख्य कारण राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अधिक अतिरिक्त साधन प्राप्त होना तथा दूसरा कारण प्रधान मंत्री द्वारा राजस्थान गहर और लघु सिंचाई बांधों के लिए 3.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त भन्तराशि देने की विनय व्यवस्था है।

वार्षिक योजना पर सर्वे भी लगभग इतना ही होने का अनुमान है।

चतुर्थ योजना के सम्बन्ध में सन् 1970-71 की वार्षिक योजना

राजस्थान राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष की वार्षिक योजना वर्षान् 1970-71 का कुल व्यय 56.23 करोड़ रु० रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष की योजना से 2.76 करोड़ रु० अधिक है।

इस योजना में सिंचाई व विद्युत् की अधिक प्राथमिकता देते हुए कृषि को ही महत्व दिया गया है।

कृषि के क्षेत्र में जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधाएँ सुविधाएँ हैं और वर्षा निर्भर हैं। वह उत्पादन बढ़ाने के विशेष प्रयत्न करने लिए जायेंगे। सबाई माधोपुर, टाक और बूंदी जहाँ कृषि उत्पादन की अच्छी सम्भावनाएँ हैं, इन जिलों की सघन कृषि क्षेत्र प्रायः के नीचे लाया जायगा। राजस्थान में कृषि की नई नीति का विस्तार प्रयत्न किया जाएगा। अगले पैदावार देने वाली किस्मों के अनर्गल क्षेत्र इस वर्ष 5.20 लाख हैक्टर से बढ़ कर 1970-71 में 6.32 लाख हैक्टर हो जायेंगा। इसी प्रकार अधिक उपज देने वाले बीजों का विस्तार भी 1969-70 में 2.51 लाख निवटल से बढ़ कर 1970-71 में 3.38 लाख निवटल हो जाने की आशा है। इस वर्ष सामाजिक खाद का सम्भावित वितरण लगभग 2.12 लाख टन होगा, यह बढ़ कर अगले वर्ष में 3.33 लाख टन हो जाने की सम्भावना है।

योजना में लगभग 40,000 हैक्टर इलाके में भू-सुरक्षा कार्य किया जायेगा, जो अनाल राहुन नार्थ के अनर्गल होन बाल कार्य के अन्तर्गत है। इन सब प्रयत्नों और सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार देने के फलस्वरूप आधा है कि 1970-71 में करीब 1.1 लाख अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।

कृषि विनाश के कारणों और तत्कालीन पर उप सिंचाई की गति देने के लिए एग्रीकल्चर रिकॉन्स्रक्शन कारपोरेशन की सहायता से निश्चित भूतल जल वाले क्षेत्रों में सफ़ेद विनाश योजना खंडों की जा रही है। एग्रीकल्चर रिकॉन्स्रक्शन कारपोरेशन के बलावा इन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए हम व्यावसायिक बैंकों और एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन के जग्य भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

चौथी योजना में प्रस्तावित प्रावधान

क्रम	प्रस्तावित प्रावधान करोड़ रुपये में
1 सिंचाई एवं विद्युत्	
2 कृषि कार्यक्रम	193.00
3 सहायता एवं सामाजिक विकास	24.00
4 उद्योग एवं लघु उद्योग विकास	7.20
5 यातायात एवं संचार व्यवस्था	7.40
6 सामाजिक सेवाएँ	11.30
7 विविध	66.70
योग	1.40
	313.00

1. पैमाना

इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि 25.40 करोड़ रुपये प्राथमिक जल वितरण योजना के लिए प्रस्तावित किया गया है, जबकि तीसरी योजना में केवल 3 करोड़ रुपये ही रखा गया था। इनमें से 10 करोड़ रु० एवं 100 नलकूप खोदने पर खर्च करने के लिए नलकूप समूहों को दिये जायेंगे। 4 करोड़ रुपये वषावत समिति क्षेत्रों में पैमाने के लिए कुएँ खोदने पर खर्च किया जायेगा। 11 करोड़ रुपये देशी क्षेत्रों में वाइप लाइन विद्युत पर व्यय किया जायेगा। ग्रामीण पैमाने की व्यवस्था करने के लिये 9.50 करोड़ रु० रखा गया है। इनसे राज्य के तीनों भागों में गनी उपलब्ध हो जायेगा।

2. विनियम

चौथी योजना के अन्त तक राज्य की विजली मण्डली व्यवस्थाओं की पूर्ति करने की योजना बनायी गयी है। योजना के अन्त तक 630 मेगावाट विद्युत् की माँग रहेगी, जिसे पूरा कर दिया जायेगा। इस योजना के अन्त तक 30 हजार कुओं की विद्युत् उपलब्ध करायी जायेगी।

3. लघु तथा उद्योग

लघु एवं उद्योग के निश्चित 7.4 करोड़ रुपये की रकम में से लगभग एक

करोड़ रुपये औद्योगिक सम्पदाओं एवं वस्तुओं को पानी, बिजली एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर व्यय नियंत्रित जायेंगे।

प्रदेश में विभिन्न खनिज सम्पदाओं की खोज पर लगभग 80 लाख रुपये व्यय किए जायेंगे। योजना में इस बात पर सर्वाधिक जोर दिया गया है कि प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा की खोज की जाय। उदयपुर में फ्लोराइट परियोजना पर 1.47 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त डेगाना में टंगस्टन सख्त तथा उदयपुर में फॉस्फेट सख्त स्थापित किये जायेंगे। औद्योगिक खनिज नियम के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

चौथी योजना में जोधपुर में एक नयी ऊनी मिल स्थापित की जायेगी तथा टोंक में चमड़े का कारखाना खोला जायेगा।

4 यातायात

इस योजना की अवधि में राज्य में सड़क निर्माण कार्य पर 12.66 करोड़ रु० व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। इसमें से एक करोड़ रुपये गाँवों में कच्ची एवं पक्की सड़क बनाने पर व्यय किए जायेंगे। लगभग 1.75 करोड़ रुपये राजस्थान महार क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य पर व्यय किये जायेंगे।

5 सामाजिक सेवाएँ

चौथी योजना में शिक्षा के विस्तार एवं उसको सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। इस योजना के दौरान 300 प्राथमिक, 200 माध्यमिक, 75 उच्च तथा 50 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की खोलने का प्रावधान किया गया है। सामान्य एवं तबनीकी शिक्षा पर कुल मिलाकर 16.25 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में चौथी योजना में 1,200 अतिरिक्त शैयाएँ स्थापित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त 200 शैयाओं की एक भ्रमणशील इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा पर 5.43 लाख रुपये तथा सायुर्वेद पर 16 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

राजस्थान की चौथी योजना की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, वह यथार्थ पर आधारित प्रतीत होती है। इस योजना में अर्थ-तन्त्र के उन पहलुओं पर पहली बार असाधारण ध्यान दिया गया है, जो अहमियत रखते हैं। सम्पूर्ण चौथी योजना का केन्द्र-विन्दु ग्राम है। ग्रहो माने में अर्थ-तन्त्र की नींव ही अब पड़ेगी, जबकि पानी व बिजली की उपलब्धि पर ध्यान दिया जायेगा, जो कि कृषि एवं उद्योग दोनों की बुनियादी आवश्यकताएँ हैं।

राजस्थान में नियोजन के २२ वर्ष

राजस्थान में नियोजन की प्रक्रिया का सुभारम्भ सन् 1951 में हुआ था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस समय तक राजस्थान का प्रशासनिक एवं वित्तीय एकीकरण भी नहीं हुआ था। नियोजन प्रक्रिया का अयन या जाना स्वयं में एक क्रान्तिकारी कदम था। परम्परा एवं सामन्तवादी व्यवस्था में से विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु आधुनिक नियोजन युग में प्रवेश, अर्थात् ज्ञान में एक साहसिक और आर्थिक परिवर्तन था। परम्परा से पोषित सामन्तवादी राजस्थान में शिक्षा का विस्तार सीमित था एवं सामाजिक कुरीतियाँ सचन फँसी हुई थी। आर्थिक क्षेत्र में तो लगभग निष्क्रियता एवं गतिहीनता की स्थिति थी। सबसे बड़ी जरूरत उस समय यह थी कि मानसून पर निर्भरता को खत्म किया जाय तथा कृषि उत्पादित को बढ़ाने के लिये आधुनिक प्रविधियों को अपनाया जाय। एक दूसरी बड़ी समस्या भूमि सुधार के उपायों का अंगीकार करने में जूझी हुई थी। मवाल यह था कि किस प्रकार स राजाओं, महाराजाओं और जागीरदारों के जंगल से भूमि को उसे उसके वास्तविक स्वामी, जेगी करने वाले किसान को सौंपा जाय। राजस्थान राज्य के यह स्थानीय लूटे परिषदी भाग के विवाद की समस्या भी उत्पत्ती हो महत्वपूर्ण थी।

यद्यपि लोकतन्त्रीय नियोजन के अनन्त विकास अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली होता है, तथापि निर्विवाद रूप से यह सचिक्त स्थायी होता है। विगत 21 वर्षों में कुल मिला कर 680 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। प्रथम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में 54, 103 एवं 212 करोड़ रुपया खर्च किया गया। तीन वार्षिक योजनाओं में 138 करोड़ रुपया खर्च हुआ तथा चतुर्थ योजना के प्रथम तीन वर्षों में 173 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इस समय तक व्यय रशि का बहुतांश अर्थात् 56 प्रतिशत व्यय एवं तिर्चाई पर किया गया। समाज सेवाओं एवं कृषि कार्यक्रमों पर क्रमशः 21 एवं 11 प्रतिशत खर्च हुआ। औद्योगिक विकास

के क्षेत्र में राज्य सरकार विभिन्न बनिबादों आंतरिक ढांचा बड़ा कर रही है। माम-
तीर पर औद्योगिक विकास का कार्य निजी क्षेत्र के हाथों में छोड़ दिया गया था।
जगले वर्ष में जो कि अत्यंत योजना का आगामी वर्ष है, लगभग 75 करोड़
रुपया व्यय होने की सम्भावना है तथा वर्तमान वर्ष में 64 करोड़ रुपया सम्भवतः
खर्च होगा।

साखान उत्पादन में वृद्धि और आत्म निर्भरता का लक्ष्य जिला सघन कृषि-
कार्यक्रम एवं सघन क्षेत्र कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया गया। ये कार्यक्रम उक्त स्थानों
पर शुरू किये गये, जहाँ पर कि बिचार्ड के लिये जल मुनिश्चित रूप से उपलब्ध था।
बड़ी, मध्यम एवं छोटी बिचार्ड परियोजनाओं द्वारा अधिक स अधिक भूमि में सिंचाई
वा विस्तार किया गया। ज्यादा भू-भंडार कर्मों वाले बीजों का इस्तेमाल किया
गया। खाद एवं अन्य कुमियाजों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग आरम्भ किया गया।
इन सभी मकीन उपकरणों के परिणामस्वरूप साखान उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
सन् 1951-52 में अनाज का उत्पादन जहाँ सिर्फ 29 लाख टन था, वह सन्
1960-61 में बढ़ कर 88 लाख टन के रिकार्ड-स्तर तक पहुँच गया। पशु-पालन के
क्षेत्र में प्रगति का लक्ष्य यह था कि छूत को बाधित न हो सके। उन्मुख किया जाय तथा
पशुओं की उच्च मूल्य-दर को कम किया जाय। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 199
पशु चिकित्सालय लघुवा इलाकों में खोले गये। ये चिकित्सालय सन् 1951 के पूर्व से
विद्यमान 141 चिकित्सालयों में आंतरिक व विदेशी स्तर पर सामूहिक अनुसंधान-
कारण की इकाईयाँ खोली गई। इनमें अलावा 139 क-ग्रोवग्राम सख (Key Village
blocks) तथा गांव पशु रक्षण फॉर्म स्थापित किए गए। जन-विकास के क्षेत्र में
अधिकांशतः दक्षिणी राज्यस्थान में निम्न कौटिकुन (degraded) भूमि का पुनर्वास करने
का तथा वैज्ञानिक विधि से पन खेतों के विस्तार का पर्याप्त सफल प्रयास किया
गया है।

छोटे किसानों की अधिक स्थिति के लिए उदयपुर, भरतपुर एवं झुजपुर
जिलों में विशेष कार्यक्रम तथा सीमान्त किसानों एवं भूमिहीन खतिहर मजदूरों के
लिये भीलागढ़ और अजमेर जिले में विशेष कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। जोधपुर,
जिलागढ़ और उदयपुर जिलों में मोन सुखी भूमि कृषि परियोजनाएँ (Dry land
farming) प्रारम्भ की गई हैं। मवाई पाषाणपुर जिले की टोडाभीष पंचायत समिति
एवं बोटा की लालपुरा पंचायत समिति में निचित भूमि के अधिकतम उपयोग की
दृष्टि में बहुत पैदावार परियोजनाएँ हाथ में ली गई हैं।

सोडतामिक विकेन्द्रीकरण के मामले में राजस्थान लक्षणी रहा है।
2 अक्टूबर, 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में ही हम गहन लोकतांत्रिक प्रतीक्षण का

भारत नृपा 1961 और पचासवें और 232 पचासवें समितियों अपने-अपने क्षेत्र के विभाग कार्य में लगी हुई है एवं उनके द्वारा ग्रामीण जनता में ग्रामीण विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए नई चेतना को जन्म दिया गया है। सहकारिता के क्षेत्र में ७८ सहस्रवर्षों कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 1962 कृषि ऋण समितियों के वार्षिक रूप में व्यवहार्य इकाई (viable) बनाने के लिये उन्हें पुनर्गठित कर दिया गया है। ऋण वितरण में प्रभावशाली प्रगति का अन्दाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि मध्य एवं मध्यम अवधि के ऋणों के वितरण की राशि जहाँ मन् 1970-71 में बढ़ाकर 16 करोड़ 73 लाख रुपये हाथी है। भूमि विकास बैंकों की प्रगति भी जो कि दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य करती है, उतनी ही प्रभावशाली एवं विविध होती है। इसके अलावा बचत और सहकारी बैंकों के पुनर्वास की और भी दृष्टि स्पष्ट दिखाने का रहा है। कृषकों को गोदाम सुविधाओं का प्रबंध करने के लिये भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। चीनी फैक्टरी, कच्चाई मिल, तेल मिल सहित विलासकर्मण प्लांट (Solvent extraction plant) जैसी बड़ी उद्योग इकाइयों का सहकारी स्तर में आविर्भाव रहा है, वस्तुतः चीनी की फैक्टरी में तो उत्पादन भी शुरू हो गया है।

विस्थापन के क्षेत्र में आसरा और चण्ड जैसी बृहत परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। पार ऐतिहासिक हिस्से का चेहरा बदलने वाली राजस्थान नहर का निर्माण कार्य प्राप्ति के पथ पर है। इन नहर के प्रथम चरण का निर्माण कार्य चौथी योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा। मन् 1971-72 में करीब-करीब दो लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई इसी नहर के द्वारा हुई थी और निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर यह उम्मीद की जाती है कि इस नहर द्वारा 12 62 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। अनेक बड़ी सिंचाई योजनाएँ, उदाहरण के लिये मरा-वाड, नर्मदा तथा निधमूल सिंचाई योजनाएँ इस समय विचारधीन हैं एवं विभिन्न स्तरों पर योजनाओं एवं बातों का प्रश्न जारी है। मध्यम स्तर की 48 परियोजनाएँ पूरा हो चुकी हैं एवं छ पर अर्थात् आसम, मेरालीडर, सेदुहाइवर्गन, जनपरा, गोपालपुरा एवं हरिश्चन्द्र नामक पर निर्माण कार्य प्रगति पथ पर है। मूल्य श्रोतों के विद्योहन के माध्यम से लघु सिंचाई कार्यक्रमों को गन्ध में विस्तृत स्थित गया। इस दिशा में राज्य स्तरीय प्रयासों को संस्थागत वित्तीय सहायता से सुदृढ़ता से पूरा करने के रूप में मदद की। इन समय लगभग १० लाख ०० सी० की 23 योजनाएँ चालू हैं। मन् 1951-52 में इन सभी श्रोतों में जहाँ 11 71 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होती थी वहाँ इस समय मन् 1971-72 में 26 31 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो रही है।

विद्युत क्षति एक उद्योगों का विकास परस्पर जुड़ा हुआ है। सन् 1950-51 में 8 MW फर्मे विद्युत क्षति उन्मुख थी तथा 42 लक्षों का विद्युतीकरण हुआ था। सिर्फ 168 पञ्जीकृत फेक्ट्रियाँ अस्तित्व में थीं। सन् 1971 में यह क्षति बढ़ कर 28 MW हो गयी थी एवं उद्योगों, राजस्वाम अल्प-शक्ति प्लांट तथा जवाहर सागर परियोजना की दूसरी एवं तीसरी इकाई चालू होगी, विद्युत क्षति की मात्रा बढ़ाकर 458 MW तक पहुँच जावेगी। चालू होने वाली बड़ी परियोजनाओं में पञ्जाब की भाखरा नावल, मध्य प्रदेश की सतपुड़ा, गायी सागर एवं राणा प्रताप सागर तथा राजस्थान में जवाहर सागर की प्रथम इकाई उल्लेखनीय है। पञ्चम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में व्याप्त साक्षरता में विद्युत मिलने शुरू हो जायगी। व्याप्त सागर परियोजना पूरी हो जाने पर राजस्थान नहर की अप्रवाहित रूप से पानी मिलेगा। सन् 1950 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जहाँ सिर्फ 3 यूनिट (KWH) था, वह 1971 में बढ़ाकर 45 यूनिट हो गया है। अधिक बिजली उत्पादन के साथ-साथ उसके संचरण और वितरण को भी उच्च प्राथमिकता दी गयी थी। सन् 1971 में राज्य में कुल मिला कर 2240 पञ्जीकृत फेक्ट्रियाँ थीं। विद्युत क्षति का अधिकांश उद्योगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, किन्तु कुछ वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुओं की विद्युत-मय बनाने तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये बिजली की माग तेजी से बढ़ती आ रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण-वायकर्म 6 अक्टूबर 1971-72 के अन्त तक 4168 स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है एवं 48389 कुओं द्वारा बिजली का उपयोग किया जा रहा है। अन्तिम में लगभग 20,000 कुओं एवं 1000 ग्रामों को प्रति वर्ष विद्युतीकृत किया जायेगा।

तीव्र औद्योगिक विकास के लिये विशेष प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भूमि सस्ता पानी एवं बिजली कुओं में छूट तथा उद्योग शक्तों पर छूट आदि देकर औद्योगिकरण को गति को तीव्रता प्रदान की जा रही है। इन समय 15 औद्योगिक क्षेत्र एवं 11 औद्योगिक एस्टेट्स (Industrial Estates) क्षेत्र आदि आवश्यक सुविधाओं सहित सुरुज हैं, जिसमें कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सके। राजस्थान औद्योगिक एवं अन्तिम विकास निगम की स्थापना दली दृष्टि से की गई है कि औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले तथा उनमें नवानता का प्रचार हो। यह निगम सुरुज क्षेत्र परियोजनाओं में भी काम लगे लगा है तथा क्षेत्र ही चार परियोजनाओं का कार्य शुरू होने वाला है। नाव्यविक क्षेत्र में इन समय प्रमुख कारखाने ये हैं ऊन मिल-बीकानेर, खनडी लोहा परियोजना, जिर स्लेटर उदयपुर, मसौन टून्स फेक्टरी खजमर, प्रेसीडेंट उपकरण फेक्टरी कोटा, एवं सोडियम सल्फेट प्लांट डीडवाना। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने राज्य में

क्षमलब्ध स्रोतों के विद्योहन में पर्याप्त सहायता दी है। हाल ही में 16 जिलों को चुना गया है, जिन्हें कि सत्यामत वित्तीय अभिकरणों द्वारा नई इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष छूट प्रदान की जायेगी। अलवर, जोधपुर, उदयपुर, नील-साहा, नागौर तथा चूरु जिले का औद्योगिक दृष्टिकोण से, सबसे पिछड़े हुए जिलों के रूप में चयन किया गया है तथा इन जिलों को भारत सरकार द्वारा तत्काल ही पूर्ण विनियोजन पर दान प्रतिशत अनुदान (Subsidy) दिया जायेगा। यह इम्प्लाइड इन इकाइयों को भी दी जायेगी, जिनका कि पूर्ण विनियोजन पचास लाख रुपये तक है। यह विनियोजन वाली इकाइयों पर भी बरीयत के आधार पर इस अनुदान के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय वित्तीय सत्यामतों के अतिरिक्त राजस्थान वित्त निगम भी एक एच मध्यम श्रेणी के निजी क्षेत्र इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। खनिज क्षेत्र में, खनिज भण्डारों के विद्योहन के लिये विभिन्न छूटों एवं संपन पर्यवेक्षण द्वारा प्रयास किए गये हैं। रॉक-फास्फेट के विशाल भण्डारों की खोज व साथ-साथ इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्तमान में इसका दैनिक उत्पादन 800 टन है तथा सन् 1972-73 में अन्त तक यह 1500 टन हो जायेगा।

यह अनुभव करते हुए कि परिवर्द्धन सुविधाओं का विकास, विद्यमान वित्तीय विधियों से अधिकतम लाभ उठाने के लिये आवश्यक है, राज्य-सरकार ने सड़कों के विस्तार को भी प्राथमिकता दी है। सन् 1950-51 में राज्य की सड़कों की लम्बाई 17339 कि० मी० थी, वहीं सन् 1971-72 में बढ़ कर 32052 कि० मी० हो गई है। इस दिशा में मध्य दृष्टिकोण यह रहा है कि गाँवों-कस्बों, एवं शहरों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ दिया जाय। जब तक हमारे पास तीव्र गति में बढ़ते वाले वाहन नहीं होंगे, अर्थात् टर्बो-वासे नहीं होंगी सड़कें स्वयं में अपर्याप्त हैं। सन् 1970 के अन्त तक 90 हजार मैनवायर्स वाहन इन सड़कों पर दौड़ रहे थे।

समाज सेवा व क्षेत्र में जहाँ सन् 1951-52 में 1-11 आयु वर्ग के सिर्फ 10.6% विद्यार्थी पाला जा रहे थे वहीं सन् 1971-72 में 58.1% हो गयी है। हम मार्क्सवादीक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने को दिना म तभी से आज बढ़ रहे हैं। 30000 श्रमदा उससे अधिक आवासीय वाले प्रत्येक गाँव में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, एवं प्रत्येक पंचायत समिति में एक या एक से अधिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हो चुकी है। कॉलेज शिक्षा की सुविधाओं का सभी जिलों तक विस्तार कर दिया गया है। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए आचारण प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में इस समय 5 विनिर्वा महाविद्यालय, 2 आर्गुबेडिक महाविद्यालय, 3

अभिप्रेत महाविद्यालय, 4 कृषि महाविद्यालय, 1 पशु चिकित्सालय महाविद्यालय तथा 6 पारिटेक्निक विद्यालय हैं। इनके अलावा राज्य भर में अनेक प्रशिक्षण संस्थायें भी प्रचालित हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्य ध्यान छुड़ाछूट की बीमारियों के नियन्त्रण एवं सम्मूलन की ओर दिया गया है। सारे राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं दवाखानों का जाल सा बिछा दिया गया है। विशाल रूप में ग्रामीण अंचल में व छहूरी क्षेत्रों में आन्तरिक (Internal) चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार किया गया है तथा विशेषज्ञ सेवाओं तथा शल्य चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ है। पिछले 21 वर्षों में 224 एलोपैथिक चिकित्सालय एवं दवाखाने खोले गये हैं तथा 8543 नवीन रोग शैयाएँ बढ़ा दी गई हैं। इस प्रकार सन् 1950-51 में जहाँ चिकित्सालयों एवं रोग शैयाओं की संख्या क्रमशः 390 एवं 5720 थी, वहीं सन् 1917-72 में बढ़ कर क्रमशः 614 एवं 14263 हो गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्तित्व में आ चुके हैं। परिवार नियोजन के कार्य की लोकप्रिय बनाने तथा उसकी सुविधाएँ बढ़ाने के लिये 330 परिवार नियोजन केंद्र खोले गये हैं, मरदादा यामोन राओ ने ही 1500 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं एवं उसकी संख्या 346 से बढ़ कर 1846 हो गई है। प्रपंच धर्म के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रोगी संख्याओं की संख्या 343 है। विगत 21 वर्षों के निवीजित विषयों के दौरान 116 बस्तियों की निस्साक्षित (Filered) जल की सफ़ाई की गई है तथा २६1 ग्रामीण मल योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। यह निर्णय लिया गया है कि सन् 1961 की जनगणना के आधार पर जिन गांवों की जनसंख्या 5,000 या उससे अधिक है उनमें मल पानी योजना प्रारम्भ कर दी जाय। इसी प्रकार से जिन गांवों की संख्या 2000 से 5,000 के बीच में है, उनमें पम्प एवं तालाब योजनाओं को लागू किया जा रहा है, तथा 200 से कम आबादी वाले गांवों को कुओं से मल दूर पानी देने की योजना कार्यान्वित की गई है। यह जाना की जाती है कि स्थूलतम विनियोजन वरके पान माधरन की पयादा फादा षट्पयादा जा संवेया। यह जाना की जा रही है कि सन् 197-74 के लान एवं राजसमान ॥ सभी बस्तियों में निस्साक्षित (Filered) जल की सफ़ाई हो सकेगी। समाज के दुर्बल वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए छात्रवृत्तियों छावादास सुविधाओं एवं अवन तथा कुओं के निर्माण के लिये विशेष महत्त्वता का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य मल मूत्र सठाने की दुराई को सामूल रूप में लपट करने के लिये धनसफल है। गाँवों पताब्दी समारोह वर्ष ॥ दौरान कम दिशा में एक वृहत् कार्यक्रम दाय में लिया गया था। हरिजन वर्गों के विद्यार्थियों एवं वाटर स्टैंड ५ स्टेशन की स्थापना का भी एक कार्यक्रम

हाथ में लिया गया था तथा हरिजनो की भवन निर्माण के लिये भी सहायता प्रदान की गई थी। श्रम कल्याण गतिविधियों की कल्याण केन्द्रों की स्थापना द्वारा एवं मजदूरों की जीवन। दशाओ की सुधारने के लिए नये आयाम प्रदान किये गये। 17 राजगार कार्यालय खोले गये और इन प्रचार इनकी सरप्रा वड नर 22 हो गई है। भवन निर्माण का विविध योजनाओं का अन्तर्गत तथा निगम द्वारा गुम्भ की मरू वडी घन राशि के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति अपने घर का निर्माण करवा सके हैं तथा भवन निर्माण प्रमण्डल की सस्था की स्थापना के माय माय और उपाय लागू आने लिए मकान बनवा सकेंगे।

बरोजगारी की समस्या

स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व सत्ता प्रतिष्ठानों पर अधीन किसी व्यक्ति को इस बात की चिन्ता नहीं थी कि हर एक आदमी को रोजगार मिला हुआ है या नहीं। पञ्चदशवीं योजनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार अवसरों का व्यापक विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ बरोजगार लोगो की मरदा भी लगातार बढ़ती जा रही है। कामों के मुकाबले में रोजगार पाने के उम्मीदवारो की मरदा तेजी के साथ बढ़ी है। इन समस्या का हल न सिर्फ जनसंख्या नियन्त्रण द्वारा किया जा रहा है बल्कि आर्थिक विकास के ढाँचे में भी आवश्यक समायोजन करके भी किया जा रहा है, आगामी कुछ वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष रोजगार अवकाश स्वयं नियोजन की सुविधाये तेजी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि ग्रामीण नियुक्तिकरण का तेजी से विकास हो रहा है क्षतिज सम्पदा का संगठित रूप से विप्लव हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है कृषु उद्योगो एवं ग्रामीण उद्योगो का प्रोत्साहन मिल रहा है, सड़को, भवन कुम्भो एवं नहरों का निर्माण किया जा रहा है तथा विविध प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास हो रहा है। इन बीच के समय में राज्य सरकार बेरोजगारी की समस्या की ओर पूर्ण ध्यान दे रही है। इसीनिर्वाह स्वातन्त्र्य स्थापना एवं डिप्लोमा प्राप्तिकर्त्ताओं की समस्या को सुलझाने के लिये 1,000 व्यक्तियों की एक सूची तैयार की गई है। इन इजितयध की विविध विभागो एवं विभागों के कार्यानुभव प्राप्त हो रहा है। 150 इजितयधो एवं डिप्लोमा प्राप्तकर्त्ताओं की उद्योगो में प्रशिक्षण देने के लिए आर्थिक छात्रवृत्ति योजनाओं शुरू की की गयी है। एक नवीन के द्रीय सेक्टर योजना भी हाथ में ली गई है तथा उसे आर० आर्द० एम०, टी०, सी० आर० एफ० सी० एवं आर० एस० आर्द० सी० द्वारा लागू किया जा रहा है। इन योजना के पांच भाग हैं, उदाहरण के लिए साम्य (Equality), तकनीकी महत्कारिता आवश्यक एस्टेट्स औद्योगिक एस्टेट्स एवं स्वदेशी गरीबो का किराया कृप। हाल ही में भारत सरकार ने एक विशेष रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है जिससे कि 1 26 करोड़ रुपये

भारत सरकार द्वारा प्रगन किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुएँ सेवा केन्द्रों, राइको एवं नालियों का निर्माण एवं सुचारु, गद्दी बस्तियों की सफाई एवं सर्वेक्षण तथा बाघ की वृद्ध योजनाएँ हाथ में ली हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण स्वनिर्धारण सर्वेक्षण का भी एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है तथा इस सर्वेक्षण के लिये दार्जिलिंग तथा कोलपुर जिलों को चुना गया है। छावनों की स्वयं रोजगार पाने में सहायता देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन चुनिन्दा क्षेत्रों में दिया जा रहा है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के रोजगार प्रदान करने एवं रोजगार पाने की क्षमता को क्षाधिकता को बढ़ा रही है और अब उन्हें अब तक रोजगार नहीं मिल जाता वह सब वर्ग (Stupid) मिलती रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्र में नये रोजगारों की रचना के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक कक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन हर जिले में दस माह के लिये 1,000 व्यक्ति को आफ जीवन प्रत्येक दर पर काम मिलेगा। लगातार अनाज वित्तित करने के लिये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (Rural work programme) हाथ में लिया गया है। राज्य के उन दस जिलों में जहाँ पर निवारण अनाज की स्थिति पैदा होती रहती है, 20 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। हर एक जिले में बोधी योजना के दौरान दस करोड़ रुपये खर्च होगा। इस कार्यक्रम के अधीन अनाज राशन के समुदायों का पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है तथा ऐसे उत्पादनमूलक कार्यों को हाथ में लिया जा रहा है जो कि उप क्षेत्र की जनसंख्या को मजदूरी देने के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर भी पैदा करेगा।

राजस्थान की पैंतची पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारम्भ अप्रैल 1951 में हुआ था। आज हम पंचवर्षीय योजना के मध्य काल में हैं। प्रारम्भ सफल एवं बहुमुखी विकास कार्यक्रमों से किया गया था और आज राज्य का सम्पूर्ण आर्थिक जीवन नई दिशाओं में विकसित हो रहा है। विकास के एक नये दौर में से हम गुजर रहे हैं। सती, कारखानों एवं जंगलों का विकास हो रहा है, नई रोजगारीय प्रतीक आगे और परिलक्षित हो रहे हैं।

आधुनिकता एवं प्रगति की दिशा में तेज गति से बढ़ते हुए इन बदलों के बावजूद भी राजस्थान राज्य देश के अपेक्षाकृत पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर जाता है। प्रति व्यक्ति मिलती की वजह से राष्ट्रीय सदन दर की 50% से भी घटती कम है। राज्य में हर वर्ष में भी वार्षिक भूमि के 22 प्रतिशत हिस्से में गिराई की सुविधा है, जबकि राजस्थान में सिर्फ 17 प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती

है। प्रति व्यक्ति बैंक में जमा राशि एवं बैंक द्वारा दिये गये ऋण की दृष्टि से भी राजस्थान का स्थान देश में सबसे नीचे आता है। सड़क एवं रेल यातायात की दृष्टि से भी हम राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता प्रतिशत 1971 की जनगणना के अनुसार 29.3 प्रतिशत है। जबकि राजस्थान का 8.8 प्रतिशत है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राजस्थान निरन्तर सूखे और अकारण से आक्रान्त रहता है एवं लगभग प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्य के किसी न किसी हिस्से में उसे अकाल का अस्तित्व रहता ही है।

अतः यह जरूरी है कि राजस्थान को पाँचवी योजना साक्षी हो। यदि सन् 1974-79 के दौरान राज्य की विकास दर को 7% तक ले जाना है तो लगभग 2,100 करोड़ रुपया खर्च करना आवश्यक होगा और फिर भी सन् 1978-79 में प्रति व्यक्ति आय की दर चौथी योजना के अन्त तक की अनुमानित 146 रु० की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की दर से कुछ कम ही रहेगी। वार्षिक एवं सामाजिक विकास की गतिविधियों में नये प्राच फूलने के लिये तथा निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रयास जारी रहेंगे।

(1) विकास की गति को तीव्रतर रूप प्रदान करना, जिससे कि राजस्थान एवं छोट राज्यों के मध्य की विकास की अवस्थाओं में जो अन्तर है, उसे पाटा जा सकता है।

(2) आय एवं सम्पत्ति के वितरण में विद्यमान असमानताओं को कम करना तथा इन बात को मूर्तिस्थित पर लगा कि विकास के सुफल समाज के अश्वेतकृत दुर्बलतम एवं दमिस्तत वर्गों को प्राप्त हो सकें।

(3) रोजगार के नये अवसर पैदा करना।

(4) दरिद्रता-रेखा से भी नीचे के जीवन-स्तर में रहने वाले जन समाज के जीवन-स्तर में गुणा भूक परिवर्तन लाना तथा उसे उर्वरमूली बनाना, जीवन के कुछं अन्विकार क्षेत्रों में जनता की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने की प्रयासमृति प्रदान करना।

उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित ब्रह्म उठाते पढेंगे:—

(i) जन क्षेत्रों की पहचान की जाय जो कि विनियोजन करने पर अल्पतम समय में अधिकतम फायदा दे सकें, जिससे कि राज्य को अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत मजबूत बन सके। इसके लिये यह भी आवश्यक होगा कि उन क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रयास किये जाएं तथा उनमें समुचित विनियोजन दिया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सविज्ञो एवं वस्तु पालन की क्षमताओं के विकास पर विशेष और देना पड़ेगा।

साथ ही कृषि में उत्पादन की बढ़ोतरी एवं अन्य सम्बन्ध क्षेत्रों के विकास पर भी खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। राज्य की विविध औद्योगिक स्थितियों के साथ अनुकूलता का ध्यान रखते हुए विकास की नई तकनीक एवं प्रणालियों को अपनाया जायेगा। अतः सूखी खेती (Dry farming) पद्धतियों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिये निःशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार से पशु चालन के क्षेत्र में पशुओं की नस्ल अच्छी उठाने सम्बन्ध पर विविध ध्यान देना पड़ेगा।

(ii) ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम को विराट स्तर पर हाथ में लेना पड़ेगा जिससे कि लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सके तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का व्यापक ढांचा तैयार हो सके।

(iii) ऐसे कार्यक्रमों की रीति में रुझान उठाने जाय कि जिससे ग्रामीण जनता की क्षमताओं का उपयोग प्रभावी ढंग में पूरी हो सके। बुनियादी भूमतम आवश्यक पूर्ति करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों के जीवन-स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाया जाय।

(iv) राज्य के विविध समस्याग्रस्त क्षेत्रों को पहचाना जाय एवं उनके विकास के लिये विशेष प्रोजेक्ट तैयार किये जाय।

(v) जनसांख्यिकी को कम करने के लिये आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक कदम उठाये जाय।

(vi) प्रशासनिक मशीन को पुनर्गठित किया जाय। सरकार की प्रायोजन निर्माण योजना को मजबूत बनाया जाय, जिससे कि योजना कार्यक्रमों का ज्यादा अच्छी तरह से लागू किया जा सके। राज्य क्षेत्र के बाहर से अधिकतम सम्भावित वित्तीय सहायता को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिये।

पंचवर्षीय योजना III अन्तर्गत लागत प्रतिशत निम्नानुसार होना चाहिये:-

क्रमांक	विकास की मद	पंचवर्षीय योजना का लागत व्यय प्रतिशत	पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित लागत व्यय प्रतिशत
1	कृषि कार्यक्रम	8.1	13.00
2	महानगरिता एवं शहरीकरण	2.9	1.9
3	मिनी विकास एवं मिचलाई	60.2	59.8
4	उद्योग एवं खनिज	2.5	4.5
5	यातायात एवं सड़क-बाहुन	3.0	4.5
6	सामाजिक सेवाएँ	22.9	15.0
7	विविध	0.4	1.3
	योग	100.00	100.00

राज्य योजना की ८८५ राशि 775 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है। यदि 600 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त हो जावे तो भी कुल विनियोजन राशि का निम्न 36% ही पूरा हो सकेगा। स्मरण रहे कि चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता की राशि 220 करोड़ रुपये थी।

दरिद्रता एवं पिछड़ेपन की समस्या से हर मोर्चे पर लड़ना आवश्यक है। राज्य में कुछ एग क्षेत्र हैं—उदाहरण के लिये गणेशपुर नहर परियोजना एवं चम्बल परियोजना, जो कि वैज्ञानिक एवं कृषि-सहायक ढंग से प्राकृतिक स्रोतों को जुटाने पर राज्य को विशेष उत्साह की दिया। ये भरे बड़ा सक्ती है। राजस्थान नहर परियोजना की पूर्णता, गमानगर, बोकानेर तथा जेम्सपुर जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र व्यापारिक बन गये। यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग एक लाख किसान परिवारों को सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से कान्हा एवं बूंदी जिले का सम्पूर्ण एग हजार वर्ग मील का चम्बल परियोजना क्षेत्र बहुमुखी विकास की राह प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार में वित्तीय नीति बहुत ही सीमित है, जो वह बाह्य सहायता की प्रतीक्षा में रहती है। उदाहरण के लिये विशेष रूप से एक अन्तः-राष्ट्रीय अभिकरणों तथा भारत सरकार द्वारा उदार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रहा है।

राज्य के मध्य-पश्चिमी एवं आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये भी विदेशी प्रयत्नों की आवश्यकता है, जिनसे कि लोगों को रोजगार मिल सके तथा उन क्षेत्रों की बुनियादी संरचना विकसित हो सके। मध्य-पश्चिमी क्षेत्र के लिए, आदिवासी विकास, भेड़ पालन, पशुओं का नस्ल सुधार, नव विस्तार एवं भू-समृद्धि जल विकास के लिये एक नूतन योजना तैयार की जा रही है। आदिवासी जनता के लिये एक वृहत सामाजिक विकास योजना की तैयारी विचारार्थ है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राप्त करने का कोशिश की जावेगी—

- (i) जनसंख्या का नियंत्रण
- (ii) जीवन की उम्मीद में वृद्धि करना,
- (iii) बालकों में छात्र प्रवेश हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना,
- (iv) छात्रावास एवं छात्रवृत्तियों के रूप में शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना।
- (v) आदिवासी क्षेत्रों के कृषिगत एवं औद्योगिक विकास के आन्तरिक ढाँचे का प्रावधान करना।

(vi) एक ऐसी मशीनरी की स्थापना करना जो कि आदिवासी जनता की सुन्दरमेवासी की समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान कर सके।

विशेषतः आर्थिक दृष्टि से समृद्ध शोको द्वारा आदिवासियों को गैर कानूनी ढंग से भूमिहीन बना देने की गति से उत्पन्न होने वाले मुकदमों को निपटने के लिये इन प्रकार की सहायता आवश्यक है।

उपयुक्त सभी योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य सरकार के पास बहुत ही सीमित वित्तीय स्रोत हैं, इसलिए राज्य योजना के अलावा भी भारत सरकार एक अन्य समस्याओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

यह गेजो के साथ सहसूस किया जा रहा है कि आर्थिक उन्नति को सामाजिक न्याय से अलग नहीं किया जा सकता है। योजना आयोग ने पाचवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में यह संकेत दिया है कि निम्नलिखित सात ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सामाजिक सेवाओं का प्रावधान तत्क्षिप्त इन क्षेत्रों में विकास के लिये आन्तरिक ढाँचा प्रदान करेगा, बलित ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में भी गुणात्मक सुधार लायेगा —

(i) प्राथमिक शिक्षा।

(ii) परिवार नियोजन एक बालको को पोषाहार के साथ सयुक्त सर्व-जनिक स्वास्थ्य की सुविधाएँ।

(iii) ग्रामीण जल प्रदाय का प्रावधान।

(iv) गाँवों में सड़कों।

(v) भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थलों का प्रावधान।

(vi) ग्रामीण विद्युतीकरण।

(vii) गरीब भूमिों का सुधार।

उपयुक्त मान क्षेत्रों में विकास आधार अत्यधिक कमजोर होने के कारण राजस्थान में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से इन सामाजिक सेवाओं के विकास के स्तर को ऊँचा उठाया जास तीर से बहुत ही मूर्खिक काम है। फिर की उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार 506 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित किया गया है जैसा कि पृष्ठ 630 पर दी गई तालिका से स्पष्ट है।

उस न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यक्रम को सम्पादित करने के लिये जितनी धन राशि की आवश्यकता पड़ेगी, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यह बासा भी की जानी है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर शुरू की जायेगी। उदाहरण के लिये कृषि में समन्वित शोध के अखिल भारतीय कार्यक्रम उच्च राष्ट्रीय मार्ग (National High Way) विशेष योजना कार्यक्रम एस एच डी ए,

क्रमांक	मद	लक्ष्य	आवश्यक धन- राशि की मात्रा (करोड़ों में)
1	प्राथमिक शिक्षा	1975 तक 6-11 आयु वर्ग में लड़कों का शत प्रतिशत स्कूल प्रवेश। सन् 1978 तक 6-11 आयु वर्ग की लड़कियों का शत प्रतिशत स्कूल प्रवेश, सन् 1978 तक 11.14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का 50% स्कूल प्रवेश।	226
2	सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ	80 हजार से एक लाख तक की आबादी के लिये एक 8 या 8 से 10 तक उप रेगुलरी सप्लाय एक पूर्ण मुक्तिरत सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना, प्रत्येक केन्द्र में वर्तमान छ रोगी रोगियों के स्थान पर 25 रोगी रोगियों का प्रावधान।	11
3	ग्रामीण सड़कें	1500 एक उससे अधिक आबादी वाले समस्त ग्रामों तक सभी मौसमों की सड़कों का निर्माण।	100
4	ग्रामीण जल प्रदाय योजना	सन् 1978-79 तक सभी ग्रामों की पैय जल उपलब्ध करना।	116
5	भूनिहीन मजदूरों के लिये आवास स्थल	इस योजना के अन्तर्गत एक लाख बर्तींग हजार परिवारों को फायदा पहुँचाया जायगा।	3
6	ग्रामीण बिजलीकरण	40% ग्रामीण जनता को बिजली प्रदान करना।	48
7	गरीब वस्तिवर्गों का सुधार	इसके अन्तर्गत जयपुर में 30 हजार परिवारों को लाभ पहुँचेगा।	2
योग			506

एक ए एल, अकाल पोखित क्षेत्र कार्यक्रम, रोजगार की कंस योजना, केन्द्र क्षेत्र सखी, सहकारी समितियों एवं ग्रामीण बिजलीकरण नियम के माध्यम से कृषि प्रदान करना इत्यादि कार्यों से एक हजार छियासी करोड़ रुपये जुटाने की आशा रखते हैं।

संस्थागत वित्त एवं निजी क्षेत्र विनियोजन को बाधित करने की योजना भी सम्भवतः 300 करोड़ रुपये का विनियोजन करवा सकेगी।

ये सारे के सारे विनियोजन सिर्फ तभी सम्भव हो सकेंगे, जबकि राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंको से धन राशि के प्रवाह को तेज किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सामयिक ऋणदायि सस्याओ एवं भारत सरकार की ओर से पिछड़े हुए राज्यों को उप-युक्त नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से पिछड़े हुए राज्यों को दी जाने वाली अधिक सहायता में तेजी लानी होगी। राजस्थान सरकार ने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सहायता के आवंटन की कसौटी ज्यादा व्यापक होनी चाहिए और आवंटन करते समय राज्यों में आम पिछड़पन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पाचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवश्यकताओं एवं सम्भाव्य क्षेत्रों की योजना होगी एवं समन्वित क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को लागू करने की तैयारी करनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा विकास के लिये विस्तृत जिला योजनाओं के निर्माण की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा, जिससे कि क्षेत्रीय कार्यक्रमों (रेग्योरियल प्रोग्राम) को अधिक सावधानी के साथ कार्यान्वित किया जा सके एवं साथ ही जिला योजनाओं एवं कार्यक्रमों में रूढ़िवादों की विकास सम्भावनाओं का प्रतिबिम्बित किया जा सके। इसी उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए आकड़ा संग्रह एवं प्रायोजना निष्पन्न (प्रोजेक्ट निरूपण) एक वृहत् मशीनरी संगठित की जा रही है।

राज्य सरकार ने एक राज्य योजना प्रमण्डल की स्थापना का निर्णय लिया है जिससे कि योजनाओं के निरूपण एवं कार्यान्वयन में राज्य सरकार को परामर्श मिल सकेगा।

मजदूरी एवं उत्पादितता

(Wages and Productivity)

किसी उत्पादन साधन के पड़त-उत्पादन (input-output) अनुपात (ratio) को उस साधन की उत्पादितता (productivity) कहते हैं। उदाहरणार्थ, धम की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन-कार्य में लगाने पर कितना धमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि होने पर उत्पादन में यदि अन्य बातों के समान रहने पर, वृद्धि होती है तो यह कहा जा सकता है कि धम की उत्पादितता (productivity) में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार उत्पादितता किसी उत्पादन साधन की कार्य-क्षमता अथवा समस्त साधनों की सम्मिलित कार्यक्षमता में वृद्धि का एक माप-दण्ड है। किसी भी उत्पादन संस्था के लिए इस माप दण्ड का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके आधार पर ही वह अपने उत्पादन-फलन (Production Function) में उत्पादन के विभिन्न साधनों के समन्वय के सम्बन्ध में आवश्यक नीति निर्धारित करती है।

मजदूरी और उत्पादितता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मजदूरी धमिक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का प्रतिफल है और धम-उत्पादितता उस प्राप्त की गई मजदूरी के बदले में दी गई सेवाओं का परिणाम है। अतः यह स्पष्ट है कि मजदूरी-वृद्धि एक ऐसी आर्थिक प्रेरणा है, जिसके प्राप्त होने पर ही धमिक अपनी उत्पादन क्षमता या उत्पादितता में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित होता है।

विकसित देशों में, जहाँ लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मजदूरी प्राप्त होती है, धमिकों की उत्पादितता में वृद्धि करने के लिए आर्थिक प्रेरणाओं (मजदूरी तथा अन्य मौद्रिक लाभ) का महत्व कम होता जा रहा है,

किन्तु अविकसित तथा विकासशील देशों में इन प्रेरणाओं का आज भी विशेष महत्त्व है। गद्दी कारण है कि मजदूरी वृद्धि तथा उत्पादित वृद्धि की प्रवृत्तियों में स सम्बन्ध स्थापित किया जाता है और मजदूरी-दरों या दूसरे शब्दों में, प्रति श्रमिक आय में वृद्धि होने पर यह अपेक्षा की जाती है कि उसकी उत्पादित में भी वृद्धि हो। इस आधार पर नीचे के शब्दों में भारत में श्रमिकों की मजदूरी तथा उनकी उत्पादित की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है।

औद्योगिक मजदूरी (Industrial Wages)

प्रत्येक देश में मजदूरी नीति का उसके सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप मजदूरी-नीति का निर्माण एवं विवास करने के लिए मजदूरी निर्धारण, मजदूरी-स्तर, मजदूरी संरचना तथा मजदूरी सुरक्षा की समस्याओं को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है।

मजदूरी निर्धारण

भारत में स्वतन्त्रता संग्राम के अन्तिम चरण तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रारम्भिक वर्षों के दौरान जपनी आर्थिक दबावों में सुधार लाने के लिए औद्योगिक श्रमिकों को मजदूरी वृद्धि के लिए सक्षम करना पड़ा। परन्तु मजदूरी वृद्धि के प्रश्न को लेकर अनेक संघर्ष हुए। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप उक्त अवधि में कई लाख अम-दिन (1947 में 166 लाख 1948 में 78 लाख, 1949 में 66 लाख तथा 1950 में 126 लाख) गंत हुए, गए जिसमें धर्म की उत्पादित जो पहले ही कम थी, और भी कम हो गई।

सन् 1950 के पश्चात् श्रम संघर्षों एवं विवादों की संख्या में तो यद्यपि कोई कमी नहीं हुई, किन्तु 'औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, 1948 (Industrial Disputes Act, 1948) के पास हो जाने के पश्चात् समझौता तथा मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था होने से औद्योगिक संघर्षों के बहुत दिन चलने की सम्भावनाएं कम हो गई। इसी समय इन संघर्षों में शारस्त्रीयक विवादों पर अन्तिम निर्णय देने के लिए विभिन्न राज्यों में औद्योगिक ट्रिब्यूनल भी स्थापित किए गए। इन व्यवस्थाओं का परिणाम यह तो अवश्य हुआ कि शीघ्र निर्णय लिए जाने से श्रम घंटों की हानि तो कम हो गई, परन्तु श्रमिकों की आर्थिक स्थिति गंवावत बनी रही। अतः इस दिशा में रचनात्मक कदम उठाने के लिए सन् 1948 में एक 'मजदूरी समिति' (Wages Committee) नियुक्त की गई, जिसमें सरकार श्रमिकों तथा नियोक्ताओं (employers) के प्रति-

निधि थे। इस समिति का उद्देश्य श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी निर्धारित करना था। देश में व्यापक औद्योगिक मण्डलों की दूर करने के लिए इस समिति ने यह सुझाव दिया कि इस समस्या का तत्कालीन हल श्रमिकों की 'उचित मजदूरी' देने की व्यवस्था करना है।

उचित मजदूरी से आशय मजदूरी की कम राशि से था जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (minimum wage) से कम न हो। इस समिति का इस सम्बन्ध में यह सुझाव भी था कि उचित मजदूरी प्रत्येक उद्योग की भुगतान क्षमता उस क्षेत्र में विभिन्न तुलनात्मक पेशों एवं व्यवसायों तथा अन्य क्षेत्रों में उसी प्रकार के उद्योग में प्रचलित मजदूरी दरों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये। परन्तु प्रारम्भ में औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा तथा पंच निर्णयों में इन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विभिन्न ट्रिब्यूनल द्वारा इस सम्बन्ध में जो निर्णय दिये गए, उनमें उद्योग की मजदूरी-भुगतान-क्षमता, देश की अर्थ-व्यवस्था में उन उद्योग के स्थान, राष्ट्रीय भाव के स्तर अथवा श्रम की उत्पादितता जैसे घटकों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

उक्त स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकी। औद्योगिक ट्रिब्यूनलों ने उचित मजदूरी की माँग का समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया। कानून अल्पुमिनियम बिल, वेतन तथा उसके श्रमिकों के मध्य सवर्ग के मिलविले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय में यह स्पष्टतः कहा गया कि यद्यपि औद्योगिक निर्णयादेश (adjudication) देते समय अनेक सिद्धान्तों, जैसे तुलनात्मक मजदूरी का सिद्धान्त, व्यापार अथवा उद्योग की उत्पादितता, जीवन स्तर तथा उद्योग की भुगतान क्षमता, को ध्यान में रखा जाता है, किन्तु यदि कोई उद्योग-पूषक मजदूरी का भुगतान करने में भी असमर्थ है तो उसे जीवित या विद्यमान रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी निर्णय में मजिस्ट्रेट के निदेशक सिद्धान्तों (Directive Principles of the Constitution) पर बल दिया गया और यह कहा गया कि श्रमिकों को जीवन-निर्वाह मजदूरी दिलाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिये। अन्य मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन निर्वाह न्यूनतम मजदूरी को अवधारणा स्थिर नहीं है। यह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। बाद में महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए मजदूरी-दर निर्धारित करने के लिए जिन मजदूरी बोर्डों की स्थापना की गई, उनके द्वारा भी इसी सिद्धान्तों का समर्थन किया गया। सन् 1948 में पारित किए गए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (The Minimum Wages Act, 1948) भी अनेक उद्योगों के असंगठित श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने में सहायक हुआ।

मजदूरी-स्तर (Wage Level)

उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कुछ ही वर्षों में सामान्य मजदूरी स्तर में तीव्र वृद्धि हुई। यद्यपि बाद में यह वृद्धि-दर स्थायी नहीं रही जा सकी, फिर भी मजदूरी का सामान्य स्तर निरन्तर बढ़ता ही गया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है

निम्नलिखित श्रेणियों में 200 व० प्रतिमाह से कम मजदूरी आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी-आय¹

(आधार वर्ष 1947 - 100)

वर्ष	मजदूरी-आय	मौद्रिक आय का सूचकांक	वर्ष	मजदूरी-आय	मौद्रिक-आय का सूचकांक
1947	737	100.0	1954	1,111	151.8
1948	833	120.0	1955	1,173	159.4
1949	986	134.4	1956	1,183	161.0
1950	959	132.0	1957	1,134	167.4
1951	1,396	140.9	1958	1,285	174.3
1952	1,112	150.9	1959	1,310	177.7
1953	1,111	151.8	1960	1,385	187.9

उपरोक्त तालिका से यह सात होता है कि सन् 1950 में श्रमिकों की औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी आय में कोई भी कमी नहीं हुई परन्तु सन् 1952, 1953 व 1954 में स्थिर रहने के बाद उसमें निरन्तर वृद्धि होती गयी। इस तथ्य की पुष्टि हमें दी गई तालिका से होती है

1 Source Indian Labour Statistics.

मजदूरी-आय का सामान्य सूचकांक¹

(General Index of Earnings)

(400 रु० प्रतिमाह से कम मजदूरी आय वाले फॅक्टरी श्रमिकों की औसत वार्षिक मजदूरी-आय के आधार पर)

(आधार वर्ष 1961 = 100)

वर्ष	सूचकांक	वर्ष	सूचकांक
1962	106	1966	139
1963	109	1967	151
1964	114	1968	160
1965	128	1969	171
		1970	175 अस्थायी

यद्यपि प्रथम तालिका में उन व्यक्तियों की मौद्रिक आय दी गई है, जिनकी आय 200 रु० प्रतिमाह से कम है, फिर भी सूचकांक में उनकी मजदूरी आय में वृद्धि की प्रवृत्ति का संकेत मिलता है।

सन् 1965 में 'बोनस भुगतान अधिनियम' (Payment of Bonus Act, 1965) में पास हो जाने पर यह अधिनियम प्रत्येक ऐसी फैक्टरी तथा संस्थान पर लागू हो गया जिसमें लेखा-वर्ष में किसी भी दिन 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हों। इस अधिनियम में यह प्रावधान विद्यमान था कि प्रत्येक ऐसी फैक्टरी अथवा संस्थान द्वारा श्रमिकों को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक लेखा-वर्ष में प्रत्येक श्रमिक के वेतन या मजदूरी का कम से कम 4% या 40 रु० (चाहे श्रमिक की दिशा में 25 रु०) जो भी अधिक हो, दिया जावेगा। अधिकतम बोनस की दर वेतन या मजदूरी के 20% के बराबर निर्धारित की गई। इस प्रकार श्रमिकों की मौद्रिक आय में जोर भी अधिक वृद्धि हो गई, जैसा कि पृष्ठ 337 पर दी गई तालिका में विभिन्न राज्यों तथा शरीर क्षेत्रों के उन फैक्टरी श्रमिकों की, जो 400 रु० प्रति माह से कम मजदूरी प्राप्त करते हैं, औसत वार्षिक आय से स्पष्ट है।

संवर्द्धनीय श्रमिकों की औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक मौद्रिक आय¹

राज्य/संघीय क्षेत्र	1901	1966	1967	1968	1969	1970
आन्ध्र प्रदेश	1,149	1,454	1,601	1,830	2,088	2,117
असम	1,599	2,130	2,099	2,108	2,340	2,363
बिहार	1,856	2,050	2,196	2,432	2,486	2,712
गुजरात	1,702	2,340	2,663	2,696	2,643	2,820
हरियाणा	—	1,112	2,064	2,219	2,436	2,616
हिमाचल प्रदेश	1,288	2,115	2,950	2,851	2,521	2,511
जम्मू व काश्मीर	—	978	1,209	1,532	1,805	1,838
केरल	1,152	1,724	2,009	2,125	2,467	2,467
मध्य प्रदेश	1,816	2,118	2,318	2,691	2,932	2,912
महाराष्ट्र	1,775	2,480	2,676	2,526	2,903	2,003
मेघालय	1,375	1,840	1,158	2,204	2,088	2,088
उड़ीसा	1,180	2,001	2,325	2,333	2,143	2,899
पंजाब	1,175	1,636	1,659	1,690	2,070	2,159
राजस्थान	761	1,412	1,882	1,853	2,003	2,003
तामिल नाडु	1,465	2,032	2,204	2,297	2,442	2,442
त्रिपुरा	—	1,171	1,897	1,945	2,010	2,010
उत्तर प्रदेश	1,264	1,825	1,978	2,157	2,200	2,293
वंगाल	1,410	2,029	2,175	2,382	2,675	2,761
अरुणाचल व मिजोरम	1,34	1,611	1,566	1,791	2,023	2,170
बिहार	1,655	2,321	2,497	2,788	3,013	2,845
गोआ, डामन व द्यू	—	2,105	1,751	1,242	2,073	2,406

यदि निर्मात्री तथा खनन उद्योगों की मौद्रिक मजदूरी आय की तुलना की जाय तो यह सात होना कि वन 1955 तक दोनो उद्योगों की मजदूरी-दरों में बढ़ने की प्रवृत्ति सामान्य थी। परन्तु 1956 के पश्चात् खनन उद्योगों, विशेषकर कोयला खानों के श्रमिकों, की मजदूरी दर में तीव्र गति में वृद्धि हुई।

मजदूरी-वृद्धि तथा मूल्य स्तर

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, अद्यपि औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी, अर्थात् मौद्रिक आय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, तथापि श्रमिकों ने जो भी काम दत्त वृद्धि से हुआ वह मूल्यों में वृद्धि के कारण अव्ययीय हो गया। मजदूरी-वृद्धि तथा मूल्य-वृद्धि का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 1951-61 की 12 वर्षों के अवधि अवधि में जबकि मौद्रिक आय में 45% की वृद्धि हुई, मूल्यों में भी इसी अवधि में 28% की वृद्धि हो गई। फलतः मजदूरी में वास्तविक वृद्धि केवल 14% ही रह गई। तन् 1970 तक के उपलब्ध आँकड़ों से वास्तविक मौद्रिक आय का ज्ञान आगे की गई तालिका से प्राप्त किया जा सकता है :

1 Source India, 1971.

भूमिकों की वास्तविक आय¹

[1961 = 100]

विवरण	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
आय का सामान्य सूचकांक	106	109	114	128	139	151	160	171	175
सम्पूर्ण भूमि के भूमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	103	106	121	132	146	166	171	169	174
वास्तविक आय के सूचकांक	103	113	94	97	95	91	94	101	98

1. Source : India 1973

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के फलस्वरूप 1963 के पश्चात् श्रमिकों की वास्तविक मौद्रिक आय में निरन्तर कमी होती गयी। यद्यपि सन् 1969 में इस में कुछ सुधार अवश्य हुआ था, परन्तु सन् 1970 के पश्चात् वह पुन नीचे की ओर उन्मुख हो गई। 1970 के पश्चात् जिस तीव्र गति से, विशेषकर 1972-73 में मूल्यों में वृद्धि हुई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज श्रमिकों की मौद्रिक आय पहले की अपेक्षा बहुत ही कम है।

मजदूरी-स्तर तथा राष्ट्रीय आय

मजदूरी राष्ट्रीय आय का एक अंग है। अतः राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर मजदूरी में वृद्धि होनी चाहिए। इस दृष्टि की जाच भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं मजदूरी-स्तर में वृद्धि का तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा ही की जा सकती है। 1951 से 1963 तक की अवधि में निर्माणाद्य उद्योगों के श्रमिकों की मौद्रिक आय में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि घरेलू साधनों से राष्ट्रीय आय (निदेशी आय को छोड़कर) 80 प्रतिशत की वृद्धि आकी गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में औद्योगिक श्रमिकों की मौद्रिक आय में वृद्धि बहुत ही कम थी।

एक सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुल राष्ट्रीय आय 1950-51 में 8,500 करोड़ रुपये थी, जो 1970 में बढ़ कर 16,544 करोड़ ८० हो गई। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ तथा उन राज्यों में जहाँ 'हरित-क्रान्ति' आई, लोगों का जीवन-स्तर भीड़ा ऊपर उठा। इस प्रकार देश में आर्थिक विकास तो हुआ, परन्तु उत्तरा पूरा लाभ देश के श्रमिकों एवं साधारण जनता को मिला है, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। इन वर्षों में आम जनता की मौद्रिक आय में वृद्धि अवश्य हुई है, परन्तु वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका प्रमाण कारण रहा है आकाश छूती हुई कीमते। मूल्यों में वृद्धि 1950 के बाद थक हो गई जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंगणश हुआ। द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के काल में हालत हद से ज्यादा बिगड़ गई। इस प्रकार, जैसा कि एक अन्य स्रोत से अप्रत्यक्ष आंकड़ों से तैयार की गई निम्न तालिका से स्पष्ट है, यद्यपि राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी का सह-सम्बन्ध रहा है, परन्तु मूल्य-वृद्धि से वास्तविक मौद्रिक आय कम होनी लगी है।

राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी

विवरण	1950-51	1960-61	1970-71
राष्ट्रीय आय (करोड़ रु० में)	10243	13264	18755
प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)	284	306	347

मजदूरी वृद्धि तथा लाभ वृद्धि

कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की भौतिक आय तथा सुयोग्य वी धाम की सुलभता करने पर यह ज्ञात होता है कि सन् 1950 तक श्रमिकों की औसत आय में वृद्धि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के बराबर ही थी। सन् 1956 में श्रमिकों की औसत आय में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई, परन्तु औद्योगिक उत्पादन भी उतनी ही तेजी से न बढ़ा। सन् 1960 से औसत आय में वृद्धि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा कम होती गई। जबकि 1951 से उत्पादन में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई, औसत आय में केवल 119 प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी थी।

उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप औद्योगिक लाभ में श्रमिकों की आय की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई। 1951-62 की अवधि में जब कि निर्माण औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों की आय में केवल 44 प्रतिशत की वृद्धि अनुमित की गई थी औद्योगिक लाभ में 129 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अधिकतर भाग औद्योगिक लाभ के रूप में वितरित किया गया और श्रमिकों को मजदूरी के रूप में उतना कम भाग ही प्राप्त हुआ।

कृषि-श्रमिकों की मजदूरी

कृषि क्षेत्र में लाभ श्रमिकों की आय में सुधार लाने के लिए भी 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948' लागू किया गया है। इस कानून के अन्तर्गत जम्मू व काश्मीर राज्य को छोड़ कर अन्य समस्त राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार ने कुछ कृषि संस्थाओं, सीनिंग फार्मों तथा पशुचरबीय उपकरणों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी है।

यद्यपि कृषि श्रमिकों की मजदूरी का नियंत्रण एवं निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 द्वारा किया जाता है फिर भी औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी की तुलना में कृषि-श्रमिकों की मजदूरी का स्तर कम ही रहा है। 1956-57 वर्ष के लिए उपलब्ध आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि कृषि-क्षेत्र की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 99.4 रु० ही थी।

सामान्य मजदूरी स्तर में वृद्धि के कारण

भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्राप्त मौद्रिक आय के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् मजदूरी स्तर में नमिका वृद्धि हुई है। मजदूरी में बढ़ने की प्रवृत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित रहे हैं

(1) राजनैतिक स्वतन्त्रता के पश्चात् श्रमिकों में आर्थिक दासता से मुक्ति पाने तथा अपने जीवन-स्तर में सुधार लाने की इच्छा बलवती हो गई, जिसकी अभिव्यक्ति औद्योगिक संघर्षों के रूप में की गई। परिणामस्वरूप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पास किया गया, जिसके आधार पर जीवन-निर्वाह मजदूरी एवं उचित मजदूरी निर्धारित की गई।

(2) औद्योगिक संघर्षों के निपटारे के लिए समझौते, निर्णयदेश, पक्ष-निर्णय-व्यवस्था तथा औद्योगिक ट्रिब्युनल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा दिए गए निर्णयों में भी जीवन-निर्वाह मजदूरी देने पर बल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी मजदूरी वृद्धि करने तथा देश के सविधान में निदेशक सिद्धान्तों का पालन करने पर जोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी में वृद्धि हुई।

(3) रुन् 1951 में जब देश को नियोजित आर्थिक विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश हुआ और तदुपरान्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू की गई, तब देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। श्रमिकों को मजदूरी-स्तर को ऊँचा उठाये बिना विकास-कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना संभव नहीं था।

(4) नियोजित आर्थिक विकास होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। देश का बढ़तुं सी विकास होने के फलस्वरूप औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय में से कुछ अधिक अंश मिलना स्वाभाविक था।

(5) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 पास होने के पश्चात् तथा अधिसमय तक कार्य करने के कारण अधिकतम की मजदूरी (overtime wages) में भी वृद्धि होने पर, श्रमिकों की मौद्रिक आय में भी वृद्धि हुई है।

(6) श्रमिकों में उत्पादित वृद्धि से लाभों में होने वाली वृद्धि में कुछ भाग

पाने के लिये किये गये संघर्षों के परिणामस्वरूप प्रेरणात्मक योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये धन से श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई है।

यद्यपि उपर्युक्त कारणों से श्रमिकों का सामान्य मजदूरी-स्तर ऊँचा उठा है, फिर भी मूल्य-वृद्धि के कारण मजदूरी-वृद्धि से श्रमिकों के जीवन-स्तर में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ। आवश्यकता इस बात की है कि मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति नियन्त्रित की जाये, जिससे श्रमिकों की वास्तविक आय में वृद्धि हो सके। दीर्घ मजदूरी दृष्टि में नहीं है, बल्कि मूल्य ढांचे में है।

उत्पादितता (Productivity)

श्रम की उत्पादितता (Productivity of Labour) का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि आर्थिक विकास की योजनाओं के अन्तर्गत आधुनिक यंत्रों के प्रयोग, विदेशी पूँजी की उपलब्धता, श्रमिकों के प्रशिक्षण आदि कारणों से श्रम की उत्पादितता में पर्याप्त वृद्धि हुई है, यद्यपि श्रमिकों की मजदूरी में उम अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जैसा कि आगे दी गई तालिका से स्पष्ट है :

श्रम की आय, श्रम एवं पूँजी उत्पादितता¹

(आधार 1951 = 100)

वर्ष	आय का सूचकांक	उत्पादितता का सूचकांक		लाभ का सूचकांक
		श्रम	पूँजी	
1952	117	102	93	77
1953	107	106	89	85
1954	112	120	97	97
1955	115	142	105	117
1956	111	134	90	128
1957	108	125	72	141
1958	104	136	64	130
1959	100	100	100	100
1960	108	105	94	126
1961	113	109	92	146

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि श्रमिकों की आय में वृद्धि श्रम-उत्पादितता में हुई वृद्धि से कम है। इस अवधि में पूँजी की उत्पादितता में अवश्य कमो हुई, परन्तु

इस कमी का कारण उद्योगों में अधिक विनियोग (1951 में 2,752 मि० रुपये से 1958 में 6,311 मि० रु० तथा 1959 में 11,342 मि० रुपये से 1961 में 24,144 मि० रुपये) हुआ, जिसका फल भविष्य में प्राप्त हुआ।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य यह विशेष उल्लेखनीय है, कि इस अवधि में अधिकारिक विनियोग किए जाने के फलस्वरूप उत्पादितता में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, फिर भी लाभों में निरन्तर वृद्धि होती गई। इसका अर्थ यह है, कि लाभों में वृद्धि धर्म-उत्पादितता में वृद्धि का ही परिणाम थी। इसके बावजूद भी श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि नहीं की गई।

धर्म-उत्पादितता में वृद्धि के कारण

भारत के योजना काल में धर्म-उत्पादितता में वृद्धि के निम्नलिखित कारण रहे हैं

1 विज्ञान एवं उत्पादन की नई प्रविधियों का विकास होने से धर्म की कार्य-क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

2 श्रमिकों की तकनीकी शिक्षा एवं उनके प्रशिक्षण की दिशा में किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप उनकी कार्य विधि में परिवर्तन आया है।

3 उत्पादन की नई-नई विधियों का समावेश किया गया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है।

4 प्रबन्ध व्यवस्था अधिक वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे लागत में कमी हो सके, और सामग्री, धर्म एवं पूंजी का अनावश्यक खर्च रोका जा सके। यह भी धर्म उत्पादितता में वृद्धि करने का एक तरीका है।

5 धर्म शक्ति को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने के लिए बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय किए गए हैं। धर्म वृद्धि से भी धर्म-उत्पादितता में वृद्धि हुई है।

6 धर्म उत्पादितता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अनेक योजना-योजनाएं एवं प्रेरणादायक योजनाएं लागू की गई हैं।

निष्कर्ष यद्यपि आधुनिक अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि मजदूरी और उत्पादितता वृद्धि में कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु एक विकासशील देश में दोनों में सहारा सम्बन्ध पाया जाता है। अतः सरकार, नियोजताओं तथा धर्म सचिवों को उत्पादितता वृद्धि के लिए मिल कर प्रयत्न करने चाहिए, जिससे अधिक अस्तित्व न रहे, और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे।